



भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति संबंधी रिपोर्ट

REPORT ON TREND AND PROGRESS OF BANKING IN INDIA

2023-24



भारतीय रिज़र्व बैंक
Reserve Bank of India

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36 (2) के अनुसार
31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए केंद्र सरकार को प्रस्तुत
भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति संबंधी रिपोर्ट

भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति संबंधी रिपोर्ट 2023-24



भारतीय रिज़र्व बैंक

भारतीय रिज़र्व बैंक 2024

सर्वाधिकार सुरक्षित। इस सामग्री के उद्धरण की अनुमति है, बशर्ते स्रोत को दर्शाया जाए।

भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई 400001 के लिए डॉ. स्नेहल एस. हेरवाडकर द्वारा प्रकाशित और उनके द्वारा जयंत प्रिन्टरी एलएलपी, 352/54, गिरगांव रोड, मुरलीधर टेम्पल कम्पाउन्ड, ठाकुरद्वार पोस्ट ऑफिस के पास, मुंबई - 400 002 में अभिकल्पित और मुद्रित।



भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

www.rbi.org.in

गवर्नर
GOVERNOR

प्रेषण-पत्र

कें.का.आनीअवि.बीआरडी. एस1044/13.01.001/2024-25

26 दिसंबर 2024
5 पौष 1946 (शक)

वित्त सचिव
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
नई दिल्ली - 110 001

प्रिय वित्त सचिव,

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36(2) के उपबंधों के अनुसार, मैं इस पत्र के साथ 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति संबंधी रिपोर्ट की दो प्रतियां सहर्ष प्रेषित कर रहा हूँ।

भवदीय,

27/12/24

संजय मल्होत्रा

क्र. सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
अध्याय I परिप्रेक्ष्य		
1	परिचय	1
2	विनियमन और पर्यवेक्षण	2
3	भुगतान और निपटान प्रणालियां	4
4	उभरती हुई प्रौद्योगिकी को अपनाना	5
5	वित्तीय समावेशन	6
6	उपभोक्ता संरक्षण	6
7	जलवायु परिवर्तन	7
8	समग्र मूल्यांकन	8
अध्याय II वैश्विक बैंकिंग घटनाक्रम		
1	परिचय	9
2	वैश्विक समष्टि-आर्थिक स्थितियां	9
3	वैश्विक बैंकिंग नीतिगत घटनाक्रम	11
4	वैश्विक बैंकिंग क्षेत्र का कार्यनिष्पादन	17
5	विश्व के सबसे बड़े बैंक	23
6	समग्र मूल्यांकन	25
अध्याय III नीतिगत परिवेश		
1	परिचय	26
2	समष्टि आर्थिक नीति निर्धारण	26
3	विनियामक और पर्यवेक्षी नीतियां	28
4	प्रौद्योगिकीय नवोन्मेष	35
5	वित्तीय बाजार	37
6	उपभोक्ता संरक्षण	38
7	ऋण वितरण और वित्तीय समावेशन	38
8	भुगतान और निपटान प्रणालियाँ	40
9	समग्र मूल्यांकन	41
अध्याय IV वाणिज्यिक बैंकों का परिचालन और प्रदर्शन		
1	परिचय	42
2	तुलन पत्र का विश्लेषण	42
3	वित्तीय प्रदर्शन	50

क्र. सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
4	सुदृढ़ता संकेतक	53
5	क्षेत्रक-वार बैंक ऋण : वितरण और एनपीए	63
6	वाणिज्यिक बैंकों में स्वामित्व का स्वरूप	70
7	कॉरपोरेट अभिशासन	71
8	भारत में विदेशी बैंकों का परिचालन और भारतीय बैंकों का विदेशी परिचालन	73
9	भुगतान प्रणालियां और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	73
10	प्रौद्योगिकी अंगीकरण और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	76
11	उपभोक्ता संरक्षण	76
12	वित्तीय समावेशन	80
13	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	84
14	स्थानीय क्षेत्र बैंक	86
15	लघु वित्त बैंक	87
16	भुगतान बैंक	88
17	समग्र मूल्यांकन	89
V सहकारी बैंकिंग घटनाक्रम		
1	परिचय	91
2	सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की संरचना	91
3	शहरी सहकारी बैंक	93
4	ग्रामीण ऋण सहकारी समितियां	102
5	समग्र मूल्यांकन	113
VI गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं		
1	परिचय	114
2	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी)	115
3	आवास वित्त कंपनियां (एचएफसी)	134
4	अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान	138
5	प्राथमिक व्यापारी	143
6	समग्र मूल्यांकन	146

बॉक्सों की सूची

क्र. सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
II.1	जीडीपी की तुलना में इष्टतम ऋण का अनुपात: एक क्रॉस-कंट्री विश्लेषण.....	18
III.1	निवेश के नए दिशानिर्देश: बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का विश्लेषण.....	32
III.2	जलवायु-संबंधी वित्तीय जोखिमों पर प्रकटीकरण ढांचा	33
III.3	गैर-परंपरागत ऊर्जा क्षेत्र के लिए बैंक ऋण	39
IV.1	वाणिज्यिक बैंकों में जमा राशि वृद्धि के निर्धारक तत्व	46
IV.2	बैंक अधिशेष सीआरएआर क्यों रखते हैं?.....	55
IV.3	बैंकों की लाभप्रदता पर ऋण विविधीकरण का प्रभाव.....	64
IV.4	विनियमित संस्थाओं द्वारा जनरेटिव एआई को अपनाना	76
V.1	अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों में गैर-ब्याज आय के निर्धारक.....	98
VI.1	एनबीएफसी के गैर-जमानती खुदरा ऋण पर हाल के विनियामक परिवर्तनों का प्रभाव.....	123

सारणियों की सूची

क्र. सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
II.1	आस्ति गुणवत्ता	19
II.2	जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में विनियामकीय पूंजी अनुपात	22
IV.1	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का समेकित तुलन पत्र	44
IV.2	एससीबी के निवेश	47
IV.3	चुनिंदा देयताओं/आस्तियों की बैंक समूह-वार परिपक्वता प्रोफाइल	49
IV.4	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के आय और व्यय के रुझान	52
IV.5	निधियों की लागत और निधियों पर प्रतिलाभ - बैंक समूह-वार	53
IV.6	एससीबी की घटक-वार पूंजी पर्याप्तता	53
IV.7	निजी प्लेसमेंट के माध्यम से बैंकों द्वारा जुटाए गए संसाधन	56
IV.8	लीवरेज अनुपात और चलनिधि व्याप्ति अनुपात	56
IV.9	निवल स्थिर निधीयन अनुपात	57
IV.10	अनर्जक आस्तियों में उतार-चढ़ाव - बैंक-समूह वार	58
IV.11	बैंक समूह-वार ऋण आस्तियों का वर्गीकरण	58
IV.12	विभिन्न माध्यमों से एससीबी के एनपीए की वसूली	59
IV.13	एआरसी द्वारा प्रतिभूतीकृत वित्तीय आस्तियों का विवरण	60
IV.14	रिपोर्टिंग की तारीख के आधार पर विभिन्न बैंकिंग परिचालनों में धोखाधड़ी	61
IV.15	घटना की तारीख के आधार पर विभिन्न बैंकिंग परिचालनों में धोखाधड़ी	61
IV.16	प्रवर्तन कार्रवाइयां	62
IV.17	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा सकल बैंक ऋण का क्षेत्र-वार विनियोजन	63
IV.18	एससीबी द्वारा एमएसएमई क्षेत्र को ऋण प्रवाह	67
IV.19	बैंकों द्वारा प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण	67
IV.20	पीएसएलसी की विभिन्न श्रेणियों पर भारित औसत प्रीमियम	69
IV.21	बैंकों के क्षेत्रक-वार जीएनपीए	69
IV.22	बोर्ड और इसकी समितियों में स्वतंत्र निदेशक	72
IV.23	भारत में विदेशी बैंकों का परिचालन	73
IV.24	भुगतान प्रणाली संकेतक	74
IV.25	एटीएम की संख्या	75
IV.26	एटीएम का भौगोलिक वितरण: बैंक समूह-वार	75
IV.27	आरबीआईओ में शिकायतों की प्रकृति	78
IV.28	बैंक समूह-वार बीमाकृत जमाराशि	79

क्र. सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
IV.29	वित्तीय समावेशन योजना में प्रगति.....	81
IV.30	एससीबी द्वारा नई खोली गई बैंक शाखाओं का स्तर-वार विवरण	82
IV.31	टीआरडीडीएस के माध्यम से एमएसएमई वित्तपोषण में प्रगति.....	83
IV.32	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का समेकित तुलन पत्र	84
IV.33	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का वित्तीय प्रदर्शन.....	85
IV.34	आरआरबी द्वारा उद्देश्य-वार बकाया अग्रिम	86
IV.35	स्थानीय क्षेत्र बैंकों का प्रोफाइल	86
IV.36	स्थानीय क्षेत्र के बैंकों का वित्तीय प्रदर्शन.....	87
IV.37	लघु वित्त बैंकों का समेकित तुलन-पत्र.....	87
IV.38	लघु वित्त बैंकों का वित्तीय प्रदर्शन	88
IV.39	भुगतान बैंकों का समेकित तुलन-पत्र.....	88
IV.40	भुगतान बैंकों का वित्तीय प्रदर्शन.....	89
IV.41	भुगतान बैंकों के चुनिंदा वित्तीय अनुपात	89
V.1	कृषि की ऋण प्रवाह में हिस्सेदारी	93
V.2	शहरी सहकारी बैंकों का टियर-वार वितरण	94
V.3	शहरी सहकारी बैंकों के तुलन पत्र.....	96
V.4	जमाराशि, अग्रिम और आस्तियों के अनुसार यूसीबी का विभाजन	97
V.5	शहरी सहकारी बैंकों द्वारा निवेश.....	97
V.6	अनुसूचित और गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों का वित्तीय प्रदर्शन	98
V.7	यूसीबी के चुनिंदा लाभप्रदता संकेतक	99
V.8	सीआरएआर-वार यूसीबी का विभाजन	100
V.9	यूसीबी की घटक-वार पूंजी पर्याप्तता.....	101
V.10	यूसीबी की अनर्जक आस्तियां.....	101
V.11	यूसीबी द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के लिए ऋण की संरचना.....	103
V.12	ग्रामीण ऋण सहकारी समितियों की प्रोफाइल.....	105
V.13	राज्य सहकारी बैंकों की देयताएं और आस्तियां.....	106
V.14	अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों के चुनिंदा तुलन पत्र संकेतक	107
V.15	राज्य सहकारी बैंकों का वित्तीय प्रदर्शन.....	107
V.16	राज्य सहकारी बैंकों के सुदृढ़ता संकेतक.....	108
V.17	जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की देयताएं और आस्तियां	109

क्र. सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
V.18	ज़िला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों का वित्तीय प्रदर्शन	109
V.19	ज़िला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के सुदृढ़ता संकेतक	110
VI.1	स्केल आधारित विनियामक ढांचे के तहत गतिविधि के अनुसार एनबीएफसी का वर्गीकरण.....	116
VI.2	एनबीएफसी की संरचना.....	116
VI.3	एनबीएफसी का स्वामित्व स्वरूप	118
VI.4	एनबीएफसी का संक्षिप्त तुलन-पत्र	118
VI.5	वर्गीकरण के अनुसार एनबीएफसी की देयताओं और आस्तियों के प्रमुख घटक	120
VI.6	एनबीएफसी द्वारा क्षेत्र-वार ऋण विनियोजन.....	122
VI.7	एनबीएफसी के उधार के स्रोत.....	126
VI.8	एनबीएफसी की विदेशी देयता.....	130
VI.9	एनबीएफसी क्षेत्र के वित्तीय मानदंड	131
VI.10	एचएफसी के स्वामित्व का स्वरूप	135
VI.11	एचएफसी का समेकित तुलन-पत्र	136
VI.12	एचएफसी के वित्तीय मानदंड	137
VI.13	एआईएफआई द्वारा स्वीकृत एवं वितरित वित्तीय सहायता	139
VI.14	एआईएफआई का तुलन पत्र	140
VI.15	2023-24 में एआईएफआई द्वारा जुटाए गए संसाधन.....	140
VI.16	एआईएफआई द्वारा मुद्रा बाजार से जुटाए गए संसाधन	141
VI.17	एआईएफआई के स्रोत और निधियों के परिनियोजन का विनियोजन.....	141
VI.18	एआईएफआईएस का वित्तीय प्रदर्शन	142
VI.19	एआईएफआई के चुनिंदा वित्तीय मानदंड.....	142
VI.20	प्राथमिक बाजार में पीडी का कार्यनिष्पादन	144
VI.21	जी-सेक द्वितीयक बाजार में एसपीडी का प्रदर्शन	144
VI.22	एसपीडी निधियों के स्रोत और उपयोग.....	145
VI.23	एसपीडी का वित्तीय प्रदर्शन.....	145
VI.24	एसपीडी के वित्तीय संकेतक	146

चार्ट की सूची

क्र. सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
II.1	संवृद्धि और मुद्रास्फीति	10
II.2	मौद्रिक नीति दरें	10
II.3	चालू खाता और सामान्य सरकारी सकल कर्ज	11
II.4	निजी गैर-वित्तीय क्षेत्र को बैंक ऋण	17
II.5	प्रावधान कवरेज अनुपात	20
II.6	आस्तियों पर प्रतिलाभ	21
II.7	लीवरेज अनुपात	21
II.8	बैंकों की सेहत के बाजार-आधारित सूचकांक	23
II.9	टियर 1 पूंजी के अनुसार शीर्ष 100 बैंकों का संवितरण	23
II.10	शीर्ष 100 बैंकों की आस्तियों की गुणवत्ता	24
II.11	शीर्ष 100 बैंकों की सुदृढ़ता	25
III.1	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में अदावाकृत जमाराशियाँ	30
III.2	ऊर्जा क्षेत्र (बिजली, गैस और जल) के लिए कुल ऋण में से एनसीई क्षेत्र हेतु ऋण का हिस्सा	39
IV.1	एससीबी की चुनिंदा समग्र राशियाँ	43
IV.2	तुलन पत्र संघटन	45
IV.3	जमाराशि वृद्धि	45
IV.4	ऋण वृद्धि	46
IV.5	ऋण वृद्धि में जनसंख्या समूहों का योगदान	47
IV.6	ऋण-जमाराशि और निवेश-जमाराशि अंतराल	48
IV.7	परिपक्वता कोष्ठकवार आस्तियों और देयताओं के अंतराल	48
IV.8	बैंकों की अंतरराष्ट्रीय देयताएं और आस्तियाँ	49
IV.9	भारतीय बैंकों के समेकित दावे	50
IV.10	बैंकों की तुलनपत्रेतर देयताएं	50
IV.11	लाभप्रदता अनुपात	51
IV.12	निवल ब्याज आय और निवल ब्याज मार्जिन	51
IV.13	प्रावधान व्याप्ति अनुपात	52
IV.14	बैंक समूहवार सीआरएआर और सीईटी1 अनुपात	54
IV.15	अधिशेष सीआरएआर	54
IV.16	जीएनपीए में कमी	57
IV.17	समग्र दबाव की तुलना में बड़े उधार खातों में दबाव	59
IV.18	पुनर्रचित मानक अग्रिम अनुपात	59

क्र. सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
IV.19	एआरसी को दबावग्रस्त आस्ति की बिक्री	60
IV.20	बैंक समूह-वार धोखाधड़ी	62
IV.21	क्षेत्रकवार जीएनपीए अनुपात	65
IV.22	विभिन्न उद्योगों में जीएनपीए अनुपात	66
IV.23	पीएसएलसी व्यापार की मात्रा	68
IV.24	पीएसएलसी बाजार में क्रेता और विक्रेता	68
IV.25	संवेदनशील क्षेत्रों में एक्सपोजर	70
IV.26	गैर-जमानती अग्रिमों की हिस्सेदारी	70
IV.27	बैंकों के स्वामित्व का स्वरूप	71
IV.28	एमडी और सीईओ के कुल पारिश्रमिक के घटक	72
IV.29	भारतीय बैंकों का विदेशी परिचालन	73
IV.30	खुदरा डिजिटल भुगतान बनाम कागज आधारित लिखतों का औसत मान	74
IV.31	डिजिटल भुगतान सूचकांक	75
IV.32	ओआरबीआईओ में प्राप्त इकाई प्रकार-वार शिकायतें	78
IV.33	शिकायतों का वितरण	78
IV.34	कर योग्य जमाराशियों के प्रतिशत के अनुसार बैंक समूहवार बीमित जमाराशियां	79
IV.35	चुनिंदा देशों में वित्तीय समावेशन की प्रगति	80
IV.36	आरबीआई – वित्तीय समावेशन सूचकांक	81
IV.37	पीएमजेडीवाई में प्रगति	82
IV.38	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की नई खुली बैंक शाखाओं का वितरण	82
IV.39	स्वयं सहायता समूह - ऋण का क्षेत्रीय वितरण और औसत ऋण आकार	83
IV.40	बैंकों की क्षेत्रीय पहुंच	84
IV.41	आरआरबी की आस्ति गुणवत्ता	85
IV.42	आरआरबी का जोखिम-भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात	86
IV.43	भुगतान बैंकों का लाभप्रदता संकेतक	89
V.1	ऋण सहकारी समितियों की संरचना	92
V.2	आस्ति के आकार के अनुसार ऋण सहकारी समितियों का विभाजन	92
V.3	यूसीबी की संख्या	93
V.4	यूसीबी में विलयन अभियान	93
V.5	आस्ति में वृद्धि	94
V.6	एससीबी की तुलना में यूसीबी का प्रदर्शन	95

क्र. सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
V.7	ऋण-जमा अनुपात: यूसीबी बनाम एससीबी.....	96
V.8	आस्तियों के आकार के अनुसार यूसीबी का विभाजन.....	96
V.9	निवेश : यूसीबी बनाम एससीबी.....	97
V.10	लाभप्रदता संकेतक: यूसीबी बनाम एससीबी.....	100
V.11	सीआरएआर : यूसीबी बनाम एससीबी.....	100
V.12	आस्ति गुणवत्ता.....	102
V.13	प्राथमिकता क्षेत्र उधार.....	102
V.14	आरसीसी बनाम यूसीबी : तुलन पत्र और आस्ति गुणवत्ता संकेतक.....	103
V.15	कुल सहकारी क्षेत्र में ग्रामीण ऋण सहकारी समितियों की हिस्सेदारी.....	104
V.16	दीर्घावधिक बनाम अल्पवाधिक आरसीसी.....	104
V.17	लाभ में चल रही सहकारी समितियां.....	105
V.18	संसाधन संरचना: अल्पावधिक सहकारी समितियां.....	106
V.19	एसटीसीबी के लाभ.....	107
V.20	राज्य सहकारी बैंकों की पूंजी पर्याप्तता.....	108
V.21	एनपीए अनुपात : एसटीसीबी बनाम डीसीसीबी.....	110
V.22	जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की पूंजी पर्याप्तता.....	110
V.23	दीर्घावधिक ग्रामीण सहकारी समितियों की देयताएं और आस्तियां: एक तुलना.....	112
VI.1	रिज़र्व बैंक के विनियमन के तहत एनबीएफआई का ढांचा.....	115
VI.2	एससीबी के क्रेडिट और जीडीपी की तुलना में एनबीएफसी के ऋण.....	117
VI.3	एनबीएफसी के पंजीकरण प्रमाणपत्र का पंजीकरण और निरस्सन.....	117
VI.4	एनबीएफसी के ऋणों और अग्रिमों की प्रकृति.....	119
VI.5	वर्गीकरण के अनुसार एनबीएफसी की कुल आस्तियां.....	119
VI.6	प्राप्तियों और देय राशियों के परिपक्वता प्रोफाइल.....	120
VI.7	वर्गीकरण के अनुसार ऋण का क्षेत्र-वार वितरण.....	121
VI.8	एनबीएफसी ऋण का वितरण.....	121
VI.9	एमएसएमई क्षेत्र को एनबीएफसी ऋण.....	122
VI.10	वाहन ऋण - एनबीएफसी बनाम एससीबी.....	124
VI.11	एनबीएफसी और एससीबी द्वारा सोने के एवज में अग्रिम.....	125
VI.12	सभी विनियमित संस्थाओं को मिलाकर बकाया सूक्ष्म-ऋण.....	125
VI.13	उधार के प्रमुख स्रोत.....	126
VI.14	एनबीएफसी के प्रति बैंकों का एक्सपोजर.....	127

क्र. सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
VI.15	एनबीएफसी के उधार का स्वरूप.....	127
VI.16	निजी एनबीएफसी के एनसीडी प्राइवेट प्लेसमेंट.....	128
VI.17	निजी एनबीएफसी द्वारा सीपी जारी करना.....	128
VI.18	एनबीएफसी-डी में जनता की जमाराशियां	129
VI.19	एनबीएफसी द्वारा ऋण बिक्री और प्रतिभूतीकरण	129
VI.20	एनबीएफसी का संरचनात्मक तरलता विवरण.....	130
VI.21	एनबीएफसी का लाभप्रदता अनुपात.....	131
VI.22	एनबीएफसी के ऋण और अग्रिमों का वर्गीकरण.....	132
VI.23	निष्पादित ऋण एवं अग्रिमों का पोर्टफोलियो विश्लेषण	132
VI.24	वर्गीकरण के अनुसार एनबीएफसी की आस्ति गुणवत्ता.....	133
VI.25	लेयर-वार एनपीए अनुपात.....	133
VI.26	क्षेत्र-वार जीएनपीए अनुपात	133
VI.27	बड़े उधार खातों में दबाव	134
VI.28	एनबीएफसी का सीआरएआर.....	134
VI.29	संवेदनशील क्षेत्रों में एक्सपोजर	135
VI.30	एचएफसी, एससीबी और अन्य एनबीएफसी द्वारा आवास क्षेत्र को ऋण.....	135
VI.31	एचएफसी द्वारा संसाधन जुटाना.....	136
VI.32	एचएफसी में जनता की जमाराशियों का विभाजन.....	137
VI.33	एचएफसी की लेयर-वार आस्ति गुणवत्ता	138
VI.34	पूंजी पर्याप्तता.....	138
VI.35	ए.आई.एफ.आई. का वितरण, आस्ति-आकार के अनुसार.....	139
VI.36	एआईएफआई द्वारा जुटाए गए रुपया संसाधनों की भारित औसत लागत और परिपक्वता	141
VI.37	चुनिंदा एआईएफआई की दीर्घकालिक पीएलआर संरचना	142
VI.38	एआईएफआई का आरओए	143
VI.39	एआईएफआई के सुदृढ़ता संकेतक	143
VI.40	पीडी के हामीदारी आढ़त की औसत दर.....	144
VI.41	एसपीडी की पूंजी और जोखिम-भारित आस्ति स्थिति	146

परिशिष्ट सारणियों की सूची

क्र. सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
IV.1	भारतीय बैंकिंग क्षेत्र, एक दृष्टि में	147
IV.2	भारत में बैंकों की अंतरराष्ट्रीय देयताएं - लिखतों के प्रकार के आधार पर.....	148
IV.3	भारत में बैंकों की अंतरराष्ट्रीय आस्तियां - लिखतों के प्रकार के आधार पर.....	149
IV.4	भारत के अलावा अन्य देशों पर बैंकों के समेकित अंतरराष्ट्रीय दावे	150
IV.5	बैंकों के समेकित अंतरराष्ट्रीय दावे: अवशिष्ट परिपक्वता और क्षेत्र	151
IV.6	भारत में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का तुलनपत्रेतर एक्सपोजर	152
IV.7	रिपोर्टिंग की तारीख के आधार पर विभिन्न बैंकिंग परिचालनों में धोखाधड़ी	153
IV.8	किसान क्रेडिट कार्ड योजना: राज्य-वार प्रगति.....	156
IV.9	संवेदनशील क्षेत्रों को बैंक समूह-वार उधार.....	158
IV.10	घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की शेयरधारिता का स्वरूप.....	159
IV.11	भारतीय बैंकों के विदेशी परिचालन	162
IV.12	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की शाखाएं और एटीएम.....	163
IV.13	सूक्ष्म वित्त कार्यक्रमों की प्रगति	166
IV.14	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रमुख वित्तीय संकेतक: राज्य-वार	167
IV.15	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) - पीएसएल लक्ष्य और उपलब्धि - 2023-24.....	169
V.1	वित्तीय प्रदर्शन के संकेतक: अनुसूचित यूसीबी.....	170
V.2	चुनिंदा वित्तीय मापदंड: अनुसूचित यूसीबी.....	172
V.3	राज्य सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति के प्रमुख संकेतक	173
V.4	जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति के प्रमुख संकेतक	174
V.5	प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के सदस्यों और उधारकर्ताओं का विवरण	175
V.6	प्राथमिक कृषि ऋण समितियां	176
V.7	प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के चुनिंदा संकेतक - राज्यवार	177
V.8	राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों की देयताएं और आस्तियां	179
V.9	राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों का वित्तीय प्रदर्शन	180
V.10	राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों की आस्ति गुणवत्ता	181
V.11	राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के प्रमुख वित्तीय संकेतक-राज्य-वार	182
V.12	प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों की देयताएं और आस्तियां.....	183

क्र. सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
V.13	प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों का वित्तीय प्रदर्शन.....	184
V.14	प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों की आस्ति गुणवत्ता	185
V.15	प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के प्रमुख वित्तीय संकेतक.....	186
VI.1	एनबीएफसी का समेकित तुलन पत्र.....	187
VI.2	एनबीएफसी-यूएल का समेकित तुलन पत्र.....	188
VI.3	एनबीएसी-एमएल का समेकित तुलन पत्र.....	189
VI.4	एनबीएसी-डी का समेकित तुलन पत्र	190
VI.5	एनबीएफसी द्वारा विभिन्न क्षेत्रों को ऋण.....	191
VI.6	एनबीएफसी-यूएल का वित्तीय प्रदर्शन.....	192
VI.7	एनबीएफसी-एमएल का वित्तीय प्रदर्शन	193
VI.8	वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत और वितरित वित्तीय सहायता.....	194
VI.9	एकल प्राथमिक व्यापारियों का वित्तीय प्रदर्शन	198
VI.10	एकल प्राथमिक व्यापारियों के चुनिंदा वित्तीय संकेतक	200

चुनिन्दा संक्षेपाक्षरों की सूची

एए	खाता समाहर्ता	सीबीपी	सह-ब्रांडिंग भागीदार
एए	अपील प्राधिकारी	सीसीबी	पूँजी संरक्षण बफर
एसीबी	बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति	सीसीआईएल	क्विलयरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
आई	उन्नत अर्थव्यवस्थाएं	सीसीपी	केंद्रीय प्रतिपक्षकार
एएफए	प्रमाणीकरण के अतिरिक्त कारक	सीसीपीए	केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिकार
एएफएस	बिक्री के लिए उपलब्ध	सीसीआर	प्रतिपक्ष ऋण जोखिम
एजीआर	वैकल्पिक शिकायत निवारण	सी-डी-अनुपात	ऋण-जमा अनुपात
एआई	कृत्रिम मेधा	सीडीएस	ऋण चूक स्वैप
एआईडी	सर्व-समावेशी दिशानिर्देश	सीडी	जमा प्रमाणपत्र
एआईएफआई	अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान	सीईओ	मुख्य कार्यपालक अधिकारी
एएनबीसी	समायोजित निवल बैंक क्रेडिट	सीईपीसी	उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण प्रकोष्ठ
एपीआई	एप्लिकेशन प्रोग्रैमिंग इंटरफेस	सीईपीडी	उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण विभाग
एआरसी	आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी	सीईओबीई	तुलनपत्र बाह्य एक्सपोजर के समकक्ष ऋण
एआरडीएल	ऑटोरिग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूटेड लैंग	सीईओ	मुख्य कार्यपालक अधिकारीगण
एआरआर	वैकल्पिक संदर्भ दर	सीईटी1	साझा इक्विटी स्तर 1
एटीएम	एटीएम	सीएफएल	वित्तीय साक्षरता केंद्र
बीबीपीओयू	भारत बिल भुगतान परिचालन इकाई	सीजीटीएमएसई	सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि न्यास
बीबीपीएस	भारत बिल भुगतान प्रणाली	सीआईआर	लागत-से-आय अनुपात
बीसी	कारोबारी प्रतिनिधि	सीआईएसबीआई	बैंकिंग अवसंरचना के लिए केंद्रीय सूचना प्रणाली
बीसीबीएस	बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति	सीकेवाईसीआर	केंद्रीय अपने ग्राहक को जानिए रजिस्ट्रारी
बीडीडीआर	अशोध्य और संदिग्ध ऋण रिज़र्व	सीएमबी	नकद प्रबंधन बिल
बीआईएस	अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक	सीएम	क्विलयरिंग सदस्य
बीओई	बैंक ऑफ इंग्लैंड	सीओडी	प्रारंभ संचालन तिथि
बीपीएस	आधार अंक	सीओआर	पंजीकरण प्रमाणपत्र
बीआर अधिनियम	बैंकिंग विनियमन अधिनियम	सीपीएमआई	भुगतान और बाजार अवसंरचना समिति
बीएसबीडीए	बुनियादी बचत बैंक जमा खाते	सीआरएआर	जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूँजी अनुपात
सीएबी	चालू खाता शेष	सीआरई	व्यावसायिक स्थावर संपदा
सीएडी	चालू खाता घाटा		
सीएजीआर	चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर		
कासा	चालू खाता और बचत खाता		
सीबीडीसी	केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा		
सीबीडीसी-आर	केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा- खुदरा		

सीआरजीएफटीएलआईएच	निम्न आय आवास के लिए क्रेडिट जोखिम गारंटी फंड ट्रस्ट	एफसीएनआर(बी)	विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक)
सीआरआईएलसी	बड़े ऋण पर सूचना का केंद्रीय भंडार	एफआई	वित्तीय समावेशन
सीआरपीसी	केंद्रीकृत प्राप्ति एवं संसाधन केंद्र	एफआईपी	वित्तीय समावेशन योजना
सीआरआर	आरक्षित नकदी निधि अनुपात	एफआईपी	वित्तीय सूचना प्रदाता
सीटीएस	चेक ट्रंकेशन सिस्टम	एफआई-यूएस	वित्तीय सूचना उपयोगकर्ता
डीबीआईई	भारतीय अर्थव्यवस्था पर डेटाबेस	एफएलसी	वित्तीय साक्षरता केंद्र
डीबीटी	प्रत्यक्ष लाभ अंतरण	एफएलडीजी	प्रथम हानि डिफॉल्ट गारंटी
डीसीसीबी	जिला सहकारी बैंक	एफपीसी	उचित आचरण संहिता
डीईए	जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता	एफपीएस	तीव्र भुगतान प्रणाली
डीएफआई	विकास वित्तीय संस्थान	फ्री-एआई	कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उत्तरदायी और नैतिक सक्षमता के लिए रूपरेखा
डीएफआर	जमा सुविधा दर	एफएसबी	वित्तीय स्थिरता बोर्ड
डीआई	जमा बीमा	एफवीआई	धोखाधड़ी भेद्यता सूचकांक
डीआईसीजीसी	निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम	एफएक्स	विदेशी मुद्रा
डीआईएफ	जमा बीमा निधि	जीसीसी	जनरल क्रेडिट कार्ड
डीएलए	डिजिटल लेंडिंग ऐप	जीडीपी	सकल घरेलू उत्पाद
डीपीआई	डिजिटल भुगतान सूचकांक	जीडीआर	वैश्विक निक्षेपागार रसीदें
ईसीबी	यूरोपीय सेंट्रल बैंक	जेनएआई	जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
ईसीबीएस	बाह्य वाणिज्यिक उधार	जीएफसी	वैश्विक वित्तीय संकट
ईसीएल	अपेक्षित ऋण हानि	जीएचजी	ग्रीनहाउस गैस
ईसीएलजीएस	आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना	जीएमएम	जनरलाइज्ड मेथड ऑफ मोमेंट्स
ईसीएम	त्रुटि सुधार शब्द	जीएनपीए	सकल अनर्जक आस्तियां
ईएमई	उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाएँ	जी- सेक	सरकारी प्रतिभूतियां
ईएमडीई	उभरती बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाएँ	जी-एसआईबी	प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण वैश्विक बैंक
ईआरपी	उद्यम संसाधन आयोजना	जीएसटी	वस्तु एवं सेवा कर
ईयू	यूरोपीय संघ	जीवीए	सकल मूल्य वर्धित
ईडब्ल्यूआई	प्रारंभिक चेतावनी सूचकांक	एचएफसी	आवास वित्त कंपनियां
ईडब्ल्यूएस	पूर्व चेतावनी संकेत	एचएफसी-डी	जमा स्वीकार करने वाली आवास वित्त कम्पनियाँ
एक्जिम बैंक	भारतीय निर्यात-आयात बैंक	एचएफटी	ट्रेडिंग के लिए धारित
एफएटीएफ	वित्तीय कार्रवाई कार्यबल	एचआईटीएम	ह्यूमेन इन दी मिडिल
एफबी	विदेशी बैंक	एचक्यूएलए	उच्च गुणवत्ता वाली चल आस्तियां
		एचटीएम	परिपक्वता तक धारित

आईबीसी	दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता	एलटीवी	ऋण-से-मूल्य
आई-सीआरआर	वृद्धिशील नकद आरक्षित अनुपात	एमसीआई	मल्टी-फंक्शन क्रिप्टो-एसेट इंटरमीडियरीज
आईसीटी	सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी	एमडी	प्रबंध निदेशक
आईएफआरएस	अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक	एमडीए	माइक्रो-डेटा विश्लेषण
आईएफएससी	अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र	एमएल	मशीन लर्निंग
आईजीआर	आंतरिक शिकायत निवारण	एमपीसी	मौद्रिक नीति समिति
आईएलएंडएफएस	बुनियादी ढांचा पट्टे और वित्तीय सेवाएं	एमआरओ	मुख्य पुनर्वित्त परिचालन
आईएमएफ	अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष	एमएसई	सूक्ष्म और लघु उद्यम
आईएमपी	तत्काल भुगतान सेवा	एमएसएफ	सीमांत स्थायी सुविधा
इनविट्स	बुनियादी ढांचा निवेश ट्रस्ट	एमएसएमई	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम
आईओ	आंतरिक लोकपाल	नाबार्ड	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
आईओएससीओ	अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन	एनएबीएफआईडी	राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक
आईआरएसीपी	आय पहचान, आस्ति वर्गीकरण और अग्रिम संबंधी प्रावधानीकरण	एनएफएससीओबी	राष्ट्रीय राज्य सहकारी बैंक महासंघ
आईएसएसबी	अंतरराष्ट्रीय धारणीयता मानक बोर्ड	एनएवी	निवल आस्ति मूल्य
आईटी	सूचना प्रौद्योगिकी	एनबीएफसी-बीएल	एनबीएफसी-बेस लेयर
जेएलजी	संयुक्त देयता समूह	एनबीएफसी-सीआईसी	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - कोर निवेश कंपनी
केसीसी	किसान क्रेडिट कार्ड	एनबीएफसी-आईसीसी	एनबीएफसी-निवेश और क्रेडिट कंपनी
केपीआई	मुख्य निष्पादन संकेतक	एनबीएफसी-आईएफसी	एनबीएफसी-अवसंरचना वित्त कंपनी
केवाईसी	अपने ग्राहक को जानिए	एनबीएफसी-एमएफआई	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - सूक्ष्म वित्त संस्थान
एलएबी	स्थानीय क्षेत्र बैंक	एनबीएफसी-एमजीसी	एनबीएफसी-बंधक गारंटी कंपनी
एलएफएफ	चलनिधि समायोजन सुविधा	एनबीएफसी-एमएल	एनबीएफसी-मिडिल लेयर
एलबीएस	अग्रणी बैंक योजना	एनबीएफसी	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनीयां
एलसीआर	चलनिधि कवरेज अनुपात	एनबीएफसी-एनओएफएचसी	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - गैर- ऑपरेटिव वित्तीय होल्डिंग कंपनी
एलईए	विधि प्रवर्तन एजेन्सी		
एलईएफ	बड़े एक्सपोजर फ्रेमवर्क		
एलआर	लीवरेज अनुपात		

एनबीएफसी-डी	जमा स्वीकार करने वाली एनबीएफसी	ओसीईएन	ओपन क्रेडिट इनेबलमेंट नेटवर्क/
एनबीएफसी-पी2पी	एनबीएफसी-समकक्षीय उधार प्लेटफॉर्म	ओडी	बेजमानती ऋण सक्षमीकरण नेटवर्क
एनबीएफसी-यूएल	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – ऊपरी परत/स्तर	ओईएफ	ओवरड्राफ्ट
एनबीएफआई	गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं	ओआरबीआईओ	निरंतर स्वरूप की निधि
एनसीसीडी	गैर-केंद्रीय समाशोधित व्युत्पन्नी	ओटीसी	भारतीय रिजर्व बैंक लोकपाल के कार्यालय
एनसीडी	अपरिवर्तनीय डिबेंचर	पी2एम	काउंटर पर
एनसीई	गैर-परंपरागत ऊर्जा	पी2पी	व्यक्ति से व्यापारी
एनडीएस-ओएम	तयशुदा लेनदेन प्रणाली- ऑर्डर मिलान	पीसीएस	व्यक्ति-से-व्यक्ति
एनडीटीएल	निवल मांग और मीयादी देयताएं	पीए	प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ
एनईएफटी	राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण	पी एंड एल	भुगतान समाहर्ता
एनजीएफएस	नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम	पीबीएस	लाभ और हानि
एनएचबी	राष्ट्रीय आवास बैंक	पीसीए	भुगतान बैंक
एनआईआई	निवल ब्याज आय	पीसीएआरडीबीएस	त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई
एनआईएम	निवल ब्याज मार्जिन	पीसीआर	प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
एनएलडीआर	राष्ट्रीय स्तर का डेटा निक्षेपागार	पीडी	प्रावधान कवरेज अनुपात
एनएनपीए	निवल अनर्जक आस्तियां	पीएलआर	प्राथमिक व्यापारी
एनओएफ	निवल स्वामित्व निधि	पीएमएवाई	मूल आधार दर
एनपीआई	राष्ट्रीय भुगतान इंटरफ़ेस	पीएमजेडीवाई	प्रधानमंत्री आवास योजना
एनपीएल	अनर्जक ऋण	पीआरएवीएएएच	प्रधानमंत्री जन धन योजना
एनआरसी	नामांकन और पारिश्रमिक समिति	पीएसबी	विनियामक अनुप्रयोग, सत्यापन और प्राधिकरण के लिए मंच
एनआरई	अनिवासी बाह्य रुपया	पीएसएल	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक
एनआरओ	अनिवासी साधारण	पीएसएलसी	प्राथमिकता प्राप्त उधार
एनएसएफआई	वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय रणनीति	पीएसओ	प्राथमिकता प्राप्त उधार प्रमाणपत्र
एनएसएफआर	निवल स्थिर निधीयन अनुपात	पीएसयू	भुगतान प्रणाली ऑपरेटर
एनएसयूसीबी	गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक	पीवीबी	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम
ओबीएस	तुलनपत्रेतर	आरबी-सीआरआईएस	निजी क्षेत्र के बैंक
		आरबी-आईओएस	रिजर्व बैंक – जलवायु जोखिम सूचना प्रणाली
		आरबीआईएच	रिजर्व बैंक - एकीकृत लोकपाल योजना
		आरबीपी	रिजर्व बैंक नवोन्मेष केंद्र
			जोखिम आधारित प्रीमियम

आरसीसी	ग्रामीण ऋण सहकारी समितियां	एसपीडी	स्टैंडअलोन प्राइमरी डीलर
आरईआईटी	रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट	एसआर	प्रतिभूति रसीद
आरई	विनियमित संस्थाएँ	एसआरओ	स्व-नियामक संगठन
आरएफ़	रेड फ्लैग्ड अकाउंट	एसआरओ-एफटी	स्व-नियामक संगठन-फिनटेक
आरएमसीबी	बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति	एसएसबी	मानक-निर्धारण निकाय
आरओए	आस्ति पर प्रतिलाभ	एसटीसीबी	राज्य सहकारी बैंक
आरओई	इक्विटी पर प्रतिलाभ	एसयूसीबी	अनुसूचित यूसीबी
आरपीओ	रिकवरी प्वाइंट ऑब्जेक्टिव	टी बिल	ट्रेजरी बिल
आरआर	आरक्षित निधि अनुपात	टीसीएफडी	जलवायु-संबंधित प्रकटीकरण पर टास्क फोर्स
आरआरबी	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	टीएफपीजी	कुल कारक उत्पादकता वृद्धि
आरएस	विनियामक सैंडबॉक्स	टीओटी	टोल ऑपरेट ट्रांसफर
आरएसए	पुनर्चित मानक अग्रिम	टीआर	व्यापार भंडार
आरटीजीएस	तत्काल सकल निपटान	ट्रेड्स	व्यापारिक प्राप्य-राशि भुनाई प्रणाली
आरटीओ	रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव	टीवीपी	लक्ष्य परिवर्तनीय वेतन
आरडब्ल्यूए	जोखिम भारित आस्तियाँ	यूई	संयुक्त अरब अमीरात
एसएएफ	पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचा	यूसीबीएस	शहरी सहकारी बैंक
सरफेसी एक्ट	वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतीकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम	यूआईएडीआई	भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
एसबीआर	स्केल-आधारित विनियमन	यूएलआई	एकीकृत ऋण इंटरफ़ेस
एससीएआरडीबीएस	राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	यूपीआई	एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस
एससीबी	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	यूटी	केंद्र शासित प्रदेश
एसडीएफ़	स्थायी जमा सुविधा	वीपी	परिवर्तनीय वेतन
एसई	पर्यवेक्षित संस्थाएं	वीआरआरआर	परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो
एसएफबी	लघु वित्त बैंक	डब्ल्यूएसीआर	भारित औसत मांग दर
एसजीआरबी	संप्रभु हरित बॉण्ड	डब्ल्यूएडीटीडीआर	भारित औसत घरेलू सावधि जमा दर
एसएचजी	स्वयं सहायता समूह	डब्ल्यूएएलआर	भारित औसत उधार दर
सिडबी	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक	डब्ल्यूएपी	भारित औसत प्रीमियम
एसएलए	सेवा-स्तरीय समझौते	डब्ल्यूईओ	विश्व आर्थिक परिदृश्य
एसएलआर	सांविधिक चलनिधि अनुपात	डब्ल्यूएलए	व्हाइट लेबल एटीएम
एसएमए	विशेष उल्लेख खाते		
एसएमएफ़	छोटे और सीमांत किसान		

समग्र वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए नवाचारों और सुरक्षा उपायों के बीच संतुलन साधते हुए वृहद विवेकपूर्ण नीतियों ने भारतीय बैंकिंग प्रणाली और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के सुदृढ़ता मापदंडों को सक्रियतापूर्वक आधार प्रदान किया है। इससे वित्तीय संस्थाएं ऋण वृद्धि बनाए रखने और घरेलू आर्थिक गतिविधि को बल देने में सक्षम बनी हैं।

1. परिचय

1.1 2022-2023 के दौरान एक ही समय में की गई वैश्विक मौद्रिक सख्ती के बाद मुद्रास्फीति कम हो रही है, किंतु 2024 में आर्थिक गतिविधि नरम पड़ने की राह पर है। इस कारण से प्रमुख केंद्रीय बैंकों को नीतिगत दरों में कटौती शुरू करनी पड़ी। मुद्रास्फीति की रफ्तार को कम करना, अर्थात् उसे लक्ष्यों के अनुरूप रखना, चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है, जबकि वैश्विक वित्तीय बाजारों में अस्थिरता का दौर है। इसके अलावा भू-राजनीतिक संघर्ष, भू-आर्थिक विखंडन, वस्तु मूल्य में अस्थिरता, जलवायु परिवर्तन, आबादी और कमजोर होती उत्पादकता वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण के लिए चुनौती बनी हुई है।

1.2 2023 में कुछ उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (ईई) के बैंकिंग क्षेत्र में आई अस्थिरता को त्वरित नीतिगत कार्रवाई करते हुए निपटाया गया जिससे एक प्रणालीगत संकट और संभावित प्रभाव-प्रसार को रोका जा सका, पूंजी बफर मजबूत हुआ, लाभप्रदता बेहतर हुई और गैर-ब्याज आय बढ़ने तथा समुचित आस्ति गुणवत्ता संतोषजनक रहने से वैश्विक बैंकिंग क्षेत्र में सुदृढ़ता के संकेत दिखाई दिए। हालांकि, कमजोर जोखिम संकेतकों वाले खस्ता बैंकों की संख्या, खासकर एशिया में, बढ़ रही है¹।

1.3 भारत में मजबूत समष्टि-आर्थिक बुनियादी व्यवस्था के कारण भारतीय बैंकिंग और गैर-बैंकिंग वित्तीय क्षेत्रों के

प्रदर्शन और सुदृढ़ता में वृद्धि हुई है। 2023-24 में लगातार छठे वर्ष बैंकों की लाभप्रदता में सुधार हुआ है, और उनका सकल अनर्जक आस्ति (जीएनपीए) अनुपात मार्च 2024 के अंत में 13 वर्षों में अपने निम्नतम स्तर 2.7 प्रतिशत पर पहुंच गया²। बैंकों की पूंजी स्थिति संतोषजनक रही, जो लीवरेज अनुपात और पूंजी बनाम जोखिम भारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) जैसे प्रमुख मापदंडों में परिलक्षित होती है। एनबीएफसी का ऋण विस्तार मजबूत रहा और साथ ही उनके तुलन-पत्र पहले से बेहतर हुए, ऋण गुणवत्ता और लाभप्रदता में सुधार हुआ तथा अतिरिक्त पूंजी राशि संतोषजनक रही।

1.4 इस पृष्ठभूमि में, यह अध्याय घरेलू बैंकिंग क्षेत्र और एनबीएफसी के समक्ष आने वाले अवसरों और चुनौतियों का समग्र परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है। खंड 2 में विनियामकीय और पर्यवेक्षी परिवर्तनों के लिए दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है। भुगतान और निपटान प्रणालियों में हुए विकास को खंड 3 में शामिल किया गया है। उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने से जुड़े अवसरों और जोखिमों पर खंड 4 में चर्चा की गई है। वित्तीय समावेशन, जमा, उपभोक्ता संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों को खंड 5 से 7 में क्रमशः शामिल किया गया है। समापन खंड 8 में अध्याय का समग्र मूल्यांकन है।

¹ अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (2024), ग्लोबल फाइनेंशियल स्टैबिलिटी रिपोर्ट, अक्टूबर।

² डेटा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के वैश्विक परिचालनों से संबंधित है।

2. विनियमन और पर्यवेक्षण

1.5 रिज़र्व बैंक के हालिया विनियामकीय उपायों के आधार पर, 'कनेक्ट 2 रेग्युलेट' कार्यक्रम के माध्यम से विनियमनों के निर्धारण में परामर्श प्रक्रिया को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर घोषित विषयों पर अपने विचारों को साझा करने के लिए रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर हितधारकों के लिए एक समर्पित खंड उपलब्ध कराया जाएगा³।

1.6 बैंकों, एनबीएफसी और अन्य वित्तीय संस्थाओं के पर्यवेक्षण की प्रक्रिया के तहत अब ध्यान प्रारंभिक पहचान और पूर्व-निवारक सुधार पर है। उन्नत ऑफ-साइट मूल्यांकन ढांचा अधिक विश्लेषणात्मक और दूरदर्शी है जिसमें मैक्रो-स्ट्रेस टेस्ट, प्रारंभिक चेतावनी संकेतक (ईडब्ल्यूआई), धोखाधड़ी भेद्यता सूचकांक (एफवीआई), माइक्रो-डेटा विश्लेषण (एमडीए), और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) तथा मशीन लर्निंग (एमएल) तकनीकों के उपयोग को शामिल किया गया है।

1.7 प्रबंध निदेशकों (एमडी) और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सीईओ, तथा बोर्ड निदेशक) सहित पर्यवेक्षित संस्थाओं (एसई) के साथ रिज़र्व बैंक की लगातार और व्यापक बातचीत को जारी रखा जाएगा। एसई के साथ जुड़ाव को 'दक्ष' पोर्टल के माध्यम से भी सुदृढ़ बनाया जा रहा है। 'दक्ष' एक सुप-टेक पहल है जिसमें विभिन्न पर्यवेक्षी प्रक्रियाओं को कारगर बनाने और मजबूत करने के लिए शुरू से अंत तक कार्य पूरा करने के लिए समाधान है। इसके अलावा सांविधिक लेखा परीक्षकों के साथ प्रत्यक्ष बातचीत ने निरीक्षण ढांचे को और मजबूत किया है। इस परामर्शी दृष्टिकोण का उपयोग बासेल III मानकों सहित विभिन्न विनियामक दिशानिर्देशों के संशोधन में किया जा रहा है। रिज़र्व बैंक जलवायु संबंधी वित्तीय जोखिमों के लिए प्रकटीकरण ढांचे पर अंतिम दिशा-निर्देश जारी करने पर भी काम कर रहा है।

गैर जमानती उधार

1.8 गैर जमानती खुदरा क्षेत्रों में उच्च ऋण वृद्धि के कारण अत्यधिक जोखिम निर्माण की संभावना को नियंत्रित करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा नवंबर 2023 में किए गए समष्टि विवेकपूर्ण उपायों के कारण ऋण वृद्धि में कुछ नरमी आई है, लेकिन चूक होने के स्तर और लीवरेज पहले से अधिक सतर्कता की मांग करते हैं। यद्यपि शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा गैर जमानती ऋण देने के लिए विशिष्ट सीमाएं निर्धारित की गई हैं और एससीबी और एनबीएफसी के निदेशक मंडल को गैर जमानती ऋण पर सीमा तय करने का विवेकाधिकार है, परंतु कुछ संस्थाओं ने इस संबंध में बहुत ऊंची सीमा तय कर रखी है जिस पर लगातार निगरानी रखने की जरूरत है। तथापि, रिज़र्व बैंक को उम्मीद है कि आरई के निदेशक मंडल विवेकशीलता दिखाएंगे और अपने स्वयं की वित्तीय सुदृढ़ता के साथ-साथ प्रणालीगत वित्तीय स्थिरता के हित में अत्यधिक उधार देने से बचेंगे⁴।

स्वर्ण ऋण

1.9 स्वर्ण आभूषणों और रत्नाभूषणों के बदले ऋण देने, जिसमें टॉप-अप ऋण भी शामिल हैं, में देखी गई कई अनियमितताओं के मद्देनजर रिज़र्व बैंक ने एसई को सलाह दी है कि वे कमियों की पहचान करने और समयबद्ध तरीके से उचित उपचारात्मक उपाय शुरू करने के लिए स्वर्ण ऋण संबंधी अपनी नीतियों, प्रक्रियाओं और प्रथाओं की व्यापक समीक्षा करें। एसई को सलाह दी गई थी कि वे अपने स्वर्ण ऋण पोर्टफोलियो की बारीकी से निगरानी करें और आउटसोर्स गतिविधियों और त्रयस्थ सेवा प्रदाताओं पर पर्याप्त नियंत्रण सुनिश्चित करें।

टॉप-अप ऋण

1.10 ग्राहकों को अपना वर्तमान घर, वाहन या सोना आदि गिरवी रखकर टॉप-अप ऋण के रूप में अतिरिक्त ऋण प्राप्त

³ भारतीय रिज़र्व बैंक (2024)। विकासवात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य, 6 दिसंबर।

⁴ भारतीय बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में समसामयिक मुद्दे, श्री शक्तिकान्त दास द्वारा फाइनेंशियल एक्सप्रेस मॉडर्न बीएफएसआई शिखर सम्मेलन, मुंबई में उद्घाटन संबोधन - 19 जुलाई 2024।

करने की सुविधाएँ मिलती हैं। कई आरई ऐसे जमानती ऋणों को कम जोखिम वाला मान सकते हैं। इसलिए ऐसी अतिरिक्त सुविधाएँ अक्सर न्यूनतम प्रक्रियाओं और उचित छानबीन के बिना स्वीकृत की जाती हैं, जिसमें शिथिल हामीदारी मानक और ऋण-मूल्य (एलटीवी) अनुपात संबंधी विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों के पालन में ढिलाई, जोखिम भार और धन के अंतिम उपयोग को सुनिश्चित न किया जाना शामिल है। इन प्रथाओं से जोखिम बढ़ सकता है, विशेष रूप से ऐसे समय में जब इन ऋणों के संपार्श्विक अस्थिर हो जाते हैं या चक्रिय मंदी का सामना करते हैं। इन चिंताओं को देखते हुए नवंबर 2023 में रिज़र्व बैंक ने निर्देश दिया था कि चल आस्तियों के बदले आरई द्वारा दिए गए सभी टॉप-अप ऋणों, जो स्वाभाविक रूप से मूल्यहास करने वाली प्रकृति के होते हैं, को ऋण मूल्यांकन, विवेकपूर्ण सीमाओं और जोखिम उद्देश्यों के लिए गैर-जमानती ऋण के रूप में माना जाए।

ऋणों पर फोर-क्लोजर प्रभार/पूर्व-भुगतान दंड

I.11 बैंकों और एनबीएफसी को वर्तमान में व्यवसाय से इतर अन्य उद्देश्यों के लिए स्वीकृत किसी भी फ्लोटिंग रेट आवधिक ऋण पर व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को, सह-दायित्वधारक(कों) के साथ या उसके बिना फोर-क्लोजर प्रभार/पूर्व-भुगतान दंड लगाने की अनुमति नहीं है। बेहतर पारदर्शिता के माध्यम से ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) को दिए जाने वाले ऋण को सुरक्षित करने के लिए ऐसे विनियमों के दायरे को व्यापक बनाने पर विचार किया जा रहा है।

निजी ऋण बाजार

I.12 बैंकों से निजी संस्थाओं की ओर ऋण मध्यस्थता में बदलाव वैश्विक स्तर पर जोर पकड़ रहा है। परंपरागत रूप से निजी ऋण संस्थाएं मध्यम आकार की कंपनियों, जो एक ऐसा खंड हैं जो आमतौर पर बैंकों और सार्वजनिक ऋण बाजारों से वित्त प्राप्त करने में चुनौती का सामना करता

है, को वित्तपोषित करने के लिए उच्च जोखिम वहन करने वाले निवेशकों से संसाधन जुटाती हैं। हाल के रुझान संकेत देते हैं कि निजी ऋण की पहुँच मध्यम आकार के कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं से परे जा रही है जिससे साझा ऋण बाजारों के साथ उनकी प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है⁵। हालांकि भारत में ऐसी निजी संस्थाओं और उनके द्वारा जुटाए गए संसाधनों का आकार बहुत बड़ा नहीं है, फिर भी, बैंकों और एनबीएफसी सहित विनियमित संस्थाओं और ऐसी फर्मों के बीच अंतर-संबंधों पर करीब से नजर डालने की जरूरत है। उनके बीच गहरा अंतर-संबंध प्रणालीगत चिंताओं को जन्म दे सकता है और साथ ही विनियमों के उल्लंघन के मामले में विनियामक मध्यस्थता की संभावना भी पैदा कर सकता है।

अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)

I.13 6 नवंबर 2024 को जारी केवाईसी मास्टर निर्देशों में किए गए संशोधनों में विनियमित संस्थाओं को ग्राहक की पहचान के सत्यापन और निरंतर ड्यू-डिलिजेंस के लिए ग्राहक से या केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री (सीकेवाईसीआर) से केवाईसी आईडेंटिफायर प्राप्त करने के लिए कहा गया है। यह विनियमित संस्थाओं द्वारा पुनः केवाईसी या केवाईसी विवरणों के आवधिक अद्यतनीकरण के उद्देश्य से सीकेवाईसीआर के उपयोग को भी अधिकृत करते हैं। संशोधन में विनियमित संस्थाओं के लिए सीकेवाईसीआर में ग्राहक अभिलेख अद्यतन करने के लिए सात दिनों की समय सीमा या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित समय सीमा भी निर्धारित की गई है। विनियमित संस्थाओं को सीकेवाईसीआर से अद्यतन जानकारी प्राप्त करने और अद्यतन अभिलेख को बनाए रखना भी अनिवार्य किया गया है।

I.14 इसके बावजूद, विनियमित संस्थाओं द्वारा कार्यान्वयन में कमी के परिणामस्वरूप कई खाते लेन-देन के लिए बंद हो रहे हैं जिससे ग्राहक अपने धन का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा अन्य संबंधित मुद्दे भी हैं, जैसे कि ग्राहकों की सहायता करने और उनके दस्तावेज प्राप्त करने में सक्रिय दृष्टिकोण का अभाव, ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों में कर्मचारियों की

⁵ अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (2024)। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टैबिलिटी रिपोर्ट, दी लास्ट माइल: वित्तीय कमज़ोरियाँ और जोखिम, अप्रैल।

अपर्याप्त तैनाती के परिणामस्वरूप शाखाओं में भीड़ होना या सेवा से इनकार करना, ग्राहकों के लिए सुविधाजनक शाखा में केवाईसी अद्यतनीकरण की सुविधा देने के बजाय उन्हें उनकी मूल शाखा में निर्देशित करना; और ग्राहकों द्वारा आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराए जाने के बाद भी सिस्टम में विवरण अपडेट करने में विफलता। सरकार से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्राप्त करने के लिए बनाए गए खातों को निष्क्रिय किए जाने या लेनदेन के लिए बंद किए जाने के भी कई उदाहरण हैं, जो विनियामक दिशानिर्देशों के विपरीत हैं। ऐसे मामलों में बैंकों के निदेशक मंडल को ऐसी नीतियां स्थापित करने और बैंकों को मानक संचालन प्रक्रियाओं को अपनाने के लिए निर्देश देना आवश्यक है जो न केवल विनियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप हों बल्कि प्रभावी कार्यान्वयन के लिए व्यावहारिक भी हों। बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि केवाईसी दिशानिर्देशों का पालन सटीकता और सहानुभूति, दोनों के साथ किया जाए⁶।

बड़ी संख्या में कर्मचारी पलायन (एट्रीशन)

1.15 चुनिंदा निजी क्षेत्र के बैंकों (पीवीबी) और लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) से कर्मचारी पलायन में वृद्धि हुई है। 2023-24 के दौरान पीवीबी कर्मचारियों की कुल संख्या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) से अधिक हो गई है, लेकिन पिछले तीन वर्षों में उनकी पलायन संख्या में तेजी से वृद्धि भी हुई है, जो औसत संख्या में लगभग 25 प्रतिशत है। बड़ी संख्या में कर्मचारी पलायन और कर्मचारी टर्नओवर दर के कारण ग्राहक सेवाओं में व्यवधान के अलावा बड़े परिचालन जोखिम उत्पन्न होते हैं, और साथ ही संस्थागत ज्ञान की हानि और भर्ती लागत में वृद्धि होती है। बैंकों के साथ समय-समय पर होने वाली चर्चाओं में रिज़र्व बैंक ने इस बात पर जोर दिया है कि कर्मचारी पलायन में कमी लाना केवल मानव संसाधन कार्य नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक अनिवार्यता भी है। दीर्घकालिक कर्मचारी जुड़ाव बनाने के लिए बैंकों को बेहतर ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया, व्यापक प्रशिक्षण और कैरियर विकास के अवसर प्रदान करने, मेंटरशिप

कार्यक्रम, प्रतिस्पर्धी लाभ और एक अनुकूल कार्यस्थल माहौल बनाने जैसी रणनीतियों को लागू करने की आवश्यकता है।

3. भुगतान और निपटान प्रणालियां

भुगतान समाहर्ता (पीए) (एग्रीगेटर)

1.16 पेमेंट विज़न 2025 के अंतर्गत सभी महत्वपूर्ण भुगतान मध्यस्थों को रिज़र्व बैंक के प्रत्यक्ष विनियमन के तहत लाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। इस विज़न के अनुसार ऑनलाइन पीए के लिए निर्धारित विनियमन दिशा-निर्देशों को पीए-पॉइंट ऑफ सेल पर भी लागू करने का प्रस्ताव है। यह कदम विनियमन में तालमेल लाएगा और मानकों का एकीकरण करेगा।

लाभार्थी का नाम देखने की सुविधा

1.17 यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) और इमीडिएट पेमेंट सर्विस (आईएमपीएस) जैसी भुगतान प्रणालियों में लेनदेन शुरू करने से पहले प्रेषक के लिए प्राप्तकर्ता का नाम सत्यापित करने की सुविधा है जिसे रियल टाइम ग्रांसेटलमेंट (आरटीजीएस) और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी) सिस्टम के साथ जोड़ा जा रहा है। यह सुविधा राशि के गलत नाम से जमा होने और धोखाधड़ी की संभावना को कम करने में मदद करेगी।

चेक ट्रंकेशन प्रणाली (सीटीएस)

1.18 चेक प्रसंस्करण के वर्तमान बैच प्रोसेसिंग दृष्टिकोण के अंतर्गत दो कार्य दिवसों तक का समाशोधन चक्र होता है। इस कार्य को बेहतर बनाने और प्रतिभागियों के लिए निपटान जोखिम को कम करने के लिए सीटीएस को 'ऑन रियलाइज़ेशन सेटलमेंट' में बदलने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। नए दृष्टिकोण के तहत चेक को कारोबार समय के दौरान निरंतर आधार पर स्कैन, प्रस्तुत और पास किया जाएगा और समाशोधन चक्र को कुछ घंटों तक कम किया जाएगा।

⁶ परिवर्तन को आगे बढ़ाने में बोर्ड की भूमिका, भारतीय रिज़र्व बैंक के उप-गवर्नर श्री स्वामीनाथन जे. द्वारा मुंबई में निजी क्षेत्र के बैंकों के निदेशकों के सम्मेलन में विशेष संबोधन - 18 नवंबर 2024।

भुगतान प्रणालियों का अंतरराष्ट्रीयकरण

1.19 रिज़र्व बैंक ने यूपीआई को अन्य देशों की जलद भुगतान प्रणालियों के साथ जोड़ने और वैश्विक स्तर पर रुपये कार्ड की स्वीकृति को बढ़ावा देने जैसी पहलों के माध्यम से वैश्विक स्तर पर भारतीय भुगतान लिखतों को अपनाए जाने के लिए प्रोत्साहन हेतु कई कदम उठाए हैं। सिंगापुर, यूएई, नेपाल, मॉरीशस, भूटान, फ्रांस, श्रीलंका और मालदीव में ऐसी व्यवस्थाएँ पहले ही चालू हो चुकी हैं। पेरू और नामीबिया में यूपीआई जैसी भुगतान प्रणाली को लागू करने का कार्य हो रहा है। रिज़र्व बैंक जून 2024 में परियोजना नेक्सस में शामिल हुआ है जो पांच देशों - मलेशिया, फिलिपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और भारत, जो इस प्लैटफॉर्म के मूल सदस्य होंगे, की घरेलू जलद भुगतान प्रणालियों को आपस में जोड़कर त्वरित सीमा पार खुदरा भुगतान को सक्षम करने के लिए एक बहुपक्षीय अंतरराष्ट्रीय पहल है।

4. उभरती हुई प्रौद्योगिकी को अपनाना

1.20 डिजिटल प्रौद्योगिकी वित्तीय समावेशन का विस्तार करने, दक्षता में सुधार करने और अखिल भारत में वास्तविक समय की सेवाओं को सक्षम करने में सहायक रही है। यूनिकाइड लेंडिंग इंटरफेस (यूएलआई) और ओपन क्रेडिट इनेबलमेंट नेटवर्क (ओसीईएन) जैसी प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने वाली पहलों से विशेष रूप से लघु व्यवसायों और व्यक्तियों के लिए ऋण पहुंच को नवीन रूप देने की उम्मीद है। रिज़र्व बैंक ग्राहकों के लिए निर्बाध और कुशल अनुभव प्रदान करने के लिए नवाचारों को प्रोत्साहित कर रहा है। तथापि, डिजिटल की ओर बदलाव से जोखिम भी उत्पन्न होते हैं जिन्हें पहचाना जाना चाहिए, उनका निपटान किया जाना चाहिए और एक स्थिर और सुरक्षित वित्तीय पारितंत्र बनाए रखने के लिए प्रबंधित किया जाना चाहिए।

1.21 रिज़र्व बैंक ने नीतिगत पहलों को प्रसारित करने, नई गतिविधियों, उत्पादों, सेवाओं और उपयोग के मामलों को समझने और बाजार आसूचना इकट्ठा करने के उद्देश्य से समय-

समय पर फिनटेक के साथ सुगठित और खुली बातचीत की है। एआई/एमएल, टोकनाइजेशन और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के आगमन के साथ वित्तीय क्षेत्र का परिदृश्य महत्वपूर्ण परिवर्तन से गुजर रहा है। हालांकि उनके अपनाने के लाभ कई हैं, किंतु एल्गोरिदम पूर्वाग्रह, निर्णयों की व्याख्या और डेटा गोपनीयता जैसे जोखिम भी अधिक हैं। प्रौद्योगिकी अपनाने की प्रक्रिया के आरंभ में ही होने वाले जोखिमों का समाधान करने के लिए रिज़र्व बैंक ने घोषणा की है कि वित्तीय क्षेत्र के लिए एक मजबूत, व्यापक और अनुकूलनीय एआई ढांचे की सिफारिश करने हेतु एआई के जिम्मेदार और नैतिकतायुक्त उपयोग के लिए एक ढांचा (एफआरईई-एआई) विकसित करने हेतु एक समिति गठित की जाएगी⁷।

डिजिटल ऋण

1.22 कई रिपोर्टें डिजिटल ऋण क्षेत्र में विवेकहीन सहभागियों की निरंतर उपस्थिति का संकेत देती हैं, जो गलत तरीके से विनियमित संस्थाओं के साथ उनके जुड़ाव का दावा करते हैं। डिजिटल लेंडिंग ऐप (डीएलए) के किसी विनियमित संस्था के साथ जुड़ाव के दावों की जांच करने में ग्राहकों की सहायता के लिए रिज़र्व बैंक विनियमित संस्थाओं द्वारा पेश किए गए डीएलए का एक सार्वजनिक संग्रह (रिपॉजिटरी) बनाने की प्रक्रिया में है। इस संग्रह में विनियमित संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत डेटा होगा, जिसमें रिज़र्व बैंक का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। जब भी कोई नया डीएलए जोड़ा जाएगा या कोई मौजूदा डीएलए हटाया जाएगा, तो उसे विनियमित संस्थाओं द्वारा अद्यतन किया जाना होगा।

यूनिकाइड लेंडिंग इंटरफेस (यूएलआई) का विस्तार

1.23 यूएलआई (जिसे पहले निर्बाध ऋण के लिए पब्लिक टेक प्लैटफॉर्म कहा जाता था) ऋणदान क्षेत्र में एक डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा है जो ऋणदाताओं को महत्वपूर्ण वित्तीय, गैर-वित्तीय और वैकल्पिक डेटा उपलब्ध कराएगा ताकि वे ऋण संबंधी सूचित निर्णय ले सकें। यूएलआई पायलट 17 अगस्त 2023 से शुरू हुआ। 6 दिसंबर 2024 तक

⁷ भारतीय रिज़र्व बैंक (2024)। विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य, 6 दिसंबर।

₹27,000 करोड़ के 6 लाख से अधिक ऋण, जिनमें बड़ी संख्या में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) ऋण (₹14,500 करोड़ के 1.60 लाख ऋण) शामिल हैं, को इस प्लैटफॉर्म से एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) का उपयोग करके वितरित किया गया है। इसमें विभिन्न बैंकों (पीएसबी, पीवीबी, एसएफबी, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक) और एनबीएफसी सहित 36 ऋणदाताओं को शामिल किया गया है। ये ऋणदाता 50 से अधिक डेटा सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रमाणीकरण और सत्यापन सेवाएं, छह राज्यों से भूमि अभिलेख डेटा, उपग्रह सेवा, लिप्यंतरण, संपत्ति खोज सेवाएं, डेयरी संबंधी सूचना और पहचान/दस्तावेज सत्यापन शामिल हैं। इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड, डिजिटल कैटल, एमएसएमई (अरक्षित), आवास, व्यक्तिगत, ट्रैक्टर, सूक्ष्म व्यवसाय, वाहन, डिजिटल स्वर्ण, ई-मुद्रा, पेंशन और डेयरी रखरखाव ऋण सहित 12 ऋण प्रकार शुरू किए गए हैं। अनुभवों और हितधारकों से प्राप्त सकारात्मक प्रतिक्रिया के आधार पर अधिक ऋण प्रकारों, डेटा प्रदाताओं और ऋणदाताओं को शामिल करने के लिए इस प्लैटफॉर्म के दायरे और व्याप्ति का विस्तार किया जा रहा है।

केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी)

1.24 सीबीडीसी-रिटेल (सीबीडीसी-आर) पायलट वर्तमान में पायलट बैंकों द्वारा प्रदान किए गए डिजिटल रुपया वॉलेट का उपयोग करके व्यक्ति-से-व्यक्ति (पी 2 पी) और व्यक्ति-से-व्यापारी (पी 2 एम) लेनदेन को सक्षम बनाता है। पायलट परियोजना के तहत सीबीडीसी-आर में प्रोग्रामेबिलिटी और ऑफलाइन कार्यक्षमता का भी परीक्षण किया जा रहा है। प्रोग्रामेबिलिटी से सरकारी एजेंसियां और उपयोगकर्ता यह सुनिश्चित कर पाएंगे कि भुगतान निर्धारित लाभों के लिए किए गए हैं। इसी तरह, संस्थाएँ अपने कर्मचारियों के लिए व्यावसायिक यात्रा जैसे निर्दिष्ट व्यय को प्रोग्राम करने में सक्षम होंगी। वैधता अवधि या भौगोलिक क्षेत्र जैसी सुविधाएँ, जिनके भीतर सीबीडीसी-आर का उपयोग किया जा सकता है, उन्हें भी प्रोग्राम किया जा

सकता है। खराब या सीमित इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में लेनदेन करने के लिए सीबीडीसी-आर (प्रोक्सिमिटी और नॉन-प्रोक्सिमिटी आधारित) में ऑफलाइन कार्यक्षमता को सक्षम करने के समाधान का भी एक सीमित उपयोगकर्ता समूह में परीक्षण किया जा रहा है। इन सुविधाओं को धीरे-धीरे पायलटों के माध्यम से बढ़ाया जाएगा।

5. वित्तीय समावेशन

1.25 भारत ने बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं तक पहुँच बढ़ाने में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। यहाँ तक कि देश के सर्वाधिक दूरदराज के क्षेत्रों तक भी पहुँच बनाई है। सेवाओं के उपयोग और गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रयासों की परिकल्पना की गई है, जिसमें लैंगिक अंतर को कम करना भी शामिल है⁸।

राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन रणनीति 2.0

1.26 वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय रणनीति (एनएसएफआई) का अगला संस्करण 2025-30 की अवधि के लिए विकसित किया जा रहा है जो व्यापक हितधारकों के परामर्श और वर्तमान रणनीति के कार्यान्वयन के दौरान प्राप्त अनुभव पर आधारित है। यह उभरती चुनौतियों से निपटने के साथ-साथ वित्तीय समावेशन को और गहरा करने पर ध्यान केंद्रित करेगा।

लीड बैंक योजना (एलबीएस) की समीक्षा

1.27 एलबीएस की प्रभावशीलता को बढ़ाने और आबादी के सभी वर्गों के लिए वित्तीय सेवाओं की बेहतर पहुँच, उपयोग और गुणवत्ता युक्त वित्तीय समावेशन को मजबूत करने के लिए इस योजना की व्यापक समीक्षा चल रही है।

6. उपभोक्ता संरक्षण

1.28 ग्राहकों के साथ उचित व्यवहार और प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र उपभोक्ता संरक्षण के सबसे महत्वपूर्ण साधन हैं। इस संबंध में, ग्रामीण और अर्ध-शहरी आबादी से आने वाली

⁸ वंचितों तक पहुँचना - बैंकिंग सेवाओं की पहुँच दूरदराज तक सुनिश्चित करना - श्री स्वामीनाथन जे. द्वारा हुबली में अग्रणी जिला प्रबंधकों और जिला विकास प्रबंधकों के सम्मेलन में दिया गया मुख्य संबोधन, 20 सितंबर, 2024।

शिकायतों की कम संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा एक सर्वेक्षण किया जा रहा है। रिजर्व बैंक बैंकों को अपने आंतरिक शिकायत निवारण ढांचे को मजबूत करने के लिए भी प्रोत्साहित कर रहा है।

1.29 ऋणों के मूल्य निर्धारण और ग्राहकों पर लगाए जाने वाले अन्य शुल्कों में विनियमित संस्थाओं द्वारा अधिक पारदर्शिता और प्रकटीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, 1 अक्टूबर 2024 से विनियमित संस्थाओं के लिए सभी नए खुदरा और एमएसएमई सावधि ऋणों के संबंध में उधारकर्ताओं को एक मुख्य तथ्य विवरण (केएफएस) प्रदान करना अनिवार्य कर दिया गया है, जिसमें ऋण की समग्र लागत सहित ऋण समझौते के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी का सरल और आसानी से समझने योग्य प्रारूप में होना शामिल है।

डिजिटल धोखाधड़ी

1.30 हालांकि डिजिटल धोखाधड़ी के कई मामले ग्राहकों पर सोशल इंजीनियरिंग हमलों के परिणामस्वरूप होते हैं, वहीं इस तरह की धोखाधड़ी को अंजाम देने के लिए छद्म बैंक खातों के इस्तेमाल में भी तेजी से वृद्धि हुई है। इससे बैंकों को न केवल गंभीर वित्तीय और परिचालन जोखिम, बल्कि प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम भी होता है। इसलिए, बैंकों को विवेकहीन (अनस्कूपलस) गतिविधियों पर नजर रखने के लिए अपने ग्राहक ऑनबोर्डिंग और लेनदेन निगरानी प्रणालियों को मजबूत करने की जरूरत है। इसके लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के साथ प्रभावी समन्वय की भी आवश्यकता है ताकि प्रणालीगत स्तर पर होने वाली चूकों का पता लगाया जा सके और उन पर समय रहते अंकुश लगाया जा सके। रिजर्व बैंक बैंकों और एलईए के साथ मिलकर लेन-देन निगरानी प्रणालियों को मजबूत करने और छद्म खातों पर नियंत्रण और डिजिटल धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए काम कर रहा है⁹। इस दिशा में एक अन्य पहल एआई/एमएल

आधारित मॉडल है जिसका नाम है MuleHunter.AI™ जिस पर रिजर्व बैंक नवोन्मेष केंद्र (आरबीआईएच) द्वारा प्रयोग किया जा रहा है¹⁰।

डार्क पैटर्न

1.31 डार्क पैटर्न, जो उपयोगकर्ताओं को वांछित व्यवहार में फंसाने के लिए एक डिज़ाइन इंटरफ़ेस और रणनीति है, जो अप-विक्रय (मिस-सेलिंग) के एक नए रूप के रूप में उभरे हैं। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने 30 नवंबर 2023 को डार्क पैटर्न की रोकथाम और विनियमन पर दिशा-निर्देश अधिसूचित किए हैं, जिसका उद्देश्य इस प्रकार की गतिविधियों की पहचान करना और उन्हें विनियमित करना है। रिजर्व बैंक भी अपने आरई के बीच ऐसी गतिविधियों के प्रचलन पर ध्यान दे रहा है और उचित नीतिगत कार्रवाइयों पर विचार कर रहा है।

7. जलवायु परिवर्तन

1.32 जलवायु परिवर्तन के जोखिमों से वित्तीय संस्थाओं की लाभप्रदता, समष्टि आर्थिक विकास की संभावनाओं और मुद्रास्फीति की गतिशीलता पर असर पड़ने की संभावना है जिससे वित्तीय स्थिरता और मूल्य स्थिरता पर उसका असर पड़ेगा। विनियमित संस्थाएं इन चिंताओं का आकलन करें इसके लिए जोखिम प्रबंधन दिशा-निर्देशों, प्रकटीकरण आवश्यकताओं, आवधिक दबाव परीक्षण और उचित सत्यापन और आश्वासन कार्यों को निर्धारित करने के साथ-साथ विनियामक और पर्यवेक्षी ढांचे को मजबूत करने की आवश्यकता है।

1.33 शुद्ध-शून्य संक्रमण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता के अनुसार रिजर्व बैंक ने प्राथमिकता क्षेत्र ऋणों के तहत नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को वित्तपोषित करने, हरित जमा रूपरेखा प्रस्तुत करने, सॉवरेन ग्रीन बॉण्ड (एसजीआरबी) जारी करने, भारत में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र

⁹ वंचितों तक पहुंचना - बैंकिंग सेवाओं की अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना - श्री स्वामीनाथन जे, उप-गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हुबली में अग्रणी जिला प्रबंधकों और जिला विकास प्रबंधकों के सम्मेलन में मुख्य संबोधन - 20 सितंबर 2024।

¹⁰ भारतीय रिजर्व बैंक (2024)। विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य, 6 दिसंबर।

(आईएफएससी) में पात्र विदेशी निवेशकों द्वारा एसजीआरबी में निवेश और व्यापार की अनुमति देने, तथा सार्वजनिक परामर्श के लिए जलवायु-संबंधी वित्तीय जोखिमों के लिए प्रकटीकरण रूपरेखा का मसौदा जारी करने जैसे सक्रिय कदम उठाए हैं।

1.34 रिज़र्व बैंक नवीकरणीय ऊर्जा के लिए जलवायु संबंधी जोखिमों के परिदृश्य विश्लेषण और दबाव परीक्षण पर मार्गदर्शन टिप्पण को अंतिम रूप देने और उसे जारी करने की प्रक्रिया में भी है, जिसमें मॉडलिंग तकनीक, परिदृश्य स्थिति पर विचार और दबाव परीक्षण अभ्यास करने के लिए कार्यप्रणाली शामिल है। आरबीआई@100 के लिए रिज़र्व बैंक के आकांक्षात्मक लक्ष्यों में जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने के लिए एक मजबूत विनियामक और पर्यवेक्षी ढांचा स्थापित करना, जलवायु जोखिमों के विरुद्ध भुगतान प्रणालियों की सुदृढ़ता बढ़ाना और एक व्यापक वर्गीकरण (टैक्सोनॉमी) को अंतिम रूप देने के लिए सरकार के साथ सहयोग करना शामिल है¹¹।

रिज़र्व बैंक जलवायु जोखिम सूचना प्रणाली (आरबी-सीआरआईएस)

1.35 विनियमित संस्थाओं द्वारा जलवायु जोखिम का आकलन करने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ स्थानीय जलवायु परिदृश्यों, जलवायु पूर्वानुमानों और उत्सर्जन से संबंधित उच्च गुणवत्ता वाले डेटा की आवश्यकता होगी। सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जलवायु संबंधी डेटा में कई प्रकार की कमियां हैं, जैसे कि स्रोत खंडित और विविध होते हैं,

प्रारूप अलग-अलग होते हैं, आवृत्तियाँ और इकाइयाँ भिन्न होती हैं। इन अंतरालों को पाटने के लिए रिज़र्व बैंक एक डेटा भंडार (रिपॉजिटरी) बनाने की योजना बना रहा है जिसका नाम होगा - रिज़र्व बैंक - जलवायु जोखिम सूचना प्रणाली (आरबी-सीआरआईएस)¹²। भंडार का पहला भाग एक वेब-आधारित निर्देशिका होगी, जिसमें मौसम संबंधी और भू-स्थानिक डेटा सहित विभिन्न डेटा स्रोतों को सूचीबद्ध किया जाएगा, जो आरबीआई की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होंगे। दूसरे भाग में मानकीकृत प्रारूपों में संसाधित डेटा-संचय शामिल होंगे। इस डेटा पोर्टल तक पहुंच चरणबद्ध तरीके से केवल विनियमित संस्थाओं को ही उपलब्ध कराई जाएगी।

8. समग्र मूल्यांकन

1.36 बैंक और एनबीएफसी भारत के वित्तीय क्षेत्र की रीढ़ हैं जो अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करके उसकी विकास आकांक्षाओं को आधार प्रदान करते हैं। रिज़र्व बैंक भुगतान और निपटान को 'डिजिटल पुश' देने के लिए बुनियादी ढाँचे के विकास को बढ़ावा देना और प्रोत्साहित करना जारी रखेगा। बैंक अपने ग्राहक-केंद्रित उपायों को सुदृढ़ करते हुए और वित्तीय समावेशन को बढ़ाते हुए उभरती हुई प्रौद्योगिकी को अपनाने में मददगार की भूमिका निभाने के लिए भी प्रतिबद्ध है। वित्तीय स्थिरता बनाए रखना सर्वोपरि लक्ष्य बना रहेगा और वह रिज़र्व बैंक की विनियामक और पर्यवेक्षी नीतियों को दिशा देता रहेगा।

¹¹ भारतीय रिज़र्व बैंक (2024)। गवर्नर का वक्तव्य, 7 जून।

¹² भारतीय रिज़र्व बैंक (2024)। विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य, 9 अक्टूबर।

वैश्विक बैंकिंग क्षेत्र ने 2024 के दौरान आस्ति गुणवत्ता और पूंजी एवं प्रावधान बफर्स में सुधार प्रदर्शित किया। ऋण वृद्धि और लाभप्रदता में कमी आई जो सख्त वित्तीय स्थितियों के प्रभाव को दर्शाती है। वैश्विक विनियामक और पर्यवेक्षी कार्रवाईयों का रुख प्रतिभूतीकरण, गैर-बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र की समुत्थानशीलता, जलवायु और प्रकृति से उत्पन्न जोखिमों तथा क्रिप्टो-आस्तियों के विनियमन से संबंधित मामलों के समाधान की ओर था। साथ ही, नीति निर्माताओं को बढ़ते भू-राजनीतिक, तेजी से उभरती नई प्रौद्योगिकियों और बढ़ते जलवायु संबंधी जोखिमों के बीच वित्तीय प्रणाली में जोखिमों के निर्माण के प्रति सतर्क रहना होगा।

1. परिचय

II.1 2024 में, वैश्विक अर्थव्यवस्था महामारी के बाद आपूर्ति-शृंखला में व्यवधानों, और कई दशकों की उच्च मुद्रास्फीति से उबर गई¹। वैश्विक विकास में स्थैर्य आया और मुद्रास्फीति प्रमुख क्षेत्राधिकारों में लक्ष्यों की दूरी कम हो गई। हालाँकि, भू-राजनीतिक तनाव, निरंतर भू-आर्थिक विखंडन, उच्च सार्वजनिक से सरकारी ऋण, व्यापक आस्ति मूल्यांकन, तकनीकी परिवर्तन से जुड़े साइबर खतरे और जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दे परिदृश्य को प्रभावित करते हैं।

II.2 वैश्विक बैंकिंग क्षेत्र ने इन उथल-पुथल से सफलतापूर्वक निपट लिया। मार्च 2023 में कुछ क्षेत्राधिकारों में बैंकों के सामने आए तनावों को त्वरित नीतिगत हस्तक्षेपों द्वारा कम किया गया। यद्यपि प्रणालीगत प्रसार-प्रभाव से बचा गया, इस प्रकरण ने बैंकों के तुलन पत्र में देयताओं के पक्ष से उत्पन्न होने वाली वित्तीय स्थिरता चुनौतियों को चिह्नित किया। फिर भी, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (ईई) और उभरती बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीई) में आस्ति गुणवत्ता, प्रावधान और पूंजी बफर संतोषजनक रहे।

II.3 इन गतिविधियों की पृष्ठभूमि में, इस अध्याय में वैश्विक बैंकिंग क्षेत्र के विकास को शामिल किया है। खंड 2 में वर्तमान वैश्विक समष्टि आर्थिक स्थितियों की समीक्षा की है। खंड 3 में वैश्विक बैंकिंग नीति विकासक्रम पर चर्चा की गई है। खंड 4 में वैश्विक बैंकिंग क्षेत्र के कार्यनिष्पादन की जांच की है, जबकि खंड 5 टियर 1 पूंजी स्थिति के आधार पर, दुनिया के शीर्ष 100 बैंकों के कार्यनिष्पादन और सुदृढ़ता पर केंद्रित है। खंड 6 में समग्र मूल्यांकन के साथ निष्कर्ष दिए हैं।

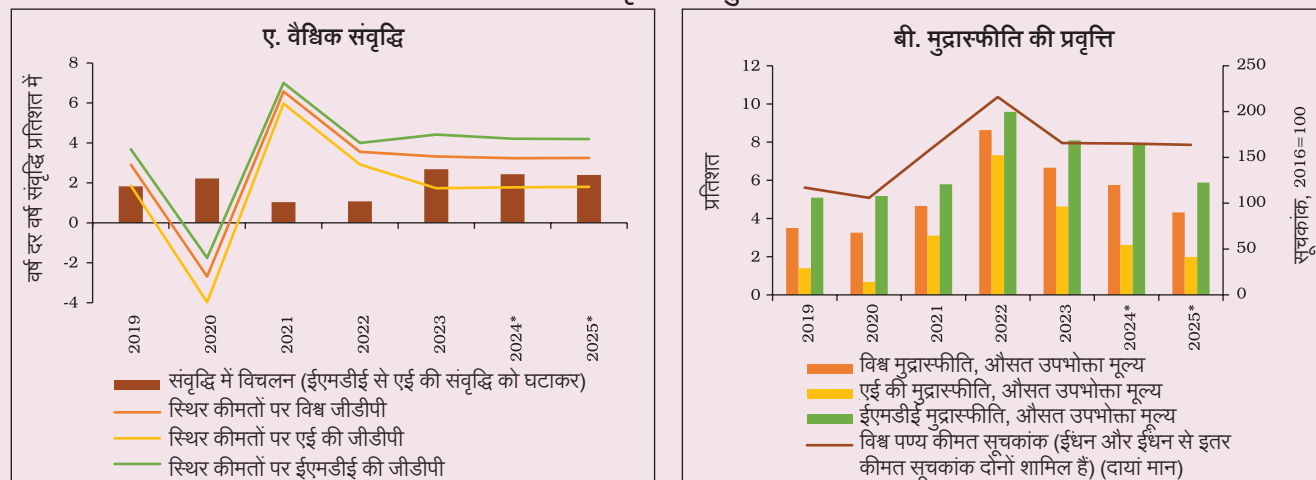
2. वैश्विक समष्टि-आर्थिक स्थितियां

II.4 वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 2024 और 2025 दोनों में 3.2 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है² (चार्ट II.1ए)। आक्रामक मौद्रिक सख्ती और खाद्य एवं ऊर्जा की कीमतों में सुधार के कारण सभी भौगोलिक क्षेत्रों में मुद्रास्फीति धीरे-धीरे कई दशकों के उच्चतम स्तर से घट रही है। यह 2023 में 6.7 प्रतिशत से घटकर 2024 में 5.8 प्रतिशत और 2025 में 4.3 प्रतिशत होने का अनुमान है (चार्ट II.1बी)। हालाँकि, सेवा मुद्रास्फीति सभी ईई में उच्च स्तर पर बनी हुई है और मुद्रास्फीति प्रक्षेपवक्र के लिए ऊर्ध्वगामी जोखिम पैदा करती है।

¹ वैश्विक क्रियाविधियों का पालन करते हुए, इस पूरे अध्याय में, वर्ष कैलेंडर वर्ष अर्थात् जनवरी से दिसंबर तक संबंधित है।

² विश्व आर्थिक परिदृश्य (डब्ल्यूईओ) (अक्टूबर 2024), अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ), अक्टूबर।

चार्ट II.1 संवृद्धि और मुद्रास्फीति



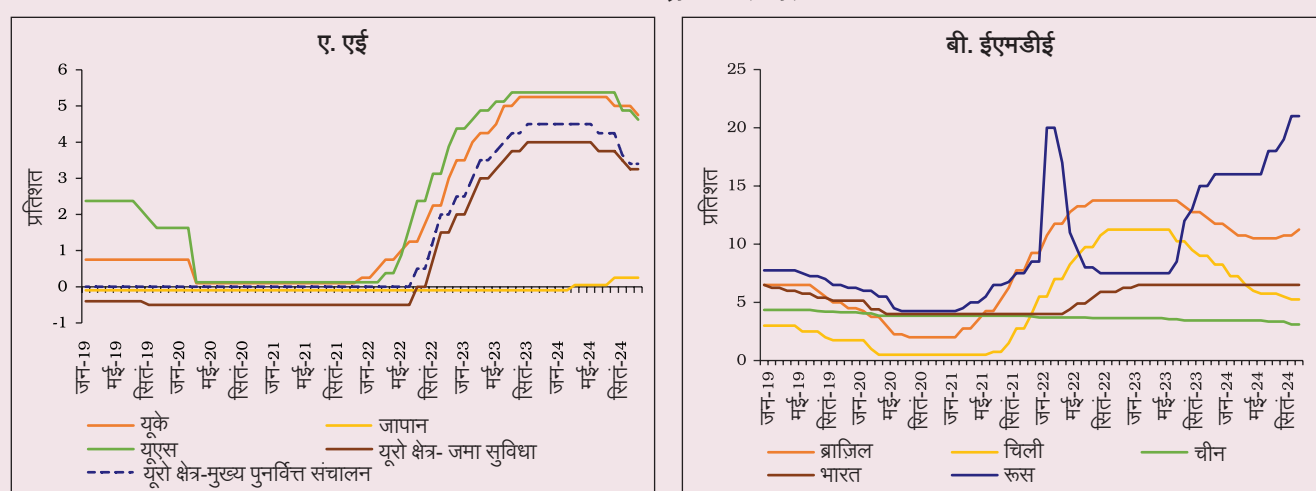
टिप्पणी: *: पूर्वानुमान।

स्रोत: विश्व आर्थिक परिदृश्य, आईएमएफ।

II.5 प्रमुख केंद्रीय बैंकों ने नीतिगत दरों को कम करना शुरू कर दिया है क्योंकि उन्हें विश्वास हो गया है कि मुद्रास्फीति लक्ष्यों की ओर बढ़ रही है। अमेरिकी फेडरल रिज़र्व ने 18 सितंबर, 2024 को संघीय निधि लक्ष्य दर 50 आधार अंक (बीपीएस) कम कर दिया जो मार्च 2020 के बाद यह पहली दर में कटौती थी और नवंबर तथा दिसंबर 2024 में 25-25 बीपीएस कम किया। यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ईसीबी) ने सितंबर 2024 से अपने मौद्रिक नीति परिचालन फ्रेमवर्क में परिवर्तन किया है। जमा सुविधा दर (डीएफआर) अब वास्तविक नीति

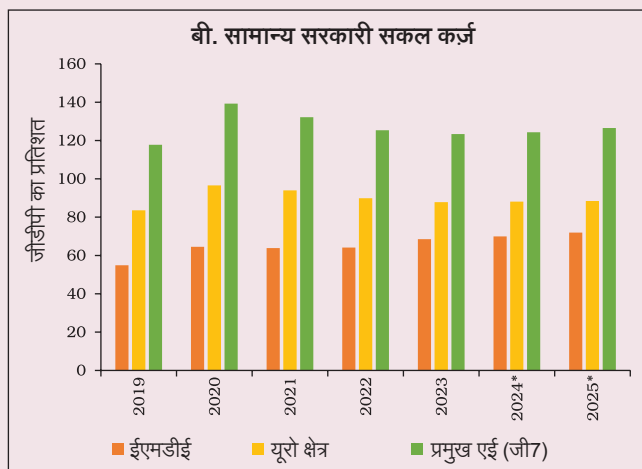
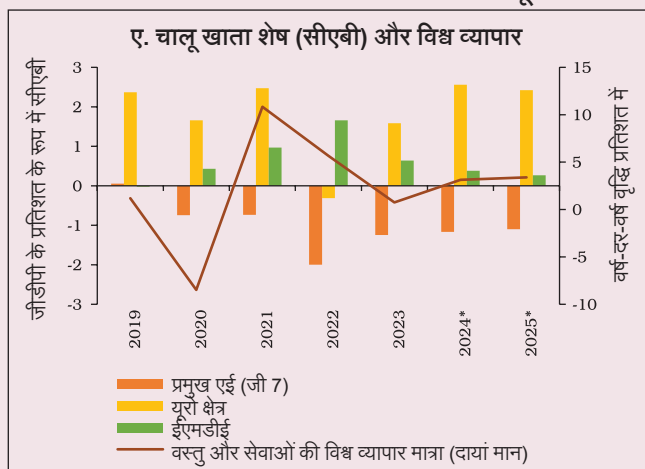
दर है जिसके माध्यम से इसीबी मुख्य पुनर्वित्त परिचालन (एमआरओ) दर जो पहले की नीतिगत दर थी, उसकी तुलना में अपनी मौद्रिक नीति रुख को संचालित करेगा। 2024 के दौरान इसीबी ने नीति दर में चार बार कटौती की। बैंक ऑफ इंग्लैंड (बीओई) ने अगस्त 2024 में 25 बीपीएस की कटौती के साथ अपना सहजता चक्र शुरू किया, इसके बाद नवंबर 2024 में और 25 बीपीएस की कटौती की गई। बैंक ऑफ जापान आठ वर्षों के बाद अपनी नकारात्मक ब्याज दर नीति से बाहर निकल आया और उसने प्रतिफल वक्र नियंत्रण को छोड़

चार्ट II.2 मौद्रिक नीति दरें



स्रोत: अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस) और ब्लूमबर्ग।

चार्ट II.3 चालू खाता और सामान्य सरकारी सकल कर्ज



टिप्पणी: *: पूर्वानुमान।

स्रोत: विश्व आर्थिक परिदृश्य, आईएमएफ।

दिया (चार्ट II.2ए)। ईएमडीई केंद्रीय बैंकों की मौद्रिक नीति प्रतिक्रियाएं अधिक विविध प्रकार की थीं। चिली ने 2023 में दरों में कटौती शुरू की और 2024 तक अपने सहजता चक्र को जारी रखा। इंडोनेशिया और दक्षिण अफ्रीका ने सितंबर 2024 में अपने सहजता चक्र को शुरू किया। दूसरी ओर, ब्राजील ने मुद्रास्फीति के लक्ष्य से ऊपर जाने की प्रतिक्रिया में सितंबर 2024 से दिसंबर 2024 के दौरान नीतिगत दर में 175 बीपीएस की संचयी वृद्धि के साथ अपने सहजता चक्र को उलट दिया। चीन ने आर्थिक वृद्धि को समर्थन देने और संपत्ति क्षेत्र के जोखिमों को दूर करने के लिए सितंबर 2024 में मौद्रिक और अन्य प्रोत्साहन उपायों की घोषणा की (चार्ट II.2बी)।

II.6 महामारी के वर्षों (2020-2022) के दौरान काफी हद तक बढ़ने के बाद आई का चालू खाता घाटा (सीएडी) कम हो रहा है, हालांकि यह महामारी से पहले के वर्षों की तुलना में अधिक बना हुआ है। वस्तुओं और सेवाओं में विश्व व्यापार की मात्रा में वृद्धि 2023 में 0.8 प्रतिशत से बढ़कर 2024 में 3.1 प्रतिशत हो गई, जो मुद्रास्फीति में कमी और एशिया से विशेष रूप से प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निर्यात में वृद्धि से प्रेरित है (चार्ट II.3ए)। सरकारी घाटा और कर्ज, जो 2020 में बड़े पैमाने पर महामारी से संबंधित समर्थन के कारण दबाव में आ गए थे, विशेष रूप से

आई के लिए उन्नत बने रहे (चार्ट II.3बी)। कड़ी वित्तीय स्थितियों के माहौल में उच्च सार्वजनिक कर्ज स्तर ने भी ईएमडीई के लिए चुनौतियां पेश की।

3. वैश्विक बैंकिंग नीतिगत घटनाक्रम

II.7 मार्च 2023 में सिलिकॉन वैली बैंक और कुछ अमेरिकी क्षेत्रीय बैंकों की विफलता और जून 2023 में यूबीएस के साथ विलयन से पहले क्रेडिट सुइस के पतन से प्रणालीगत प्रसार-प्रभाव को तेज और बड़े विनियामक कार्रवाईयों और चलनिधि सहायता के माध्यम से टाला गया। हालांकि, इन प्रकरणों ने बैंकिंग क्षेत्र की समुत्थानशीलता संबंधी चिंताएँ बढ़ा दीं और अभिशासन, जोखिम प्रबंधन प्रथाओं और विनियामक ढांचे की कमजोरियों को उजागर किया। हाल के वर्षों में, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं (एनबीएफआई) की बढ़ती भूमिका ने वित्तीय प्रणाली के लिए जटिलता की एक अतिरिक्त परत जोड़ दी है। परस्पर संबद्धता से उत्पन्न होने वाले प्रणालीगत जोखिमों को कम करने के लिए विनियामक और केंद्रीय बैंक अपने पर्यवेक्षी ढांचे को मजबूत कर रहे हैं। डिजिटल बैंकिंग और फिनटेक समाधानों को अपनाने में हुई वृद्धि पारंपरिक बैंकिंग मॉडल में सुधार और नई विनियामक चुनौतियों का समाधान करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है³।

³ <https://www.bis.org/publ/arpdf/ar2024e.pdf>

3.1 समुत्थानशील वित्तीय संस्थाओं का निर्माण⁴

11.8 मार्च 2023 की बैंकिंग उथल-पुथल ने विवेकपूर्ण विनियमन और प्रभावी पर्यवेक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डाला और बेसल III मानकों के सभी पहलुओं को लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति (बीसीबीएस) के सदस्य क्षेत्राधिकारों ने 1 जनवरी, 2023 से प्रभावी अंतिम बेसल III तत्वों को लागू करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। सितंबर 2024 तक, वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) के एक-चौथाई सदस्य क्षेत्राधिकारों ने अंतिम बेसल III तत्वों को पूरी तरह से लागू कर दिया था, जबकि अधिकांश सदस्य क्षेत्राधिकारों ने अब अधिकांश तत्वों के लिए अंतिम नियम प्रकाशित किए थे⁵। सितंबर 2023 के अंत से, 27 सदस्य क्षेत्राधिकारों में से लगभग आधे ने संशोधित ऋण जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालन जोखिम मानकों के साथ-साथ आउटपुट फ्लोर के लिए अंतिम नियम प्रकाशित किए हैं। इसके अलावा, तीन सदस्य क्षेत्राधिकारों ने संशोधित लीवरेज अनुपात एक्सपोजर परिभाषा के लिए अंतिम नियम जारी किए हैं। परिणामस्वरूप, दो-तिहाई से अधिक सदस्य क्षेत्राधिकारों ने अब बेसल III के सभी अंतिम तत्वों के लिए अंतिम नियम प्रकाशित किए हैं और ये मानक एक तिहाई से अधिक सदस्य क्षेत्राधिकारों में लागू हैं।

11.9 अन्य मानकों पर भी आगे प्रगति हुई है जिनकी कार्यान्वयन तिथियां 1 जनवरी, 2023 से पहले थीं। सितंबर 2023 के अंत से, आठ क्षेत्राधिकारों ने बैंकिंग बही मानक में ब्याज दर जोखिम को लागू करने का कार्य पूरा किया है, सात ने विभिन्न प्रकटीकरण तत्वों को लागू किया है, और दो में से प्रत्येक ने गैर-केंद्रीय समाशोधित व्युत्पन्नी (एनसीसीडी), केंद्रीय प्रतिपक्षकारों (सीसीपी) के लिए एक्सपोजर के लिए पूंजी आवश्यकताओं और बड़े एक्सपोजर फ्रेमवर्क (एलईएफ)

के लिए मार्जिन आवश्यकताओं को लागू किया है। निधियों में इक्विटी निवेश के लिए पूंजी आवश्यकताओं, प्रतिभूतीकरण फ्रेमवर्क और इंटर-डे चलनिधि प्रबंधन के लिए निगरानी साधनों के लिए, एक और सदस्य क्षेत्राधिकार ने अंतिम नियम प्रकाशित किए हैं।

3.2 इतने-बड़े-कि-ना-डूबे (टू-बिग-टू-फेल) सुधार⁶

11.10 बैंक समाधान पर एफएसबी का काम अब तक मुख्य रूप से प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण वैश्विक बैंकों (जी-एसआईबी) पर केंद्रित रहा है और इस संबंध में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। हालाँकि, 2023 की बैंकिंग उथल-पुथल ने गैर-प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों के लिए भी समाधान योजना और हानि-अवशोषण क्षमता के महत्व पर प्रकाश डाला। नवंबर 2024 में, एफएसबी ने इस बात पर जोर दिया कि समाधान योजना और निष्पादन पर मौजूदा मार्गदर्शन उन बैंकों के लिए भी प्रासंगिक हो सकता है जो विफल होने पर प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण या विकट हो सकते हैं, क्योंकि ऐसी विफलता के वित्तीय प्रणाली या व्यापक अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं।⁷ एफएसबी ने समाधान उपायों की उपयोगिता बढ़ाने, समाधान में चलनिधि प्रबंधन करने और प्रणालीगत व्यवधान और करदाताओं को नुकसान के बिना समस्या के निपटान के विकल्प सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्राधिकारों की सिफारिश की।

11.11 बीसीबीएस ने पाया है कि जी-एसआईबी मूल्यांकन ढांचा सहभागी बैंकों द्वारा रिपोर्ट किए गए संकेतकों के वर्ष के अंत के मूल्यों से प्रभावित है। इन समस्याओं को दूर करने के लिए, बीसीबीएस ने जी-एसआईबी मूल्यांकन अभ्यास में सहभागी बैंकों को वर्ष के अंत के मूल्यों के बजाय रिपोर्टिंग वर्ष के मूल्यों के औसत के आधार पर स्टॉक जी-एसआईबी संकेतकों की रिपोर्ट करने और प्रकटीकरण करने वाले संशोधनों का प्रस्ताव दिया है⁸।

⁴ बीआईएस (2024) - समयबद्धता पर आरसीएपी: बेसल III कार्यान्वयन डैशबोर्ड।

⁵ यदि अंतिम नियम प्रकाशित हो जाता है तो क्षेत्राधिकार को मानक अपनाने वाला माना जाता है, तथा यदि अंतिम नियम प्रकाशित हो जाता है और बैंकों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है तो क्षेत्राधिकार को मानक लागू करने वाला माना जाता है।

⁶ एफएसबी (2024) वार्षिक रिपोर्ट- वैश्विक वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देना

⁷ एफएसबी (2024) - विफलता में प्रणालीगत बैंकों के लिए समाधान योजना और हानि-अवशोषण क्षमता का महत्व: सार्वजनिक वक्तव्य।

⁸ बीसीबीएस (2024) - वैश्विक प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंक - संशोधित मूल्यांकन ढांचा

3.3 व्युत्पन्नी बाजारों को सुरक्षित बनाना

11.12 पिछले कुछ वर्षों में प्रमुख क्षेत्राधिकारों में, जी20 ओवर-द-काउंटर (ओटीसी) व्युत्पन्नी सुधारों के कार्यान्वयन में अच्छी प्रगति हुई है। अधिकांश वैश्विक ओटीसी व्युत्पन्नी गतिविधि वाले क्षेत्राधिकारों ने व्यापक व्यापार रिपोर्टिंग आवश्यकताओं, केंद्रीय समाशोधन और प्लेटफॉर्म ट्रेडिंग फ्रेमवर्क, और एनसीसीडी के लिए पूंजी और मार्जिन आवश्यकताओं को लागू किया है। वैश्विक ओटीसी व्युत्पन्नी बाजार गतिविधि के कम अनुपात के लिए जिम्मेदार क्षेत्राधिकारों से इन सुधारों को लागू करना बाकी है।

11.13 पिछले पांच वर्षों में, व्यापक व्यापार रिपोर्टिंग आवश्यकताओं वाले एफएसबी सदस्य क्षेत्राधिकारों की संख्या अपरिवर्तित बनी हुई है, केवल एक अतिरिक्त क्षेत्राधिकार केंद्रीय समाशोधन या प्लेटफॉर्म ट्रेडिंग फ्रेमवर्क को अपना रहा है⁹।

3.4 प्रतिभूतीकरण

11.14 2008 में वैश्विक वित्तीय संकट (जीएफसी) के बाद से जोखिम संवेदनशीलता में सुधार करने और क्लिफ प्रभावों को कम करके एवं प्रतिभूतीकरण से जुड़े प्रोत्साहनों को संरेखित करते हुए बैंकों के प्रतिभूतीकरण जोखिम के लिए पारदर्शिता में सुधार, हितों के टकराव का समाधान, विनियामक पूंजी उपाय को मजबूत करने हेतु कई विनियामक सुधार पेश किए गए हैं। जुलाई 2024 में, एफएसबी ने प्रतिभूतीकरण पर जी20 वित्तीय विनियामक सुधारों के प्रभावों का मूल्यांकन करते हुए एक परामर्शी रिपोर्ट प्रकाशित की।¹⁰ निष्कर्षों से पता चलता है कि इन सुधारों ने अर्थव्यवस्था के वित्तपोषण पर महत्वपूर्ण नकारात्मक दुष्प्रभावों के पुरेता सबूत के बिना प्रतिभूतीकरण बाजार की समुत्थानशीलता में योगदान दिया है।

3.5 गैर-बैंक वित्तीय मध्यस्थता

11.15 2022 के अंत में वैश्विक वित्तीय आस्तियों में एनबीएफआई की हिस्सेदारी लगभग आधी थी। जीएफसी के बाद, मार्च 2020 में महामारी से संबंधित बाजार में हुई उथल-पुथल, 2021 के आर्कगोस कैपिटल प्रकरण और हाल ही में चीनी संपत्ति क्षेत्र संकट के दौरान उनकी बढ़ती व्याप्ति और पारस्परिक संबंध के बारे में चिंताएं सामने आईं। अप्रैल 2024 में, बीसीबीएस ने 1999 के दिशानिर्देशों की जगह, प्रतिपक्ष ऋण जोखिम (सीसीआर) प्रबंधन के लिए दिशानिर्देशों के साथ एक परामर्शी दस्तावेज जारी किया। इनमें सीसीआर प्रबंधन में लंबे समय से चली आ रही विकट औद्योगिक कमजोरियों को हल करने के लिए महत्वपूर्ण क्रियाविधियां शामिल हैं।

11.16 साथ ही, इस क्षेत्र की सुदृढ़ता बढ़ाने और इसकी गतिविधियों की निगरानी करने के लिए, एफएसबी और मानक निर्धारण निकायों (एसएसबी) ने मार्जिन और संपार्श्विक कॉल के लिए गैर-बैंक बाजार सहभागियों की मार्जिनिंग प्रथाओं और चलनिधि प्रबंधन को बढ़ाने के लिए 2024 की शुरुआत में नीतियों का प्रस्ताव रखा।¹¹

3.6 मार्च 2023 की बैंकिंग उथल-पुथल

11.17 अक्टूबर 2024 में, एफएसबी ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें ऋण चुकौती क्षमता और चलनिधि जोखिमों के संयोजन के लिए सबसे कमजोर तीन प्रकार की संस्थाओं की पहचान की: कमजोर बैंक, जीवन बीमाकर्ता और गैर-बैंक रियल एस्टेट निवेशक।¹² रिपोर्ट में इस बात पर भी प्रकाश डाला गया है कि तकनीकी प्रगति ने आसान और तेज़ जमा अंतरण की सुविधा प्रदान की है, और सोशल मीडिया ने हाल के कुछ बैंक परिचालनों को प्रभावित किया है।

⁹ 2024 एफएसबी वार्षिक रिपोर्ट- वैश्विक वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देना

¹⁰ <https://www.fsb.org/2024/07/evaluation-of-the-effects-of-the-g20-financial-regulatory-reforms-on-securitisation-consultation-report/>

¹¹ <https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P220724-2.pdf>

¹² एफएसबी (2024) - वित्तीय प्रणाली में जमाकर्ता व्यवहार और ब्याज दर और चलनिधि जोखिम: मार्च 2023 की बैंकिंग उथल-पुथल से सबक

II.18 अक्टूबर 2024 में, जी20 ब्राजीलियाई प्रेसीडेंसी के अनुरोध पर, बीसीबीएस ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें मार्च 2023 की बैंकिंग उथल-पुथल से चलनिधि जोखिम के बारे में सीखे गए सबक का सारांश दिया गया है।¹³ इन पाठों में शामिल हैं: (i) हाल के अनुभव के आलोक में चलनिधि पर्यवेक्षण को विकसित करने की आवश्यकता हो सकती है; (ii) समेकित समूह के साथ-साथ कानूनी इकाई स्तर पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय बैंकों के जोखिमों की निगरानी और प्रबंधन को महत्व दिया जा सकता है; और (iii) चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) और निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफआर) के बेसल मानकों की मान्यताओं के अंशांकन पर चर्चा की आवश्यकता हो सकती है।

3.7 केंद्रीय प्रतिपक्ष

II.19 सीसीपी के प्रणालीगत महत्व ने सीसीपी के आवश्यक कार्यों को बनाए रखने और समाधान के दौरान वित्तीय स्थिरता पर संभावित नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए पर्याप्त चलनिधि, हानि-अवशोषण क्षमता और पुनर्पूजीकरण साधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं। 2024 में, एफएसबी ने एक "टूलबॉक्स" दृष्टिकोण तैयार किया जिसमें सीसीपी के लिए वित्तीय समाधान संसाधनों और साधनों के लिए एक वैश्विक मानक स्थापित किया गया, जिन्हें प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है।¹⁴ टूलबॉक्स दृष्टिकोण प्राधिकारियों को संसाधनों और साधनों की एक शृंखला से चयन करने की सुविधा प्रदान करता है, जो उनके क्षेत्राधिकारों में पहले से मौजूद उपकरणों का पूरक है।

3.8 सीमा पार भुगतान

II.20 अक्टूबर 2024 में, एफएसबी ने सीमा पार भुगतान के लक्ष्यों को पूरा करने पर अपनी दूसरी मुख्य निष्पादन संकेतक

(केपीआई) रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें प्रगति के क्षेत्रों पर प्रकाश डाला गया और चुनौतियों की पहचान की गई।¹⁵ रिपोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि वैश्विक स्तर पर, केपीआई लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में सीमित प्रगति दिखाते हैं और क्षेत्रों व गलियारों में अंतर बना हुआ है, जिसमें से कुछ क्षेत्रों को खासकर लागत और गति के लिए निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने में बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

II.21 जी20 रोडमैप को आगे बढ़ाने के लिए, एफएसबी ने जुलाई 2024 में दो परामर्श रिपोर्टें प्रकाशित कीं, एक जो सीमा पार भुगतान से संबंधित डेटा फ्रेमवर्क में संरेखण और अंतरसंचालनीयता को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत सिफारिशें पेश करती है, और दूसरी जो सीमा पार भुगतान सेवाओं के प्रावधान में बैंकों और गैर-बैंकों के विनियमन और पर्यवेक्षण में निरंतरता को मजबूत करने के लिए ऐसी गतिविधियों से जुड़े जोखिमों के अनुपात में नीतिगत सिफारिशें निर्धारित करती है।^{16, 17}

II.22 सीमा पार भुगतान व्यवस्था में प्रयुक्त सेवा-स्तरीय समझौते (एसएलए) संवाददाता बैंकिंग संबंधों के लिए न्यूनतम सेवा स्तर को परिभाषित करते हैं। अप्रैल 2024 में, भुगतान और बाजार अवसंरचना समिति (सीपीएमआई) ने स्पष्ट, पारदर्शी और प्रवर्तनीय एसएलए की स्थापना की वकालत करते हुए एक रिपोर्ट प्रकाशित की, जो सीमा पार भुगतान के जोखिमों को प्रभावी ढंग से कम कर सकती है, पारदर्शी और कुशल भुगतान प्रसंस्करण नियमों को पर्याप्त रूप से परिभाषित कर सकती है, समयबद्धता और निपटान की अंतिमता सुनिश्चित कर सकती है, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत तकनीकी मानकों के साथ अंतरसंचालनीयता को बढ़ावा दे सकती है।¹⁸

¹³ बीसीबीएस (2024) - 2023 की बैंकिंग उथल-पुथल और चलनिधि जोखिम: एक प्रगति रिपोर्ट

¹⁴ <https://www.fsb.org/2024/04/financial-resources-and-tools-for-central-counterparty-resolution/>

¹⁵ <https://www.fsb.org/2023/10/annual-progress-report-on-meeting-the-targets-for-cross-border-payment-2023-report-on-key-performance-indicators/>

¹⁶ <https://www.fsb.org/2024/07/recommendations-to-promote-alignment-and-interoperability-across-data-frameworks-related-to-cross-border-payments-consultation-report/>

¹⁷ <https://www.fsb.org/2024/07/recommendations-for-regulating-and-supervising-bank-and-non-bank-payment-service-providers-offering-cross-border-payment-services-consultation-report/>

¹⁸ <https://www.bis.org/cpmi/publ/d222.htm>

3.9 जलवायु और प्रकृति संबंधी जोखिम

11.23 सभी अंतरराष्ट्रीय निकायों के लिए जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले वित्तीय जोखिमों से निपटना एक प्रमुख प्राथमिकता बनी है। अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन (आईओएससीओ), अंतरराष्ट्रीय धारणीयता मानक बोर्ड (आईएसएसबी), और अन्य संबंधित निकायों ने आईएसएसबी के नए धारणीयता संबंधित प्रकटीकरण मानकों को अपनाने और लागू करने में क्षेत्राधिकारों का समर्थन करने के लिए सहयोग किया है।

11.24 जलवायु संबंधी प्रकटीकरण पर एफएसबी की प्रगति रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि सर्वेक्षण किए गए 24 एफएसबी सदस्य क्षेत्राधिकारों में से 19 ने पहले ही जलवायु से संबंधित प्रकटीकरण के लिए नियम लागू कर दिए हैं, दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं या रणनीतिक रोडमैप विकसित किए हैं। 17 एफएसबी क्षेत्राधिकारों ने आईएसएसबी मानकों और जलवायु-संबंधित प्रकटीकरण (टीसीएफडी) पर टास्क फोर्स की सिफारिशों के आधार पर स्वैच्छिक या अनिवार्य प्रकटीकरण आवश्यकताओं को निर्धारित या प्रस्तावित किया है। इसके अलावा, कई क्षेत्राधिकारों ने आश्वासन आवश्यकताओं की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं¹⁹।

11.25 इससे पहले, एफएसबी ने जुलाई 2024 में 'स्टॉकटेक ऑन नेचर रिलेटेड रिस्क' पर एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें वर्तमान और योजनाबद्ध विनियामक और पर्यवेक्षी पहलों की समीक्षा की गई थी और प्रकृति-संबंधित वित्तीय जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन और प्रबंधन करने में प्राधिकारियों के सामने आनेवाली प्रमुख चुनौतियों को रेखांकित किया गया था।²⁰ रिपोर्ट से पता चला कि एफएसबी सदस्य क्षेत्राधिकारों में वित्तीय प्राधिकारी शासनादेशों में अंतर के साथ जैव विविधता हानि और अन्य प्रकृति-संबंधित जोखिमों की प्रासंगिकता के मूल्यांकन के विभिन्न चरणों में हैं। कुछ प्राधिकार क्षेत्रों ने उनकी

पहचान भौतिक वित्तीय जोखिमों के रूप में की है, जबकि अन्य अभी भी अंतरराष्ट्रीय गतिविधियों की निगरानी कर रहे हैं, और कुछ ने अभी तक इस मुद्दे का समाधान नहीं करने का विकल्प चुना है। हालाँकि, ऐसी मान्यता है कि प्रकृति से संबंधित वित्तीय जोखिमों को प्रभावी ढंग से समझने और संबोधित करने के लिए पर्यवेक्षी समुदाय, केंद्रीय बैंकों और निजी क्षेत्र में अधिक विशेषज्ञता की आवश्यकता है।

11.26 इसके अलावा, नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम (एनजीएफएस) ने जुलाई 2024 में यूरोप और एशिया के आठ केस स्टडीज की अंतर्दृष्टि पर चर्चा करते हुए 'एडाप्टिंग सेंट्रल बैंक ऑपरेशन टू ए हॉटर वर्ल्ड' पर एक रिपोर्ट पेश की। इन मामलों के अध्ययनों ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि कैसे कुछ केंद्रीय बैंकों ने समायोजित ऋण परिचालन, समायोजित आस्ति खरीद योजनाओं और समायोजित संपार्श्विक नीतियों जैसी पहलों के माध्यम से अपनी मौद्रिक नीतियों में जलवायु-संबंधी कारकों को एकीकृत किया है²¹। हालाँकि जिन केंद्रीय बैंकों ने कार्रवाई की है, उन्होंने अब तक सतर्क और क्रमिक दृष्टिकोण अपनाया है, यह उम्मीद की जाती है कि वे अधिक सशक्त कार्रवाई करने से पहले समय के साथ संबंधित ट्रेड-ऑफ के बारे में और अधिक सीखेंगे।

11.27 एनजीएफएस ने जून 2024 में 'केंद्रीय बैंकों के लिए जलवायु संबंधी प्रकटीकरण पर गाइड' का दूसरा संस्करण प्रकाशित किया, जिसमें आधारभूत और बिल्डिंग ब्लॉक दोनों सिफारिशें पेश की गईं²²। एनजीएफएस ने जुलाई 2024 में 'प्रकृति से संबंधित वित्तीय जोखिमों पर केंद्रीय बैंकों और पर्यवेक्षकों द्वारा कार्रवाई का मार्गदर्शन करने के लिए वैचारिक ढांचा' भी प्रकाशित किया²³। इस सिद्धांत-आधारित जोखिम मूल्यांकन ढांचे का उद्देश्य केंद्रीय बैंकों और पर्यवेक्षकों को भौतिक वित्तीय जोखिमों की पहचान एवं विश्लेषण करने और उनके अधिकार क्षेत्र के संदर्भ और जनादेश के अनुसार प्रासंगिक नीतियों को विकसित करने में सहायता करना है।

¹⁹ एफएसबी (2024) – निरंतर और तुलनीय जलवायु संबंधी प्रकटीकरण प्राप्त करना - प्रगति रिपोर्ट

²⁰ <https://www.fsb.org/2024/07/stocktake-on-nature-related-risks-supervisory-and-regulatory-approaches-and-perspectives-on-financial-risk/>

²¹ <https://www.ngfs.net/en/adapting-central-bank-operations-hotter-world-current-progress-and-insights-practical-examples>

²² <https://www.ngfs.net/en/guide-climate-related-disclosure-central-banks-second-edition>

²³ <https://www.ngfs.net/en/ngfs-conceptual-framework-nature-risks>

3.10 क्रिप्टो-आस्तियां

11.28 समष्टि-आर्थिक और वित्तीय स्थिरता पर संभावित प्रभाव के साथ, हाल के महीनों में क्रिप्टो-आस्तियों और स्टेबलक्वाइन के बाजार अब तक के चरम स्तर पर पहुंच गए हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ), एफएसबी, विश्व बैंक, वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) और अन्य एसएसबी सहित अंतरराष्ट्रीय संगठन 'जी20 क्रिप्टो-आस्ति नीति कार्यान्वयन रोडमैप' के कार्यान्वयन की दिशा में मिलकर काम कर रहे हैं।

11.29 2022 की क्रिप्टो बाजार की उथल-पुथल और उसके बाद कुछ स्टेबलक्वाइन की गिरावट तथा डी-पेगिंग ने उनके अपर्याप्त विनियमन और डिजाइन से उत्पन्न होने वाली कमजोरियों को रेखांकित किया। हालाँकि ये जोखिम और चुनौतियाँ वैश्विक हैं, कुछ ईएमडी को क्षमता और संसाधन की कमी तथा विदेशी मुद्रा से जुड़े स्टेबलक्वाइन के विस्तारित सीमा-पार परिचालनों की व्यापकता के कारण अतिरिक्त जोखिम और चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। एफएसबी ने जुलाई 2024 की अपनी रिपोर्ट में, ईएमडी में विदेशी मुद्रा-पेग्ड स्टेबल कॉइन से संबंधित उच्च स्तरीय गतिविधि को संचालित करनेवाले संभावित कारकों, संबंधित वित्तीय स्थिरता जोखिमों और विनियामक चुनौतियों का पता लगाया और उनका निवारण करने के लिए सुझाव दिए²⁴।

11.30 मल्टी-फंक्शन क्रिप्टो-एसेट इंटरमीडियरीज (एमसीआई) ऐसी कंपनियाँ हैं जो क्रिप्टो आस्ति सेवाओं, उत्पादों और कार्यों की एक विस्तृत शृंखला को जोड़ती हैं, जो आमतौर पर एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के संचालन के आसपास केंद्रित होती हैं। पारंपरिक वित्तीय फर्मों की तुलना में एमसीआई को अतिरिक्त कमजोरियों का सामना करना पड़ता है क्योंकि कार्यों के कुछ संयोजन उनकी कमजोरियों को बढ़ा सकते हैं।

एफएसबी ने नवंबर 2023 में एमसीआई की वित्तीय स्थिरता के निहितार्थ पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें उनकी संरचना और कार्यप्रणाली, प्रासंगिक वित्तीय स्थिरता जोखिम, प्रमुख सूचना अंतराल और नीति विचार के निहितार्थ का विश्लेषण किया गया²⁵।

3.11 कृत्रिम मेधा (एआई) और टोकनाइजेशन

11.31 नवंबर 2024 में, 'कृत्रिम मेधा के वित्तीय स्थिरता निहितार्थ' पर एफएसबी रिपोर्ट ने एआई से संबंधित कमजोरियों की पहचान की जो प्रणालीगत जोखिम को बढ़ाने की उसकी क्षमता के लिए सामने आती हैं, जिसमें (i) तीसरे पक्ष की निर्भरता और सेवा प्रदाता संकेंद्रितता; (ii) बाजार सहसंबंध; (iii) साइबर जोखिम; और (iv) मॉडल जोखिम, डेटा गुणवत्ता और अभिशासन शामिल हैं²⁶। रिपोर्ट में कहा गया है कि जेनरेटिव एआई (जेनएआई) वित्तीय बाजारों में धोखाधड़ी और दुष्प्रचार की संभावना को भी बढ़ाता है, और गलत तरीके से संरेखित एआई प्रणाली जिसकी कानूनी, विनियामक और नैतिक सीमाओं के भीतर काम करने के लिए जांच नहीं की गई है, वह वित्तीय स्थिरता को नुकसान पहुंचाने वाले व्यवहार में संलग्न हो सकती है।

11.32 अक्टूबर 2024 में, एक एफएसबी रिपोर्ट ने वितरित खाता प्रौद्योगिकी (डीएलटी)-आधारित वित्तीय आस्ति टोकनाइजेशन के वित्तीय स्थिरता निहितार्थ का विश्लेषण किया। रिपोर्ट ने कई वित्तीय स्थिरता कमजोरियों की पहचान की, जो चलनिधि और परिपक्वता बेमेलता, लीवरेज, आस्ति मूल्य और गुणवत्ता, परस्पर संबद्धता और परिचालन कमजोरियों से संबंधित हैं²⁷।

11.33 मार्च 2024 में यूरोपीय संसद ने दुनिया का पहला कानूनी ढांचा- यूरोपीय संघ (ईयू) एआई अधिनियम अपनाया, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ईयू में प्रयुक्त एआई

²⁴ <https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P230724.pdf>

²⁵ <https://www.fsb.org/2023/11/the-financial-stability-implications-of-multifunction-crypto-asset-intermediaries/>

²⁶ एफएसबी (2024) – कृत्रिम मेधा के वित्तीय स्थिरता आशय

²⁷ <https://www.fsb.org/2024/10/the-financial-stability-implications-of-tokenisation/>

प्रणालियाँ सुरक्षित, पारदर्शी, पता लगाने योग्य, गैर-भेदभावपूर्ण और पर्यावरण के अनुकूल हैं और यह कि हानिकारक परिणामों को रोकने के लिए एआई प्रणाली की निगरानी स्वचालन के बजाय लोगों द्वारा की जाती है²⁸।

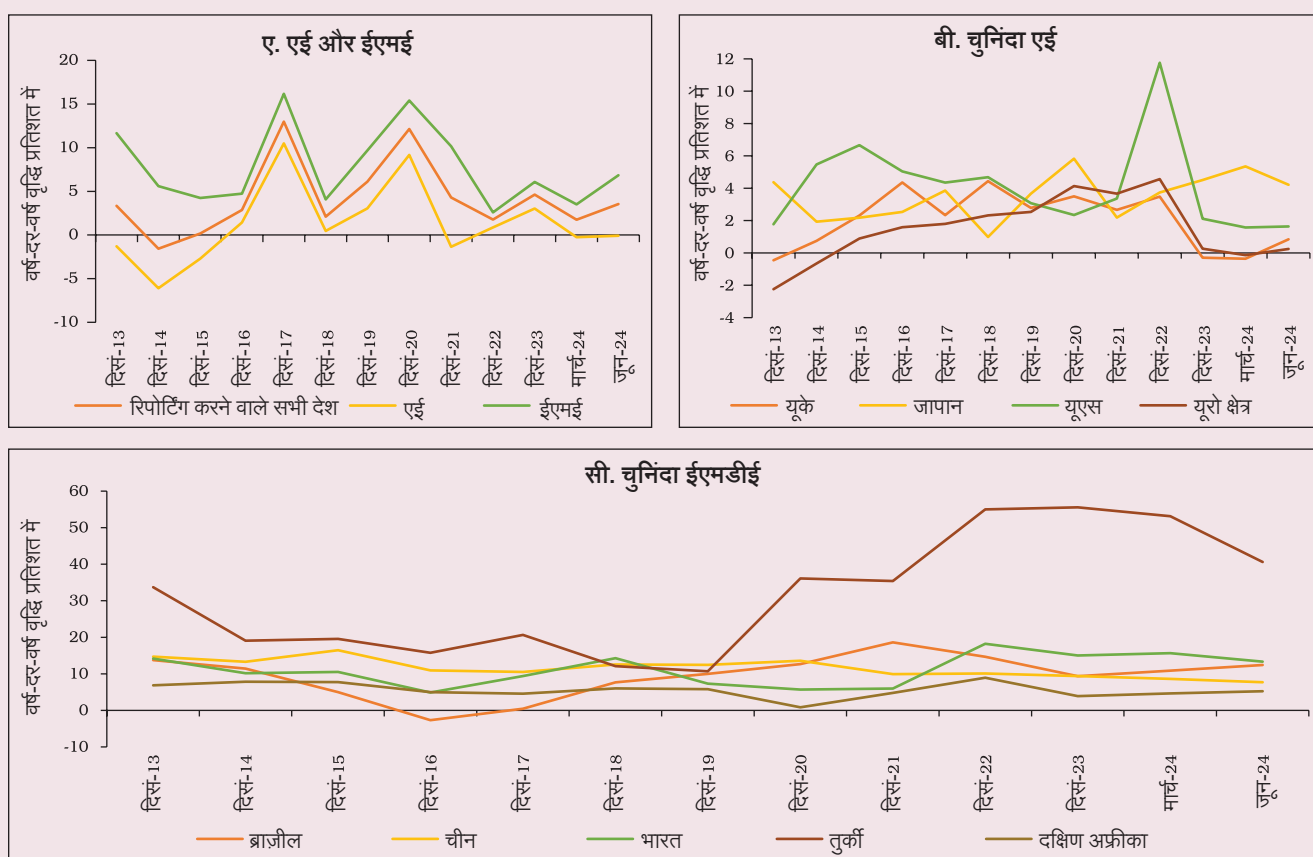
4. वैश्विक बैंकिंग क्षेत्र का कार्यनिष्पादन

11.34 निजी गैर-वित्तीय क्षेत्र में ऋण संवृद्धि, जो महामारी के बाद की अवधि में तेजी से कम हो गई थी, मजबूत आर्थिक गतिविधि और समायोजनकारी मौद्रिक और चलनिधि स्थितियों के कारण 2022 की चौथी तिमाही से 2023 के तीसरी तिमाही के दौरान फिर से बढ़ गई। उच्च उधार दरों

और सख्त क्रेडिट मानकों के बीच, बाद में जो नरमी आई, उसने हाल की दर में कटौती पर उलटफेर के संकेत दिखाए हैं²⁹ (चार्ट 11.4ए)। ईई के बीच, जापान में ऋण संवृद्धि में तेजी आई, जो आर्थिक गतिविधि में सुधार को दर्शाती है। हालाँकि, हालिया रुझान ऋण संवृद्धि में कुछ मंदी का सुझाव देते हैं (चार्ट 11.4बी)। ईएमई के बीच, तुर्की में शुरू में घरेलू क्रेडिट कार्ड के उपयोग और आर्थिक सुधार से प्रेरित ऋण संवृद्धि, 2023 की तीसरी तिमाही के बाद से धीमी हो गई है³⁰ (चार्ट 11.4सी)।

11.35 ऋण की बढ़ोतरी जीडीपी संवृद्धि का एक अच्छा चक्र शुरू कर सकती है, लेकिन एक सीमा से परे यह आर्थिक गतिविधियों के लिए हानिकारक हो सकता है (बॉक्स 11.1)।

चार्ट 11.4 निजी गैर-वित्तीय क्षेत्र को बैंक ऋण



स्रोत: कुल ऋण सांख्यिकी, बीआईएस।

²⁸ <https://www.europarl.europa.eu/topics/en/article/20230601STO93804/eu-ai-act-first-regulation-on-artificial-intelligence>

²⁹ आर्थिक बुलेटिन (2024), यूरोपीय सेंट्रल बैंक, अंक 5।

³⁰ <https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/d5b26167-65ec-45fc-b148-8ce753e53a80/III.+Non-Financial+Sector.pdf?MOD=AJPERES&CA=CHEID=ROOTWORKSPACE-d5b26167-65ec-45fc-b148-8ce753e53a80-p3LgjlU>

बॉक्स II.1: जीडीपी की तुलना में इष्टतम ऋण का अनुपात: एक क्रॉस-कंट्री विश्लेषण

ऋण की बढ़ोतरी से अर्थव्यवस्था में उच्च उपभोग, निवेश और आर्थिक गतिविधि में योगदान मिल सकता है। आर्थिक विकास पर ऋण के प्रभाव में एक उलटा यू-पैटर्न हो सकता है: एक सीमा से परे, ऋण को कम उत्पादक या अधिक जोखिम भरी गतिविधियों में लगाया जा सकता है और विकास को धीमा कर दिया जा सकता है (लॉ और अन्य, 2013) [चार्ट II.1]।

इन गतिशीलताओं का पता लगाने के लिए, जीडीपी वृद्धि और जीडीपी की तुलना में ऋण अनुपात के बीच संबंध का अनुमान इस प्रकार लगाया गया है:

$GDP_{it} = \beta_1 F_{it-1} I(F_{it-1} \leq \gamma) + \beta_2 F_{it-1} I(F_{it-1} > \gamma) + \alpha_1 X_{it} + \mu_i + \varepsilon_{it} \dots$ (Eq. 1)
जहां सबस्क्रिप्ट i देश का प्रतिनिधित्व करता है और t वर्ष का संकेत देता है। जीडीपी वार्षिक जीडीपी प्रति व्यक्ति विकास दर है, F थ्रेशोल्ड वैरिएबल (इस मामले में जीडीपी की तुलना में ऋण अनुपात) है और γ अनुमानित थ्रेशोल्ड मूल्य है। मैट्रिक्स एक्स में निवेश दर (जीडीपी के प्रतिशत के रूप में), मुद्रास्फीति दर और कुल कारक उत्पादकता वृद्धि (टीएफपीजी) जैसे नियंत्रण चर शामिल हैं। मॉडल 1 (सारणी II.1.1) में, जीडीपी से निवेश का अनुपात, टीएफपीजी और मुद्रास्फीति को नियंत्रण चर के रूप में शामिल किया गया है। मॉडल 2 में, 2008-09 के वैश्विक वित्तीय संकट (जीएफसी डमी) और 2013 के टेपर टैंट्रम एपिसोड के लिए डमी जोड़े गए हैं, जबकि मॉडल 3 में एक कोविड-19 डमी जोड़ा गया है। 16 आई और ईएमडीई के लिए 2001 से 2022 तक के वार्षिक डेटा का उपयोग अनुमानों में किया गया है। कुल बकाया ऋण डेटा में निजी क्षेत्र द्वारा बैंकों और गैर-बैंकों सहित सभी घरेलू और विदेशी स्रोतों से ली गई कुल उधारी को शामिल किया है³¹।

परिणाम नमूना देशों के लिए सकल घरेलू उत्पाद के 113.1 प्रतिशत पर क्रेडिट सीमा का सुझाव देते हैं, हालांकि यह सीमा प्रत्येक देश के लिए अलग हो

सारणी II.1.1: थ्रेशोल्ड रिग्रेशन परिणाम

	प्रति व्यक्ति वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि	प्रति व्यक्ति वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि	प्रति व्यक्ति वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि
	1	2	3
अनुमानित सीमा	113.1	113.1	113.1
95% विश्वास अंतराल	[111.9; 113.2]	[111.9; 113.2]	[111.9; 113.2]
ऋण-जीडीपी अनुपात का प्रभाव			
β_1	0.0130 (0.00927)	0.0116 (0.00983)	0.0109 (0.00984)
β_2	-0.00604* (0.00318)	-0.00706* (0.00374)	-0.00744** (0.00374)
सहपरिवर्तियों का प्रभाव			
टीएफपीजी	1.371*** (0.0563)	1.344*** (0.0575)	1.355*** (0.0572)
निवेश से जीडीपी अनुपात	0.204*** (0.0297)	0.204*** (0.0296)	0.204*** (0.0299)
मुद्रा स्फीति	0.0691 (0.0499)	0.0883* (0.0506)	0.0784 (0.0535)
जीएफसी डमी		-0.430 (0.286)	-0.362 (0.287)
टेपर टैंट्रम डमी		0.172 (0.263)	0.250 (0.268)
कोविड-19 डमी			-0.0242 (0.314)
स्थिरांक	-2.145** (0.963)	-1.987** (0.967)	-1.959** (0.971)
अवलोकन	336	336	336
आर-स्क्वेअर्ड	0.675	0.681	0.681
देशों की संख्या	16	16	16

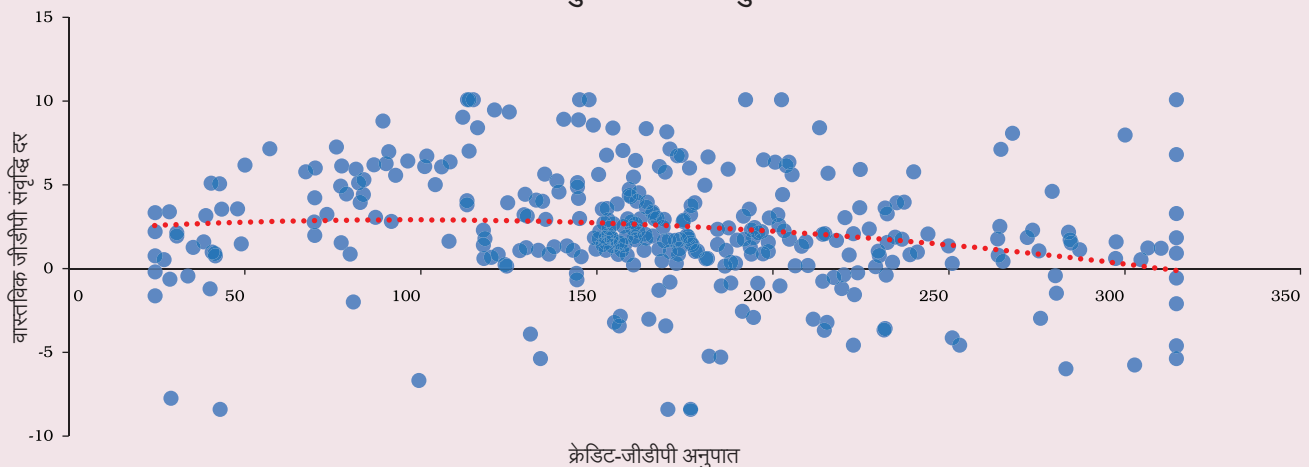
टिप्पणियाँ: 1) कोष्ठक में मजबूत मानक त्रुटियाँ।

2) *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

स्रोत: आरबीआई स्टाफ अनुमान।

सकती है और उसके संरचनात्मक कारकों के आधार पर समय के साथ भिन्न हो सकती है। महत्वपूर्ण और नकारात्मक उपरोक्त सीमा गुणांक (β_2) से पता चलता है कि सीमा से परे जीडीपी से ऋण के अनुपात का स्प्रेड आर्थिक विकास में बाधा डालता है, जो साहित्य के अनुरूप है (आर्केड, एट. अल.

चार्ट II.1.1: विभिन्न देशों में जीडीपी की तुलना में ऋण अनुपात और वास्तविक जीडीपी विकास दर



स्रोत : आरबीआई स्टाफ अनुमान।

³¹ जीडीपी की तुलना में ऋण अनुपात के आंकड़े बीआईएस से प्राप्त होते हैं, जबकि मुद्रास्फीति और जीडीपी की तुलना में निवेश अनुपात के आंकड़े आईएमएफ के डब्ल्यूईओ से प्राप्त होते हैं, तथा कुल कारक उत्पादकता वृद्धि (टीएफपीजी) के आंकड़े कॉन्फ्रेंस बोर्ड से प्राप्त होते हैं।

2012)। जैसा कि अपेक्षित था, टीएफपीजी और जीडीपी से निवेश के अनुपात का जीडीपी संवृद्धि पर सकारात्मक और महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। जीएफसी, टैपर टैट्रम और कोविड-19 के लिए डमी को शामिल करने के बाद परिणाम मजबूत बने हुए हैं (सारणी II.1.1, मॉडल 2 और मॉडल 3)।

2022 में भारत का कुल जीडीपी से ऋण का अनुपात (बैंकों और एनबीएफसी द्वारा दिए गए ऋण सहित) 90.1 प्रतिशत था, जो आई के साथ-साथ उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) और अनुमानित सीमा से नीचे था। इस प्रकार, उच्च ऋण संवृद्धि आर्थिक विकास के लिए सहायक बनी हुई है।

सन्दर्भ:

आर्कैड, जे.एल., बर्कस, ई., और पनिजा, यू. (2012)। टू मच ? आईएमएफ वर्किंग पेपर, 2012/161।

लॉ, एस.एच., और सिंह, एन. (2014)। डज टू मच फाइनेंस हार्म इकोनोमिक ग्रोथ ? जर्नल ऑफ बैंक एंड फाइनेंस, वॉल्यूम. 41, 36-44।

4.1 आस्ति गुणवत्ता

II.36 अनर्जक ऋण (एनपीएल) अनुपात बैंकों के ऋण पोर्टफोलियो के ऋण जोखिम के प्रमुख संकेतक के रूप में कार्य करता है। हाल के वर्षों में, अधिकांश आई और ईएमडीई में बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में सुधार हुआ है (सारणी II.1)। यूरो क्षेत्र में, ग्रीस ने अपने ऐतिहासिक रूप से उच्च एनपीएल अनुपात

को कम करने में 2018 के बाद से उल्लेखनीय प्रगति की है, हालांकि यह अन्य यूरो क्षेत्र के देशों की तुलना में काफी अधिक है।

4.2 प्रावधान कवरेज अनुपात

II.37 एक उच्च प्रावधान कवरेज (पीसीआर) इंगित करता है कि बैंकिंग प्रणाली में अशोध्य ऋणों को कवर करने के लिए

सारणी II.1: आस्ति गुणवत्ता (एनपीएल अनुपात)

(प्रतिशत)

देश	2015	2019	2020	2021	2022	2023	ति1:2024	ति2:2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
उन्नत अर्थव्यवस्थाएँ								
ऑस्ट्रेलिया	0.89	0.96	1.11	0.91	0.72	0.85	0.95	लागू नहीं
कनाडा	0.52	0.50	0.53	0.38	0.33	0.45	0.48	0.53
डेनमार्क	3.28	1.37	1.41	1.24	1.07	0.94	0.93	0.90
यूके	1.01	1.02	0.98	0.97	0.95	0.98	0.99	1.01
यूएस	1.47	0.86	1.07	0.81	0.72	0.85	0.90	लागू नहीं
यूरो क्षेत्र								
बेल्जियम	3.85	2.09	2.07	2.03	1.84	1.82	1.88	लागू नहीं
फ्रांस	3.52	2.51	2.38	2.17	2.08	2.06	2.06	लागू नहीं
ग्रीस	35.71	38.07	30.81	11.88	8.17	5.96	6.65	6.17
आयरलैंड	16.91	3.36	3.36	2.48	1.61	1.27	1.32	1.17
नीदरलैंड	2.71	1.83	1.88	1.72	1.60	1.55	1.54	1.57
स्पेन	5.09	3.15	2.85	2.92	3.06	3.06	3.04	2.94
उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाएँ								
अर्जेंटीना	1.57	5.70	4.15	4.29	3.09	3.55	1.96	1.82
ब्राज़ील	2.85	2.66	1.87	2.08	2.64	2.84	2.86	2.83
चीन	1.67	1.86	1.84	1.73	1.63	1.59	1.59	1.56
भारत	5.88	9.23	7.94	6.54	4.81	1.72	लागू नहीं	लागू नहीं
इंडोनेशिया	2.32	2.34	2.64	2.64	2.15	1.96	2.04	2.08
मेक्सिको	2.60	2.20	2.56	2.05	2.08	2.08	2.00	1.98
रूस	8.38	8.83	8.16	6.10	5.51	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
दक्षिण अफ्रीका	3.12	3.89	5.18	4.45	N.A.	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
थाईलैंड	2.68	3.13	3.23	3.11	2.84	2.76	2.84	लागू नहीं

टिप्पणी: लागू नहीं – डेटा उपलब्ध नहीं है।

स्रोत: वित्तीय सुदृढ़ता संकेतक, आईएमएफ।

महत्वपूर्ण प्रावधान हैं और डिफॉल्ट को संभालने के लिए बेहतर तैयारी है। 2024 की पहली तिमाही में कुछ नरमी के बावजूद, अमेरिकी बैंकों ने एई में उच्चतम पीसीआर जारी रखा (चार्ट 11.5ए)। यूरो क्षेत्र में, आयरलैंड, जिसका 2018 से पहले उच्च एनपीएल का इतिहास था, प्रावधान बफर्स का निर्माण कर रहा है। ईएमडीई के बीच, ब्राजील में बैंकों ने आस्ति गुणवत्ता में सुधार के बीच उच्च पीसीआर बनाए रखा (चार्ट 11.5बी)।

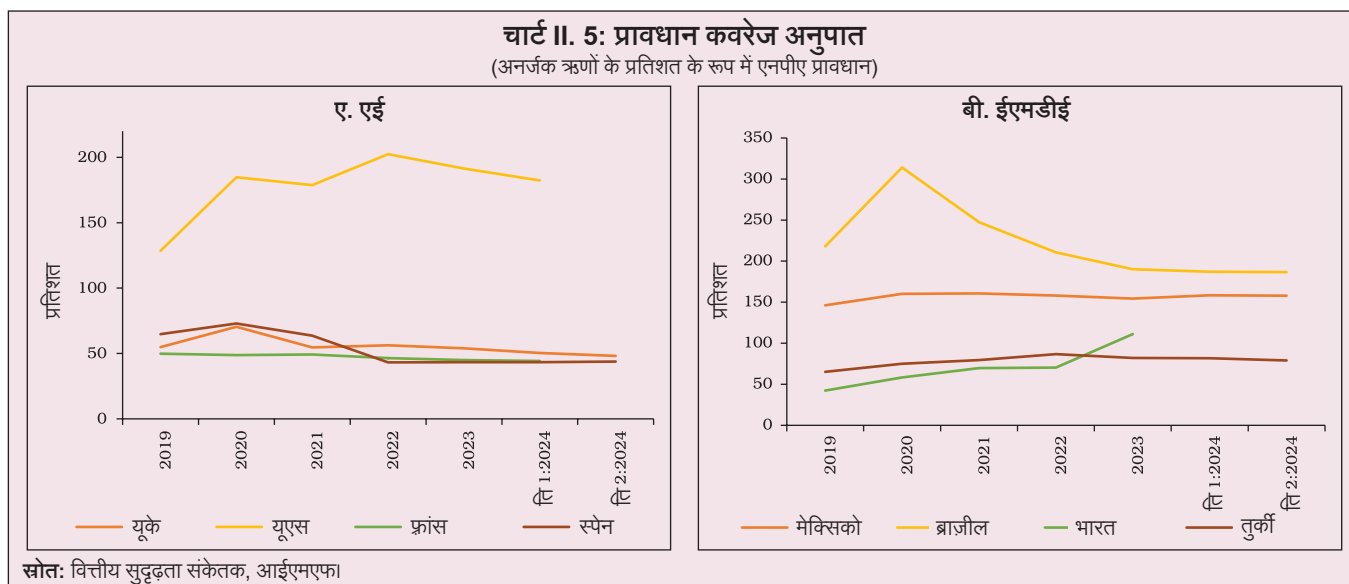
4.3 बैंक लाभप्रदता

11.38 अधिकांश प्राधिकार क्षेत्रों में बैंकों की लाभप्रदता [आस्ति पर प्रतिलाभ, (आरओए)] में उच्च ब्याज दरों के जवाब में मिश्रित उतार-चढ़ाव देखा गया। अमेरिका और तुर्की जैसे कुछ देशों में, बैंकों की लाभप्रदता कम हो गई क्योंकि उच्च नीति दरों ने उनकी उधार लेने की लागत में वृद्धि की, जबकि ऋण मांग पर भी असर पड़ा (चार्ट 11.6 ए और बी)। हालाँकि, कुछ अन्य प्राधिकार क्षेत्रों में, विभिन्न कारणों से बैंकों की लाभप्रदता में वृद्धि हुई। उदाहरण के लिए, उच्च निवल ब्याज

आय (एनआईआई), कम प्रावधानों और मध्यम लागत वृद्धि के कारण 2023 में यूके के बैंकों के आरओए में सुधार हुआ³² यूरो क्षेत्र में, ग्रीस की रेटिंग के उन्नयन से उसके बैंकों की उधार लेने की लागत कम करने में मदद मिली, जिससे उनकी लाभप्रदता बढ़ी।³³ आयरलैंड ने 2023 की पहली तिमाही में लाभप्रदता में उल्लेखनीय वृद्धि का अनुभव किया, जो नीतिगत दरों से जुड़े ऋणों पर बेहतर मार्जिन से प्रेरित था³⁴।

4.4 पूंजी पर्याप्तता

11.39 2024 की पहली छमाही में, बैंकों ने पूंजी अनुपात को विनियामक मानदंडों से काफी ऊपर बनाए रखते हुए अपनी वित्तीय स्थिति को और मजबूत किया। एई के बीच, नॉर्वे और डेनमार्क जैसे स्कैंडिनेवियाई देशों ने अपने साथियों की तुलना में उच्च पूंजी बफर बनाये रखना जारी रखा। 2023 और 2024 की पहली तिमाही में अमेरिकी बैंकों की जोखिम-भारित आस्ति की तुलना में पूंजी के अनुपात (सीआरएआर) में सुधार हुआ। हाल की नरमी के बावजूद यूके के बैंकों का अनुपात चरम स्तर पर

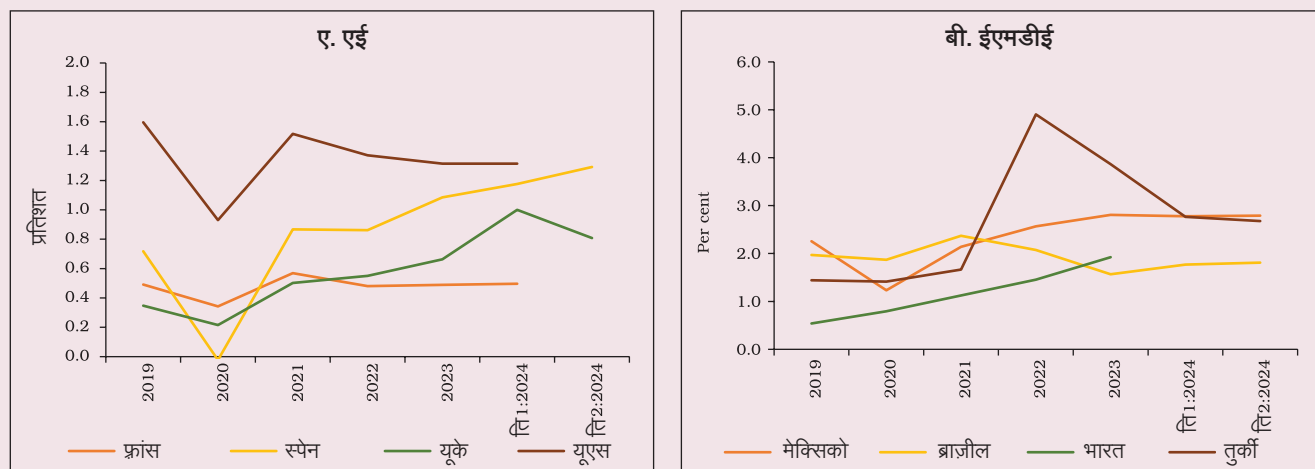


³² <https://www.fitchratings.com/research/banks/major-uk-banks-profitability-to-remain-strong-despite-lower-net-interest-income-27-02-2024>

³³ वित्तीय स्थिरता समीक्षा, सेंट्रल बैंक ऑफ ग्रीस, अप्रैल।

³⁴ वित्तीय स्थिरता समीक्षा, सेंट्रल बैंक ऑफ आयरलैंड, जून।

चार्ट II.6: आस्तियों पर प्रतिलाभ



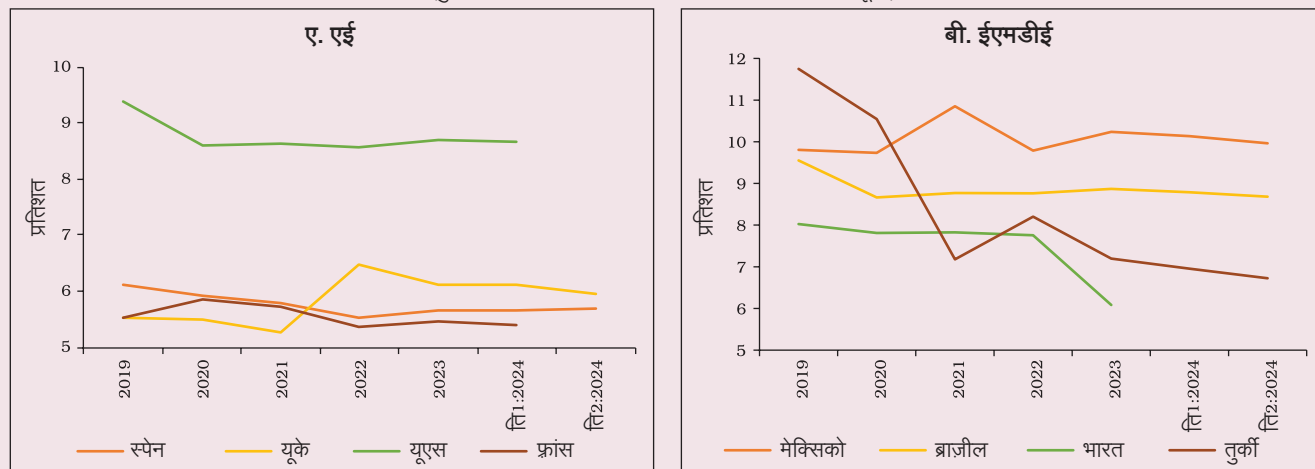
स्रोत: वित्तीय सुदृढ़ता संकेतक, आईएमएफ।

है। यूरो क्षेत्र के देशों ने अलग-अलग रुझान प्रदर्शित किए, स्पेन ने 2024 की दूसरी तिमाही में पूंजी बफर में सुधार का प्रदर्शन किया। नीदरलैंड और बेल्जियम में बैंकों के सीआरएआर में गिरावट आई लेकिन विनियामक आवश्यकताओं से यह अधिक बना रहा। ईएमडीई में, अर्जेंटीना के सीआरएआर में महामारी के बाद की अवधि में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई, जो आर्थिक चुनौतियों के जवाब में पर्याप्त पूंजी संचय को दर्शाता है³⁵ (सारणी II.2)।

4.5 लीवरेज अनुपात

II.40 लीवरेज अनुपात किसी बैंक की कुल आस्तियों में उसकी टियर 1 पूंजी के अनुपात को मापता है, जो अत्यधिक जोखिम एक्सपोजर के खिलाफ सुरक्षा के रूप में कार्य करता है। 2024 की पहली छमाही में, अधिकांश देशों में बैंकों ने लीवरेज अनुपात को 3 प्रतिशत की न्यूनतम बेसल III आवश्यकता से चरम स्तर पर बनाए रखा। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में, अमेरिका ने उच्चतम लीवरेज अनुपात बनाए रखा, जो 8.5 प्रतिशत से

चार्ट II.7: लीवरेज अनुपात
(कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में विनियामकीय टियर 1 पूंजी)



स्रोत: वित्तीय सुदृढ़ता संकेतक, आईएमएफ।

³⁵ <https://www.elibrary.imf.org/view/journals/002/2024/167/article-A001-en.xml>

सारणी II.2: जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में विनियामकीय पूंजी अनुपात

(प्रतिशत)

देश	2015	2019	2020	2021	2022	2023	ति1:2024	ति2:2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
उन्नत अर्थव्यवस्थाएँ								
ऑस्ट्रेलिया	13.80	15.70	17.56	17.87	17.80	19.95	20.40	लागू नहीं
कनाडा	14.20	15.34	16.10	17.17	17.36	17.14	17.20	16.79
डेनमार्क	19.19	22.47	23.29	22.87	22.56	23.47	23.43	23.13
नॉर्वे	18.94	24.19	24.80	25.02	25.88	24.66	25.03	25.05
यूके	19.61	21.25	21.61	22.05	21.43	21.27	21.01	21.21
यूएस	14.14	14.65	16.28	16.39	15.54	15.90	16.06	लागू नहीं
यूरो क्षेत्र								
बेल्जियम	18.69	18.75	20.34	20.44	20.05	19.61	19.22	लागू नहीं
ग्रीस	16.52	17.02	16.66	15.23	17.46	18.75	18.88	18.84
आयरलैंड	27.49	24.97	25.47	25.53	27.80	26.52	27.73	27.69
नीदरलैंड	20.11	22.86	22.79	22.34	20.94	21.08	20.62	20.40
स्पेन	14.66	15.91	16.98	17.43	16.68	17.12	17.15	17.21
उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाएँ								
अर्जेंटीना	13.28	17.49	24.19	26.20	29.86	32.51	39.46	37.06
ब्राज़ील	16.44	19.42	19.09	18.42	17.52	17.90	17.64	17.51
चीन	13.45	14.64	14.70	15.13	15.17	15.06	15.43	15.53
भारत	12.68	15.42	15.59	14.79	15.82	15.59	लागू नहीं	लागू नहीं
इंडोनेशिया	18.86	21.59	22.14	24.02	24.13	25.84	24.29	24.44
मेक्सिको	14.96	15.98	17.70	19.53	19.00	18.81	19.49	19.29
रूस	12.70	12.33	12.55	12.35	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
दक्षिण अफ्रीका	14.20	16.58	16.58	18.11	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
थाईलैंड	17.11	19.35	19.75	19.58	18.89	19.58	19.56	लागू नहीं

टिप्पणी: लागू नहीं – डेटा उपलब्ध नहीं है।

स्रोत: वित्तीय सुदृढ़ता संकेतक, आईएमएफ।

ऊपर था (चार्ट II.7ए)। कनाडाई बैंकों का लीवरेज अनुपात लगातार 5 प्रतिशत से नीचे रहा है। आम तौर पर, पूंजी के लिए विनियामक आवश्यकताएं ईएमडी में अधिक होती हैं, जो उन्हें एई की तुलना में उच्च लीवरेज अनुपात बनाए रखने के लिए प्रेरित करती हैं (चार्ट II.7बी)। अर्जेंटीना के बैंकों ने सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) जैसी कम जोखिम वाली आस्तियों में भारी निवेश किया, जिससे उनकी मूल पूंजी बढ़ गयी और बदले में, उनके लीवरेज अनुपात में वृद्धि हुई³⁶।

4.6 वित्तीय बाजार संकेतक

II.41 मार्च 2023 में बैंकिंग संकट के बाद, वैश्विक बैंकिंग शेयरों को 2023 की पहली छमाही में नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि, त्वरित नीतिगत हस्तक्षेप ने प्रणालीगत प्रसार-

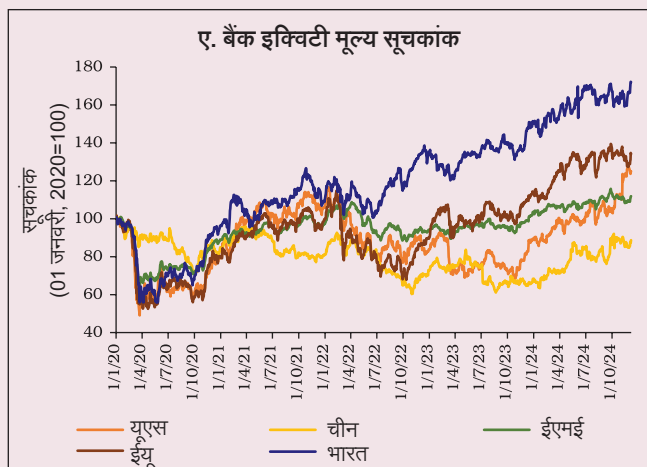
प्रभाव को सीमित कर दिया और बाजारों को शांत करने में मदद की। यूएस और ईयू बैंकिंग शेयरों में लगातार बढ़त देखी गई, खासकर 2023 की चौथी तिमाही से, जो बेहतर बाजार स्थितियों और आर्थिक स्थिरता को दर्शाता है (चार्ट II.8ए)।

II.42 बैंकों के ऋण चूक स्वैप (सीडीएस) स्प्रेड वित्तीय संस्थानों के कथित ऋण जोखिम के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, जो चूक की संभावना के बारे में बाजार की भावना को दर्शाते हैं। जीएफसी के बाद सीडीएस बाजार काफी विकसित हुआ है, जो मानकीकृत कूपनों को व्यापक रूप से अपनाने, सीसीपी पर बढ़ती निर्भरता, अग्रिम प्रीमियम की शुरुआत और सीडीएस सूचकांकों की बढ़ती लोकप्रियता के कारण चिह्नित है³⁷। बड़े पैमाने पर भूराजनीतिक तनाव और आर्थिक अनिश्चितताओं

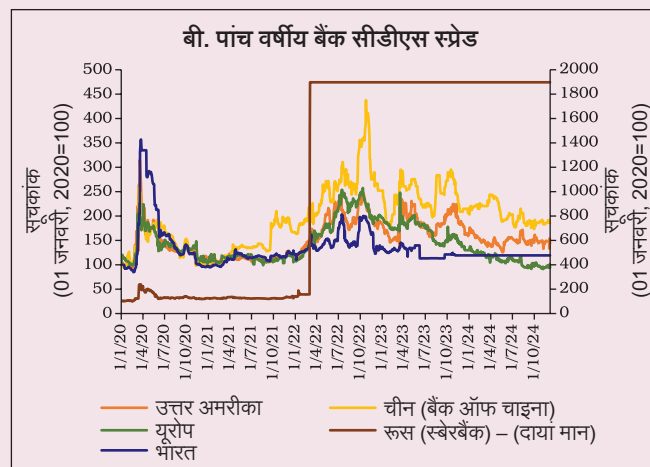
³⁶ <https://www.fitchratings.com/research/sovereigns/argentine-banks-capitalization-mitigates-central-government-exposure-28-02-2023>

³⁷ <https://www.federalreserve.gov/econres/feds/files/2022023pap.pdf>

चार्ट II. 8 बैंकों की सेहत के बाज़ार-आधारित सूचकांक



स्रोत: रिफाइनिटिव डेटास्ट्रीम

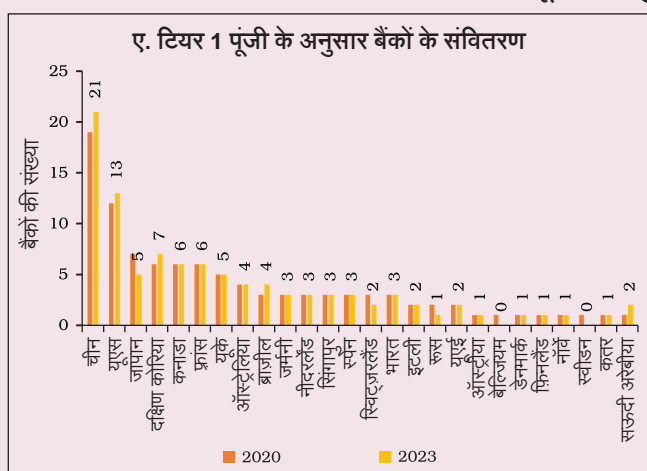


से प्रेरित 2022 में चरम के बाद, सीडीएस स्प्रेड आम तौर पर कम हो गया है, जो बेहतर बाजार रुख दर्शाता है। हालाँकि, रूस का सीडीएस स्प्रेड 2022 के बाद से, एक अपवाद बना हुआ है, जबकि चीन का स्प्रेड अन्य क्षेत्रों की तुलना में ऊंचा बना हुआ है, जो आर्थिक चुनौतियों और वित्तीय क्षेत्र की स्थिरता संबंधी चिंताओं से प्रभावित है (चार्ट II.8 बी)। इन विविधताओं से संकेत मिलता है कि हालांकि वैश्विक बाजारों ने कुछ आत्मविश्वास हासिल कर लिया है, लेकिन क्षेत्र-विशिष्ट जोखिम अभी भी बने हुए हैं।

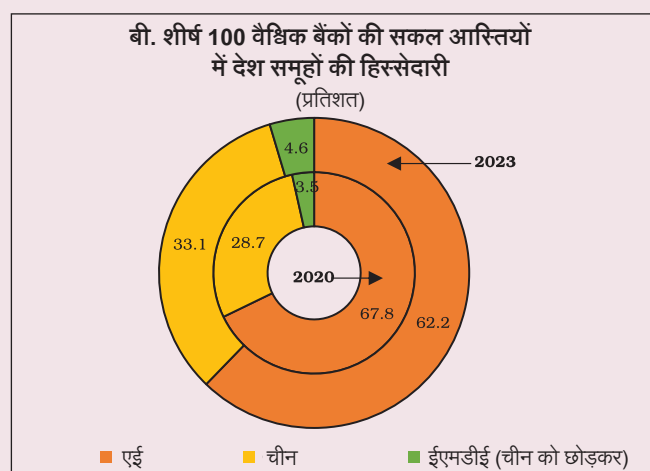
5. विश्व के सबसे बड़े बैंक

II.43 जीएफसी के बाद से टियर 1 पूंजी के आधार पर दुनिया के शीर्ष 100 बैंकों में आई बैंकों की संख्या घट रही है, जबकि चीनी बैंकों की संख्या बढ़कर 2022 और 2023 में 21 पर स्थिर हो गई है (चार्ट II.9ए)। आनुपातिक रूप से, दुनिया के शीर्ष 100 बैंकों की कुल आस्तियों में चीनी बैंकों की हिस्सेदारी बढ़ी है, जबकि आई की हिस्सेदारी घट रही है। ईएमडी की हिस्सेदारी (चीन को छोड़कर) 2022 और

चार्ट II. 9: टियर 1 पूंजी के अनुसार शीर्ष 100 बैंकों का संवितरण



स्रोत: बैंकर डेटाबेस, फाइनेंशियल टाइम्स।

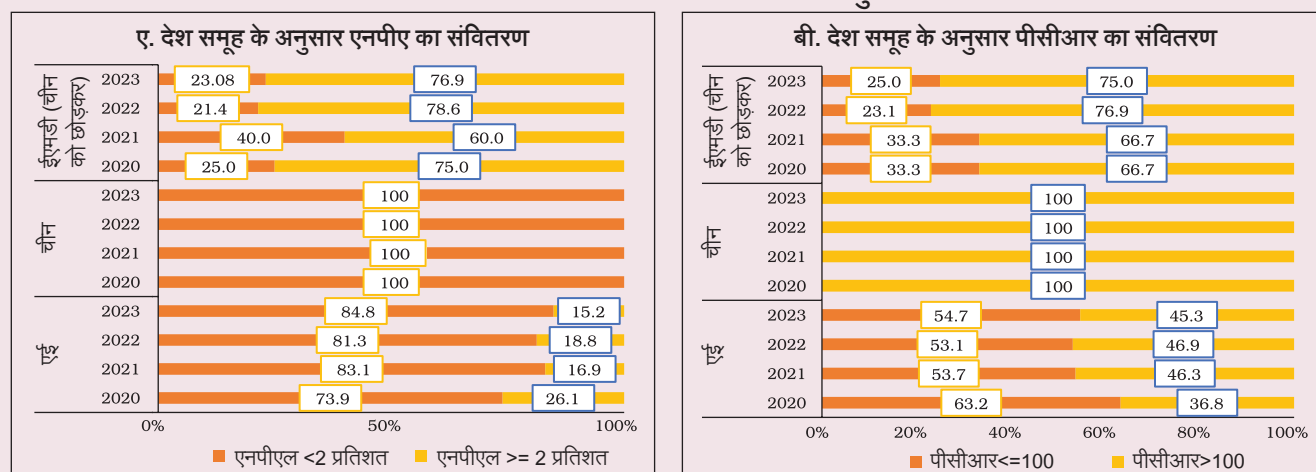


2023 में अपरिवर्तित रही (चार्ट 11.9बी)। दूसरी ओर, आई ने अपना ध्यान अपने स्थानीय बाजारों पर केंद्रित कर दिया और जोखिम एक्सपोजर को नियंत्रित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपनी उपस्थिति कम कर दी³⁸।

11.44 बड़े वैश्विक बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में सुधार हो रहा है। 2 प्रतिशत से अधिक या उसके बराबर एनपीएल अनुपात वाले बैंकों का अनुपात 2022 की तुलना में 2023 में कम हो गया, विशेष रूप से आई और ईएमडीई (चीन को छोड़कर) के लिए। इस बीच, दुनिया के शीर्ष 100 बैंकों की सूची में शामिल सभी चीनी बैंकों ने लगातार अपना एनपीएल अनुपात 2 प्रतिशत से नीचे बनाए रखा (चार्ट 11.10ए)। इसके अतिरिक्त, दुनिया के शीर्ष 100 बैंकों में चीनी बैंकों का पीसीआर 100 प्रतिशत से ऊपर रहा, जो अधिक वित्तीय सुदृढ़ता का संकेत देता है। जिन बैंकों का पीसीआर 100 प्रतिशत से ऊपर था, उनकी हिस्सेदारी 2022 में मामूली रूप से घटकर ईएमडीई के लिए 75 प्रतिशत और आई के लिए 45.3 प्रतिशत हो गई, जो 2023 में क्रमशः 76.9 प्रतिशत और 46.9 प्रतिशत थी (चार्ट 11.10बी)।

11.45 16 प्रतिशत से अधिक या उसके बराबर सीआरएआर आई और ईएमडीई बैंकों के लिए पूंजी पर्याप्तता का मॉडल क्लास था; चीनी बैंकों के लिए, यह कम अर्थात् 12 से 14 प्रतिशत के बीच था (चार्ट 11.11ए)। 6 से 8 प्रतिशत की सीमा में लीवरेज अनुपात (एलआर) को आमतौर पर विवेकपूर्ण माना जाता है और यह श्रेणी चीनी बैंकों के लिए मॉडल क्लास बनी हुई है। ईएमडीई बैंकों में द्वि-मॉडल लीवरेज अनुपात वितरण था जबकि आई बैंकों में 4 से 6 प्रतिशत की सीमा थी (चार्ट 11.11बी)। मौद्रिक नीति सख्त होने के कारण ब्याज दर आय में उछाल ने 2023 में आई और ईएमडीई दोनों में वैश्विक बैंकों की लाभप्रदता को मजबूत करने में मदद की। इसकी तुलना में, कम चीनी बैंकों ने एक से दो प्रतिशत की सीमा में आरओए की सूचना दी (चार्ट 11.11सी)। परिचालन दक्षता बैंकों की सुदृढ़ता के प्रमुख स्तंभों में से एक है, जिसमें लागत-से-आय अनुपात (सीआईआर) एक प्रातिनिधिक संकेतक के रूप में कार्य करता है। 95 प्रतिशत से अधिक चीनी बैंकों का सीआईआर 50 प्रतिशत से कम है, जो अन्य ईएमडीई और आई में बैंकों की तुलना में उच्च परिचालन दक्षता प्रदर्शित करता है (चार्ट 11.11डी)।

चार्ट 11.10: शीर्ष 100 बैंकों की आस्तियों की गुणवत्ता

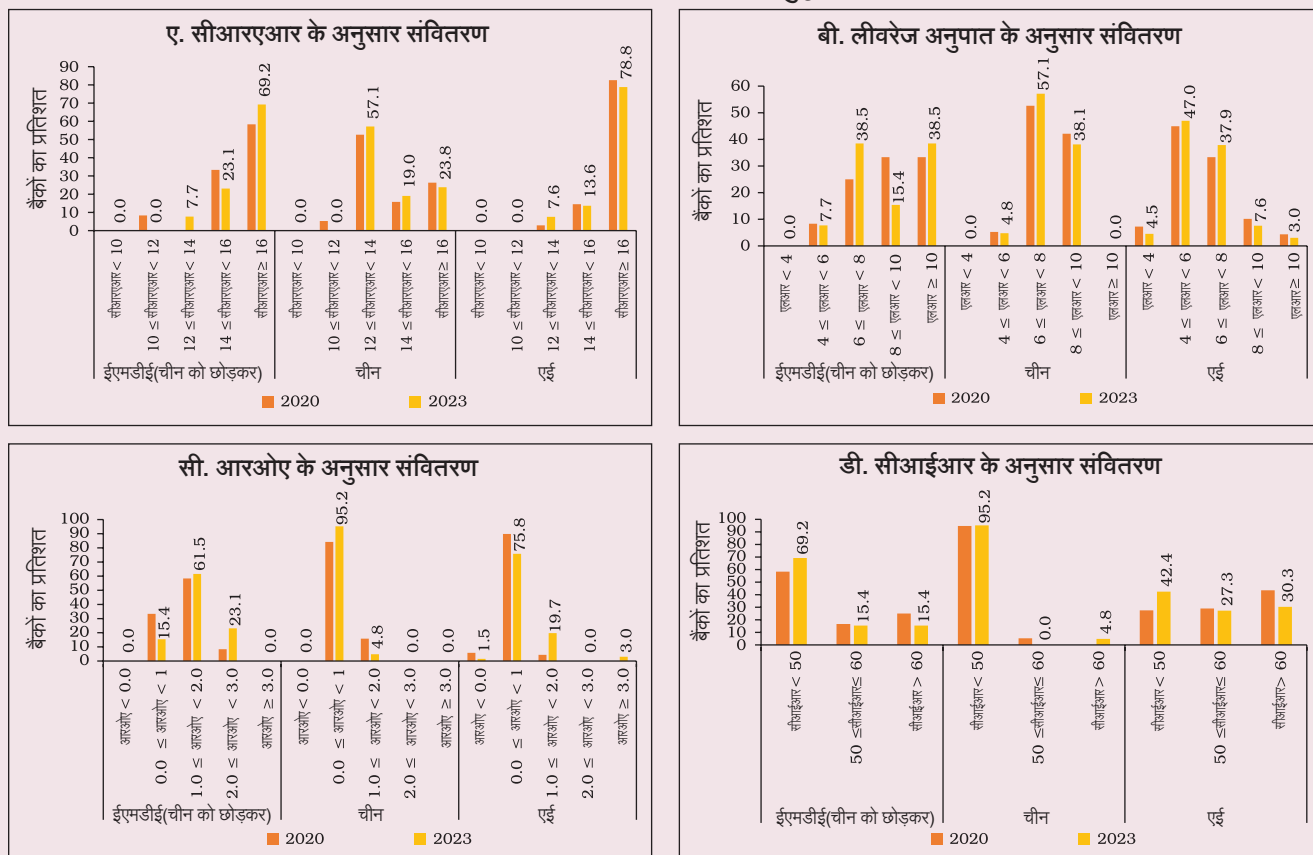


टिप्पणी: लीजेंड्स में दिए गए आंकड़े कुल में बैंकों की प्रतिशत हिस्सेदारी दर्शाते हैं।

स्रोत: बैंकर डेटाबेस, फाइनेंशियल टाइम्स।

³⁸ <https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/a-decade-after-the-global-financial-crisis-what-has-and-hasnt-changed>

चार्ट II.11 शीर्ष 100 बैंकों की सुदृढ़ता



स्रोत: बैंकर डेटाबेस, फाइनेंशियल टाइम्स।

6. समग्र मूल्यांकन

II.46 जैसे-जैसे वैश्विक अर्थव्यवस्था धीमी गति से मुद्रास्फीति लक्ष्यों के करीब पहुंच रही है, कई अर्थव्यवस्थाओं में मौद्रिक प्राधिकारियों ने सहजता चक्र शुरू कर दिया है, जबकि कुछ सख्त मोड में हैं और अन्य ने रोक दिया हैं। ऋण संवृद्धि और

लाभप्रदता में कुछ नरमी के बावजूद वैश्विक बैंकिंग क्षेत्र की वित्तीय स्थिति स्वस्थ बनी हुई है। विकास का समर्थन करते हुए वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए मौद्रिक नीति प्रयासों का समर्थन करने के लिए विवेकपूर्ण और सक्रिय वित्तीय विनियमन और पर्यवेक्षण आवश्यक हैं।

भारत में, मौद्रिक नीति के रुख को अक्तूबर 2024 में 'निभाव वापस लेने' से बदलकर 'तटस्थ' कर दिया गया। रिज़र्व बैंक की विनियामक और पर्यवेक्षी नीतियाँ, जोखिम प्रबंधन पद्धतियों को मजबूत करने, विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों के सामंजस्य और उभरते जोखिमों का समाधान करने पर केंद्रित रहीं। रिज़र्व बैंक ने सुशासन और पारदर्शिता पर जोर देते हुए ग्राहक जागरूकता और वित्तीय समावेशन में सुधार के अपने प्रयासों को जारी रखा।

1. परिचय

III.1 स्थिर समष्टि-आर्थिक परिवेश और कुशल विनियामक और पर्यवेक्षी ढांचे का लाभ उठाते हुए भारतीय वित्तीय प्रणाली, वर्ष 2023-24 और 2024-25 के दौरान विकट वैश्विक चुनौतियों के बावजूद निरंतर सुदृढ़ बनी रही। रिज़र्व बैंक वित्तीय क्षेत्र में उभरते जोखिमों के बारे में सतर्क रहा, साथ ही इस क्षेत्र में नवोन्मेषों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता के प्रति भी सचेत रहा। जलवायु संबंधी जोखिमों का समाधान करने के लिए विनियामक पहलों को मजबूत किया गया। रिज़र्व बैंक, साइबर सुदृढ़ता और विनियमित संस्थाओं (आरई) की रिपोर्टिंग दक्षता में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी का अधिकाधिक उपयोग कर रहा है।

III.2 इस पृष्ठभूमि में, अध्याय के खंड 2 में वर्ष 2023-24 और 2024-25 के दौरान रिज़र्व बैंक के मौद्रिक और चलनिधि प्रबंधन उपायों का संक्षिप्त विवरण दिया गया है, इसके बाद खंड 3 में विनियामक और पर्यवेक्षी नीतिगत प्रगति संबंधी घटनाक्रमों का विवरण दिया गया है। विभिन्न प्रौद्योगिकीय नवोन्मेषों से संबंधित नीतियों को खंड 4 में समाविष्ट किया गया है, जबकि वित्तीय बाजारों से संबंधित नीतियों पर खंड 5 में चर्चा की गई है। खंड 6 और 7 में क्रमशः उपभोक्ता संरक्षण, ऋण वितरण और वित्तीय समावेशन से संबंधित नीतियों की समीक्षा की गई है। खंड 8 में सुरक्षित और संरक्षित परिवेश में भुगतान परितंत्र

के दायरे और पहुंच को बढ़ाने के लिए पहलों का विवरण दिया गया है। खंड 9 में समग्र मूल्यांकन के साथ अध्याय समाप्त होता है।

2. समष्टि आर्थिक नीति निर्धारण

III.3 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने 2022-23 के दौरान 250 आधार अंकों (बीपीएस) की संचयी वृद्धि के बाद, मुद्रास्फीति के लगातार लक्ष्य से ऊपर रहने को ध्यान में रखते हुए 2023-24 और 2024-25 (दिसंबर 2024 तक) के दौरान नीतिगत रेपो दर को अपरिवर्तित 6.50 प्रतिशत बनाए रखा। 09 अक्तूबर 2024 को, एमपीसी ने मुद्रास्फीति-वृद्धि की उभरती गतिशीलता के अपने आकलन के आधार पर मौद्रिक नीति के रुख को 'निभाव वापस लेने' से बदलकर 'तटस्थ' करने का निर्णय लिया। इसके बाद 6 दिसंबर 2024 को, संभावित चलनिधि दबाव को कम करने और तटस्थ नीति रुख के अनुरूप, रिज़र्व बैंक ने सभी बैंकों के नकदी आरक्षित अनुपात (सीआरआर) को निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के 4.0 प्रतिशत तक कम करने का निर्णय लिया, जो 14 दिसंबर और 28 दिसंबर 2024 से शुरू होने वाले पखवाड़े में 25 आधार अंक की प्रत्येक, दो बराबर भागों में प्रभावी होगी। इस प्रकार, सीआरआर अप्रैल 2022 में सख्त नीति चक्र के शुरू होने से पहले के स्तर पर आ गई है।

वर्ष 2023-24 के दौरान के घटनाक्रम

III.4 मौद्रिक नीति रुख के समनुरूप, 2023-24 में प्रणालीगत चलनिधि, अधिशेष से घाटे में परिवर्तित हो गई। चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत औसत दैनिक निवल अंतर्वेशन, वर्ष 2022-23 में ₹1.9 लाख करोड़ के औसत दैनिक निवल अवशोषण की तुलना में 2023-24 में ₹485 करोड़ रह गया। वर्ष 2023-24 के दौरान, स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) के तहत औसत अवशोषण ₹0.90 लाख करोड़ रहा, जो एलएएफ के अंतर्गत औसत दैनिक कुल अवशोषण (₹1.16 लाख करोड़) का 78 प्रतिशत था, जबकि शेष 22 प्रतिशत का अवशोषण, परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो (वीआरआरआर) नीलामियों – मुख्य और सुसंगत परिचालनों दोनों, के माध्यम से किया गया। बैंक ने सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) का उपयोग बढ़ाया है और यह वर्ष 2022-23 के दौरान ₹0.06 लाख करोड़ की तुलना में 2023-24 के दौरान ₹0.50 लाख करोड़ की औसत दैनिक उधारी तक पहुंच गई है।

III.5 बैंकों को उनके परिचालन में अधिक लचीलापन प्रदान करने के उद्देश्य से 30 दिसंबर 2023 से सप्ताहांत और छुट्टियों के दौरान भी एसडीएफ और एमएसएफ दोनों के तहत चलनिधि सुविधाओं के प्रत्यावर्तन की अनुमति दी गई। 19 मई 2023 और 28 जुलाई 2023 के बीच अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की एनडीटीएल में वृद्धि पर 10 प्रतिशत के वृद्धिशील सीआरआर (आई-सीआरआर) को 12 अगस्त 2023 से शुरू होने वाले पखवाड़े से चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया गया था, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रणालीगत चलनिधि को अचानक आघात न पहुंचे और मुद्रा बाजार व्यवस्थित तरीके से काम कर सके।

III.6 भारित औसत मांग दर (डब्ल्यूएसीआर) - मौद्रिक नीति का परिचालन लक्ष्य – 2022-23 में 5.39 प्रतिशत की तुलना में 2023-24 में औसतन 6.63 प्रतिशत रहा, जो

नीतिगत रेपो दर में वृद्धि और बदलती चलनिधि स्थितियों को दर्शाता है। संपार्श्विक खंड में एकदिवसीय दरें, डब्ल्यूएसीआर के अनुरूप रहीं। मीयादी मुद्रा खंड में, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए 3 महीने के वाणिज्यिक पत्रों (सीपी) पर प्रतिफल में मजबूती आई, जो अन्य बातों के साथ-साथ 16 नवंबर 2023 को रिज़र्व बैंक द्वारा घोषित विनियामक उपायों को दर्शाता है। बैंक ऋण में निरंतर दहाई अंकों की वृद्धि के बीच, बैंकों ने जमा प्रमाणपत्र (सीडी) का उपयोग किया। 2023-24 में 3 महीने के खजाना बिल (टी-बिल) पर प्रतिफल स्थिर रहा। हालांकि, मध्यम से दीर्घावधि के बॉण्ड प्रतिफल में मार्च 2023 के स्तर से नरमी आई, जो अमेरिकी ट्रेजरी प्रतिफल में वृद्धि के बावजूद घरेलू गतिविधियों से प्रेरित है। 8 जून 2023 को रिज़र्व बैंक ने एससीबी [लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) और भुगतान बैंकों (पीबी) को छोड़कर] को अपने आंतरिक बोर्डों की स्वीकृति के साथ अंतरबैंक देयताओं के लिए निर्धारित विवेकपूर्ण सीमाओं के भीतर मांग और सूचना पर देय मुद्रा बाजार में उधार लेने के लिए अपनी सीमाएँ निर्धारित करने की अनुमति देकर मुद्रा बाजार परिचालन में अधिक लचीलापन पैदा किया।

वर्ष 2024-25 के दौरान के घटनाक्रम

III.7 वर्ष 2024-25 (17 दिसंबर 2024 तक) के दौरान एलएएफ के तहत औसत दैनिक निवल अवशोषण ₹0.65 लाख करोड़ रहा। जबकि एसडीएफ और रिवर्स रेपो के अंतर्गत औसत दैनिक अवशोषण ₹1.3 लाख करोड़ था, एमएसएफ के तहत औसतन ₹0.07 लाख करोड़ रहा।

III.8 वर्ष 2024-25 (17 दिसंबर 2024 तक) में रेपो दर के अनुरूप डब्ल्यूएसीआर औसतन 6.54 प्रतिशत रहा, जिसमें संपार्श्विक खंडों में एकदिवसीय दरें भी उसी के अनुरूप रहीं। मीयादी मुद्रा खंड में, कम बाजार उधार आवश्यकताओं के बीच बैंकिंग प्रणाली में बेहतर चलनिधि के कारण 3 महीने के टी-बिल पर प्रतिफल में नरमी रही। 2024-25 के दौरान एनबीएफसी

द्वारा जारी सीपी और उनकी सीडी पर प्रतिफल तुलनात्मक रूप से स्थिर रहा। वैश्विक बॉण्ड सूचकांक में भारतीय सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) को शामिल करने और 2024-25 के लिए केंद्र सरकार द्वारा बजट में बाजार उधार आवश्यकताओं को कम करने के बाद सकारात्मक भाव के कारण वर्ष 2024-25 में घरेलू बॉण्ड प्रतिफल में और कमी आई। अमेरिकी खजाना प्रतिफल में कमी और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट जैसे वैश्विक कारकों ने भी घरेलू प्रतिफल में कमी लाने में योगदान दिया।

3. विनियामक और पर्यवेक्षी नीतियां

3.1 परिचालन जोखिम प्रबंधन और परिचालनात्मक सुदृढ़ता

III.9 बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति (बीसीबीएस) के सिद्धांतों के साथ एकीकरण के लिए, 30 अप्रैल 2024 को रिज़र्व बैंक ने परिचालन जोखिम प्रबंधन और परिचालन सुदृढ़ता पर एक मार्गदर्शन नोट जारी किया। यह, आरई को अपनी परिचालन जोखिम प्रबंधन ढांचे को मजबूत करने और व्यवधान के दौरान भी महत्वपूर्ण संचालन करने में सक्षम बनाने के लिए अपनी परिचालन सुदृढ़ता को बढ़ाने हेतु व्यापक मार्गदर्शन प्रदान करता है। मार्गदर्शन नोट तीन स्तंभों पर आधारित है यथा तैयारी और सुरक्षा; सुदृढ़ता बनाना; और सीखना और अपनाना। इन तीन स्तंभों में, नोट में 17 सिद्धांत शामिल हैं। मार्गदर्शन नोट में परिचालन सुदृढ़ता के सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए, रक्षा की तीन पंक्तियाँ; परिवर्तन प्रबंधन, अंतर्संबंधों और अंतरनिर्भरताओं का निर्धारण; अन्य पक्ष पर निर्भरता प्रबंधन और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) जोखिम का समाधान किया गया है। पहले मार्गदर्शन केवल एससीबी पर लागू था, नवीनतम मार्गदर्शन सभी

वाणिज्यिक बैंकों, कतिपय सहकारी बैंकों, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं (एआईएफआई) और आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) सहित सभी एनबीएफसी को समाविष्ट करता है।

3.2 धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन

III.10 रिज़र्व बैंक ने 15 जुलाई 2024 को आरई¹ के लिए धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर मास्टर निदेश जारी किए। संशोधित निदेश, सिद्धांत आधारित और धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन के समग्र अभिशासन और अन्वेक्षा में बोर्ड की भूमिका को मजबूत करते हैं। प्रारंभ में ही धोखाधड़ी का पता लगाने और निवारण के लिए प्रारंभिक चेतावनी संकेतकों और रेड फ्लैग्ड खातों (आरएफए) पर ढांचे को और मजबूत किया गया है, जिसमें विधि प्रवर्तक एजेंसियों (एलईए) और पर्यवेक्षकों को समय पर रिपोर्टिंग आदि शामिल हैं। निदेशों के अनुसार अब आरई से स्पष्ट रूप से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का समय पर अनुपालन सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

3.3 ऋण में मॉडल जोखिम का प्रबंधन

III.11 रिज़र्व बैंक ने 5 अगस्त 2024 को आरई को अपने ऋण प्रबंधन में विभिन्न मॉडलों के उपयोग में विवेक और मजबूती सुनिश्चित करने के लिए एक मसौदा परिपत्र जारी किया था। यद्यपि मॉडलों में प्रौद्योगिकी के प्रयोग से निर्णय लेने में तेज़ी आती है, यह मॉडल जोखिम प्रबंधन ढांचे में जटिलता लाता है। मसौदा परिपत्र के अनुसार, आरई द्वारा प्रयुक्त मॉडल या तो आंतरिक रूप से विकसित हो सकते हैं या बाहरी अन्य-पक्ष आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त किए हो सकते हैं या नीति के प्रावधानों के अनुसार दोनों का मिश्रण हो सकते हैं। आरई को व्यापक सिद्धांतों का पालन करने की आवश्यकता है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उद्देश्यों में स्पष्टता, मजबूत अवधारणाएँ, विस्तृत

¹ वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएँ; सहकारी बैंक (शहरी सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक); और उच्च स्तर, मध्य स्तर और आधार स्तर में शामिल सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (₹500 करोड़ और उससे अधिक के आस्ति आकार वाली), जिनमें आवास वित्त कंपनियाँ भी शामिल हैं।

दस्तावेजीकरण, मॉडलों की मापनीयता और लचीलापन, और सुसंगत और सत्यापन योग्य परिणाम शामिल हैं। आउटसोर्स किए गए मॉडलों की संपूर्णता और परिणामों के लिए अंततः आरई जिम्मेदार और जवाबदेह होंगे। इसके अलावा, आरई को इन-हाउस या अन्यथा विकसित मॉडलों की मजबूती का आकलन करने के लिए मॉडल विकास/चयन से स्वतंत्र एक मॉडल जांच/सत्यापन प्रक्रिया लागू करने की आवश्यकता होगी।

3.4 एनबीएफसी को उपभोक्ता ऋण और बैंक ऋण के संबंध में विनियामक उपाय

III.12 कोविड के बाद, उपभोक्ता ऋण में वृद्धि, विशेष रूप से बेजमानती पोर्टफोलियो में काफी तेजी आई। बैंक उधार पर एनबीएफसी की बढ़ती निर्भरता के कारण परस्पर-संबद्धता बढ़ रही थी। हालाँकि इन ऋण श्रेणियों में दबाव के कोई बड़े संकेत नहीं दिखे, लेकिन इन खंडों में सतत उच्च वृद्धि ने विवेकपूर्ण हस्तक्षेप की आवश्यकता जताई। तदनुसार, रिजर्व बैंक ने 16 नवंबर 2023 को वाणिज्यिक बैंकों और एनबीएफसी के उपभोक्ता ऋण जोखिम, एससीबी की क्रेडिट कार्ड प्राप्ति और एनबीएफसी के प्रति एससीबी का एक्सपोजर, मूल निवेश कंपनियों को छोड़कर, आदि पर जोखिम भार को 25 प्रतिशत अंकों तक बढ़ा दिया। इसके अलावा, आरई को उपभोक्ता ऋण के लिए अपनी जोखिम सीमाओं की समीक्षा करने और विभिन्न उप-खंडों, विशेष रूप से बेजमानती उपभोक्ता ऋण जोखिमों के लिए 29 फरवरी 2024 तक बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीमाएँ लागू करने हेतु सूचित किया गया।

3.5 थोक जमा

III.13 रिजर्व बैंक ने 7 जून 2024 को एसएफबी और एससीबी [क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को छोड़कर] के लिए ₹3 करोड़ और उससे अधिक की एकल रुपया सावधि जमा और स्थानीय क्षेत्र के बैंकों (एलएबी) और आरआरबी के लिए ₹1

करोड़ और उससे अधिक की एकल रुपया सावधि जमा करते हुए थोक जमा की परिभाषा को संशोधित किया। पूर्व में 1 जनवरी 2024 को रिजर्व बैंक ने टियर 3 और 4 अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए थोक जमा सीमा को भी ₹15 लाख और उससे अधिक से बढ़ाकर ₹1 करोड़ और उससे अधिक कर दिया था।

3.6 लघु वित्त बैंकों का स्वैच्छिक रूप से सार्वभौमिक बैंकों में परिवर्तन

III.14 रिजर्व बैंक ने एसएफबी को सार्वभौमिक बैंकों में परिवर्तन के लिए 26 अप्रैल 2024 को पात्रता मानदंड जारी किए। पात्रता मानदंड के अनुसार न्यूनतम पांच वर्ष की अवधि के लिए संतोषजनक कार्य-निष्पादन के रिकॉर्ड सहित एसएफबी का अनुसूचित दर्जा होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, मान्य शेयर बाजार पर एसएफबी के शेयर सूचीबद्ध होने चाहिए। इन एसएफबी के लिए पिछली तिमाही के अंत में न्यूनतम निवल मालियत का ₹1,000 करोड़ होना तथा 15 प्रतिशत के जोखिम भारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) के प्रति निर्धारित पूंजी रखना भी आवश्यक है। इसके अलावा, उनके लिए पिछले दो वित्तीय वर्षों में सकल अनर्जक आस्ति (जीएनपीए) और निवल अनर्जक आस्ति (एनएनपीए) अनुपात क्रमशः 3 प्रतिशत और 1 प्रतिशत से कम या बराबर होना अनिवार्य कर दिया गया है। पात्र एसएफबी को परिवर्तन के लिए एक विस्तृत तर्काधार भी प्रस्तुत करना है।

3.7 क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड

III.15 तीव्रता से बदलते कार्ड परितंत्र के साथ विस्तृत विनियमनों को श्रेणीबद्ध करने के लिए रिजर्व बैंक ने 07 मार्च 2024 को क्रेडिट और डेबिट कार्डों पर अपना मास्टर निदेश संशोधित किया है। रिजर्व बैंक के साथ पंजीकृत सभी बैंकों और एनबीएफसी² को कार्ड जारीकर्ताओं के सह-ब्रांडिंग भागीदार

² एनबीएफसी-निवेश और ऋण कंपनियाँ (एनबीएफसी-आईसीसी), आवास वित्त कंपनियाँ (एचएफसी), एनबीएफसी-फैक्टर, एनबीएफसी-सूक्ष्म वित्त संस्था (एनबीएफसी-एमएफआई) और एनबीएफसी- इंफ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनियाँ (एनबीएफसी-आईएफसी)।

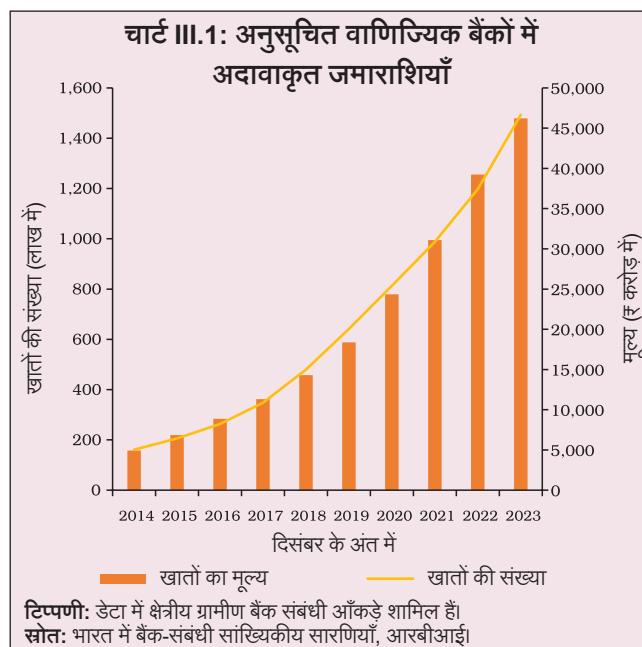
(सीबीपी) बनने की सामान्य अनुमति प्रदान की गई है। अन्य बातों के साथ-साथ, अन्य परिवर्तनों में क्रेडिट कार्डों के लिए प्रतिरूपी साधन (फॉर्म फैक्टर)³ जारी करने की अनुमति, कार्ड जारीकर्ताओं को क्रेडिट कार्ड बकाया के लिए भुगतान स्वीकार करने के लिए उनके द्वारा अधिकृत तरीकों को प्रदर्शित करने संबंधी अधिदेश और व्यावसायिक क्रेडिट कार्ड के लिए धन के अंतिम उपयोग की निगरानी करना शामिल हैं। गलत बिलिंग, ग्राहक की जानकारी साझा करने और कार्ड जारीकर्ताओं को यह सुनिश्चित करने की सूचना देने के संबंध में वर्तमान विनियमनों को भी मजबूत किया गया है कि रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित प्रमाणीकरण ढांचे के अनुसार ही किसी क्रेडिट कार्ड खाते को नामे किया जाए।

3.8 क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए कार्ड नेटवर्क के साथ व्यवस्था

III.16 अधिकृत कार्ड नेटवर्क क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए बैंकों/ गैर-बैंकों के साथ टाई-अप करते हैं। यह देखा गया कि इन विशिष्ट टाई-अप्स में से कुछ के कारण ग्राहकों के लिए नेटवर्क के विकल्प सीमित हो गए हैं। अतः रिजर्व बैंक ने 06 मार्च 2024 को निर्देश दिया कि कार्ड जारीकर्ताओं को कार्ड नेटवर्क के साथ कोई ऐसी व्यवस्था या समझौता नहीं करना चाहिए जो उन्हें अन्य कार्ड नेटवर्क की सेवाओं का लाभ उठाने से रोकता हो। 10 लाख से अधिक सक्रिय कार्डों वाले कार्ड जारीकर्ताओं को अपने पात्र ग्राहकों को कार्ड जारी करने के समय एकाधिक कार्ड नेटवर्क में से चुनने का विकल्प प्रदान करना चाहिए।

3.9 बैंकों में अदावी जमा

III.17 मौजूदा अनुदेशों के अनुसार, बैंकों के पास रखे गए किसी भी जमा खाते में जमा शेष, जिसका दस साल या उससे अधिक समय से संचालन नहीं किया गया है या दस साल या



उससे अधिक समय से अदावाकृत कोई राशि, बैंकों द्वारा रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता (डीईए) निधि में स्थानांतरित करनी आवश्यक है। 2014 से, अदावी जमा राशि की मात्रा लगातार बढ़ रही है (चार्ट III.1)। बैंकिंग प्रणाली में अदावी जमा राशि की मात्रा को कम करने और ऐसी जमा राशि को उनके सही मालिकों या दावेदारों को वापस करने के लिए 1 जनवरी 2024 को बैंकों में निष्क्रिय खातों/अदावी जमा राशियों के लिए व्यापक संशोधित दिशानिर्देश जारी किए गए थे। इन संशोधित अनुदेशों में किए गए प्रमुख बदलावों में, अन्य बातों के साथ-साथ, निष्क्रिय खातों को सक्रिय करने के लिए वीडियो ग्राहक पहचान प्रक्रिया, खाता सक्रिय रखने के लिए कुछ गैर-वित्तीय लेनदेनों और अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) को ग्राहक द्वारा कृत लेनदेन के रूप में मानना, समयबद्ध तरीके से गैर-गृह शाखाओं सहित सभी शाखाओं में निष्क्रिय खाते को सक्रिय करने की सुविधा और ग्राहक द्वारा सक्रिय नहीं करने की स्थिति में निष्क्रिय खातों में नामे लेनदेन को प्रतिबंधित करना शामिल हैं। इस संबंध में, रिजर्व बैंक द्वारा 'अनक्लेमड डिपॉजिट्स - गेटवे टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन (उद्गम)'

³ फॉर्म फैक्टर एक भौतिक या आभासी लिखत है जिसका उपयोग भुगतान या बैंकिंग लेनदेन के लिए कार्ड के स्थान पर किया जा सकता है।

पोर्टल का शुभारंभ ग्राहकों की सहायता करने में एक महत्वपूर्ण आकर्षण रहा है⁴।

3.10 विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) [एफसीएनआर(बी)] जमा पर ब्याज दर की अधिकतम सीमा

III.18 अधिक पूंजी प्रवाह को आकर्षित करने के लिए रिजर्व बैंक ने 6 दिसंबर 2024 को एफसीएनआर (बी) जमाराशियों पर ब्याज दर की अधिकतम सीमा बढ़ा दी। बैंकों को एक वर्ष से लेकर तीन वर्ष से कम की परिपक्वता अवधि वाली नए एफसीएनआर(बी) जमाराशियों को एकदिवसीय वैकल्पिक संदर्भ दर (एआरआर) में पहले के 250 आधार अंकों के योग की तुलना में 400 आधार अंक करने की अनुमति दी गई। तीन से पांच वर्ष की परिपक्वता अवधि वाली जमाराशियों के लिए, अधिकतम सीमा को पूर्व के 350 बीपीएस से बढ़ाकर एकदिवसीय एआरआर में 500 बीपीएस का योग कर दिया गया है। यह छूट 31 मार्च 2025 तक उपलब्ध कराई गई है⁵।

3.11 कारोबारी स्वरूप और निवेश के लिए विवेकपूर्ण विनियमन

III.19 रिजर्व बैंक ने 4 अक्तूबर 2024 को बैंकों द्वारा अपने मुख्य कारोबार को अन्य जोखिम वाले गैर-मुख्य कारोबारों से अलग रखने के लिए व्यवसाय के स्वरूपों पर मसौदा विनियमन जारी किए। विनियमनों के अनुसार, बैंक समूह के भीतर केवल एक इकाई को अनुमेय कारोबार के एक विशेष स्वरूप को करने की अनुमति होगी। बैंक समूह के भीतर एकाधिक इकाइयों को समान कारोबार करने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा, बैंक और उसकी समूह इकाइयों द्वारा की जाने वाली ऋण गतिविधियों में किसी भी अतिव्यापन की अनुमति नहीं होगी। बैंकों की एनबीएफसी अनुषंगी इकाइयों को उच्च स्तर में शामिल एनबीएफसी पर लागू स्केल आधारित विनियमनों का अनुपालन करना होगा और वे बैंकों पर लागू ऋण और

अग्रिमों पर विनियामक और अन्य प्रतिबंधों के अधीन रहेंगी। इसके अतिरिक्त, इसे दोहराया गया है कि किसी समूह इकाई का उपयोग किसी भी कारोबारी गतिविधि को करने के लिए मूल बैंक या अन्य समूह इकाई पर लागू विनियमों/दिशानिर्देशों को दरकिनार करने के लिए नहीं किया जाएगा, जिसकी अन्यथा अनुमति नहीं है।

3.12 वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन

III.20 निवेशों के वर्गीकरण, मापन और मूल्यांकन पर वैश्विक मानकों में महत्वपूर्ण घटनाक्रमों, घरेलू वित्तीय बाजारों में प्रगति के साथ-साथ पूंजी पर्याप्तता ढांचे पर उनके प्रभावों को ध्यान में रखते हुए 12 सितंबर 2023 को बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो के लिए विवेकपूर्ण मानदंडों की समीक्षा की गई थी। निवेश संविभागों का सिद्धांत आधारित वर्गीकरण; परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) को/से अंतरण और एचटीएम से बाहर की बिक्री संबंधी विनियमनों की सख्ती; कुछ शर्तों की पूर्ति के अधीन एचटीएम में गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) प्रतिभूतियों को शामिल करना; एचटीएम पर अधिकतम सीमाओं को हटाना; उचित कीमत पर लाभ और हानियों का बराबर व्यवहार; ट्रेडिंग के लिए धारित (एचटीएफ) के तहत स्पष्ट रूप से पहचान योग्य ट्रेडिंग बही; एचएफटी के तहत धारण अवधि पर 90 दिन की अधिकतम सीमा को हटाना और निवेश पोर्टफोलियो के और अधिक विस्तृत प्रकटन को अद्यतन मानदंडों में शामिल किया गया है। नए दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन के अनुसार बैंकों की निवेश पोर्टफोलियो संरचना के विश्लेषण से पता चलता है कि एचटीएम पोर्टफोलियो में काफी हद तक कोई बदलाव नहीं हुआ है, जबकि एचएफटी पोर्टफोलियो में वृद्धि हुई है और बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) पोर्टफोलियो में कमी आई है। (बॉक्स III.1)।

⁴ रिजर्व बैंक ने 17 अगस्त 2023 को एक केंद्रीकृत वेब पोर्टल - अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स - गेटवे टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन (उद्गम) का शुभारंभ किया, ताकि जनता को एक ही स्थान पर विभिन्न बैंकों में अपनी अदावाकृत जमाराशियों का पता लगाने में सुविधा मिल सके।

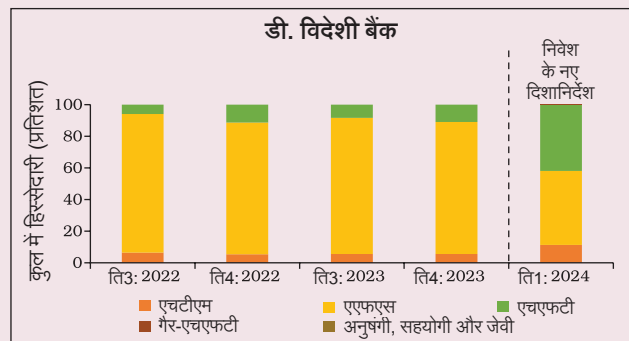
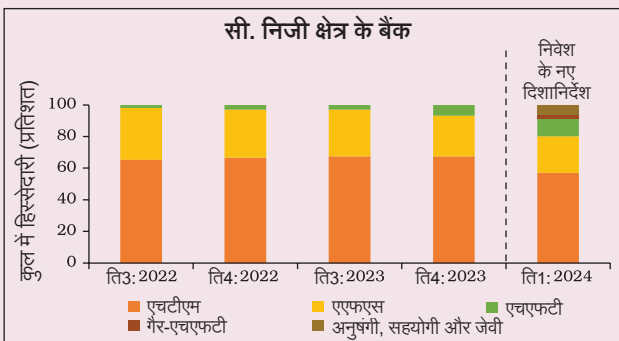
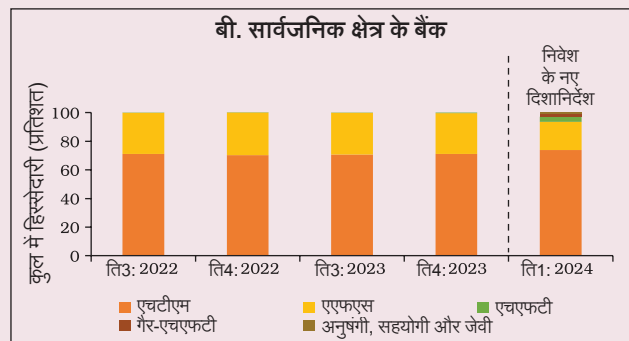
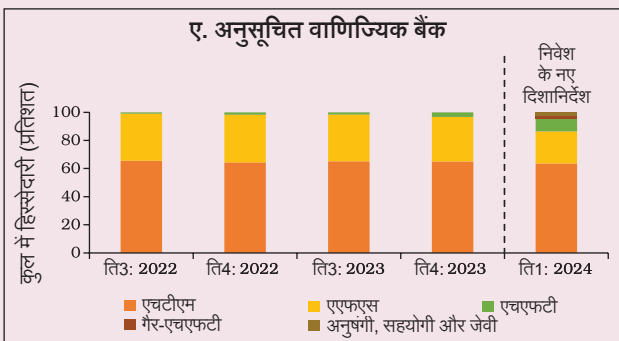
⁵ भारतीय रिजर्व बैंक (2024)। विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य, 6 दिसंबर।

बॉक्स III.1: निवेश के नए दिशानिर्देश: बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का विश्लेषण

वर्ष 2022-23 की तीसरी तिमाही से 2023-24 की चौथी तिमाही के दौरान चुनिंदा एससीबी [12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी); 14 निजी क्षेत्र के बैंक (पीवीबी); और 5 विदेशी बैंक (एफबी)] के कुल निवेश पोर्टफोलियो में एचटीएम श्रेणी का औसत हिस्सा 64.5 प्रतिशत था। नए दिशानिर्देशों को अपनाने के बाद से, यह मोटे तौर पर उसी सीमा - जून 2024 के अंत में 63.6 प्रतिशत, में बना रहा। दूसरी ओर, पुराने दिशानिर्देशों के अनुसार अवशिष्ट श्रेणी वाला एएफएस, जिसकी औसत हिस्सेदारी 33.7 प्रतिशत थी, जो अब घटकर 22.8 प्रतिशत रह गई है, यह मुख्य रूप से संशोधित दिशानिर्देशों में वर्गीकरण पर स्पष्टता को दर्शाती है। एचएफटी श्रेणी की हिस्सेदारी पुरानी व्यवस्था के तहत औसतन 1.8

प्रतिशत थी, वह बढ़कर नए दिशानिर्देशों के अंतर्गत 9 प्रतिशत हो गई है, जिसका श्रेय 90-दिवसीय धारण की अधिकतम सीमा को हटाने के कारण एचएफटी श्रेणी में जाने वाली प्रतिभूतियों और व्युत्पन्नियों के माध्यम से बचाव लाभों को बेहतर ढंग से प्राप्त करने को दिया जा सकता है (चार्ट III.1.1 ए)। बैंक समूहों में, एएफएस की हिस्सेदारी कम हो गई है क्योंकि बैंकों ने अपने पोर्टफोलियो को एचटीएम और एचएफटी श्रेणियों में पुनः आबंटित कर दिया है। पीएसबी की तुलना में पीवीबी और एफबी की एचएफटी श्रेणी की हिस्सेदारी में वृद्धि काफी अधिक थी, जो आंशिक रूप से जोखिम-वहन क्षमता और कारोबारी पद्धति में अंतर को दर्शाती है (चार्ट III.1.1 बी, सी और डी)।

चार्ट III.1.1: बैंकों का निवेश पोर्टफोलियो

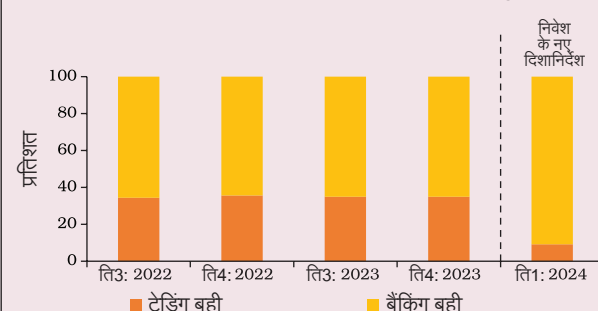


स्रोत: आरबीआई।

पूंजी पर्याप्तता के उद्देश्य के लिए बैंकिंग बही और ट्रेडिंग बही

1 अप्रैल 2024 से संशोधित निवेश मानदंडों के कार्यान्वयन के साथ-साथ, बाजार जोखिमों के लिए पूंजी शुल्क की गणना के उद्देश्य से ट्रेडिंग बही की परिभाषा को भी बीसीबीएस मानकों के अनुरूप संशोधित किया गया था⁶। पूंजीगत प्रभार की गणना के उद्देश्य से अब एएफएस पोर्टफोलियो को एचटीएम पोर्टफोलियो के साथ बैंकिंग बही का हिस्सा माना जा रहा है, पूंजी पर्याप्तता गणना उद्देश्य (एचटीएम+एएफएस) के लिए बैंकिंग बही का आकार बढ़ गया है (चार्ट III.1.2)।

चार्ट III.1.2: बैंकिंग बही की ट्रेडिंग बही से तुलना



स्रोत: आरबीआई।

⁶ बाजार जोखिम के लिए पूंजी प्रभार की गणना के लिए ट्रेडिंग बही जिसमें पहले एएफएस और एचएफटी दोनों शामिल थे, को अब केवल एचएफटी को शामिल करने के लिए संशोधित किया गया है।

बॉक्स III.2: जलवायु-संबंधी वित्तीय जोखिमों पर प्रकटीकरण ढांचा

विनियमित संस्थाओं (आरई) द्वारा जलवायु से संबंधित प्रकटीकरण, जलवायु संबंधी जोखिमों के आकलन और न्यूनीकरण के लिए महत्वपूर्ण है। वर्तमान में आरई को अपने स्तंभ 3 के प्रकटीकरण के रूप में भौतिक जोखिमों की जानकारी का प्रकट करना आवश्यक है। अंतरराष्ट्रीय रूप से स्वीकार्य मानकों के अनुरूप, मसौदा रूपरेखा में प्रकटन मानकों को पंक्तिबद्ध किया गया है। इसके अनुसार आरई को चार विषय-क्षेत्र संबंधी स्तंभों, यानी अभिशासन; कार्यनीति; जोखिम प्रबंधन; और मेट्रिक्स और लक्ष्यों पर आधारित जलवायु संबंधी वित्तीय जोखिमों और अवसरों के विविध पहलुओं पर सूचनाओं का प्रकटन करना आवश्यक है। निम्नलिखित चार विषय-क्षेत्र संबंधी स्तंभों के तहत आरई द्वारा कुछ क्षेत्र कवर करने की आवश्यकता है -

अभिशासन

- जलवायु संबंधी जोखिमों और अवसरों पर बोर्ड की निगरानी
- जलवायु संबंधी जोखिमों और अवसरों का आकलन और प्रबंधन करने में वरिष्ठ प्रबंधन की भूमिका

कार्यनीति

- अल्प, मध्यम और दीर्घ अवधि में जलवायु से संबंधित जोखिम और अवसर।
- जलवायु से संबंधित जोखिमों और अवसरों का आरई के कारोबार, कार्यनीति और वित्तीय योजना पर प्रभाव।

- विभिन्न जलवायु परिदृश्यों को ध्यान में रखते हुए आरई की कार्यनीतिक सुदृढ़ता।

जोखिम प्रबंधन

- जलवायु-संबंधी वित्तीय जोखिमों की पहचान, आकलन, प्राथमिकता, निगरानी और प्रबंधन के लिए प्रक्रियाएं और संबंधित नीतियां।
- परंपरागत जोखिम प्रबंधन के साथ जलवायु-संबंधी जोखिम प्रबंधन का एकीकरण।

मेट्रिक्स और लक्ष्य

- जलवायु संबंधी वित्तीय जोखिमों और अवसरों का आकलन करने के लिए उनकी कार्यनीति और जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं के अनुरूप उपयोग किए जाने वाले मेट्रिक्स और लक्ष्य।
- अवसर 1, अवसर 2 और अवसर 3 ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन और संबंधित जोखिम।
- चूंकि प्रकटीकरण को समग्र परितंत्र के साथ-साथ विकसित करने की परिकल्पना की गई है, इसलिए कार्यान्वयन के लिए प्रयोज्यता और समयसीमा में भी छूट प्रदान की गई है। प्रकटीकरण उचित आंतरिक नियंत्रण आकलन के अधीन है और निदेशक मंडल या बोर्ड की एक समिति द्वारा उनकी समीक्षा करने की आवश्यकता है।

3.13 जलवायु-संबंधी वित्तीय जोखिमों पर प्रकटीकरण ढांचा

III.21 जलवायु-संबंधी जोखिमों से आरई पर गहरा प्रभाव पड़ने की संभावना है, जिससे वित्तीय स्थिरता पर भी असर होगा। जलवायु परिवर्तन जोखिमों के आकलन और न्यूनीकरण के लिए दक्षता और संरचना विकसित करने के लिए आरई हेतु एक विस्तृत, सुसंगत और तुलनीय प्रकटीकरण ढांचा महत्वपूर्ण है। 28 फरवरी 2024 को रिज़र्व बैंक ने हितधारकों से टिप्पणियाँ या प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए जलवायु-संबंधी वित्तीय जोखिमों पर एक मसौदा प्रकटीकरण ढांचा जारी किया (बॉक्स III.2)।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ

3.14 जमा राशि स्वीकार करने वाली आवास वित्त कंपनियाँ (एचएफसी-डी) के लिए विवेकपूर्ण दिशानिर्देश

III.22 एनबीएफसी की तुलना में एचएफसी-डी को जमा स्वीकृति के संबंध में शिथिल विवेकपूर्ण मापदंडों के अधीन रखा

गया। चूंकि एनबीएफसी की सभी श्रेणियों में जमा राशि स्वीकृति से जुड़ी विनियामक चिंताएं समान हैं, इसलिए एचएफसी के दिशानिर्देशों को एनबीएफसी के साथ संरेखित करने के लिए 12 अगस्त 2024 को संशोधित विनियम जारी किए गए। एचएफसी-डी को सार्वजनिक जमा राशियों पर न्यूनतम चल आस्तियाँ बनाए रखने की आवश्यकता होती है, जिसे 13 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है। एचएफसी-डी द्वारा धारित सार्वजनिक जमा राशियों की मात्रा की अधिकतम सीमा को उनकी निवल स्वाधिकृत निधियों के 3 गुना से घटाकर 1.5 गुना कर दिया गया है। इसके अलावा, संशोधित सीमा से अधिक जमा राशि रखने वाले एचएफसी-डी को नई सार्वजनिक जमा राशियाँ स्वीकार करने या मौजूदा जमा को नवीनीकृत करने की अनुमति नहीं होगी, जब तक कि वे संशोधित सीमा के अनुरूप न हों। मौजूदा अतिरिक्त जमा राशियों को परिपक्वता अवधि तक जारी रखने की अनुमति दी जाएगी। एचएफसी-डी की सार्वजनिक जमा राशियों की अधिकतम अवधि भी 120 महीने

⁷ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मानक जैसे कि अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक एस2 जलवायु संबंधी प्रकटीकरण और बैंकिंग पर्यवेक्षण की बासेल समिति का जलवायु प्रकटीकरण के संबंध में परामर्शी दस्तावेज़।

से घटाकर 60 महीने कर दी गई है तथा 60 महीने से अधिक की परिपक्वता अवधि वाली मौजूदा जमाराशियों की उनकी मौजूदा पुनर्भुगतान प्रोफाइल के अनुसार वापसी करनी होगी। इसके अतिरिक्त, एक पृथक परिपत्र के माध्यम से एचएफसी की कुछ आस्तियों के लिए लागू जोखिम भार की भी समीक्षा की गई और उन्हें संशोधित किया गया।

3.15 इरादतन और बड़े चूककर्ता

III.23 इरादतन और बड़े चूककर्ताओं पर मौजूदा अनुदेशों की समीक्षा की गई और 30 जुलाई 2024 को अंतिम मास्टर निदेश जारी किए गए। एससीबी, अनुसूचित यूसीबी, एचएफसी और एआईएफआई के अलावा, इस ढांचे को एनबीएफसी-मध्य स्तर और उससे ऊपर के स्तरों तथा टियर 3 और 4 में गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी), एलएबी और आरआरबी तक विस्तारित किया गया है। इरादतन चूककर्ताओं के वर्गीकरण की प्रक्रिया को ऐसे सभी महत्वपूर्ण तथ्यों और सूचनाओं के प्रकटीकरण को शामिल करके परिष्कृत किया गया है, जिन पर 'कारण बताओ नोटिस' आधारित है, पहचान समिति के आदेश पर समीक्षा समिति के लिए लिखित प्रतिनिधित्व का प्रावधान और समीक्षा समिति द्वारा उधारकर्ता के लिए व्यक्तिगत सुनवाई का प्रावधान है। इरादतन चूक का शीघ्र पता लगाने और पहचान करने के लिए, एनपीए के रूप में वर्गीकरण के छह महीने के भीतर ₹25 लाख और उससे अधिक की बकाया राशि वाले सभी एनपीए खातों की समीक्षा निर्धारित की गई है। इन निदेशों में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) प्रक्रिया के तहत समाधान प्रक्रिया या ऋण समनुदेशन के बाद जान-बूझकर ऋण न चुकाने वाले खातों के उपचार पर भी स्पष्टता प्रदान की गई है।

3.16 एनबीएफसी के लिए संकेंद्रण मानदंडों का सामंजस्य

III.24 वृहत एक्सपोजर ढांचे (एलईएफ) संबंधी दिशानिर्देश, उच्च स्तर में शामिल एनबीएफसी (एनबीएफसी-यूएल) पर

लागू हैं। हालांकि, मध्य स्तर (एनबीएफसी-एमएल) में शामिल एनबीएफसी, क्रेडिट या निवेश संकेंद्रण मानदंडों के अधीन होते हैं। एनबीएफसी के मध्य संकेंद्रण मानदंडों के निर्धारण में एकरूपता और संगतता सुनिश्चित करने के लिए, मौजूदा संकेंद्रण मानदंडों में 15 जनवरी 2024 को संशोधन जारी किया गया था। वर्तमान में अनुमत ऋण चूक स्वैप (सीडीएस) के अतिरिक्त, ये संशोधन एनबीएफसी-एमएल द्वारा कुल जोखिम⁸ को कम करने के लिए अतिरिक्त लिखतों के उपयोग की अनुमति देते हैं। अब एनबीएफसी-मध्य स्तर (बीएल) को क्रेडिट/निवेश संकेंद्रण सीमाएं तय करने के लिए एक बोर्ड-अनुमोदित आंतरिक नीति लागू करने की आवश्यकता होगी।

3.17 आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) द्वारा साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) को सूचना प्रस्तुत करना

III.25 पूर्व दिशानिर्देशों के अनुसार, एआरसी के लिए यह निर्धारित किया गया था कि वे कम-से-कम एक सीआईसी के सदस्य बनें और उस सीआईसी को ऋण संबंधी सूचना प्रदान करें। एआरसी पर लागू सीआईसी से संबंधित दिशानिर्देशों की व्यापक समीक्षा के बाद, रिज़र्व बैंक ने 10 अक्तूबर 2024 को एआरसी द्वारा सीआईसी को सूचना प्रस्तुत करने के संबंध में एक परिपत्र जारी किया। ऐसा एआरसी के लिए सीआईसी से संबंधित दिशानिर्देशों को बैंकों और एनबीएफसी के लिए लागू दिशानिर्देशों के साथ संरेखित करने तथा बैंकों और एनबीएफसी से एआरसी को ऋण हस्तांतरण के बाद उधारकर्ताओं के क्रेडिट इतिहास को ट्रैक करने के लिए किया गया था। इस परिपत्र की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं; (i) एआरसी को सभी चार सीआईसी का सदस्य बनने की सलाह देना; (ii) एआरसी और सीआईसी के बीच सहमति के अनुसार एआरसी द्वारा सीआईसी को पाक्षिक आधार पर या कम अंतराल पर डेटा प्रस्तुत करने का

⁸ इनमें शामिल हैं: ए) अग्रिमों पर उधारकर्ता की ओर से संपार्श्विक के रूप में धारित नकद मार्जिन/जमानती राशि/प्रतिभूति जमाराशि के लिए प्रतिफलन (सेट ऑफ) का अधिकार उपलब्ध है; बी) केंद्र सरकार द्वारा गारंटीकृत दावे, जो पूंजी गणना के लिए 0 प्रतिशत जोखिम भार को आकर्षित करते हैं; सी) राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत दावे, जो पूंजी गणना के लिए 20 प्रतिशत जोखिम भार को आकर्षित करते हैं; डी) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी निधि न्यास (सीजीटीएमएसई), निम्न आय आवास के लिए क्रेडिट जोखिम गारंटी निधि न्यास (सीआरजीएफटीएलआईएच) की क्रेडिट गारंटी योजनाओं और राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) के तहत एकल योजनाओं के अंतर्गत जारी की गई गारंटियां, कतिपय शर्तों को पूरा करने के अधीन हैं।

निर्धारण करना; (iii) सीआईसी से अस्वीकृत आंकड़ों की प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर अस्वीकृत डेटा को सुधारने का निर्देश; (iv) नियमित रूप से डेटा प्रस्तुत करने/अद्यतन करने और ग्राहक शिकायत निवारण के संबंध में सर्वोत्तम प्रथाओं का एआरसी तक विस्तार।

सहकारी बैंक

3.18 प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों के लिए त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) ढाँचा

III.26 रिज़र्व बैंक ने 26 जुलाई 2024 को शहरी सहकारी बैंकों के लिए मौजूदा पर्यवेक्षी कार्रवाई ढाँचे (एसएएफ) के स्थान पर, त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) ढाँचा प्रस्तुत किया। यह ढाँचा 01 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगा तथा सर्व-समावेशी निदेशों के अंतर्गत शामिल शहरी सहकारी बैंकों को छोड़कर, टियर 2, टियर 3 और टियर 4 श्रेणियों के तहत शामिल सभी शहरी सहकारी बैंकों पर लागू होगा। हालांकि, पीसीए ढाँचे के अंतर्गत टियर 1 यूसीबी शामिल नहीं हैं, लेकिन वे मौजूदा पर्यवेक्षी ढाँचे के तहत बढी हुई निगरानी के अधीन होंगे। ढाँचे के अनुसार, वित्तीय रूप से कमजोर शहरी सहकारी बैंकों को अपनी वित्तीय स्थिति को बहाल करने के लिए समय पर सुधारात्मक उपाय शुरू और लागू करने होंगे। इस ढाँचे के तहत सुधारात्मक कार्रवाई शुरू करने के लिए पहली जोखिम सीमा में विनियामक आवश्यकता से (250 आधार अंकों तक) कम सीआरएआर; निवल एनपीए का 6.0 प्रतिशत से अधिक लेकिन 9.0 प्रतिशत से कम होना; और लगातार दो वर्षों के दौरान निवल घाटा होना शामिल है।

3.19 अशोध्य और संदिग्ध कर्ज रिज़र्व का विवेकपूर्ण उपाय

III.27 कई सहकारी बैंकों ने संबंधित राज्य सहकारी समिति अधिनियमों के प्रावधानों के तहत या विवेकपूर्ण विचार कर, लाभ और हानि (पी एंड एल) खाते में व्यय की पहचान कर या निवल लाभ से विनियोजन के माध्यम से अशोध्य और संदिग्ध कर्ज रिज़र्व (बीडीडीआर) को सृजित किया है। निवल लाभ से विनियोजन के मामले में, जब इसका उपयोग एनपीए को

समायोजित करने के लिए किया जाता है तो इससे लागू लेखांकन मानकों का उल्लंघन होता है। इसके अलावा, बैंकों में बीडीडीआर का उपचार अलग-अलग होता है और यह कई मामलों में लागू विनियामक मानदंडों से भिन्न पाया गया है। तदनुसार, व्यवहार में एकरूपता लाने के उद्देश्य से बीडीडीआर पर संशोधित अनुदेश जारी किए गए, जिनमें यह निर्धारित किया गया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 से सभी विनियामक प्रावधानों को अनिवार्य रूप से लाभ और हानि खाते में व्यय के रूप में प्रभारित किया जाएगा। इसके अलावा, निवल लाभ से विनियोजन करके मार्च 2024 के अंत तक सृजित किए गए बीडीडीआर का संशोधित व्यवहार, जो वास्तव में विनियामक प्रावधानों का प्रतिनिधित्व करता है, को भी लेखांकन मानक अनुरूपी दृष्टिकोण में संक्रमण की सुविधा के लिए एकबारगी उपाय के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

3.20 भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शहरी सहकारी बैंकों को शामिल करने के लिए पात्रता मानदंड

III.28 रिज़र्व बैंक ने 17 जनवरी 2024 को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में यूसीबी को शामिल करने के लिए पात्रता मानदंडों को संशोधित किया। वर्ष 2023 में भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट मानदंडों के अलावा, ऐसे यूसीबी जिनका सीआरएआर न्यूनतम विनियामकीय आवश्यकता से कम-से-कम 3 प्रतिशत अधिक है और जिनके संदर्भ में कोई प्रमुख विनियामकीय और पर्यवेक्षी चिंता नहीं है, उनको दूसरी अनुसूची में शामिल करने पर विचार किया जाएगा।

4. प्रौद्योगिकीय नवोन्मेष

III.29 केंद्रीय बैंकों को वित्तीय संस्थाओं में प्रौद्योगिकीय उन्नति को प्रोत्साहित करने और उन्हें असुरक्षाओं से बचाने के साथ, संतुलन बनाए रखने की संवेदनशील चुनौती का सामना करना पड़ता है। वित्तीय सेवाओं में जिम्मेदार नवाचार को प्रोत्साहित करने, दक्षता को बढ़ावा देने और उपभोक्ताओं को लाभान्वित करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने विनियामकीय परीक्षण-स्थल/सैंडबॉक्स (आरएस) स्थापित किए हैं, जो नियंत्रित

विनियामकीय वातावरण में नए उत्पादों या सेवाओं का लाइव परीक्षण करने की अनुमति देते हैं। अब तक खुदरा भुगतान, सीमा-पार भुगतान, एमएसएमई उधार एवं वित्तीय धोखाधड़ी की रोकथाम और न्यूनीकरण विषयों पर चार समूह पूर्ण हो चुके हैं, जिसमें 90 उत्पादों का परीक्षण किया गया, जिनमें से 19 उत्पाद आरएस से सफलतापूर्वक स्वीकृत हुए हैं। वित्तीय क्षेत्र में मौजूदा चुनौतियों के लिए प्रौद्योगिकी संचालित नवोन्मेषी समाधानों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए रिजर्व बैंक प्रत्येक वर्ष 'एचएआरबीआईएनजीईआर' (HaRBInger) नामक एक दीर्घावधि वैश्विक हैकथॉन का आयोजन भी करता है। वर्तमान में 'शून्य वित्तीय धोखाधड़ी' और 'दिव्यांग-अनुकूल होना' पर 'एचएआरबीआईएनजीईआर' जारी है।

4.1 फिनटेक और एम-टेक रिपॉजिटरी

III.30 रिजर्व बैंक ने 28 मई 2024 को फिनटेक रिपॉजिटरी की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य फिनटेक संस्थाओं, उनकी गतिविधियों और प्रौद्योगिकी उपयोग के बारे में आवश्यक जानकारी एकत्र करना है। विनियमित और अविनियमित, दोनों फिनटेक संस्थाओं को रिपॉजिटरी में योगदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। उसी दिन एक एम-टेक रिपॉजिटरी का भी लोकार्पण किया गया, जो विभिन्न विनियमित संस्थाओं द्वारा उभरती प्रौद्योगिकियों [जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), मशीन लर्निंग (एमएल), क्लाउड कंप्यूटिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर प्रौद्योगिकी और क्वांटम प्रौद्योगिकी] को अपनाने के बारे में जानकारी एकत्र करने पर केंद्रित है। ये सभी रिपॉजिटरी फिनटेक पारितंत्र की प्रगति के प्रति बेहतर समझ को सक्षम बनाएंगी और उपयुक्त नीति दृष्टिकोण का समर्थन करेंगी।

4.2 फिनटेक के लिए स्व-विनियामक संगठन (एसआरओ) की रूपरेखा

III.31 फिनटेक क्षेत्र में स्व-विनियमन को प्रोत्साहित करने के लिए, रिजर्व बैंक ने 30 मई 2024 को फिनटेक क्षेत्र (एसआरओ-एफटी) में स्व-विनियामक संगठनों को मान्यता देने के लिए एक रूपरेखा की घोषणा की। ये एसआरओ आचार संहिता तैयार करने, अनुपालन की जांच करने और शिकायतों का निवारण करने के लिए उत्तरदायी होंगे। रूपरेखा में उद्योग संघों को

एसआरओ-एफटी के रूप में मान्यता दिए जाने के मानदंड, उनकी गतिविधियों का दायरा, रिजर्व बैंक के प्रति जिम्मेदारियां और अभिशासन संबंधी आवश्यकताओं को रेखांकित किया गया है। यह रूपरेखा एसआरओ के कार्यों को भी अनिवार्य बनाती है, जिनमें मानक-निर्धारण और विकासात्मक गतिविधियाँ शामिल हैं। फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पॉवरमेंट को एसआरओ-एफटी के रूप में मान्यता दी गई है।

4.3 विनियामक आवेदन, मान्यता, और प्राधिकृति के लिए प्लेटफॉर्म (प्रवाह)

III.32 विनियामक आवेदन, मान्यता, और प्राधिकृति के लिए प्लेटफॉर्म (प्रवाह) का शुभारंभ 28 मई 2024 को हुआ था। यह एक सुरक्षित और केंद्रीकृत वेब-आधारित पोर्टल है, जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति या संस्था रिजर्व बैंक को प्रस्तुत किसी भी संदर्भ पर प्राधिकरण, लाइसेंस या विनियामकीय अनुमोदन प्राप्त कर सकती है। यह विनियमित संस्थाओं (आरई) के लिए कारोबारी सुगमता प्रदान करता है और यह निस्तारण के लिए निष्पादन समय को कम करेगा, जिससे विनियामकीय प्रक्रियाओं में दक्षता बढ़ेगी।

4.4 रिटेल डॉयरेक्ट मोबाइल एप्लिकेशन

III.33 आरबीआई रिटेल डॉयरेक्ट योजना नवंबर 2021 में शुरू की गई, जो वैयक्तिक निवेशकों को रिजर्व बैंक के साथ गिल्ट खाते बनाए रखने और सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने में सक्षम बनाती है। सरकारी प्रतिभूति बाजार में खुदरा निवेशकों के लिए पहुंच को और भी आसान बनाने और सुविधा बढ़ाने के लिए 28 मई 2024 को 'आरबीआई रिटेल डॉयरेक्ट' मोबाइल एप्लिकेशन का सूत्रपात किया गया। इस मोबाइल ऐप में कई उपयोगकर्ता-अनुकूल विशेषताएं हैं, जिनमें एकल साइन-ऑन सुविधा भी शामिल है, जो एक ही लॉग-इन क्रिडेंशियल का उपयोग करके प्राथमिक और द्वितीयक बाजार के बीच सहज नेविगेशन को सक्षम बनाती है।

5. वित्तीय बाजार

III.34 वित्तीय बाजार, संसाधनों के कुशल आबंटन और जोखिमों के वितरण की सुविधा प्रदान करके अर्थव्यवस्था की वृद्धि और

विकास का समर्थन करते हैं। सुरक्षित और स्थिर वित्तीय बाजार विकसित करना रिज़र्व बैंक का एक प्रमुख नीतिगत उद्देश्य है। रिज़र्व बैंक द्वारा विचाराधीन अवधि के दौरान किए गए उपायों में, अन्य बातों के साथ-साथ, मुद्रा बाजार उत्पादों पर निदेशों को युक्तिसंगत बनाना; विदेशी मुद्रा जोखिमों की बचाव-व्यवस्था (हेजिंग) के लिए विनियामक ढांचे की समीक्षा; अकेंद्रीय रूप से समाशोधित डेरिवेटिव (एनसीसीडी) लेनदेनों के लिए प्रारंभिक मार्जिन के विनियम को अनिवार्य बनाना; तथा वित्तीय बाजारों में एसआरओ की मान्यता के लिए ढांचा तैयार करना शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, विनियमित संस्थाओं के एक बड़े समूह को शामिल करने के लिए, तयशुदा लेनदेन प्रणाली-ऑर्डर मिलान (एनडीएस-ओएम) प्लैटफॉर्म तक सीधी पहुँच का विस्तार किया गया।

5.1 एक वर्ष तक की मूल या प्रारंभिक परिपक्वता वाले वाणिज्यिक पत्र और अपरिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी)

III.35 एक वर्ष तक की मूल या प्रारंभिक परिपक्वता वाले वाणिज्यिक पत्रों और अपरिवर्तनीय डिबेंचर पर मौजूदा निदेशों की समीक्षा की गई। दिनांक 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी मास्टर निदेशों ने अन्य बातों के साथ-साथ डिफॉल्ट हैंडलिंग प्रक्रियाओं को युक्तिसंगत बनाया, निर्गम प्रक्रिया को मानकीकृत किया तथा सीपी एवं एनसीडी के लिए प्रकटीकरण आवश्यकता के संदर्भ में मजबूती प्रदान की। इन संशोधनों से विभिन्न मुद्रा बाजार उत्पादों में एकरूपता आने की उम्मीद है, जिससे जारीकर्ताओं, निवेशकों और अन्य भागीदारों को लाभ होगा।

5.2 विदेशी मुद्रा जोखिमों की बचाव-व्यवस्था (हेजिंग)

III.36 विदेशी मुद्रा जोखिमों की हेजिंग के लिए विनियामक ढांचे को जनवरी 2024 में संशोधित किया गया था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अनुमत विदेशी मुद्रा (एफएक्स) डेरिवेटिव उत्पादों के समूह का विस्तार किया गया, उपयोगकर्ता वर्गीकरण ढांचे को परिष्कृत किया गया तथा काउंटर पर (ओटीसी) और एक्सचेंज में खरीदे-बेचे गए सभी प्रकार के विदेशी मुद्रा लेनदेनों के संबंध में पिछले अनुदेशों को एक ही मास्टर निदेश के तहत समेकित किया गया। इससे परिचालन दक्षता में वृद्धि होगी और

विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव तक पहुँच आसान बनेगी, विशेषकर कम एक्सपोजर वाले उपयोगकर्ताओं के लिए। यह आवश्यक जोखिम प्रबंधन क्षमताओं से युक्त उपयोगकर्ताओं के एक बड़े समूह को अपने जोखिमों को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने में भी सक्षम बनाएगा।

5.3 व्युत्पन्नी संविदाओं के लिए मार्जिन

III.37 मौजूदा निदेशों में भारत में निवासी व्यक्ति और भारत के बाहर निवासी व्यक्ति के बीच अनुमत व्युत्पन्नी संविदाओं के लिए मार्जिन की पोस्टिंग और वसूली की अनुमति दी गई थी। अकेंद्रीय रूप समाशोधित डेरिवेटिव के लिए मार्जिन आवश्यकताओं पर ओटीसी डेरिवेटिव सुधारों के कार्यान्वयन को सक्षम करने के लिए, इन निदेशों को 8 मई 2024 को संशोधित किया गया ताकि अन्य बातों के साथ-साथ, उपयुक्त संस्थाओं द्वारा भारत में और भारत से बाहर मार्जिन के आदान-प्रदान की अनुमति दी जा सके। यह भारतीय ढांचे को वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप बनाता है। भारतीय बैंकों को विदेश स्थित अपनी शाखाओं और आईएफएससी बैंकिंग इकाइयों (आईबीयू) के व्युत्पन्नी लेनदेनों के लिए मार्जिन पोस्ट करने और संग्रह करने की भी अनुमति है।

5.4 ट्रेड रिपॉजिटरी को विदेशी मुद्रा नकदी/टीओएम/स्पॉट लेनदेन की रिपोर्टिंग

III.38 प्राधिकृत व्यापारियों को उनके द्वारा सीधे या अपनी विदेशी संस्थाओं के माध्यम से किए गए सभी ओटीसी विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव संविदाओं और विदेशी मुद्रा ब्याज दर डेरिवेटिव संविदाओं की रिपोर्टिंग भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआईएल) की ट्रेड रिपॉजिटरी (टीआर) को करना अनिवार्य है। सभी विदेशी मुद्रा लिखतों के लिए टीआर में लेनदेन संबंधी डेटा की पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने 8 नवंबर 2024 को चरणबद्ध तरीके से विदेशी मुद्रा नकदी/टीओएम/स्पॉट ट्रेड को शामिल करने के लिए रिपोर्टिंग अपेक्षा का विस्तार किया। यह उपाय विदेशी मुद्रा बाजारों के लिए अधिक पारदर्शिता और प्रभावी निगरानी की सुविधा प्रदान करेगा।

6. उपभोक्ता संरक्षण

III.39 उपभोक्ता संरक्षण पर रिजर्व बैंक की नीतिगत पहलों का उद्देश्य ग्राहकों के अधिकारों की सुरक्षा, ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में वृद्धि, जागरूकता बढ़ाना तथा बैंकों और रिजर्व बैंक में शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत बनाना है। उपभोक्ता जागरूकता पहलों के एक भाग के रूप में, रिजर्व बैंक पोस्टर और लघु फिल्मों प्रकाशित करने, वित्तीय साक्षरता सप्ताहों के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने और वित्तीय साक्षरता के लिए केंद्रों (सीएफएल) और वित्तीय साक्षरता केंद्रों (एफएलसी) की स्थापना करने सहित कई पहलें कर रहा है। रिजर्व बैंक ने पुस्तिका शृंखला को जारी रखते हुए वर्ष 2024 में 'दि अलर्ट फैमिली' प्रकाशित की, जो पिछली पुस्तिकाओं से अलग वित्तीय धोखाधड़ी से आगे बढ़ते हुए विभिन्न बैंकिंग सेवाओं और सुविधाओं के संबंध में जनता का मार्गदर्शन करती है।

6.1 विनियमित संस्थाओं के लिए आंतरिक लोकपाल (आईओ)

III.40 रिजर्व बैंक ने 29 दिसंबर 2023 को आंतरिक लोकपाल तंत्र में विभिन्न विनियमित संस्थाओं पर लागू अनुदेशों को सुसंगत बनाने के लिए मास्टर निदेश जारी किए। इससे शिकायतों को आगे आंतरिक लोकपाल तक बढ़ाने की समय-सीमा, आईओ तक शिकायतें भेजने से छूट, आईओ की अस्थायी अनुपस्थिति, आईओ की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता और रिपोर्टिंग प्रारूपों के अद्यतनीकरण जैसे मामलों में एकरूपता आयी है, साथ ही उप आंतरिक लोकपाल का पद भी शुरू किया गया है। इन अनुदेशों से अनुपालन में आसानी के अलावा, ग्राहक शिकायतों की अस्वीकृति से पहले विनियमित संस्था के भीतर शीर्ष स्तरीय प्राधिकारी द्वारा समीक्षा करके तंत्र को और अधिक मजबूत बनाने की उम्मीद है।

7. ऋण वितरण और वित्तीय समावेशन

III.41 राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन कार्यनीति (एनएसएफआई) 2019-24, भारत के वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता

नीतियों के विज्ञान और प्राथमिक लक्ष्यों को रेखांकित करती है, जिनका उद्देश्य वित्तीय क्षेत्र में सभी हितधारकों के बीच व्यापक सहयोग के माध्यम से गति बनाए रखते हुए उनके प्रभाव को बढ़ाना है। पिछले पांच वर्षों में, इस कार्यनीति ने देश में व्यक्तियों और उद्यमों के लिए वित्तीय समावेशन को और अधिक मजबूत करने में सहायता की है तथा डिजिटल वित्तीय सेवाओं के प्रसार और अंगीकरण पर अधिक महत्व दिया है।

7.1 सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) को उधार देना

III.42 रिजर्व बैंक ने 11 जून 2024 को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को उधार देने संबंधी मास्टर निदेशों को अद्यतन किया, जिसमें यह अनिवार्य किया गया कि एमएसई उधारकर्ताओं को ₹25 लाख तक के ऋण देने के लिए क्रेडिट संबंधी निर्णय लेने की समय-सीमा 14 कार्य दिवसों से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस सीमा से अधिक राशि के ऋणों के लिए समय-सीमा, बोर्ड द्वारा अनुमोदित मंजूरी के लिए समय मानदंडों के अनुसार होगी।

III.43 इसके अलावा, एमएसई समूहों को अब सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार अथवा संबंधित राज्य सरकारों द्वारा निर्दिष्ट क्लस्टर/रों के रूप में परिभाषित किया गया है। इन दिशानिर्देशों में उन कार्यकलापों की सांकेतिक सूची दी गई है जो क्रेडिट लिंकेज का गठन करते हैं, जैसे कि इन समूहों के भीतर एमएसई इकाइयों की ऋण आवश्यकताओं का आकलन करना और या तो उनकी ऋण आवश्यकताओं को सीधे पूरा करना अथवा ऋण प्रस्तावों के लिए क्षेत्र में अन्य बैंकों के साथ उनकी सहबद्धता को सुविधाजनक बनाना।

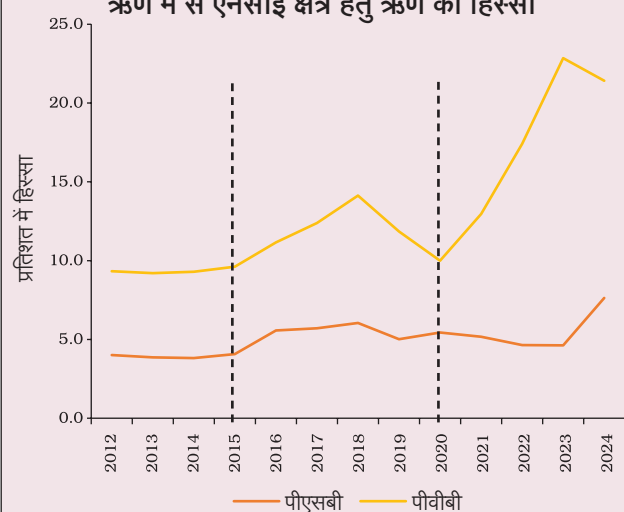
7.2 संपार्श्विक-मुक्त कृषि ऋण की सीमा में वृद्धि

III.44 कृषि निविष्टि लागत और समग्र मुद्रास्फीति में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, रिजर्व बैंक ने 6 दिसंबर 2024 को लघु और सीमांत किसानों के लिए ऋण उपलब्धता को और अधिक बढ़ाने हेतु प्रति उधारकर्ता संपार्श्विक-मुक्त कृषि ऋण की सीमा को ₹1.6 लाख से बढ़ाकर ₹2 लाख करने की घोषणा की।

7.3 प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल)

III.45 रिजर्व बैंक ने 1 जुलाई 2015 को पीएसएल मानदंडों के दायरे का विस्तार करते हुए इनमें सौर आधारित विद्युत जेनरेटर, बायोमास-आधारित विद्युत जेनरेटर, पवन-चक्कियाँ, माइक्रो-हाइड्रल संयंत्र तथा गैर-परंपरागत ऊर्जा (एनसीई) आधारित सार्वजनिक उपयोगिताओं यथा स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम तथा दूरदराज के गांवों में विद्युतीकरण हेतु उधारकर्ताओं के लिए ₹15 करोड़ तक के ऋण शामिल किए थे। यह सीमा बाद में 4 सितंबर 2020 को ₹15 करोड़ से बढ़ाकर ₹30 करोड़ प्रति उधारकर्ता कर दी गई। इन नीतिगत मध्यक्षेपों के साथ अन्य नीतियों के संगम ने गैर-पारंपरिक ऊर्जा (एनसीई) क्षेत्र के लिए उधार को बढ़ावा दिया है (चार्ट III.2 और बॉक्स III.3)।

चार्ट III.2: ऊर्जा क्षेत्र (बिजली, गैस और जल) के लिए कुल ऋण में से एनसीई क्षेत्र हेतु ऋण का हिस्सा



टिप्पणी: आँकड़े मार्च के अंत से संबंधित हैं।

स्रोत: मूलभूत सांख्यिकीय विवरणियाँ, आरबीआई।

बॉक्स III.3: गैर-परंपरागत ऊर्जा क्षेत्र के लिए बैंक ऋण

रिजर्व बैंक की नीतिगत पहलों का गैर-परंपरागत ऊर्जा (एनसीई) क्षेत्र में प्रभाव विश्लेषण, दिसंबर 2014 से दिसंबर 2023 तक के बैंक-वार तिमाही डेटा का उपयोग करके पैनल प्रतिगमन ढाँचे में किया गया है।

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 Y_{it-1} + \beta_2 GNPA_{NCE_{it-1}} + \beta_3 Policy_t + \beta_4 (Policy_t * Bank Group_{it}) + \beta_5 CDR_{it} + \beta_6 GDPgrowthrate_{t-1} + \epsilon_{it}$$

जहाँ तिमाही t में आश्रित चर (Y_{it}) ऊर्जा क्षेत्र को दिए गए कुल ऋण में से बैंक i द्वारा एनसीई को दिए गए ऋण का हिस्सा है; तिमाही $t-1$ में एनसीई क्षेत्र में बैंक i का जीएनपीए अनुपात $GNPA_{NCE_{it-1}}$ है; डमी चर $Policy_{2015_t}$, ति1:2020-21 की तुलना में ति2:2015-16 के लिए 1 का मान और अन्यथा शून्य का मान लेता है; डमी चर $Policy_{2020_t}$ के लिए ति3: 2023-24 की तुलना में ति2: 2020-21 के लिए 1 का मान और अन्यथा शून्य का मान लिया जाता है; पॉलिसी डमी और बैंक समूह डमी के बीच $Policy_t * Bank Group_{it}$ इंटरैक्शन टर्म है (पीएसबी के लिए 0, पीवीबी के लिए 1); तिमाही t में CDR_{it} बैंक i का ऋण-जमा अनुपात है; $GDPgrowthrate_{t-1}$, एक तिमाही के अंतराल के साथ सांकेतिक जीडीपी वृद्धि दर है, जिसे एक समष्टि-आर्थिक उपाय के रूप में सम्मिलित किया गया है। विनिर्देशों में डमी चर के धनात्मक और सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण गुणांक दर्शाते हैं कि दोनों नीतिगत मध्यक्षेप, ऊर्जा क्षेत्र के लिए कुल ऋण में से एनसीई क्षेत्र के लिए ऋण के अंश में वृद्धि से जुड़े थे (सारणी III.3.1)। वर्ष 2015 का नीति मध्यक्षेप पीएसबी के लिए प्रभावी था, जबकि 2020 संबंधी नीति ने एनसीई क्षेत्र के लिए पीवीबी के ऋण को बढ़ाने में मदद की (मॉडल 2)। समष्टि-आर्थिक प्रभावों (मॉडल 3) को नियंत्रित करने के बाद भी प्रतिगमन परिणाम सुदृढ़ बने हुए हैं। इस प्रकार, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र

सारणी III.3.1: प्रतिगमन परिणाम

आश्रित चर (Y) = कुल ऊर्जा क्षेत्र के लिए ऋण (एनसीई/ टीईसी) में से गैर-परंपरागत ऊर्जा क्षेत्र के लिए बैंक ऋण का हिस्सा			
चर	(1)	(2)	(3)
एनसीई/ टीईसी (L1)	0.825*** (0.0613)	0.802*** (0.0536)	0.801*** (0.0541)
एनसीई जीएनपीए अनुपात (L1)	-0.0139 (0.0281)	-0.0255 (0.0297)	-0.0249 (0.0293)
नीति 2015	0.0079 (0.0064)	0.0069** (0.0029)	0.0069** (0.0029)
नीति 2020	0.0219** (0.0090)	0.0007 (0.0050)	0.0011 (0.0047)
नीति 2015 * पीवीबी		0.0045 (0.0100)	0.0044 (0.0100)
नीति 2020 * पीवीबी		0.0406** (0.0158)	0.0406** (0.0158)
ऋण-जमा अनुपात		0.0007 (0.0008)	0.0007 (0.0008)
जीडीपी वृद्धि दर (L1)			0.0002 (0.0003)
स्थिरांक	0.0202* (0.0114)	-0.0298 (0.0678)	-0.0317 (0.0659)
प्रेक्षण	1.095	1.095	1.095
आर स्क्वायर्ड	0.688	0.693	0.693
बैंकों की संख्या	33	33	33
बैंक संबंधी नियत प्रभाव	हाँ	हाँ	हाँ

टिप्पणियाँ: 1) कोष्ठक में सुदृढ़ मानक त्रुटियाँ

2) *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

3) मॉडल 2 और 3 में पीएसबी आधारभूत श्रेणी है; इसलिए, नीति चरों के गुणांक (यथा नीति 2015 और नीति 2020), एनसीई क्षेत्र के लिए पीएसबी के ऋण पर नीतिगत प्रभाव दर्शाते हैं।

स्रोत: आरबीआई स्टाफ अनुमान।

(जारी)

के संदर्भ में नीति परिवर्तन से एनसीई क्षेत्र के लिए ऋण प्रवाह में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि, यह स्वीकारना आवश्यक है कि इस चरण में सरकार द्वारा हरित ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण नीतियां और प्रोत्साहन भी देखे गए। ये परिणाम विभिन्न नीति उपायों और प्रोत्साहनों के संयुक्त प्रभाव को दर्शाते हैं।

संदर्भ:

पोलज़िन, एफ., मिगेंड्ट, एम., ताउबे, एफए, और वॉन फ्लोटो, पी. (2015)। पब्लिक पालिसी इन्फ्लुएंस ऑन रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट्स-ए पैनल डेटा स्टडी अक्रॉस ओईसीडी कंट्रीज़। *एनर्जी पालिसी* वॉल. 80, 98-111।

8. भुगतान और निपटान प्रणालियाँ

III.46 रिज़र्व बैंक अभिनव भुगतान उत्पादों की शुरुआत करने के साथ-साथ, भुगतान और निपटान प्रणाली इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के लिए विभिन्न प्रौद्योगिकी-आधारित समाधान स्थापित करने में अग्रणी रहा है। भारत की त्वरित भुगतान प्रणाली (एफपीएस), एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) की वैश्विक पहुंच विभिन्न देशों के साथ साझेदारी के माध्यम से लगातार बढ़ रही है।

8.1 गैर-बैंक भुगतान प्रणाली परिचालकों (पीएसओ) के लिए साइबर सुदृढ़ता और डिजिटल भुगतान सुरक्षा उपाय

III.47 रिज़र्व बैंक ने 30 जुलाई 2024 को गैर-बैंक पीएसओ के लिए निदेश जारी किए, जिनका उद्देश्य उनकी सूचना सुरक्षा तत्परता और साइबर सुदृढ़ता को बढ़ाना है। ये निदेश सभी प्राधिकृत गैर-बैंक पीएसओ पर लागू होंगे और इन्हें 1 अप्रैल 2025 से बड़ी संस्थाओं से शुरू करके चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।

8.2 भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस)

III.48 बीबीपीएस एक एकीकृत बिल भुगतान प्रणाली है, जो ग्राहकों को अंतर-परिचालनीय और सुविधाजनक भुगतान सेवाएँ प्रदान करती है। भुगतान पारितंत्र के बदलते स्वरूप के आलोक में, रिज़र्व बैंक ने 29 फरवरी 2024 को एक संशोधित विनियामक ढाँचा जारी किया। कुछ प्रमुख बदलावों में, अन्य बातों के साथ-साथ, सभी प्राधिकृत गैर-बैंक भुगतान एग्रीगेटर के लिए भागीदारी मानदंड का विस्तार करना; अंतर-परिचालनीयता को बढ़ाने के उपाय; ग्राहक सुरक्षा उपाय और

गैर-बैंक भारत बिल भुगतान परिचालन इकाइयों (बीबीपीओयू) के लिए एस्करो खाते की आवश्यकता शामिल हैं।

8.3 डिजिटल भुगतान लेनदेन के लिए वैकल्पिक अधिप्रमाणन व्यवस्था पर रूपरेखा

III.49 रिज़र्व बैंक ने 31 जुलाई 2024 को डिजिटल भुगतान लेनदेन के लिए वैकल्पिक अधिप्रमाणन व्यवस्था पर मसौदा रूपरेखा जारी की। रूपरेखा के अनुसार, सभी डिजिटल भुगतान लेनदेनों को अतिरिक्त अधिप्रमाणन कारक/कों (एएफए) के साथ प्रमाणित किया जाएगा, जिनमें से किसी एक अधिप्रमाणन कारक को गतिशील रूप से सृजित किया जाना चाहिए⁹। इसके अतिरिक्त, किसी लेनदेन के लिए उपयुक्त एएफए को तय करने के लिए, ग्राहक और/या लाभार्थी के जोखिम प्रोफाइल, लेनदेन मूल्य और उद्भव-चैनल जैसे कारकों के आधार पर जोखिम-आधारित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है।

8.4 यूपीआई के माध्यम से पूर्व-स्वीकृत ऋण-व्यवस्था (क्रेडिट लाइन)

III.50 रिज़र्व बैंक ने सितंबर 2023 में पूर्व-स्वीकृत ऋण-व्यवस्था को यूपीआई के माध्यम से लिंक करने तथा भुगतान बैंकों (पीबी), लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को छोड़कर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) द्वारा इसका वित्तपोषण खाते के रूप में उपयोग करने की अनुमति दी थी। रिज़र्व बैंक ने 6 दिसंबर 2024 को घोषणा की कि एसएफबी को भी इस सुविधा का विस्तार करने की अनुमति दी जाएगी। इससे वित्तीय समावेशन को और मजबूती मिलेगी और औपचारिक ऋण में वृद्धि होगी, विशेष रूप से 'पहली बार ऋण लेने वाले' ग्राहकों के लिए।

⁹ भुगतान की शुरुआत होने के बाद गतिशील रूप से सृजित कारक उत्पन्न होता है, जो लेनदेन-विशिष्ट होता है तथा इसका पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता।

9. समग्र मूल्यांकन

III.51 प्रौद्योगिकीय नवोन्मेषों, उपभोक्ताओं की बदलती पसंद और वैकल्पिक कारोबारी मॉडलों के उद्भव से प्रेरित होकर, वित्तीय परिदृश्य में वैश्विक स्तर पर और साथ ही भारत में भी नाटकीय परिवर्तन देखने को मिल रहा है। जहाँ इन घटनाक्रमों ने प्रतिस्पर्धा और सहयोग को बढ़ावा दिया है, वहीं वे ग्राहक सुरक्षा और पर्याप्त विनियामकीय निगरानी के बारे में चिंताएँ भी बढ़ाते हैं। वर्ष 2023-24 और 2024-25 के दौरान, रिज़र्व बैंक ने सक्रिय और विवेकपूर्ण विनियामकीय और पर्यवेक्षी नीतियों को आगे भी जारी रखा, जिनमें विनियमित संस्थाओं की सुदृढ़ता, उपभोक्ता संरक्षण, शिकायत निवारण तंत्र, वित्तीय

समावेशन, जलवायु जोखिमों के न्यूनीकरण, डिजिटलीकरण और नवोन्मेष को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया। विनियमित संस्थाओं (आरई) की सुदृढ़ वित्तीय स्थिति ने उन्हें प्रौद्योगिकी को अपनाते हुए अर्थव्यवस्था की उत्पादक गतिविधियों का वित्तपोषण करने में सक्षम बनाया। अपने विनियामक ढांचों में परामर्शात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए और भारतीय बैंकिंग प्रथाओं को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाते हुए, रिज़र्व बैंक वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने और वित्तीय क्षेत्र की दक्षता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसका उद्देश्य एक लचीले और मजबूत विनियामक ढांचे के माध्यम से एक सुदृढ़ वित्तीय क्षेत्र को तराशना है ताकि स्थिरता के साथ संवृद्धि को बढ़ावा दिया जा सके।

IV

वाणिज्यिक बैंकों का परिचालन और प्रदर्शन

वर्ष 2023-24 के दौरान भारत में वाणिज्यिक बैंकों का समेकित तुलन पत्र मजबूत रहा, जिसमें ऋण और जमाराशि दोनों में निरंतर वृद्धि उल्लेखनीय है। सभी बैंक समूहों में आस्ति गुणवत्ता में वृद्धि देखी गई। पूंजी और चलनिधि बफर, विनियामकीय आवश्यकताओं से काफी ऊपर रहे और लाभप्रदता में लगातार छठे वर्ष सुधार हुआ।

1. परिचय

IV.1 भारतीय वाणिज्यिक बैंकिंग क्षेत्र ने 2023-24 और 2024-25 की पहली छमाही के दौरान निरंतर मजबूती दिखाई। मजबूत ऋण वृद्धि¹ के कारण अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के समेकित तुलन पत्र में द्विअंकीय विस्तार हुआ। बैंकों की लाभप्रदता लगातार छठे वर्ष बढ़ी और सकल अनर्जक आस्ति (जीएनपीए) अनुपात के मार्च 2024 के अंत में 13 वर्षों में न्यूनतम 2.7 प्रतिशत पर आने के कारण आस्ति गुणवत्ता में और सुधार हुआ। बैंकों की पूंजीगत स्थिति संतोषजनक रही, जैसा कि उनके लीवरेज और जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) से परिलक्षित होता है। सभी बैंक समूहों ने उच्च प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) बनाए रखते हुए चलनिधि से संबंधित विनियामक आवश्यकताओं को पूरा किया।

IV.2 उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, इस अध्याय को 17 खंडों में संयोजित किया गया है। खंड 2 में तुलन पत्र से संबंधित गतिविधियों का विश्लेषण किया गया है, इसके बाद खंड 3 और 4 में क्रमशः बैंकों के वित्तीय प्रदर्शन और वित्तीय सुदृढ़ता का आकलन किया गया है। खंड 5 बैंक ऋण और इसकी क्षेत्रक-वार गतिशीलता पर केंद्रित है। खंड 6 में वाणिज्यिक बैंकों में

स्वामित्व के स्वरूप पर चर्चा की गई है। कॉरपोरेट अभिशासन और मुआवजा प्रथाओं को खंड 7 में प्रस्तुत किया गया है। भारत में विदेशी बैंकों के परिचालन और भारतीय बैंकों के विदेशी परिचालन को खंड 8 में शामिल किया गया है। इसके बाद भुगतान प्रणालियों (खंड 9), बैंकों द्वारा प्रौद्योगिकी का अंगीकरण (खंड 10), उपभोक्ता संरक्षण (खंड 11) और वित्तीय समावेशन (खंड 12) से संबंधित घटनाक्रमों को शामिल किया गया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी), स्थानीय क्षेत्र के बैंकों (एलएबी), लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) और भुगतान बैंकों (पीबी) से संबंधित गतिविधियों की चर्चा खंड 13 से 16 तक में की गई है। खंड 17 में घरेलू वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली के समग्र मूल्यांकन के साथ अध्याय का समापन किया गया है।

2. तुलन पत्र का विश्लेषण

IV.3 मार्च 2024 के अंत में, भारत के वाणिज्यिक बैंकिंग क्षेत्र में 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी), 21 निजी क्षेत्र के बैंक (पीवीबी), 45 विदेशी बैंक (एफबी), 12 लघु वित्त बैंक (एसएफबी), छः भुगतान बैंक (पीबी), 43 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) और दो स्थानीय क्षेत्र बैंक (एलएबी) शामिल थे। इन 141 वाणिज्यिक बैंकों में से 137 को अनुसूचित बैंकों के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जबकि चार गैर-अनुसूचित थे²।

¹ इस पूरे अध्याय में, जब तक कि स्पष्ट रूप से अन्यथा न कहा जाए, जुलाई 2023 से सभी वाणिज्यिक बैंकों और निजी क्षेत्र के बैंकों के डेटा में एक गैर-बैंक का एक निजी क्षेत्र के बैंक के साथ विलय शामिल है और इसलिए डेटा पिछली अवधियों से पूरी तरह तुलनीय नहीं हो सकता है।

² एससीबी को आरबीआई अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किए जाने या अन्यथा के आधार पर अनुसूचित और गैर-अनुसूचित में वर्गीकृत किया गया है। मार्च 2024 के अंत में, दो पीबी- जियो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड और एनएसडीएल पेमेंट्स बैंक लिमिटेड और दो एलएबी- कोस्टल लोकल एरिया बैंक लिमिटेड और कृष्णा भीमा समृद्धि एलएबी लिमिटेड गैर-अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक थे।

IV.4 आरआरबी को छोड़कर एससीबी के समेकित तुलन पत्र में 2023-24 के दौरान 15.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई (विलय के प्रभाव सहित³), जबकि 2022-23 के दौरान यह 12.2 प्रतिशत थी (परिशिष्ट सारणी IV.1)। आस्तियों के मामले में, यह विस्तार बैंक ऋण में वृद्धि के कारण हुआ, जो एक साल पहले 17.4 प्रतिशत की वृद्धि के अलावा 2023-24 में 16.0 प्रतिशत बढ़ा (विलय के प्रभाव को छोड़कर)। एससीबी के निवेश में 2023-24 में 11.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई (विलय के प्रभाव को छोड़कर) जबकि एक साल पहले यह 11.4 प्रतिशत थी⁴ (चार्ट IV.1)।

IV.5 एससीबी की समेकित तुलन पत्र में पीएसबी की हिस्सेदारी मार्च 2023 के अंत में 57.6 प्रतिशत से घटकर मार्च 2024 के अंत में 55.2 प्रतिशत हो गई, जबकि पीवीबी की हिस्सेदारी 34.7 प्रतिशत से बढ़कर 37.5 प्रतिशत

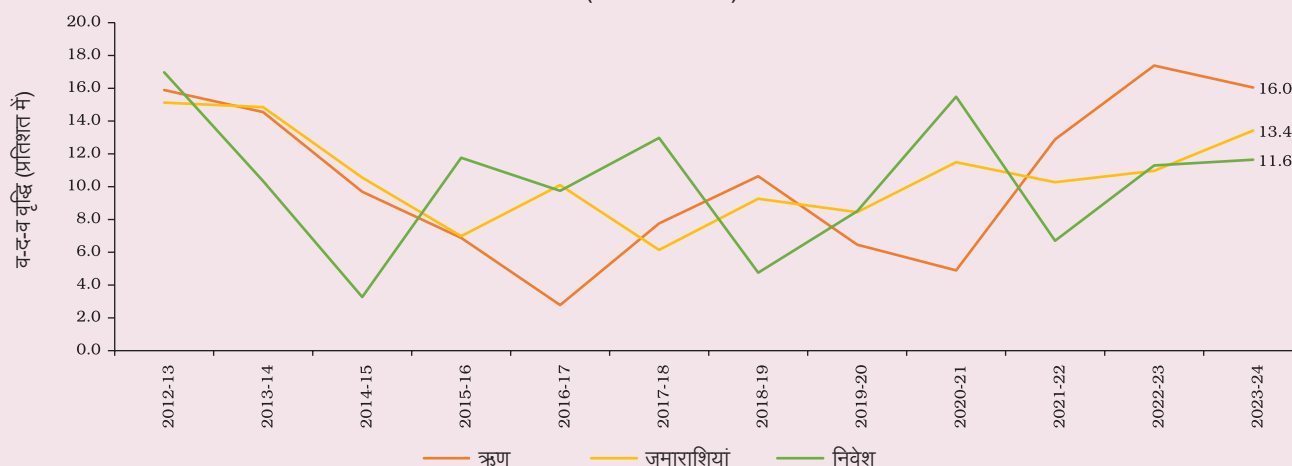
हो गई। एससीबी की कुल जमाराशियों में पीएसबी की हिस्सेदारी 59.3 प्रतिशत और कुल अग्रिमों में 55.5 प्रतिशत थी (सारणी IV.1)।

IV.6 एससीबी की कुल आस्तियों में ऋण और अग्रिमों की हिस्सेदारी 2023-24 के दौरान 2.2 प्रतिशत अंक बढ़ गई (चार्ट IV.2)।

2.1 देयताएं

IV.7 वाणिज्यिक बैंकों की जमाराशि वृद्धि 2023-24 में 13.4 प्रतिशत हो गई (विलय प्रभाव को छोड़कर)⁵ जो एक साल पहले 11.0 प्रतिशत थी। पीवीबी के नई जमाराशियों पर भारित औसत घरेलू सावधि जमा दर (डब्ल्यूएडीटीडीआर) मार्च 2022 के अंत में 4.5 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2024 के अंत में 6.6 प्रतिशत हो गई। उच्च सावधि जमा दरों ने चालू खाता और बचत खाता (सीएसए) जमाराशियों के

चार्ट IV.1: एससीबी की चुनिंदा समग्र राशियां
(मार्च के अंत में)



टिप्पणी: 2023-24 के लिए ऋण, जमाराशि और निवेश वृद्धि में किसी गैर-बैंक का निजी बैंक के साथ विलय का प्रभाव शामिल नहीं है।
स्रोत: संबंधित बैंकों के वार्षिक लेखा।

³ इस पूरे अध्याय में, विलय का तात्पर्य एक गैर-बैंक के एक निजी क्षेत्र के बैंक के साथ विलय से है।

⁴ विलय के प्रभाव को शामिल करते हुए, 2023-24 में बैंक ऋण और निवेश में क्रमशः 19.7 प्रतिशत और 13.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

⁵ विलय के प्रभाव को शामिल करते हुए 14.0 प्रतिशत।

भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति संबंधी रिपोर्ट 2023-24

सारणी IV.1: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का समेकित तुलन पत्र (मार्च के अंत में)

(राशि ₹ करोड़)

मद	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक		निजी क्षेत्र के बैंक		विदेशी बैंक		लघु वित्त बैंक		भुगतान बैंक		सभी एससीबी	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
1. पूंजी	71,176	72,877	32,468	32,832	1,11,612	1,18,603	7,811	7,844	4,512	5,001	2,27,580	2,37,158
2. आरक्षित निधि और अधिशेष	8,24,250	9,56,917	9,34,791	12,14,082	1,60,606	1,80,023	23,557	32,957	-2,404	-2,365	19,40,800	23,81,614
3. जमाराशियां	1,17,09,581	1,28,96,766	62,99,318	75,61,502	8,55,825	10,08,095	1,91,340	2,50,896	12,174	16,184	1,90,68,238	2,17,33,443
			(74,51,388)								(2,16,23,329)	
3.1. मांग जमाराशियां	7,48,951	8,00,416	8,85,492	9,88,296	2,89,545	3,46,863	7,429	10,895	393	76	19,31,810	21,46,546
3.2. बचत बैंक जमाराशियां	39,79,202	41,83,455	18,89,846	20,23,962	56,931	57,827	54,668	59,691	11,781	16,108	59,92,427	63,41,043
3.3. मीयादी जमा	69,81,428	79,12,895	35,23,981	45,49,244	5,09,349	6,03,405	1,29,243	1,80,310	-	-	1,11,44,001	1,32,45,854
4. उधारियां	9,03,824	10,24,003	8,12,969	12,84,429	2,08,739	2,03,073	31,190	28,255	519	713	19,57,241	25,40,474
5. अन्य देयताएं और प्रावधान	5,05,949	5,42,671	3,65,924	4,28,526	2,30,921	1,96,198	13,619	15,331	8,156	5,135	11,24,570	11,87,862
कुल देयताएं/ आस्तियां	1,40,14,781	1,54,93,234	84,45,470	1,05,21,372	15,67,704	17,05,993	2,67,517	3,35,284	22,957	24,668	2,43,18,429	2,80,80,550
1. आरबीआई के पास नकद और शेष राशि	6,41,731	6,18,769	4,13,201	5,32,690	93,411	1,05,980	17,840	17,503	2,295	3,004	11,68,479	12,77,947
2. बैंकों के पास जमा शेष और मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	4,23,343	4,34,252	2,36,116	1,89,051	1,19,332	74,865	4,530	6,305	4,963	4,313	7,88,284	7,08,785
3. निवेश	38,17,201	40,50,865	18,75,137	23,23,647	6,74,077	8,07,328	58,062	74,239	12,064	14,286	64,36,540	72,70,365
			(22,33,887)								(71,80,604)	
3.1 सरकारी प्रतिभूतियों में (ए+बी)	32,22,899	34,84,382	15,87,677	19,88,718	6,31,129	7,33,803	52,137	63,824	12,049	14,271	55,05,891	62,84,999
ए) भारत में	31,65,076	34,23,192	15,73,022	19,73,422	5,88,166	7,25,476	52,137	63,824	12,049	14,271	53,90,449	62,00,185
बी) भारत के बाहर	57,824	61,190	14,655	15,296	42,963	8,327	-	-	-	-	1,15,442	84,814
3.2 अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियों में	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5
3.3 गैर-स्वीकृत प्रतिभूतियों में	5,94,296	5,66,477	2,87,460	3,34,929	42,948	73,525	5,925	10,415	15	15	9,30,644	9,85,361
4. ऋण और अग्रिम	82,83,763	95,06,329	53,66,673	68,61,388	4,91,029	5,48,474	1,77,887	2,26,148	-	-	1,43,19,353	1,71,42,340
			(63,36,115)								(1,66,17,066)	
4.1 खरीदे और भुनाए गए बिल	2,84,863	3,57,393	1,34,836	1,50,780	65,506	84,506	872	1,444	-	-	4,86,077	5,94,124
4.2 नकदी ऋण, ओवरड्राफ्ट, आदि	29,10,286	33,64,717	16,98,188	19,67,085	2,07,287	2,39,685	18,266	26,966	-	-	48,34,027	55,98,453
4.3 मीयादी ऋण	50,88,614	57,84,218	35,33,648	47,43,524	2,18,236	2,24,283	1,58,750	1,97,738	-	-	89,99,248	1,09,49,763
5. अचल आस्तियां	1,15,288	1,18,864	49,347	56,755	5,624	5,956	2,735	3,353	564	1,189	1,73,558	1,86,117
6. अन्य आस्तियां	7,33,456	7,64,154	5,04,997	5,57,840	1,84,230	1,63,390	6,463	7,736	3,070	1,876	14,32,216	14,94,997

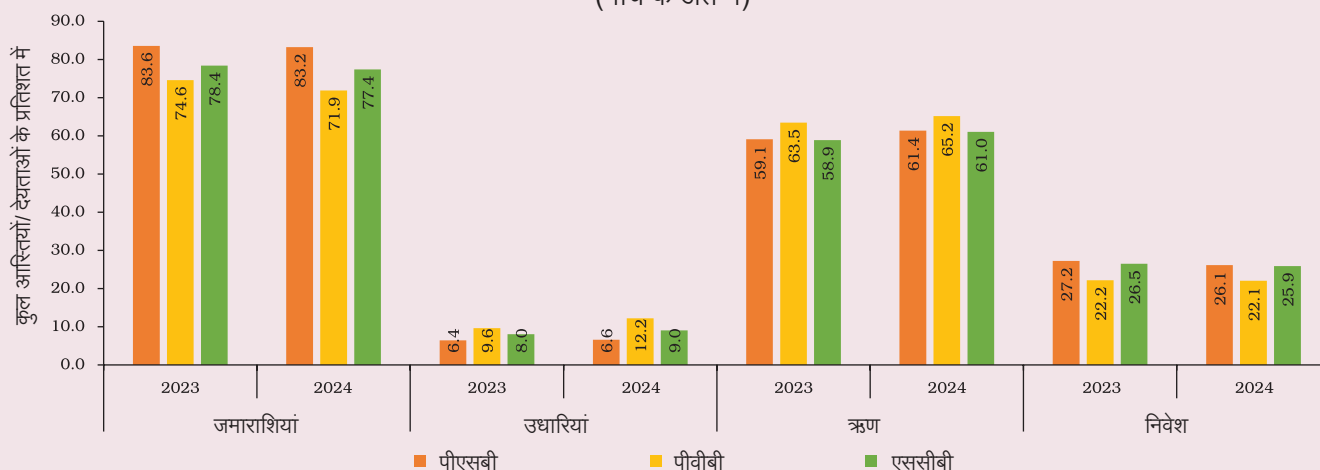
टिप्पणियां : 1. -: शून्य/ नगण्य।

2. वार्षिक खातों पर विस्तृत बैंक-वार डेटा एकत्र कर 'भारत में बैंकों से संबंधित सांख्यिकीय सारणियाँ' प्रकाशित की जाती हैं, जो <https://data.rbi.org.in> पर उपलब्ध हैं।

3. कोष्ठक में दिए गए डेटा में किसी गैर-बैंक के बैंक में विलय के प्रभाव को शामिल नहीं किया गया है। अन्य सभी डेटा में विलय के प्रभाव को शामिल किया गया है।

स्रोत : संबंधित बैंकों के वार्षिक लेखा।

चार्ट IV.2 : तुलन पत्र की संरचना
(मार्च के अंत में)



स्रोत: संबंधित बैंकों के वार्षिक लेखा।

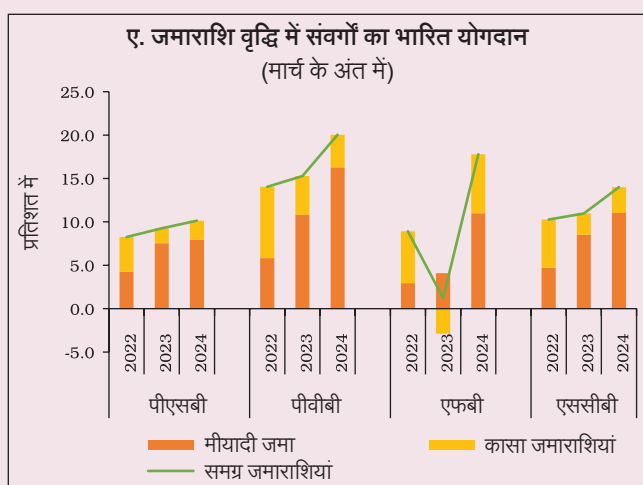
सापेक्ष सावधि जमाओं में वृद्धि की गति को तेज़ कर दिया (चार्ट IV.3)। लंबी अवधि में ब्याज दरों के बजाय आर्थिक गतिविधि का समग्र स्तर जमाशायी वृद्धि को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है (बॉक्स IV.1)।

2.2 आस्तियां

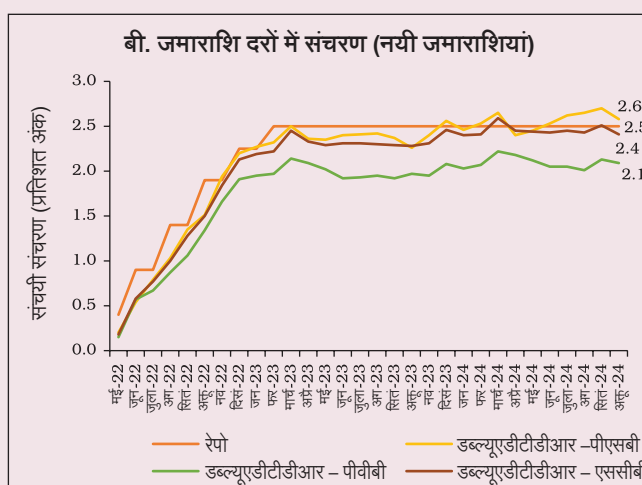
IV.8 आर्थिक गतिविधियों में तेजी के कारण 2023-24 के

दौरान ऋण वृद्धि मजबूत रही⁶ (चार्ट IV.4ए)। मौद्रिक नीति रुख को दर्शाते हुए भारित औसत उधार दर (डब्ल्यूएलआर) वर्ष के दौरान स्थिर रही। नए ऋणों पर उधार दर में संचरण सामान्यतः पीवीबी की तुलना में पीएसबी के लिए अधिक था (चार्ट IV.4बी)।

चार्ट IV.3 : जमाशायी वृद्धि



स्रोत: बैंकों के वार्षिक लेखा।



⁶ 2023-24 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 8.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि 2022-23 में यह 7.0 प्रतिशत थी।

बॉक्स IV.1: वाणिज्यिक बैंकों में जमाराशि वृद्धि के निर्धारक तत्व

भारत में वाणिज्यिक बैंकों में जमाराशि वृद्धि के निर्धारकों का मूल्यांकन जून 2012-मार्च 2024 की अवधि के लिए ऑटोरिग्रेसिव डिस्ट्रिब्यूटेड लैग (एआरडीएल) मॉडल (पेसरन और शिन, 1999) में किया गया है। साहित्य में आम सहमति के अनुसार (सालेह एम. और अन्य, 2023 और एस. ए. एस. अली और अन्य, 2019), प्रतिगमन परिणाम बताते हैं कि आय के संबंध में बैंक जमाराशि की दीर्घकालिक लोच [नॉमिनल सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) द्वारा अनुमानित] यूनिटी (1.1) के करीब है, यानी आय में एक प्रतिशत की वृद्धि, अन्य सभी चीजें समान रहने पर, दीर्घ अवधि में बैंक जमाराशि वृद्धि में लगभग एक प्रतिशत की वृद्धि से जुड़ी है। उच्चतर जमाराशि ब्याज दरें (डबल्यूएलटीडीआर) बैंक जमाराशि में बढ़ोत्तरी लाती है, लेकिन उनका प्रभाव दीर्घ अवधि में सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण नहीं है। त्रुटि सुधार टर्म (ईसीएम) का ऋणात्मक और सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण गुणांक यह दर्शाता है कि किसी भी आघात के कारण जमाराशि और आय वृद्धि के बीच किसी भी असंतुलन का लगभग 17 प्रतिशत प्रत्येक तिमाही में सुधार किया जाता है (सारणी IV.1.1)।

संदर्भ:

Pesaran, M. H., & Shin, Y. (1999). An Autoregressive Distributed-Lag Modelling Approach to Cointegration Analysis. *Econometrics and Economic Theory in the 20th Century: The Ragnar Frisch Centennial Symposium*, 371–413. Cambridge: Cambridge University Press.

Saleh, M., et al. (2023). The Impact of Financial Determinants on Bank Deposits Using ARDL Model. *Journal of Statistics Applications & Probability* 12(2): 441-452. DOI: <https://doi.org/10.18576/jsap/120210>.

S. A. S. Ali, et al. (2019). Determinants of Deposit of Commercial Banks in Sudan: an Empirical Investigation (1970-2012). *International Journal of Electronic Finance* (9), 230-255.

सारणी IV.1.1: समग्र जमाराशि के निर्धारक तत्व : एआरडीएल मॉडल

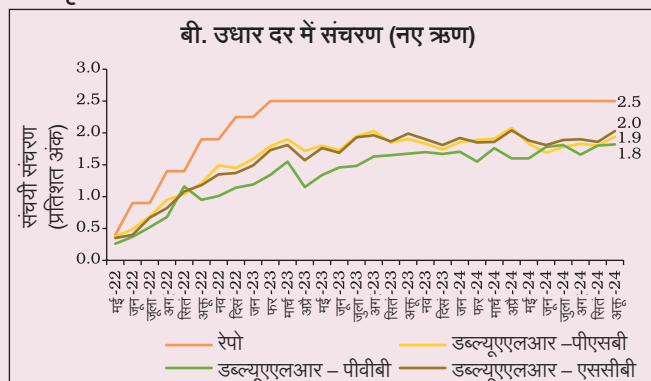
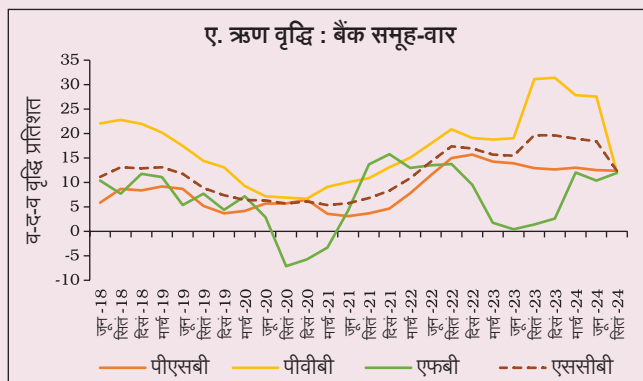
आश्रित चर: लॉग समग्र जमाराशि	
लॉग रन	
लॉग जीवीए (-1)	1.083*** (0.360)
डबल्यूएलटीडीआर आउटस्टैंडिंग (-1)	0.0458 (0.0603)
लॉग बीएसई (-1)	-0.0155 (0.211)
ईसीएम	
शॉर्ट रन	-0.166** (0.0801)
डी.लॉग जीवीए	-0.0420 (0.0678)
डी.डबल्यूएलटीडीआर आउटस्टैंडिंग	0.0479* (0.0267)
डी.डबल्यूएलटीडीआर आउटस्टैंडिंग (-1)	-0.0312 (0.0273)
डी.लॉग बीएसई	0.0716 (0.0427)
डी.लॉग बीएसई (-1)	-0.0916** (0.0403)
विमुद्रीकरण डमी	0.0244* (0.0121)
कोविड डमी	0.0299** (0.0117)
तिमाही 2 डमी	-0.00352 (0.00787)
तिमाही 3 डमी	0.00396 (0.00719)
तिमाही 4 डमी	0.00643 (0.00792)
स्थिरांक	-0.0420 (0.742)
प्रेक्षण	39
आर-स्क्वायर	0.468

स्रोत: आरबीआई स्टाफ अनुमान।

IV.9 2023-24 में ऋण वृद्धि में महानगरीय क्षेत्र की प्रभुता, जैसा कि पहले हुआ था। ग्रामीण, अर्ध-शहरी और शहरी क्षेत्रों का

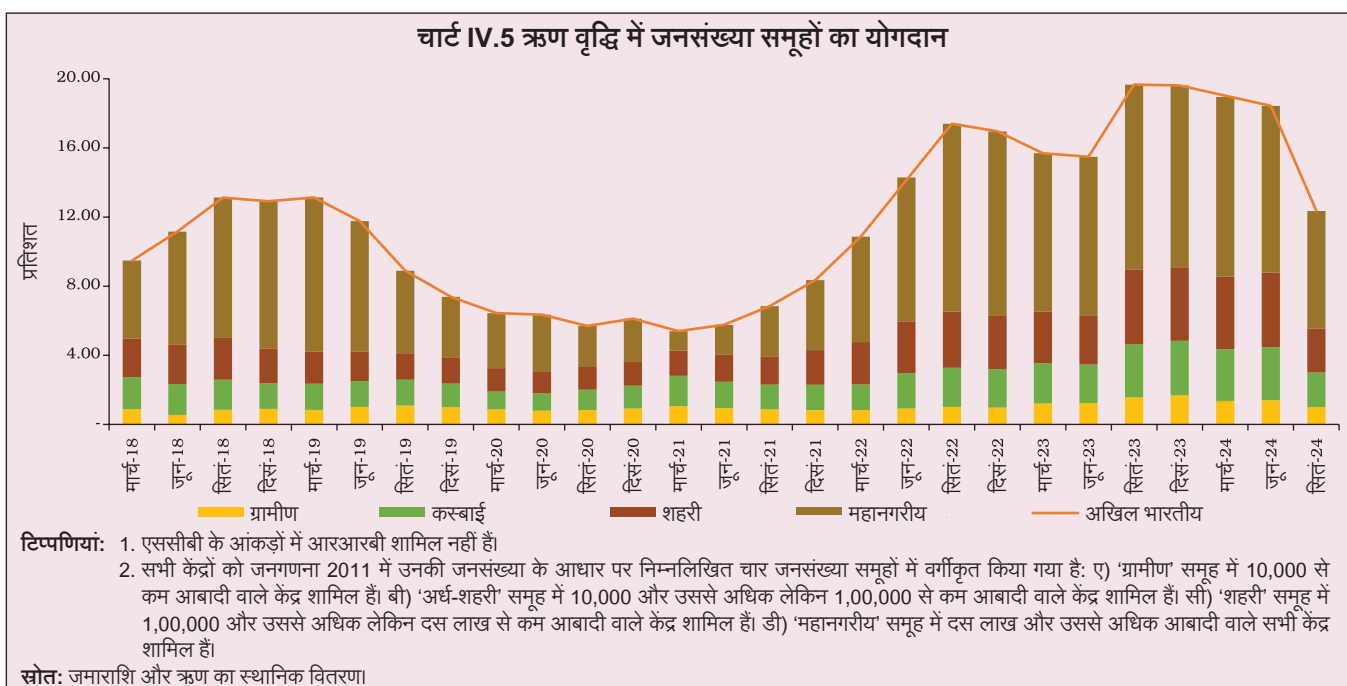
योगदान मोटे तौर पर स्थिर रहा (चार्ट IV.5)।

चार्ट IV.4 : ऋण वृद्धि



- टिप्पणियां:
- एससीबी डेटा में आरआरबी शामिल नहीं हैं।
 - 21 जनवरी 2019 से एक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को निजी क्षेत्र के बैंक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसलिए, मार्च 2019 से उस बैंक को पीएसबी समूह से बाहर रखा गया है और पीवीबी समूह में शामिल किया गया है। इसलिए, मार्च 2019 से सार्वजनिक और निजी बैंक-समूह वार वृद्धि दर समायोजित बैंक-समूह योग पर आधारित हैं।
 - 27 नवंबर 2020 से एक निजी क्षेत्र के बैंक को एक विदेशी बैंक के साथ समामेलित किया गया। इसलिए, दिसंबर 2020 से निजी और विदेशी बैंक-समूह वार वृद्धि दर समायोजित बैंक-समूह योग पर आधारित हैं।
 - क्रेडिट डेटा में अंतर-बैंक अग्रिम शामिल नहीं हैं।

स्रोत: जमा और ऋण का स्थानिक वितरण और आरबीआई।



IV.10 मार्च 2024 के अंत तक, एससीबी के 83.1 प्रतिशत निवेश सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) में थे। गैर-एसएलआर निवेशों में, डेट का हिस्सा लगभग 95 प्रतिशत था (सारणी IV.2)।

IV.11 जमाराशि वृद्धि में तेजी के कारण, ऋण की तुलना में जमाराशि वृद्धि का अंतराल 2023-24 के दौरान घटकर 3.4 प्रतिशत अंक (विलय प्रभाव को छोड़कर) हो गया (चार्ट IV.6ए)।

वर्ष के दौरान निवेश की तुलना में जमाराशि वृद्धि का अंतराल भी कम हुआ (चार्ट IV.6बी)।

2.3 आस्तियों और देयताओं का परिपक्वता प्रोफाइल

IV.12 आस्तियों और देयताओं की परिपक्वता में बेमेल बैंकिंग क्षेत्र के लिए स्वाभाविक है क्योंकि जमाराशि, जो उनके निधियों का प्राथमिक स्रोत है, की लघु से मध्यम अवधि की परिपक्वता होती है, जबकि उनके ऋणों की चुकौती की समय-

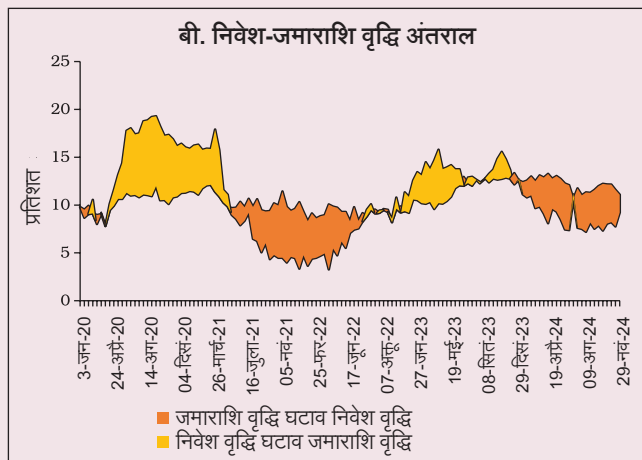
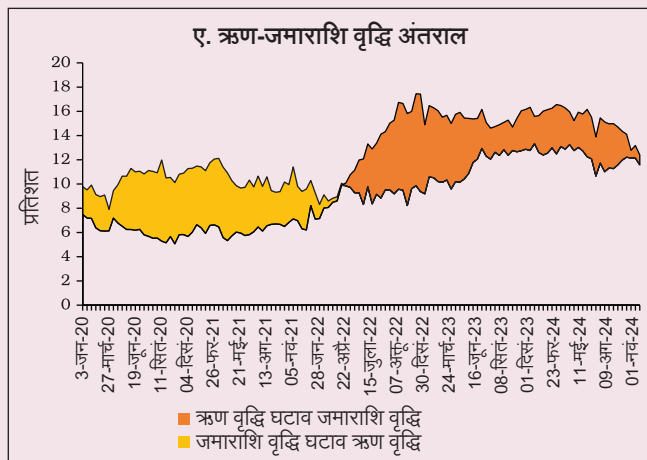
सारणी IV.2: एससीबी के निवेश
(मार्च के अंत में)

(राशि ₹ करोड़)

	पीएसबी		पीवीबी		एफबी		एसएफबी		एससीबी	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
कुल निवेश (ए+बी)	38,33,030	40,54,445	18,81,756	23,11,707	6,55,830	8,01,533	58,244	74,508	64,28,860	72,42,193
ए. एसएलआर निवेश (I+ II+III)	30,07,757	32,62,932	15,62,365	19,61,384	5,99,061	7,27,546	52,151	63,873	52,21,335	60,15,735
I. केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ	17,45,055	18,36,240	13,10,477	16,23,034	5,93,438	7,17,980	40,013	47,494	36,88,983	42,24,748
II. राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	12,60,787	14,22,323	2,51,889	3,38,350	5,623	9,566	12,139	16,379	15,30,437	17,86,618
III. अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियाँ	1,916	4,369	0	0	0	0	0	0	1,916	4,369
बी. एसएलआर से इतर निवेश (I+II)	8,25,273	7,91,513	3,19,390	3,50,323	56,769	73,987	6,093	10,634	12,07,525	12,26,458
I. ऋण प्रतिभूतियाँ	7,68,545	7,49,178	3,03,474	3,32,937	56,404	73,691	6,016	10,555	11,34,439	11,66,361
II. इक्विटी	56,728	42,335	15,916	17,386	365	297	77	79	73,087	60,097

स्रोत: परोक्ष विवरणियाँ (वैश्विक परिचालन), आरबीआई।

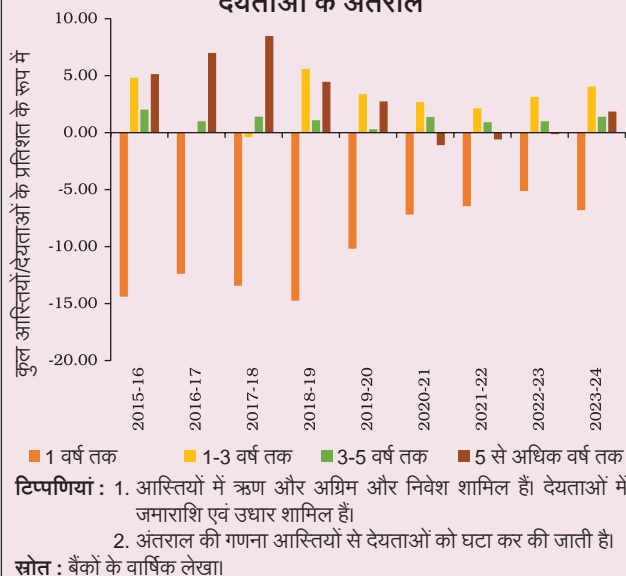
चार्ट IV.6 : ऋण-जमाराशि और निवेश-जमाराशि अंतराल



टिप्पणी : ऋण, जमाराशि और निवेश वृद्धि के आंकड़ों में विलय का प्रभाव शामिल नहीं है।
स्रोत : आरबीआई।

सीमा आमतौर पर मध्यम अवधि तक विस्तारित होती है। 2023-24 के दौरान, अल्पावधि बकेट में परिपक्वता बेमेल एक साल पहले की तुलना में बढ़ गया, हालांकि यह महामारी-पूर्व स्तरों के सापेक्ष कम रहा। अन्य बकेट⁷ में यह अंतराल धनात्मक रहा (चार्ट IV.7)। यह मुख्य रूप से बैंकों द्वारा जुटाई गई अल्पावधिक परिपक्वता जमाराशि में वृद्धि को दर्शाता है।

चार्ट IV.7 : परिपक्वता कोष्ठकवार आस्तियों और देयताओं के अंतराल



⁷ अल्पावधि को एक वर्ष तक के रूप में परिभाषित किया गया है, मध्यम अवधि को एक से पांच वर्ष तक के रूप में परिभाषित किया गया है, जबकि दीर्घावधि को पांच वर्ष से अधिक के रूप में परिभाषित किया गया है।

IV.13 एफबी को छोड़कर सभी बैंक समूहों की कुल जमाराशि में अल्पकालिक जमाराशि की हिस्सेदारी बढ़ी। दूसरी ओर, एसएफबी को छोड़कर सभी बैंक समूहों के लिए अल्पकालिक उधार की हिस्सेदारी में गिरावट आई। एफबी के सभी परिचालन – जमाराशि, उधार लेना, उधार देना और निवेश अल्पकालिक बकेट में संकेंद्रित थे। पीएसबी के निवेश आम तौर पर दीर्घकालिक लिखतों (इंस्ट्रूमेंट) में होते हैं, जबकि अन्य सभी बैंक समूह अल्पकालिक जोखिम को प्राथमिकता देते हैं (सारणी IV.3)।

2.4 अंतरराष्ट्रीय देयताएं और आस्तियां

IV.14 वर्ष 2023-24 में, सभी प्रकार के अनिवासी जमाराशियों, अर्थात् विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) [एफसीएनआर (बी)], अनिवासी बाह्य रुपया (एनआरई) और अनिवासी साधारण (एनआरओ) रुपया में वृद्धि ने भारत में बैंकों की अंतरराष्ट्रीय देयताओं में तेजी लाने में योगदान दिया (परिशिष्ट सारणी IV.2)। उनके 2023-24 में अंतरराष्ट्रीय आस्तियों में 23.5 प्रतिशत की गिरावट आई, जो एक साल पहले 13.1 प्रतिशत के संकुचन के शीर्ष पर थी, जो कि नोस्ट्रो जमाशेष और विदेशों

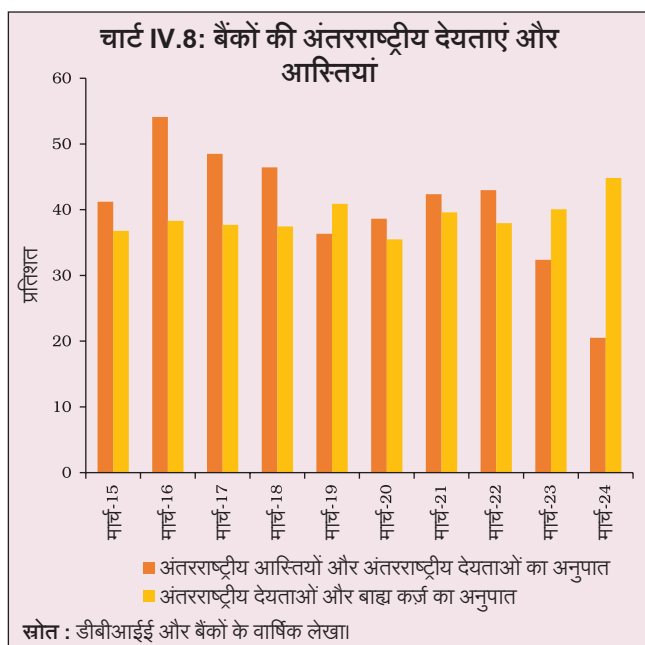
सारणी IV.3 : चुनिंदा देयताओं/आस्तियों की बैंक समूह-वार परिपक्वता प्रोफाइल
(मार्च के अंत में)

(प्रतिशत)

आस्तियां/देयताएं	पीएसबी		पीवीबी		एफबी		एसएफबी		पीबी		सभी एससीबी	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. जमा राशियां												
ए) 1 वर्ष तक	36.4	38.3	33.0	39.2	65.7	62.2	42.2	49.0	15.5	22.6	36.7	39.8
बी) 1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	21.1	22.0	31.2	27.9	26.1	30.7	54.9	44.8	84.5	77.4	25.0	24.7
सी) 3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	12.8	11.0	9.1	8.3	8.1	7.1	1.8	4.5	0.0	0.0	11.2	9.8
डी) 5 वर्ष से अधिक	29.7	28.7	26.7	24.6	0.0	0.0	1.1	1.7	0.0	0.0	27.1	25.6
II. उधारियाँ												
ए) 1 वर्ष तक	60.8	58.1	45.9	33.8	90.5	82.8	38.8	51.3	100.0	100.0	57.4	47.7
बी) 1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	16.7	16.7	32.6	37.8	7.6	16.2	50.6	35.7	0.0	0.0	22.9	27.5
सी) 3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	8.5	6.9	10.3	9.9	0.7	0.4	5.4	7.3	0.0	0.0	8.3	7.9
डी) 5 वर्ष से अधिक	14.0	18.3	11.2	18.6	1.2	0.6	5.2	5.8	0.0	0.0	11.3	16.9
III. ऋण और अग्रिम												
ए) 1 वर्ष तक	28.3	28.0	28.4	27.3	56.2	59.5	36.5	37.7	100.0	100.0	29.4	28.9
बी) 1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	34.3	36.5	36.7	34.6	23.9	23.8	36.0	36.0	0.0	0.0	34.9	35.3
सी) 3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	14.1	12.1	12.5	12.5	10.0	8.2	10.5	10.1	0.0	0.0	13.3	12.1
डी) 5 वर्ष से अधिक	23.3	23.4	22.4	25.6	9.9	8.5	17.1	16.3	0.0	0.0	22.4	23.7
IV. निवेश												
ए) 1 वर्ष तक	26.0	22.4	55.3	58.6	86.4	83.9	61.6	68.6	99.5	99.2	41.3	41.4
बी) 1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	14.6	16.3	19.1	17.2	8.2	10.4	27.0	25.9	0.1	0.4	15.3	16.0
सी) 3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	12.9	11.9	7.1	6.1	1.3	1.6	5.5	4.0	0.0	0.1	9.9	8.8
डी) 5 वर्ष से अधिक	46.4	49.4	18.5	18.1	4.2	4.1	5.9	1.5	0.4	0.3	33.4	33.8

टिप्पणी : आंकड़े तुलन पत्र के प्रत्येक घटक में प्रत्येक परिपक्वता बकेट की हिस्सेदारी दर्शाते हैं।
स्रोत : बैंकों के वार्षिक लेखा।

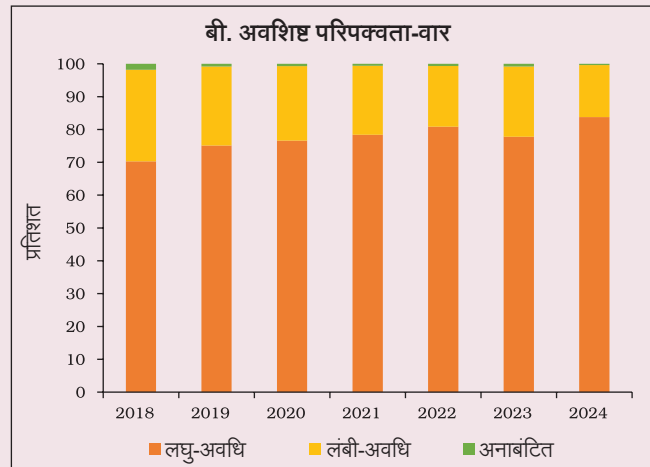
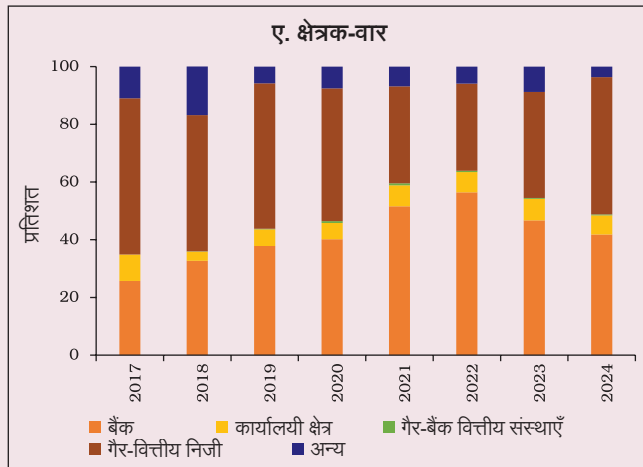
में जमा रखे जाने के साथ-साथ अनिवासियों को दिए जाने वाले ऋणों में कमी के कारण हुई थी (परिशिष्ट सारणी IV.3)।



नतीजतन, भारत में बैंकों की अंतरराष्ट्रीय आस्तियों की तुलना में देयताओं का अनुपात 2023-24 के दौरान लगातार दूसरे वर्ष घटा (चार्ट IV.8)।

IV.15 वर्ष 2023-24 में अमेरिका और यूएई को छोड़कर सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं पर भारतीय बैंकों के समेकित अंतरराष्ट्रीय दावों में वृद्धि हुई (परिशिष्ट सारणी IV.4); इसके विपरीत, पिछले वर्ष में, सिंगापुर को छोड़कर प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं पर भारतीय बैंकों के समेकित अंतरराष्ट्रीय दावों में कमी आई थी। मार्च 2024 के अंत में, भारतीय बैंकों के दावे अन्य क्षेत्राधिकारों में अपने समकक्षों से हटकर गैर-वित्तीय निजी क्षेत्र की ओर चले गए (चार्ट IV.9ए)। कम परिपक्वता अवधि वाले दावों का अनुपात बढ़ा और प्रभावशाली कोटि का बना रहा (परिशिष्ट सारणी IV.5 और चार्ट IV.9बी)।

चार्ट IV.9 : भारतीय बैंकों के समेकित अंतरराष्ट्रीय दावे
(मार्च के अंत में)



स्रोत: बैंकों के वार्षिक लेखा और डीबीआईडी

2.5 तुलन पत्र से इतर परिचालन

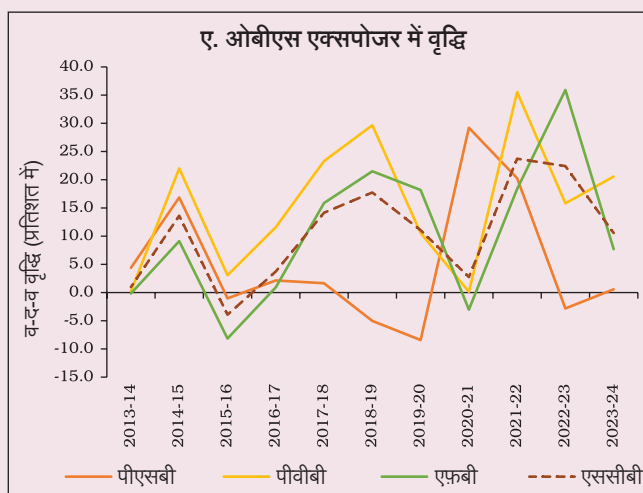
IV.16 मार्च 2024 के अंत में एससीबी की आकस्मिक देयताओं में वृद्धि धीमी हो गई, जिसका नेतृत्व वायदा विनिमय संविदा (फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स) ने किया (चार्ट IV.10ए और परिशिष्ट सारणी IV.6)। तुलन पत्र के आकार के अनुपात के रूप में, एससीबी का तुलन पत्र से इतर एक्सपोजर मार्च 2023 के अंत में 144.8 प्रतिशत से घटकर मार्च 2024 के अंत में 138.6 प्रतिशत हो गया। बैंकिंग क्षेत्र की आकस्मिक देयताओं में पीवीबी की हिस्सेदारी मार्च

2014 के अंत में 20.4 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2024 के अंत में 32.9 प्रतिशत हो गई, जबकि इसी अवधि में पीएसबी की हिस्सेदारी 24.3 प्रतिशत से घटकर 13.2 प्रतिशत हो गई (चार्ट IV.10बी)।

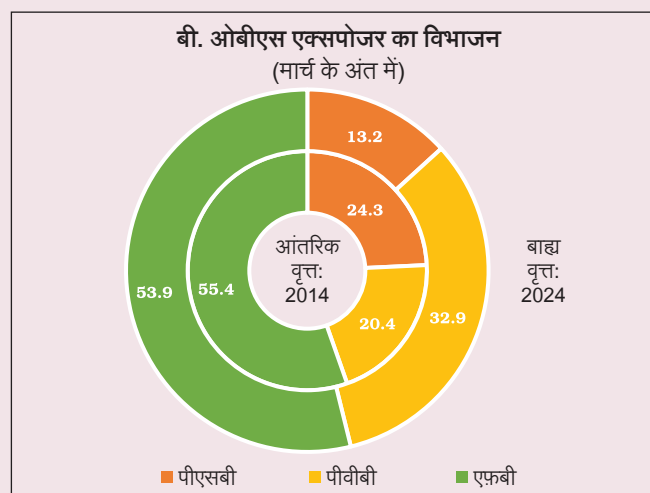
3. वित्तीय प्रदर्शन

IV.17 वर्ष 2023-24 में लगातार छठे वर्ष बैंकों की लाभप्रदता में सुधार हुआ। वर्ष 2023-24 में पीएसबी और पीवीबी दोनों ने आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए) में वृद्धि प्रदर्शित की (चार्ट IV.11)।

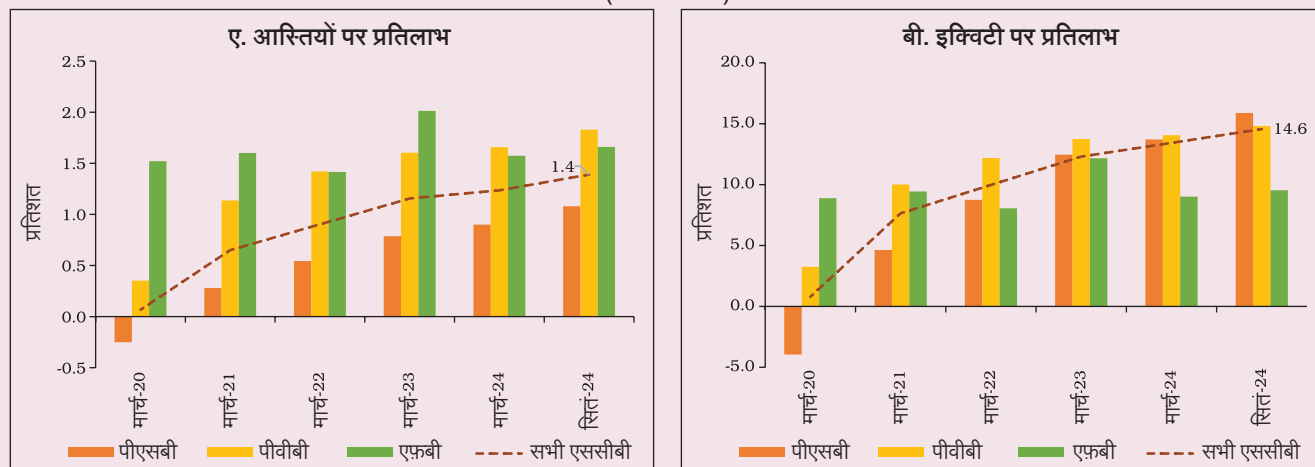
चार्ट IV.10 : बैंकों की तुलन पत्र से इतर देयताएं



स्रोत : बैंकों के वार्षिक लेखा



चार्ट IV.11 : लाभप्रदता अनुपात
(मार्च अंत में)



स्रोत: परोक्ष विवरणियां (घरेलु परिचालन), आरबीआई।

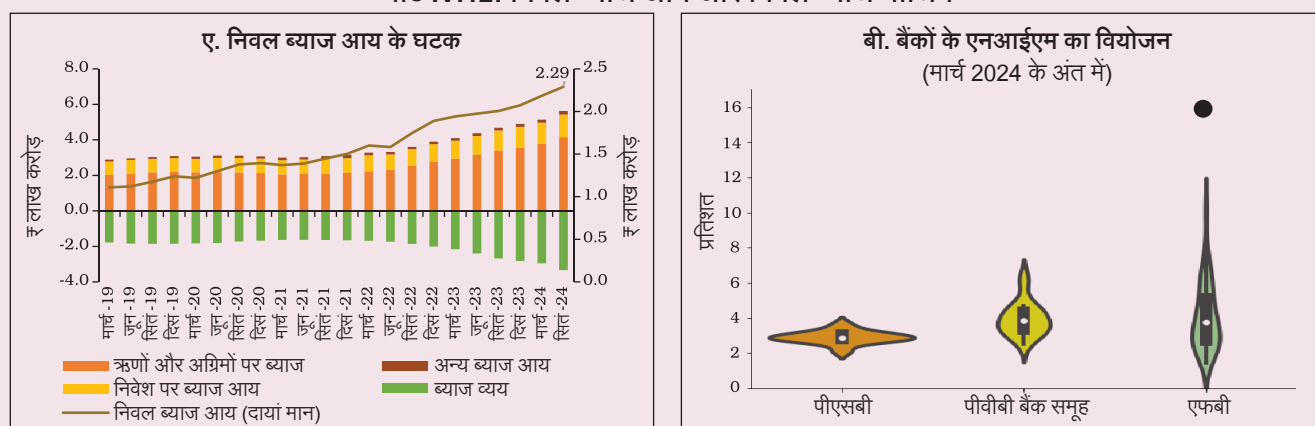
वर्ष 2024-25 की पहली छमाही में एससीबी की लाभप्रदता में वृद्धि जारी रही, जिसमें आरओए 1.4 प्रतिशत और आरओई 14.6 प्रतिशत रहा।

IV.18 वर्ष 2023-24 के दौरान, बैंकों ने उच्च ब्याज दरों पर उधार लेना शुरू किया और ऋण की तुलना में जमाराशि वृद्धि अंतराल को पाटने के लिए अपनी जमाराशि दरों में वृद्धि की। नतीजतन, उनके ब्याज व्यय की गति उनकी ब्याज आय से अधिक हो गई जिसके परिणामस्वरूप परिचालन और निवल

लाभ वृद्धि, दोनों में धीमापन आया (सारणी IV.4 और चार्ट IV.12ए)।

IV.19 ब्याज आय की तुलना में ब्याज व्यय का अनुपात 2023-24 के दौरान पिछले वर्ष के 52.2 प्रतिशत से बढ़कर 57.4 प्रतिशत हो गया। औसत निवल मार्जिन ब्याज (एनआईएम) पीवीबी के लिए सबसे अधिक था, उसके बाद एफबी और पीएसबी थे। एफबी का एनआईएम अत्यधिक विस्तारित है, उसके बाद पीवीबी और पीएसबी (चार्ट IV.12बी) हैं।

चार्ट IV.12: निवल ब्याज आय और निवल ब्याज मार्जिन



टिप्पणी : वायलिन चार्ट मार्च 2024 के अंत में बैंक-वार एनआईएम का उपयोग करके बनाया गया है। चार्ट में सफेद बिंदु माध्यिका को दर्शाता है, बीच में काली पट्टी का आधार प्रथम चतुर्थक को दर्शाता है, जबकि शीर्ष तृतीय चतुर्थक को दर्शाता है। वायलिन प्लॉट के चौड़े हिस्से वितरण की उच्च आवृत्ति को दर्शाते हैं, जबकि पतले हिस्से कम आवृत्ति को दर्शाते हैं। काला बिंदु बाहिस्थ (आउटलायर) एफबी को दर्शाता है।

स्रोत : परोक्ष विवरणियां, आरबीआई और बैंकों के वार्षिक लेखा।

सारणी IV.4: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के आय और व्यय के रुझान

(राशि ₹ करोड़ में)

	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक		निजी क्षेत्र के बैंक		विदेशी बैंक		लघु वित्त बैंक		भुगतान बैंक		सभी एससीबी	
	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. आय	9,71,421 (16.8)	12,12,665 (24.8)	6,90,504 (20.7)	9,41,864 (36.4)	1,08,132 (36.0)	1,29,870 (20.1)	33,806 (34.6)	45,449 (34.4)	5,965 (20.5)	7,102 (19.0)	18,09,829 (19.6)	23,36,949 (29.1)
ए) ब्याज आय	8,51,078 (20.0)	10,66,243 (25.3)	5,82,278 (23.6)	7,96,569 (36.8)	83,315 (26.5)	1,06,032 (27.3)	29,806 (34.7)	39,646 (33.0)	860 (92.7)	1,416 (64.6)	15,47,337 (22.0)	20,09,907 (29.9)
बी) अन्य आय	1,20,343 (-2.0)	1,46,422 (21.7)	1,08,226 (6.8)	1,45,295 (34.3)	24,817 (81.9)	23,838 (-3.9)	4,000 (34.0)	5,803 (45.1)	5,105 (13.3)	5,686 (11.4)	2,62,492 (7.0)	3,27,043 (24.6)
2. व्यय	8,66,772 (13.3)	10,71,463 (23.6)	5,66,369 (19.0)	7,66,567 (35.3)	77,987 (27.6)	1,02,984 (32.1)	29,644 (22.8)	39,230 (32.3)	5,844 (15.9)	7,103 (21.5)	15,46,615 (16.1)	19,87,346 (28.5)
ए) खर्च किया गया ब्याज	4,87,690 (18.6)	6,58,611 (35.0)	2,75,391 (22.8)	4,29,732 (56.0)	31,678 (47.5)	46,996 (48.4)	12,140 (27.6)	17,474 (43.9)	246 (57.5)	353 (43.8)	8,07,144 (21.1)	11,53,167 (42.9)
बी) परिचालन व्यय	2,44,064 (10.9)	2,95,090 (20.9)	2,02,563 (29.3)	2,39,146 (18.1)	27,958 (12.0)	34,789 (24.4)	13,150 (34.0)	17,189 (30.7)	5,579 (14.3)	6,634 (18.9)	4,93,314 (18.5)	5,92,848 (20.2)
जिनमें से : वेतन बिल	1,44,690 (9.0)	1,84,025 (27.2)	70,605 (20.0)	90,284 (27.9)	10,065 (9.6)	10,460 (3.9)	6,705 (26.4)	8,504 (26.8)	914 (15.9)	1,215 (32.9)	2,32,978 (12.6)	2,94,488 (26.4)
सी) प्रावधान और आकस्मिकताएं	1,35,018 (0.7)	1,17,761 (-12.8)	88,415 (-7.1)	97,688 (10.5)	18,351 (25.3)	21,200 (15.5)	4,354 (-9.4)	4,567 (4.9)	20 (556.9)	116 (488.4)	2,46,158 (-1.0)	2,41,332 (-2.0)
3. परिचालन लाभ	2,39,667 (19.5)	2,58,964 (8.1)	2,12,551 (11.0)	2,72,986 (28.4)	48,496 (46.8)	48,085 (-0.8)	8,516 (47.3)	10,786 (26.6)	141 (-263.0)	114 (-18.9)	5,09,371 (18.2)	5,90,935 (16.0)
4. निवल लाभ	1,04,649 (57.3)	1,41,202 (34.9)	1,24,136 (29.0)	1,75,297 (41.2)	30,145 (64.0)	26,886 (-10.8)	4,162 (327.6)	6,219 (49.4)	121 (-235.6)	-1 (-101.0)	2,63,214 (44.6)	3,49,603 (32.8)
5. निवल ब्याज आय (एनआईआई)	3,63,388 (22.0)	4,07,632 (12.2)	3,06,888 (24.4)	3,66,836 (19.5)	51,637 (16.4)	59,036 (14.3)	17,666 (40.1)	22,172 (25.5)	615 (111.7)	1,063 (72.9)	7,40,193 (23.0)	8,56,740 (15.7)
6. निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम)	2.7	2.8	3.9	3.9	3.5	3.6	7.5	7.4	3.0	4.5	3.2	3.3

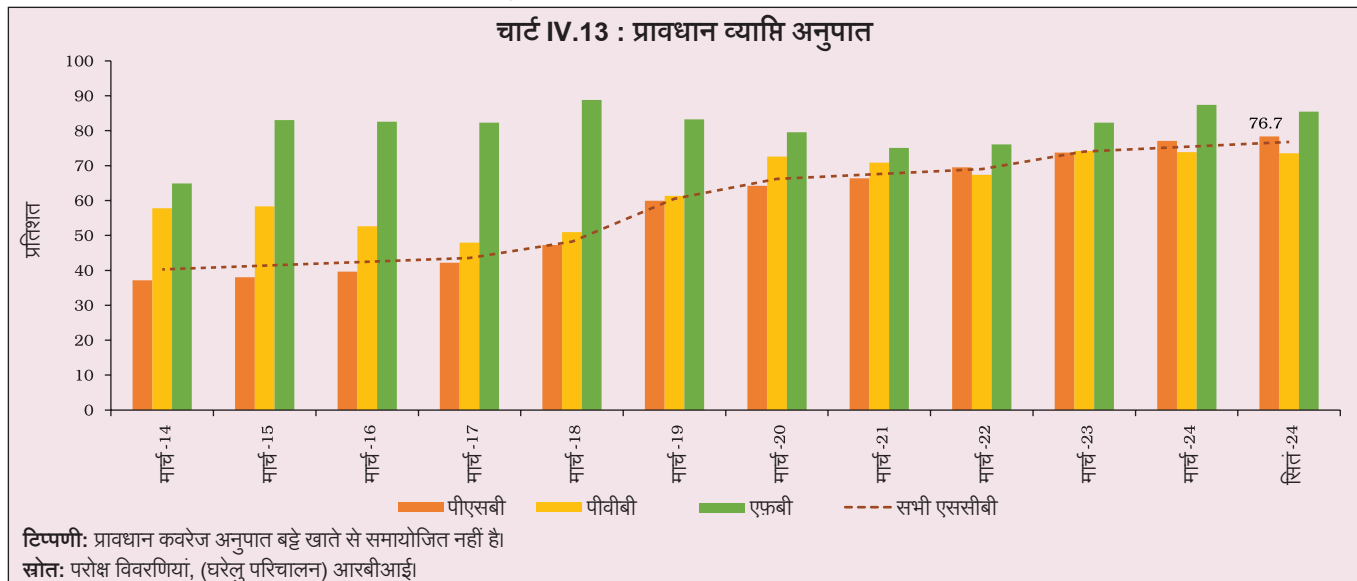
टिप्पणी : 1. एनआईएम को औसत आस्तियों के प्रतिशत में एनआईआई के रूप में परिभाषित किया गया है।
2. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत भिन्नताओं को दर्शाते हैं।

स्रोत : संबंधित बैंकों के वार्षिक लेखा।

IV.20 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) का पीसीआर (बड़े खाते में डालने के लिए समायोजित किए बिना) वर्ष-दर-वर्ष 210 आधार अंक (बीपीएस) बढ़कर मार्च 2024 के अंत में 76.2 प्रतिशत पर पहुंच गया जो मुख्य रूप से कम गिरावट को दर्शाता है। सितंबर 2024 के अंत में यह और सुधरकर 76.7

प्रतिशत हो गया जिसका श्रेय मुख्य रूप से पीएसबी को जाता है (चार्ट IV.13)।

IV.21 निधियों की लागत में 104 बीपीएस की वृद्धि और आस्तियों पर प्रतिफल में 89 बीपीएस की वृद्धि ने 2023-24 के दौरान एससीबी के स्प्रेड को कम कर दिया। एसएफबी में



सारणी IV.5: निधियों की लागत और निधियों पर प्रतिलाभ - बैंक समूह-वार

(प्रतिशत)

बैंक समूह	वर्ष	जमाराशियों की लागत	उधारियों की लागत	निधियों की लागत	अग्रिमों पर प्रतिलाभ	निवेशों पर प्रतिलाभ	निधियों पर प्रतिलाभ	स्प्रेड (कॉलम 8 - कॉलम 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
पीएसबी	2022-23	3.9	6.2	4.1	7.5	6.5	7.1	3.1
	2023-24	4.8	7.3	5.0	8.4	6.9	7.9	2.9
पीवीबी	2022-23	3.8	6.4	4.1	9.2	6.3	8.4	4.3
	2023-24	4.8	9.2	5.4	10.4	6.8	9.5	4.1
एफबी	2022-23	2.9	4.0	3.1	8.2	5.8	6.9	3.8
	2023-24	3.8	5.6	4.1	8.7	6.8	7.6	3.5
एसएफबी	2022-23	5.9	7.3	6.1	16.5	6.7	14.2	8.0
	2023-24	6.8	8.2	7.0	17.0	6.9	14.5	7.5
पीबी	2022-23	2.1	7.8	2.4	6.0	5.6	5.6	3.3
	2023-24	2.0	11.2	2.4	10.0	7.6	7.6	5.2
सभी एससीबी	2022-23	3.8	6.1	4.0	8.2	6.3	7.6	3.6
	2023-24	4.8	8.1	5.1	9.3	6.9	8.5	3.4

टिप्पणियाँ: 1. जमाराशियों की लागत = जमाराशियों पर दिया गया ब्याज / वर्तमान और पिछले वर्षों की जमाराशियों का औसत।
2. उधारियों की लागत = (व्यय किया गया ब्याज - जमाराशि पर ब्याज) / वर्तमान और पिछले वर्षों की उधारियों का औसत।
3. निधियों की लागत = खर्च किया गया ब्याज / (वर्तमान और पिछले वर्षों की जमाराशियों का औसत + उधारियों)।
4. अग्रिमों पर प्रतिलाभ = अग्रिमों पर अर्जित ब्याज / वर्तमान और पिछले वर्षों के अग्रिमों का औसत।
5. निवेशों पर प्रतिलाभ = निवेशों पर अर्जित ब्याज / वर्तमान और पिछले वर्षों के निवेशों का औसत।
6. निधियों पर प्रतिलाभ = (अग्रिमों पर अर्जित ब्याज + निवेशों पर अर्जित ब्याज) / वर्तमान और पिछले वर्षों के अग्रिमों का औसत + निवेश।

स्रोत: संबंधित बैंकों के तुलन पत्र से की गई गणना।

स्प्रेड सबसे व्यापक था जो उनके अग्रिमों पर अपेक्षाकृत उच्चतर ब्याज दरों को दर्शाता है (सारणी IV.5)।

4. सुदृढ़ता संकेतक

4.1 पूंजी पर्याप्तता

IV.22 भारत में बैंकों के लिए जोखिम-भारित आस्ति की तुलना में न्यूनतम पूंजी अनुपात (सीआरएआर) की आवश्यकता 9 प्रतिशत (पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) सहित 11.5 प्रतिशत) निर्धारित की गई है और टियर 1 पूंजी आवश्यकता 7 प्रतिशत निर्धारित की गई है जो दोनों बेसल III अपेक्षाओं से एक प्रतिशत अधिक है। मार्च 2024 के अंत में, सभी बैंक समूह अच्छी तरह से पूंजीकृत रहे, हालांकि एससीबी का सीआरएआर 30 बीपीएस

की गिरावट के साथ 16.9 प्रतिशत हो गया, जबकि टियर1 पूंजी 14.8 प्रतिशत पर थी (सारणी IV.6)। सीआरएआर में गिरावट जोखिम-भारित आस्तियों (आरडब्ल्यूए) में वृद्धि के कारण हुई जो उनके पूंजी निधियों में वृद्धि से अधिक थी। पर्यवेक्षी आँकड़ों से संकेत मिलता है कि सितंबर 2024 के अंत में एससीबी का सीआरएआर 16.8 प्रतिशत था।

IV.23 घटक बैंकों के बीच सीआरएआर और सीईटी1 का विस्तार पीवीबी के लिए पीएसबी की तुलना में अधिक था (चार्ट IV.14ए और बी)। पीवीबी के लिए सीआरएआर और सीईटी1 दोनों के माध्य और माध्यिका पीएसबी की तुलना में अधिक था।

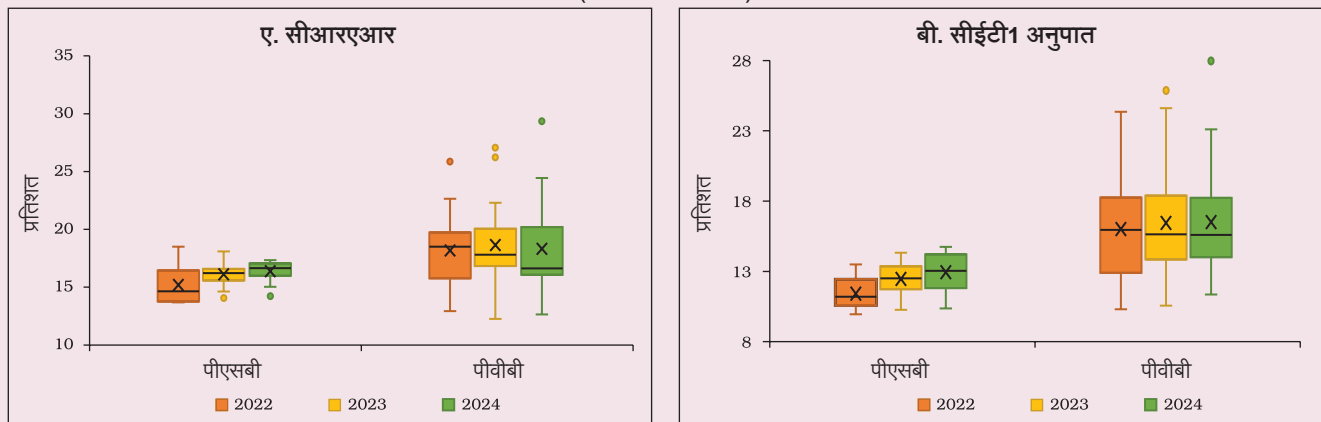
सारणी IV.6: एससीबी की घटक-वार पूंजी पर्याप्तता (मार्च अंत में)

(राशि ₹ करोड़)

	पीएसबी		पीवीबी		एफबी		एससीबी	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. पूंजीगत निधियां	10,16,789	11,74,245	10,20,953	12,83,455	2,43,096	2,70,646	23,15,358	27,69,950
i) टीयर 1 पूंजी	8,47,783	9,94,510	9,11,271	11,55,051	2,20,746	2,43,842	20,10,443	24,30,733
ii) टीयर 2 पूंजी	1,69,006	1,79,735	1,09,681	1,28,404	22,350	26,804	3,04,915	3,39,217
2. जोखिम भारित आस्तियां	65,48,771	75,59,396	54,85,172	72,14,513	12,50,775	14,18,639	1,34,38,317	1,63,84,879
3. सीआरएआर (2 के % के रूप में 1)	15.5	15.5	18.6	17.8	19.4	19.1	17.2	16.9
जिनमें से: टीयर 1	12.9	13.2	16.6	16.0	17.6	17.2	15.0	14.8
टीयर 2	2.6	2.4	2.0	1.8	1.8	1.9	2.3	2.1

स्रोत: परोक्ष विवरणियां, आरबीआई।

चार्ट IV.14: बैंक समूहवार सीआरएआर और सीईटी1 अनुपात (मार्च के अंत तक)



टिप्पणियाँ: 1. बॉक्सप्लॉट की व्हीस्कर्स अधिकतम और न्यूनतम मानों का संकेत देती हैं। एक रंगीन बॉक्स पहले चतुर्थक और तीसरे चतुर्थक के बीच की दूरी दिखाता है। प्रत्येक बॉक्स में क्षैतिज रेखा माध्यिका को दर्शाती है, जबकि 'X' माध्य को दर्शाता है।

स्रोत: परोक्ष विवरणियाँ (घरेलू परिचालन), आरबीआई।

IV.24 सभी समूह और आकार के बैंकों ने लगातार विनियामक न्यूनतम आवश्यकताओं से ऊपर सीआरएआर बनाए रखा है (चार्ट IV.15)। सीसीबी को भारतीय बैंकों पर 2016 से कई

चरणों में लागू किया गया था। अधिशेष सीआरएआर, जो सीसीबी सहित तत्कालीन लागू सीआरएआर से अधिशेष पर आकलित होता है, कई कारकों से प्रभावित होता है (बॉक्स IV.2)।

चार्ट IV.15 : अधिशेष सीआरएआर



टिप्पणी: किसी भी तिमाही के लिए, समूह औसत से नीचे (ऊपर) आसित आकार वाला बैंक छोटा (बड़ा) माना जाता है।

स्रोत: आरबीआई

बॉक्स IV.2: बैंक अधिशेष सीआरएआर क्यों रखते हैं?

बैंक अप्रत्याशित घाटे एवं आर्थिक मंदी का सामना करने, और अपनी बाज़ार प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए अधिशेष सीआरएआर को बफर के रूप में रखते हैं (लिंगडक्विस्ट, 2004)। विनियामकीय आवश्यकताओं से ऊपर के सीआरएआर, बैंकों के लिए विकल्पगत हानि हो सकती है क्योंकि अधिशेष पूंजी को उच्चतर-प्रतिफल देने वाली वाली आस्तियों में निवेश किया जा सकता है, जिसमें ऋण देना भी शामिल है (कश्यप, राजन और स्टीन, 2002)।

अधिशेष सीआरएआर के संभावित चालकों का अनुमान मार्च 2012 से दिसंबर 2023 तक 33 पीएसबी और पीवीबी के पर्यवेक्षी तिमाही पैनल डेटा का उपयोग करके फिक्स्ड इफ़ेक्ट रिग्रेशन मॉडल से लगाया जाता है।

परिणामों से संकेत मिलता है कि आरओए या एनआईएम जैसे लाभप्रदता संकेतक अधिशेष सीआरएआर पर धनात्मक प्रभाव डालते हैं (सारणी IV.2.1)। इसके विपरीत, पिछले सकल जीएनपीए अनुपात या निवल एनपीए (एनएनपीए) अनुपात द्वारा मापा गया बैंकों का पूर्व-पश्चात ऋण जोखिम, अधिशेष सीआरएआर को कम करता है क्योंकि कमजोर आर्स्ति गुणवत्ता वाले बैंक उच्च प्रावधानों का अनुमान लगाते हैं। इसके अतिरिक्त, एक बड़ा ऋण पोर्टफोलियो (ऋण से आर्स्ति अनुपात द्वारा मापा जाता है) या उच्चतर ऋण वृद्धि के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, जिसके परिणामस्वरूप अधिशेष सीआरएआर के साथ ऋणात्मक संबंध होता है। कुल आर्स्तियों के लॉग द्वारा मापा गया बैंक का आकार, अधिशेष सीआरएआर से ऋणात्मक रूप से संबंधित होता है - बड़े बैंकों को पोर्टफोलियो विविधीकरण, सुदृढ़ आर्थिक स्थिति और पूंजी बाजारों तक आसान पहुंच का लाभ हो सकता है (बर्जर और बाउमन, 2009)।

अधिशेष पूंजी रखने का निर्णय समकक्ष के व्यवहार से भी प्रभावित हो सकता है (अंगोरा, डिस्टिंगुइन और रूगेमिंतवारी, 2009)। भारतीय परिपेक्ष्य में, एक समान श्रेणी (पीएसबी और पीवीबी के आकार-वार समूह) के बैंकों द्वारा धारित औसत अधिशेष पूंजी, बैंक के स्वयं के अधिशेष सीआरएआर के साथ एक महत्वपूर्ण और धनात्मक संबंध दर्शाता है। भारत औसत मांग दर (डब्ल्यूएसीआर), जो अधिशेष पूंजी रखने की विकल्पगत हानि का प्रतिनिधित्व करता है, वह अधिशेष पूंजी होल्डिंग को कम करती है। अधिशेष सीआरएआर भी चक्रीय प्रतीत होता है, जैसा कि जीडीपी वृद्धि के साथ इसके धनात्मक और महत्वपूर्ण संबंध से स्पष्ट है।

निष्कर्षतः बैंकों द्वारा अधिशेष सीआरएआर बनाए रखना, समष्टि-आर्थिक स्थितियों के अलावा उनकी अपनी वित्तीय स्थितियों तथा समकक्षों के प्रभाव से प्रभावित हो सकता है।

सारणी IV.2.1: प्रतिगमन परिणाम

	आश्रित चर: अधिशेष सीआरएआर		
	मॉडल 1	मॉडल 2	मॉडल 3
लैग (आरओए)	0.865*** (0.0673)		1.115*** (0.0754)
लैग (एनआईएम)		1.091*** (0.0859)	
लैग (एनएनपीए अनुपात)	-0.0783*** (0.0262)		
लैग (जीएनपीए अनुपात)		-0.197*** (0.0140)	-0.0935*** (0.0162)
लैग (ऋण से आर्स्तियां)	-0.0339*** (0.0102)		-0.0274** (0.0118)
लैग (ऋण वृद्धि)		0.00347 (0.00475)	
समूह अधिशेष सीआरएआर	0.649*** (0.0474)		
लॉग (कुल आर्स्तियां)		-0.676*** (0.160)	-0.315* (0.165)
डब्ल्यूएसीआर	-0.116*** (0.0305)	-0.439*** (0.0397)	-0.411*** (0.0405)
जीडीपी वृद्धि	0.00120 (0.00792)	0.0334*** (0.00848)	0.0243*** (0.00845)
स्थिरांक	3.892*** (0.689)	12.21*** (2.084)	11.86*** (2.027)
प्रेक्षण	1,518	1,509	1,518
स्थिर प्रभाव	हाँ	हाँ	हाँ
आर-स्क्वायर	0.394	0.267	0.289
बैंकों की संख्या	33	33	33

टिप्पणियाँ: 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े बैंक स्तर पर एकत्रित मजबूत मानक त्रुटियों को दर्शाते हैं।
2. ***, ** और * क्रमशः 1 प्रतिशत, 5 प्रतिशत और 10 प्रतिशत महत्व के स्तर को दर्शाते हैं।

स्रोत: आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

संदर्भ:

- Angora, A., Distinguin, I., and Rugemintwari, C. (2009). Excess Capital of European Banks: Does Bank Heterogeneity Matter? Working paper. University of Limoges.
- Berger, A. N., and Bouwman, C. H. (2009). Bank Liquidity Creation. *The Review of Financial Studies*, 22(9), 3779-3837.
- Kashyap, A. K., Rajan, R. G., and Stein, J. C. (2002). Banks as Liquidity Providers: An Explanation for the Coexistence of Lending and Deposit-taking. *Journal of Finance*, 57(1), 33-73.
- Lindquist, K.-G. (2004). Banks' Buffer Capital: How Important is Risk. *Journal of International Money and Finance*, 23(3), 493-513.

IV.25 बैंकों द्वारा कर्ज के निजी प्लेसमेंट, पात्र संस्थागत प्लेसमेंट और इक्विटी के अधिमान्य आबंटन के माध्यम से जुटाए गए संसाधनों में 2023-24 के दौरान थोड़ी वृद्धि हुई।

पीएसबी द्वारा जुटाई गई कुल राशि में वर्ष 2022-23 की तुलना में 2023-24 में 38.6 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई (सारणी IV.7)।

सारणी IV.7: निजी प्लेसमेंट के माध्यम से बैंकों द्वारा जुटाए गए संसाधन

(राशि ₹ करोड़ में)

	2021-22		2022-23		2023-24		2024-25 (अक्तूबर तक)	
	निर्गमों की संख्या	जुटाई गयी राशि	निर्गमों की संख्या	जुटाई गयी राशि	निर्गमों की संख्या	जुटाई गयी राशि	निर्गमों की संख्या	जुटाई गयी राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
पीएसबी	34	70,719	27	70,260	26	97,380	17	90,811
पीवीबी	16	40,034	14	52,903	14	33,426	6	14,519
एफबी	0	0	2	224	0	0	0	0
कुल	50	1,10,753	43	1,23,387	40	1,30,806	23	1,05,330

टिप्पणियाँ: 1. इसमें कर्ज का निजी प्लेसमेंट, पात्र संस्थागत प्लेसमेंट और अधिमानी आबंटन शामिल हैं।

2. वर्ष 2024-25 के आँकड़े अनंतिम हैं।

स्रोत : सेबी, बीएसई और एनएसई।

4.2 लीवरेज और चलनिधि

IV.26 लीवरेज अनुपात एक गैर-जोखिम आधारित बैकस्टॉप उपाय है जो बेसल III जोखिम-आधारित पूंजी ढांचे का पूरक है। लीवरेज अनुपात (एलआर) - कुल जोखिमों के लिए टियर1 पूंजी का अनुपात - वर्ष 2023-24 के दौरान सिवाय एफबी के सभी बैंक समूहों में बेहतर हुआ (सारणी IV.8)।

IV.27 चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) - जिसे अल्पावधि में बैंकों को चलनिधि दबावों का सामना करने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है - के लिए बैंकों को दबावग्रस्त स्थितियों के 30 दिनों के निवल व्यय को पूरा करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली चल आस्ति (एचक्यूएलए) बनाए रखने की आवश्यकता होती है। मार्च 2024 के अंत में, वर्ष के दौरान मामूली कमी के बावजूद, एलसीआर 130.3 प्रतिशत था जो आवश्यक 100 प्रतिशत से अधिक था। (सारणी IV.8)

IV.28 निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफआर) - आवश्यक स्थिर निधीयन की तुलना में उपलब्ध स्थिर निधीयन का अनुपात - बैंकों की अल्पकालिक थोक निधीयन पर अत्यधिक निर्भरता को सीमित करता है और सभी तुलन पत्र और उससे इतर मदों में निधीयन जोखिम के बेहतर आकलन को प्रोत्साहित करता है, जिससे निधीयन स्थिरता को बढ़ावा मिलता है। अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप, भारत में बैंकों को न्यूनतम एनएसएफआर बनाए रखने की आवश्यकता 100 प्रतिशत है। मार्च 2024 के अंत तक, सभी बैंक समूहों ने इस लक्ष्य को पूरा किया (सारणी IV.9)।

4.3 अनर्जक आस्तियां

IV.29 बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में सुधार, जिसे उनके सकल अनर्जक आस्ति (जीएनपीए) अनुपातों द्वारा मापा जाता है, 2018-19 में शुरू हुआ। एससीबी के जीएनपीए में वर्ष-दर-वर्ष 15.9 प्रतिशत की कमी आई और 31 मार्च 2024 तक यह ₹4.8 लाख करोड़ रह गया। जीएनपीए अनुपात मार्च

सारणी IV.8: लीवरेज अनुपात और चलनिधि व्याप्ति अनुपात

(प्रतिशत)

	लीवरेज अनुपात				चलनिधि व्याप्ति अनुपात			
	मार्च-22	मार्च-23	मार्च-24	मार्च-24	मार्च-22	मार्च-23	मार्च-24	सितं-24
1	2	3	4	5	6	7	8	9
पीएसबी	5.1	5.5	6.0	6.0	155.8	153.5	129.3	127.4
पीवीबी	9.7	9.6	9.7	10.0	127.7	127.9	127.1	126.1
एफबी	11.0	11.0	10.8	10.6	171.0	154.6	145.0	142.6
सभी एससीबी	7.2	7.4	7.8	7.9	147.1	144.6	130.3	128.6

स्रोत : परोक्ष विवरणियां (वैश्विक परिचालन), आरबीआई।

सारणी IV.9: निवल स्थिर निधीयन अनुपात
(मार्च 2024 के अंत तक)

(राशि ₹ करोड़ में)

1	उपलब्ध स्थिर निधीयन	आवश्यक स्थिर निधीयन	एनएसएफआर (प्रतिशत)
2	3	4	
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	1,11,95,611	88,65,493	126.3
निजी क्षेत्र के बैंक	77,28,087	60,47,820	127.8
विदेशी बैंक	6,78,655	5,34,056	127.1
लघु वित्त बैंक	2,04,965	1,63,860	125.1
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	1,98,07,318	1,56,11,229	126.9

स्रोत : परोक्ष विवरणियां, (वैश्विक परिचालन) आरबीआई

2024⁸ के अंत में घटकर 2.7 प्रतिशत हो गया, जो 13 वर्षों में सबसे कम है, जबकि मार्च 2023 के अंत में यह 3.9 प्रतिशत था। बेहतर वसूली और उन्नयन के कारण वर्ष 2023-24 के दौरान जीएनपीए में लगभग 44.4 प्रतिशत की कमी आयी।

IV.30 मार्च 2024 के अंत में, निवल अनर्जक आस्तियां (एनएनपीए) भी घटकर दशक के निचले स्तर 0.62 प्रतिशत पर आ गईं जो कि मजबूत प्रावधान बफर के कारण संभव हुआ

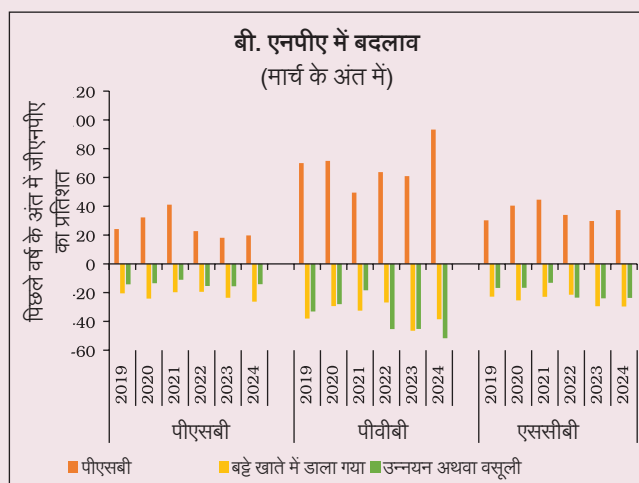
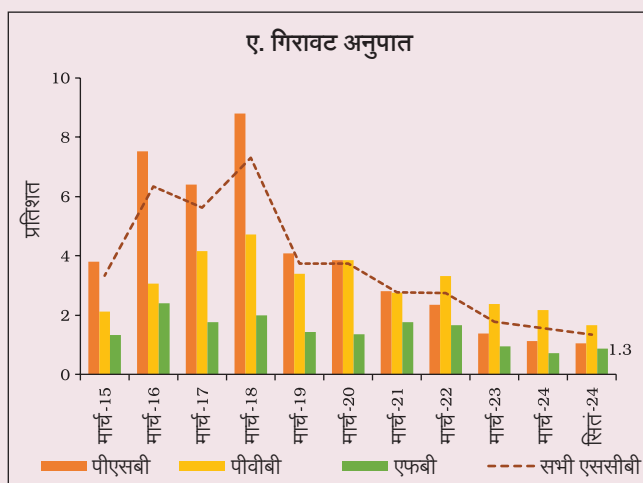
(सारणी IV.10)। सितंबर 2024 के अंत में एनएनपीए अनुपात सुधर कर 0.57 प्रतिशत हो गया।

IV.31 गिरावट अनुपात, जो वर्ष की शुरुआत में मानक अग्रिमों के हिस्से के रूप में एनपीए में नई वृद्धि को मापता है, 2023-24 के दौरान बेहतर हुआ (चार्ट IV.16ए)। लगातार तीसरे वर्ष, पीवीबी का गिरावट अनुपात पीएसबी की तुलना में अधिक रहा क्योंकि पीवीबी के एनपीए में नई वृद्धि अधिक रही (चार्ट IV.16बी)।

IV.32 आस्ति गुणवत्ता में इन लाभों को दर्शाते हुए, मार्च 2024 के अंत में सभी बैंक समूहों में कुल अग्रिमों में मानक आस्तियों का अनुपात एक वर्ष पहले की तुलना में बढ़ गया। अमानक अग्रिमों (जिसमें अवमानक, संदिग्ध और घाटे वाले अग्रिम शामिल हैं) की हिस्सेदारी में कमी संदिग्ध आस्तियों में कमी के कारण हुआ (सारणी IV.11)।

IV.33 एससीबी के कुल अग्रिमों में बड़े उधार खातों⁹ की हिस्सेदारी पिछले वर्ष के अंत में 46.5 प्रतिशत से घटकर मार्च 2024 के अंत में 43.9 प्रतिशत रह गई। विशेष उल्लेख खाता-1 (एसएमए-1)¹⁰ अनुपात में, कुल मिलाकर पीवीबी और

चार्ट IV.16: जीएनपीए में कमी



स्रोत: परोक्ष विवरणियां (वैश्विक परिचालन) और बैंकों के वार्षिक लेखा।

⁸ नवीनतम उपलब्ध पर्यवेक्षी आंकड़ों से पता चलता है कि सितंबर 2024 के अंत तक जीएनपीए अनुपात में और सुधार होकर यह 2.5 प्रतिशत हो जाएगा।

⁹ बड़े उधार खाते से तात्पर्य उन खातों से है जिनमें कुल ऋण 5 करोड़ रुपये या उससे अधिक है।

¹⁰ एसएमए-1 उन खातों को इंगित करता है जिनमें ब्याज या मूलधन का भुगतान 31-60 दिनों के बीच बकाया है।

सारणी IV.10 : अनर्जक आस्तियों में उतार-चढ़ाव - बैंक-समूह वार

(राशि ₹ करोड़ में)

	पीएसबी	पीवीबी	एफबी	एसएफबी*	सभी एससीबी
1	2	3	4	5	6
कुल एनपीए					
2022-23 के लिए अंतिम शेष	4,28,197	1,25,214	9,526	8,608	5,71,546
2023-24 के लिए प्रारंभिक शेष	4,28,197	1,25,214	9,526	8,608	5,71,546
वर्ष 2023-24 के दौरान योग	84,435	1,16,801	5,199	7,152	2,13,587
वर्ष 2023-24 के दौरान कमी (i+ii+iii)	1,73,090	1,12,852	8,202	10,170	3,04,314
i. वसूली	43,018	25,794	3,513	2,348	74,673
ii. उन्नयन	17,558	38,856	1,961	2,159	60,535
iii. बट्टे खाते में	1,12,515	48,202	2,728	5,662	1,69,106
2023-24 के लिए अंतिम शेष	3,39,541	1,29,164	6,523	5,590	4,80,818
कुल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में कुल एनपीए*					
2022-23 के लिए अंतिम शेष	5.0	2.3	1.9	4.7	3.9
2023-24 के लिए अंतिम शेष	3.5	1.9	1.2	2.4	2.7
निवल एनपीए					
2022-23 के लिए अंतिम शेष	1,02,532	29,510	1,656	1,622	1,35,320
2023-24 के लिए अंतिम शेष	72,544	31,594	799	1,796	1,06,732
निवल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में निवल एनपीए					
2022-23	1.2	0.5	0.3	0.9	0.9
2023-24	0.8	0.5	0.1	0.8	0.6

टिप्पणियाँ: 1. #: डेटा में अनुसूचित एसएफबी शामिल हैं।

2. *: संबंधित बैंकों के वार्षिक खातों से कुल एनपीए और परोक्ष विवरणियाँ (वैश्विक परिचालन) से कुल अग्रिम लेकर गणना की गई है।

स्रोत: बैंकों के वार्षिक खाते और परोक्ष विवरणियाँ (वैश्विक परिचालन), आरबीआई।

पीएसबी दोनों में और साथ ही बड़े उधार खातों में, गिरावट आई (चार्ट IV.17)।

IV.34 महामारी के बाद शुरू की गई समाधान योजनाओं (आरएसए 1.0 और आरएसए 2.0) के कारण 2021-22 में पुनर्चित खातों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी। इसके बाद, पुनर्चित मानक अग्रिम (आरएसए) की समय-सीमा समाप्त होने

और आस्ति गुणवत्ता में सुधार को दर्शाते हुए, पीएसबी और पीवीबी दोनों में पुनर्चित खातों की संख्या में कमी आई। सकल ऋणों और अग्रिमों में पुनर्चित मानक अग्रिमों (आरएसए) की हिस्सेदारी समग्र रूप से और साथ ही बड़े उधार खातों के लिए कम हो गई। सकल ऋणों और अग्रिमों में आरएसए की हिस्सेदारी पीएसबी की तुलना में पीवीबी के लिए कम रही (चार्ट IV.18)।

सारणी IV.11: बैंक समूह-वार ऋण आस्तियों का वर्गीकरण

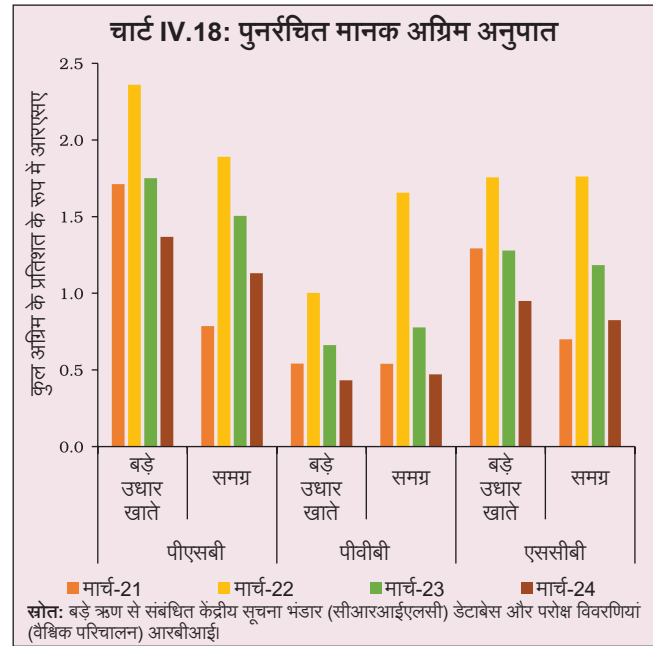
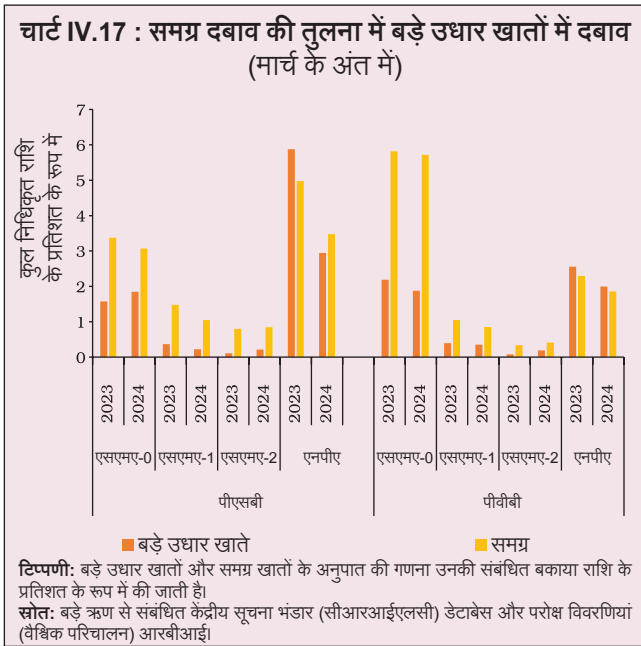
(राशि ₹ करोड़ में)

बैंक समूह	मार्च अंत	मानक आस्तियाँ		अवमानक आस्तियाँ		संदिग्ध आस्तियाँ		हानि आस्तियाँ	
		राशि	प्रतिशत*	राशि	प्रतिशत*	राशि	प्रतिशत*	राशि	प्रतिशत*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
पीएसबी	2023	72,86,427	94.8	62,444	0.8	2,28,806	3.0	1,10,054	1.4
	2024	84,24,922	96.3	58,576	0.7	1,78,483	2.0	83,681	1.0
पीवीबी	2023	51,99,732	97.8	34,288	0.6	52,469	1.0	29,033	0.5
	2024	66,96,942	98.2	44,199	0.6	52,944	0.8	26,397	0.4
एफबी	2023	4,89,212	98.1	1,697	0.3	6,648	1.3	1,182	0.2
	2024	5,39,598	98.8	1,344	0.2	4,228	0.8	950	0.2
एसएफबी**	2023	1,76,199	95.3	3,035	1.6	2,491	1.3	3,082	1.7
	2024	2,24,245	97.6	4,005	1.7	1,514	0.7	71	0.0
सभी एससीबी	2023	1,31,51,571	96.1	1,01,465	0.7	2,90,414	2.1	1,43,351	1.0
	2024	1,58,85,707	97.2	1,08,125	0.7	2,37,169	1.5	1,11,099	0.7

टिप्पणियाँ: 1. *: कुल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में।

2. **: अनुसूचित एसएफबी को संदर्भित करता है।

स्रोत: परोक्ष विवरणियाँ (घरेलू परिचालन), आरबीआई।



4.4 वसूलियां

IV.35 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतीकरण और पुनर्चना एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम के अंतर्गत आने वाले मामलों को छोड़कर, सभी चैनलों पर समाधान के लिए भेजे गए मामलों की संख्या में कमी आई है। 2023-24 के दौरान सरफेसी मामलों की संख्या में वृद्धि से निम्न आधार को परिलक्षित हुआ है क्योंकि 2022-23 के दौरान मामलों की संख्या में 24.6 प्रतिशत की कमी आई है। दिवाला एवं ऋण-शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) वसूली का प्रमुख माध्यम

बनी रही, जिसकी 2023-24 में वसूली गई कुल राशि में 48.1 प्रतिशत की हिस्सेदारी रही (सारणी IV.12)। आईबीसी के अंतर्गत सितंबर 2024 के अंत में प्राप्य मूल्य परिसमापन मूल्य का 161.1 प्रतिशत पर उच्च बना रहा।

IV.36 बैंकों ने आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) को एनपीए की बिक्री के माध्यम से अपनी तुलन पत्र को भी बेहतर किया। 2023-24 के दौरान, जीएनपीए का आस्ति की बिक्री का अनुपात पिछले वर्ष के 9.7 प्रतिशत से घटकर 5.8 प्रतिशत हो गया। बैंक समूहों में, एआरसी को अधिक बिक्री के साथ-साथ

सारणी IV.12: विभिन्न माध्यमों से एससीबी के एनपीए की वसूली

(राशि ₹ करोड़ में)

वसूली माध्यम	2022-23				2023-24 (पी)			
	संदर्भित मामलों की संख्या	शामिल राशि	वसूली गई राशि*	कॉलम (4), कॉलम (3) के प्रतिशत के रूप में	संदर्भित मामलों की संख्या	शामिल राशि	वसूली गई राशि*	कॉलम (8), कॉलम (7) के प्रतिशत के रूप में
1	2	3	4	5	6	7	8	9
लोक अदालतें	1,37,72,958	1,88,135	3,774	2.0	1,26,84,815	1,89,694	3,322	1.8
डीआरटी	56,198	4,02,753	39,785	9.9	31,414	1,06,887	16,202	15.2
सरफेसी अधिनियम	1,87,340	1,11,359	30,957	27.8	2,31,407	1,23,363	30,460	24.7
आईबीसी @	1,262	1,38,715	54,161	39.0	1,004	1,63,943	46,340	28.3
कुल	1,40,17,758	8,40,962	1,28,676	15.3	1,29,48,640	5,83,887	96,325	16.5

टिप्पणियां : 1. पी: अनंतिम।

2. *: दिए गए वर्ष के दौरान वसूल की गई राशि को संदर्भित करता है, जो दिए गए वर्ष के दौरान और साथ ही पिछले वर्षों के दौरान संदर्भित मामलों के संदर्भ में हो सकता है।

3. डीआरटी – वसूली अधिकरण

4. @: राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) द्वारा स्वीकार किए गए मामले।

स्रोत: परोक्ष विवरणियां, आरबीआई और भारतीय दिवाला एवं ऋण-शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई)।

भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति संबंधी रिपोर्ट 2023-24

जीएनपीए में कमी के कारण पीएसबी और एफबी से संबंधित अनुपात में वृद्धि हुई। पीवीबी के मामले में, एआरसी को बिक्री में गिरावट, जीएनपीए में कमी से अधिक थी, जिससे अनुपात नीचे आ गया (चार्ट 19ए)। उनके आस्तियों के बही खाता मूल्य के अनुपात के रूप में एआरसी की अधिग्रहण लागत 2023-24 में लगातार दूसरे वर्ष घटी जो आस्ति के प्राप्य मूल्य में कमी का संकेत देती है (चार्ट IV.19बी)।

IV.37 बैंकों और वित्तीय संस्थाओं ने मार्च 2024 के अंत में जारी कुल प्रतिभूति प्राप्ति (एसआर) में से 59.1 प्रतिशत सब्सक्राइब किया जो एक साल पहले यह 60.6 प्रतिशत और मार्च 2022 के अंत में 62.5 प्रतिशत था। यह निवेशक आधार के बढ़ते वैविध्य का संकेत है। अधिगृहीत आस्तियों के बही खाता मूल्य की तुलना में जारी एसआर का अनुपात 2022-23 के दौरान 29.4 प्रतिशत से घटकर 2023-24 के दौरान 27.6 प्रतिशत हो गया। पूरी तरह से भुनाए गए एसआर, जो इस माध्यम से वसूली का एक संकेतक है, पिछले वर्ष के 32.8 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 के दौरान पिछले वर्षों के बकाया एसआर का 37.5 प्रतिशत हो गया (सारणी IV.13)।

4.5 बैंकिंग क्षेत्र में धोखाधड़ी

IV.38 धोखाधड़ी वित्तीय प्रणाली के लिए प्रतिष्ठा जोखिम, परिचालन और व्यावसायिक जोखिम का कारण बनती है तथा

सारणी IV.13 : एआरसी द्वारा प्रतिभूतिकृत वित्तीय आस्तियों का विवरण

(राशि ₹ करोड़ में)

	मार्च-22	मार्च-23	मार्च-24
1	2	3	4
रिपोर्टिंग एआरसी की संख्या	29	28	27
1. अर्जित आस्तियों का खाता बही मूल्य	6,29,314	8,39,126	10,25,429
2. एससी/आरसी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीद	2,04,841	2,46,290	2,83,330
3. द्वारा सब्सक्राइब की गई प्रतिभूति रसीदें			
(ए) बैंक	1,28,007	1,49,253	1,67,483
(बी) एससी/आरसी	41,350	49,519	57,201
(सी) वित्तीय संस्थागत निवेशक	15,069	19,383	21,518
(डी) अन्य (पात्र संस्थागत क्रेता)	20,415	28,135	37,128
4. पूरी तरह से भुनाई गई प्रतिभूति रसीदों की राशि	31,331	41,078	52,332
5. बकाया प्रतिभूति रसीदें	1,25,359	1,39,422	1,48,070

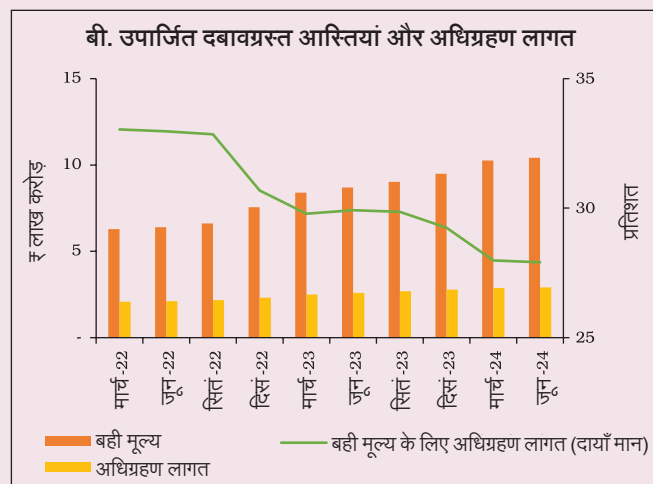
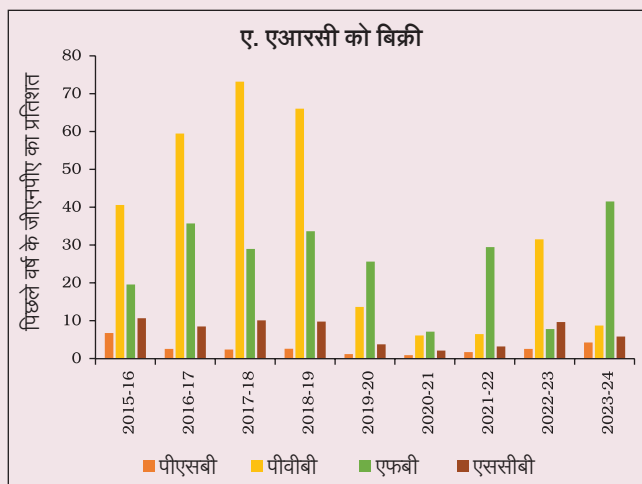
टिप्पणियाँ : 1. तिमाही के अंत तक कुल (संचयी/स्टॉक आंकड़े)।

2. एससी- प्रतिभूतिकरण कंपनियाँ और आरसी- पुनर्निर्माण कंपनियाँ।

स्रोत : एआरसी द्वारा प्रस्तुत त्रैमासिक विवरण।

वित्तीय स्थिरता को खतरा उत्पन्न करने के साथ-साथ बैंकिंग प्रणाली में ग्राहकों के विश्वास को क्षति पहुँचाती है। 2023-24 के दौरान, बैंकों द्वारा रिपोर्टिंग की तिथि के आधार पर, धोखाधड़ी में शामिल राशि एक दशक में सबसे कम थी, जबकि औसत मूल्य 16 वर्षों में सबसे कम था। (परिशिष्ट सारणी IV.7 और सारणी IV.14)।

चार्ट IV.19 : एआरसी को दबावग्रस्त आस्ति की बिक्री



स्रोत: एआरसी द्वारा प्रस्तुत त्रैमासिक विवरण और परोक्ष विवरणियाँ (घरेलू परिचालन), आरबीआई।

सारणी IV.14: रिपोर्टिंग की तारीख के आधार पर विभिन्न बैंकिंग परिचालनों में धोखाधड़ी

(राशि ₹ करोड़ में)

परिचालन क्षेत्र	2021-22		2022-23		2023-24		2023-24 (अप्रैल-सित)		2024-25 (अप्रैल-सित)	
	धोखाधड़ी की संख्या	शामिल राशि	धोखाधड़ी की संख्या	शामिल राशि	धोखाधड़ी की संख्या	शामिल राशि	धोखाधड़ी की संख्या	शामिल राशि	धोखाधड़ी की संख्या	शामिल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
अग्रिम	3,745	41,485	4,063	22,421	4,124	11,017	1,136	1,747	3,531	19,748
तुलन-पत्र से बाहर	21	1,077	14	285	11	256	4	73	0	0
विदेशी मुद्रा लेनदेन	7	7	13	12	19	38	5	5	6	1
कार्ड/इंटरनेट	3,596	155	6,699	277	29,082	1,457	12,069	630	13,133	514
जमा राशियां	471	493	652	258	2,002	240	915	103	934	363
अंतर-शाखा खाते	3	2	3	-	29	10	0	0	3	1
नकद	649	93	1,485	159	484	78	210	31	205	18
चेक/डीडी, आदि	201	158	118	25	127	42	60	14	49	54
समाशोधन खाते, आदि	16	1	18	3	17	2	2	0	3	1
अन्य	300	100	472	423	171	35	79	20	597	667
कुल	9,009	43,571	13,537	23,863	36,066	13,175	14,480	2,623	18,461	21,367

टिप्पणियां : 1. ₹1 लाख और उससे अधिक की धोखाधड़ी को संदर्भित करता है।
2. बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा रिपोर्ट किए गए आंकड़े उनके द्वारा दायर किए गए संशोधनों के आधार पर परिवर्तन के अधीन हैं।
3. एक वर्ष में रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग उस वर्ष से कई वर्ष पहले की भी हो सकती है।
4. इसमें शामिल राशि रिपोर्ट के अनुसार है और नुकसान की राशि को प्रतिबिंबित नहीं करती है। वसूलियों के आधार पर होने वाला नुकसान कम हो जाता है। इसके अलावा, ऋण खातों में शामिल पूरी राशि को दूसरे काम में नहीं लगाया जा सकता है।
5. 15 जुलाई 2024 को धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर संशोधित मास्टर निदेश जारी होने के बाद, बैंक केवल उन भुगतान प्रणाली से संबंधित लेनदेन की रिपोर्ट कर रहे हैं, जो बैंक(बैंकों) के साथ धोखाधड़ी के रूप में हुए हैं।

स्रोत : आरबीआई

IV.39 धोखाधड़ी की घटना की तारीख के आधार पर, वर्ष 2023-24 में कुल में इंटरनेट और कार्ड धोखाधड़ी की हिस्सेदारी बढ़कर राशि के संदर्भ में 44.7 प्रतिशत और मामलों की संख्या के संदर्भ में 85.3 प्रतिशत हो गई (सारणी IV.15)।

IV.40 वर्ष 2023-24 में पीवीबी द्वारा रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी के मामलों की संख्या कुल का 67.1 प्रतिशत थी (चार्ट IV.20ए)। हालांकि, शामिल राशि के संदर्भ में पीएसबी की हिस्सेदारी सबसे अधिक थी (चार्ट IV.20बी)। वर्ष 2023-24 में सभी बैंक

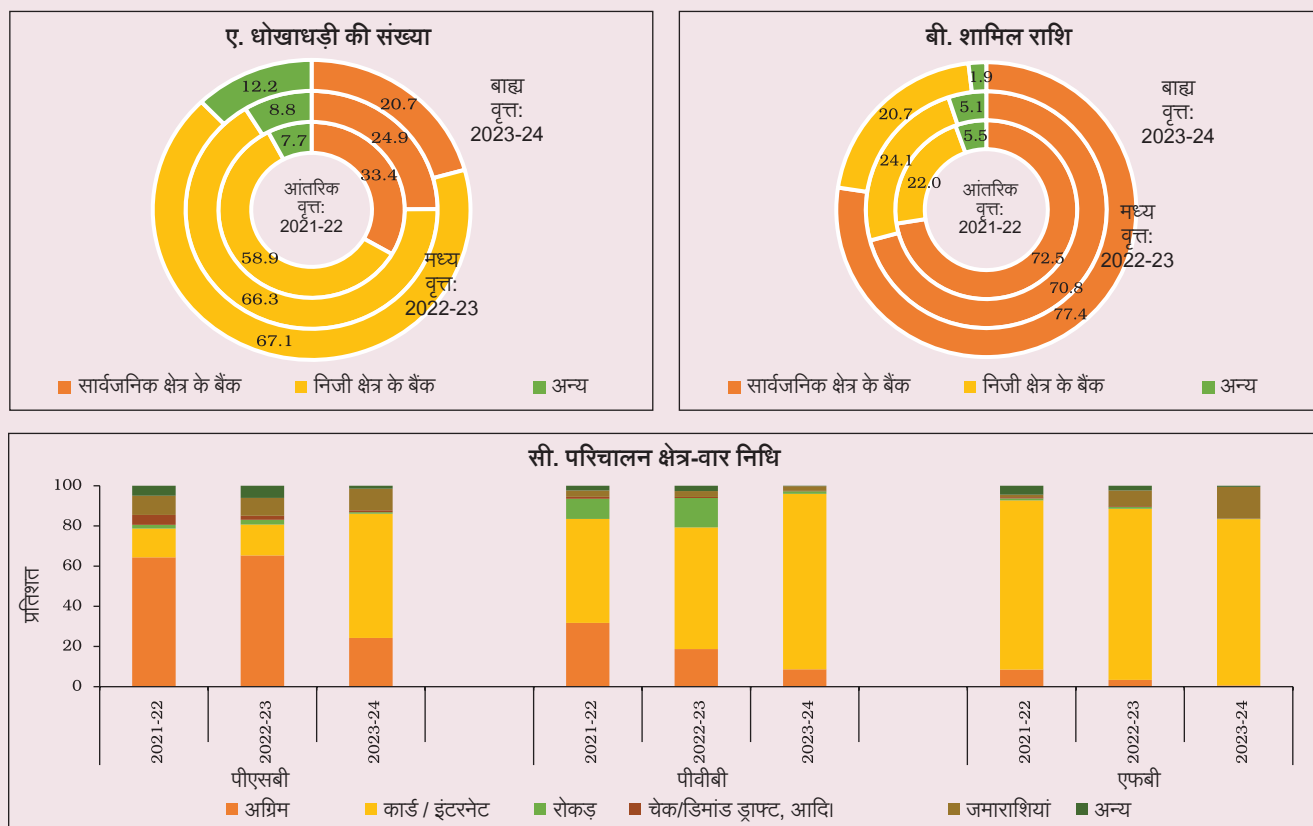
सारणी IV.15: घटना की तारीख के आधार पर विभिन्न बैंकिंग परिचालनों में धोखाधड़ी

(राशि ₹ करोड़ में)

परिचालन क्षेत्र	2021-22 से पहले		2021-22		2022-23		2023-24		2024-25 (अप्रैल-सित)	
	धोखाधड़ी की संख्या	शामिल राशि	धोखाधड़ी की संख्या	शामिल राशि	धोखाधड़ी की संख्या	शामिल राशि	धोखाधड़ी की संख्या	शामिल राशि	धोखाधड़ी की संख्या	शामिल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
अग्रिम	7,435	82,256	2,541	8,867	2,942	2,343	2,115	1,127	430	76
तुलन-पत्र से बाहर	40	1,592	2	27	4	0	0	0	0	0
विदेशी मुद्रा लेनदेन	3	1	9	8	21	47	11	2	1	0
कार्ड/इंटरनेट	1,078	165	4,395	173	11,979	626	27,604	1,214	7,454	225
जमा राशियां	519	621	456	122	716	200	1,903	230	465	182
अंतर-शाखा खाते	6	2	8	1	20	1	4	9	0	0
नकद	284	52	941	101	1,047	116	455	71	96	8
चेक/डीडी, आदि	108	156	169	29	107	22	89	36	22	36
समाशोधन खाते, आदि	9	1	19	4	14	1	12	2	0	0
अन्य	314	227	216	84	382	268	177	26	451	619
कुल	9,796	85,073	8,756	9,416	17,232	3,624	32,370	2,717	8,919	1,146

टिप्पणियां : 1. ₹1 लाख और उससे अधिक की धोखाधड़ी को संदर्भित करता है।
2. बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा रिपोर्ट किए गए आंकड़े उनके द्वारा दायर किए गए संशोधनों के आधार पर परिवर्तन के अधीन हैं।
3. घटना की तारीख पर आधारित डेटा कुछ समय के लिए बदल सकता है क्योंकि देर से रिपोर्ट की गई लेकिन पहले हुई धोखाधड़ी को जोड़ा जाएगा।
4. सारणी में आंकड़े वित्त वर्ष 2021-22 से 30 सितंबर 2024 तक रिपोर्ट किए गए मामलों से संबंधित हैं।
5. शामिल राशियां रिपोर्ट की गई राशि के अनुसार हैं और हुई हानि की राशि को नहीं दर्शाती हैं। वसूली के आधार पर हुई हानि कम हो जाती है। इसके अलावा, ऋण खातों में शामिल पूरी राशि को जरूरी नहीं कि डायवर्ट किया जाए।
6. 15 जुलाई 2024 को धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर संशोधित मास्टर निदेश जारी होने के बाद, बैंक केवल उन भुगतान प्रणाली से संबंधित लेनदेन की रिपोर्ट कर रहे हैं, जो बैंक(बैंकों) के साथ की गई धोखाधड़ी के रूप में हुए हैं।

स्रोत : आरबीआई

चार्ट IV.20 : बैंक समूह-वार धोखाधड़ी


टिप्पणी : 1. रिपोर्टिंग की तारीख के आधार पर धोखाधड़ी।
2. अन्य में समाशोधन खाते, विदेशी मुद्रा लेनदेन, अंतर-शाखा खाते, अनिवासी खाते, तुलन पत्र से इतर शामिल हैं।
स्रोत : आरबीआई।

समूहों में कार्ड और इंटरनेट धोखाधड़ियों की संख्या सर्वाधिक थी (चार्ट IV.20सी)।

4.6 प्रवर्तन कार्रवाइयां

IV.41 वर्ष 2023-24 के दौरान एफबी और एसएफबी को छोड़कर सभी बैंक समूहों में विनियमित संस्थाओं (आरई) पर लगाए गए जुर्माने की घटनाओं में वृद्धि हुई है। 2023-24 में कुल जुर्माने की राशि दोगुनी से अधिक हो गई, जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों की संख्या सबसे अधिक थी। सहकारी बैंकों पर लगाए गए जुर्माने की राशि में इस वर्ष कमी आई, जबकि जुर्माना लगाने की घटनाओं में वृद्धि हुई (सारणी IV.16)।

सारणी IV.16: प्रवर्तन कार्रवाइयां

विनियमित संस्थाएं	2022-23		2023-24	
	जुर्माना लगाने की घटना	कुल जुर्माना (₹ करोड़)	जुर्माना लगाने की घटना	कुल जुर्माना (₹ करोड़)
1	2	3	4	5
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	7	3.6	16	23.7
निजी क्षेत्र का बैंक	7	12.2	12	24.9
सहकारी बैंक	176	14.0	215	12.1
विदेशी बैंक	5	4.7	3	7.0
भुगतान बैंक	-	-	1	5.4
लघु वित्त बैंक	2	1.0	1	0.3
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	1	0.4	4	0.1
एनबीएफसी	11	4.4	22	11.5
एचएफसी	2	0.1	3	0.1
सीआईसी	-	-	4	1.0
कुल	211	40.4	281	86.1
स्रोत : आरबीआई				

5. क्षेत्रक-वार बैंक ऋण : वितरण और एनपीए

IV.42 वर्ष 2023-24 में बैंक ऋण वृद्धि आधार व्यापक थी, हालांकि इसका नेतृत्व सेवा क्षेत्र और वैयक्तिक ऋण खंड द्वारा किया गया, जिसके बाद कृषि और उद्योग का स्थान रहा (सारणी IV.17)¹¹। उपभोक्ता ऋण के कुछ उप-खंडों में उच्च वृद्धि और बैंकों की उधारी पर एनबीएफसी की बढ़ती

निर्भरता के कारण जोखिम से निपटने के लिए रिजर्व बैंक ने 16 नवंबर 2023 को इन क्षेत्रों में ऋण मानदंडों को सख्य बना दिया¹²। उपभोक्ता वस्तुओं, क्रेडिट कार्ड प्राप्तियों और एनबीएफसी को उधार, जैसे क्षेत्रों में बैंक ऋण वृद्धि, जिसके लिए जोखिम भार बढ़ाया गया था, में कमी आई है।

सारणी IV.17: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा सकल बैंक ऋण का क्षेत्रक-वार विनियोजन

(राशि ₹ करोड़ में)

क्षेत्र	के अंत में बकाया			प्रतिशत भिन्नता (व-द-व)		
	मार्च-23	मार्च-24	अक्तू-24	मार्च-23	मार्च-24	अक्तू-24
1. कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ	17,26,410	20,71,251	22,05,299	15.4	20.0	15.5
2. उद्योग (सूक्ष्म और लघु, मध्यम और बृहत)	33,66,406	36,52,804	37,74,252	5.8	8.5	7.9
		(36,35,810)	(37,59,186)		(8.0)	(8.0)
2.1. सूक्ष्म और लघु उद्योग	6,33,289	7,26,315	7,49,790	13.1	14.7	10.0
2.2. मध्यम	2,68,286	3,03,998	3,35,822	12.3	13.3	19.6
2.3. बृहत	24,64,831	26,22,490	26,88,640	3.5	6.4	6.0
3. सेवाएं, जिनमें से	37,18,805	45,92,227	47,84,938	19.5	23.5	12.7
		(44,90,467)	(47,04,550)		(20.8)	(14.1)
3.1. परिवहन परिचालक	1,92,059	2,30,175	2,46,407	14.7	19.8	15.0
3.2. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	24,924	25,917	30,581	7.1	4.0	24.0
3.3. पर्यटन, होटल और रेस्तरां	69,342	77,513	79,732	3.3	11.8	5.4
3.4. व्यापार	8,72,340	10,25,752	10,79,498	18.5	17.6	12.4
3.5. व्यापारिक स्थावर संपदा	3,22,591	4,69,013	5,07,671	8.4	45.4	13.9
		(4,00,470)	(4,52,869)		(24.1)	(26.0)
3.6. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी)	13,42,539	15,48,027	15,36,655	29.9	15.3	6.4
4. वैयक्तिक ऋण, जिनमें से	41,82,767	53,31,290	56,47,476	20.7	27.5	12.9
		(49,19,468)	(52,78,594)		(17.6)	(15.8)
4.1. टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं	20,985	23,713	23,640	17.7	13.0	6.6
4.2. आवास ऋण (प्राथमिकता प्राप्त आवास सहित)	19,91,164	27,18,715	28,71,845	14.5	36.5	12.1
		(23,31,935)	(25,25,138)		(17.1)	(17.8)
4.3. सावधि जमा के एवज में अग्रिम (एफसीएनआर (बी), एनआरएनआर जमाराशियां, आदि सहित)	1,22,484	1,25,239	1,27,533	46.4	2.2	10.9
4.4. व्यक्तियों को शेयरों, बांडों, आदि की जमानत पर अग्रिम	7,633	8,492	9,060	12.1	11.3	16.0
4.5. क्रेडिट कार्ड बकाया	2,04,708	2,57,016	2,81,392	32.5	25.6	16.9
4.6. शिक्षा ऋण	96,482	1,19,380	1,30,309	15.3	23.7	17.6
4.7. वाहन ऋण	5,01,979	5,89,251	6,16,405	24.0	17.4	11.4
4.8. स्वर्ण आभूषण के एवज में ऋण	89,370	1,02,562	1,54,282	19.6	14.8	56.2
5. बैंक ऋण	1,36,75,235	1,64,32,164	1,72,38,250	15.0	20.2	11.5
		(1,59,01,477)	(1,67,72,605)		(16.3)	(12.8)
5.1 गैर-खाद्य ऋण	1,36,55,330	1,64,09,083	1,72,19,596	15.4	20.2	11.5
		(1,58,78,397)	(1,67,53,951)		(16.3)	(12.8)

टिप्पणी : 1. आंकड़े अनतिम हैं।

2. 28 जुलाई 2023 से अब तक के आंकड़ों में किसी गैर-बैंक के बैंक में विलय के प्रभाव को शामिल किया गया है। कोष्ठक में दिए गए आंकड़ों में विलय के प्रभाव को शामिल नहीं किया गया है।

3. एनबीएफसी में एचएफसी, पीएफआई, सूक्ष्म वित्त संस्थान (एमएफआई), स्वर्ण ऋण में लगे एनबीएफसी और अन्य शामिल हैं।

स्रोत: आरबीआई

¹¹ बैंक ऋण, खाद्य ऋण और गैर-खाद्य ऋण डेटा पाक्षिक खंड -42 विवरणी पर आधारित हैं, जो सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) को शामिल करता है, जबकि क्षेत्रीय गैर-खाद्य ऋण डेटा क्षेत्रक-वार और उद्योग-वार बैंक ऋण (एसआईबीसी) विवरणी पर आधारित हैं, जो महीने के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार से संबंधित सभी एससीबी द्वारा दिए गए कुल गैर-खाद्य ऋण का लगभग 95 प्रतिशत हिस्सा देने वाले चुनिंदा बैंकों को कवर करता है।

¹² वाणिज्यिक बैंकों के उपभोक्ता ऋण जोखिम (बकाया और नए) के लिए जोखिम भार वैयक्तिक ऋणों के लिए 25 प्रतिशत अंक बढ़ाकर 125 प्रतिशत कर दिया गया, जिसमें आवास ऋण, शिक्षा ऋण, वाहन ऋण और स्वर्ण और स्वर्ण आभूषणों द्वारा संपार्श्विक ऋण शामिल नहीं हैं। इसके अलावा, एससीबी के क्रेडिट कार्ड प्राप्तियों के लिए जोखिम भार 25 प्रतिशत अंक बढ़ाकर 150 प्रतिशत कर दिया गया। एनबीएफसी को ऋण देने के लिए जोखिम भार में 25 प्रतिशत अंक की वृद्धि की गई।

IV.43 कुल ऋण में सेवाओं और वैयक्तिक ऋण खंडों की हिस्सेदारी मार्च 2013 के अंत में क्रमशः 21.9 प्रतिशत और 17.1 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2024 के अंत में क्रमशः 27.9

प्रतिशत और 32.4 प्रतिशत हो गई है¹³। ऋण विविधीकरण बैंकों को उनकी लाभप्रदता में सुधार करने में मदद कर सकता है (बॉक्स IV.3)।

बॉक्स IV.3: बैंकों की लाभप्रदता पर ऋण विविधीकरण का प्रभाव

पोर्टफोलियो विविधीकरण बैंकों की वित्तीय मध्यस्थता लागत को कम करता है और उनकी लाभप्रदता को बढ़ा सकता है (डायमंड, 1984)। हालांकि, क्षेत्र-वार ऋण विविधीकरण से मापन अदक्षता भी आ सकती है जो बैंकों की लाभप्रदता को कम कर सकती है (आचार्य, 2006)। इसलिए, बैंक लाभप्रदता पर क्षेत्र-वार ऋण विविधीकरण के प्रभाव का अनुभवजन्य साक्ष्य मिले-जुले हैं (मुलवा, 2018)।

मार्च 2015 से दिसंबर 2023 की अवधि के लिए 12 सार्वजनिक और 19 निजी क्षेत्र के बैंकों के तिमाही डेटा का उपयोग करके एक निश्चित प्रभाव पैनेल फ्रेमवर्क (समीकरण 1) में बैंकों की लाभप्रदता पर विविधीकरण के प्रभाव की जांच की जाती है।

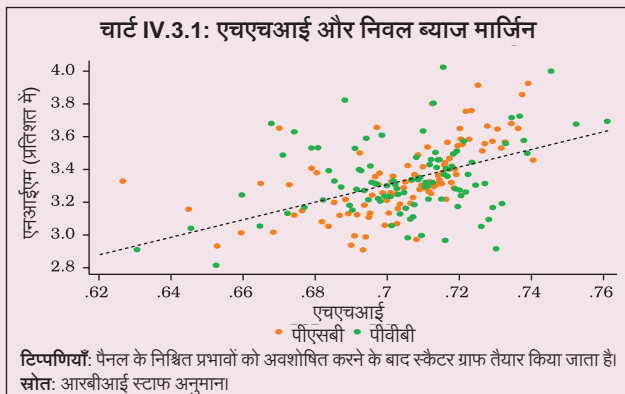
$$NIM_{it} = \beta_{i0} + \beta_1 D_{it} + \gamma V_{it} + \epsilon_{it} \quad (\text{समीकरण 1})$$

जहाँ, NIM, समय t पर बैंक i का निवल ब्याज मार्जिन है, D_{it} समय t पर बैंक i का विविधीकरण माप है, V_{it} बैंक आस्तियों, जीएनपीए अनुपात, ऋण वृद्धि और IIP वृद्धि सहित नियंत्रण चर का एक वेक्टर है। साहित्य से संदर्भ लेकर, दो विविधीकरण सूचकांक बनाए गए हैं - पहला हिश्मैन-हर्फीडाहल पद्धति का उपयोग कर और दूसरा शैनन एन्ट्रॉपी का उपयोग कर।

$$HHI_{it} = 1 - \sum_{i=1}^n s_{it}^2; \text{Entropy}_{it} = - \sum_{i=1}^n s_{it} \ln(s_{it})$$

जहाँ s_{it} समय t पर बैंक i के कुल ऋण में प्रत्येक सेक्टर¹⁴ का हिस्सा है। प्रत्येक सूचकांक का उच्च मूल्य उच्च पोर्टफोलियो विविधीकरण को दर्शाता है। स्कैटर प्लॉट पोर्टफोलियो विविधीकरण और बैंकों की लाभप्रदता के बीच धनात्मक संबंध को दर्शाता है (चार्ट IV.3.1)।

परिणाम से पता चलता है कि एनआईएम और विविधीकरण सूचकांकों के बीच धनात्मक और महत्वपूर्ण संबंध हैं, जिसने पोर्टफोलियो विविधीकरण ने लाभप्रदता के मामले में बैंकों को लाभ पहुंचाया है। इसके अधिशेष, जीएनपीए अनुपात द्वारा मापी गई आर्स्ति गुणवत्ता, एनआईएम के साथ ऋणात्मक



सारणी IV.3.1: प्रतिगमन परिणाम

चर	आश्रित चर: निवल ब्याज मार्जिन			
	(1)	(2)	(3)	(4)
लैंग (एचएचआई)	3.096*** (0.957)	2.201 (1.319)		
लैंग (एन्ट्रॉपी)			1.712*** (0.423)	1.595* (0.790)
लैंग (लॉग आस्तियां)	0.0404 (0.372)	-0.000524 (0.364)	-0.0168 (0.379)	-0.0248 (0.370)
लैंग (जीएनपीए अनुपात)	-0.0307*** (0.00544)	-0.0309*** (0.00542)	-0.0308*** (0.00548)	-0.0309*** (0.00549)
लैंग (ऋण वृद्धि) (वर्ष- दर-वर्ष)	0.00392 (0.00246)	0.00429 (0.00251)	0.00413 (0.00246)	0.00419 (0.00248)
एक्यूआर डमी	-0.183*** (0.0455)	-0.190*** (0.0494)	-0.189*** (0.0463)	-0.190*** (0.0509)
कोविड डमी	-0.00876 (0.0366)	-0.00214 (0.0348)	-0.00777 (0.0365)	-0.00632 (0.0353)
लैंग (पीवीबी*एचएचआई)		1.345 (1.671)		
लैंग (पीवीबी*एन्ट्रॉपी)				0.149 (0.911)
लॉग(आईआईपी)	1.337** (0.508)	1.402** (0.528)	1.348** (0.509)	1.364** (0.533)
स्थिरांक	-1.573 (1.495)	-1.441 (1.426)	-1.326 (1.498)	-1.283 (1.398)
प्रेक्षण	1,081	1,081	1,081	1,081
आर-स्क्वायर	0.738	0.738	0.739	0.739
स्थिर प्रभाव	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
बैंकों की संख्या	31	31	31	31

टिप्पणियाँ: 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े मजबूत मानक त्रुटियों को दर्शाते हैं।
2. ***, ** और * क्रमशः 1 प्रतिशत, 5 प्रतिशत और 10 प्रतिशत महत्व के स्तर को दर्शाते हैं।
3. कोविड डमी मार्च 2020 से मार्च 2022 तक समाप्त होने वाली तिमाहियों के दौरान मूल्य को 1 और अन्यथा शून्य माना है।
4. एक्यूआर डमी सितंबर 2015 से मार्च 2018 तक समाप्त होने वाली तिमाहियों के दौरान मूल्य को 1 और अन्यथा शून्य माना है।

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक स्टाफ का अनुमान।

रूप से सहसंबंधित है। विविधीकरण सूचकांकों (पीवीबी*एचएचआई और पीवीबी*एन्ट्रॉपी) के साथ निजी बैंक डमी की अंतःक्रिया द्वारा मापी गई पीवीबी बनाम पीएसबी की लाभप्रदता पर ऋण विविधीकरण का विभेदक प्रभाव, नगण्य पाया गया है। यह पीवीबी और पीएसबी दोनों की लाभप्रदता पर ऋण विविधीकरण के सममित प्रभाव को दर्शाते हैं (सारणी IV.3.1)।

संदर्भ:

Acharya, V., Hasan, I., & Saunders, A. (2006). Should Banks Be Diversified? Evidence from Individual Bank Loan Portfolios. *The Journal of Business*, 79(3), 1355–1412.
Diamond, D. (1984). Financial Intermediation and Delegated Monitoring. *The Review of Economic Studies*, 51(3), 393.
Mulwa, J. (2018). Sectoral Credit Diversification, Bank Performance and Monitoring Effectiveness: A Cross-country Analysis of East African Banking Industries. *Journal of Finance and Investment Analysis*, 7(2), 17–36.

¹³ मार्च 2024 के डेटा में एक गैर-बैंक का निजी क्षेत्र के बैंक के साथ विलय शामिल है। विलय को छोड़कर, मार्च 2024 के अंत में हिस्सेदारी इस प्रकार थी : सेवाएँ 28.2 प्रतिशत और वैयक्तिक ऋण 30.5 प्रतिशत।

¹⁴ क्षेत्रों में कृषि, उद्योग, सेवाएं और वैयक्तिक ऋण शामिल हैं।

IV.44 सितंबर 2024 के अंत में जीएनपीए अनुपात कृषि क्षेत्र के लिए सबसे अधिक (6.2 प्रतिशत) और खुदरा ऋणों के लिए सबसे कम (1.2 प्रतिशत) रहा। मार्च 2018 से औद्योगिक क्षेत्र की आस्ति गुणवत्ता में सुधार हो रहा है, सितंबर 2024 के अंत में जीएनपीए अनुपात घटकर 2.9 प्रतिशत रह गया। सभी बैंक समूहों में क्षेत्रक-वार ऋण का जीएनपीए अनुपात पिछले कुछ वर्षों में परिवर्तित हुआ है (चार्ट IV.21)।

IV.45 शिक्षा ऋणों का जीएनपीए अनुपात मार्च 2023 के अंत में 5.8 प्रतिशत से गिरकर मार्च 2024 के अंत में 3.6 प्रतिशत और सितंबर 2024 के अंत में 2.7 प्रतिशत हो गया, लेकिन यह खुदरा ऋणों में सबसे अधिक रहा, इसके बाद क्रेडिट कार्ड

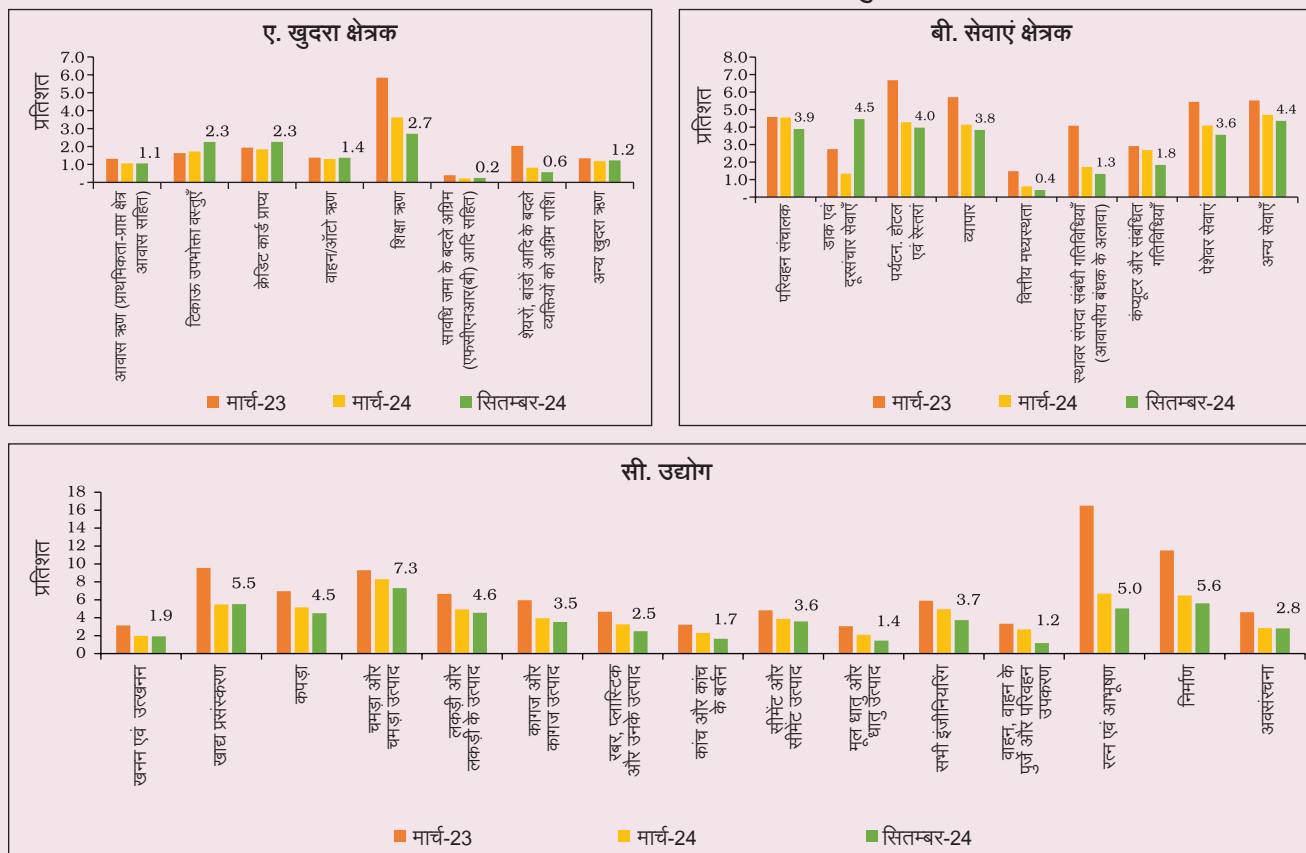
प्राप्तियों और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं में था (चार्ट IV.22ए)। सेवा क्षेत्र में, पर्यटन, होटल और रेस्तरां क्षेत्र का जीएनपीए अनुपात अधिक बना रहा, हालांकि यह मार्च 2023 के अंत में 6.7 प्रतिशत से गिरकर मार्च 2024 के अंत में 4.3 प्रतिशत और सितंबर 2024 के अंत में 4.0 प्रतिशत हो गया (चार्ट IV.22बी)। औद्योगिक उप-क्षेत्रों में, रत्न और आभूषण खंड का जीएनपीए अनुपात मार्च 2023 के अंत में 16.5 प्रतिशत से घटकर मार्च 2024 में 6.7 प्रतिशत और सितंबर 2024 के अंत में 5.0 प्रतिशत हो गया, जो आंशिक रूप से उच्च वसूली को दर्शाता है। सितंबर 2024 के अंत में, चमड़ा और चमड़ा उत्पाद उद्योग में हाल ही में कुछ सुधार के बावजूद सबसे अधिक 7.3 प्रतिशत जीएनपीए अनुपात था (चार्ट IV.22सी)।

चार्ट IV.21: क्षेत्रक-वार जीएनपीए अनुपात



स्रोत: परोक्ष विवरणियां (घरेलू परिचालन), आरबीआई।

चार्ट IV.22: विभिन्न उद्योगों में जीएनपीए अनुपात



स्रोत: परोक्ष विवरणियां (घरेलू परिचालन), आरबीआई।

5.1 एमएसएमई क्षेत्र को ऋण

IV.46 पीवीबी द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार वाले उद्यम क्षेत्रक एमएसएमई क्षेत्र को दिए ऋण में वृद्धि लगातार दोहरे अंकों में बनी हुई है, जो 2023-24 में 28.7 प्रतिशत तक पहुँच गई है। एससीबी द्वारा एमएसएमई क्षेत्र को दिया गया बकाया ऋण बढ़कर ₹27.25 लाख करोड़ हो गया, जो मार्च 2024 के अंत तक कुल समायोजित निवल बैंक ऋण (एनबीसी) का 19.3 प्रतिशत है।

IV.47 एससीबी के एमएसएमई ऋण खातों की संख्या 2023-24 के दौरान बढ़ी, जो 2020-21 से 2022-23 की अवधि के दौरान प्रवृत्ति को उलट देती है। एमएसएमई को दिए जाने वाले ऋण की मात्रा में वृद्धि, खातों की संख्या में वृद्धि की तुलना में मामूली रूप से अधिक थी, जिसके परिणामस्वरूप औसत ऋण में वृद्धि हुई (सारणी IV.18)।

5.2 प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक ऋण

IV.48 एससीबी का प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक उधार पिछले वर्ष के 10.8 प्रतिशत से बढ़ कर 2023-24 में 16.9 प्रतिशत हो गया, जिसमें पीवीबी (15.7 प्रतिशत से 23.5 प्रतिशत) और पीएसबी (7.1 प्रतिशत से 12.3 प्रतिशत) दोनों में वृद्धि शामिल है। सभी बैंक समूह अपने समग्र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार लक्ष्यों और उप-लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल रहे (सारणी IV.19)। चालू किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के तहत बकाया राशि भी पिछले वर्ष के 8.8 प्रतिशत की तुलना में 2023-24 के दौरान बढ़कर 10.7 प्रतिशत हो गई, जिसमें मुख्य योगदान दक्षिणी क्षेत्र का रहा। केसीसी के तहत बकाया राशि का सबसे अधिक हिस्सा भी दक्षिणी क्षेत्र का था। यद्यपि इसकी वृद्धि दर पिछले वर्ष के 18.3 प्रतिशत से घटकर

सारणी IV.18: एससीबी द्वारा एमएसएमई क्षेत्र को ऋण प्रवाह

(खातों की संख्या लाख में, बकाया राशि ₹ करोड़ में)

		2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	2	3	4	5	6	7
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	खातों की संख्या	111	151	150	139	144
		(-1.9)	(36.1)	(-0.7)	(-7.4)	(4.2)
	बकाया राशि	8,93,315	9,08,659	9,55,860	10,84,953	12,22,687
		(1.5)	(1.7)	(5.2)	(13.5)	(11.3)
निजी क्षेत्र के बैंक	खातों की संख्या	271	267	113	73	110
		(31.8)	(-1.4)	(-57.7)	(-35.2)	(50.2)
	बकाया राशि	6,46,988	7,92,042	9,69,844	10,89,833	14,02,324
		(14.8)	(22.4)	(22.4)	(12.4)	(28.7)
विदेशी बैंक	खातों की संख्या	3	3	2	2	3
		(14.1)	(-5.1)	(-19.0)	(-26.3)	(72.9)
	बकाया राशि	73,279	83,224	85,352	85,349	1,00,261
		(9.5)	(13.6)	(2.6)	(0.0)	(17.5)
सभी एससीबी	खातों की संख्या	384	420	265	213	257
		(19.8)	(9.4)	(-37.0)	(-19.4)	(20.5)
	बकाया राशि	16,13,582	17,83,925	20,11,057	22,60,135	27,25,272
		(6.8)	(10.6)	(12.7)	(12.4)	(20.6)

टिप्पणी : कोष्ठक में आंकड़े वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर को दर्शाते हैं
 स्रोत : आरबीआई

2023-24 के दौरान 13.2 प्रतिशत हो गई, फिर भी यह अखिल भारतीय विस्तार दर से ऊपर रही (परिशिष्ट सारणी IV.8)।

IV.49 प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण प्रमाणपत्रों (पीएसएलसी) की कुल ट्रेडिंग मात्रा 2023-24 के दौरान 25.5 प्रतिशत बढ़ी, जिसमें मुख्य योगदान पीएसएलसी-सामान्य का रहा।

सारणी IV.19: बैंकों द्वारा प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण (मार्च 2024 के अंत तक)

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	लक्ष्य/ उप-लक्ष्य (एएनबीसी/ सीईओबीई का प्रतिशत)	सार्वजनिक क्षेत्र बैंक		निजी क्षेत्र बैंक		विदेशी बैंक		लघु वित्त बैंक		अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	
		बकाया राशि	एएनबीसी/ सीईओबीई का प्रतिशत	बकाया राशि	एएनबीसी/ सीईओबीई का प्रतिशत	बकाया राशि	एएनबीसी/ सीईओबीई का प्रतिशत	बकाया राशि	एएनबीसी/ सीईओबीई का प्रतिशत	बकाया राशि	एएनबीसी/ सीईओबीई का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को अग्रिम जिसमें से	40/75*	31,85,092	42.6	24,09,329	47.4	2,51,550	41.6	1,31,967	90.6	59,77,938	45.0
सकल कृषि	18.0	14,25,554	19.1	9,51,089	18.7	49,700	18.6	38,964	26.8	24,65,307	19.0
छोटे और सीमांत किसान	10.0	8,32,757	11.2	5,05,484	10.0	29,309	11.0	26,517	18.2	13,94,068	10.8
गैर-कॉरपोरेट व्यक्ति कृषि	13.8	11,05,493	14.8	7,08,677	14.0	29,435	14.2	36,962	25.4	18,80,568	14.6
सूक्ष्म उद्यम	7.5	5,97,854	8.0	5,17,925	10.2	22,682	8.5	47,494	32.6	11,85,956	9.2
कमजोर वर्ग	12.0	10,53,784	14.1	6,37,014	12.5	32,284	12.1	52,146	35.8	17,75,229	13.7
टिप्पणियां : 1. बकाया राशि और उपलब्धि प्रतिशत वित्तीय वर्ष की चार तिमाहियों के लिए बैंकों की औसत उपलब्धि पर आधारित है। 2. *: लघु वित्त बैंकों के लिए कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण लक्ष्य 75 प्रतिशत है। 3. #: गैर-कॉरपोरेट किसानों के लिए लक्ष्य पिछले तीन वर्षों की उपलब्धि के प्रणाली-व्यापी औसत पर आधारित है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए लागू प्रणाली व्यापी औसत आंकड़ा 13.78 प्रतिशत था। 4. 20 से कम शाखाओं वाले विदेशी बैंकों के लिए, केवल 40 प्रतिशत का कुल पीएसएल लक्ष्य लागू है। 5. आंकड़े अनंतिम हैं।											
स्रोत : आरबीआई।											

टिप्पणियाँ : 1. बकाया राशि और उपलब्ध प्रतिशत वित्तीय वर्ष की चार तिमाहियों के लिए बैंकों की औसत उपलब्ध पर आधारित है।
 2. *: लघु वित्त बैंकों के लिए कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण लक्ष्य 75 प्रतिशत है।
 3. #: गैर-कॉरपोरेट किसानों के लिए लक्ष्य पिछले तीन वर्षों की उपलब्ध के प्रणाली-व्यापी औसत पर आधारित है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए लागू प्रणाली व्यापी औसत आंकड़ा 13.78 प्रतिशत था।
 4. 20 से कम शाखाओं वाले विदेशी बैंकों के लिए, केवल 40 प्रतिशत का कुल पीएसएल लक्ष्य लागू है।
 5. आंकड़े अनंतिम हैं।
 स्रोत : आरबीआई

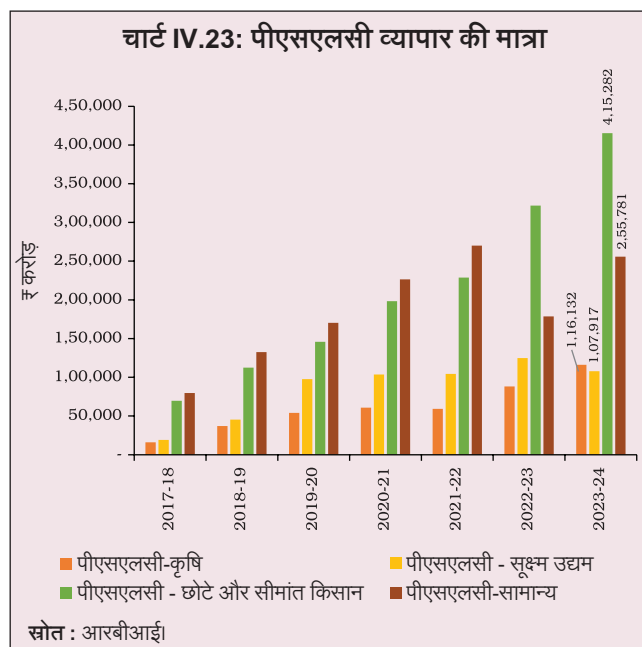
भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति संबंधी रिपोर्ट 2023-24

चार पीएसएलसी श्रेणियों में, छोटे और सीमांत किसान (एसएमएफ) श्रेणी ने सबसे अधिक ट्रेडिंग मात्रा दर्ज की, जो आंशिक रूप से कुछ बैंकों के मामले में विशेषज्ञता और अन्य बैंकों द्वारा उप-लक्ष्यों को पूरा करने में असमर्थता को दर्शाती है (चार्ट IV.23)।

IV.50 पिछले पांच वर्षों में, पीवीबी पीएसएलसी के प्रमुख निवल विक्रेता के रूप में उभरे हैं। 2023-24 में पीवीबी की कुल बिक्री में हिस्सेदारी 49.2 प्रतिशत है, जबकि पीएसबी के मामले में यह हिस्सेदारी 20.7 प्रतिशत है (चार्ट IV.24)।

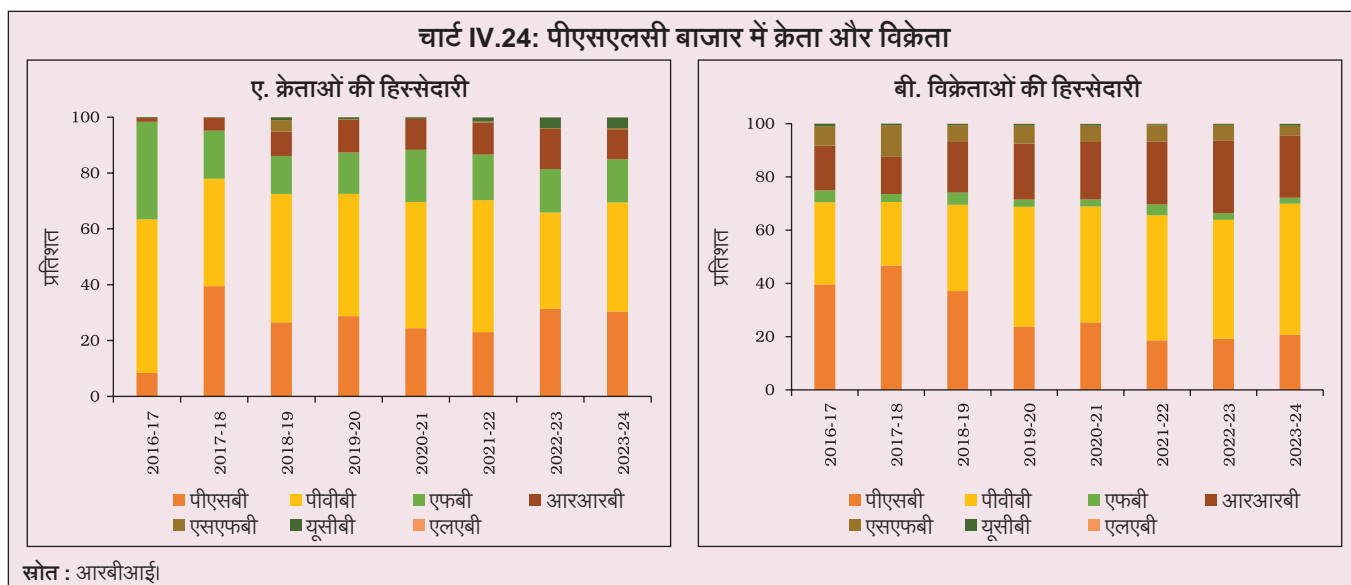
IV.51 पिछले तीन वर्षों में, पीएसएलसी-एसएमएफ को छोड़कर सभी श्रेणियों के लिए भारित औसत प्रीमियम (डब्ल्यूएपी) में गिरावट आई है। यह अन्य बातों के साथ-साथ पीएसएलसी-सूक्ष्म उद्यमों की कम मांग को दर्शाता है; क्योंकि बैंक इन क्षेत्रों को ऋण देने में आगे बढ़ रहे हैं ताकि पीएसएल उप-लक्ष्यों को व्यवस्थित रूप से पूरा किया जा सके (सारणी IV.20)।

IV.52 प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋण का जीएनपीए अनुपात मार्च 2023 के अंत में 5.4 प्रतिशत से घटकर मार्च 2024 के अंत में 4.4 प्रतिशत हो गया। फिर भी, गैर-प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में एनपीए में अधिक तेजी से गिरावट के कारण एससीबी



के कुल जीएनपीए में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की हिस्सेदारी मार्च 2023 के अंत में 51.1 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2024 के अंत में 57.3 प्रतिशत हो गई। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में एनपीए का सबसे बड़ा हिस्सा कृषि चूक का रहा।

IV.53 जहाँ, पीएसबी ने अपने एएनबीसी/ तुलनपत्रेतर एक्सपोजर (सीईओबीई) के ऋण का 42.6 प्रतिशत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिया, वहीं, इस पोर्टफोलियो का उनके कुल एनपीए में 64.2 प्रतिशत का हिस्सा रहा। एसएफबी के मामले



सारणी IV.20: पीएसएलसी की विभिन्न श्रेणियों पर भारित औसत प्रीमियम

(प्रतिशत)

	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2023-24 (अप्रै.-जून)	2024-25 (अप्रै.-जून)
1	2	3	4	5	6	7
पीएसएलसी-कृषि	1.55	1.37	0.62	0.24	0.27	0.24
पीएसएलसी- सूक्ष्म उद्यम	0.88	0.95	0.16	0.04	0.12	0.01
पीएसएलसी- लघु और सीमांत किसान	1.74	2.01	1.68	1.74	1.98	1.97
पीएसएलसी- सामान्य	0.46	0.6	0.19	0.02	0.02	0.01

स्रोत : आरबीआई

में, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उनके एएनबीसी/सीईओबीई का 90.6 प्रतिशत है; उनके कुल एनपीए में इसका हिस्सा पिछले वर्ष के 42.1 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 72.1 प्रतिशत हो गया (सारणी IV.21)।

5.3 संवेदनशील क्षेत्रों को ऋण

IV.54 पूंजी बाजार और अचल संपत्ति में बैंकों के निवेश को आस्ति की कीमतों में उतार-चढ़ाव में निहित जोखिमों को ध्यान में रखते हुए संवेदनशील माना जाता है। बैंकों के वार्षिक लेखा से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 2024 के

अंत में, इन क्षेत्रों में पीएसबी का निवेश उनके कुल ऋण और अग्रिमों का 22.1 प्रतिशत था, जो एक साल पहले के 21.7 प्रतिशत से अधिक था। संवेदनशील क्षेत्रों में पीवीबी का निवेश एक वर्ष पहले के 27.8 प्रतिशत की तुलना में बढ़कर उनके कुल ऋण और अग्रिमों का 34.7 प्रतिशत हो गया, जो काफी हद तक विलय के प्रभाव को दर्शाता है। एससीबी के पूंजी बाजार जोखिम में वृद्धि पिछले वर्ष के 20.2 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 के दौरान 31.3 प्रतिशत हो गई, जिसमें दोनों बैंक समूहों का योगदान रहा। (चार्ट IV.25ए और बी और परिशिष्ट सारणी IV.9)।

सारणी IV.21: बैंकों के क्षेत्रक-वार जीएनपीए (मार्च के अंत में)

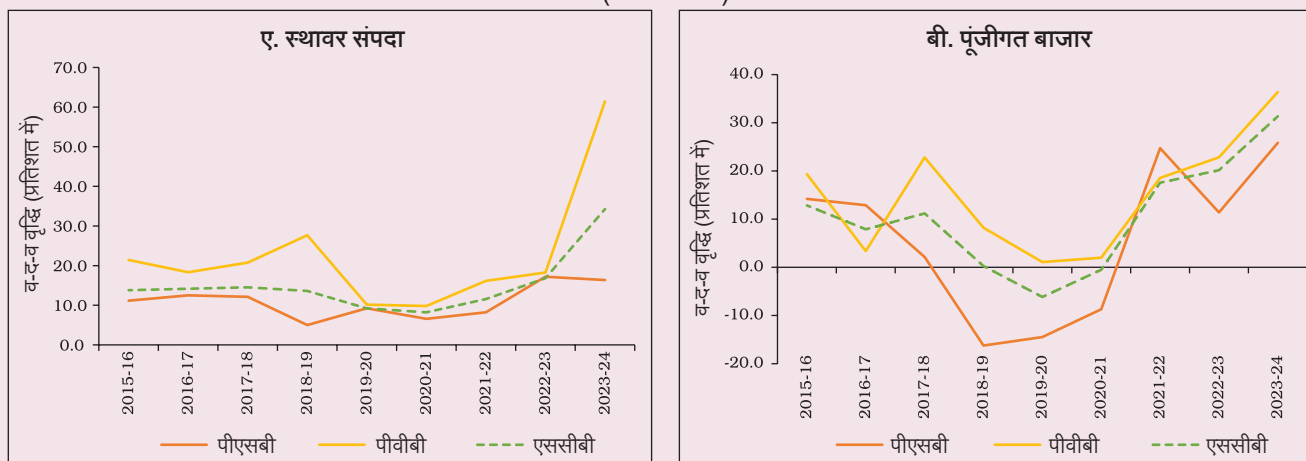
(राशि ₹ करोड़ में)

बैंक समूह	प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र		जिनमें						गैर-प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र		कुल एनपीए	
			कृषि		सूक्ष्म और लघु उद्यम		अन्य					
	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
पीएसबी												
2023	2,25,638	56.2	1,14,409	28.5	80,577	20.1	30,652	7.6	1,75,666	43.8	4,01,304	100.0
2024	2,05,777	64.2	1,06,451	33.2	75,278	23.5	24,049	7.5	1,14,963	35.8	3,20,740	100.0
पीवीबी												
2023	42,321	36.5	19,999	17.3	14,569	12.6	7,752	6.7	73,470	63.5	1,15,791	100.0
2024	49,986	40.5	21,211	17.2	18,340	14.8	10,435	8.4	73,553	59.5	1,23,540	100.0
एफबी												
2023	2,149	22.6	221	2.3	1,542	16.2	386	4.1	7,377	77.4	9,526	100.0
2024	1,795	27.5	162	2.5	1,315	20.2	318	4.9	4,728	72.5	6,523	100.0
एसएफबी												
2023	3,621	42.1	1,397	16.2	1,054	12.2	1,170	13.6	4,987	57.9	8,608	100.0
2024	4,031	72.1	1,878	33.6	1,137	20.3	1,015	18.2	1,560	27.9	5,590	100.0
सभी एससीबी												
2023	2,73,729	51.1	1,36,026	25.4	97,742	18.3	39,960	7.5	2,61,500	48.9	5,35,229	100.0
2024	2,61,589	57.3	1,29,701	28.4	96,070	21.0	35,817	7.8	1,94,804	42.7	4,56,393	100.0

टिप्पणी : प्रतिशत: कुल एनपीए का प्रतिशत।

स्रोत : परोक्ष विवरणियां (घरेलू परिचालन), आरबीआई।

चार्ट IV.25: संवेदनशील क्षेत्रों में एक्सपोजर
(मार्च-अंत में)



स्रोत : बैंकों का वार्षिक लेखा।

5.4 गैर-जमानती ऋण

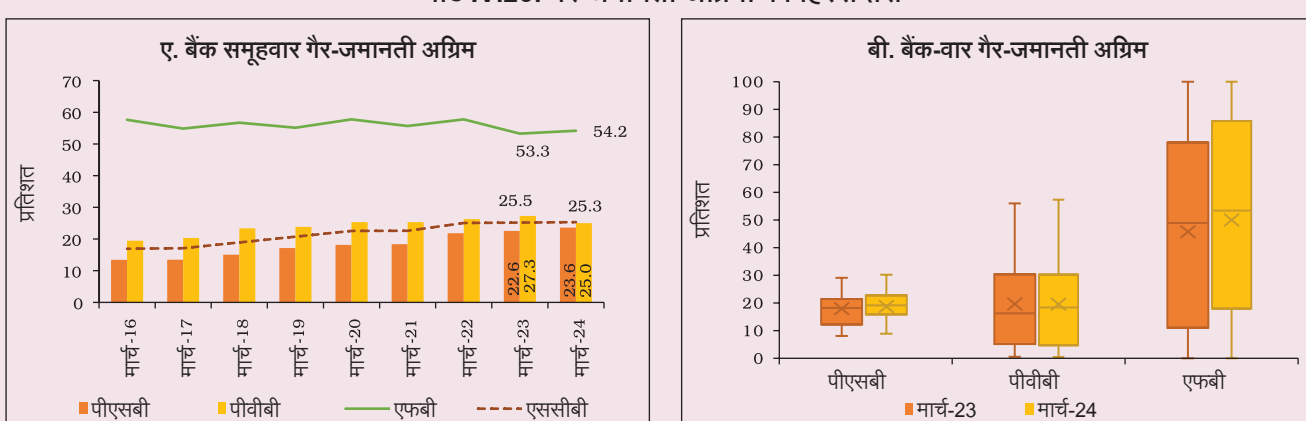
IV.55 संपार्श्विक की अनुपस्थिति या अपर्याप्तता के कारण गैर-जमानती ऋण चूक की स्थिति में बैंकों के लिए उच्च ऋण जोखिम उत्पन्न करते हैं। एससीबी के कुल ऋण में गैर-जमानती ऋणों की हिस्सेदारी मार्च 2015 के अंत से बढ़ रही थी, जो मार्च 2023 के अंत तक 25.5 प्रतिशत को छू गई। यह हिस्सा मार्च 2024 के अंत में मामूली रूप से घटकर 25.3 प्रतिशत हो गया, जिसका सबसे बड़ा हिस्सा पीवीबी का रहा, जो अन्य बातों के साथ-साथ इन क्षेत्रों में जोखिम

के निर्माण को रोकने के लिए रिजर्व बैंक के नवंबर 2023 के उपायों के प्रभाव को दर्शाता है (चार्ट IV.26ए)। विभिन्न बैंक समूहों में, पीएसबी के पास गैर-जमानती अग्रिमों का सबसे कम हिस्सा था, उसके बाद पीवीबी था। गैर-जमानती ऋणों के लिए बैंक-वार जोखिम का माध्य, माध्यिका और विसरण एफबी में सबसे अधिक था (चार्ट IV.26बी)।

6. वाणिज्यिक बैंकों में स्वामित्व का स्वरूप

IV.56 बैंकों का स्वामित्व पैटर्न बैंकों के अभिशासन, स्थिरता और समग्र प्रदर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 2023-

चार्ट IV.26: गैर-जमानती अग्रिमों की हिस्सेदारी



टिप्पणियां: 1. डेटा में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शामिल नहीं हैं।

2. बॉक्स प्लॉट की विहसकर्स अधिकतम और न्यूनतम मानों का संकेत हैं। एक रंगीन बॉक्स पहले क्वांटाइल और तीसरे क्वांटाइल के बीच की दूरी दिखाता है। प्रत्येक बॉक्स में क्षैतिज रेखा माध्यिका दिखाती है, जबकि 'X' माध्य दिखाता है।

स्रोत : बैंकों का वार्षिक लेखा।

24 के दौरान, केंद्र सरकार ने बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अपनी हिस्सेदारी घटाकर 75 प्रतिशत से नीचे कर दी (चार्ट IV.27ए)। इसके साथ ही, मार्च 2024 के अंत में सात सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता मानदंड को पूरा कर लिया। सरकार ने 19 जुलाई, 2024 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से अभी तक उक्त मानदंड को पूरा नहीं कर पाने वाले पांच सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 1 अगस्त, 2026 तक छूट प्रदान की है। पीवीबी का स्वामित्व स्वरूप अधिक विविध है (चार्ट IV.27बी)।

IV.57 2023-24 के दौरान, बैंकों में अनिवासी स्वामित्व पीवीबी, एलएबी और एसएफबी के लिए 74 प्रतिशत तथा पीएसबी के लिए 20 प्रतिशत की सीमा के भीतर रहा (परिशिष्ट सारणी IV.10)।

7. कॉरपोरेट अभिशासन

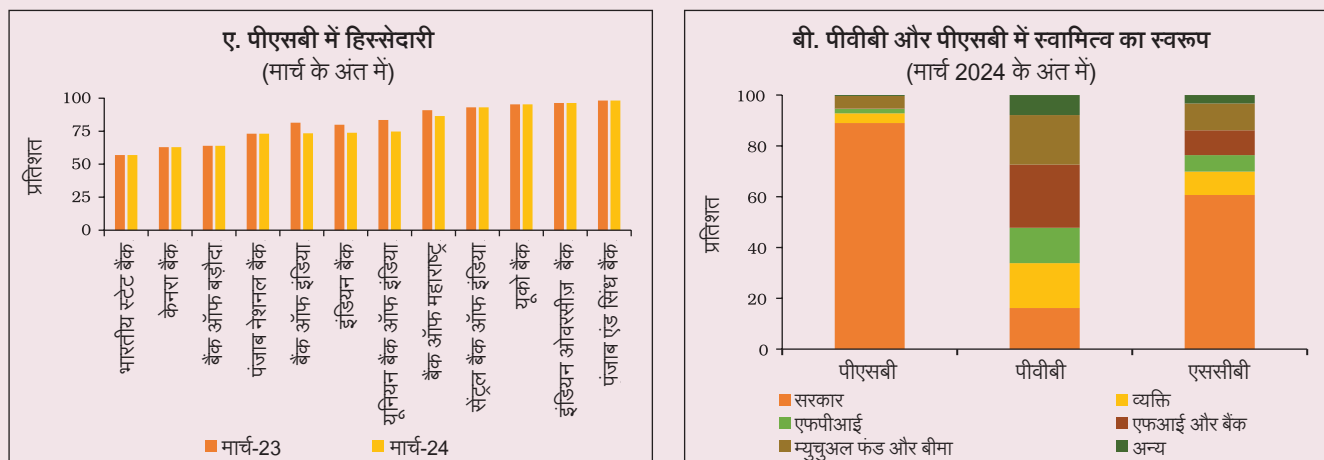
IV.58 कॉरपोरेट अभिशासन संसाधनों के आवंटन में दक्षता,

जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। रिज़र्व बैंक ने 26 अप्रैल, 2021 को बोर्ड की कुछ समितियों की संरचना; बोर्ड की अध्यक्षता और बैठकों; निदेशकों की आयु, कार्यकाल और पारिश्रमिक; और बैंकों में मजबूत और पारदर्शी जोखिम प्रबंधन और निर्णय लेने के लिए पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति के लिए मानदंड निर्धारित किए¹⁵

7.1 निदेशक मंडल का गठन

IV.59 स्वतंत्र निदेशक विशेष रूप से कार्यनीति, प्रदर्शन, जोखिम प्रबंधन, संसाधन, प्रमुख नियुक्तियों और आचरण के मानदंड संबंधी मुद्दों पर स्वतंत्र निर्णय प्रदान करके बोर्ड के विचार-विमर्श में योगदान देते हैं। मार्च 2024 के अंत में, पीवीबी और एसएफबी दोनों के लिए, बोर्ड और इसकी समिति में स्वतंत्र निदेशकों की हिस्सेदारी निर्धारित सीमा से बहुत अधिक थी (सारणी IV.22)।¹⁶

चार्ट IV.27: बैंकों के स्वामित्व का स्वरूप



टिप्पणी: एससीबी में 12 पीएसबी, 21 पीवीबी, 12 एसएफबी और 6 पीबी शामिल हैं।

स्रोत: आरबीआई और बीएसई वेबसाइट।

¹⁵ ये निर्देश सभी पीवीबी (एसएफबी सहित) और एफबी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों पर लागू किए गए थे। भारतीय स्टेट बैंक और राष्ट्रीयकृत बैंकों के संबंध में, इन दिशा-निर्देशों को केवल इस सीमा तक लागू करने के लिए निर्दिष्ट किया गया था कि वे उन पर लागू विशिष्ट कानूनों के प्रावधानों या कानूनों के तहत जारी किए गए निर्देशों के साथ असंगत न हों।

¹⁶ रिज़र्व बैंक द्वारा 26 अप्रैल, 2021 को कॉरपोरेट अभिशासन पर जारी किए गए अनुदेशों में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह अनिवार्य किया गया है कि बोर्ड की बैठकों में भाग लेने वाले कम से कम आधे निदेशक स्वतंत्र निदेशक होंगे; बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति की बैठक में भाग लेने वाले आधे सदस्य स्वतंत्र निदेशक होंगे, जिनमें से कम से कम एक सदस्य के पास जोखिम प्रबंधन में पेशेवर विशेषज्ञता/योग्यता होगी; एनआरसी की बैठक में भाग लेने वाले आधे सदस्य स्वतंत्र निदेशक होंगे, जिनमें से एक आरएमसीबी का सदस्य होगा; एससीबी की बैठक में भाग लेने वाले कम से कम दो-तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक होंगे।

सारणी IV.22: बोर्ड और उसकी समितियों के स्वतंत्र निदेशक (मार्च के अंत में)

प्रतिशत में हिस्सेदारी

	बोर्ड		बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी)		नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी)		बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी)	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
पीवीबी	65	65	67	70	78	85	83	87
एसएफबी	68	67	76	73	83	79	83	82

स्रोत: वार्षिक रिपोर्ट और बैंकों के वेबसाइट।

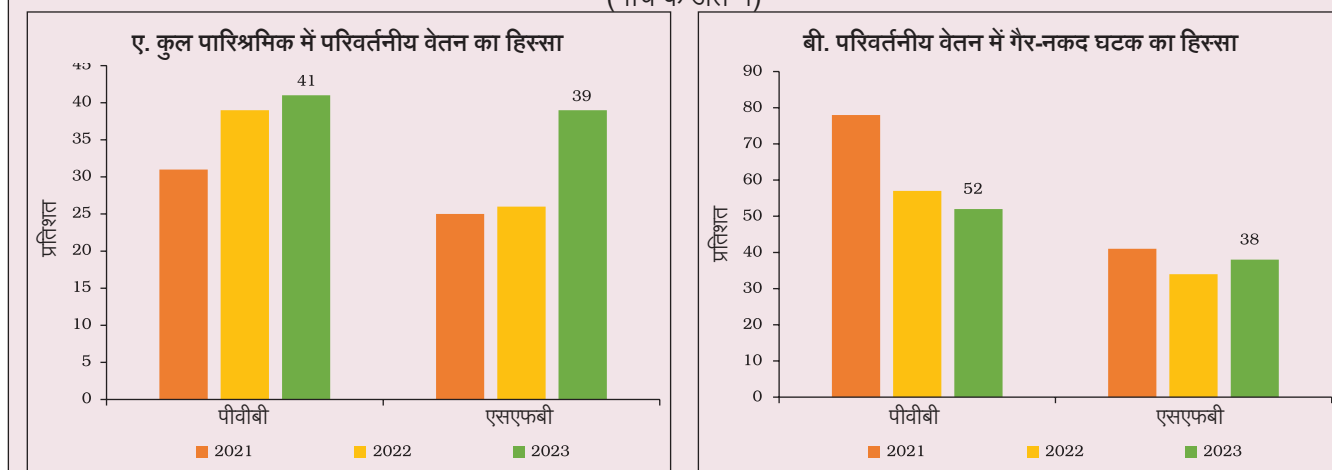
IV.60 बैंकों को बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) का गठन करना आवश्यक है, जिसमें गैर-कार्यकारी निदेशकों का बहुमत हो। बोर्ड का अध्यक्ष आरएमसीबी का सदस्य तभी हो सकता है जब उसके पास अपेक्षित जोखिम प्रबंधन विशेषज्ञता हो। पीवीबी का अनुपात, जिसमें अध्यक्ष आरएमसीबी का सदस्य नहीं है, मार्च 2024 के अंत में 38 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रहा। एसएफबी के लिए, अनुपात मार्च 2023 के अंत में 42 प्रतिशत से घटकर मार्च 2024 के अंत में 33 प्रतिशत हो गया।

7.2 कार्यपालकों को मुआवजा

IV.61 अल्पकालिक जोखिम लेने और दीर्घकालिक स्थिरता के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए, नवंबर 2019 के रिजर्व बैंक के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार मुआवजे का एक बड़ा

हिस्सा (कम से कम 50 प्रतिशत) परिवर्तनीय होना चाहिए और इसका भुगतान प्रदर्शन को पर्याप्त रूप से मापने वाले व्यक्तिगत, व्यवसाय-इकाई और फर्म-व्यापी संकेतकों के आधार पर किया जाना चाहिए।¹⁷ इसके अलावा दिशा-निर्देशों में यह भी कहा गया है कि यदि लक्ष्य परिवर्तनीय वेतन (टीवीपी) निर्धारित वेतन का 200 प्रतिशत (200 प्रतिशत से अधिक) है, तो टीवीपी का न्यूनतम 50 प्रतिशत (67 प्रतिशत) गैर-नकद घटकों के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। 2022-23 के दौरान, कुल पारिश्रमिक में वास्तविक वीपी की हिस्सेदारी पीवीबी और एसएफबी दोनों के लिए बेहतर हुई है (चार्ट IV.28ए)। वास्तविक वीपी में गैर-नकद घटक की हिस्सेदारी पीवीबी के लिए घटकर 52 प्रतिशत और एसएफबी के लिए बढ़कर 38 प्रतिशत हो गई (चार्ट IV.28बी)।

चार्ट IV.28: एमडी और सीईओ के कुल पारिश्रमिक के घटक
(मार्च के अंत में)



स्रोत : आरबीआई।

¹⁷ पूर्णकालिक निदेशकों/मुख्य कार्यकारी अधिकारियों/महत्वपूर्ण जोखिम लेने वालों और नियंत्रण कार्य कर्मचारियों के मुआवजे पर 4 नवंबर, 2019 को जारी दिशानिर्देश, 01 अप्रैल, 2020 से/उसके बाद शुरू होने वाले वेतन चक्रों के लिए प्रभावी हो गए हैं। ये दिशानिर्देश एलएबी, एसएफबी और पीबी सहित पीवीबी और शाखाओं और पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के माध्यम से भारत में परिचालन करने वाले एफबी पर लागू हैं।

8. भारत में विदेशी बैंकों का परिचालन और भारतीय बैंकों का विदेशी परिचालन

IV.62 2023-24 के दौरान, भारत में कार्यरत एफबी की संख्या में वृद्धि हुई क्योंकि विदेशी बैंकों में से एक, जिसका पहले केवल एक प्रतिनिधि कार्यालय था, ने पूरी तरह से कार्यशील बैंक शाखा खोली। हालाँकि, लगातार तीसरे वर्ष एफबी की शाखाओं की संख्या में गिरावट आई, जो वैश्विक रणनीति का पुनःसंरक्षण और व्यवसाय मूल्य अनुकूलन को दर्शाती है (सारणी IV.23)।

IV.63 भारतीय बैंक अपना विदेशी परिचालन मुख्य रूप से शाखाओं के माध्यम से करते हैं (चार्ट IV.29)। 2023-24 के दौरान, पीएसबी ने अव्यवहार्य शाखाओं को बंद करके अपनी विदेशी उपस्थिति को युक्तिसंगत बनाया, जबकि पीवीबी की विदेशी उपस्थिति अपरिवर्तित रही (परिशिष्ट सारणी IV.11)।

9. भुगतान प्रणालियां और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक

IV.64 भारत की भुगतान प्रणालियां तेजी से विकसित हुई हैं, जिसमें विविध आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए नवोन्मेष और समावेशन दोनों को अपनाया गया है, साथ ही उच्च सुरक्षा मानकों को भी बनाए रखा गया है। यह परिदृश्य पारंपरिक बैंकिंग चैनलों को अत्याधुनिक डिजिटल समाधानों के साथ जोड़ता है, जिससे सुरक्षित, त्वरित और सुविधाजनक लेनदेन संभव हो पाता है। यह परिवर्तन तकनीकी प्रगति, एक

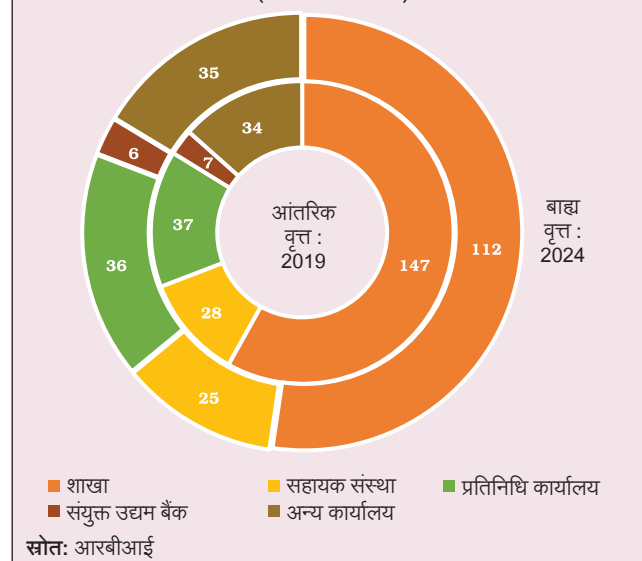
सारणी IV.23: भारत में विदेशी बैंकों का परिचालन

	शाखाओं/डबल्यूओएस के माध्यम से काम करने वाले विदेशी बैंक		प्रतिनिधि कार्यालय वाले विदेशी बैंक
	बैंकों की संख्या	शाखाएँ [#]	
1	2	3	4
मार्च-21	45	874	36
मार्च-22	45	861	34
मार्च-23	44	782	33
मार्च-24	45	780	31

टिप्पणी : # : इसमें दो विदेशी बैंक शामिल हैं अर्थात् एसबीएम बैंक (इंडिया) लिमिटेड और डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड जो पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (डबल्यूओएस) मोड के माध्यम से काम कर रहे हैं।

स्रोत : आरबीआई

चार्ट IV.29: भारतीय बैंकों का विदेशी परिचालन (मार्च के अंत में)



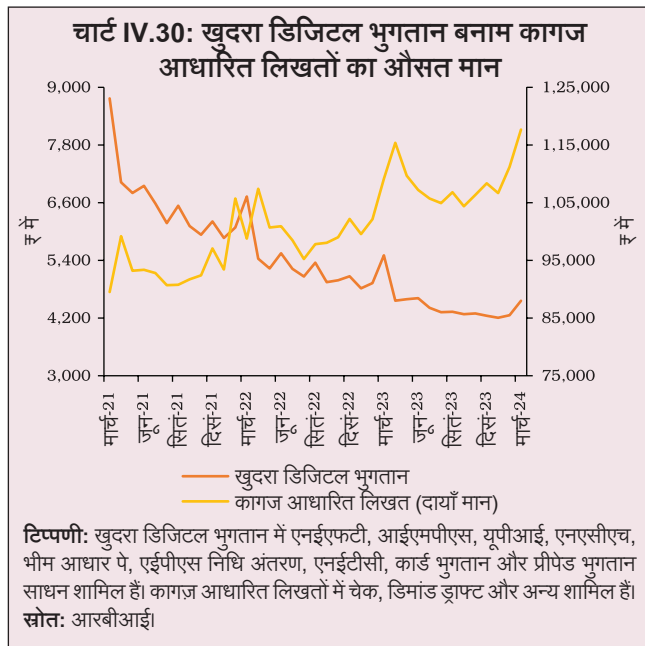
मजबूत विनियामकीय ढांचे और नकद रहित लेनदेन और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नीतिगत पहलों द्वारा प्रेरित है।

9.1 डिजिटल भुगतान

IV.65 2021-2024 के दौरान, डिजिटल भुगतान विधियों ने मात्रा के आधार पर 49.9 प्रतिशत और मूल्य के आधार पर 14.1 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) प्राप्त की। इसके विपरीत, चेक और डिमांड ड्राफ्ट जैसे कागज़-आधारित लिखतों में संकुचन हुआ, जिसमें मात्रा के आधार पर (-)10.1 प्रतिशत और मूल्य के आधार पर (-)1.6 प्रतिशत की सीएजीआर रही। छोटे मूल्य के भुगतान के लिए डिजिटल तरीकों की बढ़ती लोकप्रियता के साथ, खुदरा डिजिटल भुगतान का औसत मूल्य मार्च 2021 में ₹8,769 से घटकर मार्च 2024 में ₹4,560 हो गया है (चार्ट IV.30)

IV.66 मार्च 2024 के अंत में मूल्य के संदर्भ में कुल भुगतानों में से 97.1 प्रतिशत डिजिटल मोड के माध्यम से किए गए। लेन-देन की मात्रा के मामले में एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) का सबसे बड़ा हिस्सा है, जबकि मूल्य के मामले में तत्काल

भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति संबंधी रिपोर्ट 2023-24

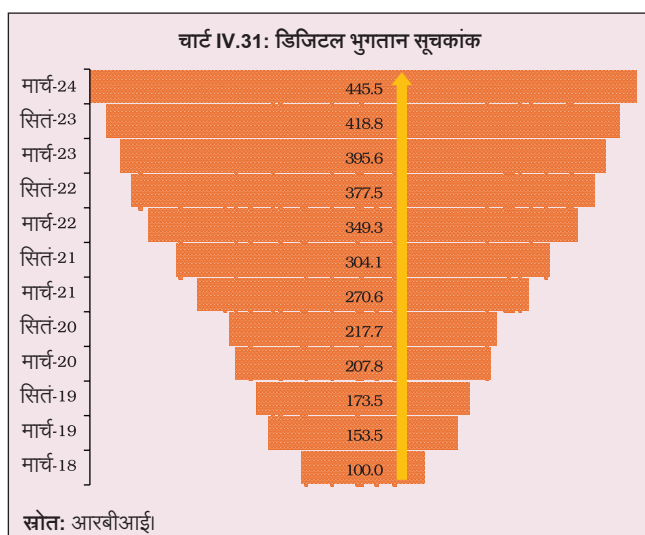


IV.67 रिज़र्व बैंक ने डिजिटलीकरण की प्रगति को मापने और डिजिटल भुगतान की गहनता और पैठ का आकलन करने के लिए जनवरी 2021 में एक समग्र डिजिटल भुगतान सूचकांक लॉन्च किया, जिसमें पाँच व्यापक मापदंड शामिल हैं: भुगतान सक्षमकर्ता; भुगतान अवसंरचना - मांग-पक्ष कारक; भुगतान अवसंरचना - आपूर्ति-पक्ष कारक; भुगतान प्रदर्शन; और उपभोक्ता केन्द्रीयता। सूचकांक की गणना अर्ध-वार्षिक रूप से मार्च 2018 को आधार वर्ष मानकर की जाती है। मार्च 2024 के अंत में, सूचकांक एक वर्ष पहले के 395.6 की तुलना में 445.5 पर था, जो पूरे देश में भुगतान प्रदर्शन और भुगतान अवसंरचना में उल्लेखनीय वृद्धि से प्रेरित था (चार्ट IV.31)।

सकल निपटान (आरटीजीएस) का सबसे बड़ा हिस्सा है (सारणी IV.24)।

सारणी IV.24: भुगतान प्रणाली संकेतक

	मात्रा (लाख)			मूल्य (₹ करोड़)		
	2021-22	2022-23	2023-24	2021-22	2022-23	2023-24
1	2	3	4	5	6	7
1. वृहत मूल्य ऋण अंतरण- आरटीजीएस	2,078	2,426	2,700	12,86,57,516	14,99,46,286	17,08,86,670
2. ऋण अंतरण	5,77,935	9,83,621	14,86,107	4,27,28,006	5,50,09,620	6,75,42,859
2.1 ईपीएस (निधि अंतरण)	10	6	4	575	356	261
2.2 एपीबीएस	12,573	17,834	25,888	1,33,345	2,47,535	3,90,743
2.3 ईसीएस	-	-	-	-	-	-
2.4 आईएमपीएस	46,625	56,533	60,053	41,71,037	55,85,441	64,95,652
2.5 एनएसीएच	18,758	19,257	16,227	12,81,685	15,41,815	15,25,104
2.6 एनईएफटी	40,407	52,847	72,640	2,87,25,463	3,37,19,541	3,91,36,014
2.7 यूपीआई	4,59,561	8,37,144	13,11,295	84,15,900	1,39,14,932	1,99,95,086
3. नामे अंतरण और प्रत्यक्ष नामे	12,189	15,343	18,250	10,34,444	12,89,611	16,87,658
3.1 भीम आधार पे	228	214	194	6,113	6,791	6,112
3.2 ईसीएस डीआर	-	-	-	-	-	-
3.3 एनएसीएच	10,755	13,503	16,426	10,26,641	12,80,219	16,78,769
3.4 एनईटीसी (बैंक खाते से जुड़ा हुआ)	1,207	1,626	1,629	1,689	2,601	2,777
4. कार्ड भुगतान	61,783	63,325	58,470	17,01,851	21,52,245	24,23,563
4.1 क्रेडिट कार्ड	22,399	29,145	35,610	9,71,638	14,32,255	18,31,134
4.2 डेबिट कार्ड	39,384	34,179	22,860	7,30,213	7,19,989	5,92,429
5. प्रीपेड भुगतान लिखत	65,783	74,667	78,775	2,79,416	2,87,111	2,83,048
6. कागजी लिखत	6,999	7,109	6,632	66,50,333	71,72,904	72,12,333
कुल डिजिटल भुगतान (1+2+3+4+5)	7,19,768	11,39,382	16,44,302	17,44,01,233	20,86,84,872	24,28,23,799
कुल खुदरा भुगतान (2+3+4+5+6)	7,24,689	11,44,065	16,48,234	5,23,94,049	6,59,11,490	7,91,49,461
कुल भुगतान (1+2+3+4+5+6)	7,26,767	11,46,491	16,50,934	18,10,51,565	21,58,57,776	25,00,36,131
स्रोत : आरबीआई						



9.2 एटीएम

IV.68 2023-24 के दौरान, स्वचालित टेलर मशीनों (एटीएम) (ऑन-साइट और ऑफ-साइट) की कुल संख्या में मामूली गिरावट आई, जिसका मुख्य कारण पीएसबी और व्हाइट-लेबल एटीएम (डब्ल्यूएलए) थे। मार्च 2024 के अंत में, पीएसबी और पीवीबी की हिस्सेदारी सभी एससीबी द्वारा लगाए गए कुल एटीएम में क्रमशः 61.6 प्रतिशत और 36.5 प्रतिशत थी (सारणी IV.25 और परिशिष्ट सारणी IV.12)।

सारणी IV.25 : एटीएम की संख्या
(मार्च अंत में)

बैंक समूह	ऑन साइट एटीएम		ऑफ-साइट एटीएम		एटीएम की कुल संख्या	
	2023	2024	2023	2024	2023 (2+4)	2024 (3+5)
1	2	3	4	5	6	7
पीएसबी	78,777	77,033	59,646	57,661	1,38,423	1,34,694
पीवीबी	41,426	45,438	35,549	34,446	76,975	79,884
एफबी	612	603	612	566	1,224	1,169
एसएफबी*	2,797	3,042	24	26	2,821	3,068
पीबी	1	0	62	0	63	0 [#]
सभी एससीबी	1,23,613	1,26,116	95,893	92,699	2,19,506	2,18,815
डब्ल्यूएलए	0	0	35,791	34,602	35,791	34,602
कुल	1,23,613	1,26,116	1,31,684	1,27,301	2,55,297	2,53,417

टिप्पणियाँ : 1. *: आंकड़े 12 अनुसूचित एसएफबी से संबंधित हैं।
2. #: पीबी द्वारा एटीएम बंद करने के कारण बड़ी गिरावट।

स्रोत : आरबीआई

IV.69 मार्च 2024 के अंत में, महानगरीय एटीएम में पीएसबी और पीवीबी की हिस्सेदारी लगभग बराबर थी। इसके विपरीत, पीएसबी ने ग्रामीण क्षेत्रों में 78.7 प्रतिशत एटीएम संचालित किए। अधिकांश डब्ल्यूएलए (83.9 प्रतिशत) ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में केंद्रित थे (सारणी IV.26)।

सारणी IV.26: एटीएम का भौगोलिक वितरण: बैंक समूह-वार
(मार्च 2024 के अंत में)

बैंक समूह	ग्रामीण	अर्ध-शहरी	शहरी	महानगरीय	कुल
1	2	3	4	5	6
सार्वजनिक क्षेत्र बैंक	28,784 (78.7)	39,773 (63.9)	34,100 (62.1)	32,037 (49.2)	1,34,694 (61.6)
निजी क्षेत्र बैंक	7,400 (20.2)	21,207 (34.1)	19,607 (35.7)	31,670 (48.7)	79,884 (36.5)
विदेशी बैंक	112 (0.3)	317 (0.5)	320 (0.6)	420 (0.6)	1,169 (0.5)
लघु वित्त बैंक*	282 (0.8)	938 (1.5)	896 (1.6)	952 (1.5)	3,068 (1.4)
भुगतान बैंक	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
सभी एससीबी	36,578 (100)	62,235 (100)	54,923 (100)	65,079 (100)	2,18,815 (100)
सभी एससीबी (व-द-व वृद्धि)	0.15	0.97	-0.84	-1.25	-0.29
डब्ल्यूएलए	17,496	11,550	3,766	1,790	34,602
डब्ल्यूएलए (व-द-व वृद्धि)	-4.63	-0.28	-1.23	-12.64	-3.32

टिप्पणियाँ : 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े प्रत्येक भौगोलिक समूह के अंतर्गत कुल एटीएम का प्रतिशत में हिस्सा दर्शाते हैं।
2. *: आंकड़े 12 अनुसूचित एसएफबी से संबंधित हैं।

स्रोत : आरबीआई

10. प्रौद्योगिकी अंगीकरण और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक

IV.70 हाल के वर्षों में बैंकिंग क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, जो प्रौद्योगिकी में तेज़ी से हुई प्रगति के कारण हुआ है। डिजिटल भुगतान से लेकर अन्य तकनीकों तक, जिन्होंने वित्तीय परिदृश्य में क्रांति ला दी है, जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (जेनएआई) में बढ़ती रुचि और वित्तीय क्षेत्र में इसके एकीकरण से वित्तीय क्षेत्र के लाभ के लिए आगे की प्रगति, नवोन्मेष, दक्षता और सुदृढ़ता को बढ़ावा देने की क्षमता है। हाल ही में रिज़र्व बैंक के एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि भारत में बैंक जीएआई को अपनाने के मामले में अभी शुरुआती चरण में हैं, हालांकि अधिकांश उत्तरदाताओं ने इसके संभावित लाभों को पहचाना है (बॉक्स IV.4)।

11. उपभोक्ता संरक्षण

IV.71 प्रौद्योगिकी आधारित बैंकिंग उत्पादों के आगमन और समाज के कमजोर वर्गों द्वारा इन उत्पादों के बढ़ते उपयोग के साथ, उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण ने अभूतपूर्व महत्व हासिल कर लिया है। इस उद्देश्य के लिए, रिज़र्व बैंक वैकल्पिक

शिकायत निवारण (एजीआर)¹⁸ तंत्र का संचालन करता है और आरई में आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र (आईजीआर) को विनियमित करता है।

11.1 शिकायत निवारण

IV.72 2023-24 के दौरान, केंद्रीकृत प्राप्ति और प्रसंस्करण केंद्र (सीआरपीसी) और भारतीय रिज़र्व बैंक लोकपाल कार्यालय (ओआरबीआईओ) को 9.34 लाख शिकायतें प्राप्त हुईं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 32.8 प्रतिशत की वृद्धि है। इन शिकायतों में से 31.5 प्रतिशत का समाधान ओआरबीआईओ द्वारा किया गया और शेष का निपटान सीआरपीसी में किया गया। वर्ष के दौरान ओआरबीआईओ द्वारा प्राप्त अधिकांश शिकायतें पीएसबी से संबंधित थीं, हालांकि कुल में उनकी हिस्सेदारी में गिरावट आई (चार्ट IV.32)।

IV.73 नवंबर 2021 से लागू रिज़र्व बैंक - एकीकृत लोकपाल योजना (आरबी-आईओएस) में संरचनात्मक परिवर्तन ने शिकायतों की श्रेणियों को युक्तिसंगत बनाया, जिसमें बहिष्करणों की एक निर्दिष्ट सूची को शामिल करते हुए 'सेवा में कमी' को शिकायत दर्ज करने का एकमात्र आधार बनाया गया। इसलिए,

बॉक्स IV.4: विनियमित संस्थाओं द्वारा जनरेटिव एआई को अपनाना

जेनएआई नियमित और दोहराए जाने वाले कार्यों को प्रभावी ढंग से कर सकता है, और संचालन की दक्षता को बढ़ा सकता है, उत्पादकता में सुधार कर सकता है और ग्राहक संतुष्टि में वृद्धि कर सकता है। साथ ही, यह गोपनीयता के उल्लंघन, जानबूझकर दुरुपयोग, पूर्वाग्रहों की शुरुआत या साइबर सुरक्षा और तीसरे पक्ष की निर्भरता जैसे मौजूदा जोखिमों के प्रवर्धन जैसे नए जोखिम भी पेश कर सकता है। अक्तूबर 2024 में रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार, 45 प्रतिशत उत्तरदाता आरई ने संकेत दिया कि वे कर्मचारियों को सहायता प्रदान करने और दस्तावेज सारांश जैसे कार्यों के लिए इसका उपयोग कर रहे थे (चार्ट IV.4.1ए)। 55 प्रतिशत उत्तरदाता, जो सर्वेक्षण किए जाने के

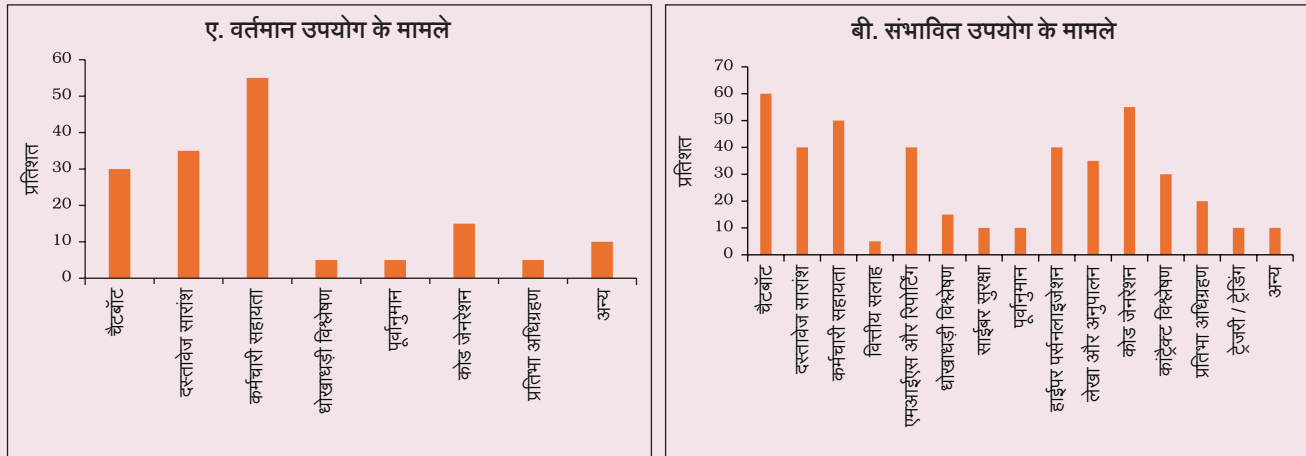
समय जेनएआई का लाभ नहीं उठा रहे थे, निकट भविष्य में इसी तरह के कार्यों के लिए इसे अपनाने पर विचार कर रहे थे (चार्ट IV.4.1बी)।

अपनाने वालों में से 20 प्रतिशत ने बताया कि वे विशिष्ट उपयोगों के लिए बिल्कुल नए सिरे से मॉडल बनाना पसंद करते हैं। फाइन ट्यूनिंग और डेटा रिट्रीवल के माध्यम से मौजूदा मॉडलों का विस्तार करना सबसे स्वीकार्य तरीका था (चार्ट IV.4.2)। ये रणनीतियाँ आरई को विशिष्ट उपयोग मामलों के लिए जेनएआई मॉडल को अनुकूलित करने, प्रदर्शन को बढ़ाने और मौजूदा वर्कफ़्लो में एआई क्षमताओं को सहजता से शामिल करने की अनुमति देती हैं।

(जारी)

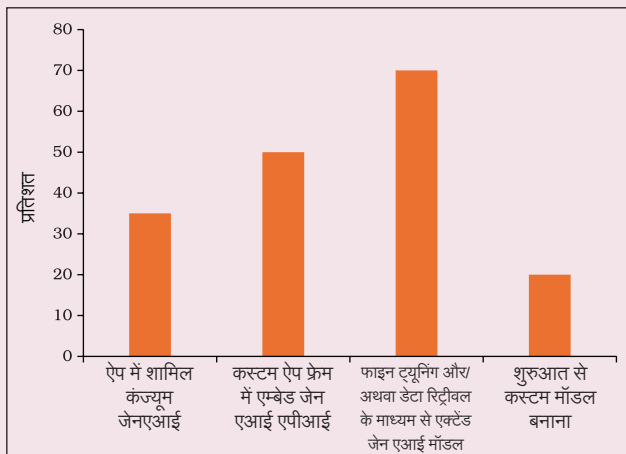
¹⁸ रिज़र्व बैंक के एजीआर ढांचे में आरबीआई लोकपाल (आरबीआईओ), उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण प्रकोष्ठ (सीईपीसी) तथा उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण विभाग (सीईपीडी) शामिल हैं। आरबीआईओ आरबी-आईओएस, 2021 के ढांचे के तहत काम करते हैं। सीईपीसी आरबी-आईओएस, 2021 के दायरे में नहीं आने वाले आरई के विरुद्ध शिकायतें लेता है। सीईपीडी आरबी-आईओएस के तहत अपील प्रक्रिया (एए) को सहायता प्रदान करता है और अपील के मामलों को संसाधित करता है।

चार्ट IV.4.1: विनियमित संस्थाओं में जेनएआई को अपनाना



टिप्पणी: सर्वेक्षण में, आरई को एक से अधिक वर्तमान या संभावित उपयोग के मामले चुनने की अनुमति दी गई थी।
स्रोत: आरबीआई

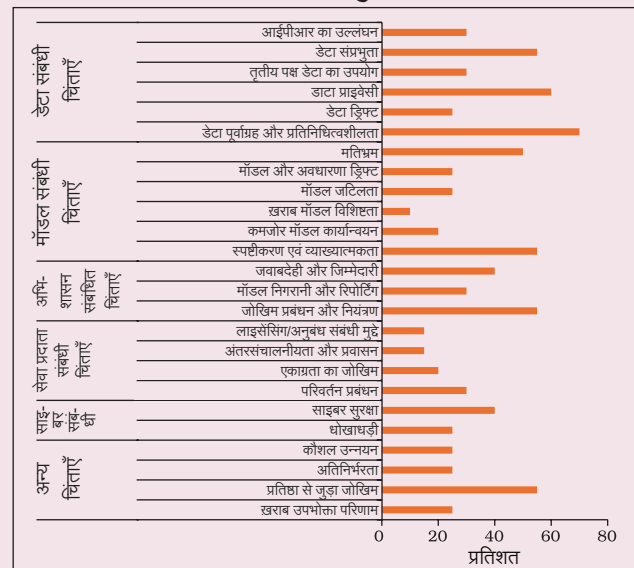
चार्ट IV.4.2: जेनएआई अपनाने के दृष्टिकोण



टिप्पणी : सर्वेक्षण में, आरई को अपने वर्तमान या संभावित उपयोग मामलों के लिए एक से अधिक दृष्टिकोण चुनने की अनुमति दी गई थी।
स्रोत: आरबीआई

चिंताओं के बीच, अधिकांश आरई ने डेटा पूर्वाग्रह और प्रतिनिधित्व को चुनौतियों के रूप में स्वीकार किया, इसके बाद डेटा गोपनीयता और मॉडलों की व्याख्या का स्थान रहा (चार्ट IV.4.3)। ऐसी चिंताओं को दूर करने के लिए, अधिकांश आरई ने ह्यूमन-इन-द-मिडल (एचआईटीएम) दृष्टिकोण¹⁹ को अपनाया। डेटा गोपनीयता संबंधी चिंताओं को कम करने के लिए, आरई ने जेनएआई-आधारित उपकरणों को प्रशिक्षित करने या उन्हें बेहतर बनाने के लिए गोपनीय या संवेदनशील डेटा

चार्ट IV.4.3: आरई द्वारा अनुभव किए गए जोखिम



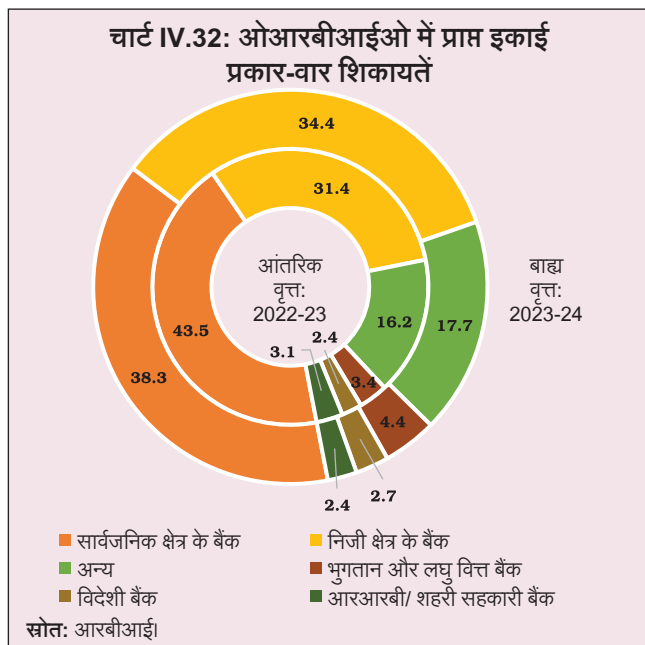
टिप्पणी : सर्वेक्षण में, विनियमित संस्थाओं को अनेक जोखिम चुनने की अनुमति दी गई थी।
स्रोत: आरबीआई

का उपयोग करने के बजाय सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डेटा या छद्म नाम वाली आंतरिक जानकारी का उपयोग करने की सूचना दी। सर्वेक्षण प्रतिभागियों में से 90 प्रतिशत ने कोर बैंकिंग और भुगतान प्रणालियों जैसे महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों के लिए जेनएआई का उपयोग नहीं करना पसंद किया।

शिकायतों की प्रकृति के आधार पर विभिन्न वर्षों में आकड़ों को कड़ाई से तुलनीय नहीं बनाया जा सकता है। उक्त चेतावनी के साथ, ऋण और अग्रिम, मोबाइल/इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग

और जमा खातों से संबंधित शिकायतें 2023-24 के दौरान सबसे अधिक थीं, जो कुल शिकायतों का 64 प्रतिशत थीं (सारणी IV.27)।

¹⁹ एचआईटीएम एक दृष्टिकोण को संदर्भित करता है जिसके तहत एआई प्रणालियों के उपयोग में निरंतर मानवीय निरीक्षण, निर्णय और नियंत्रण को एकीकृत किया जाता है, ताकि अन्य बातों के साथ-साथ एआई-जनरेटेड आउटपुट की गुणवत्ता, विश्वसनीयता, सुरक्षा और नैतिक संरेखण सुनिश्चित किया जा सके।



IV.74 वर्ष 2023-24 के दौरान आरबीआईओ को प्राप्त कुल शिकायतों में शहरी और महानगरीय क्षेत्रों से प्राप्त शिकायतों का हिस्सा 71.6 प्रतिशत था, जो इन क्षेत्रों में रिजर्व बैंक के शिकायत निवारण तंत्र के बारे में अधिक जागरूकता को दर्शाता है (चार्ट IV.33ए)। आरबीआईओ को प्राप्त कुल शिकायतों में पीएसबी और पीवीबी का हिस्सा 72.7 प्रतिशत था। पेंशन से संबंधित लगभग सभी शिकायतें पीएसबी के विरुद्ध दर्ज की गईं, जिन्हें पारंपरिक रूप से पेंशनभोगी पसंद करते हैं।

सारणी IV.27: आरबीआईओ में शिकायतों की प्रकृति

	2021-22	2022-23	2023-24
1	2	3	4
ऋण और अग्रिम	30,734	59,762	85,281
मोबाइल / इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग	42,271	43,167	57,242
जमा खाते	16,989	34,481	46,358
क्रेडिट कार्ड	34,828	34,151	42,329
एटीएम/डेबिट कार्ड	41,849	29,929	25,231
अन्य	36,607	22,551	24,355
परा बैंकिंग	1,608	2,782	4,380
पेंशन भुगतान	6,206	4,380	4,108
प्रेषण	3,443	2,940	4,101
नोट और सिक्के	302	511	539
उचित व्यवहार संहिता का पालन न करना	37,880	20	-
बिना पूर्व सूचना के शुल्क लगाना	14,519	3	-
डीएसए और रिकवरी एजेंट	1,640	7	-
प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में विफलता	22,420	5	-
बीसीएसबीआई कोड का पालन न करना	5,069	1	-
बीओ योजना के दायरे से बाहर	8,131	-	-
कुल	3,04,496*	2,34,690^	2,93,924@

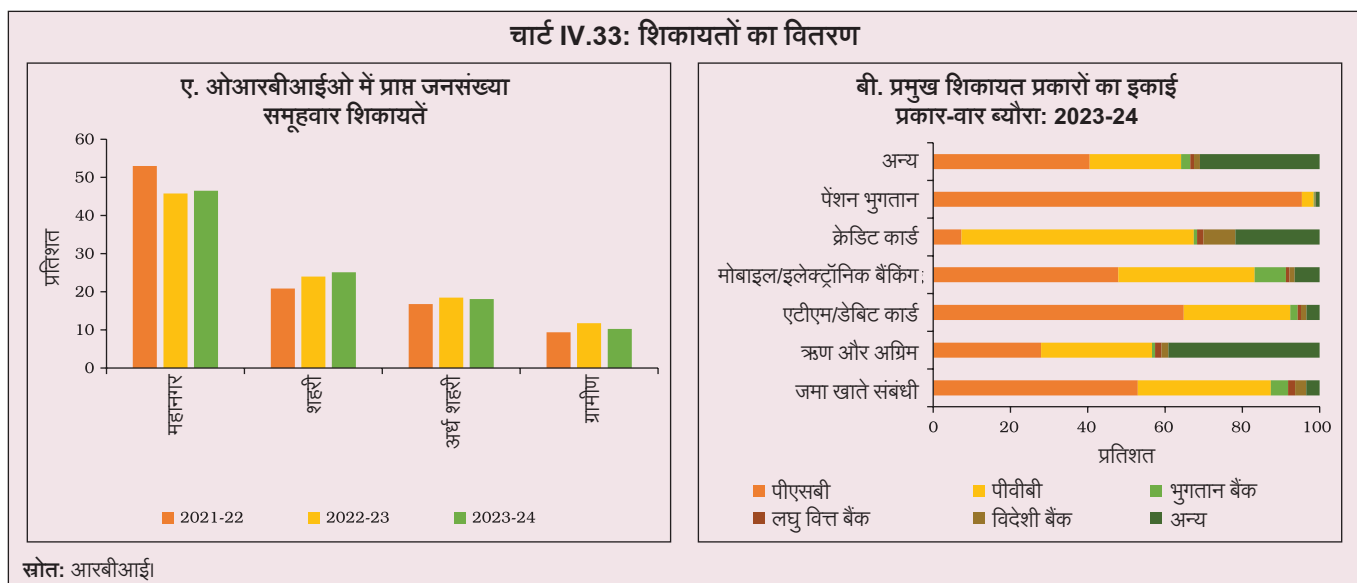
टिप्पणियाँ : 1. *: सीआरपीसी द्वारा निपटाई जाने वाली 1,13,688 शिकायतों को शामिल नहीं किया गया है।
2. ^: सीआरपीसी द्वारा निपटाई जाने वाली 4,68,854 शिकायतों को शामिल नहीं किया गया है।
3. @: सीआरपीसी द्वारा निपटाई जाने वाली 6,40,431 शिकायतों को शामिल नहीं किया गया है।

स्रोत : आरबीआई

दूसरी ओर, क्रेडिट कार्ड से संबंधित शिकायतों का एक बड़ा हिस्सा (60.1 प्रतिशत) पीवीबी के विरुद्ध दर्ज किया गया (चार्ट IV.33बी)।

11.2 जमा बीमा

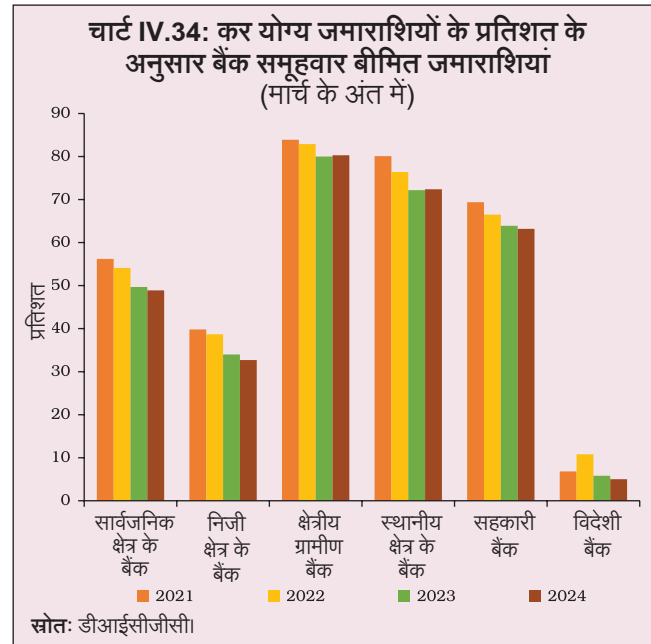
IV.75 जमा बीमा वित्तीय सुरक्षा-जाल प्रणाली का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, जो बैंकिंग क्षेत्र में जनता के विश्वास को, विशेष



रूप से छोटे जमाकर्ताओं के बीच, बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और समग्र वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देता है। भारत में, रिज़र्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) आरआरबी, एलएबी और सहकारी बैंकों सहित सभी वाणिज्यिक बैंकों को कवर करते हुए जमा बीमा का प्रबंधन करती है। मार्च 2024 के अंत में डीआईसीजीसी द्वारा 1,997 बैंकों का बीमा किया गया था। वर्तमान में, भारत में जमा बीमा कवरेज सीमा प्रति खाता प्रति जमाकर्ता ₹5 लाख है। यह सीमा 97.7 प्रतिशत जमा खातों को कवर करती है और मूल्य के संदर्भ में, 43.1 प्रतिशत मूल्यांकन योग्य जमा राशियों का बीमा किया जाता है (सारणी IV.28)।

IV.76 2023-24 में मूल्यांकन योग्य जमा राशियों में बीमाकृत जमा राशियों का अनुपात घट गया, जो बढ़ते जमा आधार को दर्शाता है (चार्ट IV.34)।

IV.77 डीआईसीजीसी के साथ मिलकर जमा बीमा निधि (डीआईएफ) का गठन किया जाता है, ताकि परिसमापन या सर्वसमावेशी निर्देश (एआईडी) लागू होने की स्थिति में बीमित



जमा राशियों के दावों का निपटान किया जा सके। 2023-24 के दौरान, डीआईएफ के माध्यम से ₹1,432 करोड़ के दावों का निपटान किया गया। मार्च 2024 के अंत में, डीआईएफ में जमाशेष राशि ₹1,98,753 करोड़ थी। बीमित जमा राशियों (9.1 प्रतिशत) की तुलना में डीआईएफ (17.2 प्रतिशत) की

सारणी IV.28: बैंक समूह-वार बीमाकृत जमा राशि

(राशि ₹ करोड़ में)

बैंक समूह	31 मार्च 2023 के अंत में				31 मार्च 2024 के अंत में (पी)			
	बीमाकृत बैंकों की संख्या	बीमित जमा	निर्धारणीय जमा	आईडीआर {(3) / (4)}	बीमाकृत बैंकों की संख्या	बीमित जमा	निर्धारणीय जमा	आईडीआर {(3) / (4)}
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. वाणिज्यिक बैंक (i to vii)	139	79,22,120	1,83,48,838	43.2	140	86,66,416	2,06,73,077	41.9
i) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	12	52,20,324	1,05,07,639	49.7	12	56,47,846	1,15,76,001	48.8
ii) निजी क्षेत्र के बैंक	21	21,20,937	62,37,833	34.0	21	23,63,912	72,35,902	32.7
iii) विदेशी बैंक	43	50,037	8,62,909	5.8	44	50,568	10,08,506	5.0
iv) लघु वित्तीय बैंक	12	66,745	1,63,183	40.9	12	89,532	2,15,426	41.6
v) भुगतान बैंक	6	12,533	12,694	98.7	6	16,794	16,937	99.2
vi) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	43	4,50,675	5,63,377	80.0	43	4,96,827	6,19,010	80.3
vii) स्थानीय क्षेत्र के बैंक	2	869	1,204	72.2	2	937	1,295	72.4
II. सहकारी बैंक (i to iii)	1,887	7,09,139	11,10,076	63.9	1,857	7,46,290	11,79,084	63.3
i) शहरी सहकारी बैंक	1,502	3,62,991	5,34,413	67.9	1,472	3,71,846	5,56,962	66.8
ii) राज्य सहकारी बैंक	33	64,041	1,46,931	43.6	33	64,202	1,48,080	43.4
iii) जिला केंद्रीय सहकारी बैंक	352	2,82,107	4,28,733	65.8	352	3,10,242	4,74,041	65.4
कुल (I+II)	2,026	86,31,259	1,94,58,915	44.4	1,997	94,12,705	2,18,52,160	43.1

टिप्पणी: आईडीआर: बीमाकृत जमा अनुपात
स्रोत : डीआईसीजीसी।

वृद्धि के साथ, आरक्षित निधि अनुपात (आरआर)²⁰ मार्च 2024 के अंत में यह एक साल पहले के 1.96 प्रतिशत से बढ़कर 2.11 प्रतिशत हो गया। डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 की धारा 21 के तहत, निगम को बीमा भुगतान की वसूली करने का अधिकार है। 2023-24 के दौरान, डीआईसीजीसी ने 2022-23 के दौरान ₹883 करोड़ की तुलना में ₹901 करोड़ के दावों की कुल वसूली की।

12. वित्तीय समावेशन

IV.78 रिजर्व बैंक ने वित्तीय पहुँच में सुधार के लिए अपनी पहल जारी रखी, जिसमें समाज के सभी वर्गों तक वित्तीय सेवाओं का लाभ पहुँचाने के लिए प्रौद्योगिकी-संचालित नवोन्मेषों का लाभ उठाना भी शामिल है। भारत में तेज़ गति से हो रहे डिजिटलीकरण के बावजूद, 2010 से 2023 की अवधि के दौरान प्रति एक लाख की आबादी पर वाणिज्यिक बैंक शाखाओं की संख्या में 1.5 गुना वृद्धि हुई (चार्ट IV.35ए)। भारत में प्रति व्यक्ति एटीएम की उपलब्धता भी 2010 से तीन गुना बढ़ गई है (चार्ट IV.35बी)।

12.1 वित्तीय समावेशन योजनाएं

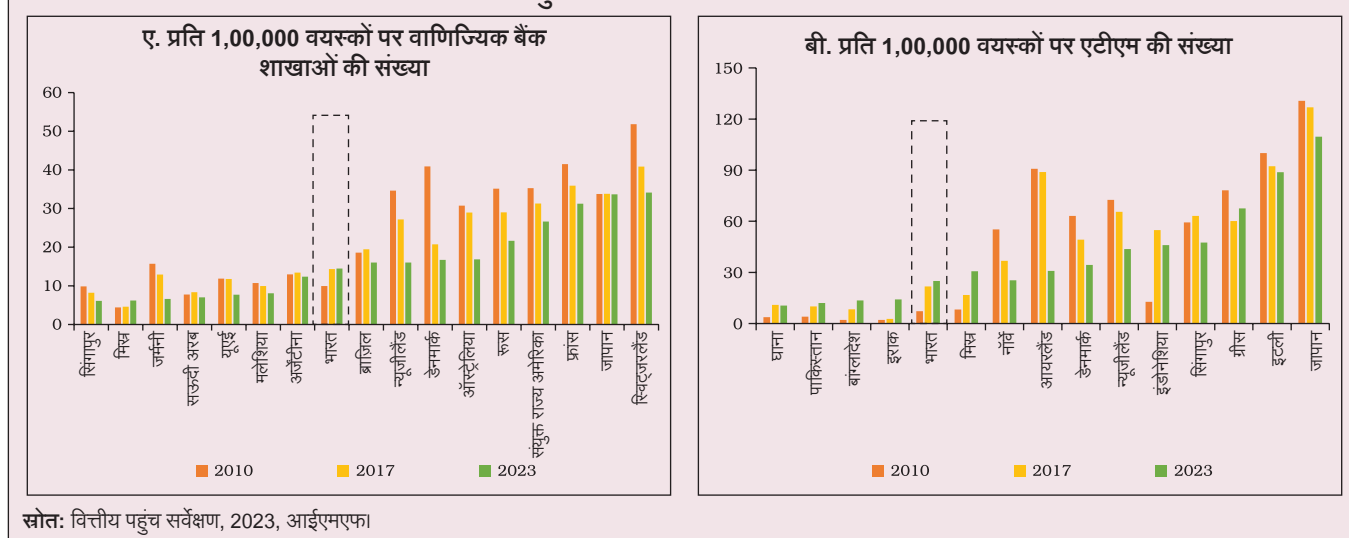
IV.79 वित्तीय समावेशन योजनाएँ (एफआईपी) बैंकिंग और बीसी आउटलेट्स की संख्या, बुनियादी बचत बैंक जमा

खाते (बीएसबीडीए), इन खातों में प्राप्त ओवरड्राफ्ट (ओडी) सुविधाएँ, केसीसी और सामान्य क्रेडिट कार्ड (जीसीसी) में लेन-देन और व्यवसाय संवाददाताओं - सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (बीसी-आईसीटी) चैनल के माध्यम से लेन-देन जैसे मापदंडों पर बैंकों की उपलब्धियों को दर्शाती हैं। मार्च 2024 के अंत में, बीसी मोड के माध्यम से बीएसबीडीए में जमा राशि शाखाओं के माध्यम से जमा राशि से अधिक हो गई, जो जमीनी स्तर पर बीसी मॉडल की प्रभावशीलता को दर्शाता है (सारणी IV.29)।

12.2 वित्तीय समावेशन सूचकांक

IV.80 रिजर्व बैंक का वित्तीय समावेशन सूचकांक (एफआईआई) देश में वित्तीय समावेशन की प्रगति पर नज़र रखता है। यह तीन आयामों अर्थात् पहुँच, उपयोग और गुणवत्ता पर आधारित 97 संकेतकों पर जानकारी एकत्र करता है। यह सूचकांक मार्च 2023 में 60.1 से बढ़कर मार्च 2024 में 64.2 हो गया, जिसमें सभी उप-सूचकांकों में वृद्धि हुई (चार्ट IV.36)। 2023-24 में एफआईआई में सुधार मुख्य रूप से उपयोग आयाम द्वारा किया गया था, जो वित्तीय समावेशन के प्रसार को दर्शाता है।

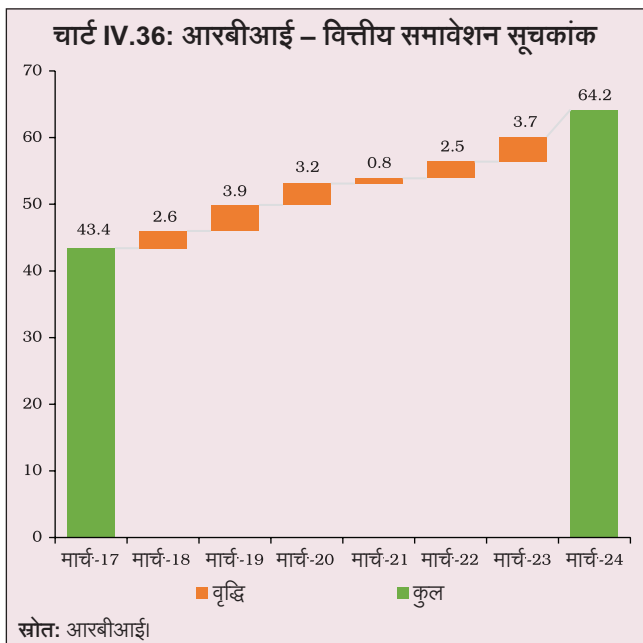
चार्ट IV.35: चुनिंदा देशों में वित्तीय समावेशन की प्रगति



²⁰ बीमाकृत जमाराशि से जमा बीमा निधि का अनुपात।

सारणी IV.29: वित्तीय समावेशन योजना में प्रगति
(मार्च के अंत में)

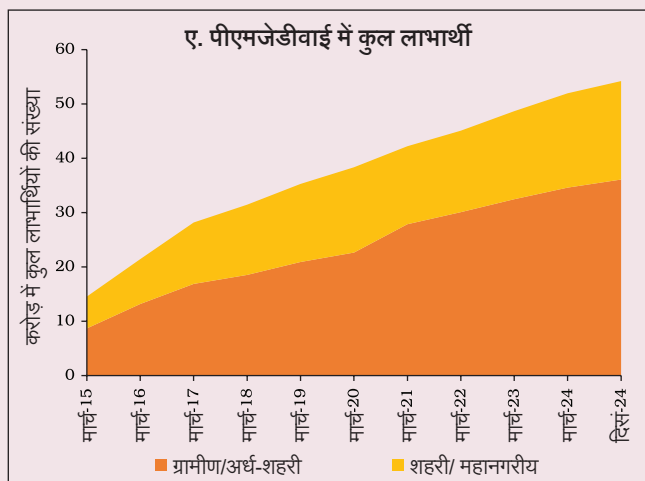
क्र. सं.		2015	2020	2021	2022	2023	2024*
1	2	3	4	5	6	7	8
बैंकिंग की पहुँच							
1	गांवों में बैंकिंग आउटलेट- शाखाएं	49,571	54,561	55,112	53,287	53,802	54,198
2	गांवों में बैंकिंग आउटलेट>2000-बीसी	90,877	1,49,106	8,50,406	18,92,462	13,48,038	12,66,756
3	गांवों में बैंकिंग आउटलेट<2000-बीसी	4,08,713	3,92,069	3,40,019	3,26,008	2,77,844	2,80,922
4	गांवों में बैंकिंग आउटलेट – कुल बीसी	4,99,590	5,41,175	11,90,425	22,18,470	16,25,882	15,47,678
5	बीसी के माध्यम से कवर किए गए शहरी स्थान	96,847	6,35,046	4,26,745	12,95,307	4,15,218	3,06,658
बुनियादी बचत बैंक जमा खाता (बीएसबीडीए)							
6	बीएसबीडीए - शाखाओं के माध्यम से (संख्या लाख में)	2,103	2,616	2,659	2,661	2,750	2,768
7	बीएसबीडीए - शाखाओं के माध्यम से (राशि करोड़ में)	36,498	95,831	1,18,392	1,20,464	1,33,661	1,46,306
8	बीएसबीडीए - बीसी के माध्यम से (संख्या लाख में)	1,878	3,388	3,796	4,015	4,105	4,290
9	बीएसबीडीए - बीसी के माध्यम से (राशि करोड़ में)	7,457	72,581	87,623	1,07,415	1,29,531	1,53,489
10	बीएसबीडीए - कुल (संख्या लाख में)	3,981	6,004	6,455	6,677	6,856	7,059
11	बीएसबीडीए - कुल (राशि करोड़ में)	43,955	1,68,412	2,06,015	2,27,879	2,63,192	2,99,795
12	बीएसबीडीए में ओडी सुविधा प्राप्त (संख्या लाख में)	76	64	60	68	51	48
13	बीएसबीडीए में ओडी सुविधा का लाभ (राशि करोड़ में)	1,991	529	534	516	572	564
केसीसी और सामान्य क्रेडिट कार्ड (जीसीसी)							
14	केसीसी - कुल (संख्या लाख में)	426	475	466	473	493	515
15	केसीसी - कुल (राशि करोड़ में)	4,38,229	6,39,069	6,72,624	7,10,715	7,68,339	8,47,237
16	जीसीसी - कुल (संख्या लाख में)	92	202	202	96	66	23
17	जीसीसी - कुल (राशि करोड़ में)	1,31,160	1,94,048	1,55,826	1,70,203	1,90,568	34,340
व्यावसायिक संवाददाता							
18	आईसीटी-ए/सीएस-बीसी-कुल लेनदेन (संख्या लाख में)#	4,770	32,318	30,551	28,533	34,055	36,388
19	आईसीटी-ए/सीएस-बीसी-कुल लेनदेन (राशि करोड़ में)#	85,980	8,70,643	8,49,771	9,05,252	11,39,521	13,10,973
टिप्पणियाँ : 1. *: अनंतिम 2. #: वित्तीय वर्ष के दौरान लेनदेन							
स्रोत : पीएसबी, पीवीबी और आरआरबी द्वारा प्रस्तुत एफआईपी विवरणी।							



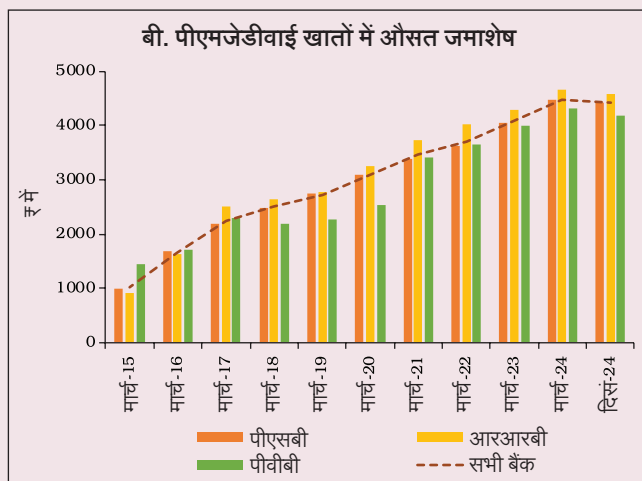
12.3 प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई)

IV.81 समाज के हाशिए पर पड़े क्षेत्रों और वर्गों में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली पीएमजेडीवाई ने अगस्त 2024 में अपनी स्थापना के 10 वर्ष पूरे करेगी। पीएमजेडीवाई के तहत लाभार्थियों की संख्या 54.2 करोड़ तक पहुँच गई, जिसमें 11 दिसंबर, 2024 तक ₹2.4 लाख करोड़ की जमा राशि थी और 66.6 प्रतिशत लाभार्थी ग्रामीण/अर्ध-शहरी क्षेत्रों में थे (चार्ट IV.37ए)। हाल ही में कुछ नरमी के बावजूद, पीएमजेडीवाई खातों में औसत शेष राशि इसके लॉन्च के बाद से चार गुना बढ़ गई है, जो बढ़ते उपयोग और पहले से बैंक रहित व्यक्तियों के औपचारिक वित्तीय प्रणाली में सफल एकीकरण को दर्शाता है (चार्ट IV.37बी)।

चार्ट IV.37: पीएमजेडीवाई में प्रगति



स्रोत: पीएमजेडीवाई, भारत सरकार।



12.4 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा नई बैंक शाखाएं

IV.82 यद्यपि बैंक डिजिटल चैनलों पर अधिक जोर दे रहे हैं, तथापि, भौतिक शाखाएँ ग्राहक जुड़ाव का मुख्य आधार हैं,

सारणी IV.30: एससीबी द्वारा नई खोली गई बैंक शाखाओं का स्तर-वार विवरण

	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	2	3	4	5
स्तर 1	1,545 (50.0)	1,558 (47.9)	2,285 (43.1)	2,675 (49.7)
स्तर 2	278 (9.0)	233 (7.2)	468 (8.8)	452 (8.4)
स्तर 3	475 (15.4)	427 (13.1)	812 (15.3)	683 (12.7)
स्तर 4	265 (8.6)	292 (9.0)	545 (10.3)	433 (8.0)
स्तर 5	179 (5.8)	229 (7.0)	424 (8.0)	368 (6.8)
स्तर 6	347 (11.2)	512 (15.7)	768 (14.5)	768 (14.3)
कुल	3,089 (100.0)	3,251 (100.0)	5,302 (100.0)	5,379 (100.0)

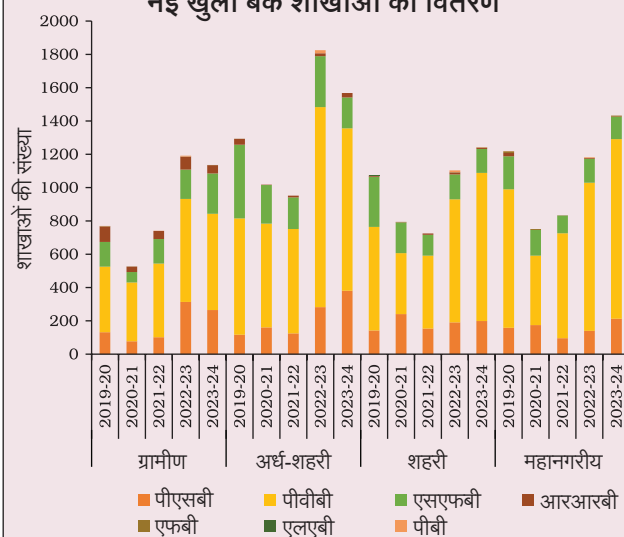
- टिप्पणियाँ :
- केंद्रों का स्तर-वार वर्गीकरण इस प्रकार है: 'स्तर 1' में 1,00,000 और उससे अधिक की आबादी वाले केंद्र शामिल हैं, 'स्तर 2' में 50,000 से 99,999 की आबादी वाले केंद्र शामिल हैं, 'स्तर 3' में 20,000 से 49,999 तक की आबादी वाले केंद्र शामिल हैं, 'स्तर 4' में 10,000 से 19,999 की आबादी वाले केंद्र शामिल हैं, 'स्तर 5' में 5,000 से 9,999 की आबादी वाले केंद्र शामिल हैं, और 'स्तर 6' में 5000 से कम आबादी वाले केंद्र शामिल हैं।
 - डेटा में 'प्रशासनिक कार्यालय' शामिल नहीं हैं।
 - सभी जनसंख्या के आंकड़े 2011 की जनगणना के अनुसार हैं।
 - कोष्ठक में दिए गए आंकड़े किसी विशेष क्षेत्र में खोली गई शाखाओं की कुल संख्या के अनुपात को दर्शाते हैं।

स्रोत : सीआईएसबीआई, आरबीआई। सीआईएसबीआई डेटा गतिशील प्रकृति का है और बैंकों से प्राप्त जानकारी के आधार पर अद्यतन किया जाता है।

बनी हुई हैं। 2023-24 के दौरान, 41.9 प्रतिशत बैंक शाखाएँ 50,000 से कम आबादी वाले केंद्रों में खोली गईं, जिससे छोटे शहरों और गाँवों में बैंकिंग की पहुँच में सुधार हुआ (सारणी IV.30)।

IV.83 2023-24 के दौरान खोली गई नई शाखाओं में से 65.5 प्रतिशत पीवीबी द्वारा खोली गईं, जिनमें से 44.1 प्रतिशत शाखाएँ ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में थीं (चार्ट IV.38)।

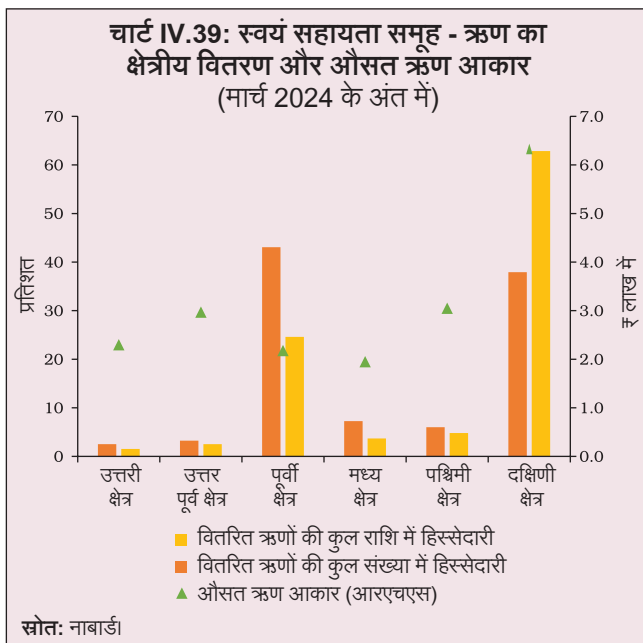
चार्ट IV.38: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की नई खुली बैंक शाखाओं का वितरण



स्रोत: सीआईएसबीआई, आरबीआई।

12.5 सूक्ष्म वित्त कार्यक्रम

IV.84 सूक्ष्म वित्त वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रभावी साधन के रूप में कार्य करता है, जिसमें कम मूल्य के ऋण सहित वित्तीय सेवाओं की डिलीवरी आबादी के वंचित और बैंक रहित वर्गों तक होती है, जिससे सामाजिक समानता और सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलता है। 2023-24 के दौरान, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और संयुक्त देयता समूहों (जेएलजी) के माध्यम से सूक्ष्म ऋण की डिलीवरी में लगातार प्रगति देखी गई। बैंकों से ऋण प्राप्त करने वाले एसएचजी की संख्या 2022-23 में 43.0 लाख से बढ़कर 2023-24 में 54.8 लाख हो गई। एसएचजी के बकाया ऋण में पिछले वर्ष के 24.5 प्रतिशत की तुलना में 2023-24 के दौरान 38.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। एसएचजी को ऋण वितरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा देश के दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्रों में केंद्रित रहा (चार्ट IV.39)। संयुक्त देयता समूहों को वितरित ऋण में पिछले वर्ष के 18.3 प्रतिशत की तुलना में 2023-24 के दौरान 41.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई (परिशिष्ट सारणी IV.13)।



12.6 व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली (टीआरडीडीएस)

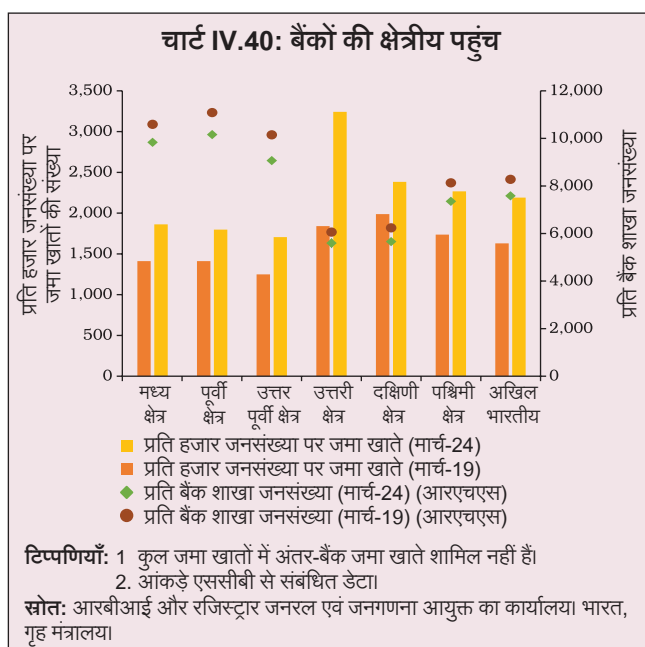
IV.85 टीआरडीडीएस एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जो कई वित्तपोषकों के माध्यम से एमएसएमई के व्यापार प्राप्ति के वित्तपोषण/छूट की सुविधा प्रदान करता है। ये प्राप्ति का कॉरपोरेट और सरकारी विभागों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) सहित अन्य खरीददारों से देय हो सकती हैं। 7 जून, 2023 को टीआरडीडीएस दिशानिर्देशों में संशोधन ने वित्तपोषकों को चूक जोखिम के विरुद्ध बचाव के लिए बीमा सक्षम बनाया, वित्तपोषकों के समूह का विस्तार किया और फैक्ट्रिंग इकाइयों के लिए द्वितीयक बाजार को सक्षम किया। इन परिवर्तनों को दर्शाते हुए, 2023-24 में अपलोड और वित्तपोषित चालान की संख्या और मात्रा में तेजी से वृद्धि हुई। वित्तपोषित चालान की सफलता दर 2022-23 में 93.9 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 94.4 प्रतिशत हो गई (सारणी IV.31)।

12.7 क्षेत्रीय बैंकिंग व्यापन

IV.86 पिछले पाँच वर्षों के दौरान, प्रति बैंक शाखा जनसंख्या के आधार पर बैंकिंग पहुँच में सभी क्षेत्रों में सुधार हुआ है। प्रति हजार जनसंख्या पर जमा खातों की संख्या के आधार पर उपयोग में सुधार सबसे ज्यादा उत्तरी क्षेत्र में स्पष्ट हुआ (चार्ट IV.40)।

सारणी IV.31: टीआरडीडीएस के माध्यम से एमएसएमई वित्तपोषण में प्रगति

वित्तीय वर्ष	अपलोड किया गया बीजक		वित्तपोषित बीजक	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	2	3	4	5
2020-21	8,61,560	19,670	7,86,555	17,080
2021-22	17,33,553	44,112	16,40,824	40,309
2022-23	27,24,872	83,955	25,58,531	76,646
2023-24	44,04,148	1,51,343	41,58,554	1,38,241
स्रोत : आरबीआई				



13. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक²¹

IV.87 मार्च 2024 के अंत में, 26 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों (पुडुचेरी, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख) में 22,078 शाखाओं के माध्यम से संचालित 12 एससीबी द्वारा प्रायोजित 43 आरआरबी थे। अपने अधिदेश के अनुरूप, आरआरबी की 91.8 प्रतिशत शाखाएँ ग्रामीण/अर्ध-शहरी क्षेत्रों में थीं। दक्षिणी क्षेत्र में आरआरबी की संख्या सबसे अधिक है, और इस क्षेत्र ने आरआरबी के कुल लाभ में लगभग आधा योगदान दिया (परिशिष्ट सारणी IV.14)।

13.1 तुलन पत्र विश्लेषण

IV.88 देयताओं के पक्ष में उधारी में मंदी के कारण आरआरबी की संयुक्त तुलन पत्र में वृद्धि पिछले वर्ष के 9.4 प्रतिशत से घटकर 2023-24 के दौरान 8.9 प्रतिशत हो गई, जबकि जमा और ऋण वृद्धि में तेजी आई (सारणी IV.32)।

सारणी IV.32: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का समेकित तुलन पत्र

(राशि करोड़ ₹ में)

क्र. सं.	मद	मार्च अंत में		व-द-व संवृद्धि प्रतिशत में	
		2023	2024 (पी)	2022-23	2023-24
1	2	3	4	5	6
1	शेयर पूंजी	17,232	19,042	15.8	10.5
2	आरक्षित निधियाँ	40,123	46,659	16.8	16.3
3	जमाराशियाँ	6,08,509	6,59,815	8.2	8.4
3.1	चालू खाते	11,945	11,952	-0.8	0.1
3.2	बचत खाते	3,19,572	3,47,193	8.5	8.6
3.3	सावधि जमा	2,76,992	3,00,670	8.2	8.5
4	उधार	84,712	92,444	14.7	9.1
4.1	नाबार्ड से	73,119	77,166	9.0	5.5
4.2	प्रायोजक बैंक	3,408	4,293	-12.1	26.0
4.3	अन्य	8,185	10,986	177.7	34.2
5	अन्य देयताएं	20,885	22,120	5.8	5.9
	कुल देयताएं / आस्तियाँ	7,71,462	8,40,080	9.4	8.9
6	उपलब्ध नकद	2,888	2,933	-7.4	1.6
7	भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष	29,332	30,990	32.3	5.7
8	चालू खाते में शेष राशि	7,150	8,173	-12.0	14.3
9	निवेश	3,13,401	3,19,099	6.0	1.8
10	ऋण और अग्रिम (निवल)	3,86,951	4,45,286	13.0	15.1
11	स्थावर सम्पदा	1,406	1,581	12.0	12.4
12	अन्य आस्तियाँ, जिनमें से	30,333	32,019	-6.9	5.6
	12.1 संचित हानि	9,841	8,921	8.6	-9.4
टिप्पणी: पी: अंतिम					
स्रोत: नाबार्ड।					

IV.89 आरआरबी के कुल निधिगत स्रोतों में जमाराशि का हिस्सा 78.5 प्रतिशत था, हालांकि 2023-24 के दौरान उनकी जमा वृद्धि एससीबी से कम रही। 2023-24 के दौरान आरआरबी की कुल जमाराशि में कम लागत वाली सीएसए जमाराशि का हिस्सा 54.4 प्रतिशत था, जो पीबी को छोड़कर एससीबी की सभी श्रेणियों में सबसे अधिक है।²² आरआरबी में प्रति खाता औसत पीएमजेडीवाई जमा राशि ₹4,667 थी, जो अन्य श्रेणियों के बैंकों के लिए ₹4,432 से अधिक थी। मार्च 2024 के अंत में आरआरबी का सी -डी अनुपात बढ़कर 71.4 प्रतिशत हो गया, जो 33 वर्षों में इसका उच्चतम स्तर है, क्योंकि ऋण और अग्रिम की वृद्धि ने जमा वृद्धि को पीछे छोड़ दिया।

²¹ आरआरबी की स्थापना छोटे और सीमांत किसानों, कृषि मजदूरों और आबादी के सामाजिक-आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को ऋण वितरण के लिए पेशेवर रूप से प्रबंधित वैकल्पिक चैनल के रूप में की गई थी। उनके कार्यात्मक फोकस क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, व्यापार, वाणिज्य और लघु उद्योग रहे हैं।

²² पी.बी. को सावधि जमा जुटाने की अनुमति नहीं है।

13.2 वित्तीय प्रदर्शन

IV.90 2018-20 के दौरान निवल घाटे के बाद, आरआरबी ने 2023-24 के दौरान ₹ 7,571 करोड़ का अपना अब तक का सबसे अधिक समेकित निवल लाभ दर्ज किया। उच्च आय वृद्धि और परिचालन व्यय (विशेष रूप से स्टाफ लागत) में कमी ने लाभप्रदता को बढ़ावा दिया (सारणी IV.33)।

सारणी IV.33: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का वित्तीय प्रदर्शन

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मद	राशि		व-द-व परिवर्तन प्रतिशत में	
		2022-23	2023-24(पी)	2022-23	2023-24
1	2	3	4	5	6
ए आय (i + ii)		59,427	70,443	5.0	18.5
i.	ब्याज आय	53,640	61,341	11.6	14.4
ii.	अन्य आय*	5,787	9,101	-32.2	57.3
बी व्यय (i+ii+iii)		54,454	62,872	2.0	15.5
i.	खर्च किया गया ब्याज	26,704	33,237	7.6	24.5
ii.	परिचालन व्यय	21,878	21,267	2.7	-2.8
	जिनमें से, वेतन बिल	16,683	15,305	2.1	-8.3
iii.	प्रावधान और आकस्मिकताएं*	5,872	8,368	-19.1	42.5
	जिनमें से, आय कर	1,424	2,430	11.4	70.7
सी लाभ					
i.	परिचालन लाभ	10,845	15,938	4.9	47.0
ii.	निवल लाभ	4,974	7,571	54.5	52.2
डी कुल औसत आस्तियां		7,16,796	7,90,902	7.5	10.3
ई वित्तीय अनुपात #					
i.	परिचालन लाभ	1.5	2.0		
ii.	निवल लाभ	0.7	1.0		
iii.	आय (ए + बी)	8.3	8.9		
	ए) ब्याज आय	7.5	7.8		
	बी) अन्य आय	0.8	1.2		
vi.	व्यय (ए+बी+सी)	7.6	7.9		
	ए) खर्च किया गया ब्याज	3.7	4.2		
	बी) परिचालन व्यय	3.1	2.7		
	जिनमें से, वेतन बिल	2.3	1.9		
	ग) प्रावधान और आकस्मिकताएं	0.8	1.1		
एफ विश्लेषणात्मक अनुपात (%)					
	सकल एनपीए अनुपात	7.3	6.2		
	सीआरएआर	13.4	14.2		

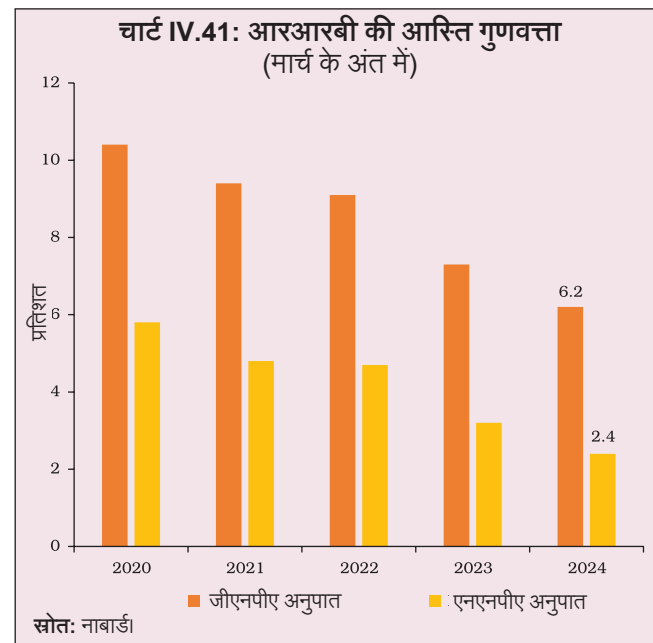
टिप्पणियाँ : 1. पी: अंतिम
2. #: औसत कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में।
3. *: वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति पर रिजर्व बैंक के मौजूदा मास्टर निर्देशों के अनुसार, निवेश में मूल्यहास के लिए प्रावधान, जिसे पहले व्यय के प्रावधान और आकस्मिकता शीर्ष के तहत रिपोर्ट किया जाता था, अब अन्य आय से घटाया जाना आवश्यक है। तदनुसार, एमटीएम घाटे के लिए आरआरबी द्वारा प्रावधानित ₹ 2,204.4 करोड़ की राशि को वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान अन्य आय से घटा दिया गया है।

स्रोत : नाबार्डी

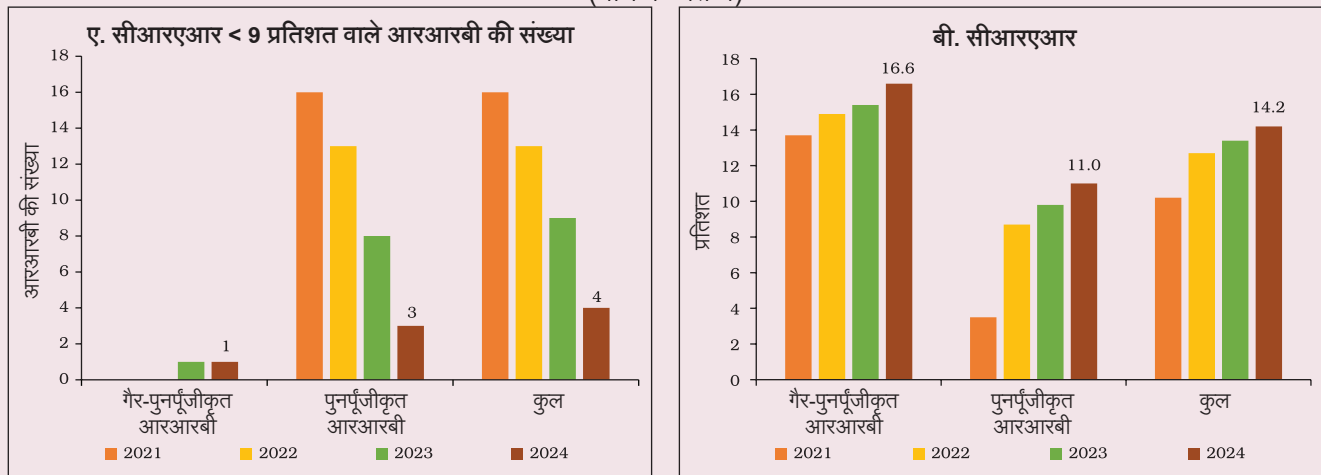
IV.91 मार्च 2024 के अंत में आरआरबी का जीएनपीए अनुपात दस साल के निचले स्तर 6.2 प्रतिशत पर पहुँच गया (चार्ट IV.41)। आस्ति गुणवत्ता में सुधार के साथ-साथ प्रावधान बफर में भी वृद्धि हुई।

IV.92 2021-23 के दौरान ₹10,890 करोड़ की पूंजीगत अंतर्वेशन के परिणामस्वरूप, 9 प्रतिशत के विनियामकीय न्यूनतम सीआरएआर से कम सीमा वाले आरआरबी की संख्या में कमी आई (चार्ट IV.42ए)। मार्च 2024 के अंत में समेकित सीआरएआर 14.2 प्रतिशत के सार्वकालिक उच्च स्तर पर था (चार्ट IV.42बी)। घाटे में चल रहे आरआरबी की संख्या 2019-20 में 18 से लगातार घटकर 2023-24 में 3 हो गई है (परिशिष्ट सारणी IV.14)।

IV.93 2023-24 के दौरान, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिया गया ऋण आरआरबी के कुल ऋण का 87 प्रतिशत रहा और सभी बैंकों ने अपने एएनबीसी/सीईओबीई का 75 प्रतिशत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण देने का लक्ष्य पूरा किया (सारणी IV.34 और परिशिष्ट सारणी IV.15)।



चार्ट IV.42: आरआरबी का जोखिम-भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात
(मार्च के अंत में)



स्रोत: नाबार्डी

14. स्थानीय क्षेत्र बैंक²³

IV.94 मार्च 2024 के अंत में, दो एलएबी (मार्च 2004 के अंत में चार से कम) थे, जिनकी 79 शाखाएँ परिचालन में थीं। वर्ष

सारणी IV.34: आरआरबी द्वारा उद्देश्य-वार बकाया अग्रिम
(मार्च के अंत में)

		(राशि करोड़ ₹ में)	
क्र. सं.	उद्देश्य	2023	2024(P)
1	2	3	4
I	प्राथमिकता (i से v)	3,62,503	4,08,810
	कुल बकाया ऋण का प्रतिशत	88.3	87.0
i.	कृषि	2,81,971	3,16,671
ii.	सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम	49,323	57,639
iii.	शिक्षा	1,744	1,609
vi.	आवास	24,503	2,6047
v.	अन्य	4,963	6,843
II	गैर-प्राथमिकता (i से vi)	48,236	61,300
	कुल बकाया ऋण का प्रतिशत	11.7	13.0
i.	कृषि	16	17
ii.	सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम	84	187
iii.	शिक्षा	218	343
iv.	आवास	9,100	13,620
v.	व्यक्तिगत ऋण	12,985	17,788
vi.	अन्य	25,833	29,345
	कुल (I+II)	4,10,738	4,70,109

टिप्पणी : पी: अंतिमा
स्रोत : नाबार्डी

2023-24 के दौरान, ऋण के साथ-साथ जमा वृद्धि में गिरावट आने से एलएबी के समेकित तुलन पत्र वृद्धि में कमी आई। जमा वृद्धि से अधिक ऋण वृद्धि होने से, सी-डी अनुपात एक वर्ष पहले के 81.1 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2024 के अंत में 81.4 प्रतिशत हो गया (सारणी IV.35)।

14.1 एलएबी का वित्तीय प्रदर्शन

IV.95 वर्ष 2023-24 के दौरान एलएबी का लाभ, ब्याज आय वृद्धि में धीमापन और ब्याज व्यय वृद्धि में तेजी के कारण गिरा (सारणी IV.36)।

सारणी IV.35: स्थानीय क्षेत्र बैंकों का प्रोफाइल
(मार्च के अंत में)

			(राशि ₹ करोड़ में)	
		2023	2024	
1	2	3	4	5
1.	आस्तियां	1,474 (15.7)	1,584 (7.5)	
2.	जमा राशियां	1,190 (16.6)	1,271 (6.8)	
3.	सकल अग्रिम	965 (15.1)	1,034 (7.2)	

टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि को प्रतिशत में दर्शाते हैं।
स्रोत : परोक्ष विवरणियाँ (वैश्विक परिचालनगत), भारतीय रिज़र्व बैंक।

²³ स्थानीय क्षेत्र बैंक (एलएबी) छोटे, निजी स्वामित्व वाले बैंक हैं, जिनकी स्थापना कम लागत वाली संस्थाओं के रूप में कार्य करने के उद्देश्य से की गई है, ताकि कुशल और प्रतिस्पर्धी वित्तीय मध्यस्थता सेवाएँ प्रदान की जा सकें। एलएबी के पास परिचालन का एक निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र होता है, जो विशेष रूप से तीन समीपवर्ती जिलों को शामिल करते हुए ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों को लक्षित करता है।

सारणी IV.36: स्थानीय क्षेत्र के बैंकों का वित्तीय प्रदर्शन

क्र. सं.	राशि (₹ करोड़ में)		वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि (प्रतिशत में)	
	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24
1	2	3	4	5
ए. आय (i+ii)	179	197	12.6	10.1
i. ब्याज आय	153	172	17.1	12.8
ii. अन्य आय	26	25	-7.6	-5.7
बी. व्यय (i+ii+iii)	143	162	7.7	13.7
i. ब्याज व्यय	63	79	8.8	25.9
ii. प्रावधान और आकस्मिक व्यय	21	15	-6.8	-26.0
iii. परिचालनगत व्यय जिनमें से, वेतन बिल	59	68	12.5	14.6
29	33	14.6	13.5	
सी. लाभ				
i. परिचालनगत लाभ/हानि	57	50	17.3	-11.9
ii. निवल लाभ/ हानि	36	35	37.7	-3.9
डी. निवल ब्याज आय	90	93	23.6	3.7
ई. कुल आस्तियां	1,474	1,584	15.7	7.5
एफ. वित्तीय अनुपात (कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)				
i. परिचालनगत लाभ	3.9	3.2		
ii. निवल लाभ	2.5	2.2		
iii. आय	12.1	12.4		
iv. ब्याज आय	10.4	10.9		
v. अन्य आय	1.8	1.6		
vi. व्यय	9.7	10.2		
vii. ब्याज व्यय	4.3	5.0		
viii. परिचालनगत व्यय	4.0	4.3		
ix. वेतन बिल	1.9	2.1		
x. प्रावधान और आकस्मिक व्यय	1.4	1.0		
xi. निवल ब्याज आय	6.1	5.9		

टिप्पणी: 'वेतन बिल' को कर्मचारियों के लिए भुगतान और प्रावधान के रूप में लिया जाता है।
स्रोत: परोक्ष विवरणियां (वैश्विक परिचालनगत) भारतीय रिज़र्व बैंक।

15. लघु वित्त बैंक²⁴

IV.96 फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक के एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ विलय के बाद, जून 2024 के अंत में भारत में 7,230 घरेलू शाखाओं के साथ 11 एसएफबी परिचालन में थे।

15.1 तुलन-पत्र

IV.97 वर्ष 2023-24 के दौरान, एसएफबी की संयुक्त तुलन-पत्र में वृद्धि दोहरे अंकों में थी, जो उनकी स्थापना के बाद से देखी गई प्रवृत्ति के अनुरूप थी। वर्ष 2023-24 के दौरान

एसएफबी की ऋण वृद्धि में कमी आई और जमा वृद्धि में तेजी आई, जिससे उधार पर उनकी निर्भरता कम हुई। एसएफबी का सी-डी अनुपात एक वर्ष पहले के 93.0 प्रतिशत से मार्च 2024 के अंत में 90.1 प्रतिशत हो गया, हालांकि यह एससीबी से अधिक रहा (सारणी IV.37)।

15.2 वित्तीय प्रदर्शन

IV.98 वर्ष 2023-24 के दौरान लगातार तीसरे वर्ष एसएफबी की आस्ति गुणवत्ता में सुधार हुआ। आय अनुपात में लाभ, व्यय अनुपात से अधिक होने के कारण वर्ष के दौरान निवल लाभ अनुपात में भी वृद्धि हुई। आस्ति गुणवत्ता में सुधार के कारण

सारणी IV.37: लघु वित्त बैंकों का समेकित तुलन-पत्र
(मार्च के अंत में)

क्र. सं.	राशि		वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि (प्रतिशत में)	
	2023	2024	2023	2024
1	2	3	4	5
1 शेयर पूंजी	7,811	7,844	8.6	0.4
2 आरक्षित निधि एवं अधिशेष	23,557	32,957	38	39.9
3 टियर II बॉण्ड और टियर II कर्ज	1,926	2,458	-15.7	27.6
4 जमा राशियां	1,91,372	2,50,896	28	31.1
4.1 चालू मांग जमा	7,456	10,895	22.7	46.1
4.2 बचत	54,667	59,691	16.2	9.2
4.3 सावधि	1,29,248	1,80,310	34.1	39.5
5 उधारियां (टियर-II बॉण्ड सहित)	31,170	28,261	10.8	-9.3
5.1 बैंक	4,241	4,500	-6.3	6.1
5.2 अन्य	26,929	23,761	14.1	-11.8
6 अन्य देयताएं और प्रावधान	13,606	15,326	14.1	12.6
कुल देयताएं और आस्तियां	2,67,517	3,35,284	25.1	25.3
7 नकद	1,371	1,333	9.7	-2.8
8 आरबीआई के पास शेष राशि	16,468	16,170	115.8	-1.8
9 अन्य बैंक शेष/ वित्तीय संस्थानों के पास शेष	4,484	6,261	-69	39.6
10 निवेश	58,115	74,283	30.8	27.8
11 ऋण और अग्रिम	1,77,887	2,26,148	28.7	27.1
12 अचल आस्तियां	2,734	3,353	18.7	22.6
13 अन्य आस्तियां	6,455	7,736	15.5	19.8

टिप्पणी: आंकड़े 12 एसएफबी से संबंधित हैं।

स्रोत: परोक्ष विवरणियां (वैश्विक परिचालनगत) भारतीय रिज़र्व बैंक।

²⁴ लघु वित्त बैंक (एसएफबी) विशेष संस्थाएं हैं जो आबादी में से वंचित और कम वंचित वर्गों को औपचारिक बचत के अवसर प्रदान करने के लिए स्थापित की गई हैं। एसएफबी का उद्देश्य उच्च प्रौद्योगिकी और कम लागत वाले परिचालन के माध्यम से छोटे व्यवसाय इकाइयों, छोटे और सीमांत किसानों, सूक्ष्म और लघु उद्योगों और अन्य असंगठित क्षेत्र की संस्थाओं को ऋण प्रदान करना है।

भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति संबंधी रिपोर्ट 2023-24

प्रावधान और आकस्मिकताएं (कुल आस्तियों के प्रतिशत के अनुसार) कम हो गईं (सारणी IV.38)।

16. भुगतान बैंक²⁵

IV.99 मार्च 2024 के अंत में, 82 शाखाओं के साथ छह पीबी परिचालन में थे। इनमें से, पाँच पीबी ने 2023-24 के दौरान परिचालनगत लाभ की सूचना दी।

सारणी IV.38: लघु वित्त बैंकों का वित्तीय प्रदर्शन

क्र. सं.	मद	राशि		वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि (प्रतिशत में)	
		2022-23	2023-24	2022-23	2023-24
1	2	3	4	5	6
ए आय (i + ii)		33,827	45,437	35.1	34.3
i.	ब्याज आय	29,806	39,588	34.7	32.8
ii.	अन्य आय	4,022	5,848	38.1	45.4
बी व्यय (i+ii+iii)		29,663	39,214	23.3	32.2
i.	ब्याज व्यय	12,139	17,473	27.6	43.9
ii.	परिचालनगत व्यय	13,153	17,186	34.0	30.7
	जिसमें से, स्टाफ पर व्यय	6,707	8,494	26.4	26.6
iii.	प्रावधान और आकस्मिक व्यय	4,371	4,555	-7.6	4.2
सी लाभ (कर पूर्व)		5,417	7,835	321.9	44.6
i.	परिचालनगत लाभ (ईबीपीटी)	8,534	10,774	49.7	26.2
ii.	निवल लाभ (पीएटी)	4,162	6,219	327.3	49.4
डी कुल आस्तियां		2,67,517	3,35,284	31.8	25.3
ई वित्तीय अनुपात #					
i.	परिचालनगत लाभ	3.2	3.2		
ii.	निवल लाभ	1.6	1.9		
iii.	आय (ए + बी)	12.6	13.6		
	ए. ब्याज आय	11.1	11.8		
	बी. अन्य आय	1.5	1.7		
iv.	व्यय (ए+बी+सी)	11.1	11.7		
	ए. ब्याज व्यय	4.5	5.2		
	बी. परिचालनगत व्यय	4.9	5.1		
	जिसमें से, स्टाफ पर व्यय	2.5	2.5		
	सी. प्रावधान और आकस्मिक व्यय	1.6	1.4		
एफ विश्लेषणात्मक अनुपात (प्रतिशत में)					
	सकल एनपीए अनुपात	4.7	2.4		
	सीआरएआर	22.5	21.6		
	कोर सीआरएआर	19.9	19.4		

टिप्पणी : #: कुल आस्तियों की तुलना में प्रतिशत के रूप में

स्रोत : परोक्ष विवरणियां (घरेलू परिचालनगत), भारतीय रिज़र्व बैंक।

16.1 तुलन-पत्र

IV.100 वर्ष 2023-24 के दौरान, भुगतान बैंकों की संयुक्त तुलन-पत्र की वृद्धि में कमी आई, जो मुख्य रूप से देनदारियों के पक्ष में जमा वृद्धि में मंदी के साथ-साथ आस्ति पक्ष में आरबीआई के पास नकदी और शेष राशि की वृद्धि में मंदी के कारण हुई। पीबी की जमा राशि देनदारियों की 62.4 प्रतिशत थी (सारणी IV.39)।

16.2 वित्तीय प्रदर्शन

IV.101 वर्ष 2022-23 के दौरान पीबी अपने स्थापना के बाद पहली बार लाभ में रहे और यह गति 2023-24 के दौरान भी जारी रही, हालांकि इसकी गति धीमी रही (सारणी IV.40)। पीबी की कुल आय में ब्याजेतर आय का हिस्सा 2021-22 के दौरान 91.3 प्रतिशत से घटकर 2023-24 के दौरान 81.7 प्रतिशत हो गया।

सारणी IV.39: भुगतान बैंकों का समेकित तुलन-पत्र (मार्च के अंत में)

क्र. सं.	मद	राशि (₹ करोड़ में)			वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि (प्रतिशत में)		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1	कुल पूंजी एवं आरक्षित निधि	2,485	2,938	3,440	41	18.2	17.1
2	जमा राशियां	7,859	12,222	16,330	69.9	55.5	33.6
3	अन्य देयताएं और प्रावधान	7,771	8,380	6,385	28	7.8	-23.8
	कुल देयताएं/ आस्तियां	18,115	23,540	26,155	45	29.9	11.1
1	आरबीआई के पास नकदी और शेष राशि	1,560	2,453	3,094	24.3	57.3	26.1
2	बैंकों और मुद्रा बाजार के पास शेष राशि	3,322	5,008	4,350	39	50.7	-13.1
3	निवेश	10,178	12,397	14,627	43	21.8	18.0
4	अचल आस्तियां	372	562	1,266	4.7	51.1	125.3
5	अन्य आस्तियां	2,683	3,120	2,819	98.8	16.3	-9.6

टिप्पणी : आंकड़े 6 पीबी से संबंधित हैं।

स्रोत : परोक्ष विवरणियां (घरेलू परिचालनगत), भारतीय रिज़र्व बैंक।

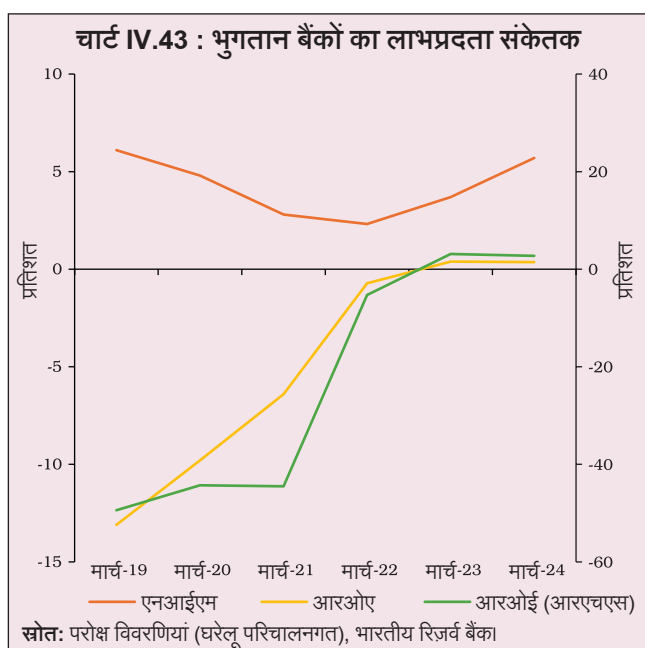
²⁵ भुगतान बैंक (पीबी) विशेष वित्तीय संस्थान हैं जिनकी स्थापना तकनीकी प्रगति का लाभ उठाकर वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है।

सारणी IV.40: भुगतान बैंकों का वित्तीय प्रदर्शन

क्र. सं.	राशि (₹ करोड़ में)			वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि (प्रतिशत में)			
	2021-22	2022-23	2023-24	2021-22	2022-23	2023-24	
1	2	3	4	5	6	7	8
ए आय							
i.	ब्याज आय	460	877	1,441	27.5	90.7	64.3
ii.	गैर-ब्याज आय	4,801	5,630	6,416	34.8	17.3	14.0
बी व्यय							
i.	ब्याज व्यय	157	247	356	56.0	57.5	44.1
ii.	परिचालनगत व्यय	5,216	6,154	7,292	13.8	18.0	18.5
iii.	प्रावधान और आकस्मिक व्यय जिसमें से,	20	15	115	-44.4	-25.5	688.6
	जोखिम प्रावधान	21	4	11	133.3	-81.7	185.3
	कर प्रावधान	-2	8	68	-111.0	415.8	773.4
सी निवल ब्याज आय		303	630	1,085	15.7	107.7	72.2
डी लाभ							
i.	परिचालनगत लाभ (ईबीपीटी)	-111	106	209	85.4	195.4	97.0
ii.	निवल लाभ / हानि	-131	92	94	83.6	170.0	3.0

स्रोत : परोक्ष विवरणियां (घरेलू परिचालनगत), भारतीय रिजर्व बैंक

IV.102 उनका एनआईएम मार्च 2023 के अंत में 3.7 प्रतिशत से सुधरकर मार्च 2024 के अंत में 5.7 प्रतिशत हो



गया, जो ब्याज व्यय के सापेक्ष ब्याज आय में वृद्धि को दर्शाता है (चार्ट IV.43)। मार्च 2024 के अंत में पीबी का आरओए और आरओई धनात्मक रहा।

IV.103 वर्ष 2023-24 के दौरान पीबी का लागत-से-आय अनुपात और कम हुआ, जो दक्षता में सुधार को दर्शाता है (सारणी IV.41)।

17. समग्र मूल्यांकन

IV.104 वर्ष 2023-24 के दौरान, बैंकों के समेकित तुलन-पत्र में मजबूत जमा और ऋण वृद्धि के कारण स्वस्थ गति से विस्तार हुआ। व्यक्तिगत ऋण तथा सेवा क्षेत्रों को दिए गए ऋण से बड़े पैमाने पर ऋण में वृद्धि हुई। बैंकों की लाभप्रदता में सुधार हुआ, जबकि चलनिधि और प्रावधान बफर संतोषजनक रहें। कम स्लीपेज से सभी क्षेत्रों में आस्ति गुणवत्ता मजबूत हुई। कुल अग्रिमों में गैर-जमानती अग्रिमों की हिस्सेदारी में कमी आई, जो इन क्षेत्रों में जोखिम के निर्माण को रोकने के लिए रिजर्व बैंक के उपायों को दर्शाता है।

IV.105 नई और उभरती हुई प्रौद्योगिकियाँ नई चुनौतियों के साथ-साथ अभिनव समाधान लाकर बैंकिंग उद्योग को नया रूप

सारणी IV.41: भुगतान बैंकों के चुनिंदा वित्तीय अनुपात (मार्च के अंत में)

क्र. सं.	मद	2022	2023	2024
1	2	3	4	5
1	आस्तियों पर प्रतिलाभ	-0.7	0.4	0.4
2	इक्विटी पर प्रतिलाभ	-5.3	3.1	2.7
3	कुल आस्तियों की तुलना में निवेश	56.1	52.7	55.9
4	निवल ब्याज मार्जिन	2.3	3.7	5.7
5	दक्षता (लागत-आय अनुपात)	102.2	98.3	97.2
6	कार्यशील निधि की तलना में परिचालनगत लाभ	-0.6	0.5	0.8
7	लाभ का अंतर	-2.6	1.5	1.3

टिप्पणी : आंकड़े 6 पीबी से संबंधित हैं।

स्रोत : परोक्ष विवरणियां (घरेलू परिचालनगत), भारतीय रिजर्व बैंक

दे रही हैं। उत्पादकता और दक्षता लाभ के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने का लक्ष्य रखते हुए, भारतीय बैंक डिजिटलीकरण में सबसे आगे हैं। हालाँकि, नई तकनीक को अपनाने के साथ, साइबर हमलों, डिजिटल धोखाधड़ी, डेटा उल्लंघनों और परिचालन विफलताओं के जोखिम भी बढ़ गए हैं।

IV.106 भविष्य में, बैंकों के लिए अपने जोखिम प्रबंधन मानकों, आईटी गवर्नेंस व्यवस्थाओं और ग्राहक ऑनबोर्डिंग तथा लेनदेन निगरानी प्रणालियों को मजबूत करने की निरंतर आवश्यकता है, ताकि संदिग्ध और असामान्य लेनदेन सहित अनैतिक गतिविधियों की जांच रखी जा सके।

शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) की जमा वृद्धि में वर्ष 2023-24 में सुधार हुआ और ऋण वृद्धि सतत बनी रही। यूसीबी के वित्तीय प्रदर्शन में उच्च लाभप्रदता, मजबूत पूंजी बफर और कम सकल सकल अनर्जक आस्तियों (जीएनपीए) के अनुपात के कारण सुधार हुआ। राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी) और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) के जीएनपीए अनुपात में गिरावट आई, लेकिन वाणिज्यिक बैंकों के सापेक्ष अधिक रहा।

1. परिचय

V.1 सहकारी बैंक भारत के वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, विशेष रूप से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और ग्रामीण विकास का समर्थन करने में। वर्षों से, सहकारी बैंकिंग क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कई सुधार किए गए हैं जैसे— इस क्षेत्र के दोहरे विनियमन से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए बैंकिंग विनियमन (बीआर) अधिनियम के तहत रिजर्व बैंक की विनियामक शक्तियों का विस्तार; पूंजी जुटाने के लिए सहकारी बैंकों को अधिक स्वतंत्रता; और इस क्षेत्र में जमाकर्ताओं के विश्वास बढ़ाने के लिए जमा बीमा सुधार। रिजर्व बैंक ने जुलाई 2024 में टियर 2 से 4 में शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिये एक त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) फ्रेमवर्क की शुरुआत की और टियर 1 यूसीबी के लिये निगरानी बढ़ाई, जो 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी।

V.2 इस पृष्ठभूमि में, शेष अध्याय समीक्षाधीन अवधि के दौरान शहरी और ग्रामीण सहकारी बैंकों के प्रदर्शन पर केंद्रित है।¹ खंड 2 में सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की विकसनशील संरचना पर चर्चा की गई है, इसके बाद खंड 3 में यूसीबी की लाभप्रदता,

आस्ति गुणवत्ता और पूंजी पर्याप्तता का मूल्यांकन किया गया है। खंड 4 अल्पकालिक और दीर्घकालिक ग्रामीण सहकारी समितियों के वित्तीय प्रदर्शन की जांच करता है। इसके बाद खंड 5 में एक समग्र मूल्यांकन किया गया है।

2. सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की संरचना

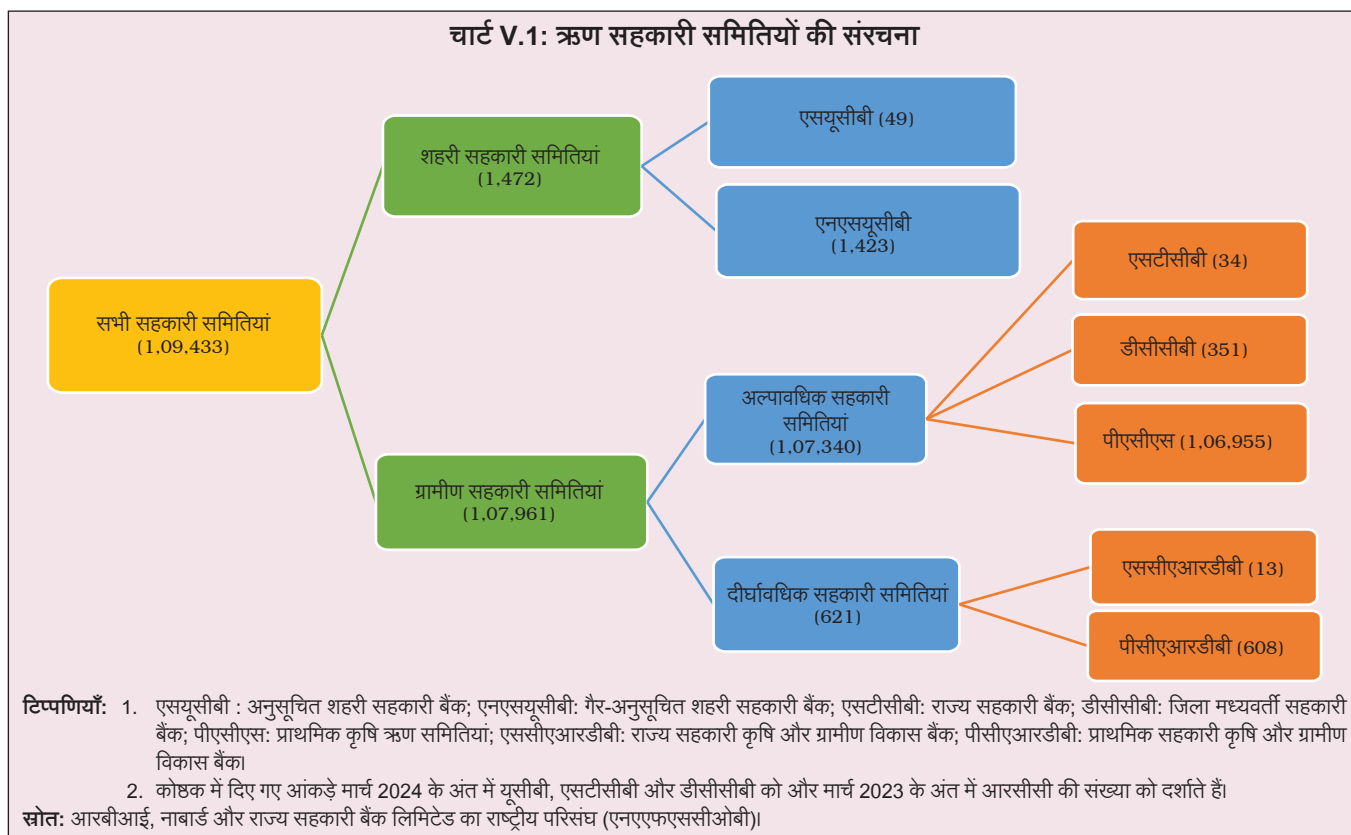
V.3 सहकारी बैंकिंग संरचना, जिसमें यूसीबी और ग्रामीण ऋण सहकारी समितियां (आरसीसी) शामिल हैं, सीमांत उधारकर्ताओं को उधार देने और गांवों और छोटे शहरों में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने पर ज़ोर देकर वाणिज्यिक बैंकिंग संस्थानों की सहायता करती है। यूसीबी को अनुसूचित या गैर-अनुसूचित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, इस आधार पर कि क्या वे भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल हैं² और उनकी भौगोलिक पहुँच (एकल-राज्य या बहु-राज्य) है। आरसीसी को अल्पकालिक और दीर्घकालिक संस्थानों में वर्गीकृत किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान, 1,472 यूसीबी और 1,07,961 आरसीसी थे³ (चार्ट V.1)। संस्थाओं की संख्या के संदर्भ में, 97 प्रतिशत से अधिक कुल सहकारी क्षेत्र, प्राथमिक कृषि ऋण समितियां

¹ यद्यपि प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पीसीएस) और दीर्घकालिक ग्रामीण ऋण सहकारी समितियां रिजर्व बैंक के विनियामक कार्यक्षेत्र से बाहर हैं, विश्लेषण की पूर्णता के लिए उनके क्रियाकलापों और प्रदर्शन का संक्षिप्त विवरण इस अध्याय में दिया गया है।

² अनुसूचित सहकारी बैंकों के अलावा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को भी अधिनियम की इसी अनुसूची में शामिल किया गया है।

³ पीसीएस, राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (एससीएआरडीबी) और प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (पीसीएआरडीबी) के डेटा एक वर्ष के अंतराल के साथ उपलब्ध हैं, अर्थात्, वे वर्ष 2022-23 से संबंधित हैं।

चार्ट V.1: ऋण सहकारी समितियों की संरचना



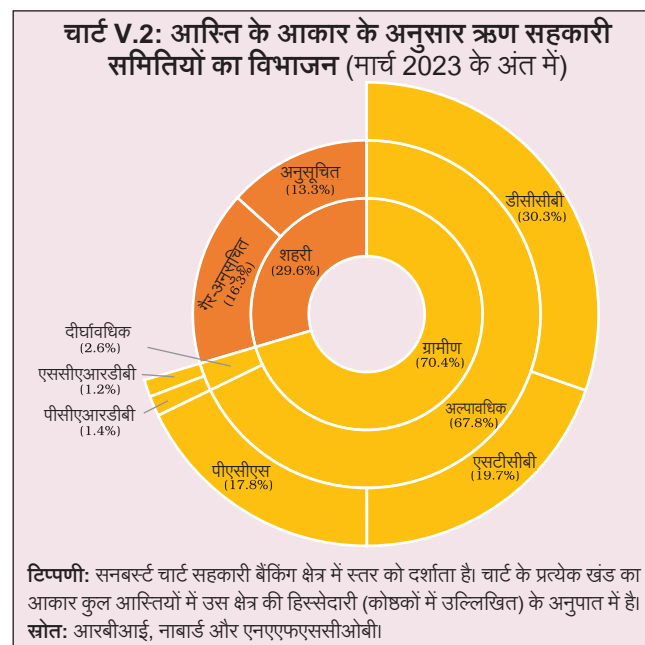
(पीसीएस) हैं, हालांकि आस्तियों के संदर्भ में, कुल सहकारी खंड में उनका हिस्सा केवल 17.8 प्रतिशत और आरसीसी में 25.3 प्रतिशत है।

समिति क्षेत्र की कुल आस्तियों (ग्रामीण और शहरी सहकारी समितियों को मिलाकर) में आरसीसी की हिस्सेदारी 70.4 प्रतिशत है (चार्ट V.2)

V.4 यूसीबी का रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमन और पर्यवेक्षण किया जाता है। राज्य सहकारी बैंक (एसटीसीबी) और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक (डीसीसीबी) संबंधित राज्य के राज्य सहकारी समिति अधिनियम के प्रावधानों के तहत पंजीकृत हैं और रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित हैं। बीआर अधिनियम की धारा 35 (6) के तहत राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा उनका पर्यवेक्षण किया जाता है।

V.5 मार्च 2023 के अंत में सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की समेकित आस्तियां ₹22.9 लाख करोड़ थीं, जो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की आस्तियों का लगभग 9.5 प्रतिशत थीं, जो मार्च 2014 के अंत के 11.2 प्रतिशत से कम थीं। सहकारी

चार्ट V.2: आस्ति के आकार के अनुसार ऋण सहकारी समितियों का विभाजन (मार्च 2023 के अंत में)



सारणी V.1 कृषि की ऋण प्रवाह में हिस्सेदारी

(प्रतिशत)

ग्रामीण ऋण सहकारी समितियां	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	वाणिज्यिक बैंक
1	2	3
2016-17	13.4	11.6
2017-18	12.9	12.1
2018-19	12.1	11.9
2019-20	11.3	11.9
2020-21	12.1	12.1
2021-22	13.0	11.0
2022-23	11.0	11.2
2023-24	9.5	11.1

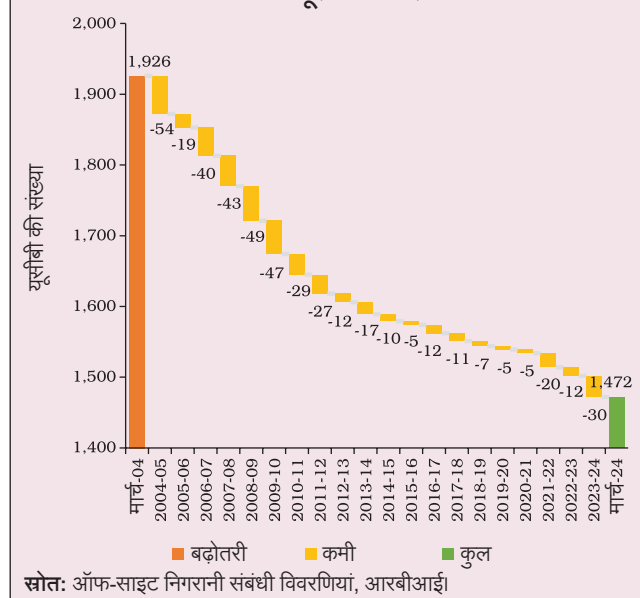
स्रोत: नाबार्ड (एन्श्योर पोर्टल)।

V.6 ग्रामीण सहकारी समितियों की स्थापना कृषि को ऋण देने के प्राथमिक उद्देश्य से की गई थी। प्रौद्योगिकी और शाखा विस्तार के माध्यम से वाणिज्यिक बैंकों की बढ़ती पहुंच के कारण वर्ष 2023-24 में कृषि के कुल ऋण में उनकी हिस्सेदारी लगातार दूसरे वर्ष घटकर 10 प्रतिशत से कम हो गई (सारणी V.1)।

3. शहरी सहकारी बैंक

V.7 उदार लाइसेंसिंग नीति के कारण 1990 के दशक में यूसीबी की संख्या में वृद्धि हुई। पिछले कुछ वर्षों में, नए लाइसेंस प्राप्त बैंकों में से लगभग एक तिहाई वित्तीय रूप से अस्थिर हो गए। वर्ष 2004-05 से, रिजर्व बैंक ने एकीकरण की प्रक्रिया शुरू की, जिसमें गैर-अर्थक्षम यूसीबी को उनके अर्थक्षम समकक्षों के साथ मिलाना, गैर-अर्थक्षम संस्थाओं को बंद करना और नए लाइसेंस

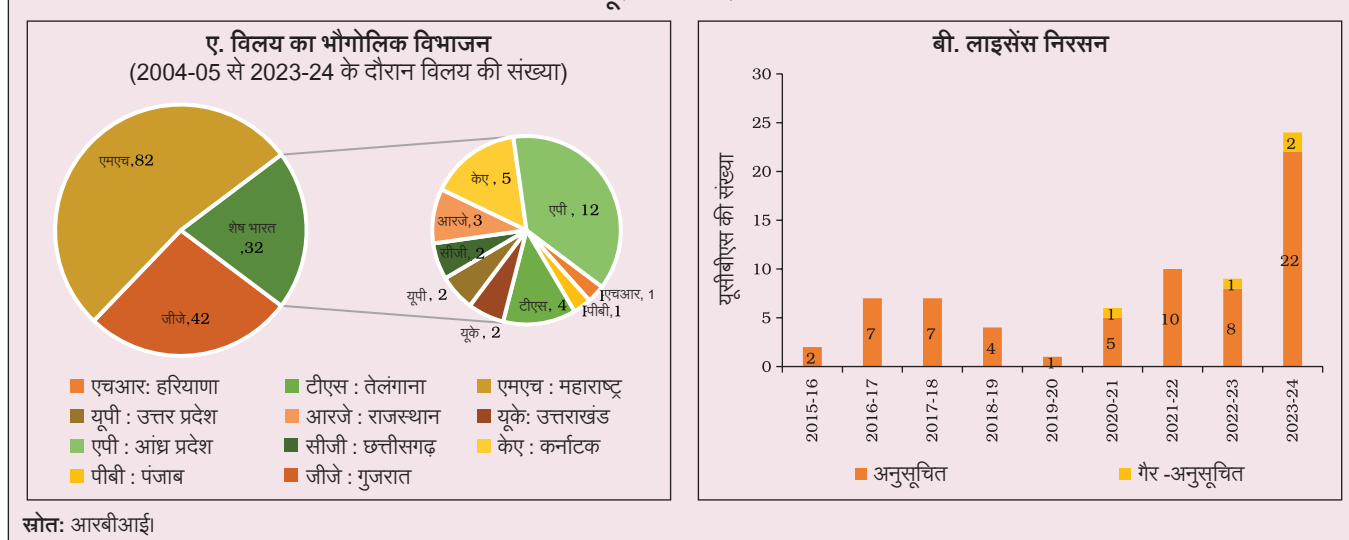
चार्ट V.3: यूसीबी की संख्या



जारी करने को निलंबित करना शामिल था। परिणामस्वरूप, पिछले दो दशकों में यूसीबी की संख्या 1,926 से घटकर 1,472 हो गई (चार्ट V.3)।

V.8 वर्ष 2004-05 के बाद से, इस क्षेत्र ने 156 विलय देखे हैं, जिनमें वर्ष 2023-24 में छह शामिल हैं, जिनमें से तीन महाराष्ट्र में थे, दो तेलंगाना में थे और एक गुजरात में था। पिछले दो दशकों में अधिकांश विलय महाराष्ट्र में हुए, इसके बाद गुजरात और आंध्र प्रदेश का स्थान रहा (चार्ट V.4ए)। वर्ष 2023-24

चार्ट V.4: यूसीबी में विलयन अभियान



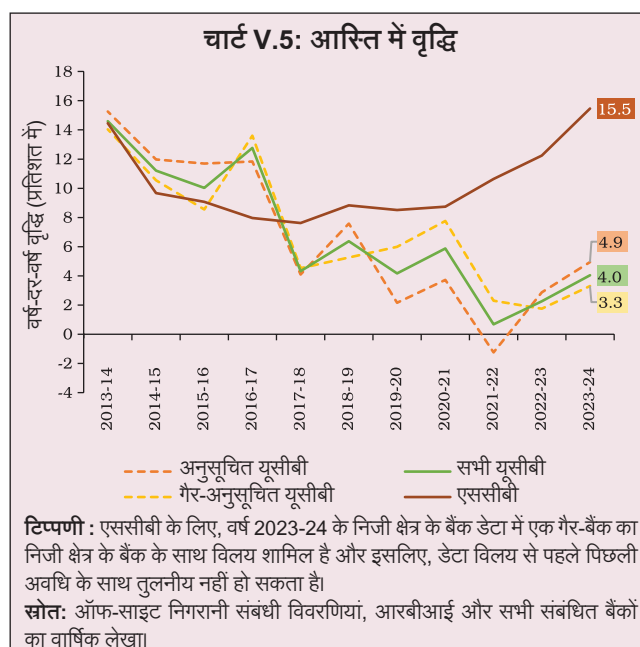
भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति संबंधी रिपोर्ट 2023-24

के दौरान, 24 यूसीबी के लाइसेंस रद्द कर दिए गए, जिससे वर्ष 2015-16 से रद्द किए गए लाइसेंसों की कुल संख्या बढ़कर 70 हो गई। 94.3 प्रतिशत रद्दीकरण गैर-अनुसूचित श्रेणी में हुए (चार्ट V.4बी)।

V.9 शहरी सहकारी बैंकों पर विशेषज्ञ समिति (अध्यक्ष: श्री एन.एस.विश्वनाथन) की सिफारिशों के अनुरूप, रिजर्व बैंक ने वर्ष 2022-23 में यूसीबी के लिए चार-स्तरीय विनियामक ढांचे को अपनाया⁴ मार्च 2024 के अंत में, टियर 1 में यूसीबी के शेयर में गिरावट आई जबकि टियर 2 की हिस्सेदारी वर्ष-दर-वर्ष (व-द-व) बढ़ी, जो आंशिक रूप से बढ़ते जमाराशियों के आधार को दर्शाती है। टियर 3 यूसीबी, यूसीबी की कुल संख्या में लगभग 5 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ, जमा, अग्रिम और कुल आस्तियों में एक तिहाई से अधिक हिस्सेदारी के साथ इस क्षेत्र पर हावी है (सारणी V.2)।

3.1. तुलन-पत्र

V.10 वर्ष 2023-24 के दौरान, यूसीबी के समेकित तुलन-पत्र ने 4 प्रतिशत की धीमी वृद्धि दर्ज की, जो पिछले वर्ष में 2.3 प्रतिशत से अधिक थी। एससीबी के सापेक्ष यूसीबी के तुलन-पत्र



का आकार लगातार सातवें वर्ष गिरकर मार्च 2024 के अंत में 2.5 प्रतिशत हो गया, जो मार्च 2017 के अंत में 3.8 प्रतिशत था, जो देयताओं में जमा वृद्धि में कमी और आस्तियों के पक्ष पर ऋण के कारण कम हुआ (चार्ट V.5)।

V.11 सभी यूसीबी की जमा वृद्धि ने वर्ष 2023-24 के दौरान 4.1 प्रतिशत तक मामूली वृद्धि प्रदर्शित की, जो एससीबी में

सारणी V.2: शहरी सहकारी बैंकों का टियर-वार वितरण (मार्च 2024 के अंत में)

(राशि ₹ करोड़ में, प्रतिशत में शेयर)

टियर का प्रकार	बैंकों की संख्या		जमाराशियाँ		अग्रिम		कुल आस्तियां	
	संख्या	शेयर	राशि	शेयर	राशि	शेयर	राशि	शेयर
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	850	57.7	63,627	11.5	41,842	12.1	88,669	12.5
2	538	36.5	1,71,039	30.8	1,03,498	29.8	2,17,142	30.7
3	78	5.3	1,93,105	34.8	1,16,143	33.5	2,39,240	33.8
4	6	0.4	1,27,698	23.0	85,420	24.6	1,62,618	23.0
सभी यूसीबी	1,472	100	5,55,469	100	3,46,903	100	7,07,669	100

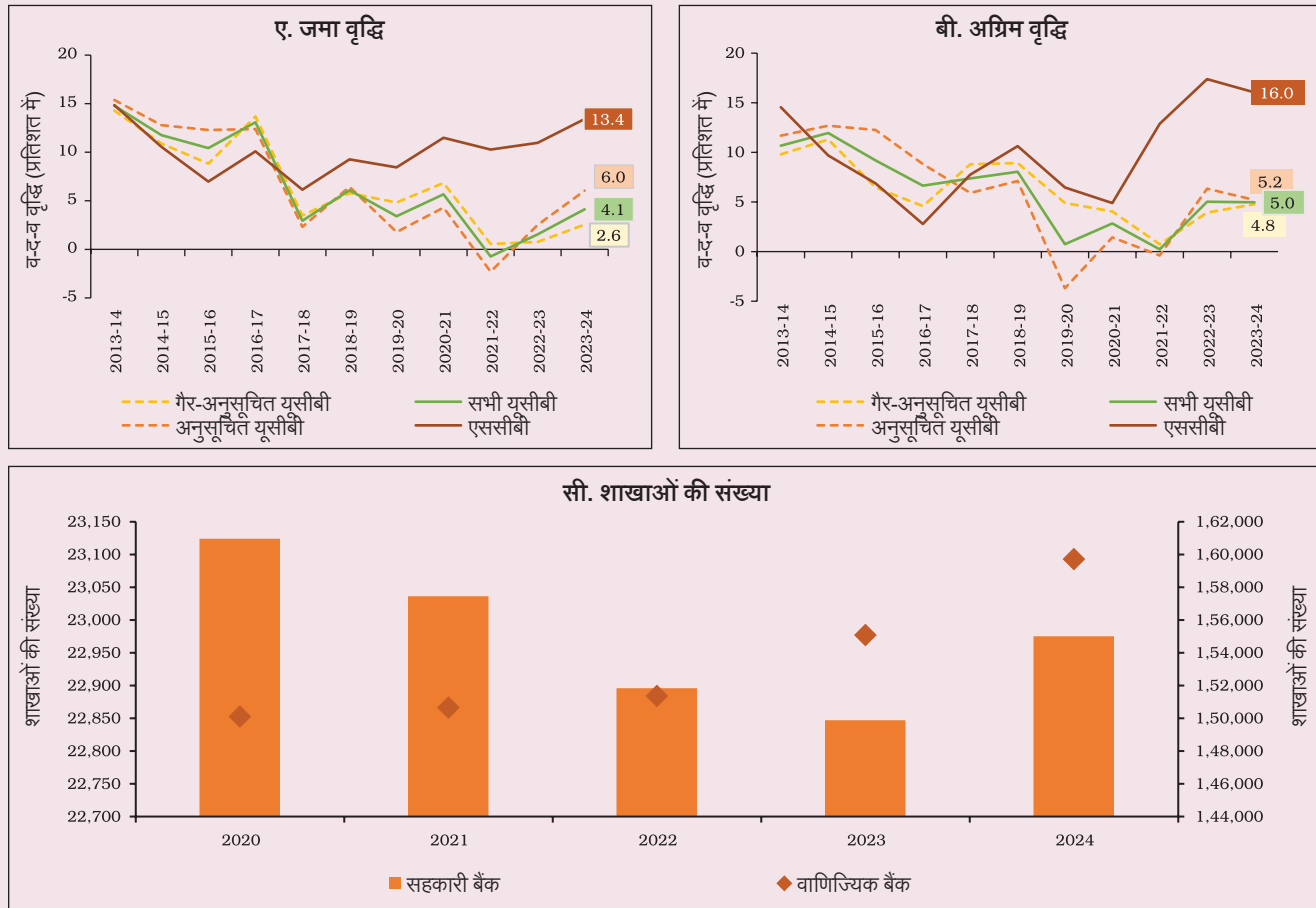
टिप्पणियाँ : 1. डेटा अनंतिम है।

2. पूर्णांकन के कारण घटकों का योग पूर्ण योग के बराबर नहीं हो सकता है।

स्रोत: ऑफ-साइट निगरानी संबंधी विवरणियां, आरबीआई।

⁴ ₹100 करोड़ रुपये तक जमाराशियों वाले यूसीबी को टियर 1 के रूप में वर्गीकृत किया गया है; टियर 2 के रूप में जिनके पास ₹100 करोड़ से अधिक और ₹1,000 करोड़ तक जमा है; टियर 3 के रूप में जिनके पास ₹1,000 करोड़ से अधिक और ₹10,000 करोड़ तक जमा है; और ₹10,000 करोड़ से ऊपर वालों को टियर 4 में रखा गया है। 01 दिसंबर 2022 के परिपत्र के अनुसार, सभी यूसीबी इकाइयों और वैतनिक यूसीबी (जमाराशियों से अलग) को टियर 1 यूसीबी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उपर्युक्त जमाराशियों की गणना तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को लेखापरीक्षित तुलन-पत्र के अनुसार की जाएगी।

चार्ट V.6: एससीबी की तुलना में यूसीबी का प्रदर्शन



टिप्पणी: वर्ष 2023-24 के लिए एससीबी के जमा और अग्रिमों के डेटा में निजी क्षेत्र के बैंक के साथ गैर-बैंक के विलय के प्रभाव को शामिल नहीं किया गया है।

स्रोत : ऑफ-साइट निगरानी संबंधी विवरणियां, आरबीआई का सीआईएसबीआई पोर्टल और संबंधित बैंकों का वार्षिक लेखा।

13.4 प्रतिशत से नीचे रहा (चार्ट V.6ए)। यूसीबी के जमा में 4.4 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वर्ष 2024-25 की पहली छमाही में गति बनी रही। यूसीबी की ऋण वृद्धि वर्ष 2023-24 में 5.0 प्रतिशत पर धीमी रही, एससीबी द्वारा दर्ज 16.0 प्रतिशत के विस्तार के एक तिहाई से भी कम थी (सारणी V.3 और चार्ट V.6बी)। हालांकि, यूसीबी की ऋण वृद्धि सितंबर 2024 के अंत में बढ़कर 6.2 प्रतिशत हो गई। हाल के वर्षों में यूसीबी की जमा और ऋण वृद्धि एससीबी से पीछे रही जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, यूसीबी की संख्या और उनके शाखा नेटवर्क में गिरावट परिलक्षित होती है (चार्ट V.6सी)। दूसरी ओर, एससीबी अपनी पहुंच का विस्तार करने के लिए प्रौद्योगिकी के

साथ-साथ कारोबार प्रतिनिधि (बीसी) मॉडल का बड़े पैमाने पर लाभ उठा रहे हैं।

V.12 यूसीबी का ऋण-जमा (सी-डी) अनुपात वर्ष 2023-24 में लगातार तीसरे वर्ष बढ़कर 62.5 प्रतिशत हो गया (चार्ट V.7)। मार्च 2024 के अंत में यूसीबी की कुल देयताओं में उधार का हिस्सा 0.8 प्रतिशत था, जो एससीबी के दसवें हिस्से (9.0 प्रतिशत) से भी कम था।

V.13 आस्तियों और जमा राशियों के संदर्भ में यूसीबी की संख्या का वितरण पिछले कुछ वर्षों बढ़ोतरी की ओर रहा है और द्वि-मोडल से एकल-मोडल में बदल गया है (चार्ट V.8)। वर्ष 2014-15 में, 40 प्रतिशत से अधिक यूसीबी ₹25 करोड़

सारणी V.3: शहरी सहकारी बैंकों के तुलन पत्र
(मार्च के अंत में)

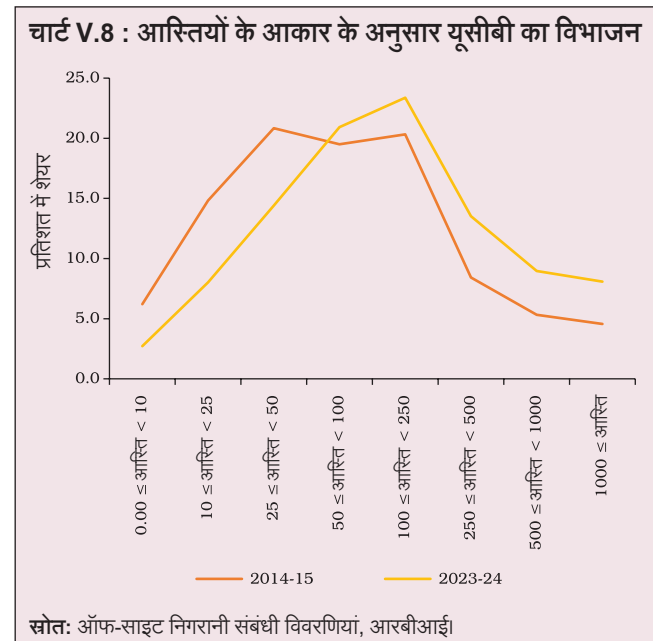
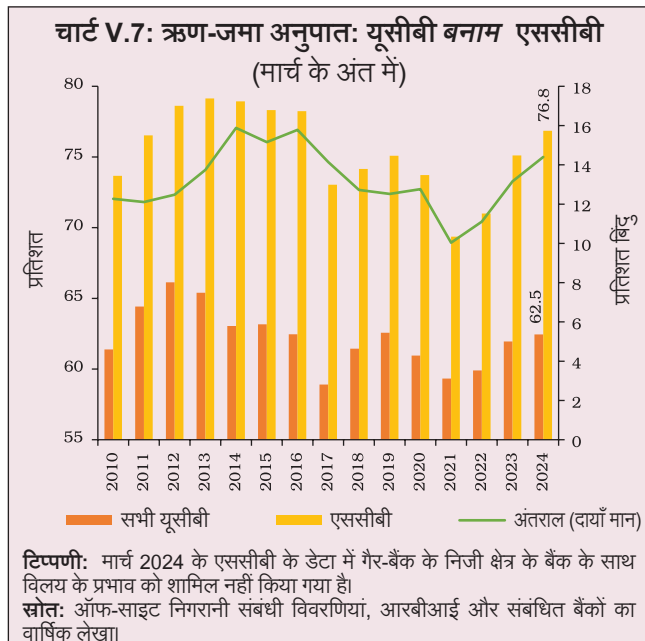
(राशि ₹ करोड़ में)

	अनुसूचित यूसीबी		गैर-अनुसूचित यूसीबी		सभी यूसीबी		सभी यूसीबी (प्रतिशत में व-द-व वृद्धि)	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2022-23	2023-24
1	2	3	4	5	6	7	8	9
देयताएँ								
1) पूंजी	4,256 (1.4)	4,293 (1.3)	10,459 (2.8)	10,831 (2.8)	14,715 (2.2)	15,124 (2.1)	3.2	2.8
2) आरक्षित निधि और अधिशेष	22,287 (7.3)	25,298 (7.9)	25,958 (6.9)	29,435 (7.6)	48,245 (7.1)	54,732 (7.7)	12.7	13.4
3) जमाराशियाँ	2,39,982 (78.3)	2,54,479 (79.1)	2,93,484 (78.6)	3,00,991 (78.0)	5,33,466 (78.4)	5,55,469 (78.5)	1.5	4.1
4) उधार	5,776 (1.9)	5,082 (1.6)	465 (0.1)	297 (0.1)	6,241 (0.9)	5,380 (0.8)	10.3	-13.8
5) अन्य देयताएं और प्रावधान	34,280 (11.2)	32,571 (10.1)	43,250 (11.6)	44,392 (11.5)	77,530 (11.4)	76,963 (10.9)	0.5	-0.7
आस्तियां								
1) हाथ में नकदी	1660 (0.5)	1759 (0.5)	4224 (1.1)	4434 (1.1)	5884 (0.9)	6193 (0.9)	-6.4	5.3
2) आरबीआई के पास शेष राशि	12,770 (4.2)	13,778 (4.3)	3,592 (1.0)	4,545 (1.2)	16,362 (2.4)	18,323 (2.6)	-0.4	12.0
3) बैंकों के पास शेष राशि	21,011 (6.9)	24,701 (7.7)	45,718 (12.2)	47,715 (12.4)	66,729 (9.8)	72,415 (10.2)	-4.9	8.5
4) कॉल और अल्प सूचना पर मुद्रा	2,554 (0.8)	2,367 (0.7)	886 (0.2)	919 (0.2)	3,440 (0.5)	3,286 (0.5)	-31.1	-4.5
5) निवेश	83,254 (27.2)	86,626 (26.9)	1,07,412 (28.7)	1,07,188 (27.8)	1,90,666 (28.0)	1,93,814 (27.4)	1.6	1.7
6) ऋण और अग्रिम	1,51,663 (49.5)	1,59,553 (49.6)	1,78,828 (47.9)	1,87,350 (48.5)	3,30,491 (48.6)	3,46,903 (49.0)	5.0	5.0
7) अन्य आस्तियां	33,668 (11.0)	32,939 (10.2)	32,957 (8.8)	33,795 (8.8)	66,625 (9.8)	66,734 (9.4)	2.4	0.2
कुल देयताएं/आस्तियां	3,06,581 (100)	3,21,723 (100)	3,73,616 (100)	3,85,946 (100)	6,80,197 (100)	7,07,669 (100)	2.3	4.0

टिप्पणियां: 1. 2024 के लिए: आंकड़े अनंतिम हैं।
2. कोष्ठक में आंकड़े कुल देयताएं / आस्तियों (प्रतिशत में) के अनुपात हैं।
3. पूर्णांकन के कारण घटकों का योग पूर्ण योग के बराबर नहीं हो सकता है।
स्रोत: ऑफ-साइट निगरानी संबंधी विवरणियां, आरबीआई।

से ₹50 करोड़ और ₹100 करोड़ से ₹250 करोड़ की आस्ति श्रेणियों में थे; वर्ष 2023-24 में, 44.3 प्रतिशत यूसीबी ₹50

करोड़ से ₹250 करोड़ की आस्ति श्रेणियों में थे। अग्रिमों के संदर्भ में, मार्च 2024 के अंत में मॉडल वर्ग ₹25 करोड़ से ₹50



**सारणी V.4: जमाराशि, अग्रिम और आस्तियों के अनुसार
यूसीबी का विभाजन
(मार्च 2024 के अंत में)**

(राशि ₹ करोड़ में)

	जमाराशियां		अग्रिम		आस्तियां	
	यूसीबी की संख्या	राशि	यूसीबी की संख्या	राशि	यूसीबी की संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7
$0 \leq X < 10$	83	495	183	1,093	40	251
$10 \leq X < 25$	164	2,914	241	4,096	118	2,072
$25 \leq X < 50$	240	8,879	282	9,921	212	7,839
$50 \leq X < 100$	300	21,543	258	18,084	308	22,489
$100 \leq X < 250$	322	52,648	256	39,538	344	55,860
$250 \leq X < 500$	156	55,565	135	47,284	199	70,093
$500 \leq X < 1000$	116	79,450	65	45,585	132	92,885
$1000 \leq X$	91	3,33,976	52	1,81,301	119	4,56,181
कुल	1,472	5,55,469	1,472	3,46,903	1,472	7,07,669

टिप्पणियाँ: 1. डेटा अनंतिम हैं।

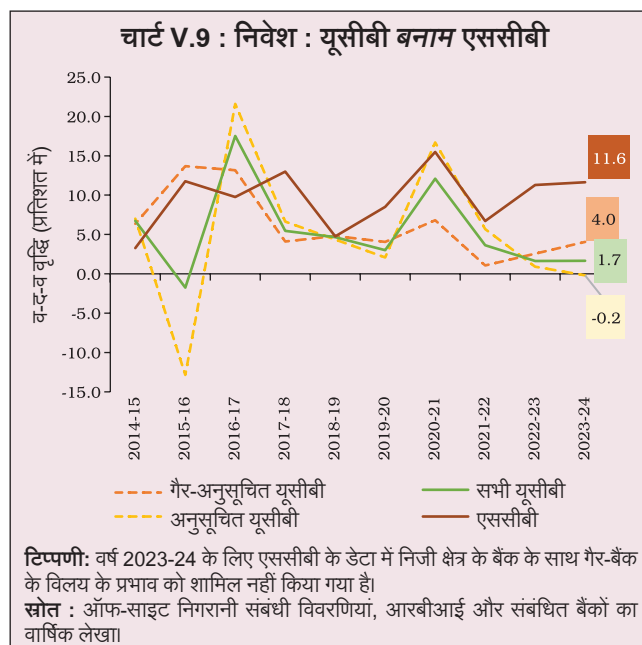
2. 'X' जमा, अग्रिम और आस्तियों की राशि को इंगित करता है।

स्रोत: ऑफ-साइट निगरानी संबंधी विवरणियां, आरबीआई।

करोड़ था, जिसमें 80 प्रतिशत से अधिक यूसीबी के पास कुल अग्रिम ₹250 करोड़ से कम थे (सारणी V.4)।

V.14 वर्ष 2023-24 के दौरान, यूसीबी की निवेश वृद्धि काफी हद तक अपरिवर्तित रही, जिससे एससीबी के साथ अंतर और बढ़ गया (चार्ट V.9)।

V.15 यूसीबी का 90 प्रतिशत निवेश एसएलआर लिखतों में रहा, जबकि एससीबी का 83 प्रतिशत था। वर्ष 2023-24 के दौरान केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में यूसीबी के एसएलआर



निवेश कम हुए (सारणी V.5)। पिछले कुछ वर्षों में, यूसीबी के कुल एसएलआर निवेशों में राज्य सरकार की प्रतिभूतियों की हिस्सेदारी बढ़ रही है।

3.2. वित्तीय प्रदर्शन और लाभप्रदता

V.16 वर्ष 2023-24 के दौरान यूसीबी के परिचालन लाभ में गिरावट आई क्योंकि कुल व्यय कुल आय की तुलना में तेज गति से बढ़ा। हालांकि निवल लाभ (कर से पहले और बाद) बेहतर आस्ति गुणवत्ता के कारण प्रावधानों और आकस्मिकताओं में

सारणी V.5: शहरी सहकारी बैंकों द्वारा निवेश

(राशि ₹ करोड़ में)

1	बकाया राशि (मार्च के अंत में)			घट-बढ़ (%)	
	2022	2023	2024	2022-23	2023-24
2	3	4	5	6	
कुल निवेश (ए + बी)	1,87,612 (100.0)	1,90,666 (100.0)	1,93,814 (100.0)	1.6	1.7
ए. एसएलआर निवेश (i से iii)	1,67,802 (89.4)	1,71,715 (90.1)	1,74,352 (90.0)	2.3	1.5
(i) केंद्र सरकार की प्रतिभूतियां	1,04,762 (55.8)	1,06,716 (56.0)	1,06,223 (54.8)	1.9	-0.5
(ii) राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	62,613 (33.4)	64,695 (33.9)	67,741 (35.0)	3.3	4.7
(iii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	427 (0.2)	304 (0.2)	388 (0.2)	-28.8	27.6
बी. गैर-एसएलआर निवेश	19,809 (10.6)	18,951 (9.9)	19,462 (10.0)	-4.3	2.7

टिप्पणियाँ: 1. 2024 के लिए: आंकड़े अनंतिम हैं।

2. कोष्ठक में आंकड़े कुल निवेश (प्रतिशत में) के अनुपात में हैं।

3. पूर्णांकन के कारण घटकों का योग पूर्ण योग के बराबर नहीं हो सकता है।

स्रोत: ऑफ-साइट निगरानी संबंधी विवरणियां, आरबीआई।

सारणी V.6: अनुसूचित और गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों का वित्तीय प्रदर्शन

(राशि ₹करोड़ में)

	अनुसूचित यूसीबी		गैर-अनुसूचित यूसीबी		सभी यूसीबी		सभी यूसीबी घट-बढ़ (%)	
	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ए. कुल आय [i+ii]	22,460	24,172	29,921	31,054	52,381	55,226	1.8	5.4
	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)		
i. ब्याज आय	19,473	21,476	28,125	29,232	47,598	50,708	2.1	6.5
	(86.7)	(88.8)	(94.0)	(94.1)	(90.9)	(91.8)		
ii. गैर-ब्याज आय	2,987	2,696	1,796	1,821	4,783	4,518	-0.8	-5.5
	(13.3)	(11.2)	(6.0)	(5.9)	(9.1)	(8.2)		
बी. कुल व्यय [i+ii]	17,820	19,785	24,592	25,999	42,411	45,784	-0.5	8.0
	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)		
i. ब्याज व्यय	11,093	12,838	16,382	17,451	27,475	30,289	-4.3	10.2
	(62.3)	(64.9)	(66.6)	(67.1)	(64.8)	(66.2)		
ii. गैर-ब्याज व्यय	6,727	6,947	8,209	8,548	14,936	15,495	7.5	3.7
	(37.7)	(35.1)	(33.4)	(32.9)	(35.2)	(33.8)		
जिनमें से: स्टाफ व्यय	2,955	2,999	4,259	4,370	7,214	7,368	2.7	2.1
सी. लाभ								
i. परिचालन लाभ की राशि	4,641	4,387	5,329	5,055	9,970	9,441	12.9	-5.3
ii. प्रावधान और आकस्मिकताएँ	2,899	1,200	2,671	1,904	5,570	3,104	15.9	-44.3
iii. करों के लिए प्रावधान	468	751	852	858	1,319	1,609	16.9	21.9
iv. करों से पहले निवल लाभ की राशि	1,742	3,187	2,658	3,151	4,400	6,338	9.3	44.0
v. करों के बाद निवल लाभ की राशि	1,274	2,435	1,807	2,293	3,080	4,729	6.4	53.5

टिप्पणियाँ: 1. 2023-24 के लिए: आंकड़े अंतिम हैं।
2. कोष्ठक में आंकड़े कुल आय/व्यय (प्रतिशत में) के अनुपात में हैं।
3. पूर्णांकन के कारण घटकों का योग पूर्ण योग के बराबर नहीं हो सकता है।

स्रोत: ऑफ-साइट निगरानी संबंधी विवरणियाँ, आरबीआई।

गिरावट होने की वजह से था। लाभांश आय में गिरावट, अचल आस्तियों की बिक्री में हानि और विदेशी मुद्रा परिचालन पर कम लाभ के कारण गैर-ब्याज आय में गिरावट आई। आंशिक रूप से कर्मचारियों के खर्चों में कमी के कारण यूसीबी के गैर-

ब्याज व्यय की वृद्धि में कमी आई (सारणी V.6 और परिशिष्ट सारणी V.1)। कुल आय में गैर-ब्याज आय का हिस्सा बड़े एसयूसीबी में अधिक था और उनकी लाभप्रदता से विपरीत रूप से संबंधित था (बॉक्स V.1)।

बॉक्स V.1: अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों में गैर-ब्याज आय के निर्धारक

जबकि ब्याज आय बैंकिंग गतिविधि का मूल है, गैर-ब्याज आय के माध्यम से विविधीकरण उच्च जोखिम-समायोजित लाभ प्राप्त करने में मदद कर सकता है (अहमद, 2017)।

भारत में एसयूसीबी की कुल आय में गैर-ब्याज आय की हिस्सेदारी वर्ष 2014-15 में 10.7 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2019-20 में 16.7 प्रतिशत हो गई थी, जो वर्ष 2022-23 में घटकर 13.3 प्रतिशत हो गई। वर्ष 2014-15 से 2022-23 की अवधि के लिए 47 एसयूसीबी के वार्षिक पैल डेटा का उपयोग करते हुए, कुल आय में गैर-ब्याज आय के हिस्से के निर्धारकों का पता लगाने के लिए दो निश्चित प्रभाव पैल प्रतिगमन मॉडल का अनुमान लगाया गया है। बैंक विशिष्ट व्याख्यात्मक चर जैसे आस्ति का आकार, आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए) और आय और लागत अनुपात और समष्टिआर्थिक नियंत्रण चर (नाममात्र जीडीपी वृद्धि) को मॉडल I में शामिल किया गया है। मॉडल II में, गैर-ब्याज आय के हिस्से पर टियर 4 एसयूसीबी की लाभप्रदता के अंतर प्रभाव का आकलन

करने के लिए एक इंटरैक्शन डमी [डमी टियर 123 * आरओए (-1)] लाया गया है। डमी टियर123 ₹10,000 करोड़ से कम के जमा आधार वाले एसयूसीबी अर्थात्, टियर 1 से 3 एसयूसीबी के लिए मान 1 लेता है और टियर 4 एसयूसीबी (जमा > ₹ 10,000 करोड़) के लिए मान 0 लेता है।

प्रतिगमन अनुमानों से संकेत मिलता है कि बड़े आस्ति आकार वाले एसयूसीबी के पास गैर-ब्याज आय का अधिक हिस्सा है। उच्च लाभप्रदता (आरओए) गैर-ब्याज आय के हिस्से को कम करती है (सारणी V.1.1)। इसके अलावा, जैसे-जैसे लाभप्रदता बढ़ती है, टियर 4 एसयूसीबी के सापेक्ष टियर 1 से 3 एसयूसीबी के लिए गैर-ब्याज आय का हिस्सा बढ़ जाता है (मॉडल II)। कुल मिलाकर, अनुभवजन्य विश्लेषण से पता चलता है कि जैसे-जैसे बैंक आकार में बढ़ते हैं, वे गैर-पारंपरिक गतिविधियों की ओर विविधता लाने में सक्षम होते हैं जो उनकी गैर-ब्याज आय को बढ़ाता है।

(जारी...)

सारणी V.1.1: एसयूसीबी की गैर-ब्याज आय के निर्धारक

व्याख्यात्मक चर	गैर-ब्याज आय का हिस्सा	गैर-ब्याज आय का हिस्सा
	(1)	(2)
गैर-ब्याज आय का हिस्सा (-1)	0.00361 (0.128)	0.00193 (0.128)
जीडीपी वृद्धि दर	-0.119* (0.0606)	-0.117* (0.0603)
लागत और आय अनुपात (-1)	-3.143 (6.719)	-3.235 (6.720)
कुल आस्ति लॉग (-1)	4.285*** (1.551)	4.613*** (1.599)
आरओए (-1)	-0.431* (0.243)	-2.953** (1.428)
डमी टियर123*आरओए (-1)		2.522* (1.392)
स्थिरांक	-19.09 (15.36)	-21.45 (15.60)
किए गए अवलोकन	376	376
आर-वर्गित	0.513	0.514

टिप्पणीयां: 1. कोष्ठक में मजबूत मानक त्रुटियां हैं।
2. *** पी<0.01, ** पी<0.05, * पी<0.1

स्रोत: आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

संदर्भ:

अहमद, एमएम (2017)। आस्ति गुणवत्ता, गैर-ब्याज आय और बैंक लाभप्रदता: भारतीय बैंकों से साक्ष्य, आर्थिक मॉडलिंग, 63, 1-14.

V.17 वर्ष 2023-24 में उच्च निवल लाभ को दर्शाते हुए, यूसीबी के आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए), इक्विटी पर प्रतिलाभ (आरओई) और निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) में सुधार हुआ। वर्ष 2024-25 की पहली छमाही में, यूसीबी की लाभप्रदता और बढ़ी (सारणी V.7)।

V.18 यूसीबी की लाभप्रदता, जो वर्ष 2019-20 में एक बड़े यूसीबी की हानि के कारण कम हो गई थी, तब से आस्ति

गुणवत्ता में सुधार के साथ ठीक हो गई है (चार्ट V.10ए और बी)।

3.3. सुदृढ़ता

V.19 सहकारी बैंकों (यूसीबी सहित) पर जुर्माना लगाने के मामलों की संख्या 22 प्रतिशत बढ़कर पिछले वर्ष के 176 से वर्ष 2023-24 के दौरान 215 हो गई। हालांकि, जुर्माने की राशि में 13.8 प्रतिशत की गिरावट आई (अध्याय IV में सारणी IV.16)। निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) ने वर्ष 2023-24 के दौरान ₹1,432 करोड़ रुपए के दावों का निपटान किया, जो पूरी तरह से परिसमापन/सभी समावेशी निर्देशों (एआईडी) के तहत रखे गए सहकारी बैंकों से संबंधित थे।

3.4. पूंजी पर्याप्तता

V.20 जुलाई 2022 में, यूसीबी के लिए संशोधित विनियामक ढांचे ने टियर 2 से टियर 4 यूसीबी के लिए न्यूनतम विनियामक पूंजी आवश्यकता को बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर दिया, जबकि इसे टियर 1 यूसीबी के लिए 9 प्रतिशत पर रखा। मार्च 2024 के अंत में, 42.3 प्रतिशत यूसीबी ऊपरी टियर (टियर 2 से

सारणी V.7: यूसीबी के चुनिंदा लाभप्रदता संकेतक

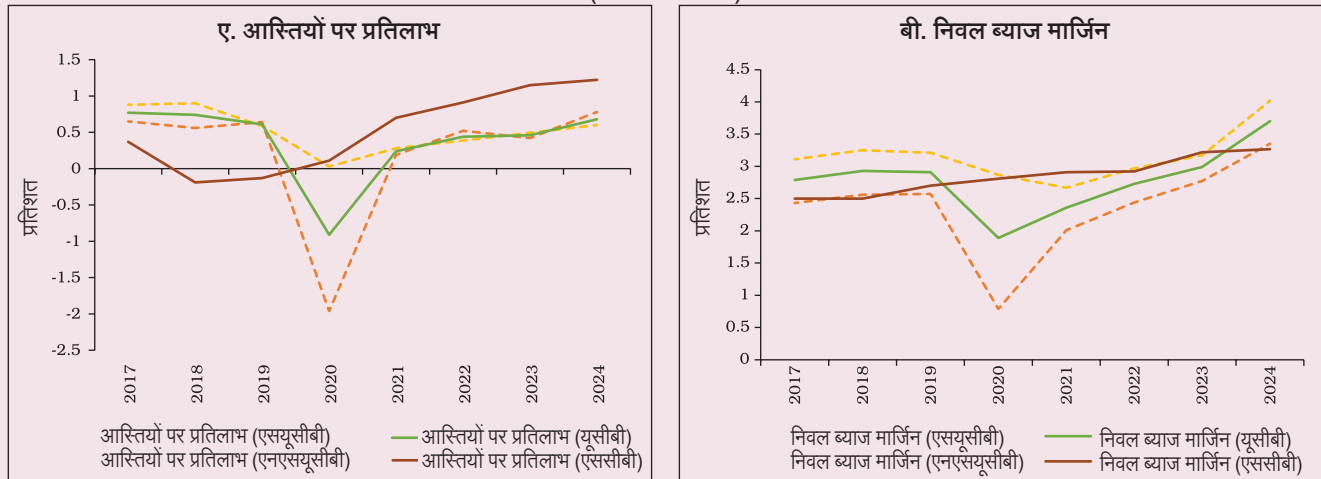
(प्रतिशत)

	अनुसूचित यूसीबी		गैर-अनुसूचित यूसीबी		सभी यूसीबी		
	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	सितं-24
1	2	3	4	5	6	7	8
आस्तियों पर प्रतिलाभ	0.42	0.78	0.49	0.60	0.46	0.68	0.84
इक्विटी पर प्रतिलाभ	5.08	8.68	5.17	5.98	5.13	7.12	8.4
निवल ब्याज मार्जिन	2.77	3.35	3.17	4.02	2.99	3.70	3.42

टिप्पणी: 2023-24 के लिए: आंकड़े अनंतिम हैं।

स्रोत: ऑफ-साइट निगरानी संबंधी विवरणियां, आरबीआई।

चार्ट V.10: लाभप्रदता संकेतक: यूसीबी बनाम एससीबी
(मार्च के अंत में)



स्रोत : बैंकों का वार्षिक लेखा और ऑफ-साइट निगरानी संबंधी विवरणियाँ, आरबीआई।

टियर 4) से संबंधित थे, जबकि 90 प्रतिशत से अधिक ने 12 प्रतिशत से ऊपर सीआरएआर बनाए रखा (सारणी V.8 और परिशिष्ट सारणी V.2)।

V.21 वर्ष 2023-24 के दौरान, यूसीबी के समेकित सीआरएआर में उच्च टियर I पूंजी के कारण सुधार हुआ, जो अन्य बातों के साथ-साथ प्रावधानों में कमी और टियर I पूंजी में पुनर्मूल्यन रिज़र्व⁵ (पहले टियर II पूंजी के रूप में जाना जाता था, उन्हें मार्च 2023 के अंत से कुछ शर्तों के अधीन टियर I पूंजी के रूप में अनुमति दी गई) को शामिल करने की विनियामक अनुमति के कारण लाभप्रदता में वृद्धि से प्रेरित था (सारणी V.9)।

सारणी V.8: सीआरएआर-वार यूसीबी का विभाजन
(मार्च 2024 के अंत में)

(बैंकों की संख्या)			
सीआरएआर (प्रतिशत में)	अनुसूचित यूसीबी	गैर-अनुसूचित यूसीबी	सभी यूसीबी
1	2	3	4
सीआरएआर < 3	1	28	29
3 ≤ सीआरएआर < 6	1	13	14
6 ≤ सीआरएआर < 9	0	14	14
9 ≤ सीआरएआर < 12	2	85	87
12 ≤ सीआरएआर	45	1,283	1,328
कुल	49	1,423	1,472

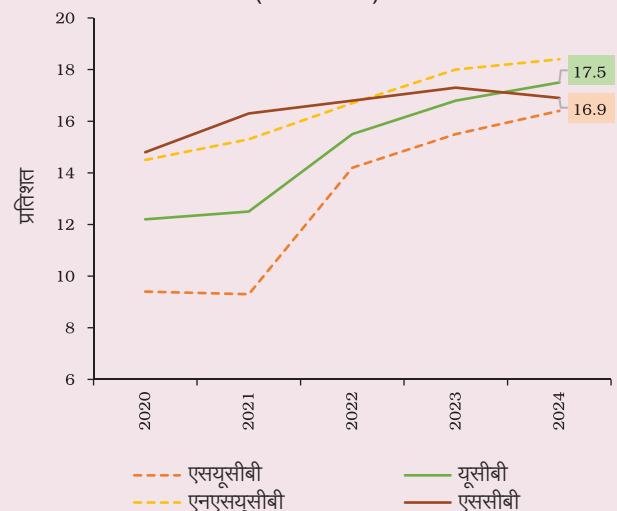
टिप्पणी: डेटा अनंतिम हैं।

स्रोत: ऑफ-साइट निगरानी संबंधी विवरणियाँ, आरबीआई।

इसके अतिरिक्त, यूसीबी द्वारा दीर्घकालिक गौण बॉण्ड जुटाने के प्रयासों ने उनके पूंजी आधार को मजबूत किया।

V.22 वर्ष 2021-22 के बाद से पूंजी में तेज वृद्धि को दर्शाते हुए, यूसीबी का सीआरएआर मार्च 2024 के अंत में एससीबी की तुलना में अधिक था (चार्ट V.11)। सीआरएआर सितंबर 2024 के अंत में 17.5 प्रतिशत पर स्थिर रहा।

चार्ट V.11 : सीआरएआर : यूसीबी बनाम एससीबी
(मार्च अंत में)



स्रोत: ऑफ-साइट निगरानी संबंधी विवरणियाँ, आरबीआई।

⁵ पुनर्मूल्यन रिज़र्व को पहले टियर II पूंजी के रूप में माना जाता था, लेकिन मार्च 2023 के अंत से कुछ शर्तों के अधीन, इसे टियर I पूंजी के रूप में अनुमति दी गई।

सारणी V.9: यूसीबी की घटक-वार पूंजी पर्याप्तता (मार्च के अंत में)

(राशि ₹ करोड़ में)

		अनुसूचित यूसीबी		गैर-अनुसूचित यूसीबी		सभी यूसीबी	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1	पूँजीगत निधि	23,367	25,964	30,715	33,238	54,081	59,202
	i) टियर 1 पूंजी	18,016	20,125	26,762	29,086	44,778	49,210
	ii) टियर 2 पूंजी	5,351	5,839	3,953	4,152	9,304	9,992
2	जोखिम-भारित आस्तियां	1,50,776	1,57,866	1,70,247	1,80,672	3,21,024	3,38,538
3	सीआरएआर (2 के % के रूप में 1)	15.5	16.4	18.0	18.4	16.8	17.5
	जिनमें से:						
	टियर I	11.9	12.7	15.7	16.1	13.9	14.5
	टियर II	3.5	3.7	2.3	2.3	2.9	3.0

टिप्पणी: 2024 के लिए: आंकड़े अनंतिम हैं।

स्रोत: ऑफ-साइट निगरानी संबंधी विवरणियां, आरबीआई।

3.5. आस्ति गुणवत्ता

V.23 सकल अनर्जक आस्तियों (जीएनपीए) के अनुपात द्वारा मापी गई शहरी सहकारी बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में लगातार तीसरे वर्ष सुधार हुआ, हालांकि यह एससीबी से काफी अधिक है (चार्ट V.12ए)। सितंबर 2024 के अंत में, यूसीबी का जीएनपीए अनुपात सितंबर 2023 के अंत में 10.9 प्रतिशत की तुलना में 9.6 प्रतिशत था। यूसीबी में, एनएसयूसीबी का जीएनपीए अनुपात अधिक था। जैसे-जैसे जीएनपीए में गिरावट गिरते प्रावधानों से आगे निकल गई, प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) में सुधार हुआ और मानक अग्रिमों⁶ के लिए यूसीबी के प्रावधानीकरण मानदंडों के चरणबद्ध सामंजस्य के साथ इसमें और वृद्धि होने की संभावना है (सारणी V.10)।

V.24 मार्च 2024 के अंत में, बड़े उधार खाते, यानी, ₹5 करोड़ और उससे अधिक के एक्सपोजर वाले खाते, यूसीबी के कुल ऋण का 24.3 प्रतिशत और उनके जीएनपीए का 31.1 प्रतिशत थे। इन खातों ने एसयूसीबी और एनएसयूसीबी के बीच भिन्न व्यवहार प्रदर्शित किए। एसयूसीबी के ऋण का 43 प्रतिशत इन खातों में केंद्रित था, जबकि इन उधारकर्ताओं के लिए एनएसयूसीबी का एक्सपोजर 10 प्रतिशत से कम था। बड़े उधारकर्ताओं की एनएसयूसीबी के एनपीए में 15.3 प्रतिशत

और एसयूसीबी के एनपीए में 63.0 प्रतिशत हिस्सेदारी थी। पूरे क्षेत्र के लिए, विशेष उल्लेख खाते-1 (एसएमए-1) में वर्ष के दौरान गिरावट आई लेकिन एसएमए-2 में वृद्धि हुई, जिसका कारण मुख्य रूप से एसयूसीबी रहा (चार्ट V.12बी)।

3.6. प्राथमिकता क्षेत्र ऋण

V.25 प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण के लिए संशोधित दिशानिर्देशों में यूसीबी के लिए उच्च लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं जिन्हें चरणबद्ध तरीके से प्राप्त किया जाना है⁷। मार्च 2023 के अंत और मार्च 2024 के अंत का लक्ष्य समायोजित निवल बैंक

सारणी V.10: यूसीबी की अनर्जक आस्तियां (मार्च के अंत में)

	अनुसूचित यूसीबी		गैर-अनुसूचित यूसीबी		सभी यूसीबी	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
सकल एनपीए (₹ करोड़)	10,016	8,422	19,188	16,988	29,204	25,411
सकल एनपीए अनुपात (%)	6.6	5.3	10.7	9.1	8.8	7.3
निवल एनपीए (₹ करोड़)	2,298	1,960	4,386	1,953	6,684	3,913
निवल एनपीए अनुपात (%)	1.6	1.3	2.7	1.1	2.2	1.2
प्रावधानीकरण (₹ करोड़)	7,718	6,462	14,802	15,035	22,520	21,497
प्रावधान कवरेज अनुपात (%)	77.1	76.7	77.1	88.5	77.1	84.6

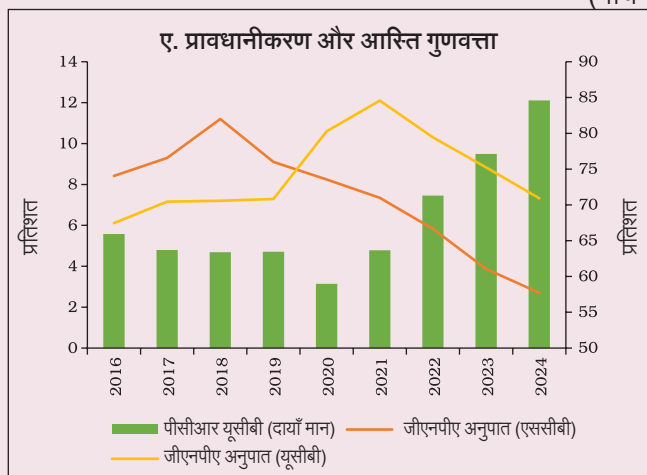
टिप्पणी: 2024 के लिए: आंकड़े अनंतिम हैं।

स्रोत: ऑफ-साइट निगरानी संबंधी विवरणियां, आरबीआई।

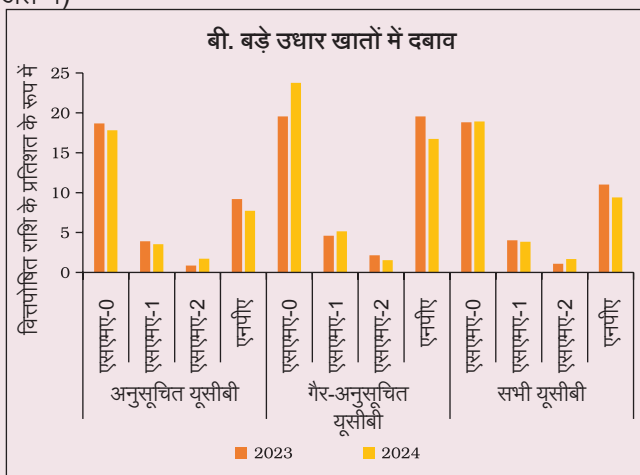
⁶ पूर्ववर्ती टियर I यूसीबी, जो 'उपर्युक्त को छोड़कर अन्य सभी ऋणों और अग्रिमों' पर 0.25 प्रतिशत का मानक आस्ति प्रावधान बनाए हुए थे, को प्रावधान आवश्यकता को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाकर 31 मार्च 2024 तक 0.30 प्रतिशत, 30 सितंबर 2024 तक 0.35 प्रतिशत और 31 मार्च 2025 तक 0.40 प्रतिशत तक पहुंचाने की आवश्यकता है।

⁷ मार्च 2020 में जारी और जुलाई 2023 में संशोधित दिशानिर्देशों में यूसीबी को क्रमशः मार्च 2024, 2025 और 2026 के अंत तक अपने एनबीसी या सीईओबीई के 60 प्रतिशत, 65 प्रतिशत और 75 प्रतिशत के लक्ष्य को पूरा करने की आवश्यकता है।

चार्ट V.12: आस्ति गुणवत्ता
(मार्च के अंत में)



स्रोत: ऑफ-साइट निगरानी संबंधी विवरणियाँ, आरबीआई और बैंकों के वार्षिक खाते।



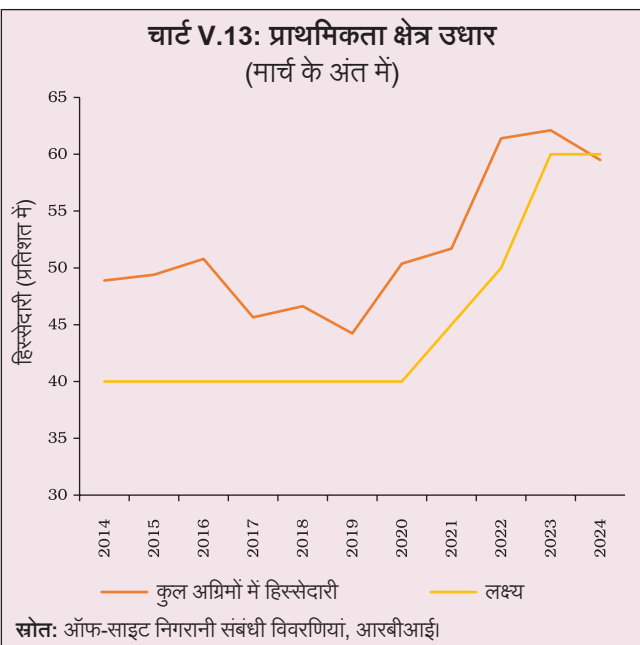
ऋण (एएनबीसी) या सीईओबीई का 60 प्रतिशत था। जबकि यूसीबी ने मार्च 2023 के अंत में आसानी से लक्ष्य पूरा कर लिया, वे मार्च 2024 के अंत में चूक गए (चार्ट V.13)।

V.26 वर्ष 2023-24 के दौरान, कुल प्राथमिकता क्षेत्र ऋण में एमएसएमई, विशेष रूप से छोटे उद्यमों की हिस्सेदारी में गिरावट आई। सूक्ष्म उद्यमों को यूसीबी का ऋण 7.5 प्रतिशत के लक्ष्य

को पार कर गया। हालांकि कमजोर वर्गों को ऋण देने में गिरावट आई, यूसीबी ने 11.5 प्रतिशत के लक्ष्य को पूरा किया। कुल अग्रिमों में नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा मामूली रूप से बढ़ा (सारणी V.11)।

4. ग्रामीण ऋण सहकारी समितियाँ

V.27 ग्रामीण ऋण सहकारी समितियाँ (आरसीसी) कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए पर्याप्त और किफायती ऋण प्रदान करने के लिए संस्थागत तंत्र के रूप में अस्तित्व में आईं। वे भीतरी इलाकों में अपनी जमीनी स्तर की उपस्थिति के कारण ग्रामीण ऋण वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आरसीसी अपने शहरी समकक्षों से उनके परिचालन के क्षेत्र, पहुंच, प्रदर्शन और देयताओं की संरचना के संदर्भ में भिन्न होती हैं। मार्च 2024 के अंत में, 2,140 शाखाओं के साथ 34 राज्य सहकारी बैंक (एसटीसीबी), 13,759 शाखाओं के साथ 351 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक (डीसीसीबी)⁸ थे। मार्च 2023 के अंत में, 6.5 लाख गांवों में फैली 1,06,955 प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (पीएसीएस) और दीर्घावधिक आरसीसी में 692 शाखाओं के साथ 13 राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (एससीएआरडीबी) और



स्रोत: ऑफ-साइट निगरानी संबंधी विवरणियाँ, आरबीआई।

⁸ इसमें जम्मू और कश्मीर में 3 डीसीसीबी शामिल हैं जिन्हें अभी लाइसेंस दिया जाना है और इसमें तमिलनाडु इंडस्ट्रियल को-ऑपरेटिव बैंक लि शामिल नहीं है जिसे केवल विनियमन/पर्यवेक्षण के प्रयोजनों के लिए डीसीसीबी माना जाता है।

सारणी V.11 : यूसीबी द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के लिए ऋण की संरचना (मार्च के अंत में)

(राशि ₹ करोड़ में)

		2023		2024	
		राशि	कुल अग्रिमों में हिस्सेदारी (%)	राशि	कुल अग्रिमों में हिस्सेदारी (%)
1	2	3	4	5	6
1	कृषि [(i)+(ii)+(iii)]	15,404	4.7	16,329	4.7
	(i) कृषि ऋण	11,470	3.5	12,328	3.6
	(ii) कृषि अवसंरचना	902	0.3	1,224	0.4
	(iii) सहायक गतिविधियाँ	3,032	0.9	2,777	0.8
2	सूक्ष्म और लघु उद्यम	1,24,658	37.7	1,29,069	37.2
	(i) + (ii) + (iii) + (iv)]				
	(i) सूक्ष्म उद्यम	52,849	16.0	56,533	16.3
	(ii) लघु उद्यम	48,903	14.8	48,495	14.0
	(iii) मध्यम उद्यम	22,281	6.7	23,492	6.8
	(iv) केवीआई को अग्रिम ('एमएसएमई के लिए अन्य वित्त' सहित)	625	0.2	549	0.2
3	निर्यात ऋण	319	0.1	723	0.2
4	शिक्षा	3,187	1.0	3,226	0.9
5	आवास	29,286	8.9	29,268	8.4
6	सामाजिक अवसंरचना	1,151	0.3	1,038	0.3
7	नवीकरणीय ऊर्जा	972	0.3	1,419	0.4
8	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के तहत 'अन्य' श्रेणी	30,121	9.1	25,326	7.3
9	कुल (1 to 8)	2,05,269	62.1	2,06,399	59.5
	जिनमें से, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के तहत कमजोर वर्गों को ऋण	45,565	13.8	42,743	12.3

टिप्पणियाँ 1. वर्ष 2024 के लिए डेटा अंतिम हैं।
2. प्रतिशत यूसीबी के कुल ऋण से संबंधित हैं।

स्रोत: ऑफ-साइट निगरानी संबंधी विवरणियाँ, आरबीआई।

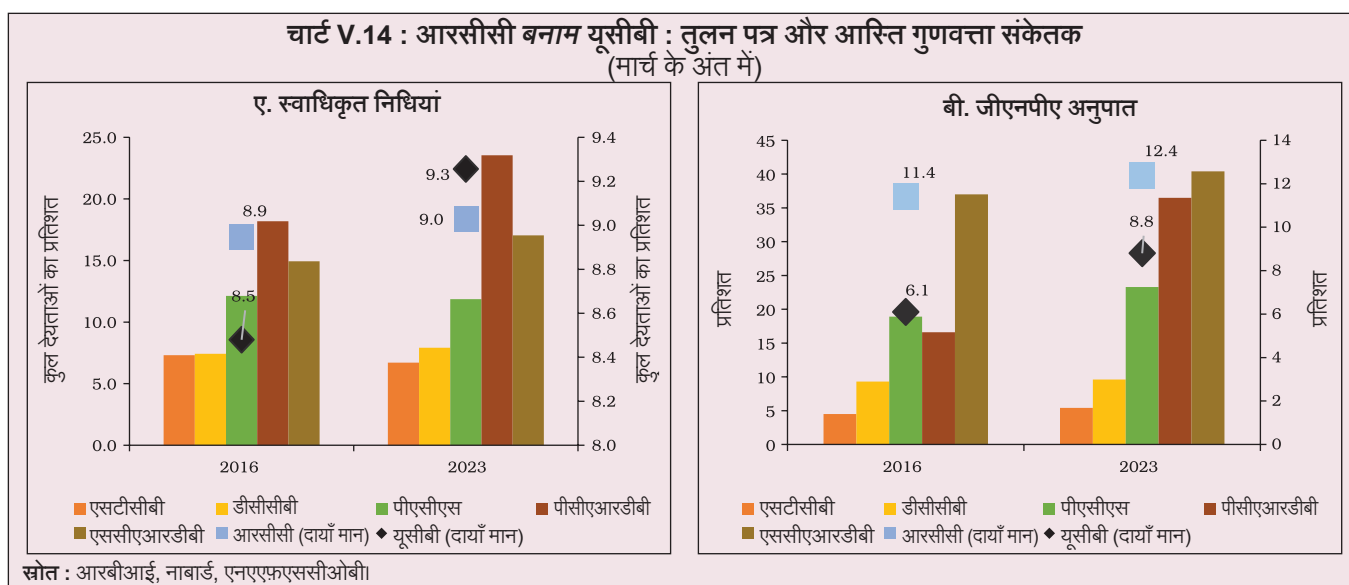
608 प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (पीसीएआरडीबी) थे।

V.28 जबकि यूसीबी मुख्य रूप से धन जुटाने के लिए जमाराशियों पर निर्भर रहते हैं, आरसीसी उधार पर बहुत अधिक निर्भर रहते हैं। मार्च 2023 के अंत में जमा राशि यूसीबी की कुल देयताओं का 78.4 प्रतिशत थी, जबकि आरसीसी के लिए यह 54.2 प्रतिशत थी। दूसरी ओर, मार्च 2023 के अंत में उधार आरसीसी की कुल देयताओं का लगभग 33 प्रतिशत और यूसीबी की देयताओं का 1 प्रतिशत से भी कम था।

V.29 यूसीबी के स्वामित्व वाली निधियों⁹ और देयताओं का अनुपात समय के साथ बढ़ा है और मार्च 2023 के अंत में आरसीसी से आगे निकल गया है, क्योंकि यूसीबी के पास अधिक रिजर्व है। आरसीसी में, एससीएआरडीबी के पास कुल देयताओं में स्वामित्व वाली निधियों का सबसे अधिक हिस्सा है (चार्ट V.14ए)। यूसीबी की आस्ति गुणवत्ता आरसीसी से बेहतर रही, जबकि दीर्घकालिक सहकारी समितियों के जीएनपीए अनुपात में गिरावट के कारण आरसीसी में गिरावट आई (चार्ट V.14बी)।

V.30 वर्ष 2022-23 में उन आरसीसी ने जिसमें अल्पकालिक और दीर्घकालिक संस्थान शामिल हैं अपने परिचालन का और

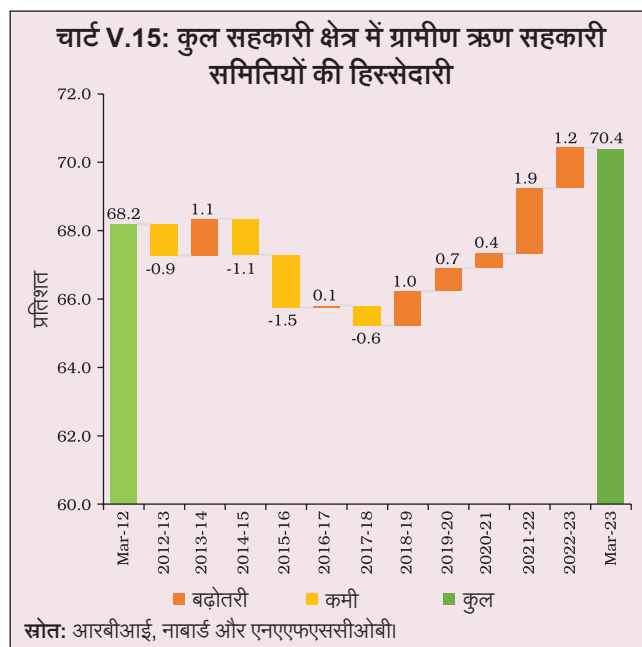
चार्ट V.14 : आरसीसी बनाम यूसीबी : तुलन पत्र और आस्ति गुणवत्ता संकेतक (मार्च के अंत में)



⁹ स्वामित्व वाले फंड में पूंजी और रिजर्व और अधिशेष शामिल हैं।

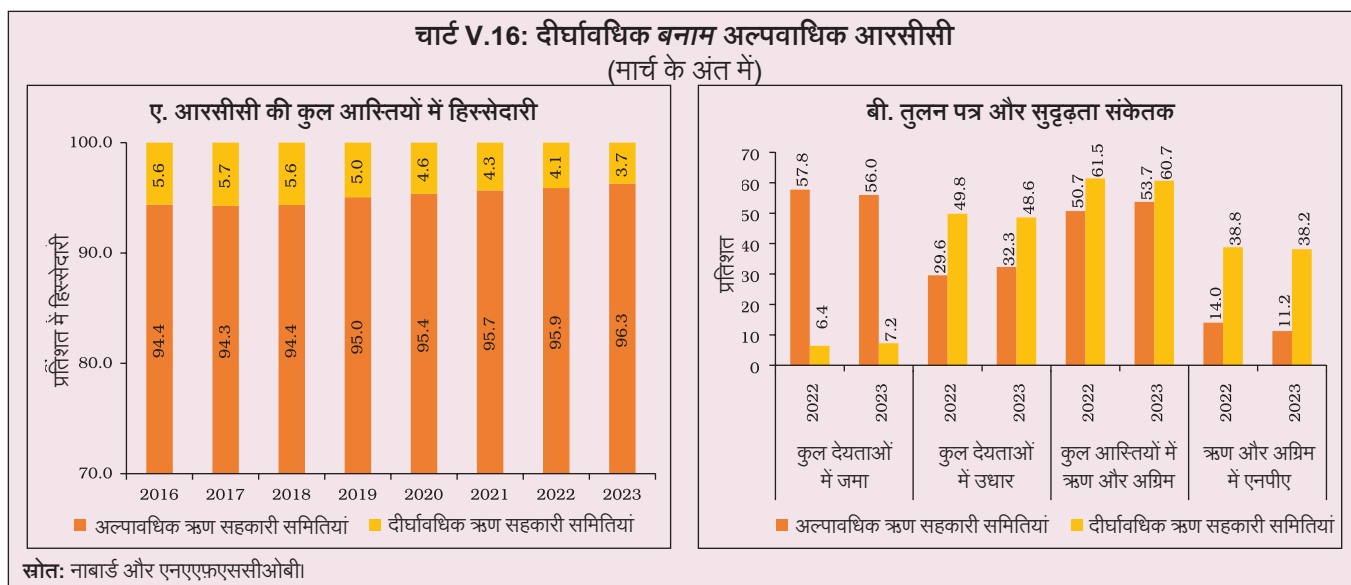
विस्तार किया। सहकारी क्षेत्र (शहरी और ग्रामीण सहकारी समितियों को मिलाकर) की कुल आस्तियों में उनकी हिस्सेदारी एक वर्ष पहले के 69.2 प्रतिशत से बढ़कर 70.4 प्रतिशत हो गई (चार्ट V.15)।

V.31 आरसीसी में, अल्पकालिक संस्थान किसानों और ग्रामीण कारीगरों को फसल ऋण और कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करते हैं। दीर्घकालिक सहकारी समितियां - एससीएआरडीबी और पीसीएआरडीबी - कृषि में निवेश के लिए निधियाँ प्रदान करती हैं, जिसमें भूमि विकास, कृषि मशीनीकरण और लघु सिंचाई, ग्रामीण उद्योग और आवास शामिल हैं। एससीएआरडीबी प्रत्यक्ष ऋण के लिए नाबार्ड जैसी संस्थाओं से तथा पीसीएआरडीबी के माध्यम से ऋण लेते हैं। आरसीसी क्षेत्र में अल्पकालिक संस्थाओं का वर्चस्व है और कुल आस्तियों में उनकी हिस्सेदारी मार्च 2023 के अंत में बढ़कर 96.3 प्रतिशत हो गई, जो मार्च 2016 के अंत में 94.4 प्रतिशत थी (चार्ट V.16ए)। जबकि उधार पर अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों ऋण सहकारी समितियों की निर्भरता यूसीबी की तुलना में अधिक है, दीर्घकालिक ऋण सहकारी समितियों का जमाकर्ता आधार विशेष रूप से छोटा है। अल्पकालिक ग्रामीण सहकारी समितियों का वित्तीय प्रदर्शन उनके दीर्घकालिक समकक्षों की तुलना में अपेक्षाकृत बेहतर रहा है (चार्ट V.16बी)। कृषि,



अनर्जक आस्तियों, कम वसूली और उच्च परिचालन लागत पर केंद्रित गैर-विविध ऋण पोर्टफोलियो के कारण आरसीसी को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

V.32 पीसीएस के कारण नीचे आने के बावजूद, आरसी क्षेत्र लगातार चौथे वर्ष लाभदायक रहा (सारणी V.12)। वर्ष 2022-23 में, आय में तेज वृद्धि (ब्याज और गैर-ब्याज दोनों) और कुल व्यय में कमी के कारण लाभ कमाने वाले पीसीएआरडीबी की संख्या में काफी वृद्धि हुई (चार्ट V.17)।



सारणी V.12: ग्रामीण ऋण सहकारी समितियों की प्रोफाइल
(मार्च 2023 के अंत में)

(राशि ₹ करोड़ में)

1	अल्पवाधक			दीर्घावधिक		ग्रामीण सहकारी बैंक	
	एसटीसीबी	डीसीसीबी	पीएसीएस	एससीएआरडीबी ⁽¹⁾	पीसीएआरडीबी ⁽¹⁾	मार्च-22	मार्च-23
2	3	4	5	6	7	8	
ए. सहकारी संस्थाओं की संख्या	34	351	1,06,955	13	608	1,05,268	1,07,961
बी. तुलन-पत्र संकेतक							
i. स्वामित्व वाली निधि (पूंजी + आरक्षित निधि)	30,318	55,216	48,565	6,545	5,527	1,35,460	1,46,171
ii. जमा राशियां	2,42,327	4,33,358	1,97,239	2,621	1,720	8,33,844	8,77,263
iii. उधार	1,54,970	1,47,207	2,01,329	12,559	16,712	4,55,373	5,32,778
iv. ऋण और अग्रिम	2,65,580	3,70,851	2,00,491	20,770	15,773	7,66,470	8,73,466
v. कुल देयताएं/आस्तियां	4,51,840	6,97,304	4,09,377 [^]	27,794	32,445	14,98,292	16,18,761
सी. वित्तीय प्रदर्शन							
i. लाभ में संस्थान							
ए. संख्या	32	305	47,794	10	351	48,461	48,492
बी. लाभ की राशि	2,517	2,879	2,142	448	525	6,754	8,512
ii. हानि में संस्थान							
ए. संख्या	2	46	37,357	3	252	39,081	37,660
बी. हानि की राशि	60	998	3,586	40	305	5,506	4,989
iii. कुल लाभ (+)/हानि (-)	2,458	1,881	-1,444	408	220	1,248	3,523
डी. अनर्जक आस्तियां							
i. राशि	14,296	35,722	44,042 ^{^^}	7,571	6,371	1,16,718	1,08,002
ii. बकाया ऋणों के प्रतिशत के रूप में	5.4	9.6	23.3	36.5	40.4	15.2	12.4
ई. मांग और ऋण वसूली अनुपात* (प्रतिशत)	91.7	76.5	78.9	42.8	39.1	-	-

टिप्पणियाँ: 1. (पी) - डेटा अनंतिम हैं।

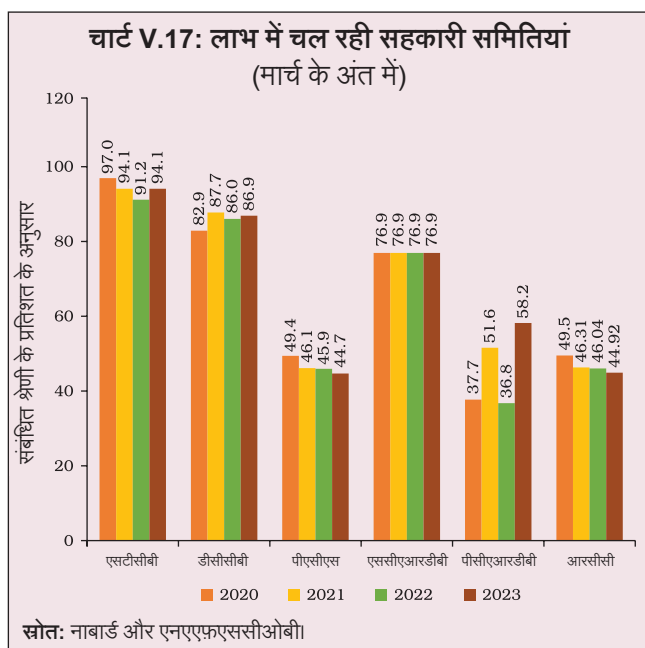
2. *: यह अनुपात जून 2022 के अंत में वसूले गए बकाया एनपीए के हिस्से को दर्शाता है।

3. वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 608 रिपोर्ट किए गए पीसीएआरडीबी में से 603 के संबंध में डेटा उपलब्ध हैं।

4. ^: कार्यशील पूंजी।

5. ^^: कुल अतिदेय।

स्रोत: नाबार्ड और एनएफएससीओबी।



4.1. अल्पकालिक ग्रामीण ऋण सहकारी समितियां

V.33 अल्पकालिक आरसीसी - राज्य स्तर पर एसटीसीबी, जिला स्तर पर डीसीसीबी और ग्राम स्तर पर पीएसीएस - मुख्य रूप से डेयरी किसानों और मत्स्य इकाइयों की फसल ऋण और कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। समय के साथ, गैर-कृषि क्षेत्र की गतिविधि, और संबद्ध क्षेत्रों को मियादी ऋण देने और सूक्ष्मवित्त को शामिल करने की वजह से उनका दायरा बढ़ गया है। अल्पकालिक आरसीसी दो-, तीन- या मिश्रित-स्तरीय संरचना में काम करते हैं।¹⁰ द्वि-स्तरीय संरचना में, एसटीसीबी अपनी शाखाओं के साथ-साथ पीएसीएस के माध्यम से भी उधार देते हैं। त्रि-स्तरीय संरचना में, एसटीसीबी सभी डीसीसीबी के लिए शीर्ष बैंक के रूप में काम करते हैं, जो मध्यवर्ती स्तर का

¹⁰ 20 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) में एक या एक से अधिक डीसीसीबी हैं और 15 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में कोई डीसीसीबी नहीं है और केवल दो-स्तरीय संरचना मौजूद है।

भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति संबंधी रिपोर्ट 2023-24

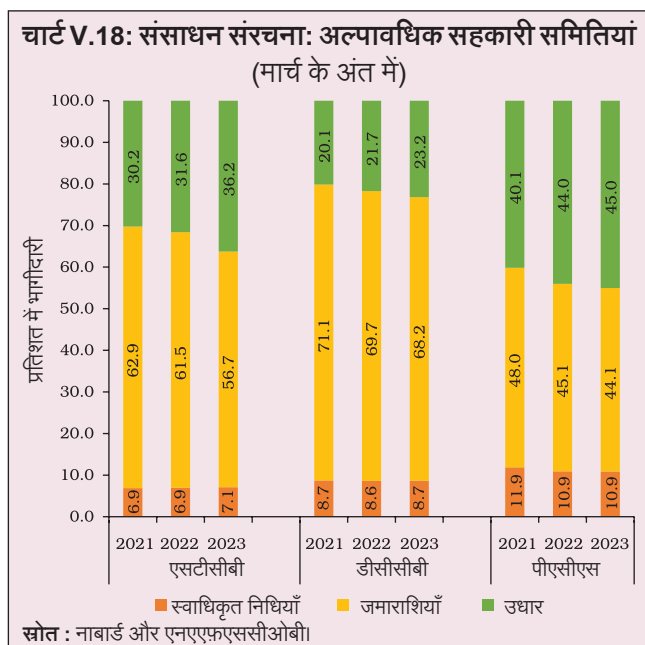
गठन करते हैं और संबद्ध समितियों को ऋण प्रदान करते हैं। मिश्रित संरचना वाले राज्यों में, एसटीसीबी कुछ जिलों में अपनी शाखाओं के माध्यम से और शेष जिलों में डीसीसीबी के माध्यम से काम करते हैं। जमा एसटीसीबी और डीसीसीबी के लिए धन का प्रमुख स्रोत है। दूसरी ओर, पीएसीएस उधार पर बहुत अधिक निर्भर है; पिछले कुछ वर्षों में जमाराशियों के हिस्से में गिरावट आई है (चार्ट V.18)।

4.1.1. राज्य सहकारी बैंक

V.34 ग्रामीण सहकारी संरचना में शीर्ष संस्थान रखने वाले एसटीसीबी, विभिन्न कृषि और गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए ऋण प्रदान करते हैं। वे अन्य दो स्तरों को चलनिधि और तकनीकी सहायता भी प्रदान करते हैं। उनके कुल ऋण पोर्टफोलियो में कृषि ऋण का हिस्सा 45 प्रतिशत से अधिक रहा।

तुलन-पत्र परिचालन

V.35 वर्ष 2023-24 में, एसटीसीबी के तुलन-पत्र लगातार चौथे वर्ष 8 प्रतिशत से अधिक बढ़े, जो आस्ति पक्ष पर ऋण और देयताओं के पक्ष पर उधार और जमा द्वारा संचालित हैं। मार्च 2024 के अंत में, सी-डी अनुपात मार्च 2023 के अंत में 109.6 प्रतिशत (एससीबी के मामले में 75.1 प्रतिशत) से



बढ़कर 114.7 प्रतिशत (एससीबी के मामले में 76.8 प्रतिशत की तुलना में) हो गया। चालू खाता और बचत खाता (सीएएसए) जमा की हिस्सेदारी मार्च 2024 के अंत में घटकर 18.6 प्रतिशत हो गई, जो मार्च 2023 के अंत में 19.5 प्रतिशत थी, जिसके परिणामस्वरूप ब्याज व्यय में वृद्धि हुई। जमा वृद्धि में सुधार हुआ लेकिन उधारों से कम रहा (सारणी V.13)।

V.36 अनुसूचित एसटीसीबी की ऋण वृद्धि वर्ष 2023-24 में कम हो गई, जबकि जमाराशि में पिछले वर्ष में कमी की तुलना में सुधार हुआ (सारणी V.14)।

लाभप्रदता

V.37 वर्ष 2023-24 के दौरान, एसटीसीबी के ब्याज व्यय की वृद्धि ब्याज आय से बढ़कर 24.9 प्रतिशत हो गई; उनकी निवल ब्याज आय (एनआईआई) में 5.7 प्रतिशत की गिरावट

सारणी V.13: राज्य सहकारी बैंकों की देयताएं और आस्तियां

(राशि ₹ करोड़ में)

	मार्च के अंत में		घट-बढ़ प्रतिशत	
	2023	2024 ¹	2022-23	2023-24
1	2	3	4	5
देयताएं				
1. पूंजी	9,774 (2.2)	10,531 (2.2)	5.5	7.7
2. आरक्षित निधि	20,544 (4.5)	22,861 (4.7)	14.3	11.3
3. जमाराशियां	2,42,327 (53.6)	2,56,819 (52.6)	0.6	6.0
4. उधार	1,54,970 (34.3)	1,73,116 (35.5)	25.2	11.7
5. अन्य देयताएं	24,226 (5.4)	24,940 (5.1)	-4.1	2.9
आस्तियां				
1. नकदी और बैंक शेष	21,237 (4.7)	22,661 (4.6)	12.6	6.7
2. निवेश	1,48,666 (32.9)	1,55,826 (31.9)	5.5	4.8
3. ऋण और अग्रिम	2,65,580 (58.8)	2,94,577 (60.3)	11.2	10.9
4. संचित हानि	1,348 (0.3)	1,146 (0.2)	-0.4	-15.0
5. अन्य आस्तियां	15,009 (3.3)	14,057 (2.9)	-12.4	-6.3
कुल देयताएं/आस्तियां	4,51,840 (100.00)	4,88,266 (100.00)	8.3	8.1
टिप्पणियाँ: 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल देयताओं/आस्तियों (प्रतिशत में) के अनुपात में हैं।				
2. वर्ष-दर-वर्ष घट-बढ़ प्रतिशत थोड़ा भिन्न हो सकता है क्योंकि सारणी में संख्या ₹1 करोड़ तक पूर्णांकित की गई है।				
3. पूर्णांकन के कारण घटकों का योग समान नहीं हो सकता है।				
4. पी: अनंतिम।				
स्रोत: नाबार्ड।				

सारणी V.14: अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों के चुनिंदा तुलन पत्र संकेतक
(मार्च के अंत में)

(राशि ₹ करोड़ में)

	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
जमा राशियां	1,87,456 (69.6)	1,97,751 (5.5)	2,11,784 (7.1)	2,04,432 (-3.5)	2,15,540 (5.4)
ऋण	1,94,310 (47.9)	2,06,322 (6.2)	2,28,194 (10.6)	2,55,750 (12.1)	2,78,147 (8.8)
एसएलआर निवेश	54,181 (63.5)	67,788 (25.1)	77,677 (14.6)	74,721 (-3.8)	77,525 (3.8)
क्रेडिट के साथ एसएलआर निवेश	2,48,492 (51.0)	2,74,110 (10.3)	3,05,871 (11.6)	3,30,471 (8.0)	3,55,671 (7.6)

टिप्पणियाँ: 1. डेटा संबंधित वर्ष के मार्च के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार से संबंधित है।

2. कोष्ठक में आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत में वृद्धि दर है।

स्रोत: आरबीआई अधिनियम की धारा 42 के तहत फॉर्म बी।

आई। तथापि, गैर-ब्याज आय में वृद्धि और परिचालन व्यय में कमी के कारण निवल लाभ में 9.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई (सारणी V.15)।

सारणी V.15: राज्य सहकारी बैंकों का वित्तीय प्रदर्शन

(राशि ₹ करोड़ में)

1	2022-23 2023-24 ¹¹		घट-बढ़ प्रतिशत	
	2	3	2022-23	2023-24
ए. आय (i + ii)	27,648	32,401	10.8	17.2
	(100.00)	(100.00)		
i. ब्याज आय	26,654 (96.4)	30,974 (95.6)	10.3	16.2
ii. अन्य आय	994 (3.6)	1,427 (4.4)	26.9	43.6
बी. व्यय (i+ii+iii)	25,191	29,710	11.1	17.9
	(100.00)	(100.00)		
i. व्यय किए हुए ब्याज	19,043 (75.6)	23,793 (80.1)	15.1	24.9
ii. प्रावधान और आकस्मिकताएं	1,920 (7.6)	1,979 (6.7)	-19.2	3.0
iii. परिचालन व्यय	4,227 (16.8)	3,938 (13.3)	12.7	-6.8
जिसमें से, मजदूरी विधेयक	2,060 (8.2)	2,077 (7)	-0.2	0.8
सी. लाभ				
i. निवल ब्याज आय	7,611	7,181	-0.3	-5.7
ii. परिचालन लाभ	3,990	4,205	35.4	5.4
iii. निवल लाभ	2,458	2,691	7.4	9.5

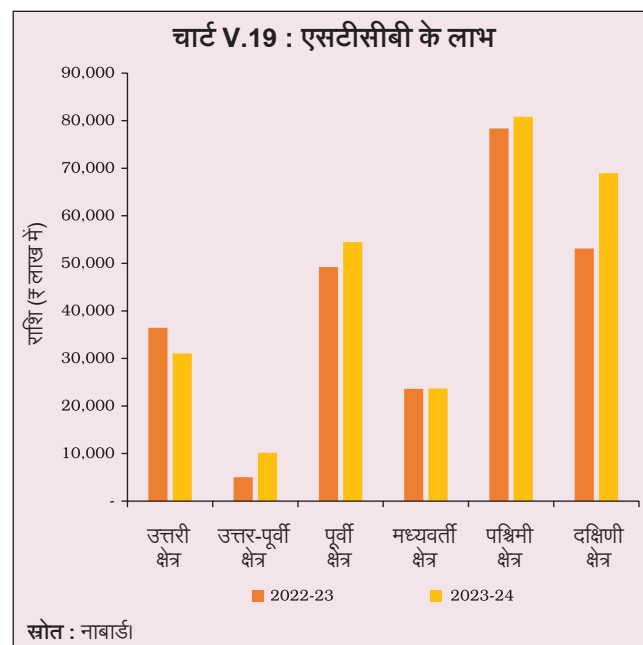
टिप्पणियाँ: 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल आय/व्यय (प्रतिशत में) के अनुपात में हैं।
2. वर्ष-दर-वर्ष घट-बढ़ प्रतिशत थोड़ा भिन्न हो सकता है क्योंकि सारणी में संख्या ₹1 करोड़ तक पूर्णांकित की गई है।
3. पूर्णांकन के कारण घटकों का योग समान नहीं हो सकता है।
4. पी: अंतिम।

स्रोत: नाबार्ड।

V.38 94 प्रतिशत एसटीसीबी (यानी 34 में से 32 एसटीसीबी) ने वर्ष 2023-24 के दौरान लाभ दर्ज किया, जबकि यह वर्ष 2022-23 में 91 प्रतिशत था।¹¹ लाभ में पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्र एसटीसीबी का प्रभुत्व था (चार्ट V.19 और परिशिष्ट सारणी V.3)।

आस्ति गुणवत्ता

V.39 एसटीसीबी की आस्ति गुणवत्ता में लगातार तीसरे वर्ष सुधार हुआ, जीएनपीए अनुपात मार्च 2021 के अंत में



¹¹ अरुणाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में एसटीसीबी ने क्रमशः छठे और चौथे वर्ष घाटे की सूचना दी, और मार्च 2024 के अंत में इन दो एसटीसीबी का संचयी नुकसान ₹35 करोड़ के करीब था।

6.7 प्रतिशत से घटकर मार्च 2024 के अंत में 4.9 प्रतिशत हो गया। हालांकि गिरावट अधिक थी, मजबूत ऋण वृद्धि के कारण जीएनपीए अनुपात में गिरावट आई। संदिग्ध श्रेणी के तहत एनपीए लगातार छह वर्षों तक बढ़ने के बाद कम हो गया। एनपीए के लिए अधिक प्रावधान किए गए और इसलिए निवल एनपीए अनुपात में भी सुधार के कारण प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) में वृद्धि हुई (सारणी V.16)।

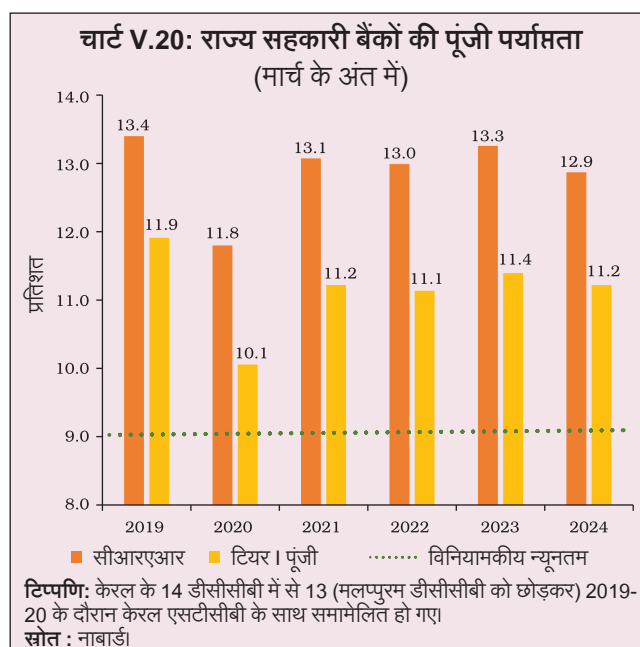
V.40 वर्ष 2023-24 के दौरान, एसटीसीबी के 70 प्रतिशत के जीएनपीए अनुपात में गिरावट आई, जिसमें अधिक प्रभाव पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्र का रहा। पूर्वी क्षेत्र में जीएनपीए अनुपात में मामूली वृद्धि के अलावा जीएनपीए अनुपात में गिरावट आई (परिशिष्ट सारणी V.3)।

पूंजी पर्याप्तता

V.41 मार्च 2024 के अंत में एसटीसीबी के समेकित सीआरएआर में गिरावट आई, क्योंकि पूंजीगत निधियों में वृद्धि जोखिम भारित आस्तियों में वृद्धि से कम रही (चार्ट V.20)। दो एसटीसीबी का सीआरएआर 9 फीसदी की विनियामकीय न्यूनतम आवश्यकता से कम था।

सारणी V.16: राज्य सहकारी बैंकों के सुदृढ़ता संकेतक

	मार्च के अंत में		घट-बढ़ प्रतिशत	
	2023	2024 *	2022-23	2023-24
1	2	3	4	5
ए. कुल एनपीए (i+ii+iii)	14.296	14.537	-0.3	1.7
i. उप-मानक	4.609 (32.2)	4.974 (34.2)	-14.4	7.9
ii. संदिग्ध	8.292 (58)	8.237 (56.7)	10.0	-0.7
iii. हानि	1.395 (9.8)	1.326 (9.1)	-0.7	-4.9
बी. सकल एनपीए अनुपात (%)	5.4	4.9	-	-
सी. निवल एनपीए अनुपात (%)	2.1	2.0	-	-
डी. प्रावधान कवरेज अनुपात (%)	67.2	68.5	-	-
ई. मांग और वसूली अनुपात (%)	91.7	92.4	-	-
टिप्पणियाँ: 1. कोष्ठक में आंकड़े कुल एनपीए (प्रतिशत में) में शेयर हैं। 2. पी : अनंतिम। 3. मांग और वसूली अनुपात में 2022-23 और 2023-24 के लिए क्रमशः जून 2022 और 2023 के अंत में वसूल किए गए बकाया एनपीए के हिस्से को शामिल किया गया है।				
स्रोत: नाबार्ड।				



4.1.2. जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक

V.42 डीसीसीबी सार्वजनिक जमा, एसटीसीबी से उधार और नाबार्ड से पुनर्वित्त के माध्यम से निधियाँ जुटाते हैं। अपने व्यापक शाखा नेटवर्क के कारण, उनके पास सीएएसए जमा तक बेहतर पहुंच है, जो मार्च 2024 के अंत में उनकी कुल जमा राशि का 41.7 प्रतिशत था (एसटीसीबी के लिए 18.6 प्रतिशत की तुलना में)। कुल अग्रिमों का 75 प्रतिशत से अधिक और डीसीसीबी के 96 प्रतिशत कृषि अग्रिम पीएसी/समितियों के लिए है।

तुलन-पत्र परिचालन

V.43 डीसीसीबी की जमा वृद्धि वर्ष 2023-24 में बढ़कर 10.0 प्रतिशत हो गई, जो एसटीसीबी (6.0 प्रतिशत) से अधिक है। अग्रिमों में उच्च वृद्धि के कारण डीसीसीबी का सी-डी अनुपात मार्च 2023 के अंत में 85.6 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2024 के अंत में 86.7 प्रतिशत हो गया (सारणी V.18)।

लाभप्रदता

V.44 डीसीसीबी के एनआईआई में वृद्धि वर्ष 2022-23 के दौरान 14.5 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2023-24 के दौरान 5.4 प्रतिशत हो गई, क्योंकि ब्याज व्यय ब्याज आय की तुलना में

सारणी V.17: जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की देयताएं और आस्तियां

(राशि ₹ करोड़ में)

1	मार्च के अंत में		घट-बढ़ प्रतिशत	
	2023	2024 ⁱⁱ	2022-23	2023-24
1	2	3	4	5
देयताएं				
1. पूंजी	26,486 (3.8)	28,661 (3.7)	8.2	8.2
2. आरक्षित निधि	28,729 (4.1)	31,701 (4.1)	8.5	10.3
3. जमाराशियां	4,33,358 (62.1)	4,76,610 (62.3)	5.0	10.0
4. उधार	1,47,207 (21.1)	1,61,728 (21.1)	14.5	9.9
5. अन्य देयताएं	61,524 (8.8)	66,876 (8.7)	7.0	8.7
आस्तियां				
1. नकदी और बैंक शेष	33,767 (4.8)	38,705 (5.1)	5.2	14.6
2. निवेश	2,47,942 (35.6)	2,65,692 (34.7)	5.1	7.2
3. ऋण और अग्रिम	3,70,851 (53.2)	4,13,161 (54)	10.2	11.4
4. संचित हानि	8,357 (1.2)	9,405 (1.2)	7.8	12.5
5. अन्य आस्तियां	36,388 (5.2)	38,615 (5)	-2.3	6.1
कुल देयताएं/आस्तियां	6,97,304 (100.00)	7,65,577 (100.00)	7.4	9.8
टिप्पणियाँ: 1. कोष्ठक में आंकड़े कुल देयताएं/आस्तियों (प्रतिशत में) के अनुपात में हैं। 2. पी : अनंतिम				
स्रोत: नाबार्डी				

तेजी से बढ़ा (सारणी V.18)। नतीजतन, निवल लाभ वृद्धि पिछले वर्ष के 38.5 प्रतिशत से वर्ष 2023-24 में तेजी से घटकर 0.7 प्रतिशत हो गई, जिसे कम आधार से लाभ हुआ (वर्ष 2021-22 में गिरावट)।

V.45 वर्ष 2023-24 के दौरान, 312 लाभ कमाने वाले डीसीसीबी और 39 घाटे में चलने वाली संस्थाएं थीं। जबकि वर्ष 2023-24 में घाटे में चलने वाले डीसीसीबी की संख्या में गिरावट आई, डीसीसीबी के संचयी हानि में 40.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब और बिहार का घाटे में रहने वाले डीसीसीबी में 64.1 प्रतिशत हिस्सा है। दूसरी ओर, पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों ने डीसीसीबी के कुल लाभ में अधिकतम योगदान दिया (परिशिष्ट सारणी V.4)।

सारणी V.18: जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों का वित्तीय प्रदर्शन

(राशि ₹ करोड़ में)

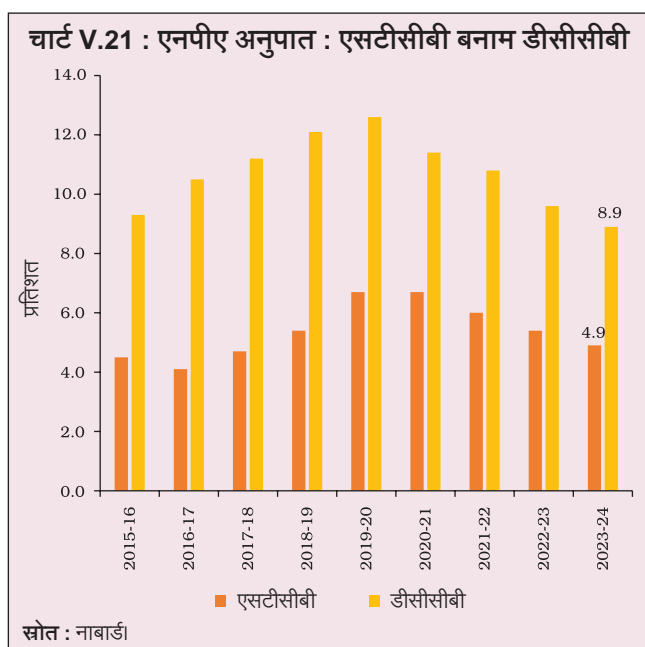
1	2022-23	2023-24 ⁱⁱ	घट-बढ़ प्रतिशत	
			2022-23	2023-24
1	2	3	4	5
ए. आय (i + ii)	46,309 (100.00)	52,408 (100.00)	11.1	13.2
i. ब्याज आय	43,967 (94.9)	49,989 (95.4)	10.8	13.7
ii. अन्य आय	2,342 (5.1)	2,420 (4.6)	17.9	3.3
बी. व्यय (i+ii+iii)	44,428 (100.00)	50,515 (100.00)	10.2	13.7
i. व्यय किए हुए ब्याज	27,600 (62.1)	32,731 (64.8)	8.6	18.6
ii. प्रावधान और आकस्मिकताएं	5,639 (12.7)	5,733 (11.3)	15.3	1.7
iii. परिचालन व्यय	11,189 (25.2)	12,051 (23.9)	11.6	7.7
जिसमें से, मजदूरी विधेयक	6,942 (15.6)	7,430 (14.7)	9.7	7.0
सी. लाभ				
i. निवल ब्याज आय	16,367	17,257	14.5	5.4
ii. परिचालन लाभ	6,933	7,107	17.6	2.5
iii. निवल लाभ	1,881	1,894	38.5	0.7
टिप्पणियाँ: 1. कोष्ठक में आंकड़े कुल देयताएं/आस्तियों (प्रतिशत में) के अनुपात में हैं। 2. पी : अनंतिम				
स्रोत: नाबार्डी				

आस्ति गुणवत्ता

V.46 डीसीसीबी की आस्ति गुणवत्ता में लगातार चौथे वर्ष सुधार हुआ, जिसमें जीएनपीए अनुपात मार्च 2020 के अंत में 12.6 प्रतिशत से घटकर मार्च 2024 के अंत में 8.9 प्रतिशत हो गया। तथापि, डीसीसीबी का जीएनपीए अनुपात एसटीसीबी की तुलना में अधिक रहा (चार्ट V.21 और सारणी V.19)। डीसीसीबी वाले 20 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में से 15 में जीएनपीए अनुपात में गिरावट आई। मध्य और पश्चिमी क्षेत्रों – विशेष रूप से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र – में उच्चतम जीएनपीए अनुपात है, और दक्षिणी क्षेत्र में उच्चतम मांग और वसूली अनुपात है (परिशिष्ट सारणी V.4)।

पूंजी पर्याप्तता

V.47 डीसीसीबी का समेकित सीआरएआर और टियर I पूंजी अनुपात मार्च 2024 के अंत में घटकर चार वर्ष के निचले स्तर



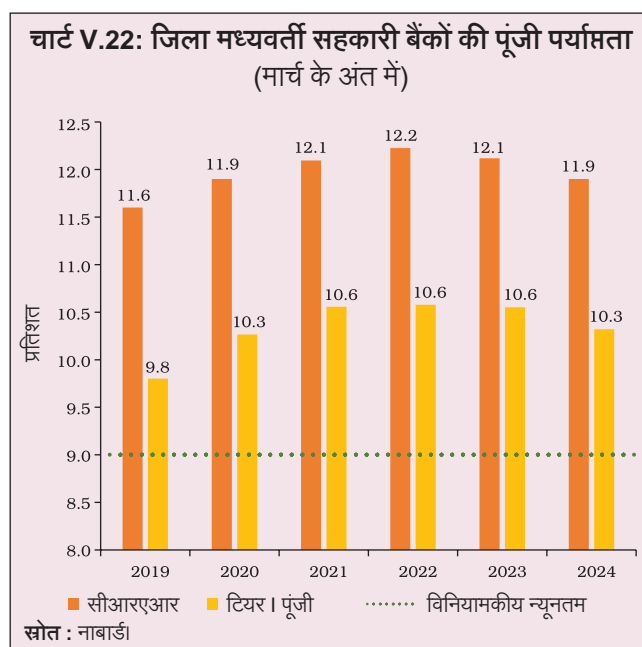
पर आ गया (चार्ट V.22)। हालांकि, 9 प्रतिशत की न्यूनतम विनियामक आवश्यकता से कम सीआरएआर वाले डीसीसीबी की संख्या मार्च 2023 के अंत में 41 से घटकर मार्च 2024 के अंत में 39 हो गई। 9 प्रतिशत से कम सीआरएआर वाले 90 प्रतिशत डीसीसीबी छह राज्यों अर्थात् मध्य प्रदेश, उत्तर

सारणी V.19 : जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के सुदृढ़ता संकेतक

	मार्च अंत		t	
	2023	2024 ^a	2022-23	2023-24
1	2	3	4	5
ए. कुल एनपीए (i+ii+iii)	35,722	36,958	-1.7	3.5
i) उप-मानक	12,541 (35.1)	13,433 (36.3)	-6.5	7.1
ii) संदिग्ध	20,739 (58.1)	20,912 (56.6)	2.2	0.8
iii) हानि	2,442 (6.8)	2,612 (7.1)	-6.8	7.0
बी. सकल एनपीए अनुपात (%)	9.6	8.9	-	-
सी. निवल एनपीए अनुपात (%)	3.9	3.4	-	-
डी. प्रावधान कवरेज अनुपात (%)	78.4	83.9	-	-
ई. मांग और वसूली अनुपात (%)	76.5	76.8	-	-

टिप्पणियाँ: 1. कोष्ठक में आंकड़े कुल एनपीए (प्रतिशत में) में शेयर हैं।
2. मांग और वसूली अनुपात में 2022-23 और 2023-24 के लिए क्रमशः जून 2022 और 2023 के अंत में वसूल किए गए बकाया एनपीए के हिस्से को शामिल किया गया है।
3. पी : अनंतिम

स्रोत : नाबार्ड



प्रदेश, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में केंद्रित थे।

4.1.3. प्राथमिक कृषि ऋण समितियां

V.48 पीएसीएस सदस्य शेयरधारकों के रूप में व्यक्तियों के साथ ग्रामीण सहकारी समिति शृंखला में सबसे निचले स्तर पर हैं। मार्च 2023 के अंत में, पीएसीएस ने 16.03 करोड़ सदस्यों और 4.9 करोड़ उधारकर्ताओं को ऋण प्रदान किया; जिसमें 45.6 प्रतिशत सदस्य और 57.3 प्रतिशत उधारकर्ता छोटे किसान हैं। उधारकर्ता और सदस्य अनुपात – पीएसीएस की ऋण पैठ को मापने के लिए एक मीट्रिक – मार्च 2022 के अंत में तेजी से घटकर 28.6 प्रतिशत होने के बाद मार्च 2023 के अंत में बढ़कर 30.7 प्रतिशत हो गया। अनुपात में सुधार सदस्यों की संख्या में कमी और उधारकर्ताओं की संख्या में वृद्धि दोनों को दर्शाता है (परिशिष्ट सारणी V.5)। पीएसीएस के 80 प्रतिशत से अधिक ऋण अल्प अवधि के थे और कृषि के लिए दिए गए थे। पीएसीएस की कुल संख्या में 29.1 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ पश्चिमी क्षेत्र का इस क्षेत्र में दबदबा है। हालांकि, दक्षिणी क्षेत्र के जमा और ऋण और अग्रिम क्रमशः 79.0 प्रतिशत और 46.2 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ हावी थे।

V.49 नाबार्ड 5 वर्षों की अवधि में देश भर में लगभग 67,930 कार्यात्मक पीएसीएस के कम्प्यूटरीकरण के लिए केंद्र प्रायोजित योजना लागू कर रहा है ताकि उन्हें डिजिटल रूप से सभी ऋण और गैर-ऋण परिचालनों के रिकॉर्ड का पता लगाने में सक्षम बनाया जा सके। योजना का कुल बजट ₹2,516 करोड़ भारत सरकार, राज्य सरकारों और नाबार्ड के बीच साझा किया जाता है। इस परियोजना में साइबर सुरक्षा के साथ क्लाउड-आधारित सामान्य सॉफ्टवेयर का विकास, राष्ट्रीय स्तर के डेटा रिपोजिटरी (एनएलडीआर) को बनाना और अपलोड करना, प्रशिक्षण और अन्य सहायता सेवाएं शामिल हैं। यह पहल डीसीसीबी और एसटीसीबी के कोर बैंकिंग समाधानों के साथ पीएसीएस के निर्बाध एकीकरण का मार्ग प्रशस्त करेगी, जिसके परिणामस्वरूप दक्षता और पारदर्शिता में सुधार होगा।

V.50 वर्ष 2022-23 में पीएसीएस की आस्ति गुणवत्ता और मांग और वसूली अनुपात में काफी सुधार हुआ; तथापि, उच्च जीएनपीए अनुपात चिंता का कारण बना हुआ है (सारणी V.12)। उच्च उधार और कुल रिजर्व में वृद्धि के कारण वर्ष 2022-23 के दौरान पीएसीएस के कुल संसाधनों में वृद्धि हुई। आस्ति पक्ष पर, अल्पकालिक ऋणों में लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि के कारण बकाया ऋणों और अग्रिमों में तेजी से विस्तार हुआ (परिशिष्ट सारणी V.6)।

V.51 वर्ष 2022-23 में, पीएसीएस की कुल संख्या का 44.7 प्रतिशत लाभ कमाने वाला था, जिसका समेकित लाभ 18.3 प्रतिशत बढ़कर 2,142 करोड़ रुपये हो गया। घाटे में चल रहे पीएसीएस का समेकित घाटा 4.3 प्रतिशत घटकर ₹3,585 करोड़ हो गया और पूरे क्षेत्र ने वर्ष 2022-23 में ₹1,443 करोड़ की हानि दर्ज की। क्षेत्रीय स्तर पर, केवल पश्चिमी क्षेत्र ने निवल लाभ दर्ज किया, जबकि दक्षिणी क्षेत्र ने सबसे अधिक हानि दर्ज की (परिशिष्ट सारणी V.7)।

4.2 दीर्घकालिक ग्रामीण ऋण सहकारी समितियां

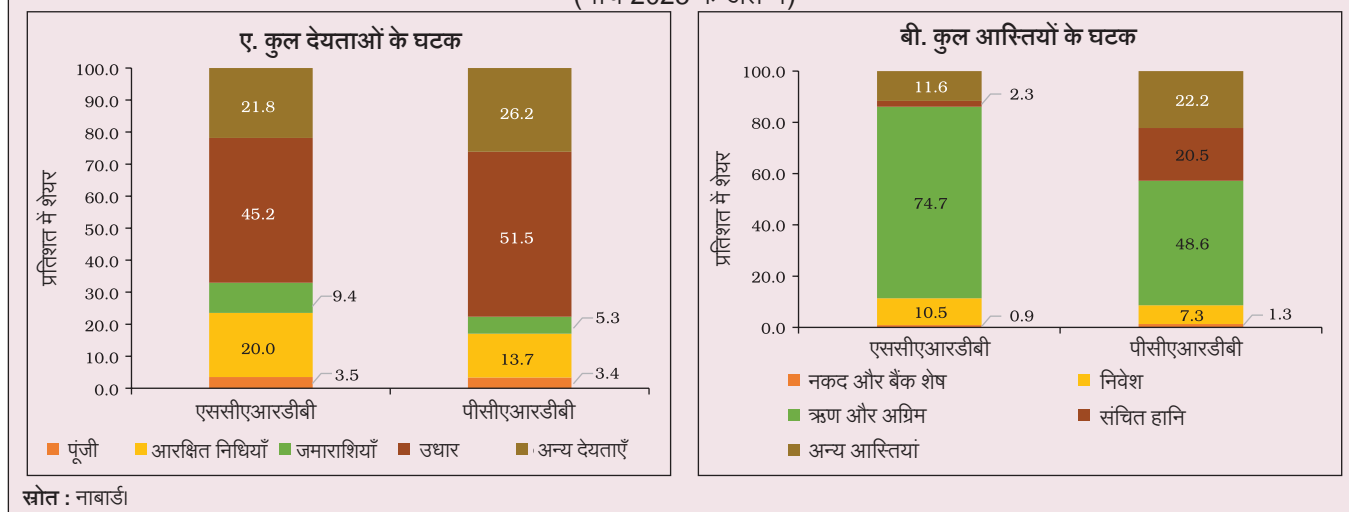
V.52 दीर्घकालिक आरसीसी की स्थापना कृषि विकास के लिए दीर्घावधिक वित्त प्रदान करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ

की गई थी और इसमें राज्य स्तर पर एससीएआरडीबी और जिला/तालुका स्तर पर पीसीएआरडीबी शामिल थे। वर्तमान में, वे पांच राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों (गुजरात, जम्मू और कश्मीर, पुडुचेरी, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश) में एकात्मक संरचना में काम करते हैं, जहां एससीएआरडीबी राज्य के विभिन्न हिस्सों में स्थित अपनी शाखाओं के माध्यम से परिचालन करते हैं और ग्राहक बैंक की प्रत्यक्ष सदस्यता के आधार पर बैंक से जुड़े होते हैं। छह राज्यों, अर्थात्, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, पंजाब, राजस्थान और तमिलनाडु में एक संघीय संरचना है, अर्थात्, एससीएआरडीबी जिला/तालुका स्तर पर संचालित सभी संबद्ध पीसीएआरडीबी की एक शीर्ष इकाई के रूप में काम करते हैं, जो बदले में, सदस्यों को नामांकित करते हैं और उन्हें ऋण प्रदान करते हैं। दो राज्यों (हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल) में एक मिश्रित संरचना है जहां एससीएआरडीबी पीसीएआरडीबी के साथ-साथ अपनी शाखाओं के माध्यम से भी काम करते हैं।

V.53 मार्च 2023 के अंत में, 1.08 करोड़ सदस्यों की कुल सदस्यता के साथ 13 एससीएआरडीबी और 608 पीसीएआरडीबी थे, जिनमें से 36 प्रतिशत उधार लेने वाले सदस्य थे। एससीएआरडीबी और पीसीएआरडीबी का व्यवसाय मॉडल उधार पर निर्भर करता है, जहां एससीएआरडीबी मुख्य रूप से नाबार्ड से उधार लेते हैं, जबकि पीसीएआरडीबी एससीएआरडीबी से वित्तीय सहायता प्राप्त करते हैं (चार्ट V.23ए)। एससीएआरडीबी के पास कम संचित हानि और कुल आस्तियों में ऋण और अग्रिम का उच्च हिस्सा है (चार्ट V.23बी)।

V.54 जनवरी 2024 में, सहकारिता मंत्रालय ने 11 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में दीर्घकालिक आरसीसी की 1,851 इकाइयों के कम्प्यूटरीकरण के लिए परियोजना शुरू की। इस परियोजना का उद्देश्य आरसीसी के कार्यकरण में परिचालन दक्षता, जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए उद्यम संसाधन योजना (ईआरपी) आधारित सामान्य सॉफ्टवेयर के साथ कम्प्यूटर हार्डवेयर उपलब्ध कराना है।

चार्ट V.23: दीर्घावधिक ग्रामीण सहकारी समितियों की देयताएं और आस्तियां: एक तुलना
(मार्च 2023 के अंत में)



4.2.1. राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

V.55 मार्च 2023 के अंत में, एससीएआरडीबी 13 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में परिचालन कर रहे थे, जिसकी 46.7 प्रतिशत शाखाएँ उत्तर प्रदेश में थीं। उधार एससीएआरडीबी की कुल देयताओं का 45.2 प्रतिशत था; इनमें से 80 प्रतिशत से अधिक उधार नाबार्ड से था, क्योंकि उनका जमा आधार सीमित था। दो वर्षों के विस्तार के बाद, ऋण और अग्रिमों में गिरावट के कारण वर्ष 2022-23 में एससीएआरडीबी के समेकित तुलन-पत्र में कमी आई। देयताओं के पक्ष में, जमा वृद्धि में मंदी के साथ-साथ एससीएआरडीबी के उधार में कमी आई (परिशिष्ट सारणी V.8)।

V.56 अपने तुलन-पत्र में कमी के बावजूद, वर्ष 2022-23 में एससीएआरडीबी के एनआईआई में 25.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई, क्योंकि ब्याज आय ब्याज व्यय से अधिक विस्तारित हुई। एनआईआई के साथ-साथ गैर-ब्याज आय में वृद्धि ने हालांकि कम आधार पर निवल लाभ में तेज वृद्धि में योगदान दिया (परिशिष्ट सारणी V.9)।

V.57 वर्ष 2023-24 में जीएनपीए अनुपात में वृद्धि हुई, और वसूली अनुपात में भी सुधार हुआ (परिशिष्ट सारणी V.10)। दक्षिणी क्षेत्र में सबसे कम जीएनपीए अनुपात और उच्चतम वसूली अनुपात था (परिशिष्ट सारणी V.11)।

4.2.2. प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

V.58 मार्च 2023 के अंत में, 8 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 608 पीसीएआरडीबी थे। वर्ष के दौरान आस्ति पक्ष पर ऋणों और अग्रिमों में कमी और देयताओं के पक्ष पर उधार में कमी के कारण पीसीएआरडीबी के समेकित तुलन पत्र में कमी देखी गई (परिशिष्ट सारणी V.12)।

V.59 वर्ष 2022-23 के दौरान, पीसीएआरडीबी की आय में 18.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि उनके व्यय में कमी आई, जिससे निवल लाभ हुआ। आय में वृद्धि ब्याज और गैर-ब्याज आय दोनों के द्वारा थी, जबकि परिचालन व्यय, विशेष रूप से मजदूरी बिल में गिरावट के कारण कुल व्यय में गिरावट आई (परिशिष्ट सारणी V.13)। पीसीएआरडीबी वाले आठ राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में से पांच ने समेकित निवल हानि दर्ज की।

V.60 अवमानक और संदिग्ध श्रेणियों में कमी के कारण वर्ष 2022-23 के दौरान पीसीएआरडीबी के जीएनपीए अनुपात में मामूली गिरावट आई। हालांकि, जीएनपीए अनुपात 40 प्रतिशत से अधिक बना रहा, क्योंकि हानि श्रेणी के ऋणों में और विस्तार हुआ (परिशिष्ट सारणी V.14)। अन्य क्षेत्रों में प्रवृत्ति के विपरीत, उत्तरी क्षेत्र के जीएनपीए अनुपात में वृद्धि हुई। इस क्षेत्र में वर्ष 2022-23 के दौरान उच्चतम जीएनपीए अनुपात और सबसे कम मांग और वसूली अनुपात बना रहा। दूसरी ओर, दक्षिणी क्षेत्र

में सबसे कम जीएनपीए अनुपात और उच्चतम मांग और वसूली अनुपात था (परिशिष्ट सारणी V.15)।

5. समग्र मूल्यांकन

V.61 वर्ष 2023-24 के दौरान, यूसीबी ने पूंजी बफर, लाभप्रदता और आस्ति गुणवत्ता में सुधार प्रदर्शित किया। हालांकि, वाणिज्यिक बैंकों के सापेक्ष उनकी ऋण और जमा वृद्धि धीमी रही। जोखिम प्रबंधन, आंतरिक लेखा परीक्षा और अनुपालन कार्य जैसे आश्वासन कार्य कुशल जोखिम प्रबंधन के लिए प्रभावी द्वारपाल हैं। इस उद्देश्य से, रिजर्व बैंक ने यूसीबी में सुदृढ़ अभिशासन प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए कई पहलों की हैं, जिसमें चार-स्तरीय विनियामक ढांचे की शुरुआत, पर्यवेक्षी

अपेक्षाओं को बताने के लिए सम्मेलनों के माध्यम से यूसीबी के बोर्ड के निदेशकों और यूसीबी के बीमा कार्यों के प्रमुखों के साथ सीधे जुड़ना। यूसीबी में आईटी और साइबर सुरक्षा जोखिम को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण कदम भी उठाए गए हैं।

V.62 ग्रामीण ऋण सहकारी समितियों में, एसटीसीबी ने लगातार दूसरों से बेहतर प्रदर्शन किया है और वर्ष 2023-24 में उच्च लाभ के साथ-साथ अपनी आस्ति गुणवत्ता में भी सुधार किया है। आगे देखें तो, सहकारी क्षेत्र को साइबर खतरों और आर्थिक अनिश्चितताओं के बारे में सतर्क रहना चाहिए और तेजी से बदलती दुनिया में प्रासंगिक बने रहने के लिए तकनीकी प्रगति के अनुसार होना चाहिए।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) ने 2023-24 में ऋण का मजबूती से विस्तार किया। ऋण गुणवत्ता में सुधार हुआ और बेहतर लाभप्रदता तथा मजबूत पूंजी बफर के साथ तुलन-पत्र में मजबूती आई। एक प्रमुख एचएफसी का एक बैंक के साथ विलय के बाद संरचनात्मक परिवर्तनों के बीच हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (एचएफसी) का ऋण भी दोहरे अंकों में बढ़ गया। उच्च लाभप्रदता के साथ-साथ अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं (एआईएफआई) द्वारा संवितरण में भी लगातार वृद्धि हुई।

1. परिचय

VI.1 गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान (एनबीएफआई) भारत की वित्तीय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण घटक हैं। रिजर्व बैंक¹ द्वारा विनियमित संस्थाओं में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी), आवास वित्त कंपनियां (एचएफसी)², अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं (एआईएफआई), और स्टैंडअलोन प्राथमिक डीलर (एसपीडी) शामिल हैं [चार्ट VI.1]।

VI.2 एनबीएफसी सरकारी और निजी दोनों स्तर पर पंजीकृत कंपनियां हैं, जो क्रेडिट मध्यस्थता का काम करती हैं और बैंक रहित और कम बैंक सेवाओं वाले क्षेत्रों के सभी लोगों को ऋण वितरण की सुविधा प्रदान करती हैं। वे उधार देने की जगह के डिजिटल परिवर्तन में भी सबसे आगे हैं और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाते हुए ग्राहकों को उनकी आवश्यकता के अनुसार ऋण प्रदान करते हैं। एचएफसी व्यक्तियों, सहकारी समितियों और कॉरपोरेट्स को आवास ऋण प्रदान करते हैं। पांच एआईएफआई, अर्थात् राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्विम बैंक),

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी), राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) और राष्ट्रीय अवसंरचना और विकास वित्तपोषण बैंक (एनएबीएफआईडी)³ शीर्ष वित्तीय संस्थान हैं जो कृषि, विदेश व्यापार, छोटे व्यवसाय और बुनियादी ढांचे जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को दीर्घकालिक वित्त पोषण प्रदान करते हैं। प्राथमिक व्यापारी (पीडी) सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) के निर्गम की हामीदारी करते हैं और सरकारी प्रतिभूति बाजार में बाजार निर्माताओं के रूप में कार्य करते हैं।

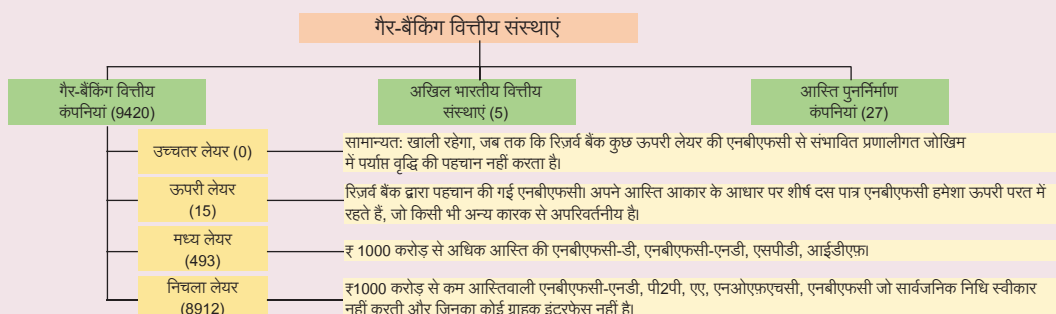
VI.3 इस अध्याय में 2023-24 और 2024-25 की पहली छमाही में एनबीएफआई के प्रदर्शन को शामिल किया गया है। खंड 2 एनबीएफसी क्षेत्र का आकलन प्रदान करता है, जिसमें ऊपरी लेयर (एनबीएफसी-यूएल) और मध्य लेयर (एनबीएफसी-एमएल) के एनबीएफसी पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। खंड 3 में एचएफसी के प्रदर्शन पर चर्चा की गई है। खंड 4 और 5 क्रमशः एआईएफआई और पीडी के प्रदर्शन का मूल्यांकन करते हैं। खंड 6 में निष्कर्षात्मक टिप्पणियां शामिल हैं।

¹ यद्यपि मॉनेट बैंकिंग कंपनियां, स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक ब्रोकिंग/सब-ब्रोकिंग व्यवसाय में संलग्न कंपनियां, निधि कंपनियां, वैकल्पिक निवेश फंड कंपनियां, बीमा कंपनियां और चिट फंड कंपनियां एनबीएफसी हैं, लेकिन उन्हें आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के तहत रिजर्व बैंक के साथ पंजीकरण की आवश्यकता से छूट दी गई है।

² वित्त (सं.2) अधिनियम, 2019 (2019 का 23) ने राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 में संशोधन किया, जिससे भारतीय रिजर्व बैंक को आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) के विनियमन के लिए कुछ शक्तियां प्रदान की गईं। एचएफसी को अब विनियामक उद्देश्यों के लिए एनबीएफसी की श्रेणी में माना जाता है।

³ एनबीएफआईडी को एक विकास वित्तीय संस्थान (डीएफआई) के रूप में स्थापित किया गया है और इसे आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45एल और 45एन के तहत रिजर्व बैंक द्वारा एआईएफआई के रूप में विनियमित और पर्यवेक्षित किया जाएगा।

चार्ट VI.1 रिज़र्व बैंक के विनियमन के तहत एनबीएफआई का ढांचा (31 मार्च 2024 के अनुसार)



टिप्पणियां : 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संस्थाओं की संख्या (अनंतिम) दर्शाते हैं।
2. एनबीएफसी, अर्थात्, एनबीएफसी-आईसीसी, एनबीएफसी-एमएफआई, एनबीएफसी फेक्टर, और एनबीएफसी-एमजीसी एसबीआर के मापदंडों के आधार पर किसी भी परत में आ सकती है। एनबीएफसी-सीआईसी, एचएफसी और आईएफसी ऊपरी या मध्य परत में हो सकते हैं।
3. सरकारी स्वामित्व वाली एनबीएफसी को आधार या मध्य परत में रखा गया है।

स्रोत : आरबीआई और एनएचबी

2. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी)

VI.4 रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित एनबीएफसी विविध व्यावसायिक रणनीतियों के साथ कार्य करने वाली विजातीय वित्तीय संस्थाओं का एक समूह है। रिज़र्व बैंक का स्केल-आधारित विनियमन (एसबीआर) ढांचा एनबीएफसी को उनके आकार, गतिविधि और कथित जोखिम के आधार पर शीर्ष, ऊपरी, मध्य और आधार लेयर्स में वर्गीकृत करता है। एसबीआर ढांचा इस मायने में प्रगतिशील है कि यह आनुपातिकता के सिद्धांत पर बनाया गया है, जिसमें विनियमन एनबीएफसी के आकार और परस्पर संबद्धता के अनुरूप हैं (चार्ट VI.1 और सारणी VI.1)। छोटे और/या कम जटिल एनबीएफसी अपेक्षाकृत कम विनियमित होते हैं, जबकि बड़े और अधिक व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण एनबीएफसी बड़ी हुई विनियामक जांच के अधीन रहती हैं।

VI.5 इन संस्थाओं की स्वाभाविक रूप से विविध और गतिशील प्रकृति को देखते हुए, रिज़र्व बैंक द्वारा जून 2024 में एनबीएफसी क्षेत्र के लिए स्व-नियामक संगठनों⁴ (एसआरओ) को मान्यता देने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे।

यह स्व-विनियमन के लिए सिद्धांत स्थापित करता है, जो मौजूदा विनियामक/सांविधिक ढांचे का पूरक है और उन्नत व्यावसायिकता, अनुपालन, नवाचार और नैतिक आचरण को प्रोत्साहित करता है।

VI.6 आस्ति के मामले में एनबीएफसी-यूएल और एमएल एनबीएफसी क्षेत्र में अग्रणी हैं। संख्या के आधार पर, आधार लेयर के एनबीएफसी (एनबीएफसी-बीएल) कुल का 96.2 प्रतिशत है, जबकि कुल आस्तियों में उनका केवल छह प्रतिशत हिस्सा है (सारणी VI.2)।

VI.7 2023-24 के दौरान एनबीएफसी⁵ द्वारा दिया गया ऋण सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 13.6 प्रतिशत था। मार्च 2024 के अंत में, यह अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के बकाया ऋण का 24.5 प्रतिशत था (चार्ट VI.2)।

VI.8 2023-24 में एनबीएफसी के पंजीकरण और पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) के रद्दीकरण की संख्या में गिरावट आई (चार्ट VI.3)। एनबीएफसी द्वारा सीओआर को छोड़ने और उनके बाद के रद्दीकरण से एनबीएफसी व्यवसाय से बाहर

⁴ रिज़र्व बैंक की विनियमित संस्थाओं के लिए एसआरओ को मान्यता देने हेतु एक सर्वव्यापी ढांचा मार्च 2024 में जारी किया गया था।

⁵ सभी खंडों में अनुवर्ती विश्लेषण सीआईसी, एचएफसी और एसपीडी को छोड़कर ऊपरी और मध्य लेयर की एनबीएफसी पर केंद्रित है (बाद के दो को अलग-अलग खंडों में शामिल किया गया है)।

सारणी VI.1 : स्केल आधारित विनियामक ढांचे के तहत गतिविधि के अनुसार एनबीएफसी का वर्गीकरण

वर्गीकरण	गतिविधि	लेयर
1	2	3
1. निवेश और क्रेडिट कंपनी (एनबीएफसी-आईसीसी)	उधार जो उत्पादक/आर्थिक गतिविधियों और निवेश के लिए प्रतिभूतियों के अधिग्रहण में सहायक है।	एसबीआर के मापदंडों के आधार पर कोई भी लेयर।
2. एनबीएफसी-इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (एनबीएफसी-आईडीएफ)	अवसंरचना ऋण।	मध्य लेयर या ऊपरी लेयर, जैसा भी मामला हो।
3. कोर निवेश कंपनी (सीआईसी)	इक्विटी शेयरों, अधिमान शेयरों, ऋण, या समूह कंपनियों के ऋणों में निवेश।	मध्य लेयर या ऊपरी लेयर, जैसा भी मामला हो।
4. एनबीएफसी-इंफ्रास्ट्रक्चर कर्ज निधि (एनबीएफसी-आईडीएफ)	कम से कम एक वर्ष के संतोषजनक प्रदर्शन को पूरा करने वाली केवल अवसंरचना परियोजनाओं में सार्वजनिक निजी भागीदारी और पोस्ट कमेंसमेंट ऑपरेशंस में लंबी अवधि के ऋण के प्रवाह की सुविधा।	मध्यम लेयर
5. एनबीएफसी-माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन (एनबीएफसी-एमएफआई)	आर्थिक रूप से वंचित समूहों को संपार्श्विक मुक्त छोटे टिकट के ऋण प्रदान करना।	एसबीआर के मापदंडों के आधार पर कोई भी लेयर।
6. एनबीएफसी-फैक्टर्स	एक समनुदेशक की प्राप्य राशियों का अधिग्रहण या प्राप्य राशियों के प्रतिभूति ब्याज के प्रति छूट पर ऋण देना।	स्केल आधारित विनियामक ढांचे के मापदंडों के आधार पर कोई भी लेयर।
7. एनबीएफसी-परिचालनेतर वित्तीय नियंत्रक कंपनी (एनबीएफसी-एनओएफएचसी)	नए बैंकों की स्थापना में प्रवर्तकों/प्रवर्तक समूहों को सुविधा।	आधार लेयर
8. बंधक गारंटी कंपनी (एमजीसी)	बंधक गारंटी व्यवसाय का संचालन	एसबीआर के मापदंडों के आधार पर कोई भी लेयर।
9. एन एनबीएफसी-अकाउंट एग्रीगेटर (एनबीएफसी-एए)	ग्राहक की वित्तीय आस्तियों के बारे में जानकारी एकत्र करना और ग्राहक द्वारा निर्दिष्ट ग्राहक या अन्य को समेकित, संगठित और पुनर्प्राप्ति योग्य तरीके से प्रदान करना।	आधार लेयर
10. एनबीएफसी-पीयर टु पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म (एनबीएफसी-पी2पी)	धन जुटाने में मदद करने के लिए उधारदाताओं और उधारकर्ताओं को एक साथ लाने के लिए एक ऑनलाइन मंच प्रदान करना।	आधार लेयर
11. हाउसिंग फाइनेंस कंपनी (एचएफसी)	आवासीय इकाइयों की खरीद/ निर्माण/पुनर्निर्माण/नवीनीकरण/ मरम्मत के लिए वित्तपोषण।	मध्य लेयर या ऊपरी लेयर, जैसा भी मामला हो।
12. स्टैंडअलोन प्राथमिक डीलर (एसपीडी)	सरकार द्वारा दिनांकित प्रतिभूतियों के जारी करने और प्राथमिक नीलामी में भाग लेने के लिए हमीदारी करता करता है।	मध्य लेयर

स्रोत : आरबीआई

निकलने या समामेलन, विलय, विघटन और स्वैच्छिक स्ट्राइक -ऑफ के बाद कानूनी इकाई नहीं रहने जैसे कारण थे। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-ए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रिज़र्व बैंक ने सीओआर

के अभ्यर्पण, डेटा गोपनीयता और ग्राहक सूचना की सुरक्षा, वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में आचार संहिता और उचित आचार संहिता (एफपीसी) सहित संबंधित दिशानिर्देशों के उल्लंघन के कारण 143 एनबीएफसी के सीओआर को रद्द कर दिया।

सारणी VI.2 : एनबीएफसी की संरचना

(मार्च 2024 के अंत में)

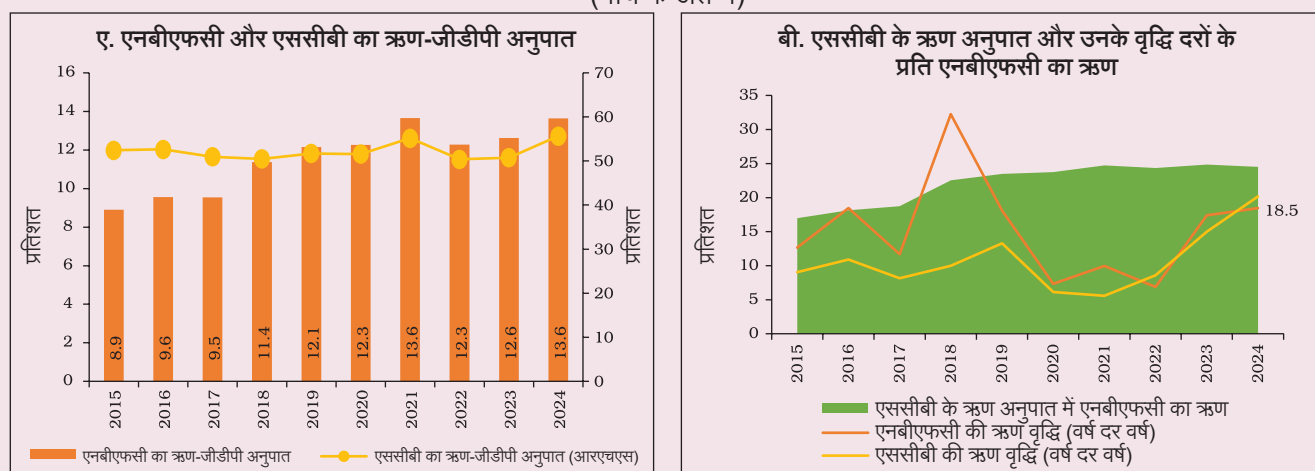
(हिस्सेदारी, प्रतिशत में)

लेयर	संख्या	आस्ति
1	2	3
एनबीएफसी - यूएल	0.1	25.2
एनबीएफसी - एमएल	3.7	68.8
एनबीएफसी - बीएल	96.2	6.0
कुल	100.0	100.0
टिप्पणी: एचएफसी, सीआईसी और एसपीडी को छोड़कर डाटा		
स्रोत : आरबीआई		

2.1. स्वामित्व का स्वरूप

VI.9 एनबीएफसी क्षेत्र में गैर-सरकारी कंपनियों का वर्चस्व है, जिसकी हिस्सेदारी मार्च 2024 के अंत में 93.1 प्रतिशत है। सरकारी कंपनियों की संख्या बहुत कम होने के बावजूद, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी क्षेत्र की कुल आस्तियों में उनका पर्याप्त हिस्सा था (सारणी VI.3)। बड़े आकार और ज्यादा निधीयन बुनियादी ढाँचे के क्षेत्र में केन्द्रित रहने के कारण 1 अक्टूबर,

चार्ट VI.2 : एससीबी के क्रेडिट और जीडीपी की तुलना में एनबीएफसी के ऋण
(मार्च के अंत में)



स्रोत: भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति पर रिपोर्ट, विभिन्न अंक; भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी की पुस्तिका, विभिन्न अंक।

2024 से सरकारी कंपनियों (बेस लेयर को छोड़कर) के लिये त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) ढाँचा शुरू किया गया।

VI.10 नौ एनबीएफसी-यूएल में से तीन जमाराशि स्वीकार करने वाली हैं जबकि बाकी जमाराशि स्वीकार नहीं करनेवाली हैं। एनबीएफसी-यूएल के रूप में पहचान के बाद, एनबीएफसी को तीन वर्षों के भीतर सूचीबद्ध होना चाहिए।

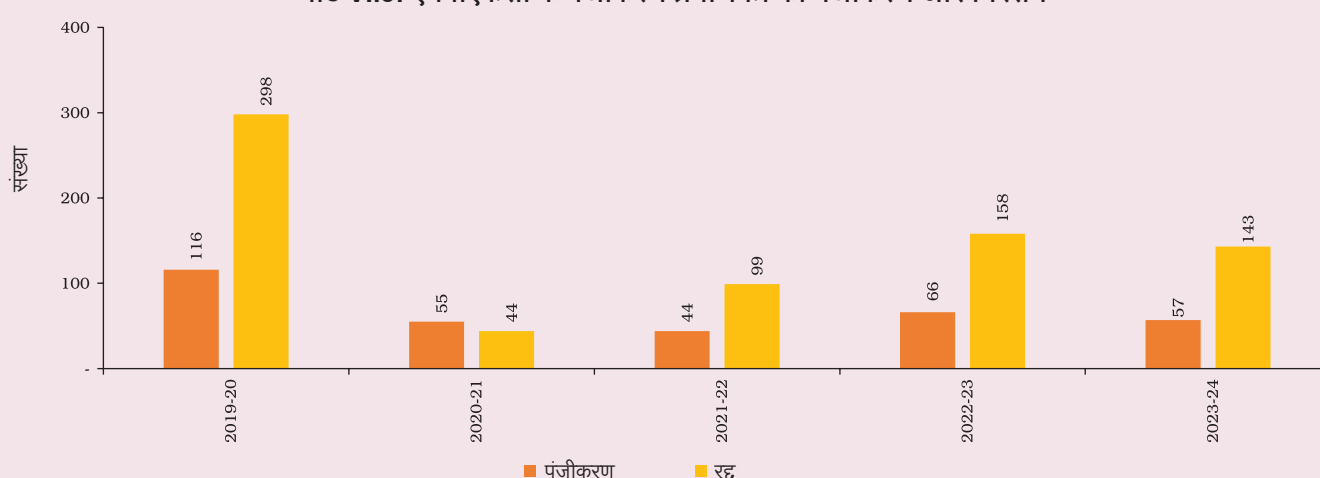
VI.11 आस्ति के मामले में, एनबीएफसी-एमएल एनबीएफसी क्षेत्र में अग्रणी है, जिसकी कुल आस्ति में 73.2 प्रतिशत की

हिस्सेदारी है। एनबीएफसी-यूएल के विपरीत, इनमें से ज्यादातर कंपनियां प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं (सारणी VI.3)।

2.2 तुलन-पत्र

VI.12 2023-24 के दौरान, एनबीएफसी क्षेत्र का तुलन-पत्र दोहरे अंक (पिछले वर्ष में 17.2 प्रतिशत की तुलना में 16.3 प्रतिशत) में पहुँच गया। देयता पक्ष पर, बैंकों से एनबीएफसी की उधारी कम हो गई, जबकि डिबेंचर के माध्यम से जुटाई गई निधि में तेजी आई, जो, अन्य बातों के साथ-साथ, नवंबर

चार्ट VI.3: एनबीएफसी के पंजीकरण प्रमाणपत्र का पंजीकरण और निरसन



टिप्पणी: आंकड़े अनंतिम हैं।

स्रोत: पर्यवेक्षी विवरणी, भारतीय रिज़र्व बैंक।

सारणी VI.3: एनबीएफसी का स्वामित्व स्वरूप
(मार्च 2024 के अंत में)

(राशि ₹ करोड़ में)

प्रकार	एनबीएफसी क्षेत्र			एनबीएफसी – यूएल			एनबीएफसी – एमएल		
	संख्या	आस्ति आकार	आस्ति शेयर प्रतिशत में	संख्या	आस्ति आकार	आस्ति शेयर प्रतिशत में	संख्या	आस्ति आकार	आस्ति शेयर प्रतिशत में
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ए. सरकारी कंपनियां	23	19,01,090	37.5	-	-	-	23	19,01,090	51.3
बी. गैर-सरकारी कंपनियां (1 + 2)	308	31,67,517	62.5	9	13,59,521	100.0	299	18,07,995	48.7
1. पब्लिक लिमिटेड कंपनियां	45	14,76,379	29.1	6	10,23,139	75.3	39	4,53,240	12.2
2. प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां	263	16,91,138	33.4	3	3,36,382	24.7	260	13,54,755	36.5
सी. कुल (ए + बी)	331	50,68,607	100.0	9	13,59,521	100.0	322	37,09,086	100.0
टिप्पणी : आंकड़े अनंतिम हैं।									
स्रोत : पर्यवेक्षी विवरणियां, भारतीय रिज़र्व बैंक।									

2023 से प्रभावी एनबीएफसी को बैंकों के उधार पर जोखिम भार में वृद्धि के प्रभाव को दर्शाता है। आस्ति पक्ष पर, ऋण और अग्रिमों में वृद्धि 2023-24 में बढ़कर 18.5 प्रतिशत हो गई, जो 2022-23 में 17.4 प्रतिशत थी, जो ऊपरी लेयर एनबीएफसी

द्वारा संचालित थी (सारणी VI.4)। गैर-जमानती ऋणों में संकुचन के कारण एनबीएफसी-एमएल की ऋण वृद्धि अपेक्षाकृत मंद थी (चार्ट VI.4)। सितंबर 2024 के अंत में गैर-जमानती ऋण संकुचित होने के बावजूद सकल ऋण का

सारणी VI.4: एनबीएफसी का संक्षिप्त तुलन-पत्र

(राशि ₹ करोड़ में)

मर्दे	मार्च 2023 के अंत में			मार्च 2024 के अंत में			सितंबर 2024 के अंत में		
	एनबीएफसी	एनबीएफसी-यूएल	एनबीएफसी-एमएल	एनबीएफसी	एनबीएफसी-यूएल	एनबीएफसी-एमएल	एनबीएफसी	एनबीएफसी-यूएल	एनबीएफसी-एमएल
1	2 (3+4)	3	4	5 (6+7)	6	7	8 (9+10)	9	10
1. शेयर पूंजी और आरक्षित निधियां	9,62,763 (21.3)	1,99,283 (26.3)	7,63,480 (20.1)	11,54,950 (20.0)	2,54,221 (27.6)	9,00,729 (18.0)	12,41,007 (22.0)	2,52,505 (17.9)	9,88,502 (23.2)
2. पब्लिक जमाराशि	85,254 (20.8)	64,797 (36.1)	20,457 (-10.9)	1,02,994 (20.8)	83,102 (28.2)	19,893 (-2.8)	1,12,512 (16.9)	92,707 (22.6)	19,805 (-3.9)
3. डिबेंचर	11,05,943 (9.8)	2,25,415 (14.1)	8,80,528 (8.8)	12,28,997 (11.1)	2,71,444 (20.4)	9,57,553 (8.7)	13,28,203 (16.2)	2,76,674 (15.0)	10,51,529 (16.5)
4. बैंक उधार	11,23,748 (23.6)	3,25,197 (27.6)	7,98,551 (22.0)	13,31,619 (18.5)	4,13,073 (27.0)	9,18,545 (15.0)	13,94,324 (16.3)	4,12,473 (14.6)	9,81,851 (17.0)
5. वाणिज्यिक पत्र	83,529 (21.8)	39,550 (61.4)	43,979 (-0.2)	1,05,374 (26.2)	54,146 (36.9)	51,228 (16.5)	1,16,143 (2.3)	48,326 (-15.6)	67,816 (20.6)
6. अन्य	9,95,882 (14.5)	2,16,808 (32.5)	7,79,074 (10.4)	11,44,673 (14.9)	2,83,535 (30.8)	8,61,139 (10.5)	12,61,403 (17.2)	2,91,100 (22.9)	9,70,303 (15.6)
कुल देयताएं / आस्तियां	43,57,119 (17.2)	10,71,050 (26.6)	32,86,069 (14.4)	50,68,607 (16.3)	13,59,521 (26.9)	37,09,086 (12.9)	54,53,592 (17.4)	13,73,785 (16.0)	40,79,806 (17.9)
1. ऋण और अग्रिम	33,99,655 (17.4)	9,18,302 (26.3)	24,81,353 (14.4)	40,27,478 (18.5)	11,85,621 (29.1)	28,41,857 (14.5)	42,92,708 (16.0)	11,94,234 (15.4)	30,98,474 (16.2)
2. निवेश	5,16,141 (18.6)	75,479 (48.9)	4,40,663 (14.7)	6,24,260 (20.9)	95,189 (26.1)	5,29,071 (20.1)	6,93,397 (33.7)	89,520 (24.8)	6,03,877 (35.1)
3. नकद और बैंक शेष राशि	1,73,802 (3.4)	46,946 (3.2)	1,26,856 (3.5)	1,72,422 (-0.8)	43,228 (-7.9)	1,29,194 (1.8)	2,01,157 (11.6)	56,110 (25.9)	1,45,047 (6.9)
4. अन्य आस्तियाँ	2,67,520 (21.5)	30,323 (34.1)	2,37,197 (20.1)	2,44,446 (-8.6)	35,483 (17.0)	2,08,963 (-11.9)	2,66,330 (9.1)	33,921 (2.1)	2,32,409 (10.2)

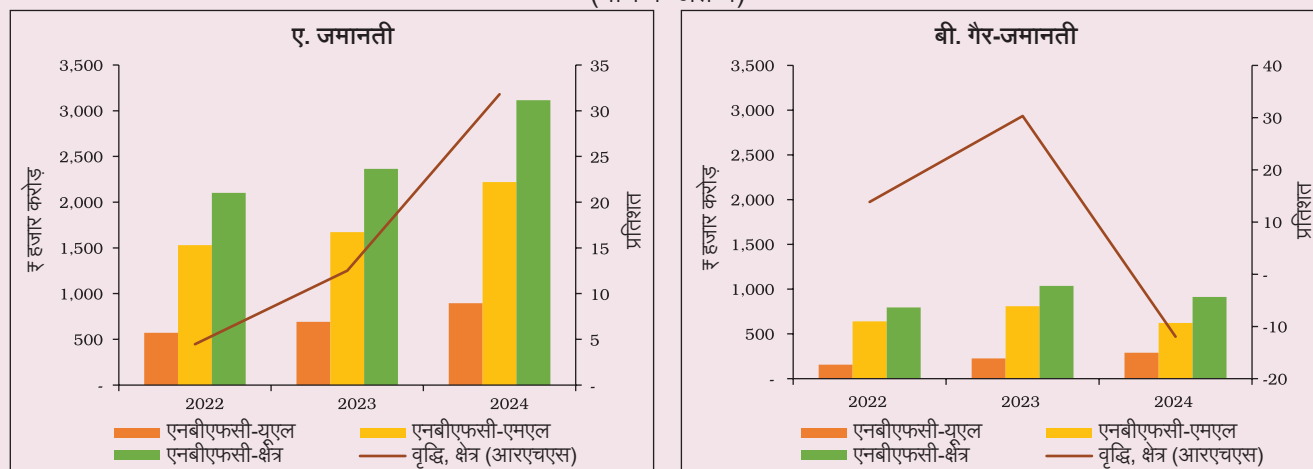
टिप्पणियां: 1. आंकड़े अनंतिम हैं।

2. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि को प्रतिशत में दर्शाते हैं।

3. एनबीएफसी की लेयर-वार पहचान मार्च 2024 के अंत में उनकी स्थिति पर आधारित है।

स्रोत: पर्यवेक्षी विवरणियां, आरबीआई।

चार्ट VI.4 : एनबीएफसी के ऋणों और अग्रिमों की प्रकृति
(मार्च के अंत में)



टिप्पणी : आंकड़े अनंतिम हैं।

स्रोत : पर्यवेक्षी विवरणियां, भारतीय रिजर्व बैंक।

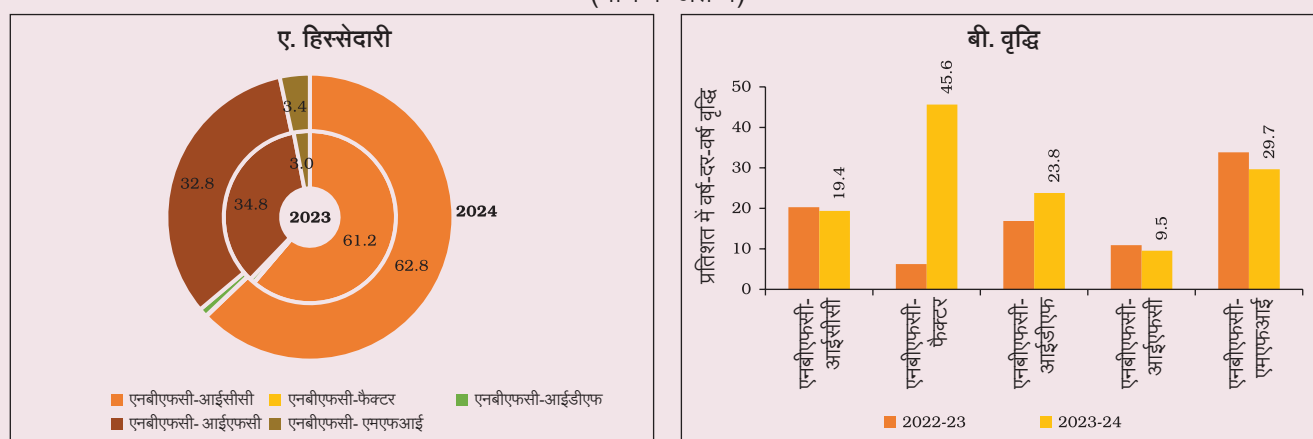
विस्तार दोहरे अंकों में जारी रहा (परिशिष्ट सारणी VI.1, VI.2 और VI.3)।

VI.13 मार्च 2024 के अंत में, एनबीएफसी-आईसीसी और आईएफसी की कुल हिस्सेदारी इस क्षेत्र की संपत्ति का 95.6 प्रतिशत रही (चार्ट VI.5ए)। ऊपरी लेयर की एनबीएफसी मुख्य रूप से एनबीएफसी-आईसीसी हैं, जो मुख्य रूप से खुदरा क्षेत्र को निधीयन करती हैं। अधिकांश एनबीएफसी-आईसीसी सरकारी स्वामित्व वाली हैं, जो मुख्य रूप से बुनियादी ढांचा क्षेत्र को ऋण प्रदान करती हैं। एनबीएफसी-एमएफआई, जो

अंतिम व्यक्ति तक क्रेडिट वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, इस क्षेत्र की कुल आस्तियों में अपना हिस्सा बढ़ा रहे हैं। एनबीएफसी-फैक्टर्स की आस्तियों में वृद्धि ने क्षेत्रीय औसत से बेहतर प्रदर्शन किया (चार्ट VI.5बी)।

VI.14 एनबीएफसी-आईसीसी, सबसे बड़ी श्रेणी, के ऋण और अग्रिमों में उच्च वृद्धि 2023-24 में बनी रही (सारणी VI.5)। एनबीएफसी-आईएफसी, दूसरी सबसे बड़ी श्रेणी, का इस श्रेणी में कर्ज देने वाली एक प्रमुख इकाई के रूप में विस्तार की गति में कमी आई है क्योंकि रेलवे बुनियादी ढांचा

चार्ट VI.5 : वर्गीकरण के अनुसार एनबीएफसी की कुल आस्तियां
(मार्च के अंत में)



टिप्पणी : आंकड़े अनंतिम हैं।

स्रोत : पर्यवेक्षी विवरणियां, भारतीय रिजर्व बैंक।

सारणी VI.5: वर्गीकरण के अनुसार एनबीएफसी की देयताओं और आस्तियों के प्रमुख घटक

(राशि ₹ करोड़ में)

देयताएं	मार्च के अंत में				सितंबर के अंत में		प्रतिशत घट-बढ़	
	2023		2024		2024		(मार्च के प्रति मार्च)	
	उधार	कुल देयताएं	उधार	कुल देयताएं	उधार	कुल देयताएं	2023	2024
	उधार	उधार	उधार	उधार	उधार	उधार	उधार	उधार
1	2	3	4	5	6	7	8	9
एनबीएफसी-आईसीसी	16,11,815	26,67,598	19,37,105	31,84,714	21,40,886	34,89,254	20.1	20.2
एनबीएफसी-फैक्टर	1,308	2,664	2,560	3,880	2,847	4,255	12.8	95.8
एनबीएफसी-आईडीएफ	31,985	39,023	40,122	48,310	44,385	53,083	18.0	25.4
एनबीएफसी-आईएफसी	12,29,875	15,15,824	13,40,429	16,60,542	13,86,069	17,39,872	11.4	9.0
एनबीएफसी-एमएफआई	99,050	1,32,010	1,25,807	1,71,161	1,18,485	1,67,127	37.8	27.0
कुल	29,74,034	43,57,119	34,46,024	50,68,607	36,92,670	54,53,592	16.8	15.9
आस्तियां	ऋण और अग्रिम	कुल आस्तियां	ऋण और अग्रिम	कुल आस्तियां	ऋण और अग्रिम	कुल आस्तियां	ऋण और अग्रिम	
एनबीएफसी-आईसीसी	18,83,195	26,67,598	23,38,506	31,84,714	25,52,461	34,89,254	21.3	24.2
एनबीएफसी-फैक्टर	2,047	2,664	3,425	3,880	3,839	4,255	4.7	67.3
एनबीएफसी-आईडीएफ	36,506	39,023	44,612	48,310	48,383	53,083	23.9	22.2
एनबीएफसी-आईएफसी	13,68,506	15,15,824	14,99,348	16,60,542	15,51,439	17,39,872	10.9	9.6
एनबीएफसी-एमएफआई	1,09,402	1,32,010	1,41,587	1,71,161	1,36,586	1,67,127	40.3	29.4
कुल	33,99,655	43,57,119	40,27,478	50,68,607	42,92,708	54,53,592	17.4	18.5

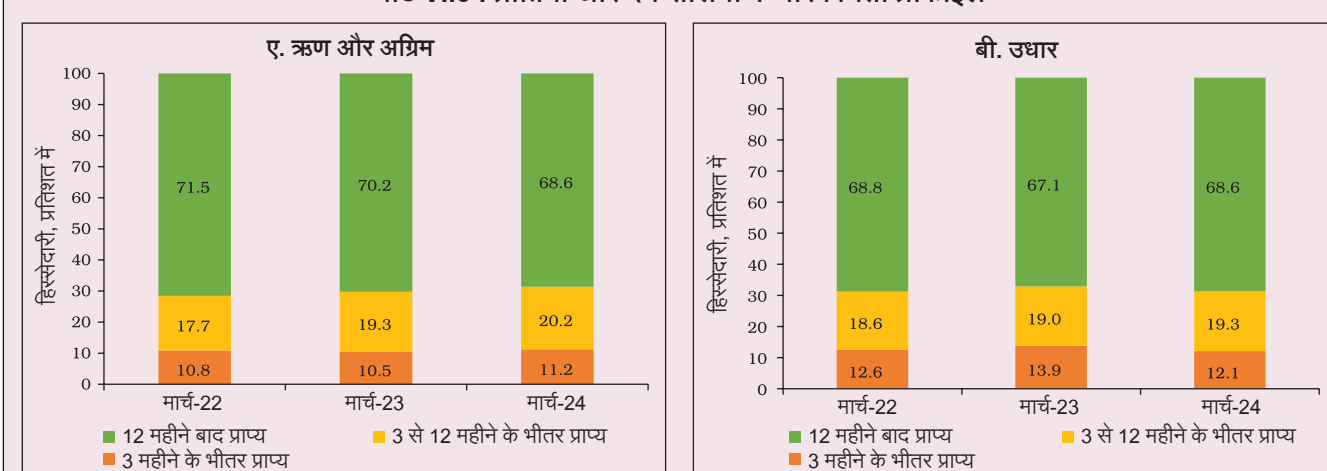
टिप्पणी: आंकड़े अनंतिम हैं।

स्रोत: पर्यवेक्षी विवरणियां, भारतीय रिज़र्व बैंक।

परियोजनाओं को ऋण देने में मामूली गिरावट दर्ज की गई। दूसरी ओर, बिजली क्षेत्र को ऋण देने में लगे दो एनबीएफसी-आईएफसी ने एक साल पहले की तुलना में 2023-24 में अधिक संवितरण दर्ज।

VI.15 एनबीएफसी ने 2023-24 के दौरान अपने तुलन-पत्र के दोनों तरफ तुलनीय परिपक्वता प्रोफाइल बनाए रखा। मार्च 2024 के अंत में, कुल क्रेडिट एक्सपोजर और कुल उधार का दो-तिहाई से अधिक दीर्घकालिक थे, अर्थात्., 12 महीने से अधिक था (चार्ट VI.6)।

चार्ट VI.6 : प्राप्तियों और देय राशियों के परिपक्वता प्रोफाइल



टिप्पणी : आंकड़े अनंतिम हैं।

स्रोत : पर्यवेक्षी विवरणियां, भारतीय रिज़र्व बैंक।

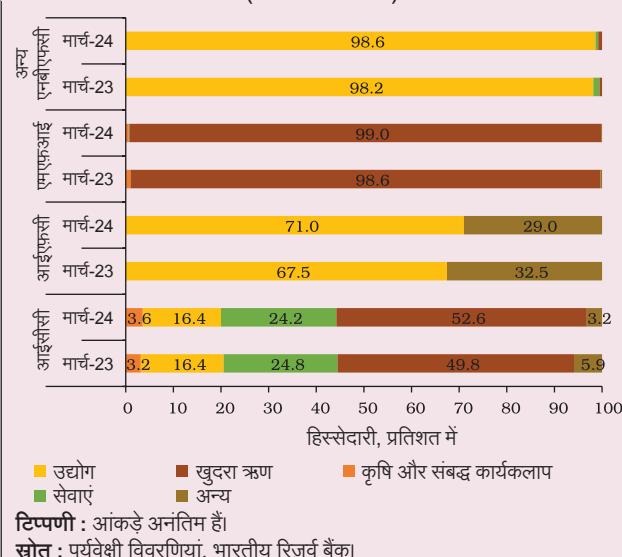
2.3 एनबीएफसी का क्षेत्रवार ऋण

VI.16 एनबीएफसी-आईसीसी के पास अपेक्षाकृत विविध ऋण पोर्टफोलियो है, जिसमें खुदरा ऋणों का वर्चस्व है। आईएफसी मुख्य रूप से उद्योगों (ज्यादातर बिजली और रेलवे) को उधार देता है। एमएफआई मुख्य रूप से संपार्श्विक मुक्त लघु टिकट ऋणों के माध्यम से खुदरा ग्राहकों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करते हैं (चार्ट VI.7)। मार्च 2024 के अंत में, एनबीएफसी-आईसीसी, आईएफसी और एमएफआई ने मिलकर इस क्षेत्र द्वारा संवितरित कुल ऋण का 99 प्रतिशत प्रदान किया है।

VI.17 एनबीएफसी के ऋण का एक प्रमुख हिस्सा उद्योग और खुदरा क्षेत्र को प्राप्त होता है (मार्च 2024 के अंत में कुल ऋण पोर्टफोलियो का 71.2 प्रतिशत)। 2023-24 के दौरान, एनबीएफसी ने बैंकों की तुलना में सभी क्षेत्रों (सेवाओं को छोड़कर) में ऋण प्रदान करने में उच्च वृद्धि दर्ज की। कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए एनबीएफसी का ऋण भी पिछले दो वर्षों में मजबूत गति से बढ़ा है, जिसके परिणामस्वरूप कुल ऋण में इसकी हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है (चार्ट VI.8)।

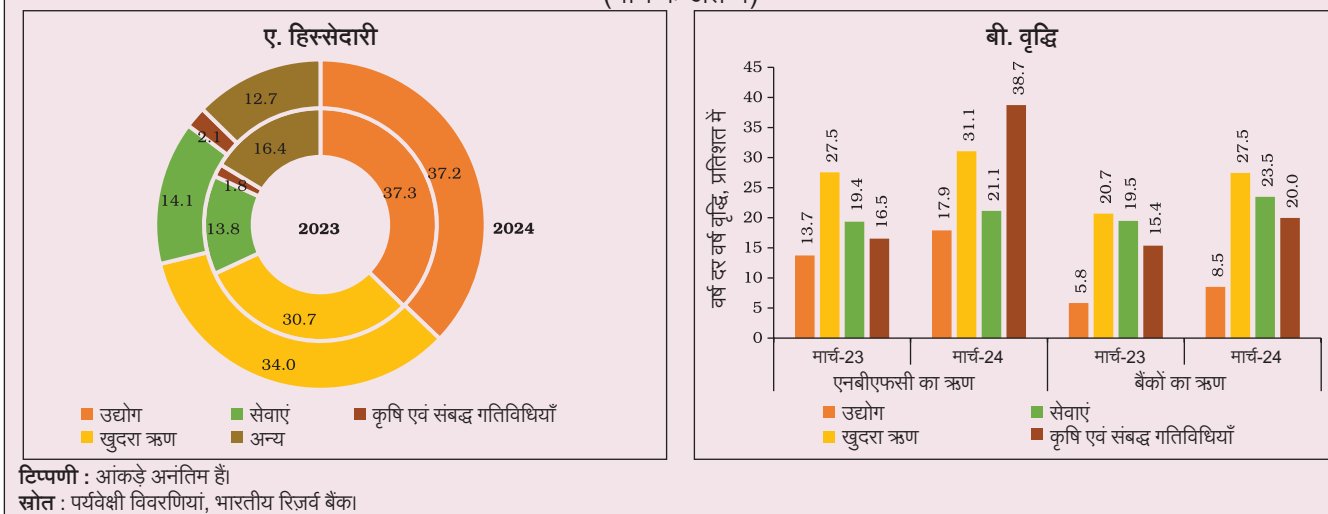
VI.18 मार्च 2024 के अंत में, बिजली क्षेत्र को ऋण उद्योगों को कुल ऋण का 75.2 प्रतिशत था, जो बड़े सरकारी स्वामित्व वाली एनबीएफसी द्वारा संचालित था (सारणी VI.6)। फरवरी

चार्ट VI.7 : वर्गीकरण के अनुसार ऋण का क्षेत्र-वार वितरण (मार्च के अंत में)



2024 में विनियमित संस्थाओं (आरई) (सभी शीर्ष और ऊपरी लेयर एनबीएफसी सहित) के लिए 'जलवायु संबंधी वित्तीय जोखिमों पर प्रकटीकरण ढांचे' पर मसौदा दिशानिर्देश जारी करते समय रिजर्व बैंक द्वारा एकाग्रता जोखिम और जलवायु संबंधी वित्तीय जोखिमों को ध्यान में रखा गया था। प्रमुख क्षेत्रों को ऋण में वृद्धि वर्ष दर वर्ष आधार पर बढ़ते हुए सितंबर 2024 के अंत में भी वृद्धि दर्ज की।

चार्ट VI.8 : एनबीएफसी ऋण का वितरण (मार्च के अंत में)



सारणी VI.6: एनबीएफसी द्वारा क्षेत्र-वार ऋण विनियोजन

(राशि ₹ करोड़ में)

मर्दे	मार्च 2023 के अंत में	मार्च 2024 के अंत में	सितंबर 2024 के अंत में	प्रतिशत घट-बढ़	
				2022-23	2023-24
1	2	3	4	5	6
1. कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियां	60,674	84,175	89,800	16.5	38.7
2. उद्योग, जिसमें	12,69,175	14,96,425	15,90,339	13.7	17.9
2.1 बिजली	9,40,408	11,25,725	11,89,784	14.5	19.7
2.2 अन्य	3,28,767	3,70,700	4,00,555	11.5	12.8
3. सेवाएं, जिसमें	4,68,009	5,66,932	6,08,246	19.4	21.1
3.1 परिवहन ओपरेटर	1,20,245	1,32,810	1,41,289	16.4	10.4
3.2 ट्रेड	69,520	92,324	1,05,415	39.5	32.8
4. खुदरा ऋण, जिसमें	10,45,168	13,69,820	15,02,697	27.5	31.1
4.1 वाहन/ओटो ऋण	3,82,825	4,74,839	5,17,092	17.3	24.0
4.2 सोने के प्रति व्यक्तियों को अग्रिम	1,28,774	1,53,481	1,74,325	8.7	19.2
4.3 सूक्ष्म वित्त ऋण/एसएचजी ऋण	1,15,187	1,48,503	1,44,162	51.1	28.9
5. अन्य	5,56,630	5,10,176	5,01,626	8.2	-8.3
सकल अग्रिम (1 से 5)	33,99,655	40,27,528	42,92,708	17.4	18.5

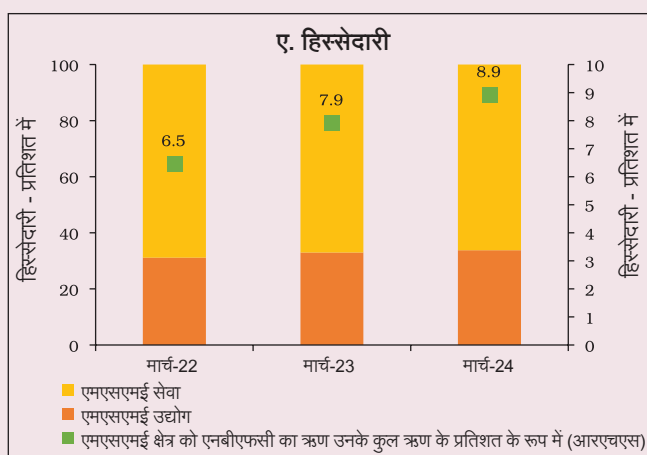
टिप्पणी : आंकड़े अनंतिम हैं।

स्रोत : पर्यवेक्षी विवरणियां, भारतीय रिज़र्व बैंक।

VI.19 एनबीएफसी ने अपने उद्योग समकक्षों की तुलना में एक बड़े हिस्से को किनारा करते हुए सेवा क्षेत्र से जुड़े एमएसएमई को बैंकों और एनबीएफसी द्वारा दिए गए कुल ऋण (मार्च 2024 के अंत में कुल ऋण का 11.7 प्रतिशत) में अपने हिस्से का लगातार विस्तार किया है (चार्ट VI.9)। एनबीएफसी का 'डिजिटल फर्स्ट' दृष्टिकोण, उदाहरण के लिए, खाता एग्रीगेटर

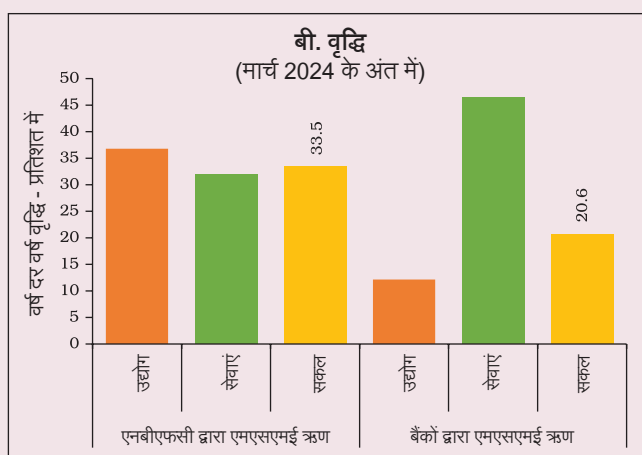
ढांचे का उपयोग, एमएसएमई को ऋण के प्रवाह में मदद कर रहा है। इसे प्रस्तावित यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस⁶ (यूएलआई) से बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

VI.20 वाहन ऋण, सोने के बदले ऋण और सूक्ष्म वित्त ऋण एनबीएफसी के मज़बूत क्षेत्र हैं जो कुल मिलाकर मार्च 2024 के अंत में उनके खुदरा संविभाग का 56.7

चार्ट VI.9 : एमएसएमई क्षेत्र को एनबीएफसी ऋण


टिप्पणी : आंकड़े अनंतिम हैं।

स्रोत : पर्यवेक्षी विवरणियां, भारतीय रिज़र्व बैंक।



⁶ भारत के लिए फिनटेक नवाचार @100: भारत के वित्तीय परिदृश्य के भविष्य को आकार देना - 28 अगस्त, 2024 को आरबीआई गवर्नर का संबोधन।

प्रतिशत रहा (परिशिष्ट सारणी VI.5)। नवंबर 2023 में मैक्रोप्रूडेंशियल उपायों को सख्त करने के बाद एनबीएफसी

द्वारा गैर-जमानती खुदरा ऋण की वृद्धि में कमी हो गई (बॉक्स VI.1)।

बॉक्स VI.1 : एनबीएफसी के गैर-जमानती खुदरा ऋण पर हाल के विनियामक परिवर्तनों का प्रभाव

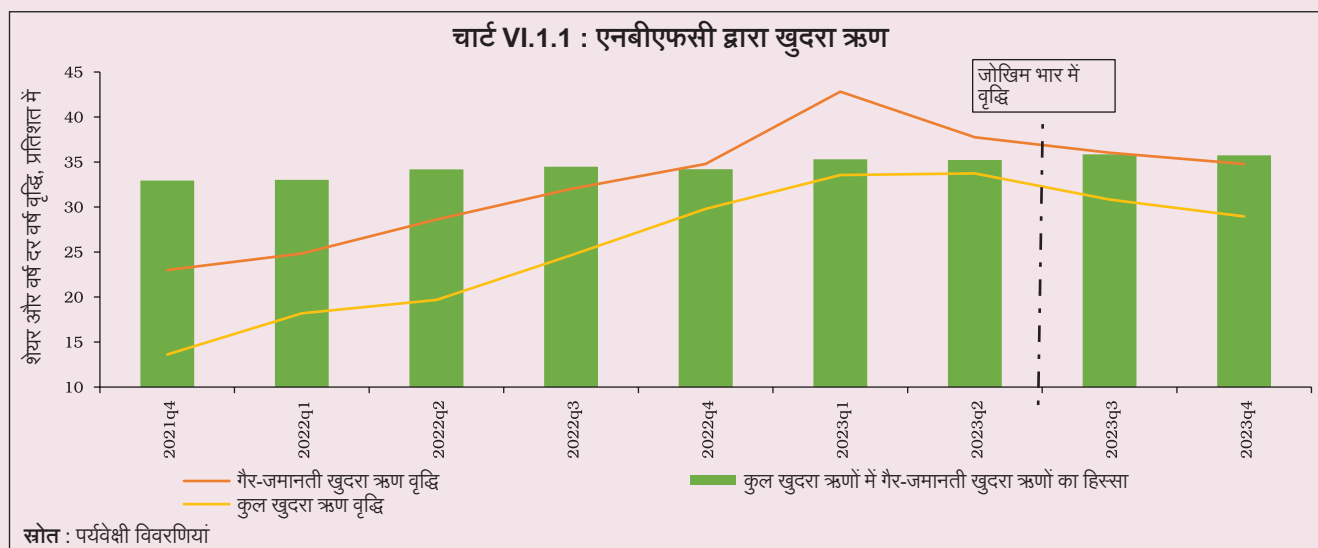
रिजर्व बैंक ने नवंबर 2023 में एनबीएफसी के उपभोक्ता ऋण जोखिमों [आवास, वाहन, शिक्षा, स्वर्ण और माइक्रोफाइनेंस/स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) ऋण जैसी श्रेणियों के ऋणों को छोड़कर] पर जोखिम भार को 100 प्रतिशत से बढ़ाकर 125 प्रतिशत कर दिया (चार्ट VI.1.1)। बैंक उधार पर एनबीएफसी की अत्यधिक निर्भरता को कम करने के लिए, उन मामलों में एनबीएफसी के लिए एससीबी के जोखिम भार को 25 प्रतिशत अंकों तक बढ़ा दिया गया था, जहां एनबीएफसी की बाहरी रेटिंग के अनुसार मौजूदा जोखिम भार 100 प्रतिशत से कम था।

एनबीएफसी के ऋणों पर जोखिम भार में बदलाव के प्रभाव को औपचारिक रूप से दिसंबर 2022 से मार्च 2024⁷ की अवधि के लिए 95 एनबीएफसी के लिए त्रैमासिक पर्यवेक्षी डेटा का उपयोग करके एक पैनल रिग्रेशन फ्रेमवर्क में जांचा गया। ये एनबीएफसी खुदरा क्षेत्र⁸ में काम करते हैं और एनबीएफसी क्षेत्र के खुदरा ऋण के 74 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित प्रतिगमन का अनुमान सिस्टम सामान्यीकृत विधि (जीएमएम) दृष्टिकोण का उपयोग करके लगाया जाता है :

$$Y_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 Y_{i,t-1} + \beta_2 Policy_t + \beta_3 Ex-Ante Share of Bank Borrowings_i + \beta_4 Ex-Ante Share of Bank Borrowings_i * Policy_t + \beta_5 X_{i,t-1}^c + \alpha_i + \varepsilon_{i,t}$$

जहां आश्रित वेरिएबल $Y_{i,t}$ को गैर-जमानती खुदरा ऋण⁹ की चार-तिमाही लॉग अंतर वृद्धि के रूप में परिभाषित किया गया है। $Policy_t$ एक डमी वेरिएबल है जिसका मूल्य रिजर्व बैंक द्वारा जोखिम भार बढ़ाने के बाद की अवधि में 1 होता है, अर्थात्, दिसंबर 2023 को समाप्त होने वाली तिमाही से और उससे पहले की अवधि में 0। $Ex-Ante Share of Bank Borrowings_i$ एक श्रेणीबद्ध वेरिएबल है जिसका मूल्य नीति के कार्यान्वयन से पहले की अवधि में एनबीएफसी द्वारा कुल उधार में बैंक उधार का हिस्सा 25 प्रतिशत मूल्य (1 अन्यथा) से कम होने के मामले में 0 होता है। $X_{i,t-1}^c$ नियंत्रणों का वेक्टर है, जिसमें एनबीएफसी-विशिष्ट चर शामिल हैं जैसे आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए), (कुल आस्ति के निवल लाभ के अनुपात के रूप में परिभाषित), सीआरएआर (जोखिम-भारित आस्तियों के लिए कुल पूंजी निधि के अनुपात के रूप में परिभाषित) और गैर-जमानती खुदरा पोर्टफोलियो का सकल गैर-निष्पादित आस्ति (जीएनपीए) अनुपात (कुल गैर-जमानती खुदरा ऋण के लिए इस खंड की गैर-निष्पादित आस्तियों के अनुपात के रूप में परिभाषित)। व्यापक आर्थिक वातावरण को नियंत्रित करने के लिए नाम मात्र रूप से सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि को भी शामिल किया गया है।

पॉलिसी डमी का नकारात्मक गुणांक यह इंगित करता है कि गैर-जमानती खुदरा ऋणों की वृद्धि दर जोखिम भार (मॉडल 1) में वृद्धि के बाद गिर गई। नकारात्मक



(जारी)

⁷ निरंतर डेटा की उपलब्धता के आधार पर 95 एनबीएफसी का उपयोग किया गया।

⁸ मार्च 2023 के अंत में।

⁹ एनबीएफसी द्वारा खुदरा ऋण की वे सभी श्रेणियां जिनके लिए जोखिम-भार बढ़ा दिया गया है, उन्हें गैर-जमानती खुदरा ऋण माना जाता है।

भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति संबंधी रिपोर्ट 2023-24

सारणी VI.1.1 : प्रतिगमन परिणाम

चर	मॉडल 1	मॉडल 2	मॉडल 3
	गैर-जमानती खुदरा ऋण वृद्धि	गैर-जमानती खुदरा ऋण वृद्धि	अन्य खुदरा ऋण वृद्धि
लैग (गैर-जमानती खुदरा ऋण वृद्धि)	0.671*** (0.0866)	0.587*** (0.120)	
पोलिसी (पोस्ट = दिसंबर 2023 से)	-0.159*** (0.0568)	0.108 (0.119)	0.00761 (0.0218)
बैंक उधार का प्रत्याशित शेयर (बेस = कम हिस्सा)		0.434 (0.559)	
पोलिसी * बैंक का प्रत्याशित हिस्सेदारी उधार		-0.359** (0.163)	
लैग (आकार)	0.330* (0.176)	0.407* (0.227)	-0.0141 (0.0962)
लैग (सीआरएआर)	0.00666 (0.00803)	0.0117 (0.0121)	-0.00491* (0.00266)
लैग (आरओए)	-0.00521 (0.0498)	-0.00270 (0.0568)	0.00646 (0.0141)
लैग (गैर-जमानती खुदरा ऋण जीएनपीए अनुपात)	-0.0438*** (0.0115)	-0.0375*** (0.0127)	
लैग (नाम मात्र जीडीपी वृद्धि)	-0.00101 (0.00361)	-0.00136 (0.00434)	0.00377* (0.00218)
लैग (अन्य खुदरा ऋण वृद्धि)			0.474*** (0.0841)
लैग (अन्य खुदरा ऋण जीएनपीए अनुपात)			-0.0303* (0.0155)
अपरिवर्तनीय	-2.744* (1.596)	-3.850* (2.211)	0.385 (0.903)
टिप्पणियां	542	530	542
एनबीएफसी की संख्या	95	93	95
एआर (1)	0.00	0.00	0.00
एआर (2)	0.55	0.42	0.58
हैनसेन सांख्यिकी	0.47	0.53	0.49

कोष्ठकों में मजबूत मानक त्रुटियां

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

टिप्पणी : आंकड़े अनंतिम हैं।

स्रोत : पर्यवेक्षी विवरणियां, आरबीआई; आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

गुणांक जो पोलिसी डम्मी के साथ बैंक उधारों के प्रत्याशित शेयर का प्रतिनिधित्व करता है, यह दर्शाता है कि गैर-जमानती खुदरा ऋण की वृद्धि में गिरावट बैंक उधारों पर प्रत्याशित निर्भरता वाली एनबीएफसी द्वारा प्रेरित थी (मॉडल 2)। बैंक उधारों पर कम प्रत्याशित निर्भरता वाली एनबीएफसी ने सांख्यिकीय रूप से कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन का सामना नहीं किया। एनबीएफसी-विशिष्ट नियंत्रणों में, गैर-जमानती खुदरा ऋण वृद्धि सकारात्मक रूप से एनबीएफसी के आकार से संबंधित है और नकारात्मक रूप से सेगमेंट के जीएनपीए अनुपात से संबंधित है। मजबूती के लिए, मॉडल 3 खुदरा ऋण पर ध्यान केंद्रित करता है जो जोखिम भार के अधीन नहीं है, अर्थात्, 'अन्य खुदरा ऋण वृद्धि' को गैर-जमानती घटक को छोड़कर कुल खुदरा ऋण के रूप में परिभाषित किया गया है। अनुमानों से पता चलता है कि ऐसे ऋण इन उपायों से प्रभावित नहीं हुए थे। कुल मिलाकर, अनुभवजन्य विश्लेषण से पता चलता है कि रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए प्रतिक्रिया विवेकपूर्ण उपायों ने नीतिगत उद्देश्य के अनुरूप गैर-जमानती खुदरा उधार की वृद्धि को कम कर दिया।

संदर्भ :

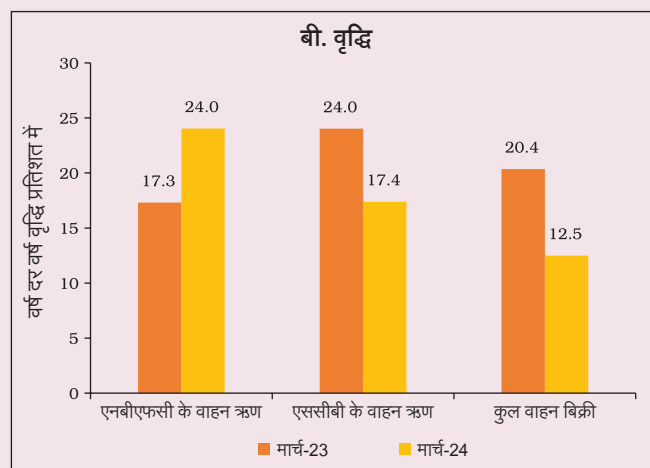
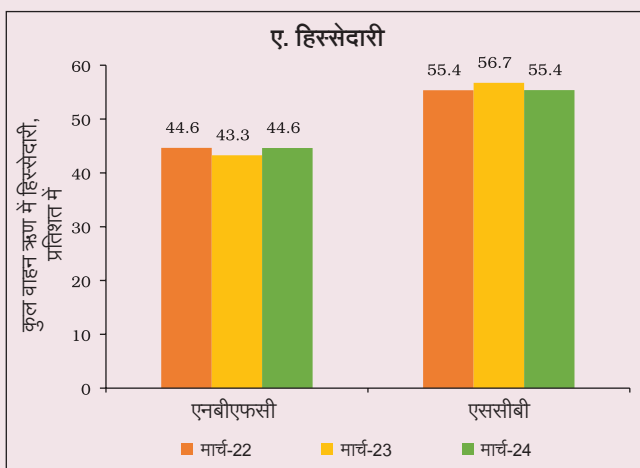
आरबीआई (16 नवंबर 2023)। एनबीएफसी को उपभोक्ता ऋण और बैंक ऋण संबंधी विनियामक उपाय।

<https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/notification/PDFs/REGULATORYMEASURES8785E7886A044B678FB8AF-2C6C051807.PDF> से लिया गया।

VI.21 वाहन ऋण एनबीएफसी के खुदरा ऋण पोर्टफोलियो का सबसे बड़ा घटक बना हुआ है, जिनकी हिस्सेदारी मार्च 2024 के अंत में 34.7 प्रतिशत थी। 2023-24 में एनबीएफसी

के वाहन ऋण एससीबी की तुलना में उच्च दर से बढ़े (चार्ट VI.10)।

चार्ट VI.10 : वाहन ऋण - एनबीएफसी बनाम एससीबी

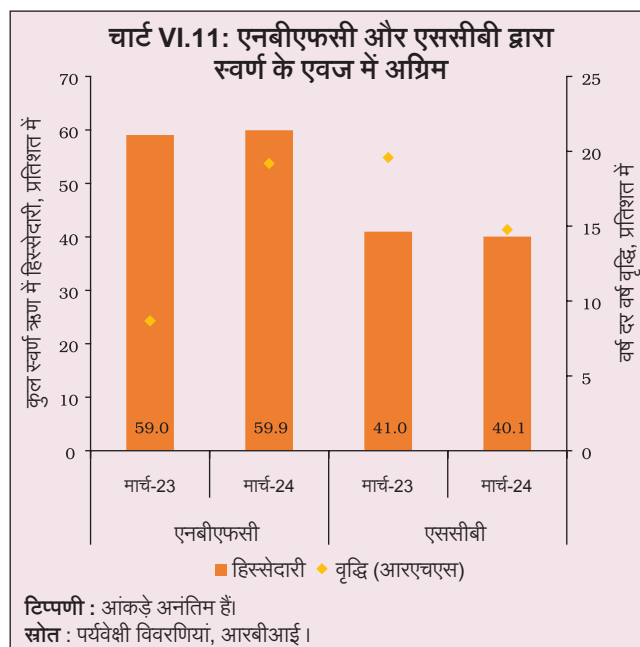


टिप्पणी : आंकड़े अनंतिम हैं।

स्रोत : पर्यवेक्षी विवरणियां, आरबीआई; सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (एसआईएम)।

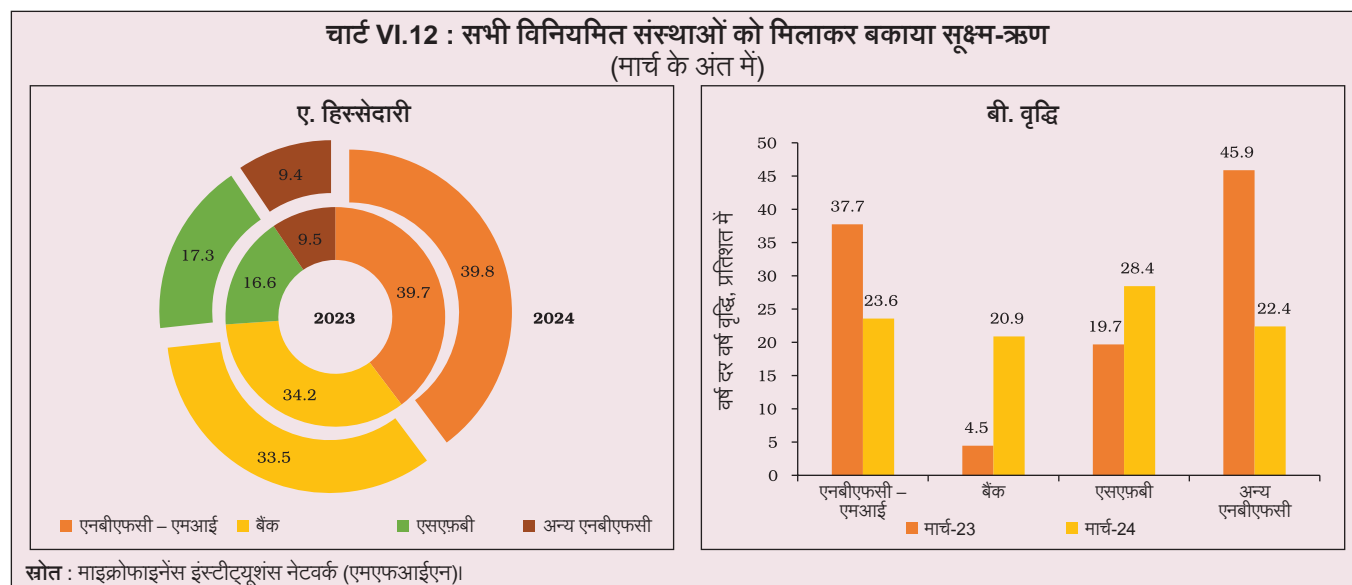
VI.22 एनबीएफसी ने मार्च 2024 के अंत में कुल स्वर्ण ऋण (बैंक और एनबीएफसी एक साथ) के 59.9 प्रतिशत हिस्से के साथ सोने के गहनों और आभूषणों की गिरवी के बदले ऋणों में अपना प्रभुत्व बनाए रखा (चार्ट VI.11)। कुछ पर्यवेक्षित संस्थाओं (एसई) की अनियमित प्रथाओं को ध्यान में रखते हुए, रिज़र्व बैंक ने 30 सितंबर 2024 को एसई को सूचित किया कि वे स्वर्ण ऋण संबंधी अपनी नीतियों, प्रक्रियाओं और प्रथाओं की व्यापक समीक्षा करें ताकि चूक की पहचान हो सके और उपचारात्मक उपाय करें।

VI.23 एनबीएफसी – एमएफआई - भारतीय माइक्रोफाइनेंस स्पेस में प्रमुख वाहक - पारंपरिक रूप से सेवाओं से वंचित समुदायों को कई वित्तीय सेवाओं तक पहुँच को सुसाध्य बनाते हुए ऋण प्राप्त करने की कठिनाइयों को कम कर दिया है। मार्च 2024 के अंत में एनबीएफसी के कुल खुदरा ऋण पोर्टफोलियो में सूक्ष्म ऋण की हिस्सेदारी 10.8 प्रतिशत थी। एनबीएफसी (एमएफआई सहित) ने कुल माइक्रो-क्रेडिट ऋणों में अपनी हिस्सेदारी बनाए रखी है (चार्ट VI.12)। एमएफआई के लिए एसआरओ ने बाजार अनुशासन और उधारकर्ताओं के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए एक उधारकर्ता के लिए माइक्रोफाइनेंस उधारदाताओं की संख्या को चार तक सीमित करने और कुल ऋणग्रस्तता को सीमित करने जैसे सुरक्षा उपाय किए हैं।



2.4 संसाधन जुटाना

VI.24 एनबीएफसी कई स्रोतों से धन जुटाती हैं, जिसमें प्रमुख हैं, बैंकों से उधार और डिबेंचर की जारी। एनबीएफसी-डी के लिए, सार्वजनिक जमाराशि निधि का एक महत्वपूर्ण स्रोत बना हुआ है। हाल ही में, आस्ति बिक्री और प्रतिभूतीकरण महत्वपूर्ण धन स्रोतों के रूप में उभरे हैं, विशेष रूप से चलनिधि प्रबंधन को सुविधाजनक बनाने में उनकी भूमिका के कारण।



सारणी VI.7 : एनबीएफसी के उधार के स्रोत

(राशि ₹ करोड़ में)

मर्दे	मार्च 2023 के अंत में	मार्च 2024 के अंत में	सितंबर 2024 के अंत में	प्रतिशत में घट-बढ़	
				2022-23	2023-24
1	2	3	4	5	6
1. डिबेंचर्स	11,05,943 (37.2)	12,28,997 (35.7)	13,28,203 (36.0)	9.8	11.1
2. बैंक उधार	11,23,748 (37.8)	13,31,619 (38.6)	13,94,324 (37.8)	23.6	18.5
3. एफआई से उधार	86,289 (2.9)	1,11,753 (3.2)	1,09,005 (3.0)	30.5	29.5
4. अंतर-कार्पोरेट उधार	1,01,924 (3.4)	1,04,788 (3.0)	1,17,369 (3.2)	21.0	2.8
5. वाणिज्यिक पत्र	83,529 (2.8)	1,05,374 (3.1)	1,16,143 (3.1)	21.8	26.2
6. सरकार से उधार	18,781 (0.6)	18,282 (0.5)	18,352 (0.5)	1.2	-2.7
7. अधीनस्थ ऋण	71,457 (2.4)	75,313 (2.2)	78,237 (2.1)	0.4	5.4
8. अन्य उधार	3,82,363 (12.9)	4,69,898 (13.6)	5,31,037 (14.4)	19.3	22.9
कुल उधार	29,74,034	34,46,024	36,92,670	16.8	15.9

टिप्पणियां : 1. आंकड़े अनंतिम हैं।

2. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल उधारों में हिस्सेदारी का संकेत देते हैं।

स्रोत : पर्यवेक्षी विवरणियां, आरबीआई।

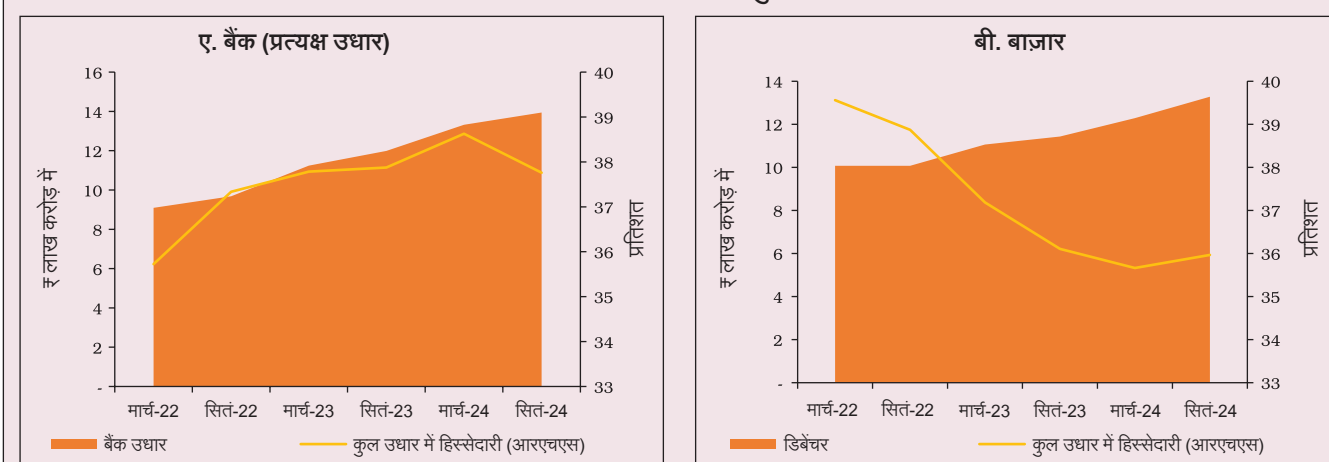
2.4.1 उधार

VI.25 वर्ष 2018 में आईएल&एफएस प्रकरण के तुरंत बाद एनबीएफसी को महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा जिनमें विश्वास में कमी, रेटिंग में कमी और नकदी की कमी शामिल थी जिसने बाजार से कर्ज लेने की उनकी क्षमता सीमित कर दी। कोविड -19 महामारी से हालात और कठिन होने के कारण निधीयन के लिए एनबीएफसी बैंकों पर और अधिक

निर्भर हो गईं। वर्ष 2023-24 में, अन्य बातों के साथ-साथ, एनबीएफसी को बैंक ऋण पर उच्च जोखिम भार के कारण बैंकों से उधार की वृद्धि में मध्यम गति मिली। बैंकों से उधार में नरमी सितंबर 2024 के अंत तक जारी रही (सारणी VI.7)।

VI.26 बैंक उधारी एनबीएफसी के लिए धन का प्राथमिक स्रोत बना हुआ है। वास्तव में, हाल के वर्षों में बाजार उधारों पर एनबीएफसी की निर्भरता में गिरावट आई है (चार्ट VI.13)।

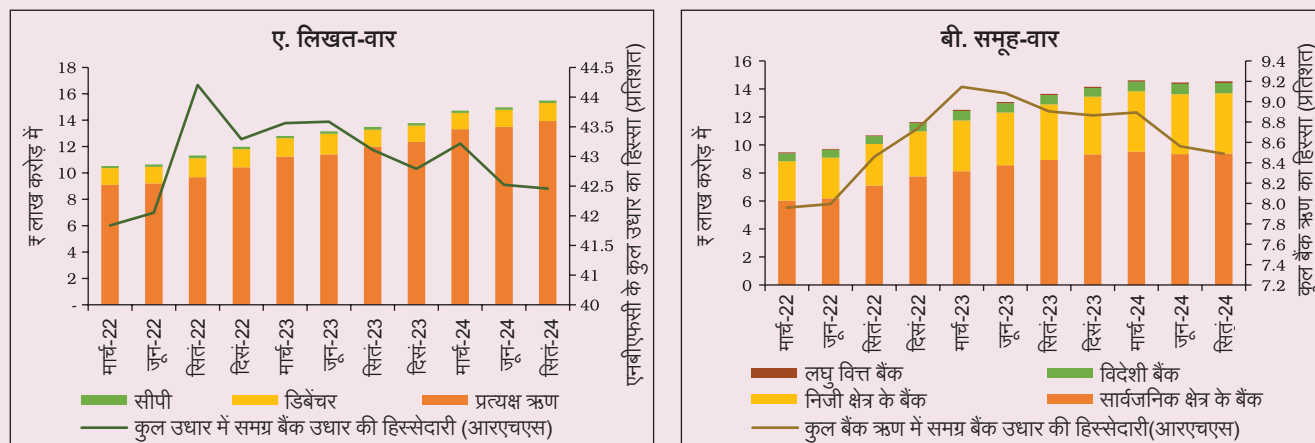
चार्ट VI.13: उधार के प्रमुख स्रोत



टिप्पणी : आंकड़े अनंतिम हैं।

स्रोत : पर्यवेक्षी विवरणियां, आरबीआई।

चार्ट VI.14: एनबीएफसी के प्रति बैंकों का एक्सपोजर



टिप्पणी : आंकड़े अनंतिम हैं।

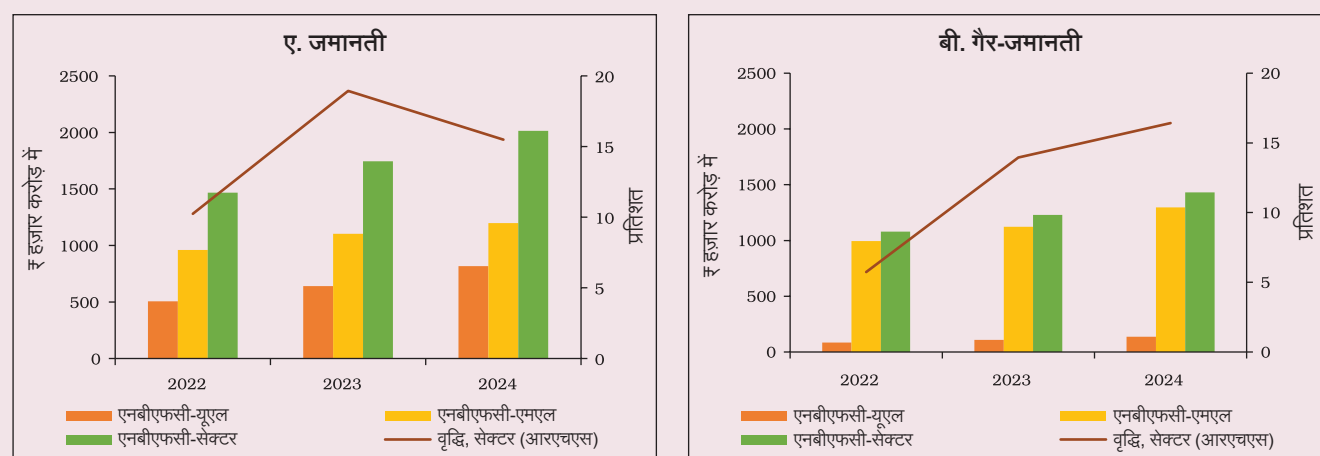
स्रोत : पर्यवेक्षी विवरणियां, आरबीआई।

VI.27 एनबीएफसी को सीधे उधार देने के अलावा, बैंक एनबीएफसी द्वारा जारी किए गए डिबेंचर और सीपी भी खरीदते हैं। बैंकों द्वारा डिबेंचर की खरीद में गिरावट के साथ, एनबीएफसी की उधारी में कुल बैंक उधार का हिस्सा मार्च 2023 के अंत के 43.1 प्रतिशत से घटकर मार्च 2024 के अंत में 42.7 प्रतिशत हो गया (चार्ट VI.14ए)। कुल बैंक ऋण के हिस्से के रूप में एनबीएफसी के लिए समग्र बैंक एक्सपोजर भी 2023-24 में घट गया (चार्ट VI.14बी)। निधि के लिए बैंकों

पर एनबीएफसी की निर्भरता में कमी समग्र वित्तीय स्थिरता के लिए के लिए अच्छा है।

VI.28 एनबीएफसी की जमानती उधार में वृद्धि 2023-24 के दौरान कम हो गई, जबकि बाजार उधार की बढ़त से गैर-जमानती उधार में तेजी आई (ऋण लिखतों, अर्थात्, डिबेंचर और वाणिज्यिक पत्र जारी करने के माध्यम से) [चार्ट VI.15]। विभिन्न स्तरों पर, एनबीएफसी-एमएल मुख्य रूप से सरकारी एनबीएफसी की उपस्थिति के कारण गैर-जमानती निधि जुटाते हैं।

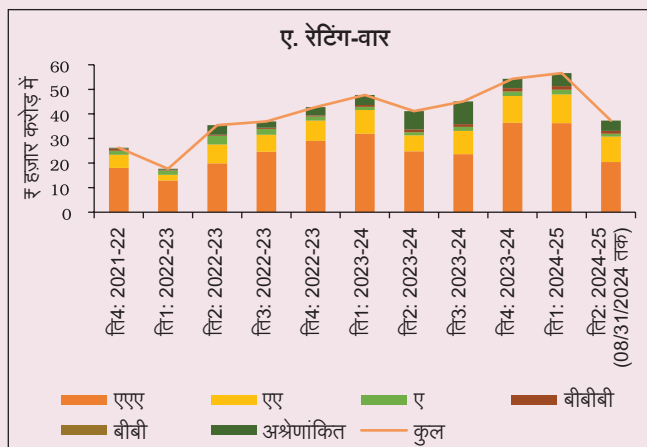
चार्ट VI.15: एनबीएफसी के उधार का स्वरूप



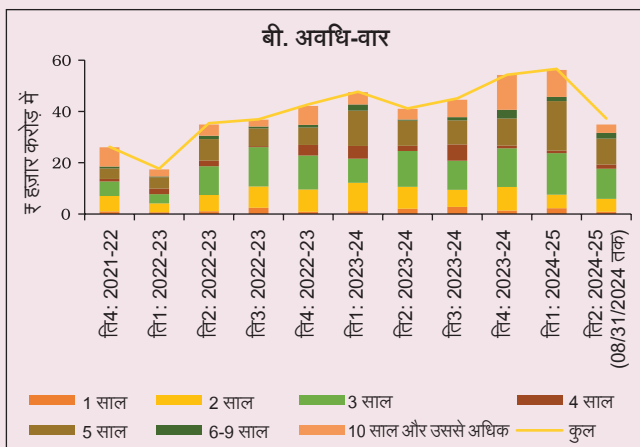
टिप्पणी : आंकड़े अनंतिम हैं।

स्रोत : पर्यवेक्षी विवरणियां, आरबीआई।

चार्ट VI.16: निजी एनबीएफसी के एनसीडी प्राइवेट प्लेसमेंट

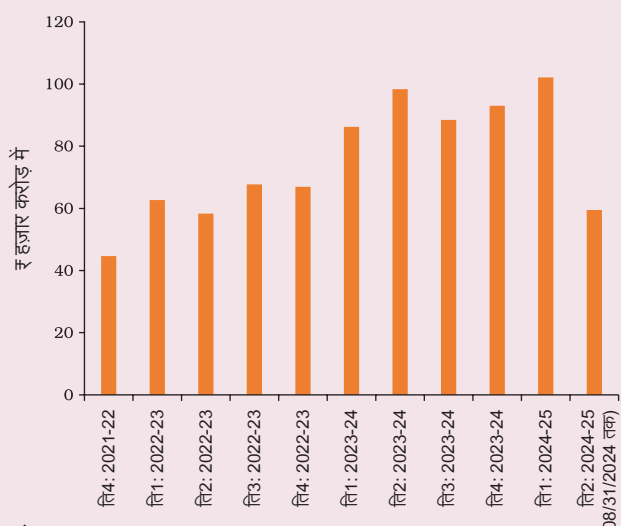


स्रोत : 1. स्टाफ अनुमान
2. प्राइम डाटाबेस



VI.29 गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) जारी करने के माध्यम से एनबीएफसी द्वारा जुटाई गई धनराशि 2023-24 में बढ़ी, जिसमें 80 प्रतिशत से अधिक निर्गम उच्च रेटेड (एएए या एए) (चार्ट VI.16) थे। 2023-24 में सीपी के माध्यम से एनबीएफसी द्वारा उधार भी बढ़ा (चार्ट VI.17)।

चार्ट VI.17: निजी एनबीएफसी द्वारा सीपी जारी करना

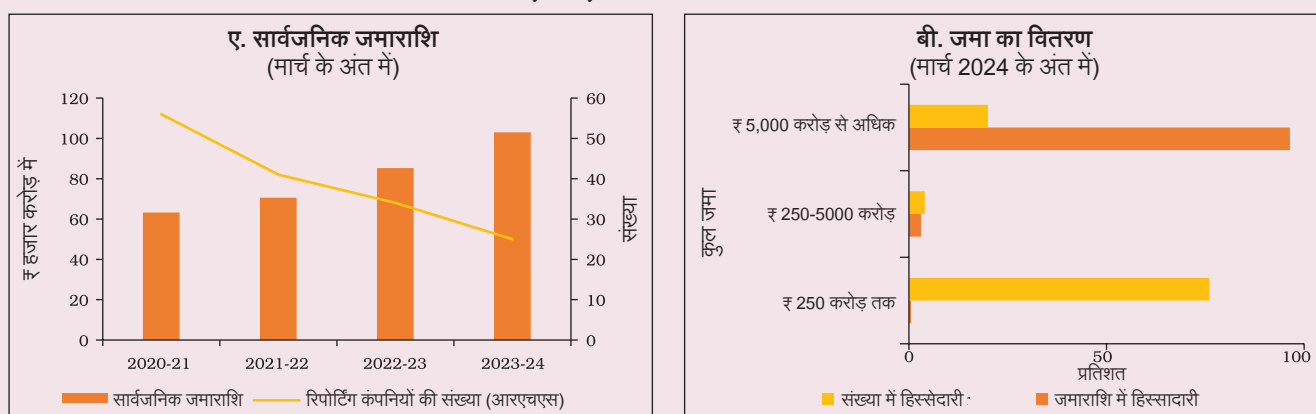


स्रोत : 1. स्टाफ अनुमान
2. प्राइम डाटाबेस

2.4.2 जनता की जमाराशियां

VI.30 2023-24 में एनबीएफसी-डी के तुलन-पत्र में 21.6 प्रतिशत का विस्तार हुआ, जिसमें जमा और ऋण दोनों में मजबूत वृद्धि हुई (परिशिष्ट सारणी VI.4)। 36 साल पहले से मार्च 2024 के अंत तक एनबीएफसी-डी की संख्या कम होकर होने के बावजूद उनकी जमा राशि में 2023-24 में दोहरे अंकों की वृद्धि (20.8 प्रतिशत) दर्ज की गई (चार्ट VI.18ए)। पांच एनबीएफसी का हिस्सा कुल जमाराशि का 96.4 प्रतिशत था (चार्ट VI.18बी)। रिज़र्व बैंक ने एनबीएफसी-डी द्वारा जुटाई गई जमाराशियों के प्रति सतर्क दृष्टिकोण अपनाया है, क्योंकि उनका बीमा निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) द्वारा नहीं किया जाता है। मौजूदा विनियामक आवश्यकताओं के अनुसार, जमाराशियों को स्वीकार करने के लिए इन एनबीएफसी को उनकी स्थायी जमा राशि पर किसी भी सेबी-पंजीकृत क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से कम से कम 'बीबीबी-' की निवेश-ग्रेड रेटिंग प्राप्त होनी चाहिए। इसके अलावा, 12 से 60 महीने की अवधि वाली और ब्याज दरों को 12.5 प्रतिशत पर सीमित जमाराशि की मात्रा उनके निवल स्वाधिकृत निधि (एनओएफ) के 1.5 गुना से अधिक नहीं होनी चाहिए।

चार्ट VI.18: एनबीएफसी-डी में जनता की जमाराशियां



टिप्पणियां : 1. एनबीएफसी-डी को उनकी कुल सार्वजनिक जमाराशि के आकार के आधार पर विभिन्न समूहों में वर्गीकृत किया गया है। किसी भी एनबीएफसी-डी के पास ₹ 250-500 करोड़ और ₹ 500-1,000 करोड़ की जमापूंजी नहीं थी।
2. आंकड़े अनंतिम हैं।

स्रोत : पर्यवेक्षी विवरणियां, आरबीआई।

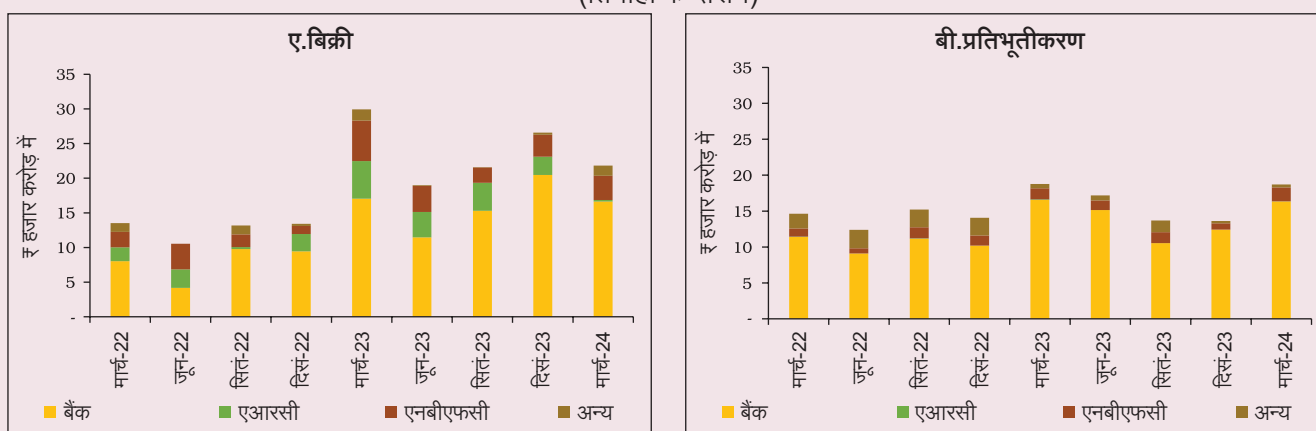
2.4.3 ऋण बिक्री और प्रतिभूतीकरण

VI.31 एनबीएफसी ने 2023-24 के दौरान प्रतिभूतीकरण की तुलना में ऋण बिक्री के माध्यम से अधिक मात्रा में निधि जुटाई¹⁰। दोनों क्षेत्र में बैंक एक प्रमुख भागीदार हैं। इन तरीकों से जुटाई गई संचयी निधियों में इस अवधि के दौरान वृद्धि देखी गई (चार्ट VI.19)।

2.4.4 विदेशी देयताएं

VI.32 घरेलू बाजार के अलावा, एनबीएफसी मुख्य रूप से बाहरी वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) और प्रतिस्पर्धी दरों पर डिबेंचर जारी करने के माध्यम से विदेशी स्रोतों से भी धन जुटाते हैं। मार्च 2024 के अंत में, विदेशी देनदारियां क्षेत्र की कुल देनदारियों का 8.8 प्रतिशत थीं, इसका मुख्य कारण

चार्ट VI.19: एनबीएफसी द्वारा ऋण बिक्री और प्रतिभूतीकरण (तिमाही के दौरान)



टिप्पणी : आंकड़े अनंतिम हैं।

स्रोत : पर्यवेक्षी विवरणियां, आरबीआई।

¹⁰ ऋण बिक्री और प्रतिभूतीकरण का उपयोग हारा ऋणदाता संस्थाएं चलनिधि सृजन, अपने ऋणों को पुनर्संतुलित करने या कार्यनीतिक बिक्री और विनियामक अनुपालन जैसे कारणों से लेती हैं।

सारणी VI.8 : एनबीएफसी की विदेशी देयताएं

(राशि ₹ करोड़ में)

मर्दे	मार्च 2023 के अंत में	मार्च 2024 के अंत में	सितंबर 2023 के अंत में	प्रतिशत घट-बढ़	
				2022-23	2023-24
1	2	3	4	5	6
1. ईक्विटी शेयर	39,331	46,931	54,637	-25.0	19.3
i) विदेशी संस्थागत निवेशक	1,351	1,861	2,193	2.6	37.7
ii) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश	37,980	45,070	52,444	-25.7	18.7
2. उधार (ईसीबी)	2,02,724	2,56,772	3,24,830	19.1	26.7
3. बाण्ड / डिबेंचर्स	1,26,349	1,24,130	1,20,221	-3.8	-1.8
4. अन्य	14,080	19,045	17,384	-16.1	35.3
कुल विदेशी देयताएं	3,82,484	4,46,877	5,17,071	3.1	16.8

टिप्पणियां : 1. आंकड़े अनंतिम हैं।

2. एनबीएफसी की विदेशी देयतायें तुलन पत्र के तहत उल्लिखित कुल देयताओं का हिस्सा हैं।

स्रोत : पर्यवेक्षी विवरणियां, आरबीआई।

ईसीबी (कुल विदेशी देनदारियों का 57.5 प्रतिशत) थे (सारणी VI.8)।

2.5 एनबीएफसी की आस्ति देयता प्रोफाइल

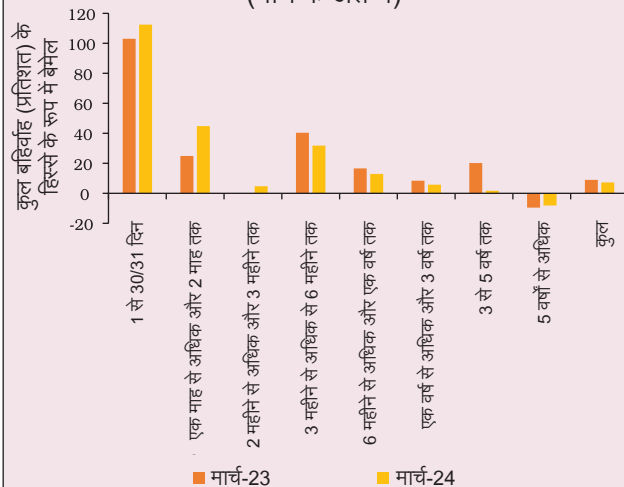
VI.33 एनबीएफसी की संरचनात्मक चलनिधि स्थिति का आकलन विभिन्न टाइम बकेट¹¹ में नकदी प्रवाह से नकदी बहिर्वाह को घटाकर किया जाता है। महत्वपूर्ण 1-30/31 दिनों की बकेट के भीतर, मार्च 2024 के अंत में एनबीएफसी के कुल बहिर्वाह के हिस्से के रूप में 100 प्रतिशत से अधिक सकारात्मक बेमेल था। सभी बकेट, पांच साल से अधिक की परिपक्वता वाले को छोड़कर, ने मार्च 2024 के अंत में एक सकारात्मक बेमेल बनाए रखा (चार्ट VI.20)।

VI.34 संभावित चलनिधि व्यवधानों के प्रति अल्पकालिक लचीलापन बढ़ाने के लिए एनबीएफसी¹³ को चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर)¹² तक बढ़ाया गया था, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके पास 30 दिनों तक चलने वाले तीव्र दबाव परिदृश्य से बचने के लिए पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाली चलनिधि आस्ति (एचक्यूएलए) हो। 1 दिसंबर, 2020 से प्रभावी, एनबीएफसी को न्यूनतम निर्धारित एलसीआर बनाए रखना होगा और 1 दिसंबर, 2024 तक क्रमिक रूप से 100 प्रतिशत के आवश्यक स्तर को प्राप्त करना होगा।

2.6 वित्तीय प्रदर्शन

VI.35 एनबीएफसी की आय का लगभग 90 प्रतिशत निधि-आधारित स्रोतों से अर्जित होता है, मुख्य रूप से ब्याज और निवेश आय के माध्यम से, जबकि शुल्क-आधारित आय शेष योगदान करती है। शुल्क और निधि-आधारित आय दोनों दोहरे अंकों में बढ़ने के कारण 2023-24 के दौरान एनबीएफसी का

चार्ट VI.20: एनबीएफसी का संरचनात्मक चलनिधि विवरण (मार्च के अंत में)



टिप्पणियां : 1. आंकड़े अनंतिम हैं।

2. बेमेल को इनफ्लो माइनस आउटफ्लो के रूप में परिभाषित किया गया है।

स्रोत : पर्यवेक्षी विवरणियां, आरबीआई।

¹¹ सकारात्मक बेमेल एक सुगम संरचनात्मक चलनिधि स्थिति को दर्शाता है, जिसे या तो नकदी प्रवाह में वृद्धि या संबंधित समयावधि में नकदी बहिर्वाह में कमी के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जबकि नकारात्मक बेमेल संबंधित समयावधि में नकदी बहिर्वाह की तुलना में नकदी अंतर्वाह की कमी की ओर संकेत करता है।

¹² एलसीआर को अगले 30 कैलेंडर दिनों में एचक्यूएलए के स्टॉक और कुल निवल नकदी बहिर्वाह के अनुपात के रूप में दर्शाया जाता है।

¹³ 5,000 करोड़ रुपये और उससे अधिक की आस्ति वाली सभी गैर-जमा स्वीकार करने वाली एनबीएफसी तथा आस्ति के आकार पर ध्यान दिए बिना सभी जमा स्वीकार करने वाली एनबीएफसी।

सारणी VI.9: एनबीएफसी क्षेत्र के वित्तीय मानदंड

(राशि ₹ करोड़ में)

मर्दे	2022-23			2023-24			छ1:2024-25		
	एनबीएफसी	एनबीएफसी-यूएल	एनबीएफसी-एमएल	एनबीएफसी	एनबीएफसी-यूएल	एनबीएफसी-एमएल	एनबीएफसी	एनबीएफसी-यूएल	एनबीएफसी-एमएल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ए. आय	4,64,021 (23.2)	1,41,310 (25.1)	3,22,712 (22.4)	5,83,957 (25.8)	1,82,115 (28.9)	4,01,842 (24.5)	3,29,583 (29.1)	1,01,219 (19.6)	2,28,365 (33.7)
बी. व्यय	3,32,638 (12.8)	1,02,181 (18.5)	2,30,457 (10.4)	4,09,765 (23.2)	1,30,395 (27.6)	2,79,370 (21.2)	2,35,161 (31.6)	71,939 (18.3)	1,63,223 (38.5)
सी. निवल लाभ	1,06,107 (72.5)	28,756 (44.3)	77,351 (86.0)	1,37,133 (29.2)	38,618 (34.3)	98,515 (27.4)	76,189 (27.0)	22,017 (24.4)	54,171 (28.1)
डी. कुल आस्तियां	43,57,119 (17.2)	10,71,050 (26.6)	32,86,069 (14.4)	50,68,607 (16.3)	13,59,521 (26.9)	37,09,086 (12.9)	54,53,592 (17.4)	13,73,785 (16)	40,79,806 (17.9)
ई. वित्तीय अनुपात (कुल आस्ति के प्रतिशत के रूप में)									
(i) आय	10.6	13.2	9.8	11.5	13.4	10.8	12.1	14.7	11.2
(ii) व्यय	7.6	9.5	7.0	8.1	9.6	7.5	8.6	10.5	8.0
(iii) निवल लाभ	2.4	2.7	2.4	2.7	2.8	2.7	2.8	3.2	2.7
एफ. आय अनुपात के प्रति लागत (प्रतिशत)*	71.7	72.3	71.4	70.2	71.6	69.5	71.4	71.1	71.5

* आय अनुपात के प्रति लागत = कुल व्यय / कुल आय।

टिप्पणियां : 1. आंकड़े अनंतिम हैं और 2024-25 के पहले अर्ध-वर्ष के लिए वित्तीय अनुपात वार्षिक कर दिए गए हैं।

2. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े प्रतिशत में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्शाते हैं।

स्रोत : पर्यवेक्षी विवरणियां, आरबीआई

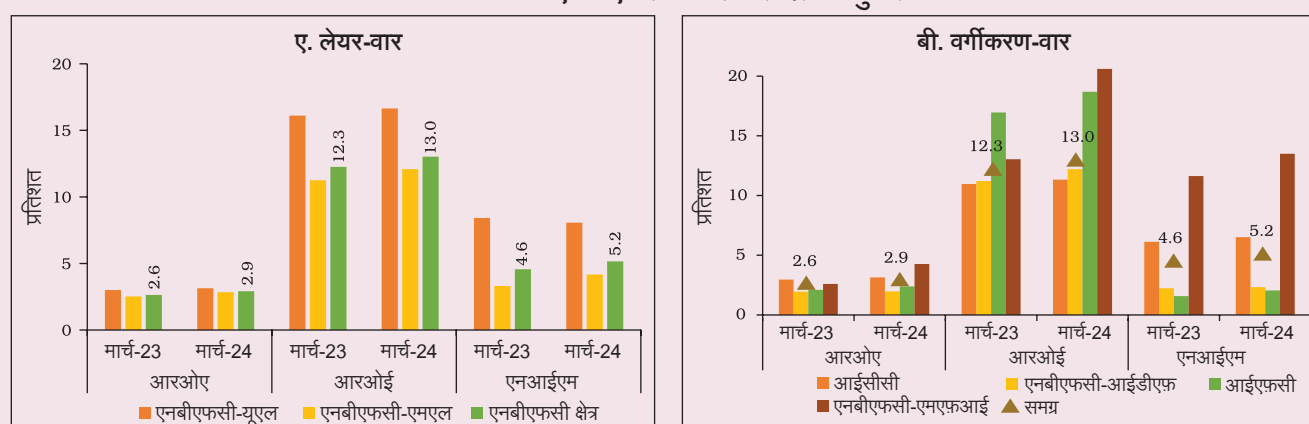
सकल आय वृद्धि 2022-23 के 23.2 प्रतिशत से बढ़कर 25.8 प्रतिशत हो गया। 2023-24 में संकलित व्यय में वृद्धि हुई, हालांकि कुल आय की तुलना में धीमी दर से। ब्याज व्यय सबसे बड़ा व्यय घटक था (मार्च 2024 के अंत में कुल का 59.0 प्रतिशत)। परिचालन व्यय के साथ अन्य वित्तपोषण लागतों ने शेष सकल व्यय में योगदान किया। आय के प्रति लागत अनुपात दोनों लेयर को प्रभावित किया, जिससे लाभप्रदता बढ़ गई। निवल लाभ में वृद्धि 2024-25 के पहले अर्ध-वर्ष में मजबूत बनी रही (सारणी VI.9 और परिशिष्ट सारणी VI.6 और VI.)।

VI.36 2023-24 के दौरान एनबीएफसी की सभी स्तरों और वर्गीकरणों में परिचालन दक्षता लाभ और प्रभावी जोखिम प्रबंधन से वित्तीय प्रदर्शन के प्रमुख संकेतक, अर्थात्, आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए) और इक्विटी पर प्रतिलाभ (आरओई) में सुधार हुआ (चार्ट VI.21)।

2.7 सुदृढ़ता संकेतक

VI.37 रिजर्व बैंक का त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) ढांचा आस्ति गुणवत्ता और पूंजी पर्याप्तता पर निगरानी योग्य

चार्ट VI.21: एनबीएफसी का लाभप्रदता अनुपात



संपत्ति पर प्रतिलाभ (आरओए) = निवल लाभ / औसत कुल आस्ति। इक्विटी पर प्रतिलाभ (आरओई) = निवल लाभ/औसत कुल इक्विटी

निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) = निवल ब्याज आय/औसत कुल आस्ति।

टिप्पणी : आंकड़े अनंतिम हैं।

स्रोत : पर्यवेक्षी विवरणियां, आरबीआई।

मैट्रिक्स के रूप में ध्यान केन्द्रित करते हुए एनबीएफसी की मजबूती और सुदृढ़ता का आकलन करता है। समग्र स्तर पर, एनबीएफसी क्षेत्र ने 2023-24 के दौरान आस्ति गुणवत्ता और पूंजी पर्याप्तता दोनों में सुधार हुआ।

2.7.1 आस्ति गुणवत्ता

VI.38 2023-24 में कुल ऋण में मानक आस्तियों की हिस्सेदारी में और वृद्धि हुई, जिससे एनबीएफसी की आस्तियों की गुणवत्ता मजबूत हो गई (चार्ट VI.22)।

VI.39 मानक आस्तियों के भीतर, ऋणों को विशेष उल्लेख खातों (एसएमए) के रूप में वर्गीकृत करते हुए ऋण खातों में प्रारंभिक दबाव की पहचान की जाती है। जबकि एसएमए-2 खातों की हिस्सेदारी कम हो गई है, एनबीएफसी को 2023-24 में एसएमए-0 और एसएमए-1 खातों के शेयरों में वृद्धि के बारे में सतर्क रहने की आवश्यकता है (चार्ट VI.23)।

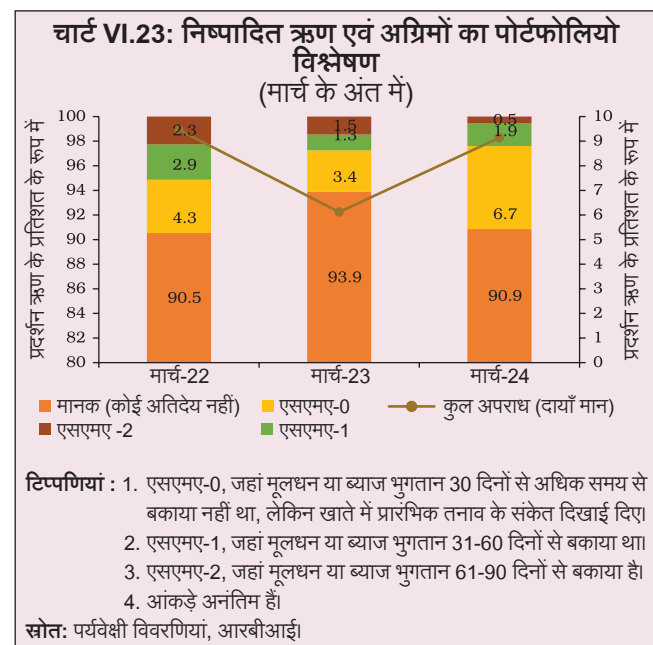
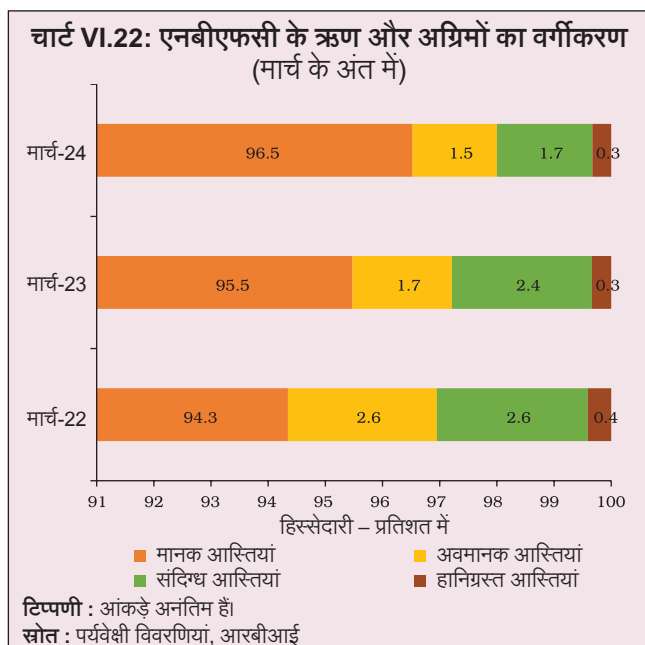
VI.40 2023-24 में एनबीएफसी की आस्ति गुणवत्ता के विभिन्न वर्गीकरणों में और सुधार हुआ, जो खराब आस्तियों के प्रभावी समाधान का संकेत देता है। एनबीएफसी ने बकाया गैर निष्पादित आस्तियों (एनपीए) के लिए भी पर्याप्त प्रावधान

बनाए रखा है [चार्ट VI.24]। यह प्रवृत्ति 2024-25 की पहली छमाही में जारी रही, जिसमें सितंबर 2024 के अंत तक सकल और निवल एनएनपीए अनुपात क्रमशः 3.4 प्रतिशत और 1.1 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।

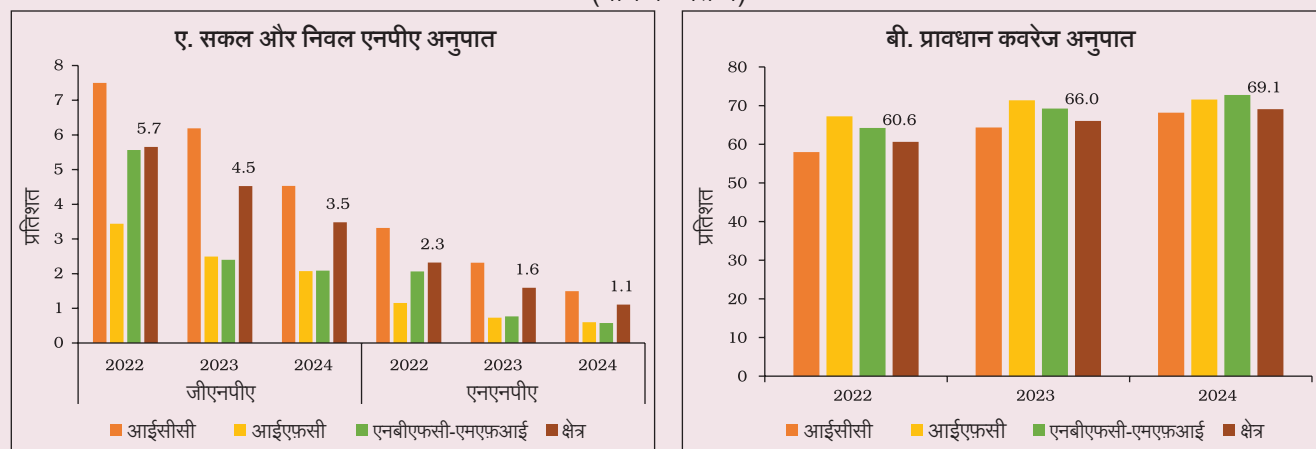
VI.41 2023-24 में एनबीएफसी-यूएल और एमएल में जीएनपीए और एनएनपीए अनुपात में गिरावट आई। उच्च प्रावधानों के कारण एनबीएफसी-एमएल का एनएनपीए अनुपात एनबीएफसी-यूएल की तुलना में कम था (चार्ट VI.25)।

VI.42 वाहन ऋण, परिवहन संचालकों और कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों की आस्ति गुणवत्ता में क्षेत्र-वार सुधार हुआ, जबकि क्रेडिट कार्ड प्राप्तियों और सोने के बदले ऋण के लिए यह मामूली रूप से कम हुआ (चार्ट VI.26)।

VI.43 2023-24 में बड़े उधार खातों (₹ 5 करोड़ और उससे अधिक का एक्सपोजर) के तहत सकल अग्रिम 14.1 प्रतिशत (पिछले वर्ष में 13.5 प्रतिशत) बढ़ गया। इन खातों की आस्ति गुणवत्ता में वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण सुधार हुआ जिससे कुल एनपीए में उनकी हिस्सेदारी कम हो गई (चार्ट VI.27)। हालांकि, बड़े उधार खातों के जीएनपीए अनुपात समग्र एनबीएफसी क्षेत्र की तुलना में अधिक था।



चार्ट VI.24: वर्गीकरण के अनुसार एनबीएफसी की आस्ति गुणवत्ता
(मार्च के अंत में)



टिप्पणी: आंकड़े अनंतिम हैं।
स्रोत: पर्यवेक्षी विवरणियां, आरबीआई

2.7.2 पूंजी पर्याप्तता

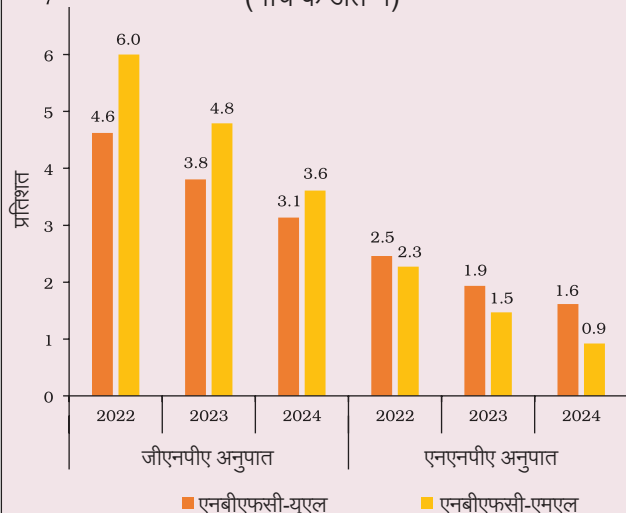
VI.44 मार्च 2024 के अंत में एनबीएफसी क्षेत्र ने पूंजी से जोखिम-भारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) 26.9 प्रतिशत बनाए रखा जो विनियामक आवश्यकता से काफी ऊपर है (चार्ट VI.28)। एसबीआर के तहत ऊपरी स्तर में एनबीएफसी [मुख्य निवेश कंपनियों को छोड़कर¹⁴ (सीआईसी)] को 15 प्रतिशत के समग्र सीआरएआर के भीतर जोखिम-भारित

आस्तियों के न्यूनतम नौ प्रतिशत की सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी (सीईटी 1) बनाए रखने की आवश्यकता होती है। सितंबर 2024 के अंत में क्षेत्र का सीआरएआर 26.1 प्रतिशत के संतोषजनक स्तर पर था।

2.8 संवेदनशील क्षेत्रों में एक्सपोजर

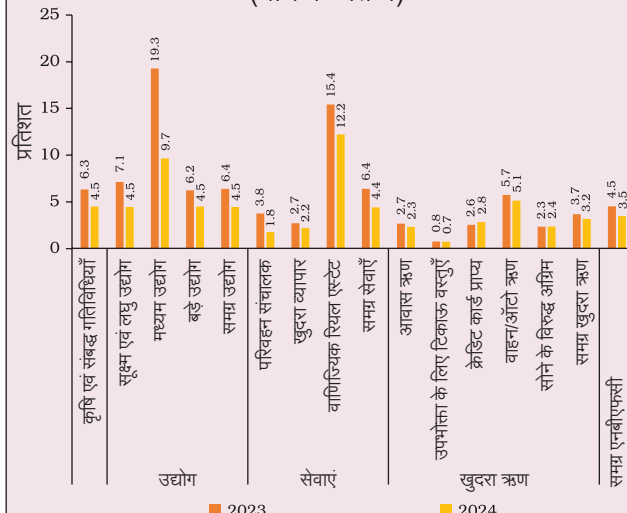
VI.45 पूंजी बाजार और वाणिज्यिक अचल संपत्ति में ऋण और निवेश में उतार-चढ़ाव की आशंका रहती है, जिसका

चार्ट VI.25: लेयर-वार एनपीए अनुपात
(मार्च के अंत में)



टिप्पणी: आंकड़े अनंतिम हैं।
स्रोत: पर्यवेक्षी विवरणियां, आरबीआई

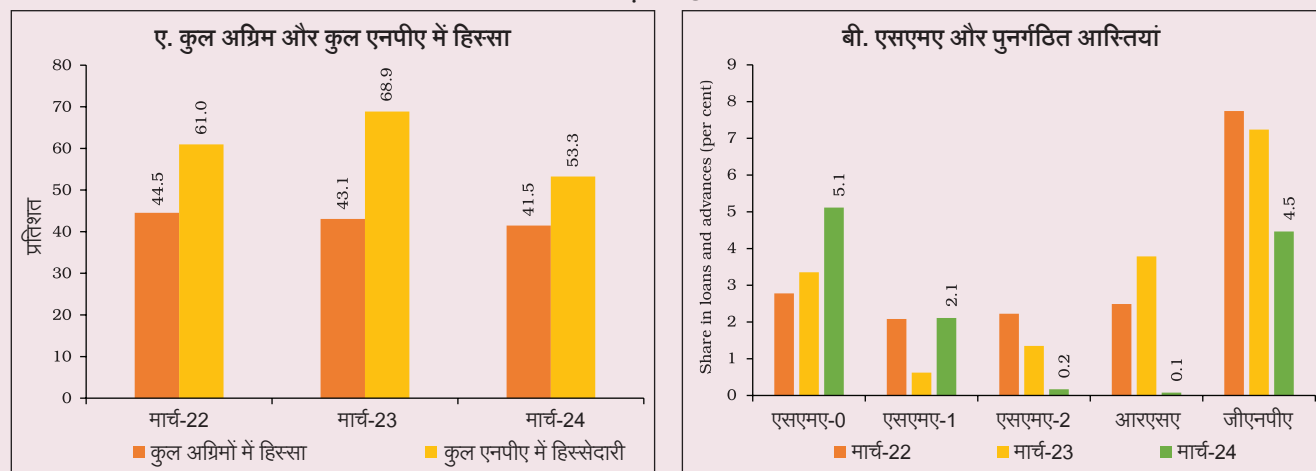
चार्ट VI.26: क्षेत्र-वार जीएनपीए अनुपात
(मार्च के अंत में)



टिप्पणी: आंकड़े अनंतिम हैं।
स्रोत: पर्यवेक्षी विवरणियां, आरबीआई

¹⁴ सीआईसी को तुलन पत्र पर अपनी कुल जोखिम भारित आस्तियों के न्यूनतम 30 प्रतिशत का समायोजित निवल मूल्य और ऑफ-तुलन पत्र मदों के जोखिम समायोजित मूल्य को बनाए रखना होगा।

चार्ट VI.27: बड़े उधार खातों में दबाव



टिप्पणी: आंकड़े अनंतिम हैं।

स्रोत: बड़े ऋणों पर सूचना का केंद्रीय भंडार (सीआरआईएलसी) डेटाबेस।

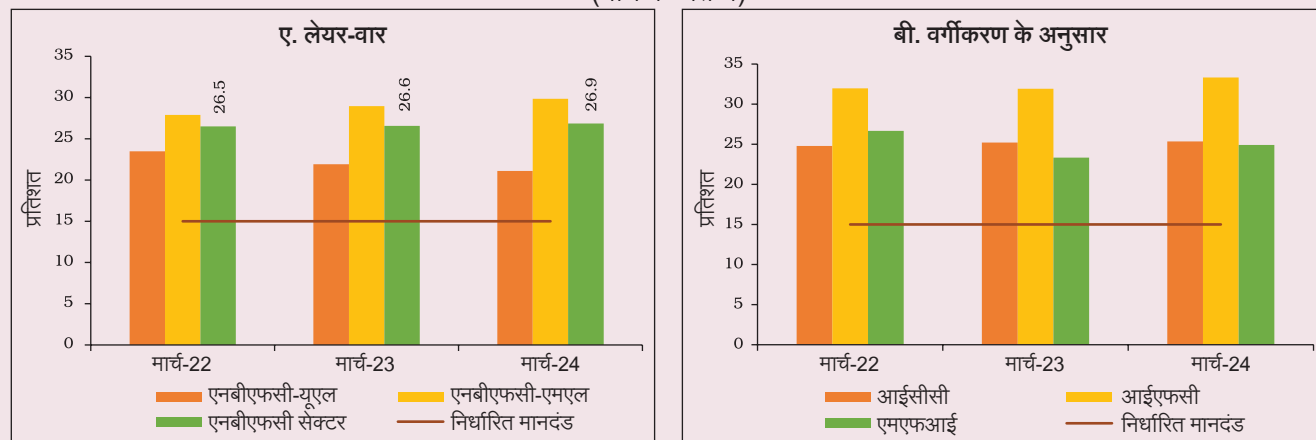
वित्तीय स्थिरता पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए इन्हें संवेदनशील क्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। मार्च 2024 के अंत में संवेदनशील क्षेत्रों में एनबीएफसी का एक्सपोजर जो मार्च 2023 के अंत में 21.2 प्रतिशत था, उनकी कुल आस्ति का 23.8 प्रतिशत हो गया, जिसका कारण पूंजी बाजार में उधार देना था (चार्ट VI.29)।

3. आवास वित्त कंपनियां (एचएफसी)

VI.46 आवास वित्त कंपनियां विशेषीकृत संस्थाएं हैं और आवास वित्त प्रदान करने में अन्य प्राथमिक ऋण देने वाले

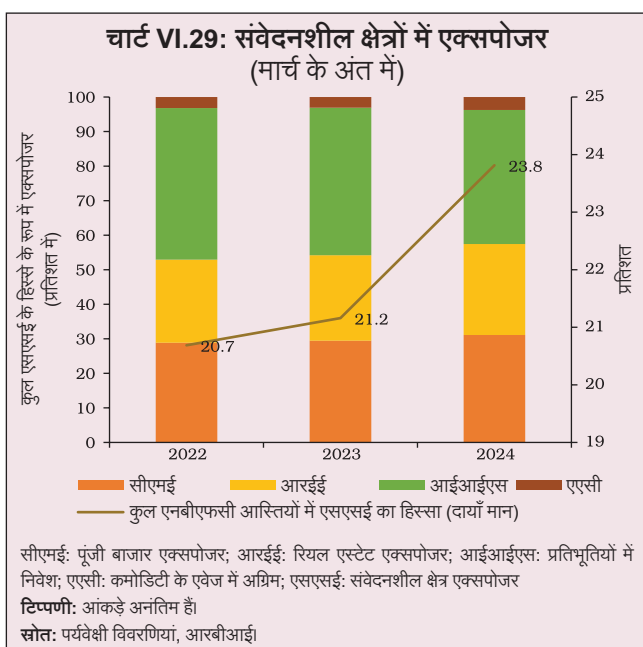
संस्थानों जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और निजी क्षेत्र के बैंकों की पूरक हैं। 09 अगस्त 2019 से प्रभावी, रिज़र्व बैंक ने एनएचबी से एचएफसी का विनियमन अपने हाथ में ले लिया। विनियामक उद्देश्यों के लिए एचएफसी को अब एनबीएफसी की श्रेणी में माना जाता है। पर्यवेक्षी जिम्मेदारियाँ और शिकायत निवारण एनएचबी के पास ही रहेगा। एसबीआर फ्रेमवर्क के तहत एचएफसी को या तो मध्य या ऊपरी लेयर में रखा जाता है। एनएचबी के पास पंजीकृत 93 आवास वित्त कंपनियों में से पांच को रिज़र्व बैंक द्वारा ऊपरी लेयर में रखा गया। 2023-24

चार्ट VI.28: एनबीएफसी का सीआरएआर (मार्च के अंत में)



टिप्पणी: आंकड़े अनंतिम हैं।

स्रोत: पर्यवेक्षी विवरणियाँ, आरबीआई



के दौरान इस क्षेत्र में एक प्रमुख विकास 1 जुलाई 2023 को एक बैंक के साथ एक बड़े एचएफसी का विलय था, जिसके परिणामस्वरूप एचएफसी की कुल आस्ति में कमी आई।

VI.47 आवास वित्त कंपनियों के विशिष्ट स्वभाव को ध्यान में रखते हुए रिज़र्व बैंक ने एचएफसी पर लागू विनियमों को सुसंगत बनाने और उन्हें चरणबद्ध तरीके से एनबीएफसी पर लागू विनियमों के अनुरूप बनाने की कोशिश की है। इसके लिए रिज़र्व बैंक ने अगस्त 2024 में संशोधित विनियम जारी किए, जो अन्य बातों के साथ-साथ पात्र एचएफसी द्वारा सार्वजनिक जमा स्वीकार करने और हेजिंग उद्देश्यों के लिए विभिन्न वित्तीय साधनों में एचएफसी की भागीदारी से संबंधित हैं (पैरा III.22)।

VI.48 एक एचएफसी सरकारी स्वामित्व वाली है, जिसकी मार्च 2024 के अंत में सेक्टर की कुल आस्ति में 8.9 प्रतिशत की हिस्सेदारी है (सारणी VI.10)। इस सरकारी स्वामित्व वाली एचएफसी ने अपनी आस्तियों में 15.6 प्रतिशत की वृद्धि

सारणी VI.10: एचएफसी के स्वामित्व का स्वरूप (मार्च के अंत में)

(राशि ₹ करोड़ में)

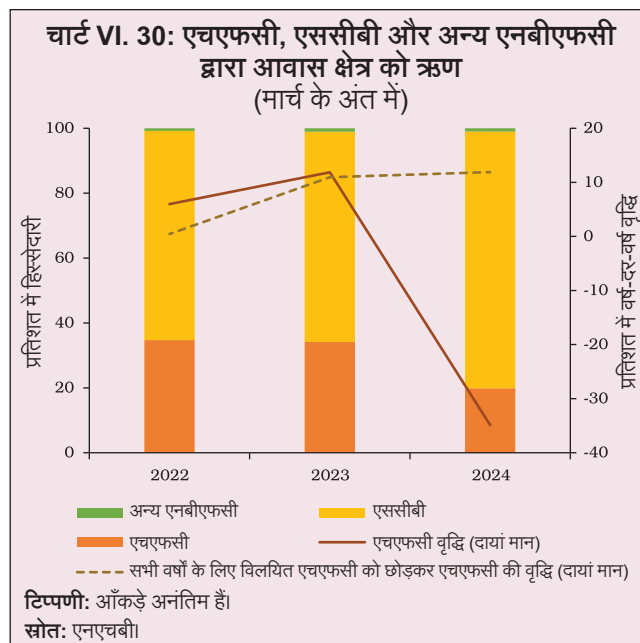
प्रकार	2023		2024	
	संख्या	आस्ति आकार	संख्या	आस्ति आकार
1	2	3	4	5
ए. सरकारी कंपनियाँ	1	83,054	1	95,990
बी. गैर-सरकारी कंपनियाँ (1+2)	96	16,04,245	92	9,78,455
1. पब्लिक लिमिटेड कंपनियाँ	74	15,95,917	71	9,66,912
(73)	(8,56,998)			
2. प्राइवेट लिमिटेड कंपनियाँ	22	8,328	21	11,542
कुल (ए+बी)	97	16,87,300	93	10,74,445
	(96)	(9,48,381)		

टिप्पणियाँ : 1. आँकड़े अनंतिम हैं।
2. 2024 के आँकड़े एचएफसी के बैंक में विलय के प्रभाव को दर्शाते हैं। 2023 के लिए कोष्ठक में दिए गए आँकड़ों में विलय की गई इकाई के आँकड़े शामिल नहीं हैं।

स्रोत: एनएचबी।

दर्ज की, जबकि बाकी एचएफसी (विलय¹⁵ के समायोजन के बाद) ने 13.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की।

VI.49 आवास क्षेत्र (बैंकों, एचएफसी और अन्य एनबीएफसी संयुक्त) के कुल ऋण में एचएफसी की हिस्सेदारी मार्च 2023 के अंत में 34.1 प्रतिशत थी; विलय के बाद मार्च 2024 के अंत में एचएफसी की हिस्सेदारी 19.9 प्रतिशत थी (चार्ट VI.30)।



¹⁵ तुलना के लिए, 2023-24 के लिए एचएफसी की वृद्धि दर की गणना वर्ष 2022-23 के लिए विलय किए गए एचएफसी को छोड़कर की गई है।

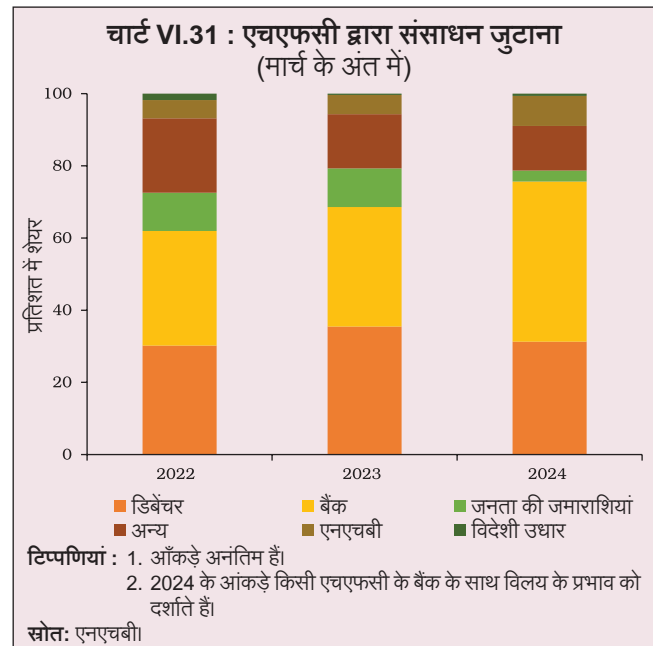
भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति संबंधी रिपोर्ट 2023-24

3.1 तुलन पत्र

VI.50 2023-24 के दौरान एचएफसी के तुलन पत्र में 13.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो मुख्य रूप से मध्यम स्तर एचएफसी द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों द्वारा संचालित है (सारणी VI.11)। देनदारियों के संदर्भ में बैंकों के माध्यम से लिया गया उधार बढ़ा, जबकि डिबेंचर के माध्यम से लिए गए उधार में कमी आई। बढ़ती आय, शहरीकरण को बढ़ावा देना और घर के स्वामित्व की बढ़ती मांग ने आवास बाजार में ऋण की मांग को बनाए रखा है। प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत सभी के लिए आवास और किफायती आवास के लिए सब्सिडीयुक्त ऋण के उद्देश्य ने भी आवास ऋण मांग को बढ़ाया है।

3.2 एचएफसी का संसाधन प्रोफाइल

VI.51 बैंकों से डिबेंचर और उधार एचएफसी के लिए धन का प्रमुख स्रोत हैं (मार्च 2024 के अंत में जुटाए गए कुल संसाधनों का 75.7 प्रतिशत) [चार्ट VI.31]।



VI.52 जमाराशि स्वीकार करने वाली आवास वित्त कंपनियों के लिए सार्वजनिक जमा राशि 2023-24 के दौरान 3.3 प्रतिशत बढ़ी (विलय के प्रभाव के लिए समायोजित), जबकि

सारणी VI.11: एचएफसी का समेकित तुलन-पत्र

(राशि ₹ करोड़ में)

प्रकार	(मार्च के अंत में) 2023			(मार्च के अंत में) 2024			मर्दान प्रतिशत घट-बढ़ (क्षेत्र)	
	एमएल	युएल	क्षेत्र	एमएल	युएल	क्षेत्र	2022-23	2023-24
1	2	3	4(2+3)	5	6	7(5+6)	8	9
1. शेयर पूंजी	13,956	28,817	42,773	14,721	30,562	45,283	6.0	6.8
2. रिजर्व एवं अधिशेष	59,570	1,95,598	2,55,168	76,540	74,324	1,50,865	13.6	24.1
3. जनता की जमाराशियां	4,903	1,30,280	1,35,183	5,076	19,689	24,764	7.9	3.3
4. डिबेंचर	42,952	4,04,211	4,47,163	59,642	1,96,411	2,56,053	25.5	10.3
5. बैंक उधारियां	1,44,893	2,73,608	4,18,501	1,86,614	1,76,984	3,63,598	11.7	17.8
6. एनएचबी से उधारियां	37,375	29,892	67,267	47,549	20,792	68,341	13.0	27.2
7. अंतर-कॉर्पोरेट उधारियां	26,085	50,430	76,516	2,577	8,833	11,411	-38.8	-67.8
8. वाणिज्यिक पत्र	4,203	57,643	61,847	10,241	20,734	30,975	23.2	58.2
9. सरकार से उधारियां	-	431	431	-	-	-	-83.3	0.0
10. गौण ऋण	4,173	10,227	14,401	4,575	6,520	11,095	-6.3	-2.7
11. अन्य उधारियां	29,168	11,397	40,565	45,448	7,231	52,680	-43.2	29.9
12. चालू देयताएं	9,326	19,113	28,439	10,784	9,304	20,088	-1.7	11.5
13. प्रावधान	4,652	26,142	30,794	6,526	13,517	20,043	-8.9	12.4
14. अन्य	6,852	61,401	68,253	4,548	14,703	19,250	264.3	-16.1
कुल देयताएं/ आस्तियां	3,88,109	12,99,191	16,87,300	4,74,841	5,99,604	10,74,445	10.5	13.3
		(5,60,272)	(9,48,381)					
1. ऋण एवं अग्रिम	3,51,770	11,06,072	14,57,842	4,36,062	5,25,390	9,61,452	9.8	14.8
2. निवेश	11,713	1,29,377	1,41,089	10,044	32,753	42,797	34.9	-3.7
3. नकद और बैंक शेष	15,098	12,597	27,695	16,480	11,006	27,486	-30.7	3.8
4. अन्य आस्तियां	9,528	51,145	60,673	12,255	30,455	42,710	11.8	6.5

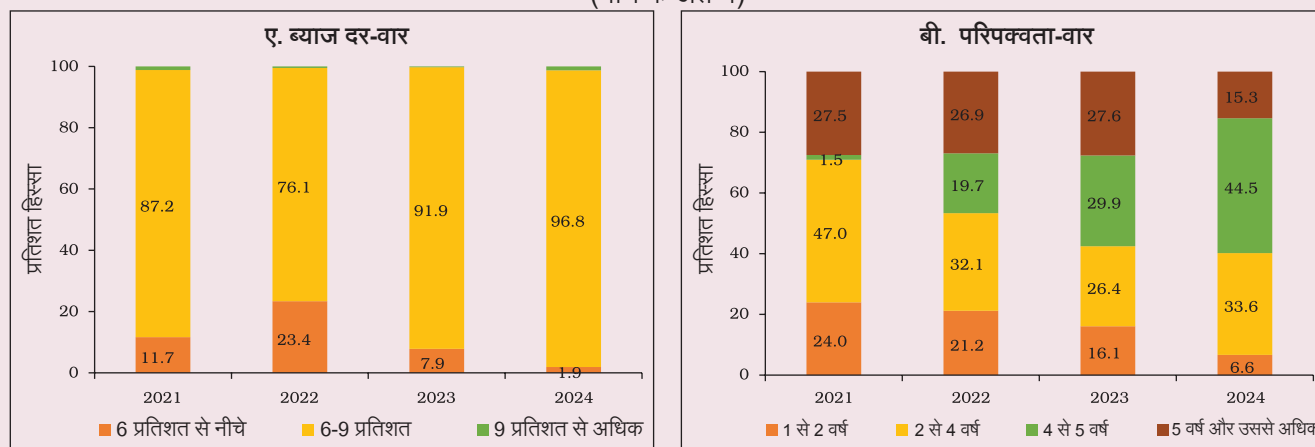
टिप्पणियां: 1. आँकड़े अनंतिम हैं।

2. 2024 के आँकड़े एचएफसी के बैंक के साथ विलय के प्रभाव को दर्शाते हैं। 2023 के लिए कोष्ठक में दिए गए आँकड़े विलय की गई इकाई के आँकड़ों को शामिल नहीं करते हैं।

3. 2023-24 के लिए विकास दर की गणना 2022-23 से विलय की गई इकाई को छोड़कर की गई है।

स्रोत: एनएचबी।

चार्ट VI.32: एचएफसी में जनता की जमाराशियों का विभाजन
(मार्च के अंत में)



टिप्पणियां : 1. आँकड़े अनंतिम हैं।
2. 2024 के आँकड़े किसी एचएफसी के बैंक के साथ विलय के प्रभाव को दर्शाते हैं।

स्रोत: एनएचबी।

पिछले वर्ष यह 7.9 प्रतिशत थी। मार्च 2024 के अंत में एचएफसी द्वारा जुटाए गए कुल संसाधनों में सार्वजनिक जमा राशि का तीन प्रतिशत था, जबकि एक साल पहले यह 10.7 प्रतिशत था, जो विलय के प्रभाव को दर्शाता है।

VI.53 जमा 6-9 प्रतिशत ब्याज दर ब्रेकेट (मार्च 2024 के अंत में 96.8 प्रतिशत जमा) में केंद्रित हैं। परिपक्वता के अनुसार 4-5 वर्ष के सेगमेंट में जमाराशियां अग्रणी हैं (चार्ट VI.32)।

3.3. वित्तीय प्रदर्शन

VI.54 2023-24 में निधि और शुल्क आय दोनों के कारण एचएफसी की आय में विस्तार हुआ। आय से मामूली रूप से अधिक व्यय बढ़ने के साथ, 2023-24 में लागत-से-आय अनुपात बढ़ गया। वर्ष के दौरान आरओए अपरिवर्तित रहा, विलय के प्रभाव के लिए समायोजित किया गया (सारणी VI.12)।

सारणी VI.12: एचएफसी के वित्तीय मानदंड

(राशि ₹ करोड़ में)

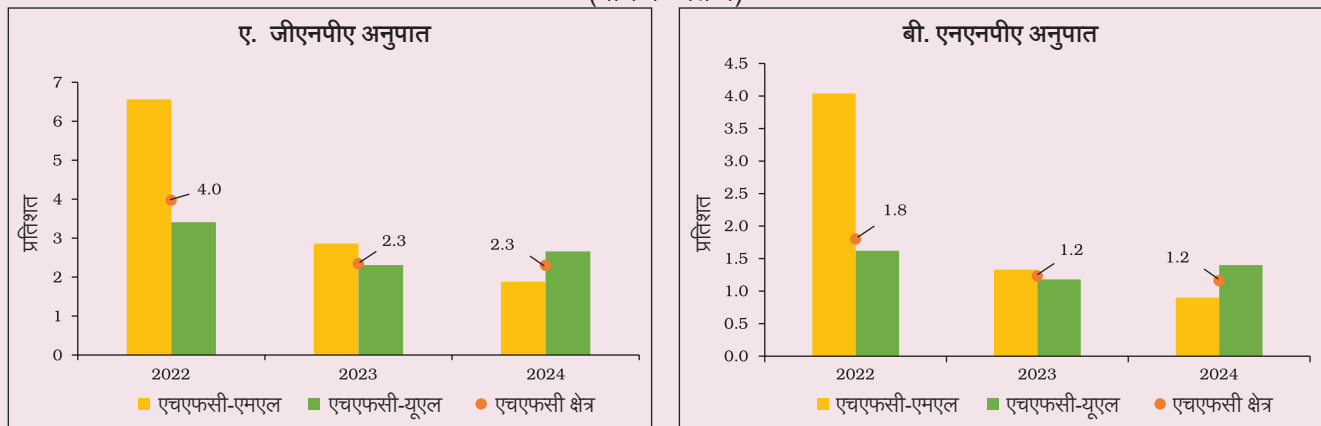
विवरण	2021-22	2022-23	2023-24	प्रतिशत भिन्नता	
				2022-23	2023-24
1	2	3	4	5	6
कुल आय	1,25,425	1,55,197	1,07,639	23.7	13.3
		(94,973)			
1. फंड आय	1,22,998	1,45,086	1,02,451	18.0	18.4
2. शुल्क आय	1,376	1,950	2,366	41.8	48.1
कुल व्यय	1,00,264	1,14,841	85,292	14.5	14.3
		(74,632)			
1. वित्तीय व्यय	74,467	87,425	61,796	17.4	19.4
2. परिचालन व्यय	10,638	13,963	14,733	31.3	24.7
कर का प्रावधान	4,766	1,798	826	-62.3	-34.2
निवल लाभ (पीएटी)	20,395	28,692	18,139	40.7	45.7
		(12,453)			
लागत-आय अनुपात	79.9	74.0	79.2		
संपत्ति पर प्रतिलाभ (आरओए)	1.3	1.7	1.7		

पीएटी = कुल व्यय - कुल व्यय + कर खर्च; लागत-आय अनुपात = कुल व्यय / कुल आय
संपत्ति पर रिटर्न (आरओए) (पीएटी/कुल आस्तियां)

टिप्पणियां: 1. आँकड़े अनंतिम हैं।
2. 2024 के आँकड़े एचएफसी के बैंक के साथ विलय के प्रभाव को दर्शाते हैं। 2022-23 के लिए कोष्ठक में दिए गए आँकड़े विलय की गई इकाई के आँकड़ों को शामिल नहीं करते हैं।
3. 2023-24 के लिए विकास दर की गणना 2022-23 से विलय की गई इकाई को छोड़कर की गई है।

स्रोत: एनएचबी।

चार्ट VI.33: लेयर-वार एचएफसी की आस्ति गुणवत्ता
(मार्च के अंत में)

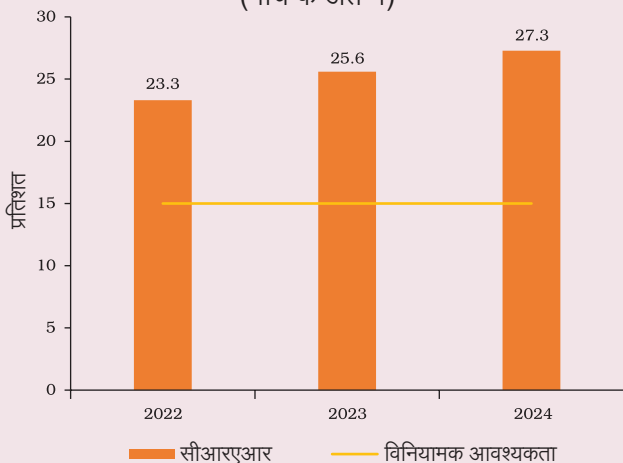


टिप्पणी: 1. आंकड़े अनंतिम हैं।
2. 2024 के आंकड़े किसी एचएफसी के बैंक के साथ विलय के प्रभाव को दर्शाते हैं।
स्रोत: एनएचबी।

3.4. सुदृढ़ता संकेतक

VI.55 2023-24 में एचएफसी की आस्ति गुणवत्ता मुख्य तौर पर स्थिर रही, जिसमें मध्य लेयर में सुधार और ऊपरी लेयर खंड में कुछ गिरावट देखी गई (चार्ट VI.33)। इस क्षेत्र के लिए सीआरएआर 15 प्रतिशत की अनिवार्य आवश्यकता से काफी ऊपर है (चार्ट VI.34)।

चार्ट VI.34: पूंजी पर्याप्तता
(मार्च के अंत में)



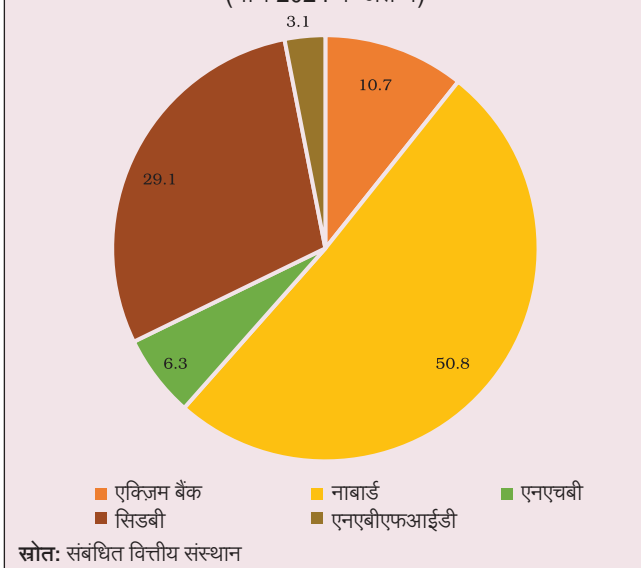
टिप्पणियां: 1. आंकड़े अनंतिम हैं।
2. 2024 के आंकड़े किसी एचएफसी के बैंक के साथ विलय के प्रभाव को दर्शाते हैं।
स्रोत: एनएचबी।

VI.56 संक्षेप में, विलय के बाद एचएफसी की आस्ति गुणवत्ता मजबूत बनी हुई है, जो दोहरे अंकों की ऋण वृद्धि करने में सहायक सिद्ध हुई है। एचएफसी द्वितीय एवं तृतीय टियर के शहरों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार कर रही हैं, जहां विकास के अवसर उपलब्ध हैं। एचएफसी के लिए विनियमनों के सामंजस्य की दिशा में हाल ही में उठाया गया कदम इस क्षेत्र के सतत विकास के लिए उत्प्रेरक का काम करेगा। आगे बढ़ते हुए, एचएफसी को भारतीय वित्तीय प्रणाली में अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए बदलते परिदृश्य के साथ तालमेल बिठाने की जरूरत है।

4. अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं

VI.57 अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं (एआईएफआई) कई क्षेत्रों की दीर्घकालिक वित्तपोषण आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मार्च 2024 के अंत में पाँच एआईएफआई (नाबार्ड, सिडबी, एनएचबी, एग्जिम बैंक और एनएबीएफआईडी) को रिजर्व बैंक द्वारा पंजीकृत, विनियमित और पर्यवेक्षित किया गया था। एक शीर्ष विकास वित्तीय संस्थान के रूप में नाबार्ड का उद्देश्य कृषि और ग्रामीण विकास को सुविधाजनक बनाना है। सिडबी को एमएसएमई क्षेत्र के प्रचार, वित्तपोषण और विकास का काम सौंपा गया है। एनएचबी

चार्ट VI.35: एआईएफआई का वितरण, आस्ति-आकार के अनुसार
(मार्च 2024 के अंत में)



हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को बढ़ावा देने और ऐसे संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली प्रमुख एजेंसी है। एगजिम बैंक का उद्देश्य निर्यातकों और आयातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करके भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना है। हाल ही में स्थापित एनएबीएफआईडी भारत में अवसंरचना क्षेत्र की दीर्घकालिक वित्तपोषण आवश्यकताओं को संबोधित करने पर केंद्रित है। नाबार्ड सबसे बड़ा एआईएफआई है, जो सभी एआईएफआई की आधी से ज़्यादा आस्तियों का योगदान करता है (चार्ट VI.35)।

4.1. एआईएफआई का परिचालन¹⁶

VI.58 एआईएफआई द्वारा स्वीकृत और वितरित वित्तीय सहायता में 2023-24 में क्रमशः 19.3 प्रतिशत और 15.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। हालांकि, एनएचबी ने वर्ष के दौरान स्वीकृत और वितरित राशि में कमी देखी, जो पहले एक बड़े एचएफसी के एक वाणिज्यिक बैंक के साथ विलय के कारण हुई थी। एनएबीएफआईडी ने, जिसने 2023-24 में अपने संचालन

सारणी VI.13: एआईएफआई द्वारा स्वीकृत एवं वितरित वित्तीय सहायता

(राशि ₹ करोड़ में)

संस्थान	प्रतिबद्ध		संवितरण	
	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24
1	2	3	4	5
एगजिम बैंक	79,764	1,06,312	68,787	89,073
नाबार्ड	3,84,319	4,42,649	3,64,832	4,36,584
एनएचबी	42,905	35,671	35,701	32,085
सिडबी	2,88,137	3,02,590	2,80,787	2,94,942
एनएबीएफआईडी	18,560	83,280	10,045	26,243
कुल	8,13,685	9,70,501	7,60,153	8,78,927

टिप्पणियाँ: 1. आंकड़े अनंतिम हैं।
2. 2023-24 के लिए एनएचबी डेटा एक एचएफसी के बैंक के साथ विलय के प्रभाव को दर्शाता है।

स्रोत: संबंधित वित्तीय संस्थान।

का पहला पूर्ण वर्ष देखा, स्वीकृतियों और संवितरण दोनों में वृद्धि दर्ज की (सारणी VI.13 और परिशिष्ट सारणी VI.8)।

4.2. तुलनपत्र

VI.59 एआईएफआई का समेकित तुलनपत्र 2023-24 में 20.1 प्रतिशत बढ़ा, जो पिछले वर्ष के 19.8 प्रतिशत से कुछ अधिक है। जबकि मुख्य रूप से सिडबी और एनएचबी द्वारा दिए गए ऋणों में मंदी के कारण ऋण और अग्रिमों में वृद्धि धीमी रही, एआईएफआई द्वारा निवेश में 31.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। देनदारियों के मामले में नाबार्ड द्वारा संचालित है बॉण्ड और डिबेंचर में 18.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसने अन्य बातों के साथ-साथ 2023-24¹⁷ में भारत का पहला एए-श्रेणांकित रुपया मूल्यवर्गीकृत सामाजिक बाण्ड जारी किया। एआईएफआई के लिए निधि के सबसे बड़े स्रोत (मार्च 2024 के अंत में सभी देनदारियों का 61.9 प्रतिशत) के रूप में 2023-24 उधार और जमाओं में मजबूत गति से वृद्धि जारी रही (सारणी VI.14)।

VI.60 सभी एआईएफआई द्वारा संसाधन जुटाने में 2023-24 में 27.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। नाबार्ड द्वारा संचालित

¹⁶ एगजिम बैंक, सिडबी, नाबार्ड और एनएबीएफआईडी के लिए वित्तीय वर्ष अप्रैल से मार्च तक है, जबकि एनएचबी के लिए यह जुलाई से जून तक है।

¹⁷ नाबार्ड ने वित्त वर्ष 2024 में इन सामाजिक बॉण्ड के ज़रिए ₹1,040.5 करोड़ जुटाए, जो भारत में पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) निवेश के लिए एक पहल है। इस निर्गम से जुटाई गई निधि का उपयोग भारत सरकार के जल जीवन मिशन के तहत पेयजल परियोजनाओं को पुनर्वित्त करने के लिए किया जाएगा।

सारणी VI.14: एआईएफआई का तुलन पत्र (मार्च के अंत में)

(राशि ₹ करोड़ में)

	2022	2023	2024	प्रतिशत भिन्नता	
				2022-23	2023-24
1	2	3	4	5	6
1. पूंजी	55,008	55,008	55,008	0.0	0.0
2. रिज़र्व	86,658	99,638	1,15,568	15.0	16.0
3. बॉण्ड और डिबेंचर	3,40,616	3,62,319	4,30,847	6.4	18.9
4. जमा	4,36,057	4,94,762	5,58,894	13.5	13.0
5. उधार	2,59,406	4,11,113	5,50,613	58.5	33.9
6. अन्य देयताएं	68,614	70,230	81,687	2.4	16.3
कुल देयताएं / आस्तियां	12,46,359	14,93,070	17,92,616	19.8	20.1
1. नकद एवं बैंक शेष	43,371	46,041	87,711	6.2	90.5
2. निवेश	1,16,334	1,00,427	1,32,375	-13.7	31.8
3. ऋण और अग्रिम	10,69,116	13,17,700	15,39,223	23.3	16.8
4. बिलों में छूट/ पुनः छूट दी गई	3,058	5,290	6,401	73.0	21.0
5. अचल आस्तियां	1,268	1,260	1,268	-0.6	0.6
6. अन्य आस्तियां	13,212	22,352	25,639	69.2	14.7

टिप्पणी : आंकड़े अनंतिम हैं।

स्रोत : संबंधित वित्तीय संस्थान।

दीर्घकालिक संसाधनों का भाग पिछले वर्ष के 37.0 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 45.1 प्रतिशत हो गया। अल्पकालिक संसाधनों पर एआईएफआई की निर्भरता 2022-23 में 58.9 प्रतिशत से घटकर 2023-24 में 51.6 प्रतिशत हो गई (सारणी VI.15)।

सारणी VI.15: 2023-24 में एआईएफआई द्वारा जुटाए गए संसाधन

(राशि ₹ करोड़ में)

संस्थाएं	जुटाए गए कुल संसाधन				कुल बकाया
	दीर्घकालिक	अल्पावधिक	विदेशी मुद्रा	कुल	
1	2	3	4	5	6
एकिज्म बैंक	11,300	37,093	29,042	77,434	1,54,611
नाबार्ड	2,13,832	2,25,343	0	4,39,175	7,60,865
एनएचबी*	25,504	9,200	0	34,704	94,407
सिडबी**	1,23,340	1,85,818	0	3,09,158	4,76,978
एनएबीएफआईडी	25,219	0	0	25,219	25,219
कुल	3,99,195	4,57,454	29,042	8,85,690	15,12,079

* अल्पकालिक प्रणाली आंकड़ा रोल-ओवर आधार पर ओवरनाइट त्रिपक्षीय रेपो डीलिंग और सेटलमेंट (टीआरईपीएस) में लेनदेन के माध्यम से उधार को दर्शाता है (रोल-ओवर आधार पर सकल राशि)।

** जुटाए गए कुल संसाधनों में अल्पावधि में बैंकों से लिए गए अल्पावधि ऋण भी शामिल हैं।

टिप्पणी: दीर्घावधि रुपया संसाधन में बॉण्ड/डिबेंचर के माध्यम से जुटाई गई उधारियाँ शामिल हैं; जबकि अल्पकालिक संसाधनों में सीपी, सावधि जमा, आईसीडी, सीडी और सावधि मुद्रा बाजार से उधार शामिल हैं। विदेशी मुद्रा संसाधनों में बड़े पैमाने पर अंतरराष्ट्रीय बाजार में बॉण्ड जारी करके उधार शामिल हैं।

स्रोत : संबंधित वित्तीय संस्थान।

VI.61 मार्च 2024 के अंत तक एआईएफआई द्वारा मुद्रा बाजार से जुटाए गए संसाधनों में वाणिज्यिक पत्र (सीपी) के माध्यम से उधारी का हिस्सा 56.1 प्रतिशत था। जबकि 2023-24 में एकिज्म बैंक, नाबार्ड और एनएचबी के सीपी जारी करने में वृद्धि हुई, सिडबी में गिरावट दर्ज की गई। एआईएफआई एक निर्दिष्ट सीमा के आधार पर मुद्रा बाजार से संसाधन जुटाते हैं, जो उनके निवल स्वामित्व वाली निधि (एनओएफ) से जुड़ा होता है। इस सीमा का उपयोग 2023-24 में बढ़कर 65.3 प्रतिशत हो गया, जो एक साल पहले 63.9 प्रतिशत था (सारणी VI.16)।

4.3. निधियों के स्रोत और उपयोग

VI.62 2023-24 में, एआईएफआई द्वारा जुटाए गए और उपयोग की गई निधि में 52.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। सिडबी के उधार (लगातार दूसरे वर्ष 100 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि) के कारण प्रमुख स्रोत के रूप में बाहरी स्रोतों ने आंतरिक निधियों का स्थान ले लिया। 2023-24 में, जुटाई गई निधि का लगभग तीन-चौथाई हिस्सा पिछले उधारों को चुकाने में इस्तेमाल किया गया (सारणी VI.17)

सारणी VI.16: एआईएफआई द्वारा मुद्रा बाजार से जुटाए गए संसाधन (मार्च के अंत में) #

(राशि ₹ करोड़ में)

	2022-23	2023-24	प्रतिशत भिन्नता
1	2	3	4
लिखत			
ए. कुल	1,54,707	1,79,181	15.8
i) सावधि जमा	8,709	12,632	45.0
ii) टर्म मनी	1,942	2,508	29.1
iii) अंतर-कॉरपोरेट जमा	-	-	-
iv) जमा प्रमाणपत्र	49,560	63,595	28.3
v) वाणिज्यिक पत्र	94,496	1,00,446	6.3
मेमो:			
बी. समावेशक सीमा [^]	2,42,208	2,74,407	13.3
सी. समावेशक सीमा का उपयोग (प्रतिशत के रूप में ए बी)	63.9	65.3	-

एनएचबी के लिए जून के अंत तक।

[^] बोर्ड द्वारा खातों को अपनाने के बाद

टिप्पणी: यह समावेशक सीमा पांच लिखतों पर लागू है - सावधि जमा; सावधि निधि उधार; जमा प्रमाणपत्र (सीडी); वाणिज्यिक पत्र (सीपी); तथा अंतर-कॉरपोरेट जमा।

स्रोत: संबंधित वित्तीय संस्थान।

4.4. परिपक्वता प्रोफाइल और उधार की लागत

VI.63 सभी एआईएफआई द्वारा जुटाए गए रुपये के संसाधनों की भारित औसत लागत 2023-24 में और बढ़ गई (चार्ट VI.36ए)। सभी एआईएफआई में, एनएबीएफआईडी द्वारा जुटाए गए संसाधनों की भारित औसत परिपक्वता सबसे अधिक थी, क्योंकि इसका ध्यान बुनियादी ढाँचे के वित्तपोषण

सारणी VI.17: एआईएफआई के स्रोत और निधियों के परिनियोजन का विनियोजन

(राशि ₹ करोड़ में)

Items	2022-23	2023-24	प्रतिशत भिन्नता
1	2	3	4
ए. निधि के स्रोत (i+ii+iii)	57,92,482	88,34,046	52.5
i. आंतरिक	34,74,360	39,25,315	13.0
ii. बाह्य	22,48,393	48,09,252	113.9
iii. अन्य [@]	69,729	99,479	42.7
बी. निधियों का विनियोजन (i+ii+iii)	57,92,482	88,34,046	52.5
i. नया अभियोजन	15,33,679	15,75,117	2.7
ii. पिछले उधारियों का पुनर्भुगतान	35,62,866	63,64,347	78.6
iii. अन्य अभियोजन	6,95,937	8,94,581	28.5
जिनमें से: ब्याज भुगतान	52,845	72,978	38.1

@: बैंकों और भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी और शेष राशि शामिल है।

टिप्पणी: आंकड़े अनंतिम हैं।

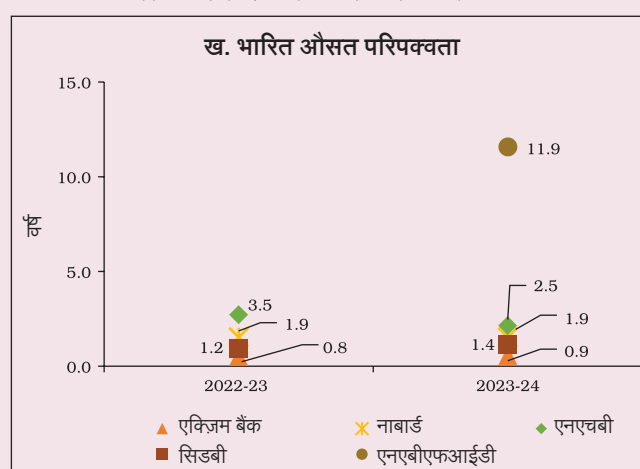
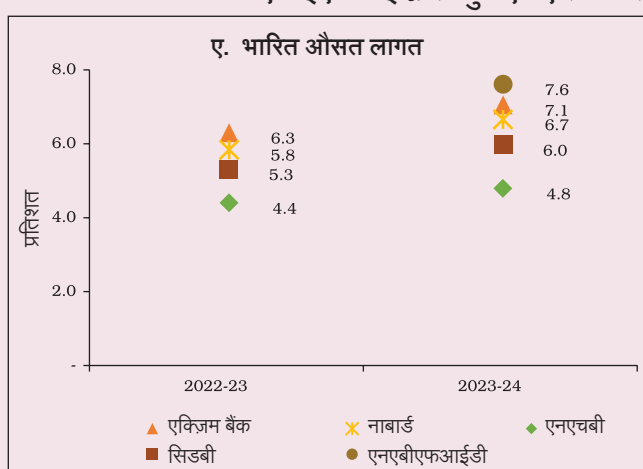
स्रोत: संबंधित वित्तीय संस्थान।

पर था (चार्ट VI.36बी)। एक्जिम बैंक और एनएचबी के लिए दीर्घकालिक प्रमुख उधार दरों (पीएलआर) में वृद्धि हुई, जबकि वे सिडबी और एनएबीएफआईडी के लिए स्थिर रहीं (चार्ट VI.37)।

4.5. वित्तीय प्रदर्शन

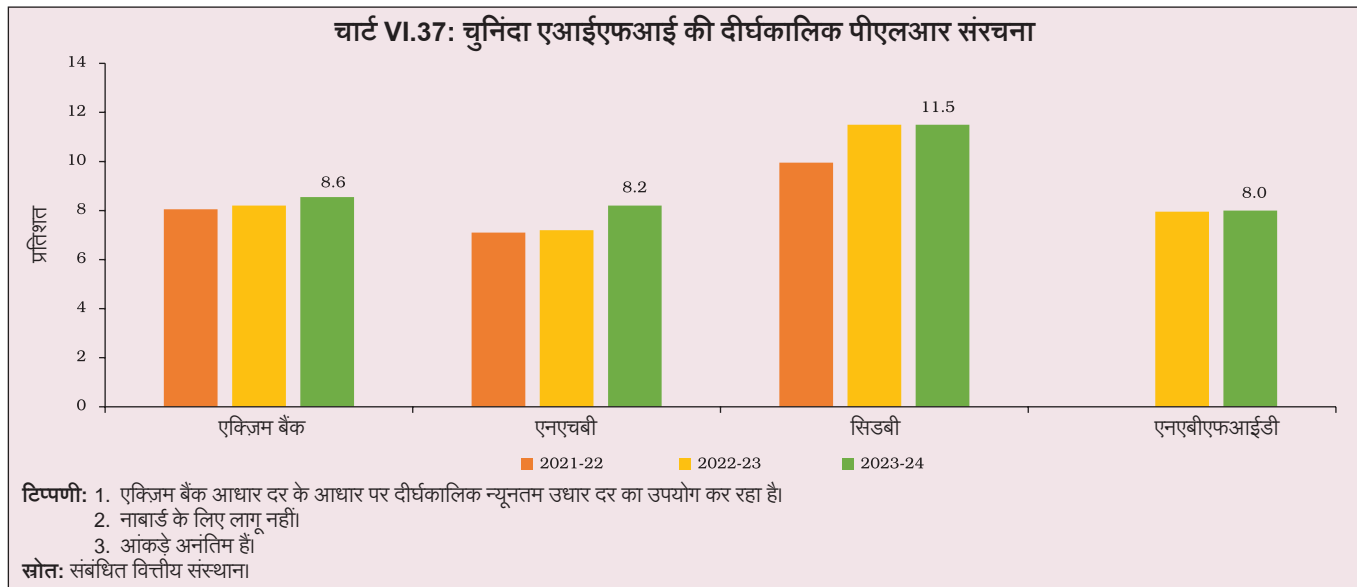
VI.64 एआईएफआई की आय 2023-24 में निरंतर बढ़ी, जोकि विशेष रूप से नाबार्ड और सिडबी की ब्याज आय से बढ़ी। व्यय पक्ष पर, नाबार्ड और सिडबी के कारण आईएफआई के ब्याज व्यय की वृद्धि में तेजी आई। एआईएफआई ने वर्ष के

चार्ट VI.36: एआईएफआई द्वारा जुटाए गए रुपया संसाधनों की भारित औसत लागत और परिपक्वता



टिप्पणी: आंकड़े अनंतिम हैं।

स्रोत: संबंधित वित्तीय संस्थान।



दौरान परिचालन लाभ और निवल लाभ में भी स्थिर वृद्धि दर्ज की (सारणी VI.18)।

VI.65 2023-24 के दौरान सभी एआईएफआई के लिए औसत कार्यशील निधियों में ब्याज आय का अनुपात बेहतर हुआ। एक्जिम बैंक, सिडबी और एनएबीएफआईडी के लिए औसत कार्यशील निधियों के अनुपात के रूप में परिचालन लाभ में गिरावट आई (सारणी VI.19)।

सारणी VI.18: एआईएफआईएस का वित्तीय प्रदर्शन

(राशि ₹ करोड़ में)

	2021-22	2022-23	2023-24	प्रतिशत भिन्नता	
				2022-23	2023-24
1	2	3	4	5	6
ए) आय	59,145	75,411	1,05,875	27.5	40.4
ए) ब्याज आय	57,666	73,982	1,04,276	28.3	40.9
बी) गैर-ब्याज आय	1,479	1,429	1,599	-3.4	11.9
बी) व्यय	43,674	56,679	82,396	29.8	45.4
ए) ब्याज व्यय	40,281	53,353	76,395	32.5	43.2
बी) परिचालन व्यय	3,393	3,326	6,001	-2.0	80.5
जिसमें से वेज बिल	2,269	1,991	3,914	-12.3	96.6
सी) कराधान के लिए प्रावधान	4,064	3,230	4,631	-20.5	43.4
डी) लाभ					
परिचालन लाभ (पीबीटी)	14,862	17,347	21,059	16.7	21.4
निवल लाभ (पीएटी)	9,817	12,568	15,913	28.0	26.6

टिप्पणी: आंकड़े अनंतिम हैं।

स्रोत: संबंधित वित्तीय संस्थान।

VI.66 एक्जिम बैंक, नाबार्ड और एनएचबी की लाभप्रदता, जैसा कि उनकी आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए) में परिलक्षित होता है, 2023-24 में बेहतर हुई (चार्ट VI.38)।

4.6. सुदृढ़ता संकेतक

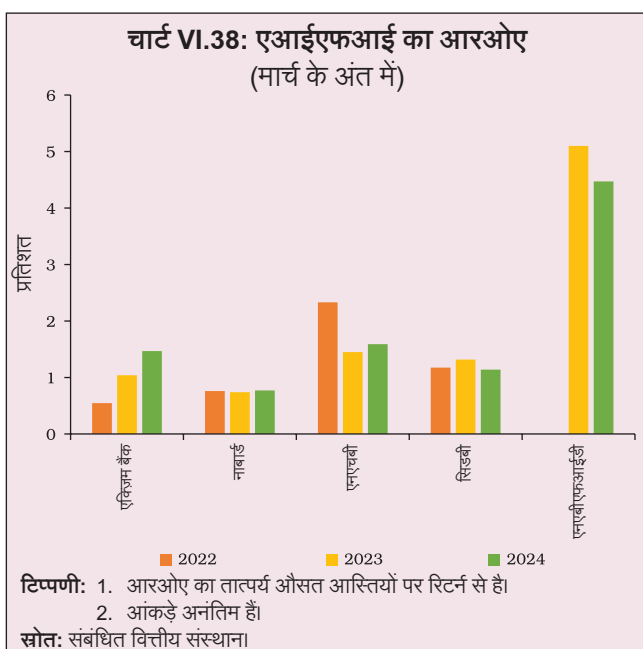
VI.67 विभिन्न क्षेत्रों में ऋण प्रवाह को बढ़ावा देने में एआईएफआई द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए, रिजर्व बैंक ने अप्रैल 2024 से एआईएफआई के लिए बेसल III पूंजी ढांचे की सीमा को बढ़ा दिया है। मार्च 2024 के अंत में, सभी एआईएफआई की पूंजी स्थिति बेहतर रही, सीआरएआर विनियामक आवश्यकता से काफी ऊपर था (चार्ट VI.39ए)। मार्च 2024 के अंत में, एक्जिम बैंक को छोड़कर, एआईएफआई की लगभग सभी आस्तियां मानक थीं,

सारणी VI.19: एआईएफआई के चुनिंदा वित्तीय मानदंड

	औसत कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में						निवल लाभ प्रति कर्मचारी (₹ करोड़ में)	
	ब्याज आय		गैर-ब्याज आय		परिचालन लाभ		2023	2024
	2023	2024	2023	2024	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
एक्जिम	7.8	9.0	0.4	0.3	2.6	2.3	4.3	7.1
नाबार्ड	5.4	6.1	0.03	0.01	1.0	1.1	1.7	1.9
एनएचबी	5.6	6.2	0.2	0.1	2.0	2.3	6.3	7.8
सिडबी	5.4	6.7	0.2	0.1	1.6	1.5	3.2	3.7
एनएबीएफआईडी	5.3	7.9	0.02	0.7	5.2	4.8	23.3	19.8

टिप्पणी: आंकड़े अनंतिम हैं।

स्रोत: संबंधित वित्तीय संस्थान।



जिनकी संदिग्ध आस्तियां 2023-24 के दौरान थोड़ी बढ़ गई थी। एक्विजम बैंक को छोड़कर सभी एआईएफआई का निवल एनपीए अनुपात शून्य था (चार्ट VI.39बी)।

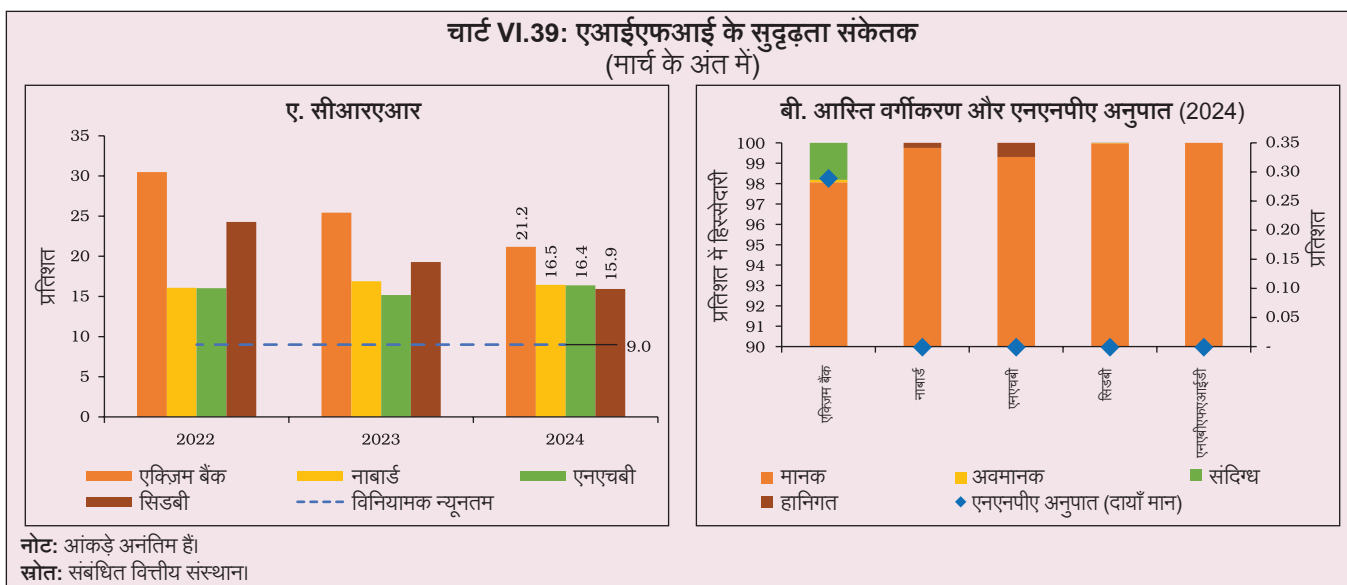
5. प्राथमिक व्यापारी

VI.68 मार्च 2024 की समाप्ति तक 21 प्राथमिक डीलर (पीडी) थे, 14 विभागीय रूप से बैंक पीडी के रूप में और 7 स्टैंडअलोन पीडी (एसपीडी) के रूप में कार्य कर रहे थे। ये

सभी आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45 आईए के तहत एनबीएफसी के रूप में पंजीकृत थे।

5.1. पीडी का संचालन और प्रदर्शन

VI.69 पीडी को केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों के निर्गमों की हामीदारी करने और प्राथमिक नीलामी में भाग लेने का अधिकार है। उन्हें अर्ध-वार्षिक आधार पर मूल्यांकन किए गए ट्रेजरी बिल (टी-बिल) और मुद्रा प्रबंधन बिल (सीएमबी) की प्राथमिक नीलामी में 40 प्रतिशत का न्यूनतम सफलता अनुपात (बोली प्रतिबद्धता के अनुपात के रूप में स्वीकार की गई बोलियाँ) प्राप्त करना भी अनिवार्य है। वर्ष 2023-24 में, सभी प्राथमिक व्यापारियों ने अपनी न्यूनतम बोली प्रतिबद्धताओं से अधिक हासिल किया और वर्ष के दौरान जारी किए गए टी-बिलों की कुल मात्रा का 69.6 प्रतिशत हिस्सा प्राप्त किया, जो पिछले वर्ष में प्राप्त 68.9 प्रतिशत से थोड़ा अधिक है। 2024-25 में (सितंबर 2024 तक), जारी किए गए टी-बिलों की कुल मात्रा में प्राथमिक व्यापारियों की हिस्सेदारी 76.4 प्रतिशत थी। दिनांकित प्रतिभूतियों के प्राथमिक निर्गम में आवंटन में प्राथमिक व्यापारियों की हिस्सेदारी 2022-23 में 56.6 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 63.5 प्रतिशत हो गई। यह 2024-25 की पहली छमाही में और बढ़कर 67.0 प्रतिशत हो गई (सारणी VI.20)।



सारणी VI.20: प्राथमिक बाजार में पीडी का प्रदर्शन

(राशि ₹ करोड़ में)

मर्दे	2021-22	2022-23	2023-24	छ1:2024-25
1	2	3	4	5
ट्रेजरी बिल और सीएमबीएस				
(ए) बोली प्रतिबद्धता	15,37,735	16,27,045	16,40,785	5,50,745
(बी) प्रस्तुत वास्तविक बोलियां	37,21,906	36,47,564	35,46,730	13,18,661
(सी) बोलियां स्वीकृत	9,59,380	9,74,028	9,96,891	3,67,511
(डी) सफलता अनुपात (सी) / (ए) (प्रतिशत में)	62.4	59.9	60.8	66.7
(ई) कुल आबंटन में प्राथमिक पीडी का हिस्सा (प्रतिशत में)	76.9	68.9	69.6	76.4
केंद्र सरकार दिनांकित प्रतिभूतियाँ				
(एफ) अधिसूचित राशि	10,80,000	14,37,000	15,43,000	7,50,000
(जी) प्रस्तुत वास्तविक बोलियां	22,22,924	25,55,668	29,79,456	17,23,480
(एच) पीडी की स्वीकृत बोलियाँ	5,33,201	8,03,600	9,79,036	4,95,320
(आई) पीडी का हिस्सा (एच)/(एफ) (प्रतिशत में)*	47.3	56.6	63.5	67.0

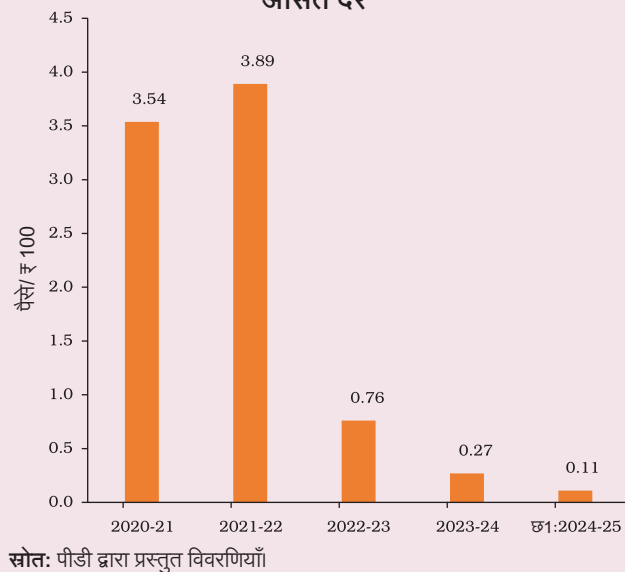
टिप्पणी: 1. आंकड़े अनंतिम हैं।
2. *कुल जारी राशि के संबंध में गणना की गई।

स्रोत: पीडी द्वारा प्रस्तुत विवरण।

VI.70 2023-24 के दौरान पीडी (जीएसटी को छोड़कर) को दिया गया हामीदारी कमीशन ₹41.1 करोड़ था, जबकि पिछले वर्ष यह ₹91.1 करोड़ था; यह 2024-25 की पहली छमाही में ₹8.34 करोड़ था। हामीदारी कमीशन की औसत दर 2022-23 में ₹0.76 पैसे/₹100 से घटकर 2023-24 में ₹0.27 पैसे/₹100 और फिर 2024-25 (सितंबर 2024 तक) में ₹0.11 पैसे हो गई (चार्ट VI.40)।

VI.71 द्वितीयक बाजार में प्राथमिक व्यापारियों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले कारोबार का लक्ष्य, सरकारी प्रतिभूतियों और टी-बिलों में पिछले तीन वर्षों के कुल बाजार कारोबार के औसत के एक विशिष्ट प्रतिशत के रूप में निर्धारित किया गया है, जिसे समग्र आधार पर लिया गया है। तदनुसार, 2022-23 के लिए एक प्रतिशत की तुलना में 2023-24 के लिए लक्ष्य 1.5 प्रतिशत तय किया गया था। सभी प्राथमिक व्यापारियों ने व्यक्तिगत रूप से न्यूनतम निर्धारित वार्षिक टर्नओवर अनुपात हासिल किया। 2024-25 के लिए लक्ष्य दो प्रतिशत तय किया गया है।

चार्ट VI 40: पीडी के हामीदारी आदत की औसत दर



स्रोत: पीडी द्वारा प्रस्तुत विवरण।

5.2. स्टैंडअलोन प्राथमिक व्यापारियों का प्रदर्शन

VI.72 प्राथमिक व्यापारियों के टर्नओवर में हामीदारी और रेपो दोनों खंडों में वृद्धि हुई, जिसके परिणामस्वरूप द्वितीयक बाजार टर्नओवर में उनके समग्र हिस्से में वृद्धि हुई (सारणी VI.21)।

सारणी VI.21: जी-सेक द्वितीयक बाजार में एसपीडी का प्रदर्शन

(राशि ₹ करोड़ में)

मर्दे	2021-22	2022-23	2023-24	छ1:2024-25
1	2	3	4	5
एकमुश्त				
एसपीडी कारोबार	25,91,788	36,02,796	51,02,936	29,60,959
बाजार कारोबार	87,98,428	1,01,21,207	1,34,32,806	82,45,716
एसपीडी का हिस्सा (प्रतिशत में)	29.5	35.6	38.0	35.9
रेपो				
एसपीडी कारोबार	95,60,700	1,32,57,623	1,87,85,160	99,25,332
बाजार कारोबार	2,55,25,641	3,40,48,195	3,83,50,154	1,95,81,992
एसपीडी का हिस्सा (प्रतिशत में)	37.5	38.9	49	50.7
कुल (एकमुश्त + रेपो)				
एसपीडी कुल कारोबार	1,21,52,488	1,68,60,419	2,38,88,096	1,28,86,291
बाजार कारोबार	3,43,24,069	4,41,69,402	5,17,82,961	2,78,27,709
एसपीडी का हिस्सा (प्रतिशत में)	35.4	38.2	46.1	46.3

टिप्पणी: 1. आंकड़े अनंतिम हैं।
2. बाजार सहभागियों / एकल पीडी के लिए कुल कारोबार में एकमुश्त और रेपो प्रथम चरण के निपटान की मात्रा शामिल है।

स्रोत: सीसीआईएल।

सारणी VI.22 : एसपीडी निधियों के स्रोत और उपयोग

(राशि ₹ करोड़ में)

	2021-22	2022-23	2023-24	छ1:2024-25	2023-24 की तुलना में 2023-24 में प्रतिशत भिन्नता
1	2	3	4	5	6
निधियों का स्रोत	86,670	1,25,165	1,58,667	1,59,108	26.8
1. पूंजी	1,849	2,368	2,368	2,512	0.0
2. रिजर्व और अधिशेष	7,426	9,724	11,243	12,738	15.6
3. ऋण (ए+बी)*	77,394	1,13,074	1,45,057	1,43,857	28.3
(ए) प्रत्याभूत	61,188	96,432	1,25,026	1,23,944	29.7
(बी) अप्रत्याभूत	16,207	16,643	20,031	19,913	20.4
निधियों का उपयोग	86,670	1,25,165	1,58,667	1,59,108	26.8
1. अचल आस्तियां	70	91	104	100	14.3
2. एचटीएम निवेश (ए+बी)	3,937	6,273	5,151	7,035	-17.9
(ए) सरकारी प्रतिभूतियाँ	3,755	6,082	4,904	6,781	-19.4
(बी) अन्य	182	191	248	254	29.8
3. चालू आस्तियां	79,861	1,18,397	1,54,122	1,51,329	30.2
4. ऋण और अग्रिम	6,753	4,839	4,526	9,135	-6.5
5. चालू देयताएँ	3,900	4,377	5,077	8,341	16.0
6. आस्थगित कर	-44	-48	-141	-133	193.8
टिप्पणी: 1. आंकड़े अनंतिम हैं। 2. * एसपीडी का बकाया उधारा					
स्रोत: एसपीडी द्वारा प्रस्तुत विवरणियाँ					

5.3. एसपीडी के निधि के स्रोत और अनुप्रयोग

VI.73 एसपीडी द्वारा जुटाई गई निधियों में 2023-24 में 26.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसमें प्रतिभूत उधार (कुल का 78.8 प्रतिशत) का योगदान अधिक रहा। चालू आस्तियों (एसपीडी की आस्तियों का 97.1 प्रतिशत) में वर्ष के दौरान 30.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई (सारणी VI.22)।

5.4. एसपीडी का वित्तीय प्रदर्शन

VI.74 उच्च ब्याज और छूट आय के कारण एसपीडी की लाभप्रदता में 2023-24 में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया। पिछले दो लगातार वर्षों में घाटा दर्ज करने के बाद एसपीडी ने 2023-24 में व्यापार लाभ अर्जित किया (सारणी VI.23)। परिणामस्वरूप, 2023-24 में उनकी आस्तियों पर प्रतिलाभ

सारणी VI.23: एसपीडी का वित्तीय प्रदर्शन

(राशि ₹ करोड़ में)

मर्दे	2021-22	2022-23	2023-24	छ1:2024-25	2023-24 में 2022-23 की तुलना में भिन्नता	
1	2	3	4	5	मात्रा	प्रतिशत
6	7					
ए. आय (i से iii)	4,030	5,382	10,270	6,221	4,888	90.8
(i) ब्याज और बट्टा	4,143	5,816	9,158	5,468	3,342	57.5
(ii) कारोबारी लाभ	-224	-495	1,060	701	1,555	-314.1
(iii) अन्य आय	112	61	52	51	-9	-14.8
बी. व्यय (i से ii)	2,625	5,074	8,422	4,949	3,348	66.0
(i) ब्याज	2,238	4,664	7,897	4,666	3,233	69.3
(ii) स्थापना और प्रशासनिक लागत सहित अन्य व्यय	386	410	524	282	115	28.0
सी. कर पूर्व लाभ	1,254	485	2,237	1,751	1,752	361.6
डी. कर पश्चात लाभ	942	342	1,663	1,308	1,321	385.9
टिप्पणी: 1. आंकड़े अनंतिम हैं। 2. पूर्णांकन के कारण आंकड़ों का जोड़ शामिल हो सकता है।						
स्रोत: पीडी द्वारा प्रस्तुत विवरणियाँ						

सारणी VI.24: एसपीडी के वित्तीय संकेतक

(राशि ₹ करोड़ में)

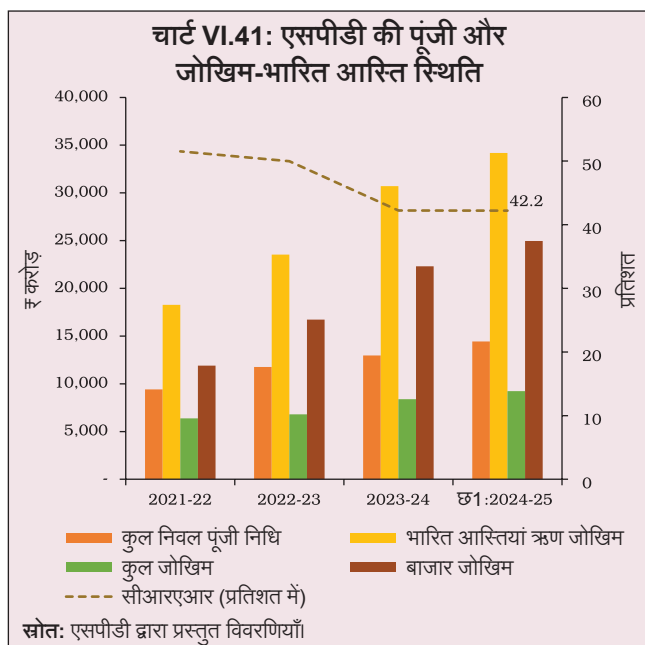
संकेतक	2021-22	2022-23	2023-24	छ1:2024-25
1	2	3	4	5
(i) निवल लाभ	942	342	1,663	1,308
(ii) औसत आस्तियाँ	79,068	1,01,642	1,40,388	1,58,257
(iii) औसत आस्तियों पर प्रतिलाभ (प्रतिशत)	1.2	0.3	1.2	0.8
(iv) निवल मालियत पर प्रतिलाभ (प्रतिशत)	10.5	3.2	12.9	9.1
(v) आय लागत अनुपात (प्रतिशत)	21.6	57.1	22.1	18.2

टिप्पणी: आंकड़े अनंतिम हैं।

स्रोत: एसपीडी द्वारा प्रस्तुत विवरणियाँ।

और निवल मालियत पर प्रतिलाभ में वृद्धि हुई। 2024-25 की पहली छमाही में, उनकी आस्तियों पर प्रतिलाभ और निवल आस्तित्व पर प्रतिलाभ में गिरावट आई, यद्यपि कि उनकी लागत-से-आय अनुपात में भी कमी आई (सारणी VI.24 और परिशिष्ट सारणी VI.9)।

VI.75 एसपीडी का संयुक्त सीआरएआर 2022-23 में 50 प्रतिशत से घटकर 2023-24 में 42.2 प्रतिशत हो



गया, जो एसपीडी की जोखिम-भारित आस्तियों में वृद्धि के कारण हुआ। सभी एसपीडी का सीआरएआर 15 प्रतिशत के निर्धारित मानदंड से ऊपर रहा (चार्ट VI.41 और परिशिष्ट सारणी VI.10)।

6. समग्र मूल्यांकन

VI.76 2023-24 के दौरान, एनबीएफसी क्षेत्र निरंतर दोहरे अंकों के तुलन-पत्र वृद्धि के साथ मजबूत रहा। घरेलू ऋण मध्यस्थता में एनबीएफसी का महत्व बढ़ रहा है। फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट गारंटी (एफएलडीजी) फ्रेमवर्क और को- लेंडिंग मॉडल जैसे नवोन्मेषी दृष्टिकोण एनबीएफसी को अपने पदचिह्न का विस्तार करने में मदद कर रहे हैं। एचएफसी ने विलय के लिए समायोजित ऋण में दोहरे अंकों की वृद्धि भी दर्ज की। एनबीएफसी की आस्तित्व गुणवत्ता में सभी श्रेणियों में सुधार हुआ। एआईएफआई के समेकित तुलन-पत्र 2023-24 में सीमांत रूप से उच्च गति की वृद्धि दर्ज हुई। सभी पीडी ने 2023-24 में अपनी न्यूनतम बोली प्रतिबद्धताओं को पार कर लिया और व्यक्तिगत रूप से न्यूनतम निर्धारित वार्षिक कुल कारोबार अनुपात हासिल किया।

VI.77 आगे बढ़ते हुए, साइबर सुरक्षा खतरों से उत्पन्न चुनौतियों के अलावा, एनबीएफसी को कुछ क्षेत्रों को ऋण प्रदान करने से जुड़े बढ़ते संकेन्द्रण जोखिम और जलवायु से संबंधित वित्तीय जोखिमों से सावधान रहने की आवश्यकता है। बैंकों पर एनबीएफसी की निर्भरता अधिक बनी हुई है, हालांकि इसमें कुछ कमी आई है; एनबीएफसी को जोखिम कम करने की रणनीति के रूप में अपनी निधि के स्रोतों में और विविधता लाने की आवश्यकता है। 'किसी भी कीमत पर विकास' जैसा अविवेकपूर्ण दृष्टिकोण प्रतिकूल होगा, और इसलिए एक मजबूत जोखिम प्रबंधन ढांचा लागू किया जाना चाहिए।

परिशिष्ट सारणी IV.1: भारतीय बैंकिंग क्षेत्र, एक दृष्टि में

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मद	बकाया राशि (मार्च के अंत में)		प्रतिशत घट-बढ़	
		2023	2024*	2022-23	2023-24*
1	2	3	4	5	6
1	तुलन-पत्र परिचालन				
	1.1 कुल देयताएं/आस्तियां	2,43,18,429	2,80,80,550	12.2	15.5
	1.2 जमा राशियां	1,90,68,238	2,17,33,443	11.0	14.0
	1.3 उधारियां	19,57,241	25,40,474	17.7	29.8
	1.4 ऋण तथा अग्रिम	1,43,19,353	1,71,42,340	17.4	19.7
	1.5 निवेश	64,36,540	72,70,365	11.4	13.0
	1.6 तुलनपत्रेतर एक्सपोजर (तुलन पत्र की देयताओं के प्रतिशत के रूप में)	144.8	138.6		
	1.7 कुल समेकित अंतरराष्ट्रीय दावे	6,65,899	6,32,852	-8.7	-5.0
2	लाभप्रदता				
	2.1 निवल लाभ	2,63,214	3,49,603		
	2.2 आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए) (प्रतिशत)	1.2	1.2		
	2.3 इक्विटी पर प्रतिलाभ (आरओई) (प्रतिशत)	12.3	13.4		
	2.4 निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) (प्रतिशत)	3.7	3.3		
3	पूंजी पर्याप्तता				
	3.1 जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) @	17.2	16.9		
	3.2 स्तर I पूंजी (कुल पूंजी के प्रतिशत के रूप में) @	86.8	87.8		
	3.3 सीआरएआर (स्तर I) (प्रतिशत) @	15.0	14.8		
4	आस्ति गुणवत्ता				
	4.1 सकल एनपीए	5,71,546	4,80,818	-23.1	-15.9
	4.2 निवल एनपीए	1,35,320	1,06,732	-33.7	-21.1
	4.3 सकल एनपीए अनुपात (सकल अग्रिम के प्रतिशत के रूप में सकल एनपीए)	3.9	2.8		
	4.4 निवल एनपीए अनुपात (निवल अग्रिम के प्रतिशत के रूप में निवल एनपीए)	0.9	0.6		
	4.5 प्रावधान कवरेज अनुपात (प्रतिशत)**	74.9	76.6		
	4.6 गिरावट अनुपात (प्रतिशत)	1.8	1.5		
5	बैंक ऋण का क्षेत्रवार अभिनियोजन				
	5.1 सकल बैंक ऋण	1,36,75,235	1,64,32,164	15	20.2
	5.2 कृषि	17,26,410	20,71,251	15.4	20.0
	5.3 उद्योग	33,66,406	36,52,804	5.8	8.5
	5.4 सेवाएं	37,18,805	45,92,227	19.5	23.5
	5.5 वैयक्तिक ऋण	41,82,767	53,31,290	20.7	27.5
6	प्रायोगिकीय विकास				
	6.1 क्रेडिट कार्डों की कुल संख्या (लाख में)	853	1,018	15.9	19.3
	6.2 डेबिट कार्डों की कुल संख्या (लाख में)	9,613	9,649	4.8	0.4
	6.3 एटीएम की संख्या (लाख में)	2.59	2.58	2.7	-0.3
7	ग्राहक सेवाएं				
	7.1 वर्ष के दौरान प्राप्त कुल शिकायतों की संख्या ^	2,34,690	2,93,924	-22.9	25.2
	7.2 वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या ##	2,45,391	2,99,022	-22.7	21.9
	7.2 में से वर्ष के दौरान समाधान/ निपटाई गई शिकायतों की संख्या	2,40,453	2,84,355	-22.7	18.3
	7.2 में से वर्ष के दौरान समाधान/ निपटाई गई शिकायतों का प्रतिशत	98	95		
8	वित्तीय समावेशन				
	8.1 ऋण-जमा अनुपात (प्रतिशत)	75.1	78.9		
	8.2 खोली गई नई बैंक शाखाओं की संख्या	5,308	5,379	63.1	1.3

टिप्पणियां : 1. * : अंतिम।

2. ** : अप्रत्यक्ष विवरणियों के आधार पर।

3. @ : आंकड़े बासेल III फ्रेमवर्क के अनुसार हैं।

4. ^ : इसमें सीआरपीसी में निपटाई गई शिकायतें और सीएमएस पोर्टल पर स्वतः समाप्त की गई शिकायतें शामिल नहीं हैं।

5. ## : निपटाई गई शिकायतों में वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतें और पिछले वर्ष से अग्रसारित शिकायतें शामिल हैं।

6. सारणी में एक बैंक के साथ गैर-बैंक के विलय के प्रभाव को दर्शाया गया है।

7. प्रतिशत घट-बढ़ में कुछ अंतर हो सकता है क्योंकि राशियों को लाख/ करोड़ रुपये में पूर्णांकित किया गया है।

परिशिष्ट सारणी IV.2: भारत में बैंकों की अंतरराष्ट्रीय देयताएं - लिखतों के प्रकार के आधार पर

(राशि ₹ करोड़ में)

देयताओं के प्रकार	बकाया राशि (मार्च के अंत में)		प्रतिशत घट-बढ़	
	2023 (पीआर)	2024 (पी)	2022-23	2023-24
1	2	3	4	5
1. ऋण और जमाराशियां	12,96,066	15,69,186	7.5	21.1
	(63.0)	(63.8)		
ए) विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) [एफसीएनआर (बी)] योजना	1,35,725	1,98,611	28.5	46.3
	(6.6)	(8.1)		
बी) विदेशी मुद्रा उधारियाँ*	96,587	1,59,151	18.4	64.8
	(4.7)	(6.5)		
सी) अनिवासी बाह्य रुपया (एनआरई) खाते	7,64,751	8,12,252	2.1	6.2
	(37.2)	(33.0)		
डी) अनिवासी साधारण (एनआरओ) रुपया खाते	1,64,786	2,28,483	16.7	38.7
	(8.0)	(9.3)		
2. प्रतिभूतियों/ बॉण्डों के निजी निर्गम	3,039	3,044	0.0	0.2
	(0.1)	(0.1)		
3. अन्य देयताएं	6,87,171	8,24,875	19.6	20.0
	(33.4)	(33.6)		
जिसमें से:				
ए) एडीआर/जीडीआर	1,18,681	1,50,363	28.6	26.7
	(5.8)	(6.1)		
बी) अनिवासियों द्वारा धारित बैंकों की इक्विटी	3,86,776	4,72,007	20.0	22.0
	(18.8)	(19.2)		
सी) भारत में विदेशी बैंकों की पूंजी/ विप्रेषणीय लाभ और अन्य अवर्गीकृत अंतरराष्ट्रीय देयताएं	1,81,714	2,02,504	13.6	11.4
	(8.8)	(8.2)		
4. ऋणात्मक एमटीएम डेरिवेटिव	69,873	60,718		-13.1
	(3.4)	(2.5)		
कुल अंतरराष्ट्रीय देयताएं	20,56,148	24,57,823	15.3	19.5
	(100.0)	(100.0)		

टिप्पणियां: 1. पीआर: आंशिक रूप से संशोधित; पी: अनंतिम।

2. *: भारत में और विदेशों से अंतर-बैंक उधार और बैंकों के बाह्य वाणिज्यिक उधार।

3. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल के प्रतिशत हैं।

4. प्रतिशत घट-बढ़ थोड़ी भिन्न हो सकती है क्योंकि पूर्ण संख्या को ₹ करोड़ में पूर्णांकित किया गया है।

5. नवीनतम बीआईएस दिशानिर्देशों के आधार पर, एमटीएम डेरिवेटिव को सितंबर 2022 तिमाही से इस विवरण में शामिल किया गया है।

स्रोत: अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग सांख्यिकी, आरबीआई।

परिशिष्ट सारणी IV.3: भारत में बैंकों की अंतरराष्ट्रीय आस्तियां - लिखतों के प्रकार के आधार पर

(राशि ₹ करोड़ में)

आस्तियों के प्रकार	बकाया राशि (मार्च अंत में)		प्रतिशत घट-बढ़	
	2023 (पीआर)	2024 (पी)	2022-23	2023-24
1	2	3	4	5
1. ऋण और जमा राशियाँ	5,52,425	4,39,804	-18.6	-20.4
	(83.0)	(86.3)		
जिसमें कि:				
(ए) अनिवासियों को ऋण	1,33,070	97,450	-5.4	-26.8
	(20.0)	(19.1)		
(बी) निवासियों को विदेशी मुद्रा ऋण	1,08,304	1,21,229	-19.4	11.9
	(16.3)	(23.8)		
(सी) बकाया निर्यात बिल	34,225	29,228	-35.7	-14.6
	(5.1)	(5.7)		
(डी) उपलब्ध विदेशी मुद्रा, यात्री चेक इत्यादि	743	858	117.5	15.5
	(0.1)	(0.2)		
(ई) नॉस्ट्रो शेष और विदेश में स्थानन	2,76,083	1,91,039	-21.2	-30.8
	(41.5)	(37.5)		
2. धारित कर्ज प्रतिभूतियाँ	44,632	11,816	-37.4	-73.5
	(6.7)	(2.3)		
3. अन्य अंतरराष्ट्रीय आस्तियाँ	21,165	13,865	32.9	-34.5
	(3.2)	(2.7)		
4. धनात्मक एमटीएम डेरिवेटिव	47,448	43,890		-7.5
	(7.1)	(8.6)		
कुल अंतरराष्ट्रीय आस्तियाँ*	6,65,669	5,09,375	-13.1	-23.5
	(100.0)	(100.0)		

टिप्पणियाँ: 1. *: सभी शाखाओं से अधूरे डेटा कवरेज को देखते हुए, स्थानिक बैंकिंग सांख्यिकी (एलबीएस) के तहत रिपोर्ट किए गए आंकड़े सभी शाखाओं से प्राप्त किए गए डेटा के साथ पूरी तरह से तुलनीय नहीं हैं।

2. पीआर: आंशिक रूप से संशोधित; पी: अंतिम।

3. पूर्णांकन के कारण घटकों का योग समान नहीं होने की संभावना है।

4. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल के प्रतिशत हैं।

5. नवीनतम बीआईएस दिशानिर्देशों के आधार पर, एमटीएम डेरिवेटिव को सितंबर 2022 तिमाही से इस विवरण में शामिल किया गया है।

स्रोत: अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग सांख्यिकी, आरबीआई

परिशिष्ट सारणी IV.4: भारत के अलावा अन्य देशों पर बैंकों के समेकित अंतरराष्ट्रीय दावे

(राशि ₹ करोड़ में)

देश	बकाया राशि (मार्च अंत में)		प्रतिशत घट-बढ़	
	2023 (पीआर)	2024 (पी)	2022-23	2023-24
1	2	3	4	5
कुल समेकित अंतरराष्ट्रीय दावे	6,65,899	6,32,852	-8.7	-5.0
जिसमें कि				
1. संयुक्त राज्य अमेरिका	2,29,016 (34.4)	1,86,677 (29.5)	-6.9	-18.5
2. यूनाइटेड किंगडम	66,094 (9.9)	67,944 (10.7)	-26.4	2.8
3. हांगकांग	20,468 (3.1)	24,972 (3.9)	-31.9	22.0
4. सिंगापुर	46,424 (7.0)	48,363 (7.6)	11.2	4.2
5. संयुक्त अरब अमीरात	85,841 (12.9)	75,242 (11.9)	-4.1	-12.3
6. जर्मनी	16,734 (2.5)	20,044 (3.2)	-46.2	19.8

टिप्पणियां: 1. पीआर: आंशिक रूप से संशोधित; पी: अनंतिम।

2. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल के प्रतिशत हैं।

3. प्रतिशत घट-बढ़ थोड़ी भिन्न हो सकती है क्योंकि पूर्ण संख्याओं को ₹ करोड़ में पूर्णांकित किया गया है।

स्रोत: अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग सांख्यिकी, आरबीआई

परिशिष्ट सारणी IV.5: बैंकों के समेकित अंतरराष्ट्रीय दावे: अवशिष्ट परिपक्वता और क्षेत्र

(राशि ₹ करोड़ में)

अवशिष्ट परिपक्वता/क्षेत्र	बकाया राशि (मार्च अंत में)		प्रतिशत घट-बढ़	
	2023 (पीआर)	2024 (पी)	2022-23	2023-24
1	2	3	4	5
कुल समेकित अंतरराष्ट्रीय दावे	6,65,899 (100.0)	6,32,852 (100.0)	-8.7	-5.0
अवशिष्ट परिपक्वता				
अल्पकालिक	5,17,959 (77.8)	5,28,829 (83.6)	-12.1	2.1
दीर्घकालिक	1,42,515 (21.4)	1,01,514 (16.0)	5.6	-28.8
अनाबंटित	5,425 (0.8)	2,509 (0.4)	13.7	-53.8
क्षेत्र				
बैंक	3,10,972 (46.7)	2,64,100 (41.7)	-24.4	-15.1
आधिकारिक क्षेत्र	49,733 (7.5)	46,513 (7.3)	-3.1	-6.5
गैर-बैंक वित्तीय संस्थाएं	1,837 (0.3)	2,457 (0.4)	-40.4	33.8
गैर-वित्तीय निजी	2,44,717 (36.7)	2,97,151 (47.0)	11.0	21.4
अन्य	58,640 (8.8)	22,631 (3.6)	36.8	-61.4

- टिप्पणियां:** 1. पीआर: आंशिक रूप से संशोधित; पी: अनंतिम।
2. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल के प्रतिशत हैं।
3. पूर्णांकन के कारण घटकों का योग समान नहीं होने की संभावना है।
4. अवशिष्ट परिपक्वता 'अनाबंटित' में परिपक्वता लागू नहीं (उदाहरण के लिए, इक्विटी के लिए) और परिपक्वता की जानकारी उपलब्ध नहीं शामिल है।
5. आधिकारिक क्षेत्र में आधिकारिक मौद्रिक प्राधिकरण, सामान्य सरकार और बहुपक्षीय एजेंसियां शामिल हैं।
6. गैर-वित्तीय निजी क्षेत्र में गैर-वित्तीय निगम तथा हाउसहोल्ड में गैर-लाभकारी संस्थाओं में सेवारत हाउसहोल्ड (एनपीआईएसआईएस) शामिल हैं।
7. अन्य में गैर-वित्तीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और अनाबंटित क्षेत्र शामिल हैं।
8. प्रतिशत घट-बढ़ थोड़ी भिन्न हो सकती है क्योंकि पूर्ण संख्या को ₹ करोड़ में पूर्णांकित किया गया है।

स्रोत: अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग सांख्यिकी, आरबीआई

परिशिष्ट सारणी IV.6: भारत में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का तुलनपत्रेतर एक्सपोजर

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक		निजी क्षेत्र के बैंक		विदेशी बैंक		लघु वित्त बैंक		भुगतान बैंक		सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	
	2024	प्रतिशत घट-बढ़	2024	प्रतिशत घट-बढ़	2024	प्रतिशत घट-बढ़	2024	प्रतिशत घट-बढ़	2024	प्रतिशत घट-बढ़	2024	प्रतिशत घट-बढ़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. वायदा विनिमय संविदा®	32,62,522 (21.1)	-6.6	1,15,28,125 (109.6)	20.0	1,88,62,772 (1105.7)	5.8	5.0 (0.0)	-	0	-	3,36,53,424 (119.8)	8.8
2. दी गई गारंटी	6,31,279 (4.1)	6.4	6,68,833 (6.4)	20.3	2,09,110 (12.3)	8.5	3,627 (1.1)	34.7	0	-	15,12,849 (5.4)	12.5
3. स्वीकृति, परांकन आदि	12,57,758 (8.1)	21.5	6,11,646 (5.8)	31.9	18,94,524 (111.1)	30.8	2,394 (0.7)	69.3	390 (1.6)	38.3	37,66,711 (13.4)	27.8
आकस्मिक देयताएं	51,51,558 (33.3)	0.6	1,28,08,605 (121.7)	20.6	2,09,66,406 (1229.0)	7.7	6,026 (1.8)	46.7	390 (1.6)	38.3	3,89,32,984 (138.6)	10.5

टिप्पणियां: 1. -: शून्य/नगण्य।

2. ®: स्वीकार्य सभी डेरिवेटिव उत्पाद (ब्याज दर स्वेप सहित) शामिल हैं।

3. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संबंधित बैंक-समूह की कुल देयताओं के प्रतिशत हैं।

स्रोत: संबंधित बैंकों के वार्षिक लेखे।

परिशिष्ट सारणी IV.7: रिपोर्टिंग की तारीख के आधार पर विभिन्न बैंकिंग परिचालनों में धोखाधड़ी (जारी)

(राशि ₹ करोड़ में)

बैंक समूह	2004-05		2005-06		2006-07		2007-08		2008-09		2009-10		2010-11	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
अग्रिम	1,564	672	1,525	1,162	1,734	1,055	1,750	721	1,976	1,388	2,190	1,263	2,382	2,740
कार्ड/ इंटरनेट	26	3	144	6	491	11	679	15	1,036	37	1,215	35	763	21
जमाराशियां	374	28	325	28	384	49	458	79	599	66	666	195	790	583
तुलन पत्र से इतर	6	33	7	25	4	4	6	8	9	22	10	370	10	212
विदेशी मुद्रा लेनदेन	16	14	10	30	28	7	25	30	15	14	16	28	19	148
नकदी	75	4	89	16	87	7	99	5	141	36	143	14	154	21
चेक/ मांग ड्राफ्ट आदि	108	15	110	9	141	10	192	17	234	15	202	17	184	27
अंतर-शाखा खाते	31	6	36	7	18	1	22	3	16	5	18	2	10	1
समाशोधन आदि खाते	20	2	23	4	35	12	30	9	52	45	51	7	34	11
अनिवासी खाते	11	2	9	0	17	1	9	4	26	2	13	2	9	2
अन्य	204	16	148	29	88	51	97	26	146	39	146	64	179	56
कुल योग	2,435	795	2,426	1,316	3,027	1,208	3,367	917	4,250	1,669	4,670	1,997	4,534	3,822

- टिप्पणियां: 1. ₹ 1 लाख और उससे अधिक की धोखाधड़ी को संदर्भित करता है।
2. बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिये गए आंकड़े उनके द्वारा दर्ज संशोधनों के आधार पर परिवर्तन के अधीन हैं।
3. एक वर्ष में रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी, रिपोर्टिंग के वर्ष से कई वर्ष पहले की हो सकती है।
4. शामिल राशियां रिपोर्ट की गई राशियां हैं और उपगत हानि की मात्रा को नहीं दर्शाती हैं। वसूली के आधार पर, उपगत हानियां कम हो जाती हैं। इसके अलावा, यह जरूरी नहीं कि ऋण खातों में शामिल पूरी राशि का विचलन हो।
5. धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर 15 जुलाई 2024 को संशोधित मास्टर निदेश जारी होने के बाद, बैंक केवल उन भुगतान प्रणाली संबंधित लेनदेनों की रिपोर्ट कर रहे हैं, जो बैंक(कों) पर धोखाधड़ी के रूप में माने गए हैं।

स्रोत: आरबीआई।

भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति संबंधी रिपोर्ट 2023-24

परिशिष्ट सारणी IV.7: रिपोर्टिंग की तारीख के आधार पर विभिन्न बैंकिंग परिचालनों में धोखाधड़ी (जारी)

(राशि ₹ करोड़ में)

बैंक समूह	2011-12		2012-13		2013-14		2014-15		2015-16		2016-17		2017-18	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
अग्रिम	1,953	3,552	2,087	6,530	1,984	7,949	2,254	16,924	2,116	17,180	2,313	20,196	2,520	22,388
कार्ड/ इंटरनेट	629	23	793	49	978	54	845	52	1,191	40	1,372	42	2,058	102
जमाराशियां	857	219	791	291	774	331	875	437	759	809	693	903	691	457
तुलन पत्र से इतर	5	373	18	1,527	15	1,088	10	699	4	132	5	63	20	16,288
विदेशी मुद्रा लेनदेन	22	130	10	98	9	144	16	899	16	31	16	2,201	9	1,426
नकदी	173	20	140	23	145	24	153	43	160	22	239	37	218	40
चेक/ मांग ड्राफ्ट आदि	172	40	141	22	180	19	254	26	234	25	235	40	207	34
अंतर-शाखा खाते	24	8	6	3	7	1	4	0	4	10	1	0	6	1
समाशोधन आदि खाते	38	31	36	7	36	24	29	7	17	87	27	6	37	6
अनिवासी खाते	11	3	17	3	38	10	23	8	8	9	10	3	6	6
अन्य	207	98	197	112	135	64	179	162	176	146	153	77	138	242
कुल योग	4,091	4,497	4,236	8,665	4,301	9,708	4,642	19,257	4,685	18,491	5,064	23,568	5,910	40,990

- टिप्पणियां:**
1. ₹ 1 लाख और उससे अधिक की धोखाधड़ी को संदर्भित करता है।
 2. बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिये गए आंकड़े उनके द्वारा दर्ज संशोधनों के आधार पर परिवर्तन के अधीन हैं।
 3. एक वर्ष में रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी, रिपोर्टिंग के वर्ष से कई साल पहले की हो सकती है।
 4. शामिल राशियां रिपोर्ट की गई राशियां हैं और उपगत हानि की मात्रा को नहीं दर्शाती हैं। वसूली के आधार पर, उपगत हानियां कम हो जाती हैं। इसके अलावा, यह जरूरी नहीं कि ऋण खातों में शामिल पूरी राशि का विचलन हो।
 5. धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर 15 जुलाई 2024 को संशोधित मास्टर निदेश जारी होने के बाद, बैंक केवल उन भुगतान प्रणाली संबंधित लेनदेनों की रिपोर्ट कर रहे हैं, जो बैंक(कों) पर धोखाधड़ी के रूप में माने गए हैं।

स्रोत: आरबीआई।

परिशिष्ट सारणी IV.7: रिपोर्टिंग की तारीख के आधार पर विभिन्न बैंकिंग परिचालनों में धोखाधड़ी (समाप्त)

(राशि ₹ करोड़ में)

बैंक समूह	2018-19		2019-20		2020-21		2021-22		2022-23		2023-24		2024-25 (सित 2024 तक)	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
अग्रिम	3,556	53,069	4,455	1,56,466	3,364	1,12,681	3,745	41,485	4,063	22,421	4,124	11,017	3,531	19,748
कार्ड/ इंटरनेट	1,866	71	2,677	129	2,545	119	3,596	155	6,699	277	29,082	1,457	13,133	514
जमाराशियां	593	148	530	616	503	434	471	493	652	258	2,002	240	934	363
तुलन पत्र से इतर	27	5,250	29	2,279	23	535	21	1,077	14	285	11	256	0	0
विदेशी मुद्रा लेनदेन	13	695	8	54	4	129	7	7	13	12	19	38	6	1
नकदी	274	56	371	63	329	39	649	93	1,485	159	484	78	205	18
चेक/ मांग ड्राफ्ट आदि	189	34	201	39	163	84	201	158	118	25	127	42	49	54
अंतर-शाखा खाते	3	0	2	0	2	0	3	2	3	0	29	10	3	1
समाशोधन आदि खाते	24	209	22	7	14	4	16	1	18	3	17	2	3	1
अनिवासी खाते	3	0	8	1	1	0	1	2	2	1	6	2	1	0
अन्य	197	244	242	172	277	54	299	98	470	422	165	33	596	667
कुल योग	6,745	59,776	8,545	1,59,826	7,225	1,14,079	9,009	43,571	13,537	23,863	36,066	13,175	18,461	21,367

टिप्पणियां: 1. ₹ 1 लाख और उससे अधिक की धोखाधड़ी को संदर्भित करता है।

2. बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिये गए आंकड़े उनके द्वारा दर्ज संशोधनों के आधार पर परिवर्तन के अधीन हैं।

3. एक वर्ष में रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी, रिपोर्टिंग के वर्ष से कई साल पहले की हो सकती है।

4. शामिल राशियां रिपोर्ट की गई राशियां हैं और उपगत हानि की मात्रा को नहीं दर्शाती हैं। वसूली के आधार पर, उपगत हानियां कम हो जाती हैं। इसके अलावा, यह जरूरी नहीं कि ऋण खातों में शामिल पूरी राशि का विचलन हो।

5. धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर 15 जुलाई 2024 को संशोधित मास्टर निदेश जारी होने के बाद, बैंक केवल उन भुगतान प्रणाली संबंधित लेनदेनों की रिपोर्ट कर रहे हैं, जो बैंक(कों) पर धोखाधड़ी के रूप में माने गए हैं।

स्रोत: आरबीआई।

भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति संबंधी रिपोर्ट 2023-24

परिशिष्ट सारणी IV.8: किसान क्रेडिट कार्ड योजना: राज्य-वार प्रगति (जारी)

(राशि ₹ करोड़ में तथा जारी कार्डों की संख्या '000 में)

क्र. सं.	राज्य/ संघशासित क्षेत्र	सहकारी बैंक				क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक			
		सक्रिय केसीसी की संख्या		सक्रिय केसीसी के तहत बकाया राशि		सक्रिय केसीसी की संख्या		सक्रिय केसीसी के तहत बकाया राशि	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	उत्तरी क्षेत्र	5,423	5,564	35,431	37,387	1,492	1,556	37,304	40,101
1	हरियाणा	1,155	1,154	12,300	13,063	297	307	8,302	9,054
2	हिमाचल प्रदेश	118	134	2,062	2,302	83	92	1,281	1,425
3	जम्मू और कश्मीर	7	7	62	63	126	134	1,068	1,152
4	लद्दाख	0	0	0	0	0	0	0	0
5	नई दिल्ली	0	0	1	0	0	0	0	0
6	पंजाब	940	910	7,194	6,645	158	160	6,100	6,582
7	राजस्थान	3,204	3,358	13,811	15,314	828	863	20,553	21,889
8	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0
	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	72	63	157	212	460	445	2,174	2,350
9	असम	1	1	21	19	287	281	1,485	1,623
10	अरुणाचल प्रदेश	1	1	7	7	3	2	22	16
11	मेघालय	16	12	32	49	35	39	201	237
12	मिजोरम	1	1	7	11	21	21	243	268
13	मणिपुर	3	3	16	18	10	10	44	48
14	नगालैंड	4	4	22	22	1	1	2	1
15	त्रिपुरा	44	37	43	73	105	90	178	157
16	सिक्किम	2	2	8	11	0	0	0	0
	पश्चिमी क्षेत्र	4,571	4,600	38,860	43,810	1,184	1,264	15,358	17,834
17	गुजरात	993	999	14,810	16,106	453	502	8,426	10,192
18	महाराष्ट्र	3,576	3,598	24,031	27,674	731	762	6,931	7,642
19	गोवा	2	2	19	30	0	0	0	0
20	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0
	मध्य क्षेत्र	8,371	8,685	38,195	36,877	4,325	4,519	55,978	62,662
21	उत्तर प्रदेश	2,727	2,673	9,070	8,964	3,677	3,851	46,843	52,694
22	उत्तराखंड	289	305	1,750	1,297	28	30	199	219
23	मध्य प्रदेश	3,865	4,008	23,146	23,946	452	464	7,577	8,041
24	छत्तीसगढ़	1,491	1,700	4,229	2,671	168	174	1,358	1,708
	दक्षिणी क्षेत्र	8,016	8,939	57,830	64,540	3,770	4,082	49,446	56,259
25	कर्नाटक	3,003	3,673	20,888	24,751	757	839	13,364	16,152
26	केरल	705	485	5,832	4,554	480	541	8,097	9,597
27	आंध्र प्रदेश	1,477	1,682	12,925	13,733	951	972	11,826	12,138
28	तमिलनाडु	1,904	2,201	12,889	16,030	80	160	1,420	3,124
29	तेलंगाना	926	897	5,297	5,470	1,502	1,568	14,724	15,233
30	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0
31	पुदुचेरी	0	0	0	1	1	2	14	15
	पूर्वी क्षेत्र	4,935	5,067	18,963	24,852	2,636	2,652	17,739	18,546
32	ओडिशा	2,939	3,358	13,475	19,624	436	447	2,575	2,737
33	पश्चिम बंगाल	1,727	1,477	4,970	4,755	417	410	2,085	2,199
34	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	7	8	18	19	0	0	0	0
35	बिहार	246	209	452	401	1,405	1,420	10,684	11,133
36	झारखंड	16	16	49	54	378	374	2,396	2,477
	कुल	31,389	32,917	1,89,436	2,07,678	13,868	14,517	1,77,999	1,97,753

टिप्पणी: *: डेटा अनंतिम हैं।

स्रोत: नाबार्ड/ अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की विवरणियाँ (आरआरबी को छोड़कर)।

परिशिष्ट सारणी IV.8: किसान क्रेडिट कार्ड योजना: राज्य-वार प्रगति (जारी)

(राशि ₹ करोड़ में तथा जारी कार्डों की संख्या '000 में)

क्र. सं.	राज्य/ संघशासित क्षेत्र	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी रहित)				कुल			
		सक्रिय केसीसी की संख्या		सक्रिय केसीसी के तहत बकाया राशि		सक्रिय केसीसी की संख्या		सक्रिय केसीसी के तहत बकाया राशि	
		2023	2024*	2023	2024*	2023	2024*	2023	2024*
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
	उत्तरी क्षेत्र	5,511	5,925	1,47,046	1,59,797	12,426	13,045	2,19,780	2,37,286
1	हरियाणा	835	901	29,440	31,883	2,287	2,362	50,042	54,000
2	हिमाचल प्रदेश	257	277	4,666	5,345	458	503	8,009	9,072
3	जम्मू और कश्मीर	778	926	5,233	5,759	911	1,067	6,363	6,974
4	लद्दाख	28	28	258	268	28	28	258	268
5	नई दिल्ली	3	3	43	43	3	3	44	43
6	पंजाब	1,100	1,164	42,129	44,604	2,198	2,235	55,423	57,830
7	राजस्थान	2,508	2,624	65,178	71,770	6,540	6,846	99,543	1,08,973
8	चंडीगढ़	1	2	99	126	1	2	99	126
	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	530	542	3,450	4,056	1,063	1,050	5,781	6,618
9	असम	400	389	2,612	2,973	688	671	4,119	4,615
10	अरुणाचल प्रदेश	6	16	52	172	10	18	81	195
11	मेघालय	21	26	127	181	72	77	360	467
12	मिजोरम	14	18	64	94	35	40	315	373
13	मणिपुर	7	6	106	92	20	20	165	159
14	नगालैंड	25	27	155	168	30	32	179	192
15	त्रिपुरा	50	53	286	326	199	181	507	556
16	सिक्किम	7	8	49	50	9	10	56	62
	पश्चिमी क्षेत्र	4,450	4,505	78,634	87,715	10,205	10,368	1,32,851	1,49,359
17	गुजरात	1,572	1,637	39,137	44,835	3,018	3,137	62,373	71,132
18	महाराष्ट्र	2,868	2,857	39,366	42,702	7,175	7,218	70,329	78,018
19	गोवा	8	9	91	138	9	12	109	169
20	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	2	2	40	40	2	2	40	40
	मध्य क्षेत्र	6,701	6,917	1,29,155	1,40,667	19,398	20,121	2,23,328	2,40,205
21	उत्तर प्रदेश	4,302	4,394	72,202	76,963	10,705	10,917	1,28,115	1,38,621
22	उत्तराखंड	191	222	4,417	4,964	509	557	6,365	6,479
23	मध्य प्रदेश	1,950	2,029	47,369	52,537	6,267	6,500	78,092	84,523
24	छत्तीसगढ़	258	272	5,168	6,203	1,917	2,147	10,756	10,582
	दक्षिणी क्षेत्र	8,013	8,488	1,38,002	1,56,799	19,799	21,509	2,45,279	2,77,598
25	कर्नाटक	961	987	19,908	21,891	4,720	5,499	54,161	62,794
26	केरल	1,409	1,566	29,472	34,885	2,594	2,592	43,401	49,036
27	आंध्र प्रदेश	2,124	2,200	36,129	39,583	4,552	4,853	60,879	65,455
28	तमिलनाडु	1,596	1,671	27,823	32,959	3,580	4,032	42,132	52,112
29	तेलंगाना	1,910	2,044	24,384	27,083	4,337	4,509	44,405	47,786
30	लक्षद्वीप	2	3	15	22	2	3	15	22
31	पुदुचेरी	12	18	272	376	13	20	286	392
	पूर्वी क्षेत्र	3,085	3,438	22,198	25,940	10,657	11,157	58,901	69,338
32	ओडिशा	596	660	5,694	6,736	3,971	4,466	21,744	29,097
33	पश्चिम बंगाल	988	1,118	7,477	8,902	3,132	3,005	14,531	15,856
34	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2	1	20	5	9	8	38	23
35	बिहार	926	1,053	6,251	7,267	2,577	2,683	17,388	18,801
36	झारखंड	574	606	2,755	3,029	968	996	5,200	5,560
	कुल	28,290	29,814	5,18,485	5,74,974	73,547	77,249	8,85,921	9,80,404

टिप्पणी: *: डेटा अनंतिम हैं।

स्रोत: नाबार्ड/ अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की विवरणियाँ (आरआरबी को छोड़कर)।

परिशिष्ट सारणी IV.9: संवेदनशील क्षेत्रों को बैंक समूह-वार उधार

(राशि ₹ करोड़ में)

क्षेत्र	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक		निजी क्षेत्र के बैंक		विदेशी बैंक		लघु वित्त बैंक		अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक*	
	2023-24	प्रतिशत में घट-बढ़	2023-24	प्रतिशत में घट-बढ़	2023-24	प्रतिशत में घट-बढ़	2023-24	प्रतिशत में घट-बढ़	2023-24	प्रतिशत में घट-बढ़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. पूंजी बाज़ार #	68,088 (0.7)	25.8	1,61,162 (2.3)	36.4	13,587 (2.5)	8.4	482 (0.2)	9.3	2,43,321 (1.4)	31.3
2. स्थावर संपदा @	20,30,270 (21.4)	16.4	22,17,737 (32.3)	61.4	1,26,363 (23.0)	-7.1	45,129 (20.0)	22.4	44,19,498 (25.8)	34.3
3. पण्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
संवेदनशील क्षेत्रों के लिए कुल अग्रिम	20,98,358 (22.1)	16.6	23,78,899 (34.7)	59.5	1,39,949 (25.5)	-5.8	45,611 (20.2)	22.2	46,62,820 (27.2)	34.1

टिप्पणियां: 1. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े संबंधित बैंक समूह के कुल ऋणों और अग्रिमों का प्रतिशत दर्शाते हैं।

2. -: शून्य/नगण्य।

3. #: पूंजी बाज़ार के प्रति एक्सपोजर में निवेश तथा अग्रिम, दोनों शामिल हैं।

4. *: भुगतान बैंकों सहित।

5. @: स्थावर संपदा क्षेत्र के प्रति एक्सपोजर में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष ऋण, दोनों शामिल हैं।

स्रोत: संबंधित बैंकों के वार्षिक लेखे।

परिशिष्ट सारणी IV.10: घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की शेयरधारिता का स्वरूप (जारी)

(मार्च 2024 के अंत में)

क्र. सं.	बैंक का नाम	सरकारी और आरबीआई	वित्तीय संस्थाएं (म्यूचुअल फंड सहित)		अन्य कॉरपोरेट		व्यक्तिक		कुल	
		निवासी	निवासी	अनिवासी	निवासी	अनिवासी	निवासी	अनिवासी	निवासी	अनिवासी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक									
1	बैंक ऑफ बड़ौदा	64.0	8.6	0.0	8.2	12.4	6.5	0.4	87.2	12.8
2	बैंक ऑफ इंडिया	73.4	15.8	4.5	0.5	0.0	5.6	0.2	95.3	4.7
3	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	86.5	4.7	1.0	0.4	0.0	7.2	0.2	98.8	1.3
4	केनरा बैंक	62.9	14.4	10.6	1.2	0.0	10.7	0.2	89.2	10.8
5	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	93.1	2.8	0.2	0.2	0.0	3.7	0.1	99.8	0.2
6	इंडियन बैंक	73.8	17.0	0.0	0.4	5.3	3.4	0.1	94.6	5.4
7	इंडियन ओवरसीज बैंक	96.4	1.3	0.1	0.1	0.0	2.2	0.1	99.9	0.1
8	पंजाब एंड सिंध बैंक	98.3	0.7	0.0	0.1	0.0	1.0	0.0	100.0	0.1
9	पंजाब नेशनल बैंक	73.2	12.4	4.8	0.5	0.0	8.9	0.2	95.0	5.1
10	भारतीय स्टेट बैंक	56.9	23.7	11.0	0.7	1.1	6.3	0.3	87.7	12.3
11	यूको बैंक	95.4	1.3	0.0	0.2	0.0	3.0	0.1	99.9	0.1
12	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	74.8	3.8	6.8	9.1	0.0	5.6	0.0	93.3	6.8

टिप्पणी: संभव है कि पूर्णांकन के कारण कुल योग 100 के बराबर न हो।

स्रोत: ऑफ-साइट विवरणियां (घरेलू), आरबीआई।

परिशिष्ट सारणी IV.10: घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की शेयरधारिता का स्वरूप (जारी)

(मार्च 2024 के अंत में)

क्र. सं.	बैंक का नाम	सरकारी और आरबीआई	वित्तीय संस्थाएं (म्यूचुअल फंड सहित)		अन्य कॉरपोरेट		व्यक्तिक		कुल	
		निवासी	निवासी	अनिवासी	निवासी	अनिवासी	निवासी	अनिवासी	निवासी	अनिवासी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	निजी क्षेत्र के बैंक									
1	एक्सिस बैंक लिमि.	0.0	37.0	55.4	1.1	1.1	5.1	0.3	43.2	56.8
2	बंधन बैंक लिमि.	0.1	12.4	31.2	41.5	0.0	14.3	0.5	68.3	31.7
3	सिटी यूनियन बैंक लिमि.	0.0	29.1	27.0	3.1	0.0	39.7	1.2	71.9	28.1
4	कैथोलिक सीरियन बैंक लिमिटेड	0.0	14.2	0.0	7.2	55.0	16.6	6.9	38.1	61.9
5	डीसीबी बैंक लिमि.	0.0	28.0	0.0	8.0	27.0	36.0	1.0	72.0	28.0
6	धनलक्ष्मी बैंक लिमि.	0.5	0.1	0.0	6.9	6.1	67.4	19.0	74.9	25.1
7	फेडरल बैंक लिमि.	0.0	44.5	33.4	2.8	0.0	19.4	0.0	66.6	33.4
8	एचडीएफसी बैंक लिमि.	0.1	29.4	55.3	1.9	0.0	13.0	0.3	44.5	55.5
9	आईसीआईसीआई बैंक लिमि.	0.2	26.1	55.7	11.4	0.0	6.3	0.2	44.1	55.9
10	आईडीबीआई बैंक लिमि.	45.5	49.4	0.0	0.5	0.0	4.0	0.6	99.4	0.6
11	आईडीएफसी बैंक लिमि.	3.7	44.2	21.4	1.6	2.3	25.3	1.5	74.8	25.2
12	इंडसइंड बैंक लिमि.	0.0	24.5	45.0	6.2	15.9	7.7	0.7	38.4	61.6
13	जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमि.	59.4	8.2	7.0	0.0	0.0	23.6	1.9	91.2	8.8
14	कर्नाटक बैंक लिमि.	0.0	23.1	0.0	3.7	18.9	52.4	2.0	79.1	20.9
15	करूर वैश्य बैंक लिमि.	0.0	34.2	0.0	4.3	15.4	45.0	1.1	83.6	16.4
16	कोटक महिंद्रा बैंक लिमि.	0.0	22.0	37.6	3.4	1.3	35.3	0.5	60.6	39.4
17	नैनीताल बैंक लिमि.	0.0	98.6	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	100.0	0.0
18	आरबीएल बैंक लिमि.	0.4	19.0	0.0	12.8	33.7	32.4	1.6	64.7	35.3
19	साउथ इंडियन बैंक लिमि.	0.0	2.0	0.0	8.5	15.2	66.4	8.0	76.8	23.2
20	तमिलनाडु मर्केटाइल बैंक लिमि.	0.0	0.4	3.5	9.0	22.4	63.2	1.5	72.6	27.4
21	येस बैंक लिमि.	0.0	41.7	22.0	1.9	0.0	34.3	0.0	78.0	22.0

टिप्पणी: संभव है कि पूर्णांकन के कारण कुल योग 100 के बराबर न हो।

स्रोत: ऑफ-साइट विवरणियां (घरेलू), आरबीआई।

परिशिष्ट सारणी IV.10: घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की शेयरधारिता का स्वरूप (समाप्त)

(मार्च 2024 के अंत में)

क्र. सं.	बैंक का नाम	सरकारी और आरबीआई	वित्तीय संस्थाएं (म्यूचुअल फंड सहित)		अन्य कॉरपोरेट		व्यक्ति		कुल	
		निवासी	निवासी	अनिवासी	निवासी	अनिवासी	निवासी	अनिवासी	निवासी	अनिवासी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	लघु वित्त बैंक									
1	एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड	0.0	14.5	36.4	11.9	3.0	34.0	0.2	60.4	39.6
2	कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड	0.1	19.1	1.4	15.4	0.0	48.0	16.0	82.6	17.4
3	इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड	0.0	45.2	2.9	22.6	0.0	28.1	1.3	95.9	4.1
4	ईएसएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड	0.0	56.6	0.0	17.4	0.8	17.2	8.0	91.2	8.9
5	फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड	0.0	81.3	9.3	7.2	0.0	2.1	0.0	90.7	9.3
6	जन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड	0.0	1.2	17.7	36.0	27.9	17.0	0.2	54.2	45.8
7	नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड	0.0	4.2	2.1	92.7	0.0	1.0	0.0	97.9	2.1
8	शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड	0.0	0.9	0.0	6.3	21.8	70.7	0.3	78.0	22.0
9	सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड	0.0	11.4	0.0	10.0	22.2	55.8	0.6	77.2	22.8
10	उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड	0.0	2.3	0.0	74.1	3.5	19.5	0.6	95.9	4.1
11	युनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड	0.0	51.0	0.0	49.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0
12	उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड	0.0	8.7	0.0	71.2	8.6	11.3	0.3	91.2	8.8
	स्थानीय क्षेत्र बैंक									
1	कोस्टल लोकल एरिया बैंक लिमिटेड	0.0	0.0	0.0	21.4	0.0	51.5	27.1	72.9	27.1
2	कृष्ण भीम समृद्धि एलएबी लिमिटेड	0.0	0.0	0.0	20.3	0.0	79.7	0.0	100.0	0.0

टिप्पणी: संभव है कि पूर्णांकन के कारण कुल योग 100 के बराबर न हो।

स्रोत: ऑफ-साइट विवरणियां (घरेलू), आरबीआई।

भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति संबंधी रिपोर्ट 2023-24

परिशिष्ट सारणी IV.11: भारतीय बैंकों के विदेशी परिचालन

(मार्च 2024 के अंत में)

क्र. सं.	बैंक का नाम	शाखा		सहायक संस्थाएं		प्रतिनिधि कार्यालय		संयुक्त उद्यम बैंक		अन्य कार्यालय*		कुल	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (कुल)	100	99	22	22	11	11	6	6	31	33	170	171
1	बैंक ऑफ बड़ौदा	29	28	7	7	0	0	2	2	10	10	48	47
2	बैंक ऑफ इंडिया	21	21	4	4	1	1	0	0	0	0	26	26
3	केनरा बैंक	3	3	1	1	1	1	0	0	0	0	5	5
4	इंडियन बैंक	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
5	इंडियन ओवरसीज बैंक	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
6	पंजाब नेशनल बैंक	1	1	2	2	2	2	2	2	0	0	7	7
7	भारतीय स्टेट बैंक	34	35	7	7	6	6	2	2	21	23	70	73
8	यूको बैंक	2	2	0	0	1	1	0	0	0	0	3	3
9	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	3	2	1	1	0	0	0	0	0	0	4	3
II	निजी क्षेत्र के बैंक (कुल)	13	13	3	3	25	25	0	0	2	2	43	43
10	एक्सिस बैंक	2	2	1	1	4	4	0	0	0	0	7	7
11	एचडीएफसी बैंक लिमि.	3	3	0	0	3	3	0	0	0	0	6	6
12	आईसीआईसीआई बैंक लिमि.	6	6	2	2	10	10	0	0	2	2	20	20
13	आईडीबीआई बैंक लिमि.\$	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
14	इंडसइंड बैंक लिमि.	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	3	3
15	फेडरल बैंक लिमि.	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2
16	कोटक महिंद्रा बैंक लिमि.	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	2	2
17	येस बैंक लिमि.	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
18	साउथ इंडियन बैंक लिमि.	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
	सभी बैंक	113	112	25	25	36	36	6	6	33	35	213	214

टिप्पणी: *: अन्य कार्यालयों में विपणन/ उप-कार्यालय, विप्रेषण केंद्र आदि शामिल हैं।

स्रोत: आरबीआई।

परिशिष्ट सारणी IV.12: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की शाखाएं और एटीएम (जारी)

(मार्च 2024 के अंत में)

क्र. सं.	बैंक का नाम	शाखाएं					एटीएम और सीआरएम		
		ग्रामीण	अर्ध-शहरी	अर्ध-शहरी	महानगरीय	कुल	शाखा स्थित	शाखेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	29,208	23,463	16,119	16,069	84,859	77,033	57,661	1,34,694
1	बैंक ऑफ बड़ौदा	2,874	2,087	1,481	1,784	8,226	8,417	2,634	11,051
2	बैंक ऑफ इंडिया	1,868	1,464	823	932	5,087	5,329	2,900	8,229
3	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	612	719	547	608	2,486	1,865	36	1,901
4	केनरा बैंक	3,103	2,750	1,901	1,844	9,598	8,198	3,958	12,156
5	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	1,604	1,335	770	794	4,503	2,857	1,144	4,001
6	इंडियन बैंक	1,984	1,526	1,174	1,160	5,844	4,336	601	4,937
7	इंडियन ओवरसीज बैंक	908	964	656	690	3,218	2,774	731	3,505
8	पंजाब एंड सिंध बैंक	582	294	370	318	1,564	1,009	26	1,035
9	पंजाब नेशनल बैंक	3,925	2,481	1,997	1,724	10,127	7,794	4,337	12,131
10	भारतीय स्टेट बैंक	8,091	6,531	4,048	3,863	22,533	24,513	39,067	63,580
11	यूको बैंक	1,113	872	639	592	3,216	2,249	228	2,477
12	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	2,544	2,440	1,713	1,760	8,457	7,692	1,999	9,691

टिप्पणियां: 1. जनसंख्या समूहों को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है: 'ग्रामीण' में 10,000 से कम की आबादी वाले केंद्र शामिल हैं, 'अर्ध-शहरी' में 10,000 और उससे अधिक लेकिन एक लाख से कम की आबादी वाले केंद्र शामिल हैं, 'शहरी' में एक लाख और उससे अधिक लेकिन दस लाख से कम आबादी वाले केंद्र शामिल हैं और 'महानगर' में 10 लाख और उससे अधिक की आबादी वाले केंद्र शामिल हैं। जनसंख्या के सभी आंकड़े 2011 की जनगणना के अनुसार हैं।

2. शाखाओं के डेटा में 'प्रशासनिक कार्यालय' संबंधी डेटा शामिल नहीं हैं।

स्रोत: बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेटाबेस (पूर्व में मास्टर ऑफिस फाइल सिस्टम) के लिए केंद्रीय सूचना प्रणाली, आरबीआई।

परिशिष्ट सारणी IV.12: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की शाखाएं और एटीएम (जारी)

(मार्च 2024 के अंत में)

क्र. सं.	बैंक का नाम	शाखाएं					एटीएम और सीआरएम		
		ग्रामीण	अर्ध-शहरी	अर्ध-शहरी	महानगरीय	कुल	शाखा स्थित	शाखेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	निजी क्षेत्र के बैंक	8,924	14,088	9,593	12,086	44,691	45,438	34,446	79,884
1	एक्सिस बैंक लिमि.	923	1,564	1,291	1,742	5,520	6,244	9,760	16,004
2	बंधन बैंक लिमि.	2,100	2,352	1,152	693	6,297	433	5	438
3	केथोलिक सीरियन बैंक लिमि.	66	367	156	193	782	683	48	731
4	सिटी यूनियन बैंक लिमि.	152	281	173	189	795	1,140	537	1,677
5	डीसीबी बैंक लिमि.	82	111	123	126	442	413	5	418
6	धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड	20	112	71	58	261	239	41	280
7	फेडरल बैंक लिमि.	215	739	288	261	1,503	1,678	335	2,013
8	एचडीएफसी बैंक लिमि.	1,547	3,019	1,759	2,405	8,730	11,649	9,289	20,938
9	आईसीआईसीआई बैंक लिमि.	1,361	1,809	1,306	1,913	6,389	9,994	7,189	17,183
10	आईडीबीआई लिमि.	432	631	480	460	2,003	2,317	986	3,303
11	आईडीएफसी बैंक लिमि.	60	268	400	477	1,205	853	311	1,164
12	इंडसइंड बैंक लिमि.	305	657	748	850	2,560	1,820	1,136	2,956
13	जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमि.	537	178	108	175	998	943	626	1,569
14	कर्नाटक बैंक लिमि.	217	213	236	253	919	916	579	1,495
15	करूर वैश्य बैंक लिमि.	137	331	165	250	883	1,463	799	2,262
16	कोटक महिंद्रा बैंक लिमि.	325	307	425	889	1,946	1,766	1,525	3,291
17	नैनीताल बैंक लिमि.	55	34	47	34	170	-	-	-
18	आरबीएल बैंक लिमि.	65	72	96	311	544	359	36	395
19	साउथ इंडियन बैंक लिमि.	110	460	183	206	959	909	412	1,321
20	तमिलनाडु मर्केटाइल बैंक लिमि.	119	257	88	88	552	498	660	1,158
21	येस बैंक लिमि.	96	326	298	513	1,233	1,121	167	1,288

टिप्पणियां: 1. जनसंख्या समूहों को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है: 'ग्रामीण' में 10,000 से कम की आबादी वाले केंद्र शामिल हैं, 'अर्ध-शहरी' में 10,000 और उससे अधिक लेकिन एक लाख से कम की आबादी वाले केंद्र शामिल हैं, 'शहरी' में एक लाख और उससे अधिक लेकिन दस लाख से कम आबादी वाले केंद्र शामिल हैं और 'महानगर' में 10 लाख और उससे अधिक की आबादी वाले केंद्र शामिल हैं। सभी जनसंख्या के आंकड़े 2011 की जनगणना के अनुसार हैं।

2. शाखाओं के डेटा में 'प्रशासनिक कार्यालय' संबंधी डेटा शामिल नहीं हैं।

3. -: शून्य

स्रोत: बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेटाबेस (पूर्व में मास्टर ऑफिस फाइल सिस्टम) के लिए केंद्रीय सूचना प्रणाली, आरबीआई

परिशिष्ट सारणी IV.12: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की शाखाएं और एटीएम (समाप्त)

(मार्च 2024 के अंत में)

क्रम. सं.	बैंक का नाम	शाखाएं					एटीएम और सीआरएम		
		ग्रामीण	अर्ध-शहरी	शहरी	महानगरीय	कुल	शाखा स्थित	शाखेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	विदेशी बैंक	124	143	158	355	780	603	566	1,169
1	एबी बैंक पब्लिक लिमिटेड कंपनी	-	-	-	1	1	-	-	-
2	अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉरपोरेशन	-	-	-	1	1	-	-	-
3	ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड बैंकिंग ग्रुप लिमि.	1	-	1	1	3	-	-	-
4	बैंक ऑफ अमेरिका, नैशनल असोसिएशन	-	-	-	4	4	-	-	-
5	बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत बी.एस.सी	-	1	-	3	4	-	-	-
6	बैंक ऑफ सिलोन	-	-	-	1	1	-	-	-
7	बैंक ऑफ चाइना लिमि.	-	-	-	1	1	-	-	-
8	बैंक ऑफ नोवा स्कॉटिया	-	-	-	1	1	-	-	-
9	बरक्लेज बैंक पीएलसी	-	1	-	2	3	-	-	-
10	बीएनपी पारिबास	-	-	-	5	5	-	-	-
11	सिटीबैंक एन.ए	-	-	4	10	14	-	-	-
12	कॉमर्सेटिव रेबोबैंक यू.ए.	-	-	-	1	1	-	-	-
13	क्रेडिट एग्रीकोल कॉरपोरेट एंड इन्वेस्टमेंट बैंक	-	-	-	5	5	-	-	-
14	क्रेडिट सुइस एजी	-	-	-	1	1	-	-	-
15	सीटीबीसी बैंक को. लिमि.	-	1	-	1	2	-	-	-
16	डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड	114	136	116	156	522	436	472	908
17	डॉयचे बैंक एजी	1	-	5	11	17	13	2	15
18	दोहा बैंक क्यू.पी.एस.सी	-	-	1	1	2	2	-	2
19	एमिरेटस एनबीडी बैंक (पी.जे.एस.सी)	-	-	1	2	3	-	-	-
20	फर्स्ट अबू धाबी बैंक पी.जे.एस.सी	-	-	-	1	1	-	-	-
21	फर्स्टरैंड बैंक लिमि.	-	-	-	1	1	-	-	-
22	हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमि.	-	-	4	22	26	46	28	74
23	इंडस्ट्रियल एंड कामर्शियल बैंक ऑफ चाइना	-	-	-	1	1	-	-	-
24	इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ कोरिया	-	-	-	1	1	-	-	-
25	जेपी मोर्गन चेंस बैंक नैशनल असोसिएशन	2	-	-	2	4	-	-	-
26	जेएससी वीटीबी बैंक	-	-	-	1	1	-	-	-
27	केईबी हना बैंक	-	1	-	1	2	1	-	1
28	कूकमीन बैंक	-	-	1	-	1	1	-	1
29	क्रुग थाई बैंक पब्लिक कं.लिमि.	-	-	-	1	1	-	-	-
30	मशरेक बैंक पीएससी	-	-	-	1	1	-	-	-
31	मिजुओ बैंक लिमि.	-	1	1	3	5	-	-	-
32	एमयूएफजी बैंक लिमि.	1	-	-	4	5	-	-	-
33	नेटवेस्ट मार्केट्स पीएलसी	-	-	-	1	1	-	-	-
34	नॉगह्युप बैंक	-	-	1	-	1	-	-	-
35	पीटी बैंक मेबैंक इंडोनेशिया टीबीके	-	-	-	1	1	-	-	-
36	कतर नैशनल बैंक (क्यू.पी.एस.सी)	-	-	-	1	1	-	-	-
37	स्बेर बैंक	-	-	-	2	2	-	-	-
38	एसबीएम बैंक (इंडिया) लिमि.	3	-	1	12	16	-	-	-
39	शिनहान बैंक	1	-	-	5	6	-	-	-
40	सोसाइटी जनरल	-	-	-	2	2	-	-	-
41	सोनोली बैंक	-	-	1	1	2	-	-	-
42	स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक	1	1	20	78	100	102	64	166
43	सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन	-	1	-	2	3	-	-	-
44	यूनाइटेड ओवरसीज बैंक लिमि.	-	-	-	1	1	-	-	-
45	वरी बैंक	-	-	1	2	3	-	-	-

टिप्पणियाँ: 1. जनसंख्या समूहों को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है: 'ग्रामीण' में 10,000 से कम की आबादी वाले केंद्र शामिल हैं, 'अर्ध-शहरी' में 10,000 और उससे अधिक लेकिन एक लाख से कम की आबादी वाले केंद्र शामिल हैं, 'शहरी' में एक लाख और उससे अधिक लेकिन दस लाख से कम आबादी वाले केंद्र शामिल हैं और 'महानगर' में 10 लाख और उससे अधिक की आबादी वाले केंद्र शामिल हैं। सभी जनसंख्या के आंकड़े 2011 की जनगणना के अनुसार हैं।
2. शाखाओं के डेटा में 'प्रशासनिक कार्यालय' संबंधी डेटा शामिल नहीं हैं।
3. शून्य

स्रोत: बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेटाबेस (पूर्व में मास्टर ऑफिस फाइल सिस्टम) के लिए केंद्रीय सूचना प्रणाली, आरबीआई।

परिशिष्ट सारणी IV.13: सूक्ष्म वित्त कार्यक्रमों की प्रगति

(मार्च के अंत में)

मद	स्वयं सहायता समूह											
	संख्या (लाख में)						राशि (₹ करोड़ में)					
	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
बैंकों द्वारा संचितित ऋण (वित्तीय वर्ष के दौरान)	27.0 (17.8)	31.5 (22.1)	28.9 (17.0)	34.0 (24.8)	43.0 (36.9)	54.8 (47.6)	58,317.6 (36,818.5)	77,659.3 (55,589.9)	58,070.6 (31,755.1)	99,729.2 (68,916.9)	1,45,200.2 (1,25,106.3)	2,09,285.9 (1,83,297.1)
बैंकों के पास बकाया ऋण	50.8 (35.1)	56.8 (39.6)	57.8 (36.0)	67.4 (47.8)	69.6 (58.9)	77.4 (65.0)	87,098.2 (58,431.6)	1,08,075.1 (73,183.9)	1,03,289.0 (61,393.1)	1,51,051.0 (1,01,840.1)	1,88,078.8 (1,61,583.9)	2,59,663.7 (2,22,452.1)
बैंकों के पास बचत	100.1 (60.2)	102.4 (62.6)	112.2 (70.1)	118.9 (77.7)	134.0 (89.4)	144.2 (91.7)	23,324.5 (14,481.6)	26,152.0 (15,836.3)	37,477.0 (21,307.8)	47,240.5 (31,077.1)	58,892.7 (40,971.9)	65,089.2 (49,738.7)
सूक्ष्म वित्त संस्थाएं												
संख्या (लाख में)						राशि (₹ करोड़ में)						
बैंकों द्वारा संचितित ऋण	0.0	0.0	0.3	0.2	0.8	0.3	13,721.0	19,133.0	12,120.3	23,173.4	36,757.0	31,497.1
बैंकों के पास बकाया ऋण	0.1	0.2	0.6	0.6	1.1	1.9	16,044.8	27,255.8	21,062.7	34,865.4	44,119.8	59,592.7
संयुक्त देयता समूह												
संख्या (लाख में)						राशि (₹ करोड़ में)						
बैंकों द्वारा संचितित ऋण (वित्तीय वर्ष के दौरान)	16.0	41.8	41.3	54.1	70.0	73.3	30,946.9	83,103.0	58,311.8	1,12,772.8	1,33,372.9	1,88,313.4

टिप्पणियां: 1. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) के तहत शामिल एसएचजी का विवरण दर्शाते हैं।

2. बैंकों से ऋण लेने वाले एमएफआई की वास्तविक संख्या खातों की संख्या से कम हो सकती है, क्योंकि अधिकांश एमएफआई एक ही बैंक से कई बार और एकाधिक बैंकों से भी ऋण लेते हैं।

स्रोत: नाबार्ड

परिशिष्ट सारणी IV.14: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रमुख वित्तीय संकेतक: राज्य-वार (जारी)

(राशि ₹ करोड़ में)

	आरआरबी की संख्या	लाभ कमाने वाले		घाटे में चल रहे		निवल लाभ/हानि	आरआरबी की संख्या	लाभ कमाने वाले		घाटे में चल रहे		निवल लाभ/हानि
	मार्च-2023	संख्या	राशि	संख्या	राशि		मार्च-2024	संख्या	राशि	संख्या	राशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
मध्य क्षेत्र	7	7	1,039.2	0	0.0	1,039.2	7	7	1,262.9	0	0.0	1,262.9
छत्तीसगढ़	1	1	167.2	0	0.0	167.2	1	1	296.2	0	0.0	296.2
मध्य प्रदेश	2	2	236.5	0	0.0	236.5	2	2	500.4	0	0.0	500.4
उत्तर प्रदेश	3	3	591.6	0	0.0	591.6	3	3	391.0	0	0.0	391.0
उत्तराखंड	1	1	43.8	0	0.0	43.8	1	1	75.3	0	0.0	75.3
पूर्वी क्षेत्र	8	6	283.1	2	973.4	-690.2	8	8	624.9	0	0.0	624.9
बिहार	2	1	32.4	1	918.4	-886.0	2	2	94.9	0	0.0	94.9
झारखंड	1	1	94.3	0	0.0	94.3	1	1	115.9	0	0.0	115.9
ओडिशा	2	2	84.9	0	0.0	84.9	2	2	162.3	0	0.0	162.3
पश्चिम बंगाल	3	2	71.6	1	55.0	16.6	3	3	251.8	0	0.0	251.8
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	7	5	127.6	2	138.2	-10.6	7	6	206.6	1	1.8	204.8
अरुणाचल प्रदेश	1	1	20.6	0	0.0	20.6	1	1	27.3	0	0.0	27.3
असम	1	0	0.0	1	138.0	-138.0	1	1	4.2	0	0.0	4.2
मणिपुर	1	0	0.0	1	0.2	-0.2	1	0	0.0	1	1.8	-1.8
मेघालय	1	1	37.8	0	0.0	37.8	1	1	62.3	0	0.0	62.3
मिजोरम	1	1	65.2	0	0.0	65.2	1	1	84.5	0	0.0	84.5
नगालैंड	1	1	0.4	0	0.0	0.4	1	1	0.3	0	0.0	0.3
त्रिपुरा	1	1	3.6	0	0.0	3.6	1	1	27.9	0	0.0	27.9
उत्तरी क्षेत्र	7	5	1,091.2	2	93.1	998.1	7	6	1,235.0	1	49.4	1,185.6
हरियाणा	1	1	275.5	0	0.0	275.5	1	1	338.2	0	0.0	338.2
हिमाचल प्रदेश	1	1	2.2	0	0.0	2.2	1	1	6.9	0	0.0	6.9
जम्मू और कश्मीर	2	0	0.0	2	93.1	-93.1	2	1	3.8	1	49.4	-45.7
पंजाब	1	1	152.7	0	0.0	152.7	1	1	141.1	0	0.0	141.1
राजस्थान	2	2	660.8	0	0.0	660.8	2	2	745.1	0	0.0	745.1
दक्षिणी क्षेत्र	10	10	3,392.6	0	0.0	3,392.6	10	9	3,990.4	1	174.3	3,816.1
आंध्र प्रदेश	3	3	1,091.5	0	0.0	1,091.5	3	3	1,404.6	0	0.0	1,404.6
कर्नाटक	2	2	47.8	0	0.0	47.8	2	1	104.2	1	174.3	-70.1
केरल	1	1	324.6	0	0.0	324.6	1	1	405.8	0	0.0	405.8
पुदुचेरी	1	1	14.3	0	0.0	14.3	1	1	18.9	0	0.0	18.9
तमिलनाडु	1	1	418.3	0	0.0	418.3	1	1	446.7	0	0.0	446.7
तेलंगाना	2	2	1,496.0	0	0.0	1,496.0	2	2	1,610.2	0	0.0	1,610.2
पश्चिमी क्षेत्र	4	4	244.6	0	0.0	244.6	4	4	476.4	0	0.0	476.4
गुजरात	2	2	219.3	0	0.0	219.3	2	2	401.3	0	0.0	401.3
महाराष्ट्र	2	2	25.3	0	0.0	25.3	2	2	75.1	0	0.0	75.1
अखिल भारत	43	37	6,178.3	6	1,204.7	4,973.6	43	40	7,796.2	3	225.5	7,570.7

टिप्पणियाँ: 1. आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक, जिसका प्रधान कार्यालय वारंगल, तेलंगाना में है, तेलंगाना के 21 जिलों और आंध्र प्रदेश के 7 जिलों में परिचालन करता है। चूंकि इसका प्रधान कार्यालय तेलंगाना में है, इसलिए इसे उपरोक्त सारणी में तेलंगाना के अंतर्गत शामिल किया गया है।

2. जे एंड के ग्रामीण बैंक का प्रधान कार्यालय जम्मू में है और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में इसकी 4 शाखाएँ हैं। बैंक का डेटा जम्मू और कश्मीर राज्य के अंतर्गत दर्शाया गया है।

स्रोत: नाबार्ड

परिशिष्ट सारणी IV.14: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रमुख वित्तीय संकेतक: राज्य-वार (समाप्त)

(राशि ₹ करोड़ में)

क्षेत्र/ राज्य	सकल एनपीए (प्रतिशत)		सीआरएआर (प्रतिशत)	
	मार्च-23	मार्च-24	मार्च-23	मार्च-24
1	14	15	16	17
मध्य क्षेत्र	7.8	7.0	12.5	12.5
छत्तीसगढ़	2.3	2.0	18.5	17.6
मध्य प्रदेश	8.5	7.0	11.2	14.3
उत्तर प्रदेश	8.3	7.8	12.3	11.5
उत्तराखंड	5.5	4.1	11.5	12.6
पूर्वी क्षेत्र	19.5	15.0	8.0	9.4
बिहार	30.6	23.8	4.8	6.6
झारखंड	4.8	3.7	11.3	10.9
ओडिशा	14.7	11.6	9.8	10.5
पश्चिम बंगाल	10.7	8.0	10.7	12.6
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	11.6	7.3	15.2	15.1
अरुणाचल प्रदेश	2.8	3.3	13.4	15.9
असम	19.7	10.4	7.8	8.7
मणिपुर	10.9	10.7	6.9	10.7
मेघालय	6.4	5.2	13.7	15.3
मिजोरम	5.4	4.9	13.3	13.7
नगालैंड	1.2	0.8	8.4	10.0
त्रिपुरा	5.1	4.7	26.8	24.3
उत्तरी क्षेत्र	3.8	3.2	12.7	13.6
हरियाणा	4.3	3.2	14.2	14.8
हिमाचल प्रदेश	4.8	3.9	8.2	8.0
जम्मू और कश्मीर	5.9	5.4	4.1	9.5
पंजाब	5.9	5.1	15.6	16.5
राजस्थान	2.6	2.3	12.4	13.1
दक्षिणी क्षेत्र	4.1	4.0	16.4	17.6
आंध्र प्रदेश	1.1	0.9	19.6	21.1
कर्नाटक	10.7	11.5	10.2	10.5
केरल	2.3	2.1	13.1	13.5
पुदुचेरी	2.0	1.4	10.5	10.4
तमिलनाडु	1.4	1.0	13.6	13.3
तेलंगाना	2.4	2.4	22.7	25.1
पश्चिमी क्षेत्र	5.3	4.3	11.2	12.7
गुजरात	2.8	2.2	13.6	15.0
महाराष्ट्र	7.7	6.4	9.0	10.5
अखिल भारत	7.3	6.2	13.4	14.2

टिप्पणियाँ: 1. आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक, जिसका प्रधान कार्यालय वारंगल, तेलंगाना में है, तेलंगाना के 21 जिलों और आंध्र प्रदेश के 7 जिलों में परिचालन करता है। चूंकि इसका प्रधान कार्यालय तेलंगाना में है, इसलिए इसे उपरोक्त सारणी में तेलंगाना के अंतर्गत शामिल किया गया है।
2. जे एंड के ग्रामीण बैंक का प्रधान कार्यालय जम्मू में है और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में इसकी 4 शाखाएँ हैं। बैंक का डेटा जम्मू और कश्मीर राज्य के अंतर्गत दर्शाया गया है।

स्रोत: नाबार्ड

परिशिष्ट सारणी IV.15: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) - पीएसएल लक्ष्य और उपलब्धि - 2023-24

क्षेत्र/ उप क्षेत्र	लक्ष्य (प्रतिशत)	उपलब्धि (प्रतिशत)	लक्ष्य/ उप-लक्ष्य को पूरा न कर पाने वाले आरआरबी
1	2	3	4
समग्र प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र	75.0	88.6	सभी आरआरबी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सभी लक्ष्य/ उप-लक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं
कृषि	18.0	34.2	
लघु और सीमांत किसान	10.0	19.0	
गैर- कॉरपोरेट किसान	13.78	94.2	
सूक्ष्म उद्यम	7.5	15.0	
कमजोर वर्ग	15.0	84.8	

- टिप्पणियाँ:**
- वित्त वर्ष 2023-24 के लिए उपलब्धि की गणना, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के लिए उधार (पीएसएल) पर रिज़र्व बैंक के मास्टर निदेशों के अनुसार सभी तिमाहियों के सामान्य औसत के रूप में समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) के प्रतिशत के रूप में की गई है।
 - एएनबीसी पिछले वर्ष की इसी तारीख के अनुसार है।
 - जारी/खरीदे गए पीएसएलसी में फैक्ट्रिंग के बाद विभिन्न श्रेणियों के तहत उपलब्धि का आकलन किया गया है।
 - एएनबीसी की गणना करते समय, निवल बैंक ऋण में बाकी पीएसएलसी (खरीदे गए पीएसएलसी में से जारी पीएसएलसी को घटाकर) जोड़े गए हैं।

स्रोत: नाबार्ड।

भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति संबंधी रिपोर्ट 2023-24

परिशिष्ट सारणी V.1: वित्तीय प्रदर्शन के संकेतक: अनुसूचित यूसीबी (जारी)

(कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)

क्र. सं.	बैंकों के नाम	ब्याज आय		परिचालन लाभ		कर पश्चात निवल लाभ	
		2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अभ्युदय को.ऑप.बैंक लिमिटेड, मुंबई	6.0	6.6	0.1	0.3	-1.8	-1.9
2	अहमदाबाद मर्केटाइल को.ऑप.बैंक लिमिटेड	6.7	6.9	2.3	2.2	1.5	1.5
3	अकोला जनता कमर्शियल को.ऑप.बैंक लिमिटेड, अकोला	6.4	7.0	1.8	1.9	1.1	1.3
4	अकोला अर्बन को.ऑप.बैंक लिमिटेड, अकोला	6.1	6.8	3.2	1.3	0.3	0.8
5	अमानत को.ऑप.बैंक लिमिटेड, बंगलुरु	0.4	0.6	-0.3	0.0	-0.2	0.2
6	आंध्र प्रदेश महेश को.ऑप अर्बन बैंक लिमिटेड	7.9	8.0	1.0	1.7	0.6	1.9
7	अपना सहकारी बैंक लिमिटेड	6.5	5.5	0.4	-0.3	-1.5	-1.4
8	बसिन कैथोलिक को.ऑप.बैंक लिमिटेड	6.5	6.8	1.5	1.5	0.7	1.1
9	भारत को.ऑप.बैंक (मुंबई) लिमिटेड, मुंबई	6.6	6.8	1.1	1.0	-1.1	0.1
10	भारती सहकारी बैंक लिमिटेड	6.1	6.5	1.5	1.8	0.6	1.0
11	बॉम्बे मर्केटाइल को.ऑप बैंक लिमिटेड	4.7	4.7	0.8	0.7	0.1	0.2
12	सिटिजन क्रेडिट को.ऑप.बैंक लिमिटेड, मुंबई	6.7	7.1	1.3	1.3	0.6	0.6
13	कॉसमॉस को.ऑप.बैंक लिमिटेड	6.8	7.0	2.4	1.9	0.7	1.6
14	डोम्बिवली नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड	6.4	6.1	3.6	2.1	0.5	0.5
15	गोवा अर्बन को.ऑप.बैंक लिमिटेड	6.7	7.1	0.8	1.2	0.6	0.9
16	गोपीनाथ पाटिल पारसिक जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, ठाणे	6.8	6.9	1.3	1.7	0.7	1.0
17	ग्रेटर बॉम्बे को.ऑप.बैंक लिमिटेड	7.1	6.8	0.7	0.6	0.2	0.2
18	इंडियन मर्केटाइल को.ऑप बैंक लिमिटेड, लखनऊ	4.9	4.2	1.4	1.0	1.4	0.9
19	जलगांव जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	7.0	7.3	1.7	1.4	0.9	0.9
20	जलगांव पीपल्स को.ऑप.बैंक लिमिटेड	6.2	6.8	1.3	1.0	0.3	0.1
21	जनकल्याण सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई	5.5	6.9	0.1	1.2	0.1	0.3
22	जनलक्ष्मी को.ऑप.बैंक लिमिटेड, नासिक	3.8	4.8	-0.6	0.5	-0.6	0.5
23	जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे	6.2	6.4	1.2	1.0	0.1	0.4
24	कल्लाप्पण्णा आवाडे इंचलकरजी जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	7.1	7.2	1.6	1.6	0.5	0.4
25	कालपुर कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड	6.1	6.7	2.3	2.4	1.3	1.5
26	कल्याण जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, कल्याण	6.5	7.3	1.0	0.9	-0.6	0.4
27	कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई	-	-	-	-	-	-
28	कराड अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड	7.0	6.8	1.5	0.9	0.5	0.6
29	खामगांव अर्बन को.ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, खामगांव	6.5	6.6	2.2	1.9	0.6	0.6
30	महानगर को.ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई	6.9	7.4	1.1	1.1	0.6	1.0
31	मेहसाना अर्बन को.ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड	7.2	7.2	2.7	2.2	1.2	1.1
32	नगर अर्बन को.ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदनगर	-	-	-	-	-	-
33	नागपुर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड	6.6	7.0	1.2	1.3	0.2	0.4
34	नासिक मर्चेन्ट को.ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड	7.8	7.4	2.7	2.6	1.5	1.5
35	न्यू इंडिया को.ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई	6.7	6.4	0.0	-0.1	-1.0	0.2
36	एनकेजीएसबी को.ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई	6.8	6.6	1.1	0.6	0.3	0.2
37	नूतन नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद	6.2	6.8	0.6	0.5	0.5	0.6
38	प्रवरा सहकारी बैंक लिमिटेड	7.9	7.8	1.9	1.8	0.5	0.6
39	पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड	-	-	-	-	-	-
40	राजारामबापू सहकारी बैंक लिमिटेड	7.3	7.1	1.7	1.4	0.5	0.5
41	राजकोट नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड	6.8	7.3	2.1	1.8	1.3	1.2
42	रुपी को.ऑप.बैंक लिमिटेड	-	-	-	-	-	-
43	सांगली अर्बन को.ऑप.बैंक लिमिटेड, सांगली	6.1	7.2	0.1	1.7	0.0	1.7
44	सारस्वत को.ऑप.बैंक लिमिटेड, बॉम्बे	5.6	6.1	1.5	1.2	0.6	0.8
45	एसबीपीपी को.ऑप.बैंक लिमिटेड, किल्ला परदी	6.2	6.4	1.7	2.3	0.6	1.7
46	शामराव विठ्ठल को.ऑप.बैंक लिमिटेड	6.8	7.1	1.2	1.4	0.7	0.9
47	शिक्षक सहकारी बैंक लिमिटेड, नागपुर	5.0	6.6	0.0	1.6	0.1	1.8
48	सोलापुर जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	6.9	6.8	1.9	1.6	1.1	1.2
49	सूरत पीपल्स को.ऑप.बैंक लिमिटेड	7.1	7.5	1.7	2.2	1.1	1.5
50	ठाणे भारत सहकारी बैंक लिमिटेड	6.9	7.4	1.0	0.9	0.3	0.4
51	टीजेएसबी सहकारी बैंक	6.8	7.1	1.7	1.6	1.0	1.2
52	वसई विकास सहकारी बैंक लिमिटेड	6.8	6.7	0.8	1.1	0.2	0.3
53	जोरास्ट्रियन को.ऑप.बैंक लिमिटेड, बॉम्बे	6.8	7.1	0.9	0.4	0.2	0.2

टिप्पणियाँ: 1. वर्ष 2023-24 के लिए आंकड़े अनंतिम हैं।

2. शून्य /नगण्य।

स्रोत: ऑफ-साइट निगरानी विवरणियां, आरबीआई।

परिशिष्ट सारणी V.1: वित्तीय प्रदर्शन के संकेतक: अनुसूचित यूसीबी (समाप्त)

(कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)

क्र. सं.	बैंकों के नाम	ब्याज विस्तार		गैर-ब्याज व्यय		प्रावधान और आकस्मिकताएँ	
		2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24
1	2	9	10	11	12	13	14
1	अभ्युदय को.ऑप.बैंक लिमिटेड, मुंबई	3.8	4.1	2.7	2.8	2.8	3.4
2	अहमदाबाद मर्केटाइल को.ऑप.बैंक लिमिटेड	3.5	3.8	1.4	1.4	0.8	0.2
3	अकोला जनता कमर्शियल को.ऑप.बैंक लिमिटेड, अकोला	2.9	3.5	2.6	2.5	0.4	0.2
4	अकोला अर्बन को.ऑप.बैंक लिमिटेड, अकोला	3.3	3.8	2.9	2.8	2.5	0.1
5	अमानत को.ऑप.बैंक लिमिटेड, बंगलुरु	0.2	0.2	0.7	0.5	0.0	0.0
6	आंध्र प्रदेश महेश को.ऑप अर्बन बैंक लिमिटेड	4.9	4.4	2.6	2.2	0.2	-0.9
7	अपना सहकारी बैंक लिमिटेड	3.9	4.0	2.7	2.4	2.4	1.4
8	बसिन कैथोलिक को.ऑप.बैंक लिमिटेड	3.8	4.1	1.4	1.3	0.5	0.1
9	भारत को.ऑप.बैंक (मुंबई) लिमिटेड, मुंबई	4.0	4.4	2.1	2.0	2.6	0.8
10	भारती सहकारी बैंक लिमिटेड	3.3	3.1	1.6	1.7	0.8	0.5
11	बॉम्बे मर्केटाइल को.ऑप बैंक लिमिटेड	1.8	1.8	3.1	3.1	0.9	0.8
12	सिटिजन क्रेडिट को.ऑप.बैंक लिमिटेड, मुंबई	3.4	3.9	2.3	2.3	0.4	0.5
13	कॉसमॉस को.ऑप.बैंक लिमिटेड	3.7	4.1	2.0	2.0	1.4	0.0
14	डोम्बिवली नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड	3.2	3.2	2.5	2.5	1.7	1.1
15	गोवा अर्बन को.ऑप.बैंक लिमिटेड	4.0	3.9	2.3	2.3	0.0	0.0
16	गोपीनाथ पाटिल पारसिक जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, ठाणे	3.3	3.2	2.6	2.6	0.6	0.5
17	ग्रेटर बॉम्बे को.ऑप.बैंक लिमिटेड	4.3	4.1	2.8	3.0	0.5	0.3
18	इंडियन मर्केटाइल को.ऑप बैंक लिमिटेड, लखनऊ	1.2	1.6	2.4	2.3	-0.1	-0.5
19	जलगांव जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	3.6	4.2	2.1	2.4	0.6	0.3
20	जलगांव पीपल्स को.ऑप.बैंक लिमिटेड	3.3	4.0	2.3	2.4	1.9	1.4
21	जनकल्याण सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई	3.3	3.5	2.4	2.9	-0.3	0.6
22	जनलक्ष्मी को.ऑप.बैंक लिमिटेड, नासिक	2.3	2.3	3.0	3.4	0.0	0.0
23	जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे	3.7	4.1	1.6	1.7	1.7	1.1
24	कल्लाप्पण्णा आवाडे इचलकरंजी जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	4.1	4.4	1.7	1.6	1.1	0.9
25	कालूपुर कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड	3.3	3.7	1.1	1.1	0.4	0.4
26	कल्याण जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, कल्याण	4.0	4.2	2.5	2.7	1.5	0.4
27	कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई	-	-	-	-	-	-
28	कराड अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड	4.0	4.1	2.1	2.1	0.9	0.4
29	खामगांव अर्बन को.ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, खामगांव	2.7	3.2	2.3	2.3	1.3	1.0
30	महानगर को.ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई	3.6	3.8	2.5	2.9	0.4	0.1
31	मेहसाना अर्बन को.ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड	4.0	4.3	1.0	1.1	1.3	0.6
32	नगर अर्बन को.ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदनगर	-	-	-	-	-	-
33	नागपुर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड	3.3	3.7	2.5	2.7	1.4	0.9
34	नासिक मर्चेन्ट को.ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड	3.8	4.2	2.4	2.4	0.7	-0.2
35	न्यू इंडिया को.ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई	4.4	4.5	2.8	2.6	2.1	0.7
36	एनकेजीएसबी को.ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई	4.0	4.3	2.6	2.3	0.3	0.2
37	नूतन नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद	4.3	5.0	1.6	1.5	0.6	0.2
38	प्रवरा सहकारी बैंक लिमिटेड	4.4	4.7	2.4	1.8	1.3	0.9
39	पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड	-	-	-	-	-	-
40	राजारामबापू सहकारी बैंक लिमिटेड	4.5	4.7	1.8	1.4	1.2	0.9
41	राजकोट नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड	3.8	4.2	1.3	1.4	0.4	0.2
42	रुपी को.ऑप.बैंक लिमिटेड	-	-	-	-	-	-
43	सांगली अर्बन को.ऑप.बैंक लिमिटेड, सांगली	4.0	4.8	2.4	2.2	0.0	0.0
44	सारस्वत को.ऑप.बैंक लिमिटेड, बॉम्बे	3.3	3.9	1.7	1.7	0.6	-0.2
45	एसबीपीपी को.ऑप.बैंक लिमिटेड, किल्ला परदी	3.0	3.1	1.9	1.7	0.7	0.1
46	शामराव विठ्ठल को.ऑप.बैंक लिमिटेड	3.8	4.2	2.5	2.2	0.2	0.2
47	शिक्षक सहकारी बैंक लिमिटेड, नागपुर	3.1	3.5	2.5	2.7	0.8	0.3
48	सोलापुर जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	3.8	3.8	1.9	2.0	1.0	0.1
49	सूरत पीपल्स को.ऑप.बैंक लिमिटेड	4.5	4.8	1.2	1.1	0.3	0.3
50	ठाणे भारत सहकारी बैंक लिमिटेड	3.7	4.1	3.3	3.6	0.6	0.4
51	टीजेएसबी सहकारी बैंक	3.7	4.0	1.9	2.0	0.4	0.0
52	वसई विकास सहकारी बैंक लिमिटेड	4.4	4.1	1.9	2.0	0.7	0.8
53	जोरारिस्ट्रियन को.ऑप.बैंक लिमिटेड, बॉम्बे	3.7	3.9	2.8	3.0	0.4	0.1

टिप्पणियाँ: 1. वर्ष 2023-24 के लिए आंकड़े अनंतिम हैं।

2. शून्य /नगण्य।

स्रोत: ऑफ-साइट निगरानी विवरणियाँ, आरबीआई।

भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति संबंधी रिपोर्ट 2023-24

परिशिष्ट सारणी V.2: चुनिंदा वित्तीय मापदंड: अनुसूचित यूसीबी (मार्च 2024 के अंत में)

(प्रतिशत)

क्र. सं.	बैंक का नाम	जमाराशियों की औसत लागत	अग्रिमों पर प्राप्त औसत प्रतिफल	कुल आस्तियों की तुलना में निवल ब्याज आय (रुप्रेड)	कार्यकारी निधियों की तुलना में निवल ब्याज आय	कार्यकारी निधियों की तुलना में ब्याजेतर आय	आस्तियों पर प्रतिलाभ (आर ओ ए)	सीआर एआर	प्रति कर्मचारी कारोबार (₹ करोड़)	प्रति कर्मचारी लाभ (₹ करोड़)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	अभ्युदय को.ऑप.बैंक लिमिटेड, मुंबई	4.6	8.6	2.3	2.5	0.9	-1.8	2.1	5.9	-0.1
2	अहमदाबाद मर्केटाइल को.ऑप.बैंक लिमिटेड	5.6	9.0	3.4	3.2	0.5	1.6	33.4	46.6	0.2
3	अकोला अर्बन को.ऑप.बैंक लिमिटेड, अकोला	4.8	10.1	3.3	3.2	1.2	0.8	15.0	54.4	0.0
4	अमानत को.ऑप.बैंक लिमिटेड, बेंगलुरु	0.0	6.7	4.3	4.1	2.8	2.3	94.2	66.9	0.0
5	आंध्र प्रदेश महेश को.ऑप अर्बन बैंक लिमिटेड	5.4	11.3	3.5	3.5	0.3	1.8	45.2	28.0	0.1
6	अपना सहकारी बैंक लिमिटेड	5.0	7.2	1.4	1.6	0.6	-1.3	5.6	85.0	-0.1
7	बसिन कैथोलिक को.ऑप.बैंक लिमिटेड	5.5	9.0	2.8	2.8	0.2	1.1	22.3	55.0	0.2
8	भारती सहकारी बैंक लिमिटेड (पुणे)	3.9	8.9	3.6	3.5	0.2	1.1	21.2	67.6	0.1
9	बॉम्बे मर्केटाइल को.ऑप बैंक लिमिटेड	3.0	9.6	3.1	4.0	1.4	0.2	15.0	85.2	0.0
10	सिटिजन क्रेडिट को.ऑप.बैंक लिमिटेड, मुंबई	4.7	8.9	3.1	3.3	0.4	0.6	23.5	49.3	0.0
11	कॉसमॉस को.ऑप.बैंक लिमिटेड	5.2	9.4	3.1	3.0	2.3	1.7	15.4	93.3	0.1
12	डोम्बिवली नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड	4.4	9.9	3.5	3.5	2.0	0.5	15.6	69.3	0.0
13	गोवा अर्बन को.ऑप.बैंक लिमिटेड	5.2	9.3	3.3	32.0	3.6	0.9	21.0	62.1	0.0
14	जी.पी. पाटिल पारसिक जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, ठाणे	4.0	8.9	3.8	3.7	0.6	1.0	21.7	48.6	0.1
15	ग्रेटर बॉम्बे को.ऑप.बैंक लिमिटेड	4.6	8.3	2.8	2.8	2.0	0.2	19.5	72.9	0.0
16	जीएस महानगर को.ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई	4.8	10.2	3.7	3.8	0.8	1.0	17.4	57.5	0.1
17	इंडियन मर्केटाइल को.ऑप बैंक लिमिटेड, लखनऊ	3.2	4.7	2.9	3.6	1.0	1.0	57.6	21.5	0.0
18	जलगांव जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	5.2	10.2	3.3	3.3	0.7	0.9	15.7	94.8	0.1
19	जलगांव पीपल्स को.ऑप.बैंक लिमिटेड	5.0	9.8	2.9	2.8	1.1	0.1	13.3	74.7	0.0
20	जनकल्याण सहकारी बैंक लिमिटेड (मुंबई)	4.4	9.3	3.2	3.6	0.8	0.3	13.7	32.1	0.0
21	जनलक्ष्मी को.ऑप.बैंक लिमिटेड (नासिक)	5.0	11.1	2.3	3.9	2.3	0.5	32.9	29.0	0.0
22	जनता सहकारी बैंक लिमिटेड (पुणे)	5.0	8.8	2.6	2.4	1.8	0.5	14.3	61.3	0.0
23	कुल्लाप्पण्णा आवाडे इचलकरंजी जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	5.9	10.4	3.2	3.4	0.5	0.5	13.2	121.6	0.0
24	कराड अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड	5.5	9.5	3.0	3.0	0.9	0.7	16.2	66.0	0.0
25	खामगांव अर्बन को.ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, खामगांव	4.4	10.2	3.5	3.5	0.9	0.7	21.4	49.3	0.0
26	मेहसाना अर्बन को.ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड	5.8	9.9	3.3	3.0	0.5	1.3	15.3	88.7	0.2
27	नागपुर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड	4.4	9.0	3.3	3.3	0.8	0.4	14.2	86.6	0.0
28	नासिक मचेंट को.ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड	5.0	9.2	3.6	3.2	1.8	1.7	31.9	33.1	0.1
29	न्यू इंडिया को.ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई	4.9	10.0	1.9	2.0	1.7	0.2	9.1	53.8	0.0
30	एनकेजीएसबी को.ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई	5.3	8.9	2.5	2.5	0.6	0.3	12.8	92.3	0.0
31	नूतन नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड (अहमदाबाद)	6.1	9.0	1.8	1.7	0.8	0.7	15.3	74.8	0.1
32	प्रवरा सहकारी बैंक लिमिटेड	5.5	10.0	3.2	3.1	0.5	0.6	14.1	48.0	0.0
33	राजारामबापू सहकारी बैंक लिमिटेड	6.1	9.4	2.7	2.7	0.6	0.6	14.3	66.6	0.0
34	राजकोट नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड	5.4	9.8	3.3	3.2	0.1	1.3	18.2	69.7	0.1
35	सांगली अर्बन को.ऑप.बैंक लिमिटेड, सांगली	5.8	9.8	2.4	2.6	1.6	1.7	14.1	52.5	0.1
36	सारस्वत को.ऑप.बैंक लिमिटेड, बॉम्बे	5.3	9.3	2.6	2.4	0.8	0.9	17.3	83.4	0.1
37	एसबीपीपी को.ऑप.बैंक लिमिटेड, किल्ला परदी	4.5	9.7	3.8	3.6	0.8	1.9	20.8	72.3	0.1
38	शिक्षक सहकारी बैंक लिमिटेड, नागपुर	4.9	10.9	3.1	3.7	2.5	1.8	16.2	73.6	0.1
39	सोलापुर जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	5.2	10.5	3.2	3.4	0.6	1.3	17.9	61.3	0.1
40	सूरत पीपल्स को.ऑप.बैंक लिमिटेड	5.9	9.4	2.9	2.7	0.6	1.6	16.6	68.2	0.3
41	एसवीसी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड	5.4	9.8	3.0	3.4	0.8	0.9	15.4	86.2	0.1
42	ठाणे भारत सहकारी बैंक लिमिटेड	4.3	8.9	3.3	3.4	1.4	0.4	14.4	62.4	0.0
43	अकोला जनता कमर्शियल को.ऑप. बैंक लिमिटेड	4.7	11.1	3.9	3.7	0.9	1.4	24.5	47.8	0.1
44	भारत को.ऑप.बैंक (मुंबई) लिमिटेड, मुंबई	5.4	9.5	2.5	2.5	0.6	0.1	13.7	95.8	0.0
45	कालपुर कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड	5.3	9.3	3.4	3.2	0.6	1.7	20.4	82.0	0.2
46	कल्याण जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, कल्याण	4.9	9.8	3.1	3.1	0.7	0.4	11.6	97.4	0.0
47	टीजेएसबी सहकारी बैंक	5.1	9.8	3.4	3.2	0.6	1.4	17.6	62.1	0.1
48	वसई विकास सहकारी बैंक लिमिटेड	49.2	8.8	2.7	2.6	0.7	0.3	16.6	55.2	0.0
49	जोरास्ट्रियन को.ऑप.बैंक लिमिटेड, बॉम्बे	4.8	8.8	3.2	3.1	0.3	0.2	22.1	50.1	0.0

टिप्पणी: 31 मार्च 2024 तक के आंकड़े अंतिम हैं।

स्रोत: अप्रत्यक्ष निगरानी विवरणियां, आरबीआई।

परिशिष्ट सारणी V.3: राज्य सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति के प्रमुख संकेतक
(मार्च के अंत में)

(राशि ₹ लाख में)

क्र. सं.	क्षेत्र/ राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश	लाभ/हानि की राशि		बकाया ऋण के प्रतिशत के रूप में एनपीए		मांग की तुलना में वसूली (%)	
		2022-23	2023-24 ¹	31-मार्च-23	31-मार्च-24	30-जून-22	30-जून-23
1	2	3	4	5	6	7	8
	उत्तरी क्षेत्र	36,429	31,052	3.0	2.2	97.7	97.6
1	चंडीगढ़	550	1,174	3.3	2.4	80.5	83.9
2	दिल्ली	2,122	2,123	0.9	0.7	98.0	98.1
3	हरियाणा	8,852	6,185	0.1	-	100.0	100.0
4	हिमाचल प्रदेश	15,912	11,876	7.0	3.9	71.8	71.9
5	जम्मू और कश्मीर	-993	-1,489	53.0	55.5	73.6	63.0
6	पंजाब	2,678	3,561	0.9	0.9	99.3	98.4
7	राजस्थान	7,308	7,621	0.2	0.2	98.8	99.8
	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	5,016	10,148	9.7	9.2	62.3	80.3
8	अरुणाचल प्रदेश	-4,990	-2,057	50.1	39.9	26.1	15.8
9	असम	1,220	1,401	9.6	9.2	63.2	66.1
10	मणिपुर	366	401	24.1	18.1	63.7	64.6
11	मेघालय	1,477	1,670	7.6	8.0	48.4	31.4
12	मिजोरम	3,966	4,246	2.8	2.5	63.1	84.8
13	नगालैंड	242	858	15.9	14.2	60.5	59.7
14	सिक्किम	504	834	4.0	3.5	87.8	59.5
15	त्रिपुरा	2,231	2,795	7.2	7.6	74.9	93.7
	पूर्वी क्षेत्र	49,218	54,449	3.7	3.9	87.0	91.3
16	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	608	746	34.9	25.8	67.9	63.4
17	बिहार	7,616	6,764	2.3	3.1	64.1	17.3
18	झारखंड	3,060	6,669	11.9	9.4	52.7	55.0
19	ओडिशा	22,914	21,589	1.0	1.1	94.0	98.7
20	पश्चिम बंगाल	15,021	18,682	5.0	4.8	89.2	89.2
	मध्य क्षेत्र	23,617	23,673	3.9	3.8	94.4	92.7
21	छत्तीसगढ़	3,389	3,683	1.9	2.0	96.4	97.2
22	मध्य प्रदेश	12,817	11,154	4.3	5.1	91.8	86.0
23	उत्तर प्रदेश	6,076	7,287	3.9	3.1	97.3	98.1
24	उत्तराखंड	1,336	1,549	4.9	4.1	96.1	97.6
	पश्चिमी क्षेत्र	78,361	80,832	8.3	7.2	84.0	77.7
25	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	945	970	2.9	4.4	68.1	68.1
26	गोवा	177	482	10.0	4.2	80.8	91.7
27	गुजरात	10,559	10,692	0.8	0.7	95.9	96.1
28	महाराष्ट्र	66,680	68,688	10.7	9.2	82.4	73.9
	दक्षिणी क्षेत्र	53,114	68,990	5.6	5.1	91.7	94.6
29	आंध्र प्रदेश	18,265	18,980	0.6	0.5	99.7	97.9
30	कर्नाटक	11,000	6,500	4.4	4.6	97.9	97.6
31	केरल	3,252	24,781	12.1	11.2	78.4	73.3
32	पुदुचेरी	1,085	60	13.9	11.6	91.5	71.6
33	तमिलनाडु	11,478	12,129	2.6	2.9	99.4	99.4
34	तेलंगाना	8,034	6,540	0.1	0.1	98.7	98.8
	अखिल भारत	2,45,756	2,69,144	5.4	4.9	91.7	92.4

टिप्पणियाँ: 1. पी: अनंतिम।

2. पूर्णांकन के कारण कुल योग घटकों के जोड़ से भिन्न हो सकता है।

3. वित्तीय वर्ष के लिए वसूली 30 जून तक है।

स्रोत: नाबार्ड।

भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति संबंधी रिपोर्ट 2023-24

परिशिष्ट सारणी V.4: जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति के प्रमुख संकेतक (मार्च के अंत में)

(राशि ₹ लाख में)

क्र. सं.	क्षेत्र/ राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश	2022-23					2023-24 ^{पी}					2023		2024 ^{पी}	
		डीसीसीबी की संख्या	लाभ	हानि	डीसीसीबी की संख्या	राशि	डीसीसीबी की संख्या	लाभ	हानि	डीसीसीबी की संख्या	राशि	अनुपात की तुलना में एनपीए (%)	मांग की तुलना में वसूली (%) (जून के अंत में)*	ऋण अनुपात की तुलना में एनपीए (%)	मांग की तुलना में वसूली (%) (जून के अंत में)*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	उत्तरी क्षेत्र	73	65	27,640	8	10,005	73	65	29,841	8	15,330	9.6	77.1	8.5	73.6
1	हरियाणा	19	19	8,045	0	-	19	19	7,122	0	-	6.3	65.6	5.8	60.2
2	हिमाचल प्रदेश	2	2	6,582	0	-	2	2	8,399	0	-	25.2	76.9	21.0	70.5
3	जम्मू और कश्मीर	3	2	132	1	1,070	3	2	443	1	639	26.7	19.6	20.4	35.4
4	पंजाब	20	14	5,248	6	8,217	20	14	7,255	6	11,410	11.0	77.6	10.7	75.9
5	राजस्थान	29	28	7,633	1	717	29	28	6,622	1	3,282	6.0	87.8	5.2	83.7
	पूर्वी क्षेत्र	58	51	21,202	7	5,025	58	52	28,422	6	9,150	8.5	73.7	8.8	76.6
6	बिहार	23	17	1,145	6	2,301	23	19	2,558	4	3,228	9.2	39.2	12.2	51.8
7	झारखंड	1	1	85	0	-	1	1	146	0	-	12.7	54.5	28.1	66.6
8	ओडिशा	17	17	9,796	0	-	17	17	11,946	0	-	7.5	74.4	7.3	78.2
9	पश्चिम बंगाल	17	16	10,176	1	2,723	17	15	13,772	2	5,922	10.0	80.0	10.1	79.0
	मध्य क्षेत्र	104	78	42,504	26	50,467	104	89	62,991	15	63,188	18.4	66.1	15.7	66.4
10	छत्तीसगढ़	6	6	12,389	0	-	6	6	19,635	0	-	11.0	76.8	9.7	78.7
11	मध्य प्रदेश	38	23	14,599	15	40,989	38	29	22,174	9	59,041	25.8	60.2	22.7	57.9
12	उत्तर प्रदेश	50	39	10,039	11	9,478	50	44	11,446	6	4,147	8.2	73.5	6.3	79.3
13	उत्तराखंड	10	10	5,477	0	-	10	10	9,736	0	-	8.8	72.3	7.6	73.3
	पश्चिमी क्षेत्र	49	47	1,21,425	2	21,824	49	46	1,29,124	3	5,585	11.2	73.9	10.3	75.2
14	गुजरात	18	18	41,377	0	-	18	18	44,729	0	-	3.7	94.1	3.0	94.4
15	महाराष्ट्र	31	29	80,048	2	21,824	31	28	84,395	3	5,585	14.1	64.1	13.2	66.0
	दक्षिणी क्षेत्र	67	64	75,159	3	12,471	67	60	79,359	7	47,093	5.8	87.9	5.8	88.8
16	आंध्र प्रदेश	13	12	13,377	1	3,569	13	11	13,126	2	30,855	3.6	89.6	4.8	88.1
17	कर्नाटक	21	20	21,697	1	7,655	21	18	26,726	3	12,123	6.7	91.9	7.2	91.8
18	केरल	1	0	-	1	1,247	1	0	-	1	3,869	15.4	66.1	15.4	66.1
19	तमिलनाडु	23	23	31,080	0	-	23	23	27,200	0	-	6.3	83.7	5.5	88.6
20	तेलंगाना	9	9	9,004	0	-	9	8	12,307	1	246	3.8	85.4	3.2	84.7
	अखिल भारत	351	305	2,87,929	46	99,791	351	312	3,29,737	39	1,40,346	9.6	76.5	8.9	76.8

टिप्पणियाँ : 1. पूर्णांकन के कारण कुल योग घटकों के जोड़ से भिन्न हो सकते हैं।

2. वित्तीय वर्ष के लिए वसूली 30 जून तक है।

स्रोत: नाबार्ड।

परिशिष्ट सारणी V.5: प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के सदस्यों और उधारकर्ताओं का विवरण

(संख्या हजार में)

अखिल भारत	सदस्य		उधारकर्ता	
	2022	2023	2022	2023
1	2	3	4	5
अनुसूचित जाति	17,919	17,759	5,856	5,420
अनुसूचित जनजाति	19,527	19,254	3,745	3,209
लघु कृषक	70,217	73,057	27,518	28,189
ग्रामीण कारीगर	7,189	7,298	1,454	1,273
अन्य और सीमांत किसान	54,318	43,011	9,775	11,137

स्रोत: एनएफएससीओबी।

परिशिष्ट सारणी V.6: प्राथमिक कृषि ऋण समितियां

(राशि ₹ करोड़ में)

	मार्च के अंत में		प्रतिशत में घट-बढ़	
	2022	2023	2021-22	2022-23
1	2	3	4	5
देयताएं				
1. कुल संसाधन (2+3+4)	3,91,518	4,47,134	9.89	14.21
2. स्वाधिकृत निधियां (ए+बी)	42,754	48,566	1.05	13.59
ए. चुकता पूंजी	19,792	22,191	3.54	12.12
जिसमें से, सरकार का अंशदान	866	889	-3.78	2.66
बी. कुल आरक्षित निधियां	22,962	26,375	-1.01	14.86
3. जमाराशियां	1,76,390	1,97,239	3.20	11.82
4. उधारियां	1,72,374	2,01,329	20.50	16.80
5. कार्यशील पूंजी	3,69,896	4,09,377	10.51	10.67
आस्तियां				
1. कुल बकाया ऋण (ए+बी)	1,59,700	1,88,842	-26.36	18.25
ए. अल्पावधि	1,29,171	1,54,650	-32.05	19.73
बी. मध्यावधि	30,529	34,192	14.12	12.00

टिप्पणी: वर्ष-दर-वर्ष घट-बढ़ में कुछ अंतर हो सकता है क्योंकि पूर्ण संख्याओं का ₹ करोड़ में पूर्णांकन किया गया है।

स्रोत: एनएफएससीओबी।

परिशिष्ट सारणी V.7: प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के चुनिंदा संकेतक - राज्यवार (जारी)
(मार्च 2023 के अंत में)

(राशि ₹ लाख में)

क्र. सं.	राज्य	पीएसीएस की संख्या	जमाराशियां	कार्यशील पूंजी	बकाया ऋण तथा अग्रिम		लाभ वाली समितियां	
					कृषि	कृषीतर	संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	उत्तरी क्षेत्र	15,081	17,15,959	57,48,792	26,84,829	78,138	10,076	60,371
1	चंडीगढ़*	17	6	5	0	0	10	1
2	हरियाणा	776	45,843	16,24,138	6,02,697	33,508	50	875
3	हिमाचल प्रदेश	2,193	6,10,846	7,72,194	1,20,728	12,511	1,847	6,800
4	जम्मू और कश्मीर	609	405	3,514	2,168	901	474	19
5	पंजाब*	3,998	7,72,226	13,28,203	7,12,988	22,050	2,062	22,908
6	राजस्थान	7,488	2,86,632	20,20,738	12,46,248	9,169	5,633	29,768
	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	9,741	3,16,586	1,59,417	36,967	32,356	1,000	9,114
7	अरुणाचल प्रदेश	35	एन.ए.	5,830	0	0	13	22
8	असम*	766	0	11,123	575	20	309	7,639
9	मणिपुर	309	7	1,214	5	1	148	96
10	मेघालय	510	2,15,876	8,169	4,296	44	217	129
11	मिजोरम	73	3,071	532	410	311	38	928
12	नगालैंड*	7,601	97,313	1,17,058	30,245	31,586	N.A.	N.A.
13	सिक्किम	179	227	119	1,225	260	153	269
14	त्रिपुरा	268	92	15,371	211	134	122	30
	पूर्वी क्षेत्र	18,632	7,98,038	17,05,953	9,32,530	41,617	4,351	7,660
15	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	58	110	2,364	1,748	854	20	32
16	बिहार*	8,463	17,533	50,816	0	0	1,180	604
17	झारखंड	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.
18	ओडिशा	2,703	5,68,806	11,45,467	7,80,159	10,179	772	3,646
19	पश्चिम बंगाल	7,408	2,11,589	5,07,306	1,50,624	30,584	2,379	3,378
	मध्य क्षेत्र	16,043	2,52,035	17,22,415	6,83,267	57,123	8,227	34,953
20	छत्तीसगढ़	1,924	26,828	6,10,162	1,58,144	3,105	996	7,165
21	मध्य प्रदेश*	4,457	81,731	6,45,546	3,39,959	11,892	2,153	13,124
22	उत्तराखंड	733	1,36,656	3,40,780	1,05,134	42,125	542	12,891
23	उत्तर प्रदेश*	8,929	6,820	1,25,927	80,031	0	4,536	1,774
	पश्चिमी क्षेत्र	31,167	10,66,120	64,20,812	44,60,381	6,14,524	14,421	26,722
24	गोवा	93	12,202	19,848	1,013	5,815	53	446
25	गुजरात	9,212	76,845	18,88,074	16,37,777	58,675	6,735	14,211
26	महाराष्ट्र	21,862	9,77,072	45,12,891	28,21,590	5,50,034	7,633	12,065
	दक्षिणी क्षेत्र	16,291	1,55,75,148	2,51,80,342	60,74,386	21,86,080	9,719	75,414
27	आंध्र प्रदेश	2,042	3,69,807	24,50,386	14,75,391	0	1,194	30,162
28	तेलंगाना*	823	40,254	7,05,820	5,79,231	21,218	579	5,994
29	कर्नाटक	7,240	17,84,113	49,11,666	23,14,548	9,22,180	4,231	14,024
30	केरल*	1,620	1,21,69,710	1,35,32,893	4,46,114	2,28,188	927	14,150
31	पुदुचेरी	53	21,815	29,644	35	22,060	16	350
32	तमिलनाडु	4,513	11,89,449	35,49,933	12,59,067	9,92,435	2,772	10,734
	अखिल भारत	1,06,955	1,97,23,884	4,09,37,731	1,48,72,360	30,09,837	47,794	2,14,234

टिप्पणियां: 1. *: डेटा पिछले वर्ष से संबंधित हैं।

2. पूर्णांकन के कारण कुल योग घटकों के जोड़ से भिन्न हो सकता है।

3. एन.ए.: उपलब्ध नहीं।

स्रोत: एनएफएससीओबी।

भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति संबंधी रिपोर्ट 2023-24

परिशिष्ट सारणी V.7: प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के चुनिंदा संकेतक - राज्यवार (समाप्त)
(मार्च 2023 के अंत में)

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य	हानिग्रस्त समितियां		अर्थक्षम	संभावित रूप से अर्थक्षम	निष्क्रिय	अप्रचलित	अन्य
		संख्या	राशि					
1	2	10	11	12	13	14	15	16
	उत्तरी क्षेत्र	4,375	79,695	12,752	1,556	434	205	134
1	चंडीगढ़*	5	0	4	0	13	0	0
2	हरियाणा	726	58,577	776	0	0	0	0
3	हिमाचल प्रदेश	254	1,079	642	1,388	130	4	29
4	जम्मू और कश्मीर	75	2	461	57	17	72	2
5	पंजाब*	1,513	6,619	3,505	111	150	129	103
6	राजस्थान	1,802	13,417	7,364	0	124	0	0
	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	947	10,869	9,387	265	66	23	0
7	अरुणाचल प्रदेश	20	12	32	0	0	3	0
8	असम*	419	9,909	709	57	0	0	0
9	मणिपुर	70	66	183	103	10	13	0
10	मेघालय	293	842	401	68	41	0	0
11	मिजोरम	7	4	46	27	0	0	0
12	नगालैंड*	एन.ए.	एन.ए.	7,601	0	0	0	0
13	सिक्किम	22	12	147	10	15	7	0
14	त्रिपुरा	116	23	268	0	0	0	0
	पूर्वी क्षेत्र	9,915	23,531	14,108	2,767	587	412	758
15	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	26	197	43	12	3	0	0
16	बिहार*	3,962	94	8,463	0	0	0	0
17	झारखंड	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.
18	ओडिशा	1,912	21,766	1,649	509	11	1	533
19	पश्चिम बंगाल	4,015	1,473	3,953	2,246	573	411	225
	मध्य क्षेत्र	5,031	44,383	13,326	2,094	386	167	70
20	छत्तीसगढ़	782	23,240	1,888	36	0	0	0
21	मध्य प्रदेश*	2,129	17,824	3,663	720	4	0	70
22	उत्तराखंड	152	3,167	660	69	0	4	0
23	उत्तर प्रदेश*	1,968	153	7,115	1,269	382	163	0
	पश्चिमी क्षेत्र	12,444	20,202	24,349	4,683	1,100	862	173
24	गोवा	13	75	58	4	13	18	0
25	गुजरात	1,590	6,512	5,622	2,867	432	158	133
26	महाराष्ट्र	10,841	13,615	18,669	1,812	655	686	40
	दक्षिणी क्षेत्र	4,645	1,79,871	10,717	4,390	279	98	807
27	आंध्र प्रदेश	842	92,009	1,157	832	16	0	37
28	तेलंगाना*	242	2,827	702	112	1	0	8
29	कर्नाटक	1,398	4,948	4,638	2,174	117	72	239
30	केरल*	658	68,110	1,580	0	15	25	0
31	पुदुचेरी	29	3,209	16	29	7	0	1
32	तमिलनाडु	1,476	8,768	2,624	1,243	123	1	522
	अखिल भारत	37,357	3,58,550	84,639	15,755	2,852	1,767	1,942

टिप्पणियां: 1. *: डेटा पिछले वर्ष से संबंधित हैं।
2. पूर्णांकन के कारण कुल योग घटकों के जोड़ से भिन्न हो सकता है।
3. एन.ए.: उपलब्ध नहीं।

स्रोत: एनएएफएससीओबी।

परिशिष्ट सारणी V.8: राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों की देयताएं और आस्तियां

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	मार्च अंत में		प्रतिशत में घट-बढ़	
	2022	2023 ^क	2021-22	2022-23
1	2	3	4	5
देयताएं				
1. पूंजी	967 (3.4)	973 (3.5)	1.9	0.6
2. आरक्षित निधियां	5,294 (18.8)	5,572 (20)	3.5	5.2
3. जमाराशियां	2,584 (9.2)	2,621 (9.4)	2.1	1.4
4. उधारियां	13,409 (47.7)	12,559 (45.2)	0.9	-6.3
5. अन्य देयताएं	5,842 (20.8)	6,069 (21.8)	8.5	3.9
आस्तियां				
1. नकदी और बैंक शेष	241 (0.9)	253 (0.9)	3.2	4.7
2. निवेश	2,357 (8.4)	2,913 (10.5)	3.8	23.6
3. ऋण तथा अग्रिम	20,854 (74.2)	20,770 (74.7)	-0.4	-0.4
4. संचित हानि	586 (2.1)	627 (2.3)	13.2	6.8
5. अन्य आस्तियां	4,058 (14.4)	3,231 (11.6)	22.9	-20.4
कुल देयताएं/ आस्तियां	28,097 (100.00)	27,794 (100.00)	3.0	-1.1

- टिप्पणियां:**
1. कोष्ठकों में दिये गए आंकड़े कुल देयताओं/ आस्तियों के अनुपात (प्रतिशत में) हैं।
 2. वर्ष-दर-वर्ष घट-बढ़ में कुछ अंतर हो सकता है क्योंकि सारणी में पूर्ण संख्याओं का ₹ 1 करोड़ में पूर्णांकन किया गया है।
 3. पूर्णांकन के कारण कुल योग घटकों के जोड़ से भिन्न हो सकता है।
 4. पी- अनंतिम

स्रोत: नाबार्ड

परिशिष्ट सारणी V.9: राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों का वित्तीय प्रदर्शन

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मद	की अवधि में		प्रतिशत में घट-बढ़	
		2021-22	2022-23 ^क	2021-22	2022-23
1	2	3	4	5	6
ए.	आय (i + ii)	2,457 (100.00)	3,412 (100.00)	4.8	38.9
	i. ब्याज आय	2,069 (84.2)	2,364 (69.3)	-4.1	14.2
	ii. अन्य आय	388 (15.8)	1,049 (30.7)	107.9	170.4
बी.	व्यय (i + ii + iii+ iv)	2,373 (100.00)	3,004 (100.00)	8.8	26.6
	i. व्ययकृत ब्याज	1,009 (42.5)	1,035 (34.4)	-14.3	2.6
	ii. प्रावधान और आकस्मिकताएं	614 (25.9)	563 (18.7)	32.3	-8.3
	iii. परिचालन व्यय	750 (31.6)	1,407 (46.8)	39.2	87.5
	जिसमें से : वेतन बिल	390 (16.5)	395 (13.1)	12.1	1.2
सी.	लाभ				
	i. परिचालन लाभ	698	971	11.2	39.0
	ii. निवल लाभ	85	408	-48.4	382.0

टिप्पणियां: 1. कोष्ठकों में दिये गए आंकड़े कुल देयताओं/ आस्तियों के अनुपात (प्रतिशत में) हैं।
2. वर्ष-दर-वर्ष घट-बढ़ में कुछ अंतर हो सकता है क्योंकि सारणी में पूर्ण संख्याओं का ₹ 1 करोड़ में पूर्णांकन किया गया है।
3. पूर्णांकन के कारण कुल योग घटकों के जोड़ से भिन्न हो सकता है।
4. पी- अन्तिम

स्रोत: नाबार्ड।

परिशिष्ट सारणी V.10: राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों की आस्ति गुणवत्ता

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	मार्च अंत में		प्रतिशत घट-बढ़	
	2022	2023 ^अ	2021-22	2022-23
1	2	3	4	5
ए. कुल एनपीए (i + ii + iii)	7,522	7,571	8.4	0.7
i. अवमानक	2,786 (37)	2,362 (31.2)	19.2	-15.2
ii. सदिग्ध	4,701 (62.5)	5,173 (68.3)	2.9	10.0
iii. हानि	35 (0.5)	35 (0.5)	-1.2	2.2
बी. ऋण की तुलना में एनपीए अनुपात (%)	36.1	36.5		
सी. मांग की तुलना में वसूली अनुपात (%)	40.8	42.8		

- टिप्पणियां: 1. कोष्ठकों में दिये गए आंकड़े कुल एनपीए के अनुपात हैं।
 2. वर्ष-दर-वर्ष घट-बढ़ में कुछ अंतर हो सकता है क्योंकि पूर्ण संख्याओं का ₹ 1 करोड़ में पूर्णांकन किया गया है।
 3. पूर्णांकन के कारण कुल योग घटकों के जोड़ से भिन्न हो सकता है।
 4. पी-अनंतिम।

स्रोत: नाबार्ड।

परिशिष्ट सारणी V.11: राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के प्रमुख वित्तीय संकेतक-राज्य-वार
(मार्च के अंत में)

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	क्षेत्र / राज्य/ यूटी	शाखाएं	लाभ/ हानि		ऋण की तुलना में एनपीए अनुपात (%)		वसूली अनुपात (%) [*] (जून अंत में)	
		2023	2022	2023 ^{पी}	2022	2023 ^{पी}	2021	2022 ^{पी}
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	उत्तरी क्षेत्र	104	-5,825	16,336	57.2	62.9	18.5	22.4
1	हरियाणा @	0	-4,873	-2,057	77.6	76.6	11.6	11.6
2	हिमाचल प्रदेश #	51	185	-165	42.7	38.0	42.6	41.0
3	जम्मू और कश्मीर*	51	-2,283	-1,790	49.4	55.0	30.7	32.4
4	पंजाब @	0	273	19,680	45.3	62.0	25.7	42.2
5	राजस्थान @	2	873	669	53.8	55.6	18.2	16.7
	उत्तर पूर्वी क्षेत्र	5	-38	16	99.5	98.3	8.8	29.8
6	असम*	-	-	-	-	-	-	-
7	त्रिपुरा*	5	-38	16	99.5	98.3	8.8	29.8
	पूर्वी क्षेत्र	11	615	700	24.5	24.7	33.9	34.7
8	बिहार*	-	-	-	-	-	-	-
9	ओडिशा@	-	-	-	-	-	-	-
10	पश्चिम बंगाल #	11	615	700	24.5	24.7	33.9	34.7
	मध्य क्षेत्र	323	491	9,808	80.2	81.9	29.1	29.1
11	छत्तीसगढ़@	-	-	-	-	-	-	-
12	मध्य प्रदेश@	-	-	-	-	-	-	-
13	उत्तर प्रदेश*	323	491	9,808	80.2	81.9	29.1	29.1
	पश्चिमी क्षेत्र	176	3,331	6,006	58.5	44.1	9.0	14.4
14	गुजरात*	176	3,331	6,006	58.5	44.1	9.0	14.4
15	महाराष्ट्र@	-	-	-	-	-	-	-
	दक्षिणी क्षेत्र	73	9,892	7,936	15.9	14.1	71.0	73.9
16	कर्नाटक@	25	2,930	4	33.0	38.7	32.2	32.0
17	केरल @	16	2,930	3,447	11.1	8.3	84.0	86.5
18	पुदुचेरी*	1	15	22	8.1	8.8	89.5	91.2
19	तमिलनाडु@	31	4,018	4,464	22.0	11.6	79.9	88.6
	अखिल भारत	692	8,466	40,803	36.1	36.5	40.8	42.8

@: संघीय संरचना

#: मिश्रित संरचना

*: एकल संरचना

-: लागू नहीं

टिप्पणियां:

1. पूर्णांकन के कारण घटकों का जोड़ सटीक कुल से भिन्न हो सकता है।
2. छत्तीसगढ़ में 2014-15 के दौरान अल्पकालिक सहकारी ऋण संरचना का दीर्घकालिक सहकारी ऋण संरचना के साथ विलय कर दिया गया। साथ ही असम, बिहार, ओडिशा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में एससीएआरडीबी अब कार्यशील नहीं हैं।
3. वित्तीय वर्ष के लिए वसूली 30 जून तक है।
4. पी – अनंतिम।

स्रोत: नाबार्ड।

परिशिष्ट सारणी V.12: प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों की देयताएं और आस्तियां

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	मार्च के अंत में		प्रतिशत में घट-बढ़	
	2022	2023 ^P	2021-22	2022-23
1	2	3	4	5
देयताएं				
1. पूंजी	1,076 (3.2)	1,094 (3.4)	0.1	1.7
2. आरक्षित निधियां	4,402 (13.2)	4,433 (13.7)	44.6	0.7
3. जमाराशियां	1,675 (5)	1,720 (5.3)	6.6	2.7
4. उधारियां	17,286 (51.7)	16,712 (51.5)	1.4	-3.3
5. अन्य देयताएं	9,022 (27)	8,486 (26.2)	-9.9	-5.9
आस्तियां				
1. नकदी और बैंक शेष	557 (1.7)	420 (1.3)	8.4	-24.7
2. निवेश	2,305 (6.9)	2,378 (7.3)	-13.6	3.2
3. ऋण तथा अग्रिम	16,623 (49.7)	15,773 (48.6)	3.1	-5.1
4. संचित हानि	6,545 (19.6)	6,664 (20.5)	10.2	1.8
5. अन्य आस्तियां	7,431 (22.2)	7,210 (22.2)	-0.8	-3.0
कुल देयताएं/ आस्तियां	33,461 (100.00)	32,445 (100.00)	2.2	-3.0

टिप्पणियां: 1. कोष्ठकों में दिये गए आंकड़े कुल देयताओं/ आस्तियों के अनुपात (प्रतिशत में) हैं।
 2. वर्ष-दर-वर्ष घट-बढ़ में कुछ अंतर हो सकता है क्योंकि सारणी में पूर्ण संख्याओं का ₹ 1 करोड़ में पूर्णांकन किया गया है।
 3. पूर्णांकन के कारण कुल योग घटकों के जोड़ से भिन्न हो सकता है।
 4. पी - अंतिम डेटा।

स्रोत: नाबार्डी

परिशिष्ट सारणी V.13: प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों का वित्तीय प्रदर्शन

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	की अवधि में		घट-बढ़ प्रतिशत	
	2021-22	2022-23 ^क	2021-22	2022-23
1	2	3	4	5
ए. आय (i + ii)	2,877	3,419	-3.3	18.8
	(100.00)	(100.00)		
i. ब्याज आय	1,824	1,912	-9.9	4.8
	(63.4)	(55.9)		
ii. अन्य आय	1,053	1,507	10.7	43.1
	(36.6)	(44.1)		
बी. व्यय (i + ii + iii)	3,467	3,199	0.2	-7.7
	(100.00)	(100.00)		
i. व्ययकृत ब्याज	1,701	1,632	-6.4	-4.1
	(49.1)	(51)		
ii. प्रावधान और आकस्मिकताएँ	1,067	948	-1.3	-11.1
	(30.8)	(29.6)		
iii. परिचालन व्यय	698	619	24.2	-11.4
	(20.1)	(19.3)		
जिनमें : वेतन बिल	493	433	47.2	-12.2
	(14.2)	(13.5)		
सी. लाभ				
i. परिचालन लाभ	478	1,168	-20.0	144.5
ii. निवल लाभ	-589	220		

टिप्पणियाँ: 1. कोष्ठकों में दिये गए आंकड़े कुल आय/ व्यय के अनुपात (प्रतिशत में) हैं।
2. वर्ष-दर-वर्ष घट-बढ़ में कुछ अंतर हो सकता है क्योंकि पूर्ण संख्याओं का ₹ 1 करोड़ में पूर्णांकन किया गया है।
3. पूर्णांकन के कारण कुल योग घटकों के जोड़ से भिन्न हो सकता है।
4. पी - अनंतिम डेटा।

स्रोत: नाबार्ड।

परिशिष्ट सारणी V.14 : प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों की आस्ति गुणवत्ता

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	मार्च के अंत में		प्रतिशत में घट-बढ़	
	2022	2023 ^अ	2021-22	2022-23
1	2	3	4	5
ए. कुल एनपीए (i + ii + iii)	6,768	6,371	-0.7	-5.9
i. अवमानक	2,925 (43.2)	2,552 (40)	-9.9	-12.8
ii. संदिग्ध	3,812 (56.3)	3,784 (59.4)	7.3	-0.7
iii. हानि	30 (0.4)	36 (0.6)	63.0	17.9
बी. सकल एनपीए अनुपात (%)	40.7	40.4	-	-
सी. मांग और वसूली अनुपात (%)	35.6	39.1	-	-

- टिप्पणियां:
1. कोष्ठकों में दिये गए आंकड़े कुल एनपीए के अनुपात हैं।
 2. वर्ष-दर-वर्ष घट-बढ़ में कुछ अंतर हो सकता है क्योंकि पूर्ण संख्याओं का ₹ 1 करोड़ में पूर्णांकन किया गया है।
 3. पूर्णांकन के कारण कुल योग घटकों के जोड़ से भिन्न हो सकता है।
 4. पी - अनंतिम।
 5. वित्तीय वर्ष के लिए वसूली 30 जून तक है।

स्रोत: नाबार्ड।

परिशिष्ट सारणी V.15: प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के प्रमुख वित्तीय संकेतक

(राशि ₹ करोड़ में)

राज्य	2021-22				2022-23 ^{पी}				ऋण की तुलना में एनपीए का अनुपात		वसूली अनुपात (%) (जून अंत में)	
	लाभ		हानि		लाभ		हानि		2022	2023 ^{पी}	2021	2022 ^{पी}
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
उत्तरी क्षेत्र	18	985	127	40,600	102	35,310	43	14,821	69.9	70.8	16.0	16.5
हरियाणा	0	0	19	17,266	0	0	19	8,088	85.0	86.5	10.2	12.2
हिमाचल प्रदेश	0	0	1	55	0	0	1	164	34.6	31.8	52.1	53.6
पंजाब	5	355	84	16,642	87	34,866	2	97	78.7	84.0	13.6	13.5
राजस्थान	13	630	23	6,638	15	444	21	6,472	40.1	35.8	32.6	31.3
मध्य क्षेत्र	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
छत्तीसगढ़	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
मध्य प्रदेश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
पूर्वी क्षेत्र	12	1,995	12	2,535	8	2,630	16	3,259	35.4	34.2	38.1	36.2
ओडिशा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
पश्चिम बंगाल	12	1,995	12	2,535	8	2,630	16	3,259	35.4	34.2	38.1	36.2
पश्चिमी क्षेत्र	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
महाराष्ट्र	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
दक्षिणी क्षेत्र	173	6,562	262	25,331	241	14,539	193	12,427	30.5	30.0	58.6	64.4
कर्नाटक	48	2,620	131	8,097	56	1,997	124	8,386	20.5	19.9	58.0	58.5
केरल	30	2,528	46	12,040	59	9,154	15	2,102	33.8	34.8	57.5	63.6
तमिलनाडु	95	1,414	85	5,194	126	3,387	54	1,939	20.1	12.5	68.3	80.5
अखिल भारत	203	9,542	401	68,467	351	52,478	252	30,507	40.7	40.4	35.6	39.1

टिप्पणियां:

1. छत्तीसगढ़ में 2014-15 के दौरान अल्पकालिक सहकारी ऋण संरचना का दीर्घकालिक सहकारी ऋण संरचना के साथ विलय कर दिया गया।
2. पूर्णांकन के कारण कुल योग घटकों के जोड़ से भिन्न हो सकता है।
3. पी - अनंतिम डेटा।
4. वित्तीय वर्ष के लिए वसूली 30 जून तक है।
5. वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए डेटा रिपोर्ट किए गए 608 पीसीएआरडीबी में से 603 से संबंधित हैं।

स्रोत: नाबार्ड।

परिशिष्ट सारणी VI.1: एनबीएफसी का समेकित तुलन पत्र

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	मार्च 2022 के अंत में	मार्च 2023 के अंत में	मार्च 2024 के अंत में	सितंबर 2024 के अंत में	प्रतिशत घट- बढ 2023-24
1	2	3	4	5	6
1. शेयर पूंजी	1,11,939	1,21,904	1,47,168	1,43,974	20.7
2. आरक्षित निधियां और अधिशेष	6,81,772	8,40,859	10,07,781	10,97,033	19.9
3. जनता की जमाराशियां	70,564	85,254	1,02,994	1,12,512	20.8
4. कुल उधारियां (ए + बी)	25,45,808	29,74,034	34,46,024	36,92,670	15.9
ए. जमानती उधार	14,66,499	17,44,236	20,14,281	21,59,496	15.5
ए.1 डिबेंचर्स	5,70,619	6,21,407	6,65,740	7,22,876	7.1
ए.2 बैंकों से लिया गया उधार	7,29,122	9,05,331	10,70,442	11,24,714	18.2
ए.3 एफआई से लिया गया उधार	56,484	73,218	94,328	89,892	28.8
ए.4 उपचित ब्याज	19,520	15,220	17,011	33,966	11.8
ए.5 अन्य	90,754	1,29,060	1,66,760	1,88,049	29.2
बी. गैर-जमानती उधार	10,79,309	12,29,798	14,31,742	15,33,174	16.4
बी.1 डिबेंचर्स	4,36,537	4,84,536	5,63,256	6,05,327	16.2
बी.2 बैंकों से लिया गया उधार	1,80,357	2,18,416	2,61,177	2,69,610	19.6
बी.3 एफआई से लिया गया उधार	9,654	13,071	17,424	19,114	33.3
बी.4 रिश्तेदारों से लिया गया उधार	2,919	2,598	2,624	2,621	1.0
बी.5 अंतर कंपनी उधार	84,223	1,01,924	1,04,788	1,17,369	2.8
बी.6 वाणिज्यिक पत्र	68,568	83,529	1,05,374	1,16,143	26.2
बी.7 उपचित ब्याज	17,061	17,716	21,021	22,450	18.7
बी.8 अन्य	2,79,989	3,08,008	3,56,077	3,80,542	15.6
5. चालू देयताएं और प्रावधान	3,08,930	3,35,068	3,64,639	4,07,402	8.8
कुल देयताएं/ कुल आस्तियां	37,19,012	43,57,119	50,68,607	54,53,592	16.3
1. ऋण और अग्रिम	28,95,753	33,99,655	40,27,478	42,92,708	18.5
1.1 जमानती	21,00,743	23,63,698	31,15,385	32,47,905	31.8
1.2 गैर जमानती	7,95,010	10,35,957	9,12,093	10,44,803	-12.0
2. निवेश	4,35,053	5,16,141	6,24,260	6,93,397	20.9
2.1 सरकारी प्रतिभूतियां	65,406	93,677	1,22,147	1,33,764	30.4
2.2 इक्विटी शेयर	2,32,800	2,54,920	3,39,837	3,73,979	33.3
2.3 अधिमानी शेयर	4,362	17,474	12,104	6,270	-30.7
2.4 डिबेंचर्स और बॉण्ड	32,265	33,287	35,577	43,551	6.9
2.5 म्यूचुअल फंड इकाइयां	62,612	63,917	57,272	73,775	-10.4
2.6 वाणिज्यिक पत्र	1,714	2,311	2,547	4,552	10.2
2.7 अन्य निवेश	35,894	50,556	54,777	57,505	8.3
3. नकदी और बैंक शेष	1,68,099	1,73,802	1,72,422	2,01,157	-0.8
3.1 हाथ में नकदी	5,195	6,377	6,446	4,948	1.1
3.2 बैंकों में जमाराशियां	1,49,547	1,54,876	1,51,525	1,79,584	-2.2
4. अन्य	2,20,106	2,67,520	2,44,446	2,66,330	-8.6
मेमो आइटम					
1. पूंजी बाजार का एक्सपोजर	2,22,019	2,71,505	3,74,072	3,55,037	37.8
जिनमें से : इक्विटी शेयर	1,59,728	1,87,270	2,71,512	2,42,775	45.0
2. कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में सीएमई	6.0	6.2	7.4	6.5	
3. लीवरेज अनुपात	2.4	2.3	2.1	2.2	

टिप्पणियां: 1. डेटा अनंतिम हैं।
2. वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-24 के लिए दिया हुआ डेटा 31 मार्च 2024 तक अपर लेयर और मिडिल लेयर में आने वाले एनबीएफसी (सीआईसी, एचएफसी और एसपीडी को छोड़कर) से संबंधित हैं।
3. प्रतिशत आंकड़ों का पूर्णांकन किया गया है।

स्रोत: एनबीएफसी की तिमाही विवरणियां, आरबीआई।

परिशिष्ट सारणी VI.2: एनबीएफसी-यूएल का समेकित तुलन पत्र

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	मार्च 2022 के अंत में	मार्च 2023 के अंत में	मार्च 2024 के अंत में	सितंबर 2024 के अंत में	प्रतिशत घट- बढ़ 2023-24
1	2	3	4	5	6
1. शेयर पूंजी	7,000	7,344	9,034	5,299	23.0
2. आरक्षित निधियाँ और अधिशेष	1,50,838	1,91,938	2,45,188	2,47,205	27.7
3. जनता की जमाशियाँ	47,609	64,797	83,102	92,707	28.2
4. कुल उधरियाँ (ए + बी)	5,89,763	7,48,506	9,53,405	9,60,200	27.4
ए. जमानती उधार	5,06,124	6,40,877	8,17,360	8,34,850	27.5
ए.1 डिबेंचर्स	1,87,833	2,13,684	2,56,627	2,63,501	20.1
ए.2 बैंकों से लिया गया उधार	2,48,512	3,18,979	4,08,471	4,07,733	28.1
ए.3 एफआई से लिया गया उधार	18,143	30,005	44,041	28,807	46.8
ए.4 उपचित ब्याज	7,874	6,165	8,229	8,460	33.5
ए.5 अन्य	43,762	72,044	99,993	1,26,350	38.8
बी. गैर जमानती उधार	83,639	1,07,630	1,36,045	1,25,349	26.4
बी.1 डिबेंचर्स	9,802	11,731	14,817	13,173	26.3
बी.2 बैंकों से लिया गया उधार	6,318	6,218	4,602	4,740	-26.0
बी.3 एफआई से लिया गया उधार	-	-	-	-	
बी.4 रिश्तेदारों से लिया गया उधार	973	615	700	652	13.7
बी.5 अंतर-कॉर्पोरेट उधार	12,769	21,059	25,589	27,971	21.5
बी.6 वाणिज्यिक पत्र	24,511	39,550	54,146	48,326	36.9
बी.7 उपचित ब्याज	1,593	1,889	2,569	2,303	36.0
बी.8 अन्य	27,673	26,568	33,622	28,184	26.5
5. चालू देयताएं और प्रावधान	50,849	58,463	68,793	68,374	17.7
कुल देयताएं/ कुल आस्तियां	8,46,058	10,71,050	13,59,521	13,73,785	26.9
1. ऋण और अग्रिम	7,27,253	9,18,302	11,85,621	11,94,234	29.1
1.1 जमानती	5,71,374	6,91,720	8,95,934	9,03,899	29.5
1.2 गैर-जमानती	1,55,878	2,26,582	2,89,687	2,90,335	27.9
2. निवेश	50,703	75,479	95,189	89,520	26.1
2.1 सरकारी प्रतिभूतियां	25,677	37,465	50,634	46,854	35.2
2.2 इक्विटी शेयर	10,265	14,195	21,454	17,299	51.1
2.3 अधिमानी शेयर	50	114	35	15	-69.6
2.4 डिबेंचर्स और बॉण्ड	2,247	1,608	1,634	2,236	1.6
2.5 म्यूचुअल फंड इकाइयां	4,590	10,567	7,116	7,253	-32.7
2.6 वाणिज्यिक पत्र	-	691	1,005	2,017	45.3
2.7 अन्य निवेश	7,875	10,838	13,312	13,848	22.8
3. नकदी और बैंक शेष	45,483	46,946	43,228	56,110	-7.9
3.1 हाथ में नकदी	726	673	853	1,358	26.7
3.2 बैंकों में जमाशियां	38,171	44,046	38,463	49,823	-12.7
4. अन्य	22,619	30,323	35,483	33,921	17.0
मेमो आइटम					
1. पूंजी बाजार का एक्सपोजर	30,320	41,880	48,744	54,870	16.4
जिनमें से : इक्विटी शेयर	5,017	10,553	16,504	16,787	56.4
2. कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में सीएमई	3.6	3.9	3.6	4.0	
3. लीवरेज अनुपात	2.3	2.4	2.3	2.4	

टिप्पणियां: 1. डेटा अनंतिम हैं।
2. वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-24 के लिए दिया हुआ डेटा 31 मार्च 2024 तक अपर लेयर और मिडिल लेयर में आने वाले एनबीएफसी (सीआईसी, एचएफसी और एसपीडी को छोड़कर) से संबंधित है।
3. प्रतिशत आंकड़ों का पूर्णांकन किया गया है।

स्रोत: एनबीएफसी की तिमाही विवरणियाँ, आरबीआई

परिशिष्ट सारणी VI.3: एनबीएसी-एमएल का समेकित तुलन पत्र

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	मार्च 2022 के अंत में	मार्च 2023 के अंत में	मार्च 2024 के अंत में	सितंबर 2024 के अंत में	प्रतिशत घट- बढ 2023-24
1	2	3	4	5	6
1. शेयर पूंजी	1,04,939	1,14,559	1,38,135	1,38,675	20.6
2. आरक्षित निधियां और अधिशेष	5,30,934	6,48,921	7,62,594	8,49,827	17.5
3. जनता की जमाराशियां	22,955	20,457	19,893	19,805	-2.8
4. कुल उधारियाँ (ए + बी)	19,56,046	22,25,527	24,92,619	27,32,471	12.0
ए. जमानती उधार	9,60,375	11,03,359	11,96,921	13,24,646	8.5
ए.1 डिबेंचर्स	3,82,786	4,07,723	4,09,113	4,59,375	0.3
ए.2 बैंकों से लिया गया उधार	4,80,610	5,86,352	6,61,971	7,16,981	12.9
ए.3 एफआई से लिया गया उधार	38,342	43,213	50,288	61,085	16.4
ए.4 उपचित ब्याज	11,646	9,055	8,783	25,506	-3.0
ए.5 अन्य	46,992	57,016	66,767	61,699	17.1
बी. गैर जमानती उधार	9,95,670	11,22,168	12,95,697	14,07,825	15.5
बी.1 डिबेंचर्स	4,26,736	4,72,806	5,48,440	5,92,154	16.0
बी.2 बैंकों से लिया गया उधार	1,74,038	2,12,199	2,56,574	2,64,870	20.9
बी.3 एफआई से लिया गया उधार	9,654	13,071	17,424	19,114	33.3
बी.4 रिश्तेदारों से लिया गया उधार	1,947	1,983	1,924	1,968	-2.9
बी.5 अंतर-कॉर्पोरेट उधार	71,454	80,864	79,199	89,398	-2.1
बी.6 वाणिज्यिक पत्र	44,058	43,979	51,228	67,816	16.5
बी.7 उपचित ब्याज	15,468	15,827	18,452	20,147	16.6
बी.8 अन्य	2,52,316	2,81,440	3,22,455	3,52,358	14.6
5. चालू देयताएं और प्रावधान	2,58,081	2,76,605	2,95,846	3,39,029	7.0
कुल देयताएं/ कुल आस्तियां	28,72,954	32,86,069	37,09,086	40,79,806	12.9
1. ऋण और अग्रिम	21,68,501	24,81,353	28,41,857	30,98,474	14.5
1.1 जमानती	15,29,369	16,71,978	22,19,451	23,44,006	32.7
1.2 गैर-जमानती	6,39,132	8,09,375	6,22,406	7,54,469	-23.1
2. निवेश	3,84,350	4,40,663	5,29,071	6,03,877	20.1
2.1 सरकारी प्रतिभूतियां	39,729	56,212	71,513	86,911	27.2
2.2 इक्विटी शेयर	2,22,535	2,40,725	3,18,383	3,56,681	32.3
2.3 अधिमानी शेयर	4,313	17,360	12,069	6,256	-30.5
2.4 डिबेंचर्स और बॉण्ड	30,018	31,679	33,943	41,315	7.1
2.5 म्यूचुअल फंड इकाइयां	58,022	53,350	50,156	66,522	-6.0
2.6 वाणिज्यिक पत्र	1,714	1,620	1,542	2,535	-4.8
2.7 अन्य निवेश	28,019	39,717	41,465	43,658	4.4
3. नकदी और बैंक शेष	1,22,616	1,26,856	1,29,194	1,45,047	1.8
3.1 हाथ में नकदी	4,469	5,704	5,594	3,590	-1.9
3.2 बैंकों में जमाराशियां	1,11,376	1,10,830	1,13,061	1,29,761	2.0
4. अन्य	1,97,487	2,37,197	2,08,963	2,32,409	-11.9
मेमो आइटम					
1. पूंजी बाजार का एक्सपोजर	1,91,700	2,29,625	3,25,328	3,00,167	41.7
जिनमें से: इक्विटी शेयर	1,54,711	1,76,717	2,55,008	2,25,988	44.3
2. कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में सीएमई	6.7	7.0	8.8	7.4	
3. लीवरेज अनुपात	2.4	2.2	2.0	2.1	

टिप्पणियां: 1. डेटा अनंतिम हैं।

2. वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-24 के लिए दिया हुआ डेटा 31 मार्च 2024 तक अपर लेयर और मिडिल लेयर में आने वाले एनबीएफसी (सीआईसी, एचएफसी और एसपीडी को छोड़कर) से संबंधित है।

3. प्रतिशत आंकड़ों का पूर्णांकन किया गया है।

स्रोत: एनबीएफसी की तिमाही विवरणियां, आरबीआई

परिशिष्ट सारणी VI.4: एनबीएफसी-डी का समेकित तुलन पत्र

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	मार्च 2022 के अंत में	मार्च 2023 के अंत में	मार्च 2024 के अंत में	सितंबर 2024 के अंत में	प्रतिशत घट- बढ़ 2023-24
1	2	3	4	5	6
1. शेयर पूंजी	7,048	8,178	8,075	8,170	-1.3
2. आरक्षित निधियां और अधिशेष	1,04,963	1,28,224	1,55,219	1,67,891	21.1
3. जनता की जमाराशियां	70,564	85,254	1,02,994	1,12,512	20.8
4. कुल उधारियाँ (ए + बी)	3,01,017	3,65,642	4,57,846	5,07,693	25.2
ए. जमानती उधार	2,60,271	3,06,685	3,82,154	4,33,172	24.6
ए.1 डिबेंचर्स	1,02,909	1,09,487	1,25,077	1,51,047	14.2
ए.2 बैंकों से लिया गया उधार	1,19,735	1,30,355	1,72,039	1,89,245	32.0
ए.3 एफआई से लिया गया उधार	11,370	9,748	10,946	9,978	12.3
ए.4 उपचित ब्याज	3,657	2,678	3,294	4,349	23.0
ए.5 अन्य	22,600	54,418	70,797	78,553	30.1
बी. गैर जमानती उधार	40,746	58,957	75,692	74,521	28.4
बी.1 डिबेंचर्स	6,094	7,553	7,902	8,118	4.6
बी.2 बैंकों से लिया गया उधार	85	905	652.47	451.4189	-27.9
बी.3 एफआई से लिया गया उधार	-	-	0	0	
बी.4 रिश्तेदारों से लिया गया उधार	48	52	73.1331	0	40.6
बी.5 अंतर-कॉर्पोरेट उधार	11,106	18,216	23,119	26,582	26.9
बी.6 वाणिज्यिक पत्र	7,899	16,589	27,682	24,491	66.9
बी.7 उपचित ब्याज	1,066	1,476	1,712	1,809	16.0
बी.8 अन्य	14,448	14,166	14,550	13,071	2.7
5. चालू देयताएं और प्रावधान	71,159	73,639	79,885	88,959	8.5
कुल देयताएं/ कुल आस्तियां	5,54,751	6,60,937	8,04,019	8,85,225	21.6
1. ऋण और अग्रिम	4,63,831	5,52,904	6,86,374	7,46,825	24.1
1.1 जमानती	3,59,896	4,25,438	5,30,345	5,30,483	24.7
1.2 गैर-जमानती	1,03,935	1,27,467	1,56,029	2,16,342	22.4
2. निवेश	45,953	59,872	69,038	78,113	15.3
2.1 सरकारी प्रतिभूतियां	25,655	30,383	39,992	37,362	31.6
2.2 इक्विटी शेयर	12,279	14,894	16,337	19,020	9.7
2.3 अधिमानी शेयर	3	67	5,6735	5,6735	-91.5
2.4 डिबेंचर्स और बॉण्ड	317	888	503.4778	1007.4021	-43.3
2.5 म्यूचुअल फंड इकाइयां	4,523	6,844	3,766	6,332	-45.0
2.6 वाणिज्यिक पत्र	100	705	1735.9268	2625.9386	146.2
2.7 अन्य निवेश	3,077	6,092	6,698	11,759	10.0
3. नकदी और बैंक शेष	32,750	29,323	27,796	36,105	-5.2
3.1 हाथ में नकदी	637	612	1088.0694	1133.5392	77.8
3.2 बैंकों में जमाराशियाँ	32,112	28,711	22,653	30,446	-21.1
4. अन्य	12,217	18,838	20,810	24,182	10.5
मेमो आइटम					
1. पूंजी बाजार का एक्सपोजर	15,798	27,544	38,966	41,836	41.5
जिनमें से: इक्विटी शेयर	595	2407	14833	15047	516.2
2. कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में सीएमई	2.8	4.2	4.8	4.7	
3. लीवरेज अनुपात	4.2	4.2	2.2	2.3	

टिप्पणियां: 1. डेटा अनंतिम हैं।
2. वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-24 के लिए दिया हुआ डेटा 31 मार्च 2024 तक अपर लेयर और मिडिल लेयर में आने वाले एनबीएफसी (सीआईसी, एचएफसी और एसपीडी को छोड़कर) से संबंधित हैं।
3. प्रतिशत आंकड़ों का पूर्णांकन किया गया है।

स्रोत: एनबीएफसी की तिमाही विवरणियाँ, आरबीआई

परिशिष्ट सारणी VI.5: एनबीएफसी द्वारा विभिन्न क्षेत्रों को ऋण

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	मार्च 2022 के अंत में	मार्च 2023 के अंत में	मार्च 2024 के अंत में	सितंबर 2024 के अंत में	प्रतिशत घट- बढ़ 2023-24
1	2	3	4	5	6
सकल अग्रिम (1 से 5)	28,95,753	33,99,655	40,27,528	42,92,708	18.5
1. कृषि और संबंध कार्यकलाप	52,069	60,674	84,175	89,800	38.7
2. उद्योग (2.1 से 2.4)	11,15,957	12,69,175	14,96,425	15,90,339	17.9
2.1 सूक्ष्म और लघु	42,353	69,410	1,00,627	1,21,589	45.0
2.2 मध्यम	16,013	19,483	20,961	21,504	7.6
2.3 बड़े	8,90,104	10,21,373	12,32,434	13,00,359	20.7
2.4 अन्य	1,67,486	1,58,908	1,42,404	1,46,887	-10.4
3. सेवाएं (3.1 से 3.10 = 3.ए से 3.डी)	3,92,121	4,68,009	5,66,932	6,08,246	21.1
3.1 परिवहन परिचालक	1,03,283	1,20,245	1,32,810	1,41,289	10.4
3.2 कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	1,652	2,107	3,082	2,579	46.3
3.3 पर्यटन, हॉटेल और रेस्तरां	5,971	7,519	7,439	7,860	-1.1
3.4 नौवहन	172	185	272	216	46.9
3.5 पेशेवर सेवाएं	20,154	23,580	25,239	29,377	7.0
3.6 व्यापार	49,837	69,520	92,324	1,05,415	32.8
3.6.1 थोक व्यापार (खाद्य की खरीद के अलावा)	9,290	10,657	14,500	17,632	36.1
3.6.2 खुदरा व्यापार	40,547	58,863	77,824	87,784	32.2
3.7 वाणिज्यिक स्थावर संपदा	80,264	81,662	88,512	89,482	8.4
3.8 एनबीएफसी	33,774	47,664	60,356	64,319	26.6
3.9 विमानन	1,143	826	455	438	-44.9
3.10 अन्य सेवाएं	95,873	1,14,700	1,56,442	1,67,272	36.4
कुल 3.ए से 3.डी	3,92,121	4,68,009	5,66,932	6,08,246	21.1
3.ए सूक्ष्म और लघु	1,11,482	1,60,253	2,09,555	2,24,653	30.8
3.बी मध्यम	17,503	20,322	28,550	25,073	40.5
3.सी बड़े	76,915	78,518	80,697	95,366	2.8
3.डी अन्य	1,86,221	2,08,917	2,48,129	2,63,155	18.8
4. खुदरा ऋण (4.1 से 4.10)	8,19,433	10,45,168	13,69,820	15,02,697	31.1
4.1 आवास ऋण (प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के आवास सहित)	22,340	32,172	33,600	38,467	4.4
4.2 उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएँ	24,771	31,541	40,957	48,142	29.9
4.3 क्रेडिट कार्ड प्राप्त राशि	32,710	44,007	55,736	61,171	26.7
4.4 वाहन/ ऑटो ऋण	3,26,347	3,82,825	4,74,839	5,17,092	24.0
4.5 शैक्षणिक ऋण	14,145	25,324	44,904	58,466	77.3
4.6 मीयादी जमाराशि पर अग्रिम (एफसीएनआर(बी), आदि सहित)	41	213	151	202	-29.3
4.7 शेयर, बॉण्ड, आदि पर वैयक्तिक अग्रिम	11,473	13,389	21,780	23,991	62.7
4.8 स्वर्ण पर वैयक्तिक अग्रिम	1,18,501	1,28,774	1,53,481	1,74,325	19.2
4.9 सूक्ष्म वित्त ऋण/ एसएचजी ऋण	76,223	1,15,187	1,48,503	1,44,162	28.9
4.10. अन्य खुदरा ऋण	1,92,881	2,71,735	3,95,868	4,36,679	45.7
5. अन्य ऋण	5,16,173	5,56,630	5,10,174	5,01,626	-8.3

टिप्पणियां: 1. डेटा अनंतिम हैं।

2. वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-24 के लिए दिया हुआ डेटा 31 मार्च 2024 तक अपर लेयर और मिडिल लेयर में आने वाले एनबीएफसी (सीआईसी, एचएफसी और एसपीडी को छोड़कर) से संबंधित हैं।

3. प्रतिशत आंकड़ों का पूर्णांकन किया गया है।

स्रोत: एनबीएफसी की तिमाही विवरणियां, आरबीआई।

परिशिष्ट सारणी VI.6: एनबीएफसी-यूएल का वित्तीय प्रदर्शन

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	2021-22	2022-23	2023-24	छ1: 2024-25
1	2	3	4	5
ए. कुल आय	1,12,952	1,41,310	1,82,115	1,01,219
(i) निधि आधारित आय	1,07,477	1,32,676	1,71,480	95,976
	(95.2)	(93.9)	(94.2)	(94.8)
(ii) शुल्क आधारित आय	588	2,424	4,219	2,314
	(0.5)	(1.7)	(2.3)	(2.3)
बी. व्यय	86,201	1,02,181	1,30,395	71,939
(i) वित्तीय व्यय	43,258	52,579	72,748	39,868
	(50.2)	(51.5)	(55.8)	(55.4)
जिसमें से, ब्याज भुगतान	21,849	29,132	42,930	24,514
	(25.3)	(28.5)	(32.9)	(34.1)
(ii) परिचालन व्यय	22,903	30,588	37,349	19,606
	(26.6)	(29.9)	(28.6)	(27.3)
(iii) अन्य	20,039	19,014	20,298	12,465
	(23.2)	(18.6)	(15.6)	(17.3)
सी. कर प्रावधान	6,823	10,373	13,102	7,263
डी. कर पूर्व लाभ	26,751	39,129	51,720	29,280
ई. निवल लाभ	19,928	28,756	38,618	22,017
एफ. कुल आस्तियां	8,46,058	10,71,050	13,59,521	13,73,785
जी. वित्तीय अनुपात (कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)				
(i) आय	13.4	13.2	13.4	14.7
(ii) निधिगत आय	12.7	12.4	12.6	14.0
(iii) शुल्क आय	0.1	0.2	0.3	0.3
(iv) व्यय	10.2	9.5	9.6	10.5
(v) वित्तीय व्यय	5.1	4.9	5.4	5.8
(vi) परिचालन व्यय	2.7	2.9	2.7	2.9
(vii) कर प्रावधान	0.8	1.0	1.0	1.1
(viii) निवल लाभ	2.4	2.7	2.8	3.2
एच. आय के लिए लागत (प्रतिशत)	76.3	72.3	71.6	71.1

- टिप्पणियां:**
1. डेटा अनंतिम है और वर्ष 2024-25 की पहली छमाही के अनुपातों को वार्षिकीकृत किया गया है।
 2. कुल आय में गैर-वित्तीय आय भी शामिल है, जो सारणी में रिपोर्ट नहीं की गई है।
 3. वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-24 के लिए दिया हुआ डेटा 31 मार्च 2024 तक अपर लेयर और मिडिल लेयर में आने वाले एनबीएफसी (सीआईसी, एचएफसी और एसपीडी को छोड़कर) से संबंधित है।
 4. कोष्ठकों में दिये आंकड़े संबंधित कुल का शेयर (प्रतिशत में) है।
 5. प्रतिशत आंकड़ों का पूर्णांकन किया गया है।

स्रोत: एनबीएफसी की तिमाही विवरणियां, आरबीआई।

परिशिष्ट सारणी VI.7: एनबीएफसी-एमएल का वित्तीय प्रदर्शन

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	2021-22	2022-23	2023-24	छ1: 2024-25
1	2	3	4	5
ए. कुल आय	2,63,729	3,22,712	4,01,842	2,28,365
(i) निधि आधारित आय	2,45,353	2,79,241	3,68,892	2,12,037
	(93)	(86.5)	(91.8)	(92.9)
(ii) शुल्क आधारित आय	11,452	14,522	18,211	10,117
	(4.3)	(4.5)	(4.5)	(4.4)
बी. व्यय	2,08,718	2,30,457	2,79,370	1,63,223
(i) वित्तीय व्यय	1,25,178	1,40,759	1,69,159	99,662
	(60)	(61.1)	(60.6)	(61.1)
जिसमें से, ब्याज भुगतान	58,582	72,485	94,985	48,447
	(28.1)	(31.5)	(34)	(29.7)
(ii) परिचालन व्यय	37,493	47,232	58,601	35,189
	(18)	(20.5)	(21)	(21.6)
(iii) अन्य	46,046	42,465	51,610	28,372
	(22.1)	(18.4)	(18.5)	(17.4)
सी. कर प्रावधान	13,426	14,904	23,958	10,971
डी. कर पूर्व लाभ	55,011	92,255	1,22,473	65,142
ई. निवल लाभ	41,585	77,351	98,515	54,171
एफ. कुल आस्तियां	28,72,954	32,86,069	37,09,086	40,79,806
जी. वित्तीय अनुपात (कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)				
(i) आय	9.2	9.8	10.8	11.2
(ii) निधिगत आय	8.5	8.5	9.9	10.4
(iii) शुल्क आय	0.4	0.4	0.5	0.5
(iv) व्यय	7.3	7.0	7.5	8.0
(v) वित्तीय व्यय	4.4	4.3	4.6	4.9
(vi) परिचालन व्यय	1.3	1.4	1.6	1.7
(vii) कर प्रावधान	0.5	0.5	0.6	0.5
(viii) निवल लाभ	1.4	2.4	2.7	2.7
एच. आय के लिए लागत (प्रतिशत)	79.1	71.4	69.5	71.5

- टिप्पणियां:**
1. डेटा अनंतिम है और वर्ष 2024-25 की पहली छमाही के अनुपातों को वार्षिकीकृत किया गया है।
 2. कुल आय में गैर-वित्तीय आय भी शामिल है, जो सारणी में रिपोर्ट नहीं की गई है।
 3. वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-24 के लिए दिया हुआ डेटा 31 मार्च 2024 तक अपर लेयर और मिडिल लेयर में आने वाले एनबीएफसी (सीआईसी, एचएफसी और एसपीडी को छोड़कर) से संबंधित है।
 4. कोष्ठकों में दिये आंकड़े संबंधित कुल का शेयर (प्रतिशत में) है।
 5. प्रतिशत आंकड़ों का पूर्णांकन किया गया है।

स्रोत: एनबीएफसी की तिमाही विवरणियां, आरबीआई।

भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति संबंधी रिपोर्ट 2023-24

परिशिष्ट सारणी VI.8: वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत और वितरित वित्तीय सहायता (जारी)

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	ऋण*							
	2022-23		2023-24		अप्रै-सित 2023		अप्रै-सित 2024	
	एस	डी	एस	डी	एस	डी	एस	डी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ए. अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (1 से 5)	7,98,186	7,53,909	9,55,137	8,73,592	4,41,252	3,14,050	3,69,686	2,87,209
1. नाबार्ड	3,83,494	3,64,248	4,42,156	4,36,033	1,67,846	96,819	1,65,768	1,05,670
2. सिडबी	2,86,308	2,79,309	3,02,581	2,94,942	1,71,759	1,65,598	1,13,520	1,14,244
3. एक्विजम बैंक	66,969	64,875	91,672	84,696	52,153	30,650	53,393	40,313
4. एनएचबी@	42,905	35,701	35,671	32,085	23,243	15,260	16,275	12,310
5. एनएबीएफआईडी	18,511	9,775	83,058	25,836	26,252	5,722	20,729	14,672
बी. विशेष वित्तीय संस्थान (6,7 और 8)	750	561	1,364	763	647	264	943	423
6. आईवीसीएफ	-	-	-	-	-	-	-	-
7. आईसीआईसीआई वेंचर	-	-	-	-	-	-	-	-
8. टीएफसीआई	750	561	1,364	763	647	264	943	423
सी. निवेश संस्थान (9 और 10)	-	-	-	-	-	-	-	-
9. एलआईसी	-	-	-	-	-	-	-	-
10. जीआईसी	-	-	-	-	-	-	-	-
डी. वित्तीय संस्थान (ए+बी+सी)	7,98,936	7,54,469	9,56,500	8,74,355	4,41,899	3,14,313	3,70,629	2,87,632
ई. राज्य स्तरीय संस्थान (11 और 12)	4,910	4,579	4,606	5,256	..	..	..	..
11. एसएफसी^	4,910	4,579	4,606	5,256	..	..	..	..
12. एसआईडीसी	..	..	..	..	..	..	..	..
एफ. सभी वित्तीय संस्थाओं द्वारा कुल सहायता (डी+ई)	8,03,847	7,59,048	9,61,106	8,79,611	4,41,899	3,14,313	3,70,629	2,87,632

एस: स्वीकृतियां, डी: संवितरण, शून्य:- उपलब्ध नहीं है, एन.एम : सार्थक नहीं है

* ऋणों में रुपया ऋण और विदेशी मुद्रा ऋण शामिल हैं।

@ एनएचबी डेटा जुलाई-जून से संबंधित है।

#: अन्य में गारंटी शामिल है।

^: डेटा चार एसएफसी से संबंधित है।

टिप्पणी: 1. आंकड़े अनंतिम हैं।

2. पूर्णांकन के कारण योग घटकों के योग के समान नहीं होने की संभावना है।

स्रोत: संबंधित वित्तीय संस्थान।

परिशिष्ट सारणी VI.8: वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत और वितरित वित्तीय सहायता (जारी)

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	हामीदारी और प्रत्यक्ष अभिदान							
	2022-23		2023-24		अप्रै-सितं 2023		अप्रै-सितं 2024	
	एस	डी	एस	डी	एस	डी	एस	डी
1	10	11	12	13	14	15	16	17
ए. अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (1 से 5)	1,806	1,476	-	-	-	9	-	-
1. नाबार्ड	-	-	-	-	-	-	-	-
2. सिडबी	1,806	1,476	-	-	-	9	-	-
3. एकिज़म बैंक	-	-	-	-	-	-	-	-
4. एनएचबी@	-	-	-	-	-	-	-	-
5. एनएबीएफआईडी	-	-	-	-	-	-	-	-
बी. विशेष वित्तीय संस्थान (6,7 और 8)	-	-	-	-	-	-	-	-
6. आईवीसीएफ	-	-	-	-	-	-	-	-
7. आईसीआईसीआई वेंचर	-	-	-	-	-	-	-	-
8. टीएफसीआई	-	-	-	-	-	-	-	-
सी. निवेश संस्थान (9 और 10)	1,00,516	52,919	1,66,525	78,584	62,950	11,934	83,050	33,177
9. एलआईसी	1,00,516	52,919	1,66,525	78,584	62,950	11,934	83,050	33,177
10. जीआईसी	-	-	-	-	-	-	-	-
डी. वित्तीय संस्थान (ए+बी+सी)	1,02,322	54,395	1,66,525	78,584	62,950	11,943	83,050	33,177
ई. राज्य स्तरीय संस्थान (11 और 12)	..	..	..	..	..	..	..	..
11. एसएफसी^	..	..	..	..	..	..	..	..
12. एसआईडीसी	..	..	..	..	..	..	..	..
एफ. सभी वित्तीय संस्थाओं द्वारा कुल सहायता (डी+ई)	1,02,322	54,395	1,66,525	78,584	62,950	11,943	83,050	33,177

एस: स्वीकृतियां, डी: संवितरण, शून्य...:- उपलब्ध नहीं है, एन.एम : सार्थक नहीं है

* ऋणों में रुपया ऋण और विदेशी मुद्रा ऋण शामिल हैं।

@ एनएचबी डेटा जुलाई-जून से संबंधित है।

#: अन्य में गारंटी शामिल है।

^: डेटा चार एसएफसी से संबंधित है।

टिप्पणी: 1. आंकड़े अनंतिम हैं।

2. पूर्णांकन के कारण घटकों का योग अलग हो सकता है।

स्रोत: संबंधित वित्तीय संस्थान।

परिशिष्ट सारणी VI.8: वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत और वितरित वित्तीय सहायता (जारी)

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	अन्य#							
	2022-23		2023-24		अप्रै-सितं 2023		अप्रै-सितं 2024	
	एस	डी	एस	डी	एस	डी	एस	डी
1	18	19	20	21	22	23	24	25
ए. अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (1 से 5)	13,693	4,768	15,364	5,335	11,212	2,891	3,513	1,733
1. नाबार्ड	825	584	493	551	386	142	83	127
2. सिडबी	23	2	9	-	6	-	2	-
3. एकिजम बैंक	12,796	3,912	14,640	4,377	10,729	2,749	3,402	1,498
4. एनएचबी@	-	-	-	-	-	-	-	-
5. एनएबीएफआईडी	50	270	222	407	91	-	26	108
बी. विशेष वित्तीय संस्थान (6,7 और 8)	-	-	90	90	90	90	-	-
6. आईवीसीएफ	-	-	-	-	-	-	-	-
7. आईसीआईसीआई वेंचर	-	-	-	-	-	-	-	-
8. टीएफसीआई	-	-	90	90	90	90	-	-
सी. निवेश संस्थान (9 और 10)	605	306	-	245	-	128	-	126
9. एलआईसी	605	306	-	245	-	128	-	126
10. जीआईसी	-	-	-	-	-	-	-	-
डी. वित्तीय संस्थान (ए+बी+सी)	14,298	5,074	15,454	5,670	11,302	3,110	3,513	1,859
ई. राज्य स्तरीय संस्थान (11 और 12)	..	..	..	..	..	..	..	..
11. एसएफसी^	..	..	..	..	..	..	..	..
12. एसआईडीसी	..	..	..	..	..	..	..	..
एफ. सभी वित्तीय संस्थाओं द्वारा कुल सहायता (डी+ई)	14,298	5,074	15,454	5,670	11,302	3,110	3,513	1,859

एस: स्वीकृतियां, डी: संवितरण, शून्य...- उपलब्ध नहीं है, एन.एम : सार्थक नहीं है

* ऋणों में रुपया ऋण और विदेशी मुद्रा ऋण शामिल हैं।

@ एनएचबी डेटा जुलाई-जून से संबंधित है।

#: अन्य में गारंटी शामिल है।

^: डेटा चार एसएफसी से संबंधित है।

टिप्पणी: 1. आंकड़े अनंतिम हैं।

2. पूर्णांकन के कारण योग घटकों के योग के समान नहीं होने की संभावना है।

स्रोत: संबंधित वित्तीय संस्थान।

परिशिष्ट सारणी VI.8: वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत और वितरित वित्तीय सहायता (समाप्त)

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	कुल								प्रतिशत घट-बढ़			
	2022-23		2023-24		अप्रै-सितं 2023		अप्रै-सितं 2024		2023-24		अप्रै-सितं 2024	
	एस	डी	एस	डी	एस	डी	एस	डी	एस	डी	एस	डी
1	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
ए. अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (1 से 5)	8,13,685	7,60,153	9,70,501	8,78,927	4,52,464	3,16,950	3,73,200	2,88,941	19.3	15.6	-17.5	-8.8
1. नाबार्ड	3,84,319	3,64,832	4,42,649	4,36,584	1,68,232	96,961	1,65,851	1,05,797	15.2	19.7	-1.4	9.1
2. सिडबी	2,88,137	2,80,787	3,02,590	2,94,942	1,71,765	1,65,607	1,13,522	1,14,244	5.0	5.0	-33.9	-31.0
3. एक्जिम बैंक	79,764	68,787	1,06,312	89,073	62,882	33,399	56,796	41,810	33.3	29.5	-9.7	25.2
4. एनएचबी@	42,905	35,701	35,671	32,085	23,243	15,260	16,275	12,310	-16.9	-10.1	-30.0	-19.3
5. एनएबीएफआईडी	18,560	10,045	83,280	26,243	26,342	5,722	20,756	14,780	348.7	161.2	-21.2	158.3
बी. विशेष वित्तीय संस्थान (6,7 और 8)	750	561	1,454	853	737	354	943	423	93.8	52.2	28.0	19.6
6. आईवीसीएफ	-	-	-	-	-	-	-	-	n.m.	n.m.	n.m.	n.m.
7. आईसीआईसीआई वेंचर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. टीएफसीआई	750	561	1,454	853	737	354	943	423	93.8	52.2	28.0	19.6
सी. निवेश संस्थान (9 और 10)	1,01,121	53,225	1,66,525	78,829	62,950	12,062	83,050	33,303	64.7	48.1	31.9	176.1
9. एलआईसी	1,01,121	53,225	1,66,525	78,829	62,950	12,062	83,050	33,303	64.7	48.1	31.9	176.1
10. जीआईसी	-	-	-	-	-	-	-	-	n.m.	n.m.	n.m.	n.m.
डी. वित्तीय संस्थान (ए+बी+सी)	9,15,556	8,13,938	11,38,479	9,58,609	5,16,151	3,29,366	4,57,192	3,22,667	24.3	17.8	-11.4	-2.0
ई. राज्य स्तरीय संस्थान (11 और 12)	4,910	4,579	4,606	5,256	..	..	..	..	..	..	..	..
11. एसएफसी^	4,910	4,579	4,606	5,256	..	..	..	..	..	..	..	..
12. एसआईडीसी	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
एफ. सभी वित्तीय संस्थाओं द्वारा कुल सहायता (डी+ई)	9,20,467	8,18,517	11,43,085	9,63,865	5,16,151	3,29,366	4,57,192	3,22,667	24.2	17.8	-11.4	-2.0

एस: स्वीकृतियां, डी: संवितरण, शून्य...:- उपलब्ध नहीं है, एन.एम : सार्थक नहीं है

* ऋणों में रुपया ऋण और विदेशी मुद्रा ऋण शामिल हैं।

@ एनएचबी डेटा जुलाई-जून से संबंधित है।

#: अन्य में गारंटी शामिल है।

^: डेटा चार एसएफसी से संबंधित है।

टिप्पणी: 1. आंकड़े अनंतिम हैं।

2. पूर्णांकन के कारण योग घटकों के योग के समान नहीं होने की संभावना है।

स्रोत: संबंधित वित्तीय संस्थान।

परिशिष्ट सारणी VI.9: एकल प्राथमिक व्यापारियों का वित्तीय प्रदर्शन (जारी)

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	प्राथमिक व्यापारियों के नाम	वर्ष	आय			
			ब्याज पर आय (डिस्काउंट आय सहित)	ट्रेडिंग लाभ	अन्य आय	कुल आय
1	2	3	4	5	6	7
1	एसटीसीआई प्राइमरी डीलर लिमि.	2022-23	846	-49	2	799
		2023-24	1,041	139	2	1,182
		छ1:2024-25	567	148	1.36	716
2	एसबीआई डीएफएचआई लिमि.	2022-23	952	-12	6	946
		2023-24	1,378	44	8	1,430
		छ1:2024-25	785	86	3	874
3	आईसीआईसीआई सिक्यूरिटीज प्राइमरी डीलरशिप लिमि.	2022-23	1,249	45	27	1,322
		2023-24	2,110	312	26	2,448
		छ1:2024-25	1,227	148	22	1,397
4	पीएनबी गिल्ट्स लिमि.	2022-23	1,222	-237	16	1,001
		2023-24	1,518	-48	8	1,478
		छ1:2024-25	795	68	5	868
5	मोर्गन स्टैनली इंडिया प्राइमरी डीलर प्राइवेट लिमि.	2022-23	803	-54	3	752
		2023-24	1,376	280	3	1,659
		छ1:2024-25	831	34	19	884
6	नोमूरा फिक्सड इन्कम सिक्यूरिटीज प्राइवेट लिमि.	2022-23	353	-139	2	216
		2023-24	615	215	2	832
		छ1:2024-25	520	90	2	612
7	गोल्डमैन सॅक्स (इंडिया) कैपिटल मार्केट प्राइवेट लिमि.	2022-23	391	-50	5	346
		2023-24	1,120	118	3	1,241
		छ1:2024-25	742	127	0	870
8	कुल	2022-23	5,816	(495)	61	5,382
		2023-24	9,158	1,060	52	10,270
		छ1:2024-25	5,468	701	51	6,221

स्रोत: एसपीडी द्वारा प्रस्तुत की गई विवरणियाँ।

परिशिष्ट सारणी VI.9: एकल प्राथमिक व्यापारियों का वित्तीय प्रदर्शन (समाप्त)

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	प्राथमिक व्यापारियों के नाम	वर्ष	व्यय			कर पूर्व लाभ	कर पश्चात लाभ	निवल मालियत पर रिटर्न (प्रतिशत)
			ब्याज पर व्यय	अन्य व्यय	कुल व्यय			
1	2	3	8	9	10	11	12	13
1	एसटीसीआई प्राइमरी डीलर लिमि.	2022-23	712	30	741	47	34	4.4
		2023-24	944	43	987	266	198	22.4
		छ1:2024-25	499	21	520	229	170	16.1
2	एसबीआई डीएफएचआई लिमि.	2022-23	786	41	827	29	20	1.4
		2023-24	1,226	41	1,267	242	180	12.0
		छ1:2024-25	690	27	717	275	205	12.0
3	आईसीआईसीआई सिक्यूरिटीज प्राइमरी डीलरशिप लिमि.	2022-23	1,063	136	1,199	175	128	8.1
		2023-24	1,871	172	2,043	586	437	25.4
		छ1:2024-25	1,094	99	1,194	477	356	18.3
4	पीएनबी गिल्टस लिमि.	2022-23	973	47	1,020	-85	-77	-5.8
		2023-24	1,411	66	1,477	99	70	5.4
		छ1:2024-25	690	29	719	223	168	12.0
5	मोर्गन स्टैनली इंडिया प्राइमरी डीलर प्राइवेट लिमि.	2022-23	571	58	629	195	145	5.0
		2023-24	1,049	73	1,121	560	418	11.4
		छ1:2024-25	649	41	690	217	161	4.1
6	नोमूरा फिक्सड इन्कम सिक्यूरिटीज प्राइवेट लिमि.	2022-23	260	47	308	94	70	6.3
		2023-24	519	72	590	118	88	7.4
		छ1:2024-25	443	38	481	53	40	2.6
7	गोल्डमैन सॅक्स (इंडिया) कैपिटल मार्केट प्राइवेट लिमि.	2022-23	299	50	350	30	22	1.4
		2023-24	878	58	935	365	272	10.5
		छ1:2024-25	601	27	628	277	207	7.3
8	कुल	2022-23	4,664	410	5,074	485	342	3.2
		2023-24	7,897	524	8,422	2,237	1,663	12.9
		छ1:2024-25	4,666	282	4,949	1,751	1,308	9.1

स्रोत: एसपीडी द्वारा प्रस्तुत की गई विवरणियाँ।

परिशिष्ट सारणी VI.10: एकल प्राथमिक व्यापारियों के चुनिंदा वित्तीय संकेतक (जारी)

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	प्राथमिक व्यापारियों के नाम	पूँजीगत निधियां (टियर I+टियर II+उपयुक्त टियर III)					सीआरएआर (प्रतिशत)				
		2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	छ1: 2024-25	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	छ1: 2024-25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	एसटीसीआई प्राइमरी डीलर लिमि.	731	777	790	902	1,111	28.9	32.3	21.8	29.1	26.8
2	एसबीआई डीएफएचआई लिमि.	1,245	1,311	1,247	1,426	1,612	33.4	42.4	46.1	36.0	35.9
3	आईसीआईसीआई सिक्यूरिटीज प्राइमरी डीलरशिप लिमि.	1,723	1,899	1,792	1,903	2,274	44.1	47.7	42.9	26.6	25.8
4	पीएनबी गिल्टस लिमि.	1,306	1,426	1,238	1,313	1,453	45.6	66.4	31.8	34.0	41.7
5	मोर्गन स्टैनली इंडिया प्राइमरी डीलर प्राइवेट लिमि.	2,105	2,290	3,384	3,774	3,922	51.9	58.5	88.6	69.8	64.1
6	नोमुरा फिक्सड इन्कम सिक्यूरिटीज प्राइवेट लिमि.	1,064	1,068	949	1,226	1,766	60.2	49.1	43.0	33.7	50.1
7	गोल्डमैन सॅक्स (इंडिया) कैपिटल मार्केट प्राइवेट लिमि.	626	648	2,363	2,429	2,293	109.1	116.1	76.0	67.6	63.7
	कुल	8,798	9,418	11,763	12,973	14,433	45.3	51.5	50.0	42.2	42.2

स्रोत: एसपीडी द्वारा प्रस्तुत की गई विवरणियाँ

परिशिष्ट सारणी VI.10: एकल प्राथमिक व्यापारियों के चुनिंदा वित्तीय संकेतक (समाप्त)

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. स.	प्राथमिक व्यापारियों के नाम	सरकारी प्रतिभूतियों के स्टॉक और खज़ाना बिल (बाज़ार मूल्य)					कुल आस्तियाँ (चालू देयताओं और प्रावधानों का निवल)				
		2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	छ1: 2024-25	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	छ1: 2024-25
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	एसटीसीआई प्राइमरी डीलर लिमि.	11,398	13,616	14,664	14,436	14,224	11,405	12,025	12,286	12,536	12,642
2	एसबीआई डीएफएचआई लिमि.	9,589	12,390	16,645	21,360	24,956	9,837	12,659	16,955	21,840	22,739
3	आईसीआईसीआई सिक्क्यूरिटीज प्राइमरी डीलरशिप लिमि.	15,766	15,864	24,784	31,594	37,817	18,067	17,545	31,873	33,845	39,519
4	पीएनबी गिल्टस लिमि.	10,907	15,267	18,518	23,008	21,635	11,179	13,819	16,948	21,240	20,569
5	मोर्गन स्टैनली इंडिया प्राइमरी डीलर प्राइवेट लिमि.	12,533	13,645	12,691	26,662	22,363	13,004	16,314	15,452	28,109	25,055
6	नोमुरा फिक्सड इन्कम सिक्क्यूरिटीज प्राइवेट लिमि.	4,044	4,849	6,474	12,337	13,085	4,419	5,629	7,396	13,170	15,115
7	गोल्डमैन सॅक्स (इंडिया) कैपिटल मार्केट प्राइवेट लिमि.	3,457	3,468	15,491	21,853	15,932	3,830	4,722	17,949	22,831	16,485
	कुल	67,694	79,099	1,09,267	1,51,248	1,50,029	71,758	82,733	1,18,878	1,53,591	1,52,124

स्रोत: एसपीडी द्वारा प्रस्तुत की गई विवरणियाँ

